

नयी तालीम

“युवावस्था जीवन का स्वर्णकाल है जब कि (प्रत्येक) व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए अनूद्य आदर्श अर्जित करता है और आन्तरिक शक्ति विकसित करता है। हमारी युवापीढी को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे यह देश की सस्कृति और उसकी उज्ज्वल परम्परा को समझ सें और उसके लिए जरूर गौरव सें ताकि वह देश के हित में ही उनका अपना हित सम्भावित है ऐसा समझ सके। देश को उनसे बहुत आशाएँ हैं।”

मोरारजी देसाई



अखिल भारत नयी तालीम समिति

सेवाग्राम

वर्ष : २६]

अगस्त-सितम्बर, १९७७

[संक : १]

सम्पादक-मण्डल :

श्री श्रीमन्नारायण - प्रधान सम्पादक

श्री वज्रुभाई पटेल

श्रीमंती मदालसा नारायण

डॉ० मदनमोहन शर्मा

अनुक्रम

हमारा दृष्टिकोण

गौंव वालोंसे सम्बन्ध जोड़ें

बुनियादी तालीम

कार्य ताला

सरणाभिनन्दन एक राष्ट्रीय सत्कार

छठी योजना गांधीवादी हो

बुनियादी तालीम का एक प्रयोग

रचनात्मक कार्य की दिशा ,

स्वर-सत्कार

विज्ञान में सुधार

महात्मा गांधी

मोराजी देसाई

जाविर हुसैन

नादिक अली

श्रीमन्नारायण

राधाबहन

मदालसानारायण

अगस्त-सितम्बर '७७

- 'नई तालीम' का वर्ष अगस्त से शरम्भ होता है।
- 'नई ताली' का वार्षिक शुल्क वारह रुपए हैं और एक अंक का मुख्य दो व
- पत्र व्यवहार करते समय माहक अपनी सच्चा सिखना न भूलें।
- 'नई तालीम' में व्यक्ति विचारों की पूरी जिम्मेदारी लेखक की होती है।

श्री प्रभाकरजी द्वारा ज भा नई तालीम समिति सेवानामके लिए प्रकाशित
राष्ट्रभाषा प्रेस, वर्धा में मुद्रित

हमारा दृष्टिकोण

शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन :

१० और ११ अगस्त को दिल्ली में शिक्षा मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था जिसका उद्घाटन प्रधान मंत्री श्री मोरारजी भाई देसाई ने किया। यह सम्मेलन कई दृष्टि से महत्वपूर्ण था, क्योंकि 'जनता पार्टी' की केंद्रीय सरकार गठित होने के बाद इसमें शिक्षा की नई नीति निर्धारित करना आवश्यक था। उत्तर भारत के लगभग सभी प्रदेशों में भी राज्य सरकारें जनता पार्टी की ही हैं।

अने उद्घाटन भाषण में श्री मोरारजी भाई ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि १०+२+३ के 'नए' शिक्षाक्रम को तभी सफल बनाया जा सकेगा जब वह महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित बुनियादी शिक्षा के मूल सिद्धान्तों पर आधारित हो। इसके लिए यह जरूरी है कि हर स्तर पर शिक्षा का माध्यम समाज-उपयोगी उत्पादक थम हो। यह भी आवश्यक है कि शिक्षा का संबंध आस-पास की विकास योजनाओं से वैज्ञानिक ढंग से जोड़ा जाए और विद्यार्थी समाजसेवा के कार्य को अपनी शिक्षा का अविभाज्य अंग माने। प्रधानमंत्रीजी ने कहा कि यदि हमारी शिक्षा पद्धति में इस प्रकार का कोई बुनियादी परिवर्तन न किया गया तो १०+२+३ का नया शिक्षाक्रम लगभग बेकार साबित होगा। हमारी समस्याएँ हल करने के बजाए उसको बजह से कुछ नई उलझने पैदा होंगी और शिक्षित बेकारों की समस्या ज्यों की त्यों बनी रहेगी।

श्री मोरारजी भाई देसाई ने मातृभाषा माध्यम की हर स्तर पर व्यवस्थित ढंग से लागू करने पर भी बहुत जोर दिया। हमारी राष्ट्रीय नीति के अनुसार इस समय हाईस्कूल तक तो शिक्षा का माध्यम सामान्यतः मातृभाषा ही है। कालेजों में मातृभाषा माध्यम ऐच्छिक रूप से चलाया जा रहा है। किन्तु मेडिकल और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों की शिक्षा इस समय भी अंग्रेजी द्वारा ही अनिवार्य रूप में दी जा रही है। वर्धा में हमने कालेज स्तर पर मातृभाषा माध्यम का प्रारम्भ सन् १९४६ में ही किया था। इस अभिक्रम का उदघाटन स्वयं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किया था। इस समय श्री हमारे वर्धा, नागपुर और जबलपुर कालेजों में एक काम तक सारी वाणिज्य शिक्षा हिन्दी और मराठी माध्यम द्वारा दी जा रही है। मातृभाषा माध्यम को सफल बनाने के लिए कामर्स के टेक्नीकल विषयों पर भी हिन्दी और मराठी में बहुत-सी सुन्दर और उपयोगी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इसलिए यह अनुभव से सिद्ध हो चका है कि हमारे देश में ऊँची से ऊँची शिक्षा प्रादेशिक भाषाओं में दी जा सकती है।

किन्तु हमें खेद है कि शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में प्रधान मंत्री श्री मोरारजी भाई के विचारों और सुझावों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। उन्होंने यही तर्क दिया कि नई शिक्षा प्रणाली को कुछ हेर-फेर के साथ सारे देश में लागू कर दिया जाए। कई प्रदेशों ने तो इसे प्रारम्भ कर भी दिया है। गैर राज्य इसे छोटी पचवर्षीय योजना के अन्त तक कार्यान्वित करें। सम्मेलन के प्रस्ताव में वृत्तियाँ दी शिक्षा के मिद्वान्ती का जिक्र भी नहीं है। मातृभाषा माध्यम को अनिवार्य बनाने में सम्बन्ध में भी कोई सिफारिश नहीं की गई है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री नागडवाला ने भी अपने सम्मेलन में यह बात माध्यम में इन विषयों का उल्लेख नहीं किया है। और न केन्द्रीय शिक्षा मंत्री डा. प्रतापचन्द्र चन्द्र ने प्रधानमंत्री के विचारों का समर्थन किया है। यह गन्तव्य बड़े आश्चर्य के दुःख का विषय है।

नई तालीम समिति की दिल्ली में तारीख १८ जुलाई को जो बैठक हुई थी उसकी सिफारिशें हम इस अंक में अलग प्रकाशित कर रहे हैं। हमारा निश्चित मत है कि यदि १०+२+३ के नए शिक्षा-धर्म में नई तालीम के मूलभूत सिद्धान्तों को ईमानदारी से लागू न किया गया तो वह एक महंगी निष्फलता साबित होगी। इस समय सारी दुनिया के शिक्षा शास्त्रियों का यह निश्चित मत है कि हमारी शिक्षा का आधार उत्पादक और समाजोपयोगी धर्म हो। यूनेस्को के अन्तरराष्ट्रीय शिक्षा कमिशन ने भी इसी बात पर बल दिया है। हम आशा करते हैं कि केन्द्रीय और राज्य सरकार प्रधानमंत्री श्री मोरारजी भाई के सुझावों पर एक बार फिर बहुत गहराई से विचार करनी और शीघ्र ही योग्य निर्णय लेंगी।

“पब्लिक” स्कूलों का भविष्य :

भारतीय संसद के पिछले अधिवेशन में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए केन्द्रीय शिक्षामंत्री डा. प्रतापचन्द्र चन्द्रन कहा था कि पब्लिक स्कूलों को बन्द करा देना उचित नहीं होगा, क्योंकि वे अपने ढंग से उपयोगी कार्य कर रहे हैं। किन्तु जनता पार्टी के कई प्रमुख सदस्यों ने अपना स्पष्ट मत जाहिर किया है कि वर्तमान पब्लिक स्कूलों को अपना रंग-ढंग बदलना ही होगा और यदि वे ऐसा न कर तो उन्हें बन्द भी करना जरूरी हो जाएगा। नई तालीम समिति का यह निश्चित विचार है कि अब इन पब्लिक स्कूलों को अपनी वर्तमान पढ़ाई का ढाँचा और तौर-तरीका बदलना ही चाहिए। हमारी राष्ट्रीय नीति के अनुसार पढ़ाई का माध्यम मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा होना चाहिए। किन्तु इन पब्लिक स्कूलों में इस समय भी शुरू से ही बच्चों को अंग्रेजी भाषा द्वारा शिक्षा दी जाती है। विभाषा फॉर्मूले के अनुसार उनमें राष्ट्रभाषा हिन्दी को भी उचित स्थान नहीं दिया जाता। उनका सारा वातावरण भी अंग्रेजी और ईसाई संस्कृति से भरा रहता है। यह सबदृष्टि से बहुत अनुचित है और इस सम्बन्ध में केन्द्र व राज्य सरकारों को जल्द ही योग्य निर्णय लेना चाहिए।

य पब्लिक स्कूल मते ही चालू रख जाऐं क्योंकि उनमें कुछ बिभेपताएँ तो हैं ही। किंतु यह नितांत आवश्यक है कि उनका पढ़ाई का ढाँचा हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप हो। यह कहना पर्याप्त नहीं है कि चूँकि वे सरकार से कोई आर्थिक सहायता नहीं लते इसलिए उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में पूरी आजादी होनी चाहिए सरकारी सहायता न लत हुए भी उन्हें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार अपना ढाँचा ढालना ही होगा। यदि वे ऐसा करने की तैयार न हों तो उन्हें चालू रखने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। नहीं, तब आजाद देश के बच्चा और नवयुवकों का एक नया वर्ग खड़ा कर जाऐंग और इसके कारण हमारे राष्ट्र में समानता के बजाय सामाजिक व आर्थिक विभेदताएँ और भी गहरी बनेंगी। यह सर्वथा अनुचित और अवांछनीय होगा।

गाँव वालों से संबंध जोड़े

महात्मा गांधी

[बुनियादी शिक्षा को सफल बनाने की दृष्टि से महात्मा गांधी ने धीमे-धीमे ग्रामों में नए नए स्कूलों में सन १९४५ में विस्तृत चर्चा की थी और सुझाया था कि स्वदेशीय के माध्यम से ग्रामीणों में साधारण सम्बन्ध स्थापित करना चाहिए। यह चर्चा नई तकनीक के पाठकों के लिए यहाँ दी जा रही है। यह कामगोपनीय भवनक प्रकाशित नहीं हुई है।]

साधुजी — गाँव में बिखरकर रहना ठीक नहीं है। गाँव में काम करने के लिए वहाँ रहना है तो बाय वर्तकों का जीवन अलग होना जरूरी है यदि एस नहीं रहेंगे तो हमारा खोला हो जाएगा। अलग रहने से अभिप्राय उनका हो कि हम से उनका जैसे धरा और वातावरण में न रहने से है। हमें अलग रहना है पर वहाँ रहते हुए हमारा हाड और हृदय एक होना है। स्वाभाविक की आवादी बढ़ रही है, दुगुनी हुई है इसीसे रोग बढ़ते हैं। लोगो को जगह चाहिए, घर में हवा चाहिए खेतों में जाकर क्या नहीं रहते क्योंकि चोरों का डर है। इसलिए कंसी भी गंदगी हो गाँव में ही रहें।

बाहर के लोग (बाय वर्तकों) गाँव में रहेंगे व गाँव के नियंत्रण में नहीं रहेंगे। यहाँ नियंत्रण का अर्थ ठीक नहीं है तुम्हारा एक एक शब्द तोलकर होता है। बाहर के लोग जो गाँव में रहते हैं उन्हें गाँव के उसका और स्थिति आदि सामाजिक जीवन में हिस्सा लेना चाहिए, व हर चीज में हिस्सा नहीं ले सकते। व क्या चीज ले सकते हैं और क्या नहीं, यह उन्हें बताना चाहिए। देहात के लोग हमारी नकल करते हैं परंतु दूर से ही व समझ नहीं पाते कि उन्हें हमारे जीवन से क्या लेना है। देहातों की सारी शिक्षा में इतनी अधिक चीजें ग्रहण करना है। यह देखकर भागना नहीं, उनमें से अच्छी

चीजे ग्रहण करना है। कूड़े को सुधारना है। मैं चाहूँ तो कूड़े कचरे को बम से उड़ा दूँ और दूसरा गाँव बसा दूँ। मगर मैं यह काम नहीं चाहता हूँ। कि बम से उड़ा कर नया गाँव बसाऊँ। चाहे इस काममें (सुधारने) में दो पीढ़ी ही क्यों न लग जाए।

शान्ता बहन — गाँववालों से सम्बन्ध जोड़ने के लिए क्या करे ?

गांधीजी — घर-घर जाकर बीमारों को देखो, जाकर उनके यहाँ सफाई भी करो, नई तालीम का यह हिस्सा है। जीवन का कोई भी विभाग ऐसा नहीं है जो नई तालीम में नहीं आता, सब चीजों पर उसका कब्जा है। जहाँ तक हो सके तू ही (शान्ता) डाक्टर भी बनेगी। नैसर्गिक-उपचार पर मरोसा हो तो डाक्टर की जरूरत नहीं होगी। एक दिन ऐसा था कि मैं यह सब करता था। परन्तु आज नहीं कर सकता हूँ। इसलिए दूसरों को भी नहीं रोक सकता। इसलिए मरीजों को देखना भी तेरा काम है।

शिक्षक के गुण य होने चाहिए कि उसका जो विश्वास हो वही करे, वह लोगों को जसा वह बंसा करे यह शक्ति उसमें आनी चाहिए उसके पास जितने बच्चे आएंगे, वे उसे लेकर उनके घर जाएंगे और उनकी माताओं का सिखाएगा।

शान्ता बहन — सेवाश्रम में अलग अलग संस्थाओं के काम चलेंगे। उनके सेवाश्रम में चलनेवाली अन्य संस्थाओं के कामों में कहीं तक मेरी जिम्मेदारी होगी? उनके प्रति मेरा क्या बर्तव्य होगा? सेवाश्रम में चलनेवाली अन्य संस्थाओं के कामोंमें कहीं तक मेरी जिम्मेदारी होगी?

गांधीजी — गाँव में काम करनेवाला निश्चित जगह लेकर वह रहे क्योंकि तू तो इस काम को लेकर ही इस काम के लिए बैठेगा। मदद माँग सकती है। यदि दूसरे मदद दे सकें तो दे, नहीं तो बांग्र भूख रहे तो रहे, परन्तु पसन्दगी तेरी ही रहेगी। तेरे में शक्ति होनी चाहिए, आत्म विश्वास होना चाहिए, कि काम होगा ही तू लाचार न हो, लाचार होगी तो पगु बनेगी। प्रौढ़-शिक्षा आता

नहीं। इन शिक्षिता से काम लेना ही है। देहातियों से काम लेना आसान है। वे अन्य कार्यकर्ता तो पढ़े लिखे हैं न।

नई तालीम का पूरा चित्र मेरे हृदय में बैठा है मैं ही नई तालीम का जन्म दाता हूँ। मैं जानता हूँ कि वह क्या चीज है। देहातियों को जागृत करना है। जिस शिक्षक में वह स्वभाव पैदा हो गया है वह ही जानेगा। मनुष्य स्वभाव को जीत लेना है।

विषय का विषय ज्ञान हो परन्तु शिक्षिका और विद्यार्थी दोनों में साथ तो होना ही चाहिए। यदि यह सिद्ध नहीं होता है तो यह समझना होगा कि कहीं गलती है।

शान्ता बहन —सेवाग्राम के इंदु गिंद की सस्य ओ का सेवाग्राम से क्या संबंध होगा?

गांधीजी —सेवाग्राम की सब सस्याएँ मेरा ही काम है। वे अहिंसा मार्ग के काम हैं। अंग्रेजी तरीके से चरने वाले एक के पीछे अनेक मनुष्य आए और उसी से यज्ञ-शास्त्र आया। इसका स्वरूप पश्चिम से आया। वैसी ही विश्व मूर्ति बनी। इसमें सामान्य काम भी हिंसा से करना होता है। यदि हम वैसे बने तो कैसे ठीक होगा? इसके उल्टा हमें शान्ति से मार्ग निवातना है। इसी से हम शकट होती हैं।

सबको साथ रखना है शान्ति और महत्त्व से काम लेना है। "सबको मिलाना" इसमें ही सारी नई तालीम की नींव डाली गई है। अहिंसा से सबको सिखाना चाहते हैं। सबको साथ लेकर काम करें इसके बाद अक्षर ज्ञान हो। इसलिए उद्योगों का अहिंसा के साथ गहरा तात्त्विक है। इसमें आज का समाज में एक तरफ काम करनेकी वृत्ति है और दूसरा काम लेनेवाला है। लेकिन नये समाज में अब एव साथ सब काम करेंगे। ये सस्याएँ मेरी स्वेच्छा से हुआ काम है। अब वहाँ एक दुनिया पैठ गई है। इसलिए मैंने कहा है कि सबसे ज्यादा काम यहाँ ही हो सकता है। अकला आदमी सब काम नहीं कर सकता। पहले दर्जे का काम सभी हो सकता है जब उसके साथ सबकी आकंक्ष काम लेनेकी 'मिन्न' आजाए। हम, अलग-

अलग कंकरी जैसे है मगर हमें एक साथ मिलाकर ईंटकी तरह बनना होगा, फिर उनसे घर बनाता है। मेरा सहयोग का अर्थ अंग्रेजी को अपरेशन नहीं, वह तो मेरा अहिंसा का सहकार है। हमें गांधी के सामने एक आदर्श होकर दिखाना है। यहाँ की अनेक समस्याएँ एक के सदृश दिखाई दें। हम एक सौ पञ्चीस आदमी एक से ही नजर आएँ तो कुछ बताना नहीं होगा। गाँववाले देख सकेंगे। मकान को बोलने की जरूरत नहीं रखरख को कारी आवाज करते हैं।

बाहर के नए आदमी सेवाश्रम में रहने आएँ तो आएँ मगर तुम्हारी इजाजत से। गाँव के लोग भी इन नए आनेवालों से कहें कि शान्ता बहन की बिट्ठी लेकर आओ। नई तालीम का काम अवश्य है। किसी को पता नहीं चलेगा कि वह क्या चीज है लेकिन वह नई तालीम होती ही रहेगी। जैसे बच्चे पढ़ते हैं उन्हें पता नहीं कि वे क्या पढ़ते हैं मगर वह पढ़ाई तो दिल में बैठ जाती है, उसमें पीछे हटना नहीं है।

भय निवारण :

शान्ता बहन—देहात में काम करने के लिए गाँववालों के भय को कैसे दूर करें ?

गांधीजी—यदि लोग कहें कि काम मत करो, हमें डर लगता है तो हमें (काम करने वालों को) बहना है कि आपको डर लगता है तो सिपाही से कहकर हमें पकड़वा दो। पर हम डटे रहेंगे। सफाई और काम करते रहेंगे। अगर हमसे डर बिल्कुल निवृत्त जाए और लोगों को इस पर विश्वास हो जाए कि हम निडर हैं तो अपने आप उनका डर निवृत्त जाएगा। लेकिन अभी हम में वह नहीं है। वह बात मेरे अनुभवसे बाहर है। “बेतिया के लोग डरपोक थे मुझे ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि वे चले जाओ वा हटो, ऐसा कहेंगे शान्ता बहन की बात बर लूँ। सेवाश्रम में वह स्वतंत्र काम चलाएंगे महाँ काम बड़ा है। इतनी समस्याएँ हैं परन्तु वह उसी चीज को देखेंगी जो नई तालीम के दायरे में आ सकती है।

जाजूजी —क्या वह गुड का काम भी देखेगी ?

गाँधीजी — मैं तो कह सकता हूँ कि यदि गुड वाला भी मेरे पास आए तो मैं यत्न दूँ कि वह वैसे हो सकता है। सब चीज का संशोधन मैं करने वाला हूँ। वह यह, यही नहीं कह सकती है। वह कहती है मैं स्वतंत्र रूपसे आपके मातहत काम करूँगी। आपसे पूछकर काम करूँगी क्योंकि यह आपका काम है। आपने कहा है कि सेवाग्राम तैयार हो जाए तो मैं समझूँगी कि सारा हिंदुस्तान तैयार हुआ है।

शांतिा वहन नई तालीम की दृष्टि से बैठेगी वह शिक्षण की दृष्टि से बैठेगी तो दूसरा काम बहुत कम रह जाएगा। दूसरा कोई काम करे तो वह उन्हें शिक्षिका की दृष्टिसे बताएगी कि ऐसा करो नहीं करेंगे तो जैसा मन चाहे वैसा चले।

नई तालीम अपने आप चलने वाली चीज है। स्वाश्रयी हो सकती है। गुडवाला अपने आप उसके पास पूछने के लिए आया— शांतिा वहन कैसे करूँ कि लड़का को भी साथ ले सकूँ। अगर वह स्वतंत्र मिजाज का आदमी है तो वह दुख शांतिाके लिए एक विषय बन जाता है। ओटनलट है न? उसे सोचना होगा कैसे मैं इसके साथ कैसे चलूँ कि वह मेरे साथ सीधे चले। स्वाश्रयी बनना है तो कोई चीज नई तालीम के बाहर रह नहीं सकती।

जो काम उस ढाँचे में नहीं आता वह उसे छोड़ देगी। उसने मेरा सहारा लिया है कि मैं हिसाब ले लूँ कि वह क्या कर सकती है और क्या-क्या नई तालीम में आता है क्या-क्या नहीं। दूसरे कार्य कर्ता के पास मैं नई तालीम की बात नहीं करूँगी। वह ग्राम उद्योग या चरखा ले ले। जितना कर सकते हो करो उस स्वाश्रयी बनाओ।

गाँधीजी — क्या करोगी? अंडल्ट एज्युकेशन से शुरु करोगी न?

शांतिा वहन — गाँव में तो पूरा ममाज से सम्बन्ध होगा वहाँ वातावरण बनाना होगा और यह अस्वाभाविक भी न हो ऐसा लगता है इसलिए उनके साथ स्वाभाविक सम्बन्ध कैसे बढ़ाया जाए? वहाँ पुरुष है स्त्रिया है, नवयुवक हैं वच्चे हैं। इनमें से कई कुटुम्ब सस्या से सम्बन्ध रखते हैं लेकिन सस्यावा जीवन उनका जीवन है ऐसा नहीं मानते हैं। उनमें यह भाव कैसे पैदा किया जाए? ग्राम पंचायत

का काम है। मालगुजार भी गाँव का एक प्रौढ़ है उसपर गाँव की जिम्मेदारी है। ऐसे कई प्रश्न हैं। इसलिए मुझे गाँव में जाकर ही रहना होगा। मैंने सोचा है एक एक मुहल्ले में १५ दिन रह कर लोगों से सम्बन्ध बढ़ाऊँ और उनमें मिल जाऊँ। वही ठीक होगा न? मेरे साथ यदि और कोई आएँ तो हम सब इसी तरह गाँव में फैल जाएँगे। शिक्षामें इतनी चीजें आती हैं उसे देखकर भागना नहीं उसमें से अच्छी चीजें ग्रहण करनी हैं। कूड़े को सुधारना है। यदि चाहें तो इस कूड़े कचरे को बम से उड़ा दें और दूसरा गाँव वसा दें मगर यह बात मैं नहीं चाहता हूँ चाहे उस सुधारके शिक्षा के काम में दो पीढ़ी ही क्यों न लग जाएँ।

शान्ता बहन :—फिर गाँव से सम्बन्ध बढ़ाना है तो किस तरह प्रवेश करें ?

गांधीजी :—घर-घर जाकर बीमारों को देख रेख और सफाई भी कर। यह नई तालीम का हिस्सा है जीवन का एक भी विभाग ऐसा नहीं है कि जो नई तालीम में नहीं आता हो। सब चीजों पर उसका कब्जा है। जहाँ तक हो सके तू डाक्टर भी बनेगी और नैसर्गिक उपचार पर भरौसा हो तो डाक्टरकी भी जरूरत नहीं होगी। एक दिन ऐसा था कि मैंने डाक्टर को नहीं बुलाया था। उस समय मेरा पदम आगे बढ़ा था। पर आज नहीं कर सकता हूँ। इसलिए दूसरों को भी नहीं रोक सकता हूँ। मरीजों को देखना भी तेरा काम है परन्तु अभी तेरी यह हैसियत नहीं है। शिक्षक में यह गुण होना चाहिए कि जो बिदवास्त हो वही नरे। लोगों को हम बहें और वे वस्ता करें यह शक्ति हममें आनी चाहिए क्योंकि जितने बच्चे उसके पास आएँगे वे गुण लेकर घर जाएँगे और माँ बाप को सिखाएँगे।

शान्ता बहन :—मेवाग्राम देहात में अलग-अलग विधायक कार्य अलग-अलग समूहों के माफ़ेन चलेगा उनके बारे में मेरा क्या करण होगा जैसे ग्राम उद्योग, छादी बायें, दवा-शास्त्रा, इन संस्थाओं के कार्यमें मेरी क्या जिम्मेदारी रहेगी ?

गांधीजी — घर लेकर रहे पर निश्चित जगह लेकर रहे क्योंकि जो इस काम को लेकर बैठे वह सारी जिम्मेदारी लेकर चले। तू मदद मांग सकती है। यदि मदद दे सके तो द नहीं तो काम अधूरा रहे परन्तु पसंदी तेरी ही रहेगी। तेरे में शक्ति होनी चाहिए। आत्म-विश्वास होना चाहिए कि काम होगा ही तू लाचार न हो लाचार होगी तो पगु बनगी।

अॅडल्ट एज्युकेशन आसान नहीं जब कि देहातियोसे काम लेना आसान है। लेकिन शिक्षितों से काम लेना आसान नहीं है, मगर तेरा आत्म-विश्वास हो कि काम लेना ही होगा। नई तालीम क्या चीज है वह तू अभी नहीं जानती लेकिन उसका पूरा चिन्म मेरे हृदय में बैठा है। मैं ही नई तालीम का जन्म दाता हूँ। मैं जानता हूँ कि वह क्या चीज है। देहातियों को जाग्रत करना है। जिस शिक्षक में यह स्वभाव पैदा हो गया है वह ही जानेगा कि सत्य मनुष्य स्वभाव को जीत लेना है। उनका साथ किस तरह वातें करनी, होगी वह पहचान लेता है। विषय का ज्ञान न हो परन्तु शिक्षक और विद्यार्थी दोनों में साथ होना जरूरी है। यदि यह सिद्ध नहीं होगा तो कहीं-न-कहीं गलती है यह समझ ले।

शान्ता बहन — गाँव में पानीका इतना कम बँसा हो। पानी तो गंदा है और कुएँ भी बुरे हैं।

गांधीजी — बड़े परिश्रम से ही सही पर पानी तो उबाल कर पीना है। जो गन्दे कुएँ हैं उन्हें बंद कर दो। इस काम में पैस खर्च करेंगे क्योंकि ये बीमारी का घर है, ज्यादा कुएँ हैं, इतने कुआँ की जरूरत नहीं है बंद करके से पल्लों से पानी भी बनेगा। आम कुओंके साफ रखने का खर्च तो जनता को ही देना होगा। निजी कुएँ मालिक सुधारें नहीं तो मालकी छोड़ दो और उस पब्लिक फंड से सुधारें। इस तरह सब कुएँ हमारे हाथ आ जाएँ। देहात के लिए देहाती वाटर-वर्क बन जाए पर यह कैसे हो यह सोचने की बात है। काम ऐसा हो कि सारे हिन्दुस्तान के लिए हो सदा हो सस्ता हो। सनातन का आदर्श सबके लिए हो और खर्च भी हो और फिर वह सात लाख देहात के एक नमूना बने।

शान्ता बहन —गारनेखर भाई कहते हैं कि इनेक्ट्रिसिटी से यह काम आसान होगा।

गांधीजी —इनेक्ट्रिसिटी के बारे में मैंने कहा है कि मुझे वाँधो मत। पहले तो वह दो कि सारे हिन्दुस्तान में हो सक्ता है तब मुझे लगना इतनी पावर तो लेनी होगी फिर ऐसे कामों के लिए पब्लिक फंड जमा कर। पब्लिक भी हिस्सा रहे और उसमें आश्रम का हिस्सा भी रहे। आश्रम गाँव के किनारे है और हमें तो लोगों को तालीम देनी है।

शान्ता बहन —आपने कहा था गाँव में रहने जाए तो आश्रम से ही शुरू ही मगर आश्रम का खाना और रहन-सहन साविक है और गाँववालों से अलग है व देहान में कैसे रह सकेंगे?

गांधीजी —परिश्रम से ही सही पर पानी तो नाल कर पीना ही है। मैंने पहले सोचा था दहात में ही रहूँगा मगर चेचक का टीका आदि मुझ नहीं जना था। मुझे क्लेम रहना है ऐसा डाक्टर ने इसीलिए कहा था। प्लेगी डार्ट के विषय में यह बात है कि थोड़ा दूध तो लाना ही चाहिए प्राणीज प्रोटीन थोड़ा रा भी होनेसे दूसरी प्रोटीन अच्छी पचती है। अतएव थोड़ा प्रमाण दूध का रखें। १० तोला दूध और एक तोला घी मगर सच्चा घी हो।

आसादबी —बच्चोंको हम १ तोला तेल देते हैं।

गांधीजी —वह पूरा नहीं है, आज वह चलता है—क्याकि उन्हें घर में कुछ भी मिलता नहीं मगर अपना माप हम उसपर से न निकालें अपना शरीर ईश्वर का घर यानी जनता का है ऐसा मानते हैं, जनता के कारण हम ज़िन्दा रहना चाहते हैं तो शरीर अच्छा रखना है। आश्रम में तबीयत बिगडती है उसका कारण यह है कि ये लोग प्रमाण नहीं रखते, अब तबीयत बिगडनी ही।

मुशीला बहन —यहाँ मसाला और न होने के कारण स्वादिष्ट खाना नहीं होता इसलिए प्रमाण नहीं रख सकते।

गांधीजी —स्वादिष्ट खाना नहीं है इसलिए प्रमाण नहीं है यह मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। दहात में जो खाना है वही

खाते हैं खाने में भी बला है। आश्रम-जीवन में शिक्षा देनी है। न तो ज्यादा नहीं और न छोड़ना ये बातें सीखने लायक हैं।

शान्ता बहन — खानेमें दूध होना जरूरी है और माँ बाप दूध के लिए पैसा दें ऐसा आपने कहा है, बच्चों को दूध देने के लिए उनके जेब में पैसे वहाँ हैं ?

गांधीजी — वही तो करना है। उसमें अंडल्ट एज्युमेंशन है। उन्हें जिम्मेवारी समझना है। उनकी बचाने की शक्ति बढ़ाना है। उन्हें भिक्षुक नहीं बनाना है। आखिर उन्हें खान-पीना तो देना ही है। उनके ढंग दो हैं एक है रुस बा। हमें वही चीज अपने ढंग में करनी है। यदि हम नहीं कर पाते तो कुछ बर्बाद है। मैं मानता हूँ कि वह बनना चाहिए। वहाँ तो उन्होंने सारी दुनियाँ का नहीं सोचा। एक बड़ समाज का सोचा है। यहाँ तो एक सेनाग्राम लेता हूँ माने सारे दुनियाँको ही लेता हूँ। उनका समग्र जीवन लेकर एक सेनाग्राम देहात में कितना हो सकता है वह देखना है। एक बचाए और मौ खाए तो नहीं हो सकता है। हरेक बचाए और हरेक खाए तो हो सकता है। मुझे मरीज के मरने की परवाह नहीं है मगर मरीज होने से रोकूँ इतना बस है। अच्छे समाज में पगु बहुत बम रहते हैं। बच्चे को तो माँ-बाप खिलाते ही हैं अच्छे कुटुम्ब में बच्चे भी लम्बे अगसे (समय) तक भार नहीं होने। यदि ३-४ वर्ष का भी बच्चा बचाने लगे है तो हमारी तानीम है। कालेजवाले दरिद्री बनते हैं।

सेनाग्राम का आदमी हमारे यहाँ काम करता है। हम इसके बाल बच्चाका नहीं देखते हैं हमें उनके साथ के वर्तन में उनके और उनके बच्चों के साथ के व्यवहार में भिन्नता लानी है और रिस्तेदारीकी भावना निर्माण करनी है। वे उनका खाना अलग, कपड़े अलग रखते हैं। उसमें भी बला है। वे अपने को अलग समझते हैं मगर वे हमारे रिस्तेदार और सहकारी साथी हैं। हमें तो समझना होगा कि हम उनके साथ कैसे चलें अपने को अलग रखते हैं तो उसमें सुधार लाना होगा।

शान्ता बहन — यदि खाने में दूध न मिले तो क्या चीजें देनी होगी ?

गांधीजी — इसीलिए जो भूमिहारी हैं उनसे मैं चला हूँ कि यदि और कुछ न मिले तो भूमि, अण्डे ग्राहो लेकिन आवाहारी को पहुँचा नाम न मिले तो मृत्यु मर जाओ। दक्षिण अफ्रीका में मृत्युग्रहियों ने आवाहार के लिए किस तरह तगवारी जमा की थी वह समझने लायक है। आवाहारी को मनस्पर्ति-शास्त्र जानना ही चाहिए। देहात के गरीबों को शिवा के मोषों जैसा बनाना है।

शांता बहन — भूमिहीन की आवादी बहुत बड़ गई है, नई आवादी बढ़ानी है तो घरों की व्यवस्था बंभी हो ?

गांधीजी — नया सेवास्यम अपना हो तो जगह हम देंगे। लोग घर अपने ढाँप बनाएँ मगर जमीन पर उनका रुक नहीं होगा। यदि घर बदलना पड़ा तो जो दूसरा आदमी जाएगा वह घर बनाने में जितना पैसा लगाया गया होगा उतना देकर घर ले सकेगा। लेकिन लोग घर के लिए जमीन माँगकर घर बसा लेंगे परन्तु पैसे की जगह परिश्रम देकर खाली रहने के लिए घर लेना पसंद नहीं करेंगे।

हमारे हाथ में राजस्व नहीं है और मैं आचार-विचार का भी जोर नहीं कर सकता हूँ। मैं जो सत्याग्रह करना चाहता हूँ वैसा हो तो जनता मुझे आप ही सहारा दे देगी। मगर लोग मुझे समझ लें। वे मुझे समझ लें तो फिर मेरा स्थान-स्थान नहीं रहेगा। हमारे खेतों को मैं उजाड़ दूँगा और लोगो को बसने के लिए जगह दे दूँगा। वे आज भी हमारे यहाँ आ जाएँगे लेकिन मैं चाहता हूँ कि वे यह करने को तैयार नहीं हों। वे यह चाहेंगे कि जमीन मिल जाए उसके लिए मैं तैयार नहीं हूँ। मैं जमीन का मालिक नहीं यह वे नहीं मानेंगे। वे तो जमीन माँगेंगे।

शांता बहन — गाँव में दो विस्म के आदमी हैं। एक तो वे जिनके पास जमीन नहीं है और जमीन के मालिक नहीं बनोगे लेकिन पैसा और परिश्रम लगाकर मकान बनाना चाहते हैं। दूसरे वे हैं जिनके पास जमीन है पैसा नहीं है यदि वे अपनी जमीन पर घर बनाएँ तो विस्मो द्वारा पैसा अदा करेंगे पर तब तक वे घर पर कब्जा नहीं रखेंगे ऐसे लोगो को किस तरह मदद करनी होगी ?

गांधीजी — इसके लिए एक सहकारी गृह निर्माण समिति बनानी चाहिए। घर बनाने के लिए उन्हें पैसा उधार देना होगा और लोगो को सस्ती बरदास्त करनी पड़ेगी। जब तक भूरा पैसा अदा नहीं किया जाएगा तब तक घर, सोसायटी का रहेगा। हमें लोन निकालना होगा।

शान्ता बहन — पुराने घर चोरोके डर से बचे थे। वहाँ लोग पैसे गाड़कर रखते थे। इसलिए वे ऐसे थे। यदि कोऑपरेटिव्ह बैंक जैसी पब्लिक सायबरी हो तो घर अच्छे बनेंगे।

गांधीजी — यह पक्ष ना बदल नहीं है। वे लोग पैसे घरमें दबाकर रखन हों तो उसे निकलवाना चाहिए। सोना तो सरकार ने सब खींच लिया। १ पौंड में १० शि दिए। अब जा रखने है उसका प्रबध करके फिर घर बनाना है। इसमें डर रहेगा ही नहीं।



संस्था कुल

गांधी स्मारक निधि का मासिक

सम्पादक — श्री पूर्णचन्द्र जैम

वार्षिक शुल्क—५ रुपये,

एक प्रति—५० पैसे

रचनात्मक प्रवृत्तियो, कार्यों सर्वोदय मगठन एवं

राष्ट्रीय हस्तकला की जागरूकी देनवाला

एक प्रभावशाली माध्यम

संपर्क करें—व्यवस्थापक, संस्थाकुल

गांधी स्मारक निधि,

राजघाट, नई दिल्ली-२

बुनियादी तालीम

मोरादजी देसाई

[१०-११ अगस्त की नई दिल्ली में शिक्षा मंत्रियों का महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रधान मंत्री श्री मोरादजी भाई देसाई ने बुनियादी तालीम की अनिवार्यता पर ध्रुत जोर दिया था। उनके उद्घाटन भाषण के मुख्य अंश यहाँ प्रकाशित किए जा रहे हैं।]

यदि हमें अपनी सही हालत में आना है और देश को उन्नत बनाना है—जैसा कि हम उसे उन्नत बनाना चाहते हैं तो उचित शिक्षा को तथा हमारे सपनों और गांधीजी के स्वराज्य के सपनों को पूरा करने को मैं महत्त्व देता हूँ।

मेरी दृष्टि में कृषि और शिक्षा ये दो विषय अन्य सभी विषयों से अधिक महत्वपूर्ण हैं। कृषि पर हमारी आर्थिक उन्नति निर्भर है। उसी के बिना और आर्थिक उन्नति गढ़ी जानी है। शिक्षा पर हमारे मानव एवं भावी नागरिकों की निर्भरता निर्भर है। हमारे हर एक बाल पर हमारी युवापीढ़ी को दी जाने वाली शिक्षा के गुणों का असर पड़ता है।

हम शिक्षा-पद्धति की उन खामियों के शिकार हैं जो पाश्चिमात्य विचारधारा द्वारा भारत के धर्म-परिवर्तनार्थ हम पर आरोपित की गई थी और मेकॉले द्वारा अपने मूनाघार से पक्क-ग्रष्ट या च्युत कर दी गई थी। यह वही है जो अभी भी बटल है और यही वह दिशा है जिसे हमें बदलना है। मुझे खुशी है कि जाय सब इन दृष्टिकोणों पर विचार कर रहे हैं। किन्तु जब तक हम शिक्षा सबंधी अपनी वृत्ति एवं अंतर वस्तुमें मूलमूल परिवर्तन नहीं करते तब तक मुझे भय है कि पैबन्द लगाने से कोई लाभ नहीं होने वाला है और यही हो रहा है।

१०+२+३ की शिक्षा संरचना को लीजिए। मैं नहीं जानता कि यह क्या है। मुझे नहीं मानूम कि यह कैसे कोई लाभ पहुँचाएगी। इसने और अधिक बुरे के लिए परेशान कर दिया है। मैं नहीं समझता कि उसने कुछ अधिक भला किया है। शिक्षा में इस तरह का परिवर्तन कोई परिवर्तन नहीं है। मैं समझता हूँ कि अतः यह जनता को केवल दिग्भ्रमित करता है कि वह सोचने लगती है कि हम कुछ अधिक अच्छा कर रहे हैं।

शिक्षा का उद्देश्य यह देखना है कि उसने मानव को जिस बुद्धिमत्ता और क्षमता को दिया है वह उचित अनुपात में उसकी खुद की भी समझ में आती है या नहीं तथा आजीवन वह अपनी बुद्धिमत्ता और क्षमता को बढ़ाते हुए पूरी तरह से भलीभाँति उसका सदुपयोग करता है या नहीं। शिक्षा का यह सही उद्देश्य है और यदि उसकी उपलब्धि नहीं होती है तो शिक्षा अपनी उपयोगिता के उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाएगी। अतः उसे उत्कृष्ट सारभूत चरित्र उत्पन्न करना चाहिए। वह निर्भयता और सत्य प्रदान करे। क्या ये गुण हममें हैं? हम तो दूसरों के लिए चिन्तन, हिम्मत, साहसिकता, भय-रहित प्रोत्साहन के अभाव में एकमेक भ्रष्टाचार और स्वार्थपरता में पीड़ित हैं। यदि हममें उपर्युक्त गुण नहीं आते तो फिर हम क्या करने जा रहे हैं। जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ तो हैं ही और रहेंगी किन्तु हम उन्हें और अधिक न बढ़ाएँ। यदि हमारे जीवन में सुलझाने के लिए और सामना करने के लिए कठिनाइयाँ नहीं हैं तो मचमुच में जीवन में आनन्द नहीं रहेगा। इसलिए उन्हें हमें ललकारना चाहिए। ऐसा करने में शिक्षा हमारी मदद करे और यही उसने नहीं किया है। महात्मा गाँधी ने इस देश के लोगों को सिखाया और उसे नई दिशा देने के लिए जो कुछ किया वही कुछ हद तक किया गया है। दुर्भाग्य से शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित लोगों ने जैसा उसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए था वैसा नहीं बढ़ाया।

हमें भूत में नहीं जाना चाहिए, न उसकी चोर-फाड़ ही करनी है और न किसी व्यक्ति को दोष ही देना है। मैं सोचता हूँ कि हम सभी उसी तरह की शिक्षा की निष्पत्ति हैं अतः किसी को दोष न दें। यही कारण है कि हमें उससे हानि उठानी पड़ रही है। जो आज उस जगह पर

है उनमें से भी किसी की भूल नहीं है किन्तु अब यह हमारी भूल होगी। यह जानते हुए कि वमी कहाँ है और अब हमें क्या करना है, हम इन बाधाओं, बिम्बों को सही स्थिति पर आने की दृष्टि से यदि दूर न करें।

हमारे लिए यह भी कोई अच्छे भाव्य की बात नहीं है कि मुझे यहाँ अंग्रेजी में बोलना पड़ रहा है और मैं नहीं जानता कि कितनी अधिक अवधि तक मुझे यह करते रहना पड़ेगा। अंग्रेजी भाषा से मेरी कोई लड़ाई नहीं है किन्तु उसे हम भारतीय भाषा तो नहीं कह सकते। मेरा तात्पर्य यह है कि क्या भाषायी दृष्टि से भ्रष्ट इतना गरीब है कि उसकी अपनी भाषा नहीं रह सकती? यहाँ भी हमारी शिक्षा का ही दुस्मानुभव है और कुछ क्षेत्रों में भय और बाधाएँ उत्पन्न की जा रही हैं। मैं किसी के भय को बढ़ाना नहीं चाहता। मैं किसी की बाधाओं को, आपत्तियों को टालना या तरह नहीं देना चाहता। जनता पर जबरदस्ती कुछ लादा नहीं जा सकता। यह प्रजासत्त नहीं है। किसी पर कुछ जबरदस्ती लादने का तो सवाल ही नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को क्या भारत का हित नहीं सोचना चाहिए? वह कौन परेगा? मैं सोचता हूँ कि वैदिक शिक्षा अर्थात् शिक्षा के क्षेत्र में लगे हुए लोगों का ही यह कर्तव्य है किन्तु दूसरों को शिक्षित करने से पहले उन्हें अपने आप को शिक्षित करना है।

शिक्षा मंत्रियों का यही काम है जिसका आपको समझा बताया है। यदि आप मुझ से सहमत हैं तो मैं समझता हूँ कि शिक्षा को बदलने और अच्छी अंतर्वस्तु देने में तथा अपने अनुरूप बनाने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। मैं यह जानता हूँ कि पूरे घूम जाओ की पद्धति से शीघ्र ही कुछ कर सकना सम्भव नहीं है। यह न तो सक्षम तरीका ही है और न वांछनीय ही। लेकिन यदि हम तय करते हैं कि हमें क्या करना है कहाँ पहुँचना है तब हम जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँच सकते हैं और हमें जल्दी से जल्दी गन्तव्य स्थान पर पहुँचना है तो हमें उसमें अपरिहार्य बिलम्ब न करना चाहिए। और न हमें अपनी क्षमता और पावन शक्ति से अधिक थम ही करना चाहिए। ये वे मापदण्ड हैं जिनपर हमें अपने कार्यक्रम आधारित करने चाहिए। यदि आप इन श्रृंखलाओं पर सोचें

तो मुझे विश्वास है कि आप भी उन्हीं निर्णयों पर पहुँचेंगे जिन पर मैं पहुँचा हूँ।

अब शिक्षा के माध्यम की बात। बालकों की शिक्षा का माध्यम आदि से अन्त तक मातृभाषा क्यों न हो? इसमें कहीं झगड़ा है? इसके बारे में किसे झगड़ना चाहिए? इसके बारे में कोई नहीं झगड़ेगा। धर्म शिक्षा रास्त्री भी कहने लगते हैं कि मातृभाषा की अपेक्षा अंग्रेजी को अधिक महत्व दिया जाए, अपनी सर्वसाधारण भाषा को भी नहीं बल्कि अंग्रेजी को अधिक महत्व दिया जाए। क्या यह दुर्बलता या कमजोरी नहीं है, जिससे हमें क्षति उठानी पड़ रही है? यदि आप इस कमजोरी का अनुभव करते हैं तो क्या हमें उसे हटाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? भारत के लिए होनिकारक हुए बिना उसे अधिक से अधिक सम्भाव्य हितावह रीति से हटाइए। और इसे किया जा सकता है। मैं नहीं कहना कि प्रत्येक प्रदेश में प्राथमिक से पीएच. डी. तक मातृभाषा में शिक्षा क्यों नहीं दी जा सकती? रास्ते में क्या रुकावट है? यह कहना कि हमारी भाषाएँ विकसित एवं समुन्नत नहीं हैं, केवल हीन भावना है और अपनी ही चीजों के प्रति सम्मानहीनता है। जब अंग्रेज यहाँ ये तब देश के सारे हिस्सों में देशी रियासतें थी जिनमें शासन का कार्य जनता की भाँटा में चलता था। यदि वे उस कार्य के उपयुक्त नहीं थी तो उनमें कार्य कैसे होता था? यदि आप किसी भाषा का उपयोग न करते तो स्वभावतः पुस्तकें प्रकाशित नहीं होगी। पर यदि आप पुस्तकों के प्रकाशित होने तक ठहरेंगे और फिर कहें कि भाषा का प्रयोग हो सकता है तो आपको चिरतन काल तक रुकना पड़ेगा। यदि आप भाषा का उपयोग नहीं करते हैं तो वह समृद्धिशाली नहीं होती है। और हमें तो उसे समृद्धिशाली बनाना है। दुःख की बात तो यह है कि कृषि की शिक्षा भी अंग्रेजी में ही दी जाती है। कृषक उसे कैसे समझेंगे और वे उससे कैसे लाभान्वित होंगे तथा वे गाँवों में दूसरों तक कैसे सम्प्रेषित करेंगे? यही कारण है कि महाविद्यत्तर्यों में निकलकर आनेवाले अधिकांश लोग नौकरियाँ ही करना चाहते हैं और कृषि को समृद्ध नहीं करते जो कि उन्हें करना चाहिए। अतः मेरी दृष्टि में ये सब स्पष्ट बातें हैं जिनके

लिए अधिक तर्क की आवश्यकता नहीं है। मैं इन पर अधिक नहीं कहूँगा। यह आवश्यक भी नहीं है।

आप सब शिक्षा मंत्री होने के कारण इसमें उत्तनी ही रुचि रखते हैं। मैं नहीं मानता कि आप मुझसे अधिक रुचि रखते हैं। वरन् आपकी भी समान रुचि है। मैं आशा करता हूँ कि आप समान रूप से इसलिए रुचि रखते हैं कि एवमान शिक्षा मंत्री हो जाना शिक्षा में बहुत रुचि उत्पन्न नहीं करता। वह तो पहले से ही वर्तमान रहनी चाहिए। दुर्भाग्य से अब तक शिक्षा मंत्री के पद इसी प्रकार दिए जाते रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि अब ये ऐसे नहीं होंगे।

हमें यह देखना है कि प्राथमिक स्तर से ही उचित ध्यान दिया जाए क्योंकि यही सब आधार रखा जाता है और हम उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। 'बच्चे को मनुष्य का गिता' कहा जाता है। क्योंकि वह मनुष्य बनता है, वह पिता बनता है और यदि वह ठीक नहीं है तो भावी पीढ़ी ठीक नहीं होती। जो लोग मेरी ओर आपकी तरह बूढ़े हो गए हैं, या अंधेड़ उम्र के हैं या तरुण हैं उनकी कुछ उन्नति कठिन है। चीनी मिट्टी के कप के टूटने के बाद उसमें सुधार सम्भव नहीं है। विन्तु जब वह कच्ची मिट्टी होती है तब उसे चाहे जैसा आकार दिया जा सकता है। इसीलिए यदि हम स्वयं सावधान हैं तो ये बच्चे ही हैं जिनका इन आदर्शों के अनुसार संवर्धन सम्भव है। यदि मैं कहूँ तो कह सकता हूँ कि हमें उन्हें अपने उस साथे में नहीं ढालना है जो बहुत वांछनीय साँना नहीं है। और मैं यह प्रार्थना करूँगा कि यही हमें प्राथमिक, माध्यमिक एवं महाविद्यालयीन शिक्षा के किस्म-संवर्धन की दृष्टि से विचार करना है।

हम सभी दृष्टियों से बच्चों की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम उनके शारीरिक गठन के बारे में नहीं सोच रहे हैं। मैं एक बार कुछ आँकड़े पढ़कर सचमुच चिंतित हुआ था कि भारतीयों की ऊँचाई घट रही है। जब कि अन्य देशों में वह बढ़ती जा रही है, वे ऊँचे होते जा रहे हैं। ऊँचा या नीचा होना उतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं

है जितना कि ऊँच होना अथवा पिछड़ना। यदि आप गतिहीन या निश्चल रहने हैं तो आप पिछड़ते हैं या नीचे गिर पड़ते हैं। अतः प्रत्येक को प्रगति करनी है। किन्तु हम प्रगति नहीं कर रहे हैं वरन् हम तो पीछे जा रहे हैं। चर्चा के स्वास्थ्य की ओर जैसा कुछ ध्यान दिया जाना चाहिए वैसा नहीं दिया जा रहा है। हम दापहर व भोजन तथा अन्य अनिवार्य कार्यभार मोचते हैं। व अपने में अच्छे हैं किन्तु एक भान व अपने में विनमूल अच्छे नहीं। व तो चर्चा व स्वास्थ्य की ओर ध्यान देने के साधन मात्र हैं। मृग इमम मन्द नहीं हैं कि इन विना भी स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जा सकता है।

ईश्वर ने मनुष्य की आदर्शजनक सृष्टि की है। वह हर स्थिति में रह सकता है और हर प्रतिबल परिस्थिति व बावजूद भी अपने को महान बना सकता है। मानव को यह क्षमता दी गई है और शिक्षा में हमें उस प्राप्त करने की स्थिति उत्पन्न करनी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें प्रतिबल परिस्थितियाँ में रहना चाहिए। कुछ बाधाओं व कारणों तथा कठिन परिस्थितियों में हानि व कारण किसी को भी न ता चिल्लाया मचानी चाहिए, न एकदम निराशावादी हो बनना चाहिए और न हताश हो होना चाहिए। आप दुनिया व अनेक उदाहरणों से देखें कि प्रत्येक व्यक्ति यदि चाह और दृढ़ निश्चयी हो तो बाधाओं को पार कर सकता है। असल में बहुत से महान व्यक्ति सुखी परिस्थितियों की नहीं, बल्कि विपरीत परिस्थितियों की उपज हैं। यह जीवन का सत्य है। अतएव पान्थों को बचपन से ही यह गुण सिखाया जाना आवश्यक है।

परन्तु यह केवल तभी सम्भव है जब हमारे पास उपयुक्त शिक्षक हों। अतएव शिक्षक हमारी शिक्षा है। पाठ्यक्रम उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उपयुक्त शिक्षक। शिक्षक का व्यक्तिगत आचरण और व्यवहार ही बालकों पर अपना प्रभाव डालता है। इसी पर हमें ध्यान देना आवश्यक है। इस दिशा में शिक्षकों को प्रशिक्षित करने वाली संस्थाओं को अधिक प्रभावशाली बनाया जाना है। व व्यापारिक संघों में रूपांतरित होने के कारण ह्रासशील हो रही हैं। क्या यदि

अति नाछनीय है? विद्यार्थी प्रभावित होते हैं और फिर इसी कारण छात्रों और शिक्षकों के बीच जशान्ति दिखाई देती है। यह क्यों होना चाहिए? शिक्षकों, विद्यार्थियों और समाज के बीच क्या संघर्ष है? कोई संघर्ष नहीं हो सकता। दोनों के बीच मेल्याण की अनुरूपता है। फिर भी वे संघर्ष उत्पन्न करते हैं। इसमें केवल अधिक समझ की आवश्यकता है। इस विद्या में भी हमें सोचना और काम करना है।

इसलिए मेरे मन में कोई सन्देह नहीं है कि बुनियादी शिक्षा को अपने सही रूप में और उपयुक्त शिक्षकों के सहित आना चाहिए। यह तभी हो सकता है जब कि शिक्षा मशीन प्रभावित हो जाएँ और ऐसा करने का दृढ़ निश्चय करे। फिर इसे कोई नहीं रोक् सकता। और इस पर आप सब को विचार करना है, आपस में चर्चा करनी है, एक निश्चय पर पहुँचना है। मैं आपको कुछ भी करने पर बाध्य नहीं कर सकता। मैं ऐसा करने का प्रयत्न भी नहीं करूँगा। मैं तो केवल आप लोगों को सब तक मनवाता, समझाता रह सकता हूँ जब तक कि मुझे सरलता नहीं मिल जाती। मैं केवल इतना ही कर सकता हूँ। शिक्षा डंडे का ज्ञान नहीं है। यह तो और कुछ से मनवाने की प्रक्रिया और आत्मोद्धारण की ही प्रक्रिया अविवक्षित है। और इसमें इसी तरह व्यवहार किया जाना चाहिए।

यदि आप बुनियादी शिक्षा से प्रारम्भ करते हैं और प्रत्येक विद्यार्थी को हर स्तर पर उत्पादक काम देते हैं तो आप उसे एकदम भिन्न व्यक्ति बना देंगे। वह आत्मविश्वासी अधिक होगा और अपना इन्तजाम कैसे करे, इसमें वह जानेगा। प्रथम श्रेणी के एम एस सी, एम ए कुछ इंजीनियर डाक्टर मेरे पास आकर अपनी बेकारी की बात मुझसे कहें यह विचारा करणार्थक दृश्य है? कोई डाक्टर क्यों ऐसा अनुभव करे? कला का व्यक्ति कुछ हद तक अपने को असहाय अनुभव करे यह मैं समझ सकता हूँ, किन्तु यदि उसने उचित शिक्षा प्राप्त की है तो उसे भी ऐसा अनुभव करने का कोई कारण नहीं है। किन्तु ये भी अपने को असहाय अनुभव करते हैं। इसका क्या मतलब है? यह हमारी शिक्षा की कमी को ही बताता है। इसी को हमें ठीक करना है। किन्तु यह तभी हो

पाएगा जब कि हम उह चारित्रिक दृष्टिकोण देंगे जिसकी कि आज नितान्त कमी है। और चारित्रिक दृष्टिकोण अपने से अधिक दूसरो के बारे में सोचने से ही आता है। यह चारित्रिकता ही है जिसकी ओर मैं लौटना चाहता हूँ। यही चारित्रिकता इस देश की अपनी विपत्ति है। यह हमारी सस्रुति का मूल-तत्व है। यह मूल-धार है जिस हमने दृष्टि स ओझल कर दिया है। मैं उम्मीद दृष्टि स शिक्षाको जाँचना चाहूँगा और यही उसमें कमी पाई जाती है। हमें इस कमी की पूर्ति करनी होगी। यह आप ही सोचें कि इसे सर्वोत्तम रीति से आप किस प्रकार कर सकते हैं। उसका करन के नवन तरीके हो सकते हैं। किंतु वे सब सक्षम तरीके हो और वे हो सकते हैं यत हमें जानना चाहिए। इस सम्बन्ध में गाँधीजी ने हमें बहुत-सी कल्पनाएँ दी हैं। वे कल्पनाएँ ही नहीं हैं किंतु उन्होंने उदाहरण सहित समझाया है कि हम क्या करना हैं। वे एस व्यक्ति थे जो दूसरो को तब तक कोई सलाह नहीं देत थे जब तक कि वे स्वयं उसका सफल प्रयोग नहीं कर देत थे। वे वह कुछ कमी किसी स नहीं कहत थे जो वे स्वयं नहीं करत थे। सचमुच यही वह चारित्रिक दृष्टिकोण है और इसे को हम युवारीढी के मस्तिष्क में बैठाना है। इसीलिए इसका कोई उपयोग नहीं है कि मैं आपको यह विस्तार स कहूँ कि आप यह करिए वह करिए। ये वे कसौटी हैं जिन पर हमारा हर कार्यक्रम कस जाएँ और जाँच जाएँ।

हमारी विचित्र मनोवृत्ति तो देखिए। यदि हम अँग्रेजी बोलन में गलतियाँ करत हैं तो बहुत सज्जित होत हैं किंतु अपनी-अपनी मातृ भाषा में की जान वाली गलतियों की हन बिना तक नहीं करत। आप भी उनकी चिन्ता नहीं करत। यह किस प्रकार की शिक्षा है ?

आखिरकार सभी शिक्षा मन्त्रियों ने यह स्वीकार किया है कि शास्त्र अथवा छात्र अपनी मानभाषा में शिक्षा ग्रहण कर सकता है। इसमें कोई मतभेद नहीं है। फिर भी हम उडबडान हैं क्योंकि हममें दृढ़ विश्वास नहीं है। और जिनमें विश्वास है उनमें अंग बढ़न की दृढ़ता नहीं है। यही कठिनाई आती है। इस समयजस में हमें और अधिक नहीं रहता है। उसकी कीमत चवान के लिए २० वर काफी लम्बी

अवधि है। अब बिना किसी की दोष दिए हम नए सिरे से ठीक से क्रमिक गति बनाएँ जिससे हम वास्तविक शिक्षा की प्रस्थापना कर सकें जो इस देश का भूतकालिक महान वैशिष्ट्य था। देश में पहले ऐसी ही शिक्षा थी। औप्रेजो के जमाने में यह छो गई और गलत चीज हम पर लाद दी गई। अब हमें यह देखना है कि वह बदल जाती है और उसके स्थान पर उपयुक्त व्यवस्था आती है। उसमें जितनी अच्छी चीजें हैं उन्हें हम अवश्य लेगे उन्हें हम छोड़ेंगे नहीं। जहाँ से जो भी कुछ अच्छा है सबका हम इसमें समावेश करेंगे। किन्तु यह समावेश तभी हो सकेगा जब कि आधार हमारा अपना हो। यदि आप अपने पैरों पर खड़े होंगे तभी कुछ इधर से उधर ले जा सकेंगे। किन्तु यदि आप अपने पैरों को ही छो देते हैं तो फिर आप क्या ले जाएंगे? आप क्या पा सकते हैं? आप कैसे शक्ति प्राप्त करेंगे? अतः हम उस स्थिति और समय को लाना है और वह आसन्न है क्योंकि इस देश ने सारे ससार के सामने अपनी यह कार्यशक्ति प्रदर्शित की है जिसको लोग आज प्रशंसा करते हैं। किन्तु हम उस प्रशंसा से प्रसन्न न हो और न यह मानने लगें कि हम एकदम ठीक हैं। अब तो हमें केवल यह बहने का बल देंगी कि हम सही दिशा में हैं और हम जागे बढ़ने जाना है। इसी के बारे में सोचने और आगे बढ़ने के अवध में मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा।

मैं एक बात और कहना चाहूँगा। शिक्षा को मही शिक्षा व्यवस्था के लिए सरकारी नियंत्रण के स्फोटक परिणामों से प्रस्त नहीं होना चाहिए। क्योंकि सदुद्देश्य प्राप्त होने पर भी उदात्त प्रभाव स्फोटक है। वह और कुछ नहीं कर सकती। सरकार को शिक्षा का समर्थन करना और उसे आर्थिक सहायता देनी चाहिए। इसका यह मतलब नहीं है कि वह उस पर पूरा नियंत्रण रखे। ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकारी नहीं बल्कि गैर सरकारी स्तर पर शिक्षा के साथ समुचित व्यवहार होता चाहिए। नियंत्रण का यही प्रयोग हो जहाँ कुछ भूलें होती हैं। जहाँ सरकार जो चाहती है वह नहीं होता है उसे गटवारिए, खींचिए। यदि कहीं हिस्सारी गडबडी है या पैसे का गबन है और गैरनिस्त है तो अवश्य ही उसके बारे में कहिए। किन्तु यह सब होने पर

भी गैरशिस्त कभी-कभी स्वाभाविक है। इस सबमें अब परिवर्तन होना आवश्यक है। अतः मैं यह चाहता हूँ कि शिक्षा और सहकार्य दोनों साथ साथ रहें। इनमें सरकार का उस तरह का गलाघोटू नियंत्रण न हो। यह आपको देखना है कि इसका अनुभव किया जाता है। मेरी दृष्टि में शिक्षा के क्षेत्र में विकेन्द्रीकरण सच्चे अर्थों में होना अनिवार्य है।

मैं सोचता हूँ कि जिन भूलभूत बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता था उनके बारे में मैंने आपको कह दिया है। अब बातें उनके अनुरूप ही होंगी। व आपक लिए है क्योंकि आप उनका व्यवहार करेंगे। जहाँ जो आवश्यक हो वह विस्तार आप करेंगे। मैं तो इन प्रक्रिया में सहायता मान कर सकता हूँ इससे अधिक मैं कुछ नहीं कर सकूँगा। प्रत्यक्ष दिना मैं आपको हर सम्भव मदद करने के लिए तैयार हूँ किन्तु मैं उस आप पर सविनया नहीं चाहता। उससे कोई लाभ नहीं। किन्तु यदि उसकी कोई भाग होगी तो यह आपके नियंत्रण में है। वस यही मैं आपसे कह सकता हूँ। आप से दो शब्द फेरकर मुझ खुशी है और मैं प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। मुझे यह आशा है कि आप उपयोगी निपाय करण और दृढ़ता के साथ उन्हें यथा सम्भव गीघ्रातिरीघ्र उचित रूप में अमल में लाएँगे।



कार्य-शाला

जाकिर हुसैन

[दूसरे युगिवादी शिक्षा सम्मेलन, जामिया मिलिया, दिल्ली १९४१ के अवसरपर दिए गए उद्घाटन भाषणसे]

काम की शिक्षा का आवश्यक अंग बनाए जाने के सम्बन्ध में आज ही कुछ कहा जाता हो ऐसा नहीं है। लोग इसके सम्बन्ध में बहुत पहले से कहते आ रहे हैं। कहने वालों में से प्रत्येक ने इसे अपने ढंग से कहा है। किसी के लिए 'काम' सिद्धान्त है तथा उसे पाठ्यक्रम में एक विषय के रूप में स्वीकृत किए बिना इसी रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। अन्यो के लिए यह 'विषय' है तथा इसके लिए तासिका निर्धारित की जानी चाहिए और पणालिका तथा पाठ्यक्रम में आगे कोई परिवर्तन किए जाने आवश्यक नहीं है। तीसरे के लिए काम ऐसा होना चाहिए जिसका गुणवत्ता मिले और कुछ ऐसा कहते हैं कि सम्पूर्ण क्रियाशीलता 'आशीर्वाद' है। अतः कोई हर्ज नहीं यदि क्रियाशीलता कुछ उत्पादन नहीं करती क्योंकि अच्छे कुछ मजदूर तो हैं नहीं। उनकी क्रियाशीलता ही उत्पादक है। जिनके ये विचार हैं उनमें मेरा कोई झगड़ा नहीं है। मैं केवल अपनी बात कहना चाहता हूँ और मेरी राय यह है कि जब हम शिक्षा के सम्बन्ध में काम के बारे में कहते हैं तब हमें उसी काम को लेना है जो शरीर और मस्तिष्क के लिए सवर्गुण शिक्षाप्रद है। काम ऐसा हो जो मनुष्य को और अच्छा मनुष्य बनाए। मेरा विश्वास है कि अपने किए हुए काम के गुण-दोषों की परीक्षा करने पर मनुष्य उत्पन्न करता है। जब मनुष्य कोई शारीरिक या मानसिक काम हाथ में लेता है तब वह उसे अपने लिए सभी शिक्षाप्रद बना सकता है जब कि वह उससे प्रभावित हुआ हो और अपनाए गए काम के प्रति उसने पूरा ध्यान

किया हो तथा अपने काम के लिए आवश्यक शिस्त को अपने आप पर
 आरोपित करने के लिए वह राजी हो। प्रत्येक काम नहीं किन्तु सम्योजित
 काम ही शिक्षाप्रद हो सकता है। यत्र द्वारा किया जा सके वाला
 या यत्रवत् किया गया काम शिक्षाप्रद नहीं हो सकता। किए जाने वाले
 काम की योजना हमारे मस्तिष्क में होनी चाहिए। उद्देश्य की पूर्ति
 हेतु उचित उपाय योजना की मानसिक प्रक्रिया दूसरी सीढ़ी है। फिर
 सामग्री एवं चुने हुए यंत्रोंसे काम के क्रियान्वयन का क्रम आता है।
 तदनन्तर अन्तिम अवस्था में इस बात की जाँच होती है कि तैयार
 सामग्री मूल योजना के अनुसार है या नहीं। वह उन उचित माध्यमों
 द्वारा निमित्त है या नहीं जो योजना बनाते समय सोचे गए थे तथा, उसमें
 लगने वाली सामग्री और मजदूरी न्यायसंगत है या नहीं। ये कामकी
 प्रक्रिया की चार निर्धारित स्थितियाँ हैं जो उस शिक्षा प्रद बनाती हैं।
 किन्तु यही सब कुछ नहीं है। कोई भी काम सतत रूप से दोहराए जाने
 पर एक सीमा तक निपुणता उत्पन्न करता है। किन्तु शारीरिक, मानसिक
 या भाषा विषयक निपुण्य शिक्षात्मक गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है।
 शिक्षित मनुष्य सम्बन्धी हमारे मन में सामान्य विचार निपुण व्यक्ति के
 नहीं है। निपुणता तो चोरा द्वारा भी प्राप्त की जाती है। धोखेबाजी
 से पनपने वाले भी और सच को झूठ दिखा सके वाले भी इसे प्राप्त
 करते हैं। ऐसी निपुणता शिक्षा का सम्पन्न नहीं हो सकता। हम अपने
 विषय की ओर अधिक व्याख्या यह कहकर करनी होगी कि काम सचमुच
 शिक्षाप्रद तभी हो सकता है कि जब वह एकमात्र व्यक्तिगत उद्देश्यों से
 परे मूल्य की दृष्टि से अधिक सार्थक हो। मूल्य हमसे भी पर है जिम्मे
 हम स्वीकार या अमीकर करते या मानते तथा सम्मान करते हैं।
 वह जो अपने लिए काम करता है निस्सन्देह निपुण हो जाता है किन्तु
 हम उसे सही रूप में या सचमुच शिक्षित नहीं मानते। केवल वह जो
 उच्च मूल्यों का अमीकार करता है, सही रूप में अपने आप को शिक्षित
 बनाता है। इन उच्च उद्देश्यों के अमीकार करने की इच्छा में वह केवल
 अपना मनोरंजन या सतोष ही नहीं खोजता बल्कि अपनी सम्पूर्ण समता
 एवं शक्ति को वर्तव्य रूप में अपने काम की पूर्ति में लगाता है। यह उसके
 व्यक्तित्व की उन्नति में सहायक होता है एवं उसकी चारित्रिक प्रवृत्ति
 को ऊँचा उठाता है।

सन्तोष और आनन्द की सारी व्यक्तिगत इच्छा को मनुष्य उन मार मूल्या की सेवा हेतु रूपांतरित करनेका निश्चय करता है जिन्हें वह सेवा करने योग्य समझता है। उसे अपनी सेवाओं को उस उद्देश्य के अनुरूप बनाने में प्रयत्नशील होना चाहिए जिसके लिए वह समर्पित है। इसके अतिरिक्त पारिवारिक शिक्षा और क्या है? शिल्प एवं श्रद्धा मानसिक कार्य दोनों इस प्रकार संचमुच शिक्षाप्रद बनाए जा सकते हैं तथा दोनों समान रूप से प्रेरणाहीन अथवा व्यर्थ भी हो सकते हैं। सही कर्मशाला वह है जहाँ काम शुरू करने से पहले अच्छे योजना की आदत अपनाते हैं, उपाया और प्रसाधना के बारे में सोचते हैं और उद्देश्य की शिक्षा में किए गए कार्य की उपलब्धियों के सम्बन्ध में आलोचनात्मक अध्ययन करते हैं। इस प्रकार वे धीरे धीरे यह अनुभव करेंगे कि जो कुछ वे करना चाहते हैं उसके लिए यदि आवश्यक पूरी शक्ति और कुशलता नहीं लगती है, फिर से और ध्यान पूर्वक नहीं करते हैं तो अपने कार्य के प्रति गैर ईमानदार और, गैर बफादार होंगे। जो काम की शिक्षाप्रद बनाना चाहते हैं उन्हें सतत ध्यान में रखना चाहिए कि बिना निश्चित उद्देश्यके कोई काम नहीं होता। उसके अपने आदर्श और नियम होते हैं जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। केवल समय बिताने की दृष्टि से कुछ भी अपरिणामकारक कार्य करते रहना ग्राह्य एवं सतोपजनक नहीं होता। चीजों से खिलवाड़ करते रहकर मनोरंजन मात्र करते रहने की भी गुंजाइश नहीं है। किसी दृष्टि से गतिविधि प्राप्त प्रवृत्ति को 'काम' कहते हैं। इसमें आत्मालोचन टाला नहीं जा सकता एवं जो इसकी आवश्यकताओं की मांगों की पूर्ति करते हैं उन्हें एक अमूल्य आनन्द का अनुभव होता है जिससे अग्रणी और कुछ नहीं हो सकता। काम कठोर आत्मानुशासन है, काम प्रार्थना है।

किन्तु दिव्य कठोर तपस्या एवं प्रार्थना में भी आनन्द स्वार्थपरक हो सकते हैं। स्वयं में अपनी जगह की सुरक्षितता का भरोसा करके दूसरों को उनके भ्रातृत्व के भरोसे छोड़ देते हैं। संचमुच अपने आदर्शों के अनुरूप होने वाली कार्यशाला व्यक्ति को व्यक्तिपरक एवं स्वार्थी कभी नहीं होने देगी। वह तो सर्वसाधारण उद्देश्य के लिए अपने को एक समाज

के रूप में स्थापित कर देगी। इस समाज में पूर्ण सत्योग वर्तमान रहेगा एवं प्रत्येक को सौंपी गई जिम्मेवारी की पूर्ति द्वारा सर्वसाधारण उद्देश्य की उपलब्धि होगी। प्रत्येक का श्रम सर्वसाधारण ढाँचे से इस प्रकार निर्गडित होगा कि एक की भूल सबके कार्यों को नष्ट कर देगी तथा तेज गति वाला धीमी गति वालेको पीछे न रहने दगा। इस प्रकार यह शाला अपने कार्य के द्वारा अत्यन्त निवृत्त का सम्बन्ध प्रस्थापित करेगी और स्वभावकी विभिन्नता के बावजूद सहकार्य की क्षमता तथा जिम्मेवारी की भावना आदि गुणों का संवर्धन करेगी जिनकी दृष्टि को आज सचमुच आवश्यकता है। व्यक्तिगत आवश्यकताओंकी पूर्ति की अपेक्षा सामाजिक कर्तव्या का निर्वाह अधिक महत्वपूर्ण है।

सच्ची कार्य शाला संगठित कार्य कलापा से अपने छात्रों को प्रशिक्षित करने मात्र से संतुष्ट नहीं होगी बल्कि इस संगठित कार्य-कलाप से एक ऐसी सहकारी समिति का गठन करेगी जिसमें प्रत्येक, केवल अपनी जिम्मेवारियों से ही अवगत नहीं है बल्कि अपना काम भी पूरा करता है।

मैं समझता हूँ कि सच्ची कार्यशाला अपनी छोटी सी सहकारी समितिको उच्चतर उद्देश्यका साधन बनाएगी बशर्ते कि उसके छात्र व्यक्तिगत लाभपर विजय पाकर सामूहिक दलदल तथा लोभलिप्सा के गड्ढे में न गिर पड़ें।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि कार्यशाला अपने छात्रों द्वारा स्वीकृत जिम्मेवारी को कार्य द्वारा पूरा करना सिखाएंगी—सहकारिता का आधार पर अपने सभी कार्योंका आयोजन करेगी और इस विश्वास को पैदा करेगी कि शाला एक समाज है और उसका सारा काम समाज की सेवा है। अन्तमें यह इस आकांक्षा को विकसित करेगी कि समाज आदर्श की उस स्थिति तक पहुँच जाए कि जिसकी मानव मस्तिष्क कल्पना कर सकता है। इस प्रकार वह इस विश्वास की आधारशिला रखेगी कि निर्धारित काम का करना समाज के प्रत्येक व्यक्ति का काम है एवं उसका नैतिक कर्तव्य है कि व्यक्ति का काम और उसका जीवन हर तरह से अच्छा समाज बनाने में सहायक हो।



तरुणाभिनन्दन : एक राष्ट्रीय संस्कार

सादिक अली

[पिता मयाय ने १३ अगस्त को 'तरुण नागरिक दिवस' के रूप में मनाने का आग्रह कई वर्ष पहले किया था। उसने आठार दिन गांधी जी वहाँ पर एक महत्वपूर्ण आयोजन किया गया था जिसका उद्घाटन महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री शास्त्रि भली साहब ने किया था। उनका उद्घाटन भाषण का मुख्य अंग यहाँ दिया जा रहा है।]

वहाँ मेरे लिए कोई नई जगह नहीं है। यहाँ मैं अवसर आया हूँ लेकिन आजादी हासिल करने के पहले। जब आजादी के जग में हम लगे हुए थे तब अफसर वहाँ आने का मौका प्राप्त हुआ था। उस वक्त भी वहाँ सावजनिक महत्व की जगह थी और आज भी वैसे ही महत्व में जगह है। गुप्त रयार थे कि वहाँ न तो मुझे वहाँ जाना ही होगा। लेकिन अगला हुआ कि वह मौका मुझे जल्दी ही मिल गया। मेरे पास अचाय श्री श्रीमन्नेजी और बहुत सदासजाजी ने यहाँ आने का निमन्त्रण भजा किसे मैंने खुशी से पसन्द किया। इस सभारोह का सबध नौजवानों से है और वे नौजवान जो आजाद हिन्दुस्तान में पैदा हुए। यह उन की खुशकिस्मती है। हमारी पीढी के लोग तो एक गुलाम हिन्दुस्तान में पैदा हुए थे। लेकिन हमारी भी खुशकिस्मती थी कि हमने आजादी के जग में हिस्सा लिया और पुरानी पीढी के बड़े बड़े इंसानों से मिलन का मौका मिला। हमारे पिछले ७०-८० बरस का इतिहास बड़ा दानदार इतिहास है। उसमें बड़े बड़े इंसान पैदा हुए और बड़े बड़े विचार उठे। उस जमाने में जो बड़े बड़े इंसान पैदा हुए उनका नाम लन की मुम जरूरत नहीं है। उनमें सबसे बड़े गांधीजी थे जो यहाँ बर्नो तक रहे। गांधीजी में बहुत सी खूबियाँ थी बहुत सी विशेषताएँ थी। लेकिन एक विशेषता यह भी थी कि वे हिन्दुस्तान को आजाद करने में लगे हुए थे। आजाद कराने के साथ-साथ उनकी यह भी चिन्ता

थी कि जब मुल्क आजाद हो जाएगा तब आजाद मुल्क कैसा होना चाहिए। गांधीजी का मकसद सिर्फ अंग्रेजों को हिन्दुस्तान से निकाल देने भर से पूरा नहीं होता था। वे जानते थे कि अंग्रेज को यहाँ से चला जाना पड़ेगा, लेकिन उनके जाने के बाद हिन्दुस्तान का मकसा क्या होगा, किस किस प्रकार हिन्दुस्तान हम यहाँ बनाएँगे? गांधीजी के विचारों के मुताबिक हिन्दुस्तान में हर कोम का इन्सान बसेगा। सब धर्मों को हिन्दुस्तान में बराबर का स्थान मिलेगा। हमारे देश का एक विधान है, कस्टीड यूनिन है। गांधीजी ने हिन्दुस्तान का विधान बनाने के काम में कोई खास हिस्सा नहीं लिया। लेकिन हमारी जो कांग्रेस है उसने यह विधान बनाने में खासा हिस्सा लिया। जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता थे, गांधीजी को छोड़कर; उन सब लोगों ने हिन्दुस्तान के विधान को बनाने में अपना पूरा सहयोग दिया जितना भी हम छम था वह हमें लगाया। हमारा सविधान बनना और लोग कहते हैं कि बड़ा कानदार सविधान है और हमने ज़्यादा अच्छा सविधान बनाना जरा मुश्किल है हमें अपने सविधान से प्रेरणा लेनी चाहिए।

आ। हम क्या करना चाहते हैं? हमारे पास एक ही काम है— हिन्दुस्तान को बनाना। हिन्दुस्तान को बनाना कोई मामूली काम नहीं है। हिन्दुस्तान मामूली मुल्क नहीं है। एक विशाल—बहुत बड़ी आबादी वाला, मुल्क है। इसकी आबादी ३० करोड़ से शुरू होकर आज ६० करोड़ तक पहुँच गई है। ६० करोड़ लोगों की समस्याओं को हल करना जरा मुश्किल काम है। एक कुशल हिन्दुस्तान बनाना तान्त्रिकों के हिन्दुस्तान बनाना, सवित्तशाली हिन्दुस्तान बनाना यह गम्भीर उद्देश्य अपने सामने रखकर हमें हिन्दुस्तान को बनाना है तो ऐसा हिन्दुस्तान बनाने के लिए साफ रास्ता भी होना चाहिए। गांधीजी ने दिखाया है वह रास्ता जिस पर हमने आगे चलना है। आज जो नागरिक हैं पैदा होते हैं और अभी भी हमारे सामने बैठे हुए हैं जिन्होंने २१ बप पूरे कर लिए हैं और जिन्हें अभी मताधिकार प्राप्त हो रहा है। वे हिन्दुस्तान के नागरिक हैं। उनको वोट देना अधिकार मिल रहा है। वे अच्छे नागरिक बनना चाहते

हैं। लेकिन अगर अच्छा नागरिक बनना है तो साफ रास्ता होना चाहिए। गांधीजी ने इस मुल्क को एक रचनात्मक कार्यक्रम दिया। सन १९२०-२१ में गांधीजी ने कहा कि हिन्दुस्तान को आजाद करना है तो इस मुल्क को सुन्दर तरीके से आजाद कराना चाहिए। हिन्दू-मुस्लिम, दोनों कौमों की एकता लाजिमी है, आवश्यक है। हमारे देश में जो गरीबी, बेकारी है वह दूर होनी चाहिए। इस तरह का रचनात्मक कार्यक्रम गांधीजी ने हमको दिया। आगे चलकर उन्होंने इन बातों पर अमल करनेको कहा। इस मुल्क के अन्दर बाईस कमजोरियाँ हैं, बाईस बीमारियाँ हैं। अगर हमें अपने मुल्कको स्वतंत्र करना है, ताकतवर बनाना है तो हमको इन बीमारियों को दूर करना चाहिए। चाहे वह गरीबी की समस्या हो, चाहे बेकारी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या। हमारे आपस के जो झगड़े हैं वे सब खत्म होने चाहिए। हिन्दुस्तान को बनाने का पूरा तक्का सब सामने आएगा, इसमें पहले नहीं। वह नकशा जो गांधीजीने बताया जिसमें ऊपर बताई गई सभी छात्रियों, बीमारियों को दूर करना है। जब तक हम उनके बताए रास्ते पर नहीं चलेंगे सब तक एक कुशल हिन्दुस्तान, ताकतवर हिन्दुस्तान, आजाद हिन्दुस्तान नहीं बना सकेंगे।

हमारे संविधान में हर आदमी को स्वतंत्र होना चाहिए। आर्थिक सामाजिक न्याय होना चाहिए। प्रेस स्वतन्त्र होना चाहिए। हर आदमी को काम मिलना चाहिए। हिन्दुस्तान के अन्दर यह सब चीजें होनी चाहिए। जैसा मैंने आपसे कहा, दो रास्ते हैं—एक सरकार का रास्ता और दूसरा गांधीजी का रास्ता। दोनों एक रास्ते नहीं हैं, कुछ भिन्न हैं, लेकिन बहुत-सी बातों में समानता है। हम देखते हैं सरकार की तरफ; सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ। देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट की तरफ। देखते हैं भारत सरकार की तरफ, पार्लियामेंट की तरफ। न्यायी हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जिला मजिस्ट्रेट, एम्.पी., एम्.एल.ए. — इस सब का योगदान है एक कुशल सरकार बनाने में और चलाने में। अगर आप समझे कि सारा बोझ इनके ऊपर छोड़ दे एक ताकतवर हिन्दुस्तान, शक्तिशाली हिन्दुस्तान

बनाने के लिए तो यह जरा मुश्किल काम होगा। पार्टी पॉलिटिक्स की जरूरत है हिंदुस्तान में। क्याकि डेमोक्रेसी में किसी राजा-महाराजा का राज नहीं होता बल्कि जनता द्वारा बनाई गई पार्टियों—और उनमें से बहुमत वाली पार्टी का राज्य होता है। लोगों को यह हक है कि वे अच्छी से अच्छी पार्टी को वोट दें। जिस पार्टी को ज्यादा मत प्राप्त हो वह सरकार बना सकती है—यह राजनीति है। गांधीजी ने इसको स्वीकार किया कि प्रजातन्त्र प्रशासन में पार्टी पॉलिटिक्स की जगह है। लेकिन क्या हर चीज में पार्टी-पॉलिटिक्स घस जाए? बहुत से क्षेत्र हैं जिनमें पॉलिटिक्स से कोई सम्बन्ध नहीं है। वह बड़ा विशाल क्षेत्र है। वह बड़ा उम्रवा चौड़ा क्षेत्र है। पार्टी क्षेत्र के अंदर कुछ लोग हिस्सा लेंगे जब कि वोट देने का अधिकार—आजाद मूल्य बनाने का अधिकार हर एक व्यक्ति को है। इसमें हर आदमी हिस्सा ले सकता है। हर आदमी हक्दार है चाहे वह किसान हो मजदूर हो डाक्टर हो इंजीनियर हो छात्र विद्यार्थी हो टीचर हो—वे सब हमारा नागरिक हैं। आज जो एम पी चुनकर आते हैं उनकी जिम्मेदारियाँ हैं। किसान मूल्य के लिए फसल उगाता है और डाक्टर लोगों की बीमारी दूर करता है और अपनी कमाई भी करता है। उसको अपनी कमाई भी करनी है घर का इतना काम भी करना है मूल्य की भी कुछ खिदमत करनी है। लेकिन सिर्फ हम अपनी भलाई के लिए जीने का काम करेंगे तो यह मूल्य के प्रति कफादारी नहीं होगी। हर आदमी को ८० फीसदी अपने तथा अपने परिवार के प्रति कर्तव्य निभाना चाहिए और २० फीसदी देश के प्रति। अगर हम इस तरीके से काम करेंगे तो कोई शक नहीं कि बहुत जल्द ही एक कुशल हिंदुस्तान गैर-विभाजित हिंदुस्तान बनाने में कामयाब हो जाएंगे।

कुछ लोग कहते हैं कि अहिंसा में ताकत नहीं होती। गांधीजी का कहना था कि अहिंसा में जितनी ताकत होती है उतनी ताकत किसी में भी नहीं होती। इसका उदाहरण आप लोगों के सामने है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर मानी हुई फौज को हमारा यहाँ से हटना पड़ा, नत्ता जाना पड़ा। अपने मूल्य को आजाद करने के लिए हमें अपने यहाँ

से गरीबी, शिक्षा में सुधार तथा गाँवों और शहरों की दूरी को कम करना पड़ेगा औद्योगीकरण करना पड़ेगा। कुछ लोगों का कहना है कि गाँधीजी औद्योगीकरण नहीं चाहते थे। उनका यह कहना बिल्कुल गलत है। गाँधीजी औद्योगीकरण चाहते थे देन को आगे ले जाना चाहते थे लेकिन वे शहरों या औद्योगीकरण नहीं चाहते थे। वे चाहते थे कि हर गाँव आगे बढ़े।

अभी मैंने आपसे पार्टी पॉलिटिक्स की बात कही थी। हमारे सिस्टम में पॉलिटिक्स का अपना क्षेत्र है अपनी जगह है और बहुत अच्छी जगह है, महत्वपूर्ण है। लेकिन बहुत से ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ पॉलिटिक्स को आने की जरूरत नहीं है। एक पार्टी के अन्दर हर आदमी हिस्सा ले सकता है। लेकिन जिस मकसद के लिए हम आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं वह एक अच्छी चीज है नौजवानों के लिए। गुजरात में इसकी शुरुआत हुई और सम्माननीय मदालसाजी चाहती है कि यह चारों तरफ फैले। हमारे देश में आज भी बहुत से नौजवान हैं जो बेकार हैं परेशान हैं। हर नौजवान इज्जत के साथ अपना सिर ऊँचा करके जिन्दगी जी सके। हिन्दुस्तान की आजादी की रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए। यह बहुत आवश्यक है।

1. गाँधीजी का ख्याल था—गरीबी की समस्या को आसानी से हल नहीं किया जा सकता। इनके बड़े मुल्क के अन्दर क्या हम सब लोगों को काम दे सकते हैं? हर आदमी को काम मिले—आजादी भी रहे, डेमोक्रेसी अच्छी तरह से चले। हमारे जो अधिकार हैं सुरक्षित रहें। हमारे जो कर्तव्य हैं उनका भी हम पालन करें। हमारे अधिकार और कर्तव्य दोनों बराबरी से हर नागरिक द्वारा अमल में लाए जाएँ। यह हिन्दुस्तान का एक मन्त्र है। गाँधीजी से हम प्रेरणा ले सकते हैं और सगतिार लेते रहें। दुनिया उनसे प्रेरणा ले रही है। गाँधीजी का आखिरी मकसद दुनिया को बदलना था। गाँधीजी दुनिया को बदलना चाहते थे। दुनिया के समाज को बदलना चाहते थे। लेकिन हिन्दुस्तान का और उद्देश्य नामयाव हो गया तो वह मजबूत, ताकतवर बनेगा और

तभी यह दुनिया के ऊपर अपनी छाप डाल सकता है। अगर हम सही रास्ते पर चले, सही मायने में हमारी ताकत बनी तो एक न एक दिन हम दुनिया के ऊपर अच्छा असर डालेंगे। आज हर एक देश शांति की बात करता है। दुनिया की दो बड़ी फौजी ताकतें भी दुनिया में शांति स्थापित करना चाहती हैं। लेकिन जो रास्ता गाँधीजी ने बताया है जिस पर हम चलने की कोशिश करें तो मैं समझता हूँ कि दुनिया भर में अच्छा असर डाल सकेंगे।

मुझे बहुत खुशी है कि बहून मदालसा ने यह नई सस्था बनाई है। १५ बरस से अपने यहाँ चलाकर मजबूत करने के लिए उसे धीरे धीरे फैलाया, जिसका नौजवानों से ताल्लुक है। मेरी शुभकामनाएँ उसके साथ हैं। मेरी आशा है कि यह सस्था पनपती जाएगी और ज्यादासे ज्यादा लोगों का भला करेगी और मुल्क की भी भलाई करेगी। मैं श्रीमती मदालसाजी का शुक्रिया अदा करता हूँ।

अब हम सब यह प्रतिज्ञा करें।

- * भारत के प्रति कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति हम अफादार और निष्ठावान रहेंगे।
- * राष्ट्र के स्वातंत्र्य तथा उसकी एकता की रक्षा करने और उसे सुदृढ़ बनाने के लिए हम समर्पण की भवना से कार्य करते रहेंगे।
- * किसी कार्य सिद्धि के लिए हम कभी हिंसा का आश्रय नहीं लेंगे।
- * प्रदेश, भाषा, धर्म और जाति सम्बन्धी सभी मतभेदों को तथा आर्थिक व राजकीय कठिनाइयों को हम शान्तिमय तरीकों से सुलझाने का भरसक प्रयत्न करेंगे।

जय हिन्द !



छठी योजना गांधी वादी हो

श्रीमन्नारायण

अब तक महात्मा गांधी का नाम रस्सी तौर पर लिया जाता था, इसलिए पिछले चुनाव की जीत के बाद २३ मार्च को जब जनता-पार्टी के ससद सदस्यों ने राजघाट पर गांधीजी द्वारा शुरू किए गए काम की पूरे मनोयोग से आगे बढ़ाने की शपथ ली तो एक सुखद आश्चर्य हुआ। इससे पहले जनता-पार्टी के घोषणा-पत्र में यह वायदा किया गया था कि अगर वह सत्ता में आई तो अन्तपोष तथा आर्थिक व राज-नैतिक सत्ता के सब से निचले स्तर तक बिबेन्द्रीकरण के गांधीवादी सिद्धान्तों के आधार पर देश के विकास की कोशिश करेगी। हमें उम्मीद है कि जनता-पार्टी के लोग महात्मा गांधी की समाधि पर ली गई प्रतिज्ञा को सच्ची लगन से निमाएंगे।

गांधीजी के विचारों को लेकर बुद्धिजीवी तथा युवा पीढ़ी के कुछ लोगों के मन में कभी-कभी यह शक पैदा होता है कि विज्ञान तथा तन्मालाजी के आधुनिक युग में क्या गांधीजी के आदर्श और कार्य-पद्धति देश के विकास की दिशा में कोई सार्थक भूमिका निभा सकते हैं। पर इधर पश्चिम में एक नई हवा देखने में आई है। अमरीका तथा यूरोप के देशों में ऐसे बहुत से लेख तथा पुस्तकें पिछले दिनों प्रकाशित हुई हैं जिनमें गांधीजी को न सिर्फ आज के लिए उपयोगी बताया गया है बल्कि कहा गया है कि उनके विचार हमारे समय से बहुत आगे हैं। जापान के 'मोज्यो विश्वविद्यालय' के प्रो मोरियोतो इन दिनों गांधीजी पर शोध कर रहे हैं। एक बातचीत में उन्होंने बताया, उनका यह दृढ़ विश्वास है कि गांधीजी अपने समय से सौ बरस आगे थे। इसी तरह अमरीकी पत्रिका 'न्यूजवीक' के स्तम्भकार थॉरेन्डा तारजी चित्ताची ने गांधीजी के विचारों पर लिखी एक प्रभावशाली लेखमाला में कहा है कि विभिन्न

मुहों पर गांधीजी के विचारों को अथ पश्चिमी बुद्धिजीवियों के बीच उत्तरोत्तर स्वीकृति प्राप्त होती जा रही है। वहाँ लोग यह स्वीकार करने लगे हैं कि पश्चिम की विभिन्न सामाजिक, आर्थिक समस्याओं का हल गांधीजी की इस उक्ति में निहित है कि हमारी जरूरतें तो पूरी हा पर उन जरूरतों को हम सीमित रखना चाहिए। यह सही है कि धरती पर हमारी जरूरत भर के लिए हमारा पर्याप्त साधन यह है और हम पर व हमारी लालच को कहीं तक पूरा करण ?

अजमेरटोना में हुए संयुक्तराष्ट्र के पिछले सम्मेलन के दौरान इस बात की तरफ हमारा ध्यान खींचा गया था कि आने वाले कुछ ही दिनों में पानी की पूँद तक तेल के बराबर महंगी हो जाएगी। उन्नत देशों में ऊर्जा का संकट मुँह बाएँ है। यह सही है कि विश्वास के रास्ते में ऊर्जा आदि के भयंकर अभाव से भविष्य में आने वाली मुश्किलों की तरफ 'रोम क्लब' द्वारा दिए गए इशारों को दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अयशास्त्रिया तथा वैज्ञानिकों द्वारा चुनौती दी जा रही है। 'हडसन' संस्थान के संस्थापक निर्देशक हरमन बॉन ने अपनी हाल में प्रकाशित एक किताब 'अगले दो सौ वर्ष' में दावा किया है कि मानव जातिका भविष्य बहुत सुन्दर है, आने वाले समय में सब तरफ से सम्पन्न हो जाएंगे और वे प्रकृति की क्षमता पर काबू पा लेंगे। परन्तु लोग भी मानते हैं कि धीरे धीरे कोयला तथा तेल से मिलन वाली ऊर्जा को सारे ऊर्जा तथा भूताप पर आधारित तबनालाजी से बदलना होगा।

कुछ महीने पहले टाइम पत्रिका में लिखे एक लम्बे मसूदे में कहा था कि आधुनिक विज्ञान और तबनालाजी को अब पहले की तरह 'गो-भाता' नहीं समझा जाता अब वैज्ञानिक उपलब्धियों को भी लोग चक की नजर से देखने लग रहे हैं। आणविक शक्ति जिस अभी हाल तक विज्ञान की मानवता की एक महान् भेट समझा जाता था, अब आसका की नजर से देखी जाती है। लागो में यह एहसास बढ़ता जाता है कि जिस अणु में सम्पन्नता बढ़ाने में मदद मिल रही है उसी में बम भी बनाया जाता है और इससे दुनिया किसी भी समय तबाह हो सकती है। डा. शूमाखर ने अपनी ताजा किताब 'स्मॉल इज

बूटीफुल' में लिखा है, बुद्धिमत्ता इसी में है कि विज्ञान और तकनालोंजी को एक नई समन्वित, सौम्य, महिम्न, श्रेष्ठ और सुन्दर दिशा दी जाए। अपनी किताब में उन्होंने गांधीजी के इस विचार की तरफ ध्यान खींचा है कि दुनिया को उत्पादन की वजाय बहुजन के लिए उत्पादन पर जोर देना चाहिए। आदमी लघु है और लघु ही सुन्दर होता है। प्रो. डायमण्ड ने 'मनस' के एक हात के ही अंक में प्रकाशित अपने लेख में 'नौकर-दाही की श्वेतरूपी समाप्ति', साझे-स्वामित्व और पैदावार के साधनों के विकेंद्रीकरण की यत्नात्मकता को है। इसी तरह ग्राइन ईजली ने अपनी किताब 'सिबरेजन एंड द एम ऑफ साइन्स' में तकनालोंजी की तमाम महंगी योजनाओं को तत्काल ग्रस्त कर देने की सलाह दी है और कहा है कि 'विज्ञान का विकास उस सीमा के भीतर रहकर ही किया जाना चाहिए जिसमें मनुष्य के प्रति आदर और धार तथा प्रकृति से अनुराग बना रहता हो।'

ओ. ई. सी. डी. पेरिस के विकास केन्द्र ने इस वर्ष एक उल्लेखनीय शोध प्रकाशित किया है, उसका शीर्षक है 'टुथडेंस एंड री-डिफीनीशन ऑफ डेवेलपमेंट' इस निताब के सम्पादक का कहना है कि 'विकास' एक भ्रामक विचार है। तेज विकास का एक अनिवार्य परिणाम यह होता है कि अमीर और गरीब तबकों के बीच तनाव बढ़ता चला जाता है और निर्माण की वजाय विध्वंस की तकनीक अधिक प्रभावी हो जाती है। इसके सम्पादक इस निश्चित राय के हैं कि ऐसा विकास जो एक आदमी को दूसरे के खिलाफ करता हो, मुखतापूर्ण है। उन्होंने इस धारणा को गलत बताया है कि पूरी दुनिया के विकास का कोई एक मॉडल हो सकता है। उनका कहना है कि हर समाज को अपना रास्ता खुद तय करना है। जरूरत इस बात की है कि पूंजी निर्माण और पैदावार के ढाँचे का पुनर्गठन किया जाए, उत्पादन के साधनों का पुनर्वितरण हो ताकि कुछ देशों के इस क्षेत्र में आर्थिक साम्राज्यवाद को समाप्त किया जा सके।

यूनेस्को प्रेस द्वारा प्रकाशित एक और पुस्तक 'कल्चर, सोसायटी एण्ड इकॉनामिक्स फॉर ए न्यू वर्ल्ड' में भी उसके सम्पादक ने तकनालोंजी

के साम्राज्यवाद के विरुद्ध चेतावनी दी है। 'जो देश अपनी तकनालोंजी का विकास नहीं कर पाए वे दूसरे देशों से तकनालोंजी उधार लेकर अपना नुकसान ही करते हैं, इस विचार के सम्पादक का कहना है कि हमें आदमी के श्रम के उपयोग के नए तरीके विकसित करने होंगे 'विविधता का सिर्फ सांस्कृतिक मूल्य ही नहीं है—उसके ठोस आर्थिक लाभ भी हैं। इसे विकास के रास्ते की रुकावट नहीं समझना चाहिए गांधीजी ने भी ठीक यही बातें कही थी।

विकास की तेज दर के प्रति दुनिया भर में अयंशाम्त्री अब सदाब हो उठे हैं। जापान जिसने पश्चिमी आर्थिक ढाँचे को अपनाकर पिछले दस सालों में अपनी पैदावार दुगुनी कर ली थी अब विकास की दर को कम करने की योजना बना रहा है ताकि प्राकृतिक साधनों को चुक जाने से बचाया जा सके और राष्ट्रीय जीवन में सांस्कृतिक मूल्यों को पुनर्स्थापित किया जा सके।

पिछले वर्षों से विकसित देश हवा और पानी के सङ्कलन की गम्भीर समस्या का सामना कर रहे हैं। पूरी दुनिया में सङ्कलनशाम्त्री और पर्यावरण वैज्ञानिक उन तरीकों की खोज में लगे हैं जिनसे इस जहरीले सङ्कलन को रोका जा सके।

यूरोप और अमरीका के लोगों में योग के प्रति असाधारण रूप से दिलचस्पी बढ़ी है। वे अपनी बीमारियों का इलाज मँहगी दवा और जटिल चिकित्सा पद्धति की बजाय आसान सस्ते और धरेनू उपायों से करना पसंद करते हैं। कुछ दिन पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी विकासशील देशों को आसान और सस्ते देशी इलाजों को बढ़ावा देने की सलाह दी थी। पश्चिमी देशों में बड़ शहरों में जड़ी-बूटी की नई दुकानें तथा योग सिखाने के नए केन्द्र बढ रहे हैं। वहाँ अधिकाधिक योग प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ झुक रहे हैं।

भारत में पूर्ण शराबबन्दी किए जाने पर गांधीजी हमेशा जोर देते थे। आज पश्चिम के विकसित देशों में भी शराब की लत को लेकर चिन्ता बढ़ती जा रही है। अमरीका और रूस की सरकारें शराब

प्राप्त लेखक सखरोव ने भी अहिंसा को एक श्रेष्ठ अम्य माना है। हमारी पिछली रूढ़ियों के इतिहास ने राजनैतिक उद्देश्यों को पाने के लिए हिंसा के प्रयोग की निरर्थकता को बिल्कुल पक्के तौर पर साबित कर दिया है।

मुझे पूरा भरोसा है कि जनता पार्टी-गाँधीजी-के सपने के भारत को साकार करनेमें कोई कसर न उठा रखेगी। कई वर्षों पहले महान फ्रांसीसी दार्शनिक रोमा रोलाँ ने कहा था—'कुछ अर्थों में तो गाँधीजी आज के विज्ञान से भी आगे बढ़ गए थे, भविष्य की समस्याओं को उन्होंने भाँप लिया था। इस अर्थ में वे एक अत्याधुनिक व्यक्ति थे। मुझे जरा भी शक नहीं है कि गाँधीजी के विचार कभी पुराने नहीं पड़ेंगे, वे हमेशा हमें भविष्य का रास्ता खोजने में मददगार साबित होंगे।'

हमें उम्मीद करनी चाहिए कि छठवीं योजना का प्रारूप गाँधीवादी आदर्शों के अनुरूप होगा। गाँधीजी के समाजवाद की कल्पना राजनैतिक और आर्थिक सत्ता के विकेन्द्रीकरण पर आधारित है। इसका अर्थ है हमारी विकास योजनाओं को इस तरह बनाया जाए कि वे नीचे गाँव तक पहुँच सकें। वे योजनाएँ लोगों के लिए हों और उन्हीं के सहारे चलाई जाएँ। सामूहिक कार्यक्रमों के माध्यम से उनमें आत्मनिर्भरता बड़े और इस तरह सरकार का दखल कम से कम होता चला जाए ऐसी कोई गाँधीवादी योजना तभी सफल हो सकेगी जब राष्ट्रीय स्तर पर पूरी सादगी और कफायत बरती जाए।

जीवन कुटीर
बधा (महाराष्ट्र)



बुनियादी तालीम का एक प्रयोग

राधाबहन

सक्षमी आश्रम की गाँधीजी के आदीर्षादि के साथ पूज्य सरला बहनजी ने कुमाऊँ की महिलाओं के लिए बुनियादी तालीम की सस्था के रूप में वर्ष १९४६ में प्रारम्भ किया था। पूरे उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्र में सर्वोदय विचार का व नोवशक्ति जागरण की दिशा में जो कार्य हुआ है वह इस सस्था की दी गई प्रेरणा की एक उपलब्धि है। साथ ही इसके भीतर बुनियादी तालीम की दृष्टि से जो अनुभव आया, जो परिणाम निकला वह भी एक उपलब्धि है।

पर्वतीय क्षेत्र की ग्रामों में आई बालिकाएँ ही हमारी छात्राएँ हैं और उन्हीं ग्रामों से आई हैं। हमारी शिक्षिकाएँ औसत में हमारी पारिवारिक पूर्ण भूमिका यह है कि हम श्रम प्रधान रहे हैं उसमें भी अकुशल श्रमही प्रधान रहा है शिक्षा अध्ययन अथवा चिंतन मनन की परम्परा नहीं रही है। न ही सिलाई कढ़ाई गृहकार्य कुशलता, बालसंगोपन गशीनों पर काम करने का कोई पारिवारिक संस्कार रहा है। इस प्रकार की हम छात्राएँ व शिक्षिकाएँ इस सस्था में एकत्र हुई हैं जहाँ हमारे ग्रामीण जीवन के अनुकूल गौशाला में गायें व भेंसों हैं जिनके लिए खेतों पहाड़ी ढलानों व पेड़ों से चारा काटकर सिर पर डोकर ले आती हैं छोटी सी खेती है जिसमें सागभाजी व फल पैदा करने के लिए कम्पोस्ट खाद तैयार करके उसे सिर पर डोकर खेतों को देती हैं। हाथ से चलाने वाले औजारों से खेत खोदने होते हैं और पहाड़ के सीमित पानी को बटोर-बटोर कर सिंचाई करनी होती है। साथ में एक उद्योग शाला है जहाँ यहाँ क पर्वतीय भोटिया लोगों के परम्परागत चर्पों बालीन अड्डों कतुओं तथा बागेश्वरी चर्पों पर कताई बुनाई का काम हम

सीखनी व करती है। हमारा छात्रावास जीवन में भी जंगल से लपेटा व बोझ न आना मोटर सड़क से अपन भोजनालय क लिए अनाज को ढोकर ल आना जैसे सभी काय पूणत पर्वतीय ग्रामीण पद्धति पर होत है, सारांश कि माहोन पूणत पर्वतीय ग्राम का है।

विन्तु खती में खुदाई आदि व मुधर ओजार छात्रावास में साफ हव दार घर व फलश गौचालय उद्योग शाला में रुई कताई क ग्रामोद्योगी यत्र सिल इ मशीन एव स्वटर-बुनाई क हस्त यंत्र रसोई में विद्युत् खालित चक्की गोशाला में गोबर गैस सयन आदि साधन हमारी तालीम व इस परम्परागत माहोन को जीवन का वह विकास दना चाहत ह जो आज पर्वतीय ग्रामो को स्वावलम्बी व समृद्ध करन क लिए इस समाज की एक माँग है इस पर्वतीय जीवन की एक आवश्यकता है।

हमारा सामूहिक जीवन द्वारा शिक्षा का पहला आधार यह रहा है कि एक भोजनालय में शिक्षिकाएँ व छात्राएँ एक पक्ति में भोजन करती ह। हमारी पूरी सस्या क सदस्या क लिए एक ही रसोई है। और वह ह हमारा सामूहिक भोजनालय। उसी तरह एक छात्रावास की छत क नीचे छात्राओ व विभिन्न टोलियों क साथ शिक्षिकाएँ सोती है। और उसी तरह खत खतिलान, वनप्रांतर अथवा गौशाला व उद्योग शाला में छात्राएँ व शिक्षिकाएँ सही अर्थों में 'टु सव दि स्वीट' क लिए जुडती है अर्थात् जीवन व बुनियादी तीन कामा क लिए तीन सहज कार्यक्रम (१) सहभोजन (२) सहजीवन (३) सहकर्म।

इस सारी दिनचर्या में श्रम की प्रतिष्ठा व श्रम शिक्षण के लिए अलग से कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता होती ही नहीं। ना ही कोई औपचारिक कार्यक्रम या विशेष व्यवस्था का आयोजन करना पडता है परन्तु जीवन व जिन मूल्यों को हम दना चाहत ह उह आसानी से दे पात ह। इस सारी व्यवस्था में यह महत्वपूर्ण ह कि शिक्षको की दृष्टि इस सम्बन्ध में साफ हो कि जीवन की दिशा क्या होगी? हम किस तरह क समाज की स्थापना करना चाहत ह? प्रत्यक्षत आज हमारा समाज रचना क्या है उसकी समस्याएँ क्या ह? उसकी गरिमाएँ क्या ह?

लक्ष्मी आश्रम को ऐसे शिक्षकों की एक पूरी सदस्य टीम आज तक नहीं मिली, यह एक दिक्कत रही है।

बच्चों के ऊपर बौद्धिक ज्ञान का बोझ बढ़ते जाने का प्रश्न हमारे देश में पिछले कुछ वर्षों से प्रचलित रहा है, याने बढ़ गया है। इस कारण पढ़ाई की किताबों कापियों का बोझ भी बढ़ा है और पढ़ने के घण्टों की संख्या भी परन्तु सह-कर्मयुक्त सहजीवन के अन्दर एक ऐसा संक्षिप्त व्याख्याकरण बनता है जिसमें पूरा जीवन ही शिक्षा की एक खुली किताब होता है। यहाँ खाते समय भी भोजन के तत्वों पर साय-साध चर्चा होने लगती है, खेत में मिट्टी की रचना व उसके इतिहास का प्रसंग छिड़ सकता है, एक कमर में रहते हुई छात्राएँ अपनी शिक्षिका से हिन्दी, गणित, इतिहास भूगोल किसी भी विषय की जानकारी ले लेती हैं। इससे हमने पाया है कि बौद्धिक बर्ग व घण्टे ड़ाई या तीन घंटे बच्चों के लिए पर्याप्त है। हम उनका निजी अध्ययन, के लिए उन्हें एक या डेढ़ पढ़ाओर भी दत्त है इससे पुस्तकें व कापियाँ स्वतः अपेक्षाकृत कम हो जाती हैं पर बौद्धिक स्तर सामान्य विद्यालयों के बच्चों से कितनी ह्रासत में कम नहीं बरन् इन छात्राओं की लेखन व प्रगटन की मौखिकता विशेष होती है।

लोकतन्त्र में नागरिक के सही व्यक्तित्व के लिए हमने तीन पहलुओं पर प्रयोग किया है। पहला—छात्रावास में छात्राओं का मन्त्रीमण्डल और सामूहिक कार्य के लिए बनाई गई टोलियाँ, इसके कारण जुटकर काम करने के कर्तव्य व समझ को पहले देकर तब प्रायः गए अधिकारा के उपयोग का गुण दिन प्रतिदिन छात्राओं व व्यक्तित्व में भजता जाता है। दूसरा—ग्रामी अथवा क्षेत्र की समस्याओं के हल में संप्रयत्न जुटाया व उनका अध्ययन करना, इसके लिए समय-समय पर अलग-अलग पहलू तथा जन-सुरक्षा इस प्रकार का या यह प्रत्यक्ष कार्य उनके मानस पर स्पष्ट छाप डालना है। तीसरा—अध्ययन प्रवास, जो छात्राओं के मस्तिष्क में अपने दबे वा-सजीव चित्र उजागर करता है।

शिक्षण धावकम्बन हमारा एक जानदार प्रोग्राम रहा है। आठवीं वक्षा के बाद याने १५ वर्ष की उम्र की छात्राओं अपनी शिक्षा ग्रहण

कापियां पुस्तकें आदि तथा अपने भोजन व वस्त्र पर आने वाला व्यय वदम प्रति वदम रु० १० वरून करने के लिए तैयार होना पड़ता है। इसलिए छात्रा अपने अध्ययन से अतिरिक्त समय में कोई ऐसी उत्पादक या शैक्षणिक प्रवृत्ति की जिम्मेवारी लेती है जो उसकी आय का जरिया बनती है। एक मोटे अंदाज में प्रथम वर्ष में आय उसके खर्च की ३% द्वितीय वर्ष में १%, तृतीय वर्ष में ३% तथा चतुर्थ वर्ष में पूर्ण स्वावलम्बन-इस तरह रहती है। यह क्रम व्यक्तियों की अपनी व्यक्तिगत रुचि व शक्तियां तथा शिक्षिकाओं द्वारा दिए गए मार्गदर्शन व प्रेरणा पर भी निर्भर करता है। किन्तु १५ वर्ष से ऊपर के बच्चों की शिक्षा इत्यादि खर्च का भार न तो माँ बाप पर पड़ना चाहिए न ही वह समाज पर ही पड़े। साथ ही विद्यार्थी को उत्पादन करके सन्नाह का सहयोगी बनना प्रारम्भ कर देना चाहिए जो एक पहाड़ी कृषक का सड़का १२-१३ वर्ष की उम्र से ही बन लगता है। हमारे इस विचार को शिक्षण स्वावलम्बन के इस प्रयोग ने पुष्टि दी है, हमारी कतई बुनाई की उद्योग-शाला, खेती गौनाला, विद्यालय एवं छात्रावास इन सभी को हमने शिक्षण स्वावलम्बन की प्रवृत्तियों का आधार बनाया है। किन्तु मुख्यतः उद्योग-शाला उत्पादन कार्य देने का मुख्य रोल अदा करती है।

हमारी समस्याएँ — हमारी उपलब्धियाँ आपक हैं किन्तु थोड़ी हैं। पर समस्याएँ कठिन व अधिक संख्या में हैं सर्वप्रथम समस्या है सरकार द्वारा नई तालीम की मान्यता नहीं होना, जिसके कारण हम छात्राओं को दो बारगा से शिक्षा बोर्ड की सामान्य फाइनल परीक्षाओं के लिए तैयार करना पड़ता है।

(१) परीक्षा के बाद प्राप्त होने वाले शिक्षा बोर्ड के सर्टिफिकेट में, जिसे सरकारी व गैर सरकारी तथा सामाजिक मान्यता प्राप्त है, भविष्य में बहना को आजीविका व अन्य अवसरों के लिए एक सुरक्षितता मिलती है।

(२) योग्यता व शक्तियाँ होते हुए भी अनात्मविश्वास व हीनता की गूथों से ग्रसित रहने की स्थिति से मुक्ति मिलती है।

दोन दोनो कारणो वा उन्मूलन हुआ है । किन्तु इससे नई तालीम की दिशा मे हमे बठिनाइयाँ आई हैं । परीक्षामूलक वातावरण को, जो कि शिक्षा या तालीम के वातावरण वा हनन करता है, मन्द करने के लिए हमें बहुत ही मेहनत करनी पडी है । साथ ही छात्राओं को कई व्यय के बौद्धिक विषया मे समय देना पडा है । जो कि परीक्षाओ के लिए अनिवार्य थे, किन्तु जीवन के लिए बेमेल हैं । आधुनिक परीक्षा पद्धति एवं परीक्षापूतकता शिक्षा ने सत्य को समाप्त कर देती है और जीवन के प्रति व्यावहारिक दृष्टिकोणको दबाकर एक अस्पष्ट वात्पनिवता ले आती है, जो व्यक्तिगत की समरसता व प्रभाव को छिन्न-भिन्न करती है ।

लेकिन आत्म विन्यासहीनता या हीन भावना की गूथी भी व्यक्तियों के लिए उतनी ही गतक चीजें हैं । आज हम इस दुराहे पर खडे हैं ।

मेरे विचार से इसका यह हल है जिसकी ओर सक्षमी आश्रम उत्सुकता से देख रहा है ।

(१) देश मे नई तालीम को कई स्वतन्त्र प्रयोग है । अपनी-अपनी क्षेत्रीयता को बनाए रखकर समग्र शिक्षा का स्वरूप उसमें परिलक्षित हो ।

(२) इस प्रकार की शिक्षण संस्थाओं को शासन द्वारा स्वायत्तता प्राप्त हो ताकि आज के इस संक्रमण काल में डिग्री व सर्टिफिकेट आदि की मान्यता मूल्य-भेद न पैदा करे ।

(३) नई तालीम का शिक्षण गाँधी विचार मे चल रहे व उसके लिए काम कर रहे रचनात्मक कार्यकर्ता अपनी संज्ञानो को दिलाएँ तब यह स्पष्ट होगा कि नई तालीम एक सक्षम मानव बनाने वाली क्रान्ति-कारी शिक्षा पद्धति है, न कि गाँधी का मात्र चित्पूर ।

आज तो नई तालीम को न सकारो से मान्यता मिली है और न ही उसका नाम लेने वाले, उसकी प्रशंसा करने वाले रचनात्मक कार्यकर्ताओ से, अतः ये दोनों पहलू बराबर महत्वपूर्ण हैं ।

आज देश का वातावरण ऐसा है कि इस दिशा में प्रयत्न किया जा सकता है, सरकारी मान्यता से भी आवश्यक पारिवारिक मान्यता है रचनात्मक परिवार की मान्यता, ये दोनों ही प्राप्त हो तो नई तालीम के सजीवन से देश को प्राण मिलेगा।

दूसरी समस्या इस दिशा में जुटकर प्रयोग करने वाली सक्षम टीम का अभाव भी है। जिन शिक्षिकाओं व कार्यकर्ताओं के बल पर हम यहाँ तक पहुँचे थे समाज में अपने जीवन का कार्य इस नहीं बना पाए हैं क्योंकि इसकी मान्यता न होना एक मुख्य दोष रहा है।

फिर भी हम आशाविन हैं कि देश व विश्व, आन ध्यान दिनों में बुनियादी शिक्षा के महत्व को अधिक म अधिक समयता जाएगा।



गांधी मार्ग

गांधी विचारक सृजनारमक साहित्य का मासिक
सारगर्भित लेख, लघु लेख, कहानी, नाटक, कविता,
सस्मरण एवं व्यक्ति-चित्रों से युक्त
विचारशील पाठकों एवं सर्वसाधारण पाठकों के लिए पठनीय
सम्पादक

श्री धीमन्नारायण, श्री भवानीप्रसाद मिश्र

वार्षिक शुल्क ₹ १२ द्विवाषिक ₹ २२

एक प्रतिका मूल्य ₹ ६

सम्पक करें व्यवस्थापक 'गांधीमार्ग' (हिन्दी मासिक)

गांधी शान्ति प्रतिष्ठान, २२१-२२

दीनदयाल उपाध्याय मार्ग

नई दिल्ली-२

रचनात्मक कार्य की दिशा

सर्वसम्मत निवेदन

[गांधी स्मारक निधि के १७ १८ १९ अगस्त को नई दिल्लीमें रचनात्मक कार्य संबंधी एक विचार गोष्ठी आयोजित की थी। उस विचार गोष्ठी के अन्त में जो सब सम्मत निवेदन प्रकाशित किया गया था। उसे पाठकों को जानकारी के लिए यही दिया जा रहा है]

अखिल भारत रचनात्मक कार्यकर्ता सम्मेलन दिनांक १७ १८, और १९ जुलाई १९७७ को नई दिल्ली में हुआ। उसकी ओर से रचनात्मक संस्थाओं और कार्यकर्ताओं के संस्तु विचारों के लिए कई व्यापक सुझाव दिए गए थे। इनमें एक यह था कि रचनात्मक कार्य के अध्ययन के लिए एक केन्द्र होना चाहिए जो रचनात्मक संस्थाओं की सेवा उनके काम की पुनर्निरीक्षण और मूल्यांकन करके, प्रयोग करके, उनके क्रिया कलापों में अधिक सामंजस्य बिठाकर रचनात्मक कार्यकर्ताओं की दक्षता में उन्नति करके तथा क्षेत्रीय कार्य के लिए अधिक कारगर पद्धतियों को सुझाकर कर सके।

अखिल भारतीय सम्मेलन के सुझावों को त्रिधात्मक रूप देने की दृष्टि से गांधी स्मारक निधि ने एक राष्ट्रीय विचार गोष्ठी आयोजित की। यह गोष्ठी राजघाट स्थित गांधी राष्ट्रीय संग्रहालय में १७ १८, और १९ अगस्त १९७७ को हुई। इसमें देश के विभिन्न भागों की रचनात्मक संस्थाओं तथा स्वयंसेवी एजन्सियों से संबंधित ४० से अधिक प्रमुख कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। चर्चा के आधारस्वरूप गोष्ठी के सम्मुख कई विचार पत्र (Papers) थे। जिनमें रचनात्मक कार्यको सघन बनाने के लिए तथा अध्ययन अनुसंधान और मूल्यांकनकी दृष्टि से रचनात्मक संगठनों की आवश्यकताओं को निश्चित करने के लिए सुझावों की रूपरेखा दी गई थी। गोष्ठी द्वारा विचार किए गए

मुख्य मुद्दों तथा चर्चा के अंत में किए गए सर्वसम्मति निर्णयों को निम्न-लिखित निवेदन के रूप में सर्व सम्मति से स्वीकार किया गया —

१. रचनात्मक कार्य आन्दोलन

गोष्ठी यह मानती है कि, विशेष करके स्वतंत्रता के बाद, देश के विभिन्न भागों में रचनात्मक कार्य केवल उन्हीं लोगों द्वारा नहीं किया जा रहा है जो गांधीजी के विचार और आचार से प्रत्यक्ष प्रभावित हुए थे, बल्कि और भी विभिन्न मंचों के अंतर्गत हो रहा है जिनको सामाजिक कार्य, समाज-सुधार, स्वयंसेवी प्रयास जन सहयोग सामुदायिक कार्य जैसे नाम दिए गए हैं। विभिन्न नाम से किए जानेवाले इन सभी क्रिया कलाओं को रचनात्मक कार्य आन्दोलन माना चाहिए। यद्यपि सामाजिक और रचनात्मक इन एजेन्सिया की दृष्टि के आर्थिक और सामाजिक विकास में सम्पूर्ण देन निश्चित ही सीमित है किन्तु राष्ट्र को खुलहाल बनाने की उन सबकी मिली जली क्षमता असाधारण है। इसलिए इस समय क्षेत्रीय काम में लगे रचनात्मक संगठनों को एक ऐसे राष्ट्रव्यापी विस्तृत आधारवाले आन्दोलन का बीजबिन्दु मानना चाहिए जो सतत विवसित होगा और अधिकाधिक रूप से ऐसी क्षमता प्राप्त करता जाएगा कि वह न केवल सरकारी कार्यक्रमों का पूरक बने या उनके कार्यान्वयन में सहायक हो बल्कि जनता के समीप काम करके भविष्य के लिए नए मार्ग और नमूने सुझानेवाला सिद्ध हो।

२. मूल उद्देश्य

अपनी प्रसिद्ध पुस्तिका 'रचनात्मक कार्यक्रम उसका अर्थ और स्थान' (CONSTRUCTIVE PROGRAMME ITS MEANING AND PLACE) में गांधीजी ने रचनात्मक कार्य की विभिन्न १९ भदों के बारे में जो भाग-दर्जन दिया था उसको ध्यान में रखत हुए गोष्ठी को यह लगा कि इस समय, विशिष्ट विस्तार से भी अधिक आवश्यकता इस बात की है कि उस कार्यक्रम की पृष्ठभूमि में जो सिद्धान्त तथा मूल लक्ष्य थे उन पर ध्यान दिया जाए। यही नहीं, वर्तमान परिस्थितियों और जनसत्ता के विभिन्न भागों की

आवश्यकता के प्रकाश में इस कार्यक्रम की पुनः व्याख्या भी आवश्यक है। गांधीजी के सत्य और अहिंसा के बुनियादी मूल्यों के बारे में कार्यकर्ताओं को अत्यन्त सजग और सतर्क रहना है। मानवीय परिस्थितियों और सामाजिक मूल्यों की भाषा में, इनमें यह निहित है कि नागरिक अधिकारों और कर्तव्यों, लोकतांत्रिक कार्यात्मकता और मानवीय प्रतिष्ठा के प्रति गहरी प्रतिबद्धता हो।

गांधीजी के लिए रचनात्मक कार्य, कुछ निश्चित मूल्यों और परिवर्तन पद्धतियों को ध्यान में रखते हुए, समाज और अर्थव्यवस्था दोनों की पुनर्रचना का माध्यम था। इसलिए रचनात्मक कार्य सम्बन्धी दृष्टिकोण में समुदाय के अंदर सामान्य हित और कर्तव्य की भावना, आपसमें सहभागिता सामुदायिक कर्म तथा आत्म-निर्भरता, स्थानीय संसाधनों का अधिक उपयोग, सर्वोदय के लिए आवश्यक अंत्योदय, राजमन्दी और समझा-बुझाकर परिवर्तन पर आग्रह तथा अच्छे, ध्येयों के लिए अच्छे साधनों पर बल, अतर्निहित है। लोककल्याण, राहत तथा अन्य सहायता के परे, रचनात्मक कार्य का आवश्यक उद्देश्य समाज-आर्थिक परिवर्तन और पुनर्रचना तथा स्वतंत्रता, समानता तथा व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर आधारित सामाजिक और मानवीय संबंध है। अन्ततः उसकी आशा यही थी कि सर्वोदय के आदर्शों पर आधारित समाज का निर्माण होगा जिसकी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था अहिंसात्मक और शोषणहीन होगी।

गौण्टी का यह विचार है कि देशभर में व्यापक रूप से रचनात्मक कार्य करने के बजाय, वह कुछ छोटे क्षेत्रों में साधन रूप से किया जाए। ऐसे क्षेत्रों में, जो कुछ ग्रामों के समूह हो सकते हैं या संपूर्ण विभाजित प्रखण्ड, विभिन्न क्रियाकलापों की, समुदाय के संपूर्ण संभयन और पहल पर, समग्र दृष्टि से करना है। हर घर में, विशेषरूप से उनमें जो पिछड़े गए हैं, पहुँचाने वाले काम के द्वारा रचनात्मक कार्यकर्ताओं को विकास के ऐसे नमूनों या प्रकार का सृजन करने का काम करना है जो महत्वपूर्ण जरूरतों का समाधान करे और जिनका संतत विस्तार अन्य उपयुक्त क्षेत्रों में किया जा सके।

३. समाज को संगठित करना

गोष्ठी ने इस पर बल दिया कि रचनात्मक संगठनों और पचायत तथा सहकारी संस्थाओं की, जो बहुत सी विकासकीय गतिविधियों की प्राथमिक प्रशासनिक इकाईयाँ हैं, सफलता में धनिएठ सबध है। इसलिए समाज में चेतनता और दिलचस्पी का स्तर उठ कर, उनके त्रियात्मक ढग में सुधार करके तथा उनके कार्यकर्ताओं की दक्षता को बढाकर, रचनात्मक कार्यकर्ताओं और संगठनों का यथासम्भव प्रयास, उन संस्थाओं को गतिशील बनाने का होना चाहिए।

स्थानीय लोकतन्त्र तथा आर्थिक, प्रशासनिक और नागरिक कार्यों के विकेन्द्रीकरण का आधार ऐसी ग्रामसभा है जिसका सदस्य ग्राम का प्रत्येक प्रौढ हो। इसलिए यह जरूरी है कि जहाँ भी पहले से कानूनी प्रावधान है, इसकी (ग्राम सभा की) बैठक बहुधा होती रहनी चाहिए और उनको इसका प्रयास करना चाहिए कि जनता की राय और उनकी आवश्यकताओं का असर ग्राम पचायतों और अन्य पचायती राजसंगठनों के निर्णयों पर पड़ता रहे। समुदाय के विभिन्न तरह के लोगों की शक्ति के उपयोग के लिए ग्रामसभा के अतर्गत स्त्रियों युवकों तथा बच्चों के विशेष संगठन होने चाहिए। ग्राम पचायत द्वारा विशेष कार्यों के लिए रचित समितियों में ग्रामसभा के त्रियाशील सदस्यों को शामिल किया जाना चाहिए, जिससे गाँव के स्तर पर भागीदारी का क्षेत्र विस्तृत हो।

ग्राम समुदाय में दलबन्दी और विपक्षिताओं के अस्तित्व की ओर भी गोष्ठी का ध्यान गया। उसको लगा कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाएँ एक आवश्यक अर्थ में सुदृढ बनेगी यदि कम-से-कम प्रखण्ड के स्तर तक राजनीतिक दल किसी ऐसी आचार-संहिता पर सहमत हो जाए जिसमें पदाधिकारियों के चयन और संस्था के निर्णयों में दलगत राजनीति की दृष्टि न होकर समूचे तौर पर जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति आदि की दृष्टि रहे। ग्राम और प्रखण्ड स्तर पर निर्णयों के लिए सर्वानुमति या कम-से-कम सामान्य निर्वाचकों के किसी विशाल

बहुमत, जैसे तीन-चौथाई, का आग्रह रखने से बहुत लाभ होगा। इस प्रकार आपसी समझौते की जो भावना निर्मित होगी उससे समुदाय में इसकी क्षमता बढ़ेगी कि वह अपने साधनों और जनशक्ति का उपयोग अधिक दुर्बल लोगों के हित से संबंधित विकास में कर सके।

गोष्ठी ने यह मान्य किया कि अधिक समूहों की शक्ति तथा विकास को बढ़ाने तथा नीचे से अधिकाधिक दबाव डालने की उनकी क्षमता में वृद्धि के कदम उठाने की आवश्यकता तथा प्रासंगिकता है। यह लगा कि खेतिहर मजदूर, ग्रामीण कारीगर और भाजिनल किसान जैसे लोगों को यथासंभव सामुदायिक संगठन के ढांचे में एकजुट करने के लिए विभिन्न तरीकों को आजमाना और विकसित करना चाहिए, जिससे वे अपने हितों की रक्षा कर सकें और उनकी बहुवृद्धि के लिए उठाए गए सामाजिक तथा आर्थिक कदमों और भूमि धारों का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन हो सके। जनता के अधिक दुर्बल और प्रतिकूल स्थितिवाले विर्गों समूहों के आर्थिक और सामाजिक हितों की रक्षा और सुदृढ़ता के लिए बनाए जानेवाले संगठनों में, जाति-उपजाति तथा सामाजिक भेदाभेद का, गैर विचार किए प्रत्येक संबंधित व्यक्ति तथा परिवार को समानता तथा सार्वभौम सदस्यता के आधार पर प्रवेश मिलना चाहिये। ग्रामीण विर्गों को संगठित करने के प्रयासों के परिणाम सर्वोत्तम तभी निकलेगे जब कि वे प्रयास गांधी विचार पर आधारित होंगे, पुनः और मनुता से बचा जाएगा और पूरे समुदाय में ही सामाजिक एकात्मता तथा एक-दूसरे के लिए चिंता की विस्तृत भावना को प्रोत्साहन दिया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में तथा महान अन्यायों को दूर करने के लिए, अन्तिम विवरण के रूप में सत्याग्रह किया जा सकता है।

देश के कई भागों में, भूदान तथा ग्रामदान के बड़े बड़े क्षेत्र हैं। जहाँ भी संभव हो, उपर्युक्त प्रस्तावित दिशा में भूदान-भूमि तथा हमारे लाभान्वित लोगों के विकास के प्रयोग किए जाएँ और उनका उपयोग पूरे समुदाय के जीवन के पुनर्निर्माण में बीज केन्द्र के रूप में किया जाए।

सामुदायिक स्तर पर अधिक प्रभावी क्रिया तथा अधिक दुर्गल और निधन समूहों के संगठना के लिए उपर्युक्त सुझावों के कारगर क्रिया-व्ययन की दृष्टि से गोष्ठी को यह लगा कि पंचायती, सहकारी मस्याओं भूदान तथा ग्रामदान भूमि सुधार विषयक तथा अन्य सवधित वर्तमान कानूनों का आज की आवश्यकताओं और पिछले १०-१५ वर्ष में होनेवाले परिवर्तन के प्रकाश में, केन्द्रीय तथा प्रादेशिक सरकारों के साथ सहयोग करके पुनर्निरीक्षण किया जाना चाहिए।

४. रचनात्मक कार्य क्षेत्र

गोष्ठी ने उन दिशाओं पर भी विचार किया जिनमें विकास के वर्तमान स्तर पर लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए रचनात्मक कार्य को अधिक विस्तृत और व्यापक बनाने की जरूरत है। चुने हुए क्षेत्रों में सघन काम करने वाले रचनात्मक संगठनों को विभिन्न प्रवृत्तियों में समग्रता की पद्धति अपनाने स्थानीय समुदाय को अपने काम में साथ देने, स्थानीय प्रभावी नतृत्व को आगे लाने तथा कार्यकर्ताओं के गुण विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए। गोष्ठी को यह लगा कि कृषि विकास ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, और क्षेत्रीय समुदाय के स्तर पर अनौपचारिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य सबधी दक्षभास जैसे मार्गजनिक नीति नीति के यद्गते हुए कार्य क्षेत्र के लिए रचनात्मक संगठनों के अपने भी स्रोत विकसित करने तथा ज्ञान बढ़ाने के विशेष प्रयास करने चाहिए। रचनात्मक संगठनों को रचनात्मक कार्य सबधी धारणाओं और दायरे को व्यापक बनाना चाहिए। तथा राष्ट्रीय ऐक्य और सांस्कृतिक विकास, जनसंख्या नियंत्रण, स्वास्थ्य और सफाई, जल-प्रदाय तथा प्रौढ शिक्षा जैसे महत्व के क्षेत्रों में भी अपने अनुभव तथा स्रोतों का आवश्यक विकास करना चाहिए।

गोष्ठी ने यह बात स्वीकार की कि विगत वर्षों में विकास प्रशासन का एक सुसम्पन्न ढाँचा निमित्त हो गया है और ग्रामीण समाज की हित की दृष्टि से अनेक एजेंसियों ने मिलकर काम किया है। नदीहरणत जिला और प्रखण्ड का विकास कर्मचारी, पंचायती राज्य और सहकारी

संगठन, कृषि विश्वविद्यालय और प्रशिक्षण तथा शोध में लगी अन्य सस्थाएँ मार्केटिंग बोर्ड्स और विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हुए सार्वजनिक और निजी उद्योग कार्यक्रम। इन सभी एजेंसियों को परस्पर अपने प्रयासों का तालमेल बैठाना चाहिए, और साथ ही दूसरी ओर रचनात्मक संगठनों को, एक सामान्य हित के ऐसे कार्यक्रम में एकदूसरे को भागीदार मानकर उनको अपना निवट सहयोग देना चाहिए।

गोष्ठी को यह अच्छा लगा कि सार्वजनिक रीतिनीति के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में केन्द्रीय और राज्य सरकारें, जैसा कि आवश्यक है, अधिनाधिक क्षेत्र विकास की दृष्टि, अन्तर्पचारिक पद्धतियों के प्रयोग, सामुदायिक क्रिया पर बल, अधिक दुर्बल वर्गों तथा अन्य लक्ष्यनिष्ठ समूहों की आवश्यकता की पूर्ति के प्रयास और रचनात्मक तथा स्वयंसेवी संगठनों के एक बड़े 'रोल' की दिशा में, प्रगति के साथ बढ़ती जा रही है। केन्द्रीय तथा प्रादेशिक सरकारों और स्वयंसेवी सस्थाओं दोनों से अब अपेक्षा है कि सारे कार्य में अधिक जोरदार पहल वे करें। अब यह विशेष रूप से आवश्यक है कि राजकीय विभाग उनको अन्य एजेंसियों अपनी गतिविधियों, दृष्टि और पद्धतियों से रचनात्मक संगठनों, पंचायतों, सहकारी सस्थाओं आदि को अवगत रखने के लिए विशेष योजनाएँ चलाएँ। व्यवस्थित और सुनियोजित ढंग से उनकी सहायता, प्रशिक्षण और फण्ड के बँटवारे की प्रक्रिया का विकास किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित की जानी चाहिए जिसमें रचनात्मक संगठन, सामुदायिक सस्थाएँ और सभी सरकारी तथा सकार-निर्मित एजेंसियाँ, लोगों की सेवा में लगातार भागीदार के रूप में काम कर सकें। प्रत्येक का 'रोल' क्या होगा यह स्पष्ट हो और हर एक उसका ध्यान रखे तथा साथ ही, सारी संरचना और सहायता की शैलियों में लचीलापन भी रहे।

५. कार्यकर्ता शक्ति खड़ी करना और उसका प्रशिक्षण।

गोष्ठी में भाग लेनेवालों को अपने-अपने क्षेत्रीय अनुभवों के आधार पर यह लगा कि रचनात्मक संगठनों की सफलता के लिए

सबसे महत्वपूर्ण शर्त कार्यकर्ताओं का गुण स्तर, योग्यता तथा उनकी समर्पित भावना और उनकी उपलब्धि है। जो भी कार्यक्रम हाथ में लेने है उनके लिए प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं के सहकार की आवश्यकता है। इसलिए, अपने कार्य के फैलाव के अनुसार, रचनात्मक संगठनों के पास कार्यकर्ताओं का ऐसा एक छोटा समूह होना चाहिए जो स्थानीय समुदाय और सरकार तथा सङ्घित एजेंसियों सबके साथ काम करने की योग्यता रखते हों। ऐसे कार्यकर्ताओं के समाज में उनका समुचित स्थान मिलना चाहिए और उचित मानधन तथा अन्य सुविधाओं के लिए उनकी आवश्यकता किया जाना चाहिए। देश में कई ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत-से युवा और योग्य व्यक्ति काम कर रहे हैं इस जानकारी से गोष्ठी को प्रोत्साहन मिला। यह भी जानकारी में आया कि बहुत से व्यक्ति जो सरकारी और गैर सरकारी पदों से सेवा निवृत्त हुए हैं जिन्हें पर्याप्त अनुभव है तथा जिनका स्वास्थ्य ठीक है, सेवाभावना में ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के लिए तैयार हैं। सरकारी कर्मचारियों अध्यापक तथा दूसरों को अध्ययन-अवकाश की सुविधाएँ मिलनी चाहिए जिससे वे मध्य स्वयंसेवी संगठनों के साथ देहात में स्वयंसेवी कार्य कर सकें ॥

—जैसा कि पहले ऊपर कहा जा चुका है रचनात्मक संगठनों के कार्यकर्ताओं के पर्याप्त प्रशिक्षण को गोष्ठी बहुत महत्व देती है। उसका मुनाफा है कि सामाजिक और स्वयंसेवी संस्थाओं में वर्तमान प्रशिक्षण सुविधाओं और उसकी सक्षमताओं का सर्वेक्षण किया जाए और उसको सफल बनाने के लिए कदम उठाए जाएँ। गोष्ठी ने यह आशा भी व्यक्त की कि केन्द्र और प्रादेशिक सरकारों की जो संस्थाएँ विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों के प्रशिक्षण में लगी हैं वे रचनात्मक संगठनों द्वारा मनोनीत कार्यकर्ताओं के लाभ के लिए विशेष प्रशिक्षण और नव संस्करण के कार्यक्रमों को प्रारम्भ करनी ॥

६. रचनात्मक कार्यके लिए साधन

गोष्ठी ने साधनों के प्रश्न पर बड़ी सावधानी से विचार किया जिसमें रचनात्मक संस्थाएँ प्रत्यक्ष सेवा करके और ठीक शैलियाँ तथा

पद्धतियाँ कायम कर विशाल जनता की, विशेष रूप से अधिक दुर्बल और प्रतिकूल अवस्थावाले समूहों की आर्थिक और सामाजिक बहुवृद्धि में उचित योगदान कर सके। इसको लगा कि जिस सीमा तक रचनात्मक संगठनों को विश्वास योजनाओं के क्रियान्वयन तथा स्थानीय क्षेत्र और समुदायों की सेवा का स्पष्ट 'रोल' सौंपा जाएगा, उस सीमा तक केन्द्र तथा प्रादेशिक सरकारों के संबंधित विभागों और क्षेत्रीय कार्यक्रमों में से वे वित्तीय सहायता ले सकेंगे। इसके बारे में केन्द्र और प्रादेशिक सरकारों द्वारा अपने विभिन्न विभागों और संगठनों को मोटे निदेश दिए जाने की जरूरत होगी।

निकट के वर्षों में, साथ और वृत्ति संगठन 'फ्रीडम फ्रॉम हंगर कैम्पेन' के अंतर्गत तथा अन्य विदेशी स्वैच्छिक सहायता के स्वीकृत स्रोतों से भारत सरकार की मारफत जो सहायता रचनात्मक संगठनों को प्राप्त हुई है, उसकी गोष्ठी ने सराहना की। इस सहायता से स्वयंसेवी संगठनों को काम बहुत अच्छी तरह करने में सुविधा हुई है। फिर भी, गोष्ठी को यह लगा कि विदेशी साधनों का 'रोल' नामूली और पूरक ही हो सकता है, मुख्य प्रयास तो देश के अपने सरकारी और गैर सरकारी साधनों से ही अधिक-से-अधिक सहायता जुटाने का होना चाहिए। गोष्ठी ने इस बात को सर्वोच्च महत्व दिया कि स्थानीय समुदाय का चेतना और प्रेरणा तथा समर्थ, विशेष रूप से अधिक दुर्बल वर्गों के मंगल के प्रति अतिसह्य भावना में वृद्धि कर, उन समुदायों के साधनों को विकसित किया जाए और सहायता जुटाई जाए। संगोष्ठी ने इस पर ध्यान दिया कि निम्न केन्द्र सरकार ने व्यावसायिक उद्यम की इस दृष्टि से कर में महत्वपूर्ण रियायत दी है कि वे ग्रामीण विकास की योजनाओं में आर्थिक सहायता दें। गोष्ठी ने आशा व्यक्त की कि इन सुविधाओं का उपयोग ऐसे बड़े और सतत बढ़ने वाले विकास-क्षेत्रों के निर्माण में किया जाएगा जिसका उद्देश्य ग्रामीण समुदायों और रचनात्मक संगठनों के ग्रामीण क्रियाकलापों में सहायता देने का होगा। सार्वजनिक अधिकारियों ने और प्रतिनिधित्व के सहयोग से इसके लिए तरीके विकसित किए जाने चाहिए।

७. रचनात्मक कार्य अनुभव का विश्लेषण और मूल्यांकन

देश में विभिन्न परिस्थितियों के अतर्गत विभिन्न क्षेत्रों को रचनात्मक कार्य-अनुभव के सतत विश्लेषण और मूल्यांकन की आवश्यकता पर गोष्ठी ने गहराई से विचार किया। यह वाछनीय है कि रचनात्मक और स्वयंसेवी एजेंसियों द्वारा होनेवाले काम की नियमित जानकारी प्राप्त करने की तथा इस जानकारी और अनुभव की यथा-समय दूसरों को मुहैया कराने की पर्याप्त व्यवस्था हो। उनके द्वारा अनुभव की गई कठिनाइयों, उनकी सफलताओं तथा विफलताओं, का तटस्थ अध्ययन उनके सहयोग में किया जाना चाहिए। रचनात्मक संगठनों की इस बात में सहायता की जानी चाहिए कि जिन समस्याओं का हल अभी तक नहीं मिल सका है उनके सतोपजनक उत्तर की खोज की दृष्टि से वे मूजनात्मक सामाजिक प्रयोग कर सकें। सामाजिक आर्थिक और तकनीकी विकास के क्षेत्रों में जो बहुत सी समस्याएँ इस समय प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्य में लगी हैं, उनके भी साधनों का इस्तेमाल, सामुदायिक स्तर की महत्वपूर्ण समस्याओं के हल में अधिकाधिक सहायता के लिए किया जाना चाहिए।

गोष्ठी का विचार रहा कि रचनात्मक कार्य के अध्ययन और मूल्यांकन के लिए किसी उपयुक्त केन्द्र के स्थापनायें शीघ्र कदम उठाए जाएँ तो इन विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित प्रयास हो सकता है। यह केन्द्र एक ओर तो इसके लिए प्रयत्न करेगा कि रचनात्मक संगठनों से लगातार सूचना मिलती रहे और दूसरी ओर ऐसा ही प्रयत्न विश्वविद्यालयों और विभाग के विभिन्न क्षेत्रों के अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र से चलेगा। यह केन्द्र रचनात्मक कार्यकर्ताओं, विकास कर्मचारियों और समाज-वैज्ञानिकों को समय-समय पर अपने अनुभव और चिंतन के आदान प्रदान के लिए तथा अपने ज्ञान और पद्धतियों को, विशेषरूप से उनकी जो सफल सिद्ध हुई हों, जानकारी देने के लिए, एकत्रित करेगा।

प्रस्तावित केन्द्र की स्थापना तथा अध्ययन, विश्लेषण, मूल्यांकन, अनुसंधान और प्रयोग के लिए, जिनका सवध, रचनात्मक कार्य से

और रचनात्मक तथा स्वयंसेवी कार्य-कर्ताओं के प्रशिक्षण की सुधरी पद्धतियों से होगा, एक विस्तृत योजना अधिवक्ता सोच विचार के बाद तैयार की जानी चाहिए।

८. राष्ट्रीय और प्रादेशिक नीति

गोष्ठी ने यह आशा व्यक्त की कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकार अपनी ओर से अपनी-अपनी नीति में इसका यथासम्भव प्रयास करेंगी कि रचनात्मक और स्वयंसेवी संगठनों की इसमें सहायता की जाए कि वे अ आवश्यक सेवाओं के लिए जनता की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तथा जनता के निवृत्तम विकासकीय कार्यों के लिए स्थानीय समुदायों की क्षमता और साधन का तथा स्वयंसेवी प्रयासों के सहज शाय्यताओं का इस्तेमाल कर सकें। ऐसी राष्ट्रीय और प्रादेशिक नीति के बिनासे तथा नियन्त्रयन में, रचनात्मक संस्थाएँ खुशी से उस समर्थन और सहायता को देने के लिए तैयार रहेंगी जिसके लिए उनसे इच्छा व्यक्त की जाएगी।

९. रचनात्मक कार्य पर समिति

गोष्ठी को लगा कि विकास के जिस स्तर पर हम पहुँच गए हैं, उस पर सगाज कार्य के कई क्षेत्रों में, जैसे आर्थिक और प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण, रोजगार का विस्तार, भूमि सुधारों का क्रियान्वयन, ग्रामीण औद्योगीकरण तथा गाँव और उद्योग के संबंध में उत्पादन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण और आगक्षण तथा सार्वजनिक नीतियों की समीक्षा, तीव्र करने की जरूरत है।

गोष्ठी ने गांधी स्मारक निधि के अध्यक्ष से यह निवेदन किया कि इस सर्वसम्मति वक्तव्य में दी गई सिफारिश पर आगे कार्यवाई करने के लिए रचनात्मक कार्य पर एक समिति बनाएँ। इस समितिकी रचनात्मक कार्य अध्ययन केन्द्र संबंधी प्रस्तावों की तपसील में जाना और कुछ विशेष प्रकार की रचनात्मक प्रवृत्तियों का विशेषतया हरिजन और आदिवासियों संबंधित कार्यों, व्यवस्थित पुनर्निरीक्षण प्रारम्भ करना होगा।

राष्ट्रीय रचनात्मक कार्य विचार-गोष्ठी अध्यक्ष, गांधी स्मारक निधिद्वारा गठित कार्यान्वयन (फॉलो-अप) समिति

- १ डा श्रीमन्नारायण, अध्यक्ष, गांधी स्मारक निधि —अध्यक्ष
 - २ डा र रा दिगंबर, अध्यक्ष, गांधी शांति प्रतिष्ठान, नई दिल्ली
 - ३ श्री सिद्धराज ढड्डा, अध्यक्ष, सर्व सेवा सघ, गोपुरी (वर्धा)
 - ४ श्री विचित्र नारायण शर्मा, अध्यक्ष भारतीय खादी ग्रामोद्योग सघ, लखनऊ
 - ५ श्री अण्णानाहेव महम्मदुल्ले, अध्यक्ष, गांधी सेवा सघ सेवाग्राम (वर्धा)
 - ६ श्री दयामलाल, अध्यक्ष, हरिजन सेवक सघ, नई दिल्ली
 - ७ डा सुशीला नंद्यर, अध्यक्ष, अखिल भारतीय नानाबदी परिषद, नई दिल्ली
 - ८ श्री ल म श्रीकान्त, उपाध्यक्ष भारतीय आदिम जाति सेवक सघ, नई दिल्ली,
 - ९ श्री धरमसीभाई खटाऊ, अध्यक्ष, अ भा कृषि मोसवा सघ, वर्धा
 - १० श्रीमती लक्ष्मी एन मेनन, अध्यक्ष, कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट, इंदौर
 - ११ डा मोहनसिंह मेहता, अध्यक्ष, सेवा मंदिर, उदयपुर
 - १२ श्री जे पी नायक, सचिव, इण्डियन काउंसिल आफ सोशल साइन्स रिसर्च, नई दिल्ली
 - १३ श्री सतीशचन्द्र आर-१२।१, राजनगर, गाजियाबाद
 - १४ श्री पूर्णचन्द्र जैन मंत्री, गांधी स्मारक निधि नई दिल्ली
 - १५ श्री तरलोक सिंह, ११० सुन्दर नगर, नई दिल्ली
- उक्त समिति को तीन तक अन्य सदस्य सहवर्ण करने का अधिकार होगा।



स्वर-संस्कार

[स्वर वर्णों की जानकारी देने के साथ-साथ उन्हें कविता के माध्यम से भरतापूर्वक याद किया जा सकता है । इसी दृष्टि से अ से झ तक १२ स्वरों पर आधारित कविताएँ यहाँ प्रस्तुत की जा रही हैं]

स्वर-संकेत :

अ आ इ ई उ ऊ ढम
ए ऐ ओ औ की ङम ङम
अं अंगूर हमें हैं माते
अः गीत हम हिल मिल गाते

स्वरावली :

अ

अनन्त है आनन्द अपार
घरती-माता का आधार
शिशु मंगलमय रूप उदार
मानव महिमा अपरंपार

इ

इला श्यामला घरती माता
गुमधुर फल फूलों की दाता
रंग विरंगी फूल अनेक
ले लूँ मैं उनसे से एक !

उ

उड़न खटोला उड़ता जाए
बैठे बालक मोव बनाए
हिमगिरि पर्वत पर उड़ जाए
'जय जय' करते हाथ हिलाए ।

आ

आभा फैल रही सुकुमार
पंछी कलरव करें उदार
सोता मैना चिड़िया रानी
बानी से हम सुनें कहानी

ई

ईश्वर की महिमा है प्यारी
भारत माता की बलिहारी
गंगा-जमना बहती धारा
धमक रहा है भाग्य-सितारा

ऊ

ऊपर से नीचे हम आते
भारत का गुण गौरव गाते
गुमधुर मीठे फल हम खाते
वर्षा में हम पूब मचाते

ए

एक बने हम, नेक बने हम
सगुण गुणी गुणवान बने हम
ज्ञानी ध्यानी धीर बने हम
देशभक्त बलवीर बने हम !

ओ

ओजस तेजस् दोनों मँया
बलि बलि जाए प्यारी मँया
साहसी अमित उदार
नैया तैर रही मँसधार

अ

अचल चंचल चाँव चाँव
कौधा करता काँव काँव
हम्मा हम्मा गोमाता की
जय बोली गंगा माता की

ऋ

ऋ से ऋषि हुए भारत में
अगणित ज्ञानी ध्यानी
आश्रमवासी बने तपस्वी
ज्ञानी वर विज्ञानी

जीवन कुटीर
वर्धा (महाराष्ट्र)

—मदालसा नारायण

ऐ

ऐतिहासिक देश प्यारा
हिंद वरदायक हमारा
गगन में चमका सितारा
धर धरती दिव्य धारा

औ

औजार गुणी गुणमय हैं नाम
आते हैं वे सब के काम
करामात हूँ वे बिछलाते
उनसे खेल खिलाते बनते

अ

अ मनोहर हैं गुलबस्ता
घर में बना पड़ा होसरता
दीदी ने हैं इसे बनाया
मैया ने हैं इसे सजाया !

~ ~



शिक्षा में सुधार

नई तालीम समिति के सुझाव

अखिल भारत नई तालीम समिति की एक आवश्यक बैठक नई दिल्ली में १७ जुलाई को केन्द्रीय गांधी स्मारक निधि कॉलोनी में हुई थी। उसने शिक्षा सुधार सबंधी नीचे लिखे सुझाव शिक्षा मंत्री भारत सरकार को दिए हैं -

केन्द्र तथा अन्य कई राज्यों में अब जब कि जनता सरकार राष्ट्रीय विकास के विभिन्न क्षेत्र में महात्मा गांधी के आदर्शों को लागू करने के लिए वचनबद्ध है, अखिल भारत नई तालीम समिति आशा करती है कि सरकार निम्नलिखित सुझावों पर गम्भीरतासे विचार करेगी।

१- सभी स्तरों पर शिक्षा सामाजिक रूप से लाभप्रद और उत्पादक गतिविधियों के द्वारा दी जाए जो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की आर्थिक प्रगति और विकास से सम्बद्ध हो। शिक्षा के विभिन्न स्तरों के पाठ्यक्रम में कम से कम ५० प्रतिशत समय इन उत्पादक और रचनात्मक गतिविधियों को दिया जाए।

२- प्राइमरी से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक पाठ्यक्रमों में तीन मूल बातों पर विशेष धन दिया जाए -

१- उत्पादक श्रम को शिक्षा का अभिन्न अंग मानकर स्वावलम्बन, आत्मविश्वास और श्रम का महत्व।

२- छात्रों और अध्यापकों को सार्वक समान सेवा के कार्यक्रमों से सम्बद्ध कर राष्ट्रीयता और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना।

३- नैतिक और चारित्रिक मूल्यों का निर्माण, एकताकी आवश्यकता तथा सभी धर्मों के प्रति समान आदर।

इन पाठ्यक्रमों में अपनी प्राचीन सांस्कृतिक देन का सामान्य ज्ञान, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का संक्षिप्त इतिहास, राष्ट्रीय एकता पर ध्यान देना, अंतरराष्ट्रीय सहयोग तथा अहिंसा, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता आदि विषयों को शामिल किया जाना चाहिए।

शिक्षा में उचित समय पर विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रमों में 'गांधी विचार' का अध्ययन भी शुरू किया जाना चाहिए।

३- नई शिक्षा प्रणाली तब ही अर्थपूर्ण हो सकती है जब शिक्षा को नौकरी से सम्बन्ध न किया जाए। सरकारी विभाग तथा निजी

या सरकारी क्षेत्र की नौकरियों में भर्ती के लिए उद्योग, वाणिज्य या सरकारी रोजगार में लगे लोगों के लिए बिना डिग्री के पाठ्यक्रमों की प्रणाली की स्थापना करना आवश्यक है।

४- विभिन्न चरणों में १०+२+३, वाले शिक्षा के ढांचे को अपनाया जाना चाहिए। दस वर्ष की स्कूली शिक्षा के बाद बड़ी सख्या में अनेक प्रकार के द्विवर्षीय व्यावसायिक पाठ्यक्रम चालू किये जाएँ जो छात्रों को रोजगार के अवसर प्राप्त करने और जीवन में स्थिर होने में सक्षम बनाएँ। उच्चस्तर माध्यमिक शिक्षा को बुनियादी शिक्षा के आधार पर व्यावसायिक बनाया जाए। संज्ञात्मक और व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त छात्रों में कोई अन्तर नही रखना चाहिए।

प्रथम दस वर्ष की स्कूली शिक्षा में "शारीरिक और उत्पादक कार्य पर बल दिया जाए तथा अन्य कार्यक्रमों का विकास किया जाए और यथा-संभव ऐसा प्रशिक्षण दिया जाए जो बच्चों के पर्यावरण के अनुकूल हो।

केन्द्रीय और पब्लिक स्कूलों समेत सभी स्कूल मातृ भाषा माध्यम और त्रिभाषा फार्मुले के सम्बन्ध में भी राष्ट्रीय शिक्षा ढांचे के अनुसार हो तो भारत की विविधतापूर्ण सभ्यता का विस्तार करें।

५- स्कूली क्षेत्र में नए प्रयोगों को प्रोत्साहन देने के लिए "स्वायत्तता प्राप्त कालेज" के समान स्कूलों को भी चलाया जाए।

६- स्कूल और कालेज आस-पास के क्षेत्र में 'व्यावहारिक शिक्षा' के कार्यक्रम चलाएँ। संज्ञात्मक ज्ञान देने के साथ-साथ विभिन्न व्यवसायों में लोगों की कार्यकुशलता सुधारने तथा उसका स्तर बढ़ाने का भरसक प्रयत्न किया जाए।

७- शिक्षा मंत्रालय देश में बुनियादी शिक्षा की प्रगति की समीक्षा, अनुमान और मार्गदर्शन के लिए एक राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा परिषद की स्थापना करे। राज्य सरकार भी अपने-अपने क्षेत्रों में ऐसी ही बुनियादी शिक्षा परिषदों की स्थापना करें।

८- देश के सम्मुख बुनियादी शिक्षा का अधिक अच्छा आदर्श प्रस्तुत करने के लिए बुनियादी और उत्तर-बुनियादी शिक्षा संस्थाएँ अपने कार्य और अन्य सम्बन्धित शिक्षा में सुधार करने के लिए ठोस प्रयत्न करें।

९- बुनियादी शिक्षा के पक्ष में उचित वातावरण बनाने के लिए अखिल भारत नई तालीम समिति प्रत्येक राज्य में व्यापक आधार पर इकाइयों का गठन करे।

If thy aim be great and thy means small, still act, for by action alone these can increase Thee"

—Shri Aurobindo

Assam Carbon products Limited
Calcutta--Gauhati--New Delhi.

"यदि आपका प्रयत्न बड़ा है, और आपके साधन छोटे हैं, तो भी कार्यरत रहो, क्योंकि कार्य करते रहनेसे ही वे आपको समृद्धि प्रदान करेंगे।"

—श्री अरविन्द

आसाम कार्बन प्रॉडक्ट्स लिमिटेड

कलकत्ता - गोहाटी - न्यू बेहली

हम केवल व्यापारिक संस्थान ही नहीं हैं

आज के गतिशील संसार में कोई भी उद्योग
समाज की आवश्यकताओं की अवहेलना नहीं
कर सकता, क्योंकि सामाजिक उत्तरदायित्व
व्यापार का आवश्यक अंग बन गया है।

इण्डिया कारबन लिमिटेड

केल्साइन्ड पेट्रोलियम कोक के निर्माता

नूनमाटी, गोहाटी-781020

नई तालीम अगस्त-सितम्बर '७७

रजि० सं० WDA/1

लायसेंस नं० ११

हिन्दुस्थान शुगर मिल्स लिमिटेड का विभाग
मेरास उदयपुर सीमेंट वर्क्स
की
शुभ कामनाएँ

उच्च धेनी का 'शक्ति' छाप सीमेंट जिसका उपयोग बड़े पैमाने पर सब तरह के नवनिर्माण कार्य के लिए मजबूती तथा विश्वस्तता के साथ किया जाता है।

ध्यवस्था एवं विधी कार्यालय—

फैक्टरी,
पो. भो. बजाज नगर
(सी. एफ. ए.)
जि. उदयपुर (राजस्थान)
फोन : दशहरा : ३६ और ३७
उदयपुर २६०६

शहर कार्यालय,
६० नया पतेपुरा
उदयपुर ३१३००१
फोन ४४९, ग्राम 'बी'
उदयपुर

नयी तालीम

विद्यालय में परमेश्वर का आनन्दस्वरूप प्रगट होना चाहिए। ईश्वर के रूप तो अनन्त हैं, पर उसके तीन रूप बड़े प्रसिद्ध हैं। एक है सत्य, दूसरा है चित् याने ज्ञान और तीसरा है आनन्द। कर्मयोग में, संसार में, जीवन में सत्य प्रधान होता है। ज्ञानियों की गुहा में और विद्वानों के पुस्तकालय में ज्ञान प्रधान होता है। भक्ति-मार्ग में आनन्द प्रधान होता है। विद्यालय याने भक्ति-मार्ग, याने यहाँ हर चीज़ जो की जाएगी वह आनन्द के लिए ही की जाएगी।

— विनोबा



अखिल भारत नयी तालीम समिति

सेवाश्रम

सम्पादक-मण्डल :

श्री धीमन्नारायण - प्रधान सम्पादक

श्री वज्रुभाई पटेल

श्रीमती मदालसा नारायण

डॉ० मदनमोहन शर्मा

वर्ष २६

अंक १

अनुक्रम

समाप्त दृष्टिकोण		
शक्ति याज्ञिक सम्बन्ध जोड़ें	महात्मा गांधी	७१
शिक्षकों की स्वातंत्र्यता चाहिए	बिनोबा	८९
देश की नई शिक्षा पद्धति	मोरायजी देसाई	९१
गांधीवादी योजना की रूपरेखा	श्रीमन्नारायण	९९
प्राकृतिक चिकित्सा का महत्त्व	...	१०७
एजुभाई	मदालसा नारायण	११९
सेवाप्राम-आयम-युक्त	...	१२१

अक्टूबर-नवम्बर '७७

- * 'नई छाती' का वर्ष अणुस्तर से प्रारम्भ होता है।
- * 'नई छाती' का वार्षिक दृष्टिकोण बारह रूप हैं और एक एक का मुख्य दो हैं।
- * दण्ड-संयमन करते समय राष्ट्र अपनी सच्चा जिम्मेदारी न भूलें।
- * 'नई छाती' में अणु विचारों की पूरी जिम्मेदारी लेखक की होती है।

श्री प्रभाकरजी द्वारा अ. भा. नई छाती समिति सेवाप्राम-युक्त प्रकाशित और
राष्ट्रभाषा प्रेस, बर्मा में मुद्रित

हमारा दृष्टिकोण

१ अखिल भारत तथा अन्य शिक्षा सम्मेलन

जनता पार्टी का राज्य दिल्ली व उत्तरप्रदेश के कई प्रदेशों में करीब सात महीने से चल रहा है। इस बीच शासन की ओर से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। प्रेस व भाषणों की स्वतंत्रता वापिस दी गई है और आपातकालीन आनक का वातावरण समाप्त किया गया है। यह भी स्पष्ट है कि जनता सरकार गांधीजी के सपने के भारत का निर्माण करने के लिए कचन-बद्ध है। कृषि खादी ग्रामोद्योग मद्य-निषेध, गोसेवा, प्राकृतिक चिकित्सा, आदि रचनात्मक कार्यक्रमों को अहमियत दी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के सन्तुलित विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

किन्तु अभी तक शिक्षा सुधार की तरफ पर्याप्त चिन्तन नहीं हो सका है। केन्द्रीय शिक्षामंत्री डा प्रतापचन्द्र चन्दर काफी प्रयत्न कर रहे हैं कि देशकी शिक्षा पद्धति को नई दिशा दी जाए। प्रधानमंत्री श्री मोरारजीभाई देसाई ने भी हाल ही में गुजरात विद्यापीठ के अपने दीक्षान्त भाषण में कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। उनके भाषण के मुख्य अंग अन्यत्र इसी अंक में प्रकाशित किए गए हैं। लेकिन अब यह निहायत जरूरी है कि नई शिक्षा-मरजना के सम्बन्ध में ठोस निर्णय लिए जाएं और उन्हें व्यवस्थित ढंग से मारे देश में लागू किया जाए। *

इस दृष्टि से अखिल भारत नई तालीम समिति की ओर से दिल्ली में एक शिक्षा-सम्मेलन १८, १९, २० दिसम्बर को आयोजित किया गया है। इसका उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री श्री मोरारजीभाई करेंगे। डा चन्दर भी इसमें उपस्थित रहेंगे। सभी राज्यों के शिक्षा

मंत्रियो व प्रमुख विश्वविद्यालयोंके कुलपतियोंको आमन्त्रित किया गया है। देशभर के चुने हुए लगभग १५० शिक्षाशास्त्री व बुनियादी तालीमके कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेंगे। हम आशा करते हैं कि इस सम्मेलनमें कुछ निश्चित सर्वानुमति प्रकट होगी जिसके अनुसार भारत की शिक्षा-पद्धतिको ढाला जा सकेगा।

यह तो जाहिर ही है कि महात्मा गांधी के विचारों के अनुरूप ही हमें अपनी सभी शिक्षण-संस्थाओं में हर स्तर पर समाज-उपयोगी उत्पादक श्रम को शिक्षा का माध्यम बनाना होगा। नटपि बिनोबा ने नई बाग समझाया है कि कर्म और ज्ञान का अद्वैत ही बुनियादी शिक्षा का मूल मंत्र है। विद्यार्थियों को यह पता ही नहीं लगना चाहिए कि उन्हें उत्पादक उद्योगों द्वारा कोई पाठ्यक्रम सम्बन्धी ज्ञान दिया जा रहा है। यह प्रक्रिया-अनुसन्ध विसकुल सहज और स्वाभाविक होना चाहिए। छात्र और शिक्षक मिलकर इस कर्म-ज्ञान-यज्ञ में भाग लें—“महवीर्यम् करवावहे।” यह यज्ञ निरन्तर आनन्द देनेवाला हो तभी वह सही शिक्षा का स्रोत बन सकेगा। यदि विद्यार्थियों को बाल मंदिरों, स्कूल व कालिजों में अध्ययन द्वारा आनन्द की अनुभूति प्राप्त न होती रहे तो वह तालीम निकम्मी ही समझी जाएगी।

हमारी नई सरकार देश की बेकारी व गरीबी को अगले दस वर्षों में समाप्त करना चाहती है। ऐसा करने के लिए शहरों व गाँवों में छोटे उद्योगों व ग्राम-उद्योगों का व्यापक जाल बिछाना होगा। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने की खास कोशिश करनी होगी। जाहिर है कि यह उद्देश्य आवश्यक शिक्षा-मुद्धार के बिना सफल नहीं हो सकेगा। शिक्षा और विकास-कार्यों के बीच अटूट सम्बन्ध जोड़ना होगा। यह तभी मुमकिन हो सकेगा अब हमारी शिक्षा-प्रणाली गांधीजी की “नई तालीम” योजना के अनुरूप श्रद्धापूर्वक पुनर्गठित की जाएगी।

२. प्राकृतिक चिकित्सा और शिक्षण-संस्थाएँ :

अखिल भारत प्राकृतिक चिकित्सा परिषद् की ओर से १४, १५, १६ अप्रैलको गावगमती आश्रम, अहमदाबाद में गन्द्रहवाँ अधिवेशन,

सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई ने किया। सम्मेलन में देशभर के करीब ६०० प्राकृतिक चिकित्सक व कार्यकर्ता शामिल हुए। विस्तृत चर्चाओं के अन्त में जो प्रस्ताव पारित किए गए वे इसी अवसर में अलग दिए गए हैं। बंसर, हृदय रोग व बुद्धि-रोगों के लिए प्राकृतिक चिकित्सा प्रयोगों पर विशेष प्रकाश डाला गया। यह भी समझाया गया कि भारत के ग्रामीण-क्षेत्रों में जा स्वास्थ्य-योजना चालू की जा रही है उसमें प्राकृतिक जीवन चिकित्सा को प्रमुख स्थान देना अत्यन्त आवश्यक है।

लेकिन यह स्पष्ट है कि देश में प्राकृतिक जीवन दर्शन को तभी स्याई रूप से प्रतिष्ठित किया जा सकता है जब इसके बुनियादी सिद्धान्त हमारी शिक्षण-संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में शामिल किए जाएं और प्रारम्भ से ही बच्चों को प्राकृतिक चिकित्सा का महत्व समझाया जाए। इस बारे में सम्मेलन ने एक प्रस्ताव भी प्रकाशित किया है। हम आशा करते हैं कि विभिन्न राज्यों के शिक्षा विभाग इस ओर धीरे ध्यान देंगे।

३ देश की वर्तमान अवस्था

प्रतिवर्ष हम गांधी जयंती के अवसर पर राष्ट्रपिता का पुण्य-स्मरण करते हैं और उनके रचनात्मक कार्यक्रमों पर आवश्यक जोर देने रहते हैं। हममें से कुछ का ख्याल है कि खादी व ग्रामोद्योग ही महात्मा गांधी की विचारधारा के असली प्रतीक हैं। दूसरों का विचार है कि मद्य-निषेध हर्जित व आदिवासियों का कल्याण व नई तालीम कार्यक्रम विशेष महत्व रखते हैं। अन्य लोगों की धारणा है कि प्राकृतिक चिकित्सा व बुद्धिरोग निवारण की योजनाएँ गांधीजी के रचनात्मक काम की बुनियाद हैं। दरअसल इन सभी कार्यक्रमों की अपनी विशेष अहमियत है। किन्तु हम यह कभी न भूलें कि बापूकी विचारधारा और जीवन-मूल्यों का मत्व है 'साधन-शुद्धि'। उन्होंने हमें बार-बार समझाया था कि यदि हम अपने पवित्र साधनों के लिए अपवित्र साधनों का इस्तेमाल करेंगे तो अमफल ही होंगे। विनोबाजी ने इसे 'गांधीजी के नए अद्वैत' की संज्ञा दी है। माध्य और साधन के बीच कोई दीवार खड़ी नहीं की जा सकती। वे एक दूसरे के अविभाज्य अंग हैं। 'साधन शुद्धि'

का सिद्धान्त प्रकृति के नियमों की तरह अटन है, उसकी अनिवार्यता अवाट्य है। वह बोग आदर्शवाद नहीं, नितान्त व्यावहारिक भत्य है।

इस समय देश की अवस्था मनमुच चिन्तनीय है। रोज ही हड़तालें घराब व उपवासों के समाचार अखबारोंमें छपने रहते हैं। कानून की व्यवस्था ढीली व अस्त व्यस्त होती जा रही है। प्रत्येक वर्ग अधिक वेतन व महंगाई भत्ता मांगता है और यह भी चाहता है कि रोजमर्रा के उपयोग की चीजों के दाम कम हों। हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि यदि उत्पादन नहीं बढ़ेगा और मुद्रा की मात्रा निरन्तर बढ़ती जाएगी तो कीमतें नियंत्रण में लाना कैसे संभव होगा। अगर वर्तमान परिस्थिति पर धाबू पाना है तो जनता व विभिन्न वर्गों को अपना जीवन में आत्मनिष्ठा तो लाना ही होगा न? महात्मा गांधी ने १९३१ में ही स्वराज्य भिनन के पहले स्पष्ट शब्दों में कहा था— 'अनुशासन और विवेकयुक्त जनतन्त्र, दुनिया की सबसे सुन्दर वस्तु है।' हम इसी प्रकार का प्रजातन्त्र स्थापित करने का पूरा प्रयत्न करना है।

बापू ने एक और विचार हमें दिया था। वह था 'अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों का पालन। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था— 'मैं तो एक ही अधिकार जानता हूँ— अपने कर्तव्यों को पूरा करने का अधिकार।' किन्तु इस समय तो हम सब अधिकारों की माँगों के चक्कर में पड़ गए हैं। जिम्मेदारियों का हमें बहुत कम भान है। यह दयनीय व चिंताजनक हानि हमारे राष्ट्र के लिए मनुष्य बहुत खतरनाक है। भगवान् हमें सन्मति प्रदान करें।

४ 'वर्ग पधर्प' व गान सत्याग्रह

कुछ सप्ताह पहले भाई जयप्रकाशनारायणजी ने एक प्रसंगपर कह दिया था कि हरिजनो व अन्य कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए 'वर्ग पधर्प' अनिवार्य है। इस विचार को दक्षिण सभी समाचार पत्रों ने गहरापूर्ण ढंग से प्रकाशित किया और उसके कारण काफी गलतफहमी भी पैदा हुई। बाद में श्री जयप्रकाशजी ने कई दफा यह स्पष्ट कर दिया है कि यह 'वर्ग पधर्प' गांधीजी के आदर्श के अनुसार ही होना चाहिए। उसमें भावसंवादी हिंसा व वर्ग कलह का स्थान नहीं हो सकता। किन्तु

शब्दों के प्रयोग से भी अनावश्यक भ्रम व बुद्धि भेद पैदा हो जाना स्वाभाविक है। इसलिए अच्छा हो यदि हम 'वर्ग-संघर्ष' के स्थान पर 'सत्याग्रह' शब्द का प्रयोग करें। यह शब्द बापू ने दिया था और उनका नहीं अर्थ अब मारे ममार में व्यापक हो चुका है।

हाल ही में आचार्य कृपलानी ने विलुप्त सही कहा है कि हरिजनो का संरक्षण देने की जिम्मेदारी संघों को सौंप उठा लेनी चाहिए। गरीब वर्गों को ही अपनी सुरक्षा के लिए नये संगठन बनाने के लिए मजबूर होना पड़े यह उचित नहीं है। गांधी के देश में इस प्रकार की परिस्थिति सामा नहीं देनी। इसीलिए बापू ने हरिजन संघ के प्रमुख कार्यकर्ता संघों में से ही चुने थे। इस समय भी हम अभी का पावन कर्तव्य हो जाता है कि हरिजनो व गिरिजनो की हिफाजत की समुचित व्यवस्था की जाए ताकि आए दिन होनेवाली धर्मनाक घटनाएँ बंद हो और भांग में एकता व भाईचारे का शुद्ध वातावरण स्थापित हो सक।

यह भी आवश्यक है कि हरिजनो की समस्याओं को दलगत राजनीति के जज्जिए से न देखा जाए। सभी पार्टियों का यह कर्तव्य है कि मिलकर इस बलब का घाने का प्रयत्न करें।

५ 'घर का छत्ता'

समाचार पत्रों से ज्ञात होता है कि कन्द्रीय जनता सरकार के कुछ प्रमुख नेता उत्तरप्रदेश त्रिहार मध्यप्रदेश व राजस्थान जैसे विज्ञान प्रदेशों का विभाजन करके कई नए छोटे राज्य बनाने का विचार कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि इन समाचारों में कितना सत्य है। किन्तु यदि इस तरह का थोड़ा भी विचार किया जा रहा हो तो यह समुचित चिन्ता नहीं है। जिस समय १९५६ में राज्य पुनर्गठन कमिशन की सिफारिशें प्रकाशित हुई थी और उनका अनुसार भारत सरकार व राष्ट्रसंघ काय समिति द्वारा निर्णय लिए जा रहे थे मैं कांग्रेस का एक महामंत्री था। उस वक़्त हमें देश के विभिन्न प्रदेशों के नेताओं व कार्यकर्ताओं की मनोवृत्ति का ओष्ठानुभव मिला वह अत्यन्त कटु व गौघनीय था। मुझे कई सप्ताह तक अखिल भारत कांग्रेस कमेटी व जतर मतर रोड के दफ्तर में सुबह तीन बजे तक बैठकर सभी तरह के प्रतिनिधि मण्डलों

के सुझावों को शान्ति व धीरज से सुनना पड़ा था। फिर भी कार्य-कतारों को पूरा रातोपूरा दिखाना बड़ी ही कठिन समस्या साबित हुई। मैंने स्पष्टतया अनुभव किया कि भाषावार प्रान्त रचना के प्रश्न पर तब-तब नेता भी अपना भावार्थक व मानसिक सतुलन खो बैठे थे। फिर भी किसी तरह यह मामला तय हुआ। किन्तु बाद में भी इस सिलसिले को बढ़ा करना संभव न हुआ और सन् १९६९ में बम्बई के बड़े प्रदेश को तोड़कर महाराष्ट्र व गुजरात के दो नए राज्य संगठित करने पड़े। तब भी यह चक्र नहीं रुक सका और १९६७ में छोटे पंजाब के भी तीन हिस्से करने पर केन्द्रीय शासन को बाध्य होना पड़ा।

अब फिर इस कठिन व जटिल प्रश्न को उठाना भारत की एकता के लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। यह मामला सिर्फ उत्तर के हिन्दी प्रदेशों के पुनर्गठन में समाप्त नहीं होगा। यह पूरा देश के अन्य सभी राज्यों में फैलेगी और उसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। न गालूम देश में कितने और नए राज्य बनाने पड़ेंगे।

जनता पार्टी न मभीर संकल्प जाहिर किया है कि यह दस वर्ष में देश की गरीबी व बफारी दूर करेगी। यह उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है, और उसको प्राप्त करने के लिए बड़े परिश्रम व सम्वसित शक्ति की आवश्यकता होगी। इसी बीच अगर राज्यों के पुनर्गठन का पेचीदा मसला पड़ा कर दिया गया तो सभी बुनियादी व ठोस कार्य पिछड़ जाएंगे और राष्ट्र की संगठित शक्ति पूरी तरह बिखर जाएगी।

यह कुछ हद तक सही है कि छोटे राज्यों में अधिक विकास की गति अधिक तेज हो सकती है। किन्तु इस कार्य को गतिशील बनाने का एक और भी तरीका है। उत्तर प्रदेश व मध्यप्रदेश जैसे बड़े राज्यों में क्षेत्रीय विकास मण्डल संगठित किए जा सकते हैं। जो हो, इस प्रकार राज्यों को फिर संगठित करने का विचार कम से कम दूर साल तक छोड़ देना ही सब दृष्टि में हितकर होगा। यह एक 'बुरा का छत्ता' है। इस समय उभे छेड़ना देश की एकता को गहरी टेम पहुँचाना होगा।

गाँव वालों से संबंध जोड़ें

महात्मा गांधी

[बुनियादी शिक्षा को सफल बनाने की दृष्टि से महात्मा गांधी ने श्रीमती शान्ताबहन नाइमबर से सन् १९४५ में विस्तृत चर्चा की थी और सुझाया था कि सेवाग्राम के गाँववालों से सीधा सम्बन्ध स्थापित करना चाहिए। यह चर्चा गत अंक में प्रारम्भ की गई थी। यह किन्तु उसकी दूसरी और समापन किरत है।]

गांधीजी :—क्या करोगी, प्रौढ शिक्षा में ही शुरू करोगी क्या ?

शान्ता बहन —हाँ। सेवाग्राम देहात के नौजवानों को हाथ में लेना है उनसे सम्बन्ध बढ़ाना है, उनमें जागृति पैदा करनी है तो क्या कहें ? कैसे सम्बन्ध बढ़ाऊँ ?

गांधीजी :—यह समझ लो मैं अस्पताल नहीं हूँ, मैं शिक्षक हूँ मुझे उन नव युवकों से काम लेना है वगैरह पैसे में। वे मुझे मदद देंगे फिर भी मेरे मन में आता है कि वही मुझे वह धोखा तो नहीं, देंगे ? लेकिन नव युवकों पर शिद्दाग करना है और उनमें काम तो लेना ही है।

उनमें यादवीत के जगिए परिचय होगा। जब एवाच-से परिचय हो तब उनके घर में ही शुरू करो (घर के बारे में पूछो कि क्या वह परिवार आश्रयस्थल रखता है। उनकी आयदाद के बारे में पूछना। तैल आदि जानवरों की वह ठीक में देखभाल करना है या नहीं। उन्हें वह खाना खुराक क्या देता है। तुम्हें उसे खाना है कि उनसे वह प्रेम से व्यवहार करे। लाठी में आर नहीं लगाए। उनपर वे बताएंगे कि इनके बिना बेल चलते नहीं, पर मेरी नजरमें उनका यह जवाब ठीक नहीं है। जानवरों पर जैसी मस्तिष्क हिन्दुस्तान में होती है वंगी वही नहीं होती। उसे घरके बारे में कहो कि यदि छोटे भाई बहन है तो उसे पैमाने आदि की मफाई देखना है।

सेवाग्राम में दो चार जगह बगीचे, मंदिर आदि होना चाहिए। वही पहली तालीम होगी। वहाँ उमंगें बातें करें और नहें कि अपने साथ अपने अड़ोसी पड़ोसीको भी लेते आएँ। वातचीत में ही उन्हें इतिहास भूगोल का ज्ञान देना है। एक बोर्ड तो रखोगी। इच्छा है अक्षर ज्ञान भी दो। इकट्ठा होनेवालों के नाम का परिचय कर लो और थोड़ा मजाक भी करो। इस तरह परिचय बढ़ाओ उन्हें इकट्ठा करो। उन्हें सहयोगकी बात सिगानो है। जा नहीं आते उन्हें बलाना है।

मान लो तुम्हारे हाथ सत्ता और जमीन आ गई। सत्ता का अधिकार पाली पटेल और पटवारी के हाथ में रहता है। यदि जमीन हमारे हाथ में है और हम सब जानकार हैं और फिर हमने बीज बोया, सहयोग से सरकार का कर दे दिया तो हमारा वस्तु बच गया और पाम भी हुआ। हम सहयोग में ही खेती सिखाएंगे। खेती हाथ में आ जाए तो पैसों का भी सुधार हो सनता है। इस सब में गे अपनी सुविधा के अनुसार समय कर करो।

मान्ता —यहाँ तो गोसायन्ती गाँव वालों की होगी फिर क्या मतलब ?

बाबू —यहाँ जो होने वाला है यह गह है कि गुंडे ही पहले हमारे पास आएँगे। यज्जा बड़ी चीज होती है, फिर इनके पास पैसा भी है। पैसों वालों को गुंडे ही मानो।

गाँव के कुएँ

जा मुझे तुम्हें तो उन्हें बन्द कर दे, इस काम में पैसा खर्च करेंगे क्योंकि मैं बीमारी के घर हूँ। इतने मुँहों की, जलरस नहीं है। इससे बन्द करने में लोगों के मनोबिन्द के लिए पक्षित स्वयंसेवक भी बनेंगे। जनता के कुओं का स्वर्ण जनता को ही देना होगा। निजी कुओं मालिक सुधारें, नहीं तो मालिकी छोड़ दे जिससे जनता के रूप में उसे सुधारा जा सके। इस तरह सब तुम्हें हमारे हाथ आ जाएँगे। देहातो के लिए देहात के पात्र स्वर्ण हो जाएँ, किन्तु वे कैसे हों यह गोबने की बात है। यह काम ऐसा सादा और सरल हो कि भागे हिन्दुस्तान में हो सके।

सेवाग्राम का आदर्श सबके लिए और कम खर्च का हो। वहाँ की खात लाख देहातों के लिए एक नमूना बने। बिजली के बारे में मैं कहूँगा कि मुझे बाँधो मत। पहले यह कह दो कि सारे हिंदुस्तान में बिजली हो सकती है तब मुझे लगेगा कि इतनी पावर तो होनी ही चाहिए। ऐसे काम के लिए जनता से घन इकट्ठा करे। जनता की निधि रह उसमें आश्रम का भी हिस्सा रहे। आश्रम भी जनता के ही रूप से चल रहा है और गाँव के किनारे बसा है। हमें तो लोगों को सालीम देनी है। ■

भोजन :

शाना —गाँव में रहने जाए तो आश्रम से ही वह काम शाह हो ऐसा आपने कहा है। आश्रम का खाना और रहन सहन सार्विक है और गाँववाला से अलग है वे देहात में कैसे रहेंगे और जिनका खान पान सब कुछ अलग है उनसे (गाँववालों से) कैसे मिलेंगे ?

बापू —बड़े परिश्रम से ही सही—पानी तो उबाल कर पीना है। जो यह नहीं करते वे देहात में कैसे रहते हैं। पहले मैंने सोचा था कि देहात में रहूँगा मगर बैक्सीनेशन (चेचक का टीका) इत्यादि मुझे नहीं लेना था। डाक्टर ने इसीलिए मुझे अलग ही रहने को कहा था। बेल्लेन्ड डाईट के विषय में यह बात है कि थोड़ासा दूध तो लेना ही चाहिए। प्राणीज प्रोटीन थोड़ा-सा भी लेनेसे दूसरी प्रोटीन—अच्छी पचती है अतः एक थोड़ा प्रमाण दूध का रखें। १० तोला दूध और ९ तोला घी—मगर मक्का घी हो।

आगा देवी —बच्चाको हम एक तोला तेल देते हैं।

बापू —यह बस नहीं। घर में (उनको) कुछ मिलता ही नहीं इसलिए आज वह चलता है। मगर अपना माप हम उमपर से न निकालें। अपने शरीर को ईश्वर का घर अर्थात् जनता की धरोहर मानते हैं। जनता के लिए हम जिंदा रहना चाहते हैं तो शरीर को अच्छा रखना ही है। उनके सामने घी खाओ और कहो तुम्हारा इसके बिना चलता है कि तुमरा चलना संभव नहीं अतः तुम घी लो। वहाँ आश्रम में तबियत

बिगड़ती है उसका कारण यह है कि यहाँ लोग मानते हैं कि जितना मिलता है उतना खाना ही चाहिए, ऐसे में तो तबियत बिगड़ेगी ही।

मुशौला बहन — यहाँ मसाला गैरा न होने के कारण खाना स्वाद नहीं होता इसलिए प्रमाण नहीं रख सकते।

बापू — खाना स्वाद नहीं है इसलिए बहुत खाया जाता है; मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। देहात में तो जितना खाना है वह लोग खाते ही हैं। खाने में भी कला है। आधम जीवन में हमें यह शिक्षा देनी है। ज्यादा न खेना तथा झूठ न छोड़ना इत्यादि बातें सीखने सायक है।

शान्ता — खाने में दूध होना जरूरी है और माँ-बाप दूध के लिए पैसा दें ऐसा आपने कहा है। किन्तु बच्चों को दूध देने को उनके पास पैसे कहाँ हैं?

बापू — वह तो करवाना ही है उसमें प्रौढ-शिक्षा है। उन्हें जिम्मेदारी समझानी है। उनकी बचाने की शक्ति बढ़ानी है। उन्हें शिक्षुक नहीं बनाना है। आखिर में तो उनको खाना पीना देना ही है। उसका दो ढग है—एकरुसका है। वे ही चीज अपने ढग से हमें करनी है। यदि हम उन्हें नहीं कर पाते तो समझ लो कि वही कुछ बर्मी है। मैं मानता हूँ वह बनना चाहिए। वहाँ तो उन्होंने सारी दुनिया की बात नहीं सीखी उन्होंने तो एक बड़े समाज का सोचा है। मैं एक सेवाग्राम को लेता हूँ इसके माने सारी दुनिया को लेता हूँ। उनका समग्र जीवन लेकर एक देहात में बिठना हो सकता है, हमें यह देखना है। एक बच्चा और सौ खाएँ यह तो नहीं हो सकता। हरेक बच्चा और खाएँ तो हो सकता है। मुझे मरीज के मरने की परवा नहीं मगर मरीज होने से रोके इतना काफी है। अच्छे समाज में पग बहुत कम रहते हैं—बच्चे को तो माँ-बाप पिलाने ही हैं किसी को नहीं लगता कि बच्चा उनके सिर पर बोझ है। अच्छे कुटुम्ब में बच्चे भी अपने सपने तक भार नहीं होते। बच्चा ३-४ वर्ष का हुआ और बचाने लगता है। यह तो हमारी सामीप है। बानेज घाने दखिो बाने हैं।

सेवाग्राम का आदमी हमारे यहाँ वाम करता है, हम उसके बच्चों को नहीं देखते। हमें उनका साथ अपने बर्तन में तथा उनके बच्चों और उनके साथ व्यवहार में मित्रता और रिश्तेदारी की भावना का निर्माण करना है। उनके बपड़े अलग उनका खाना अलग और वे भी अपने को अलग रखते हैं उसमें भी सुधार करना है। वे अपने को हमसे अलग समझते हैं।

प्रश्न — यदि खाने में दूध न मिले तो कौन-कौन सी चीज देनी होगी ?

बापू — जो मासाहारी हैं उन्हें मैं कहता हूँ कि यदि और कुछ न मिले तो मास अण्डे खाओ। लेकिन शाकाहारी को बहूँगा कि शाक न मिले तो भूखे मर जाओ। क्योंकि शाकाहारी को 'वनस्पति शास्त्र' जानना चाहिए। देहात के गरीबों को 'अंसा कि रक्षिया' बना ठीक वैसा ही बनाना है।

प्रार्थना :

शान्ता — प्रार्थना किस तरह चलाएँ ?

बापू — आम प्रार्थना में राजकर्ता का इल्जाम नहीं लग सकता मगर यह आम प्रार्थना शायद कठिन होगी। रामचन्द्र तो है—पर राम के सामने शिकायत हो तो हम सहन कर लेंगे, वह तो ईश्वर का नाम है। मैं तो सबका अप बदल देता हूँ। हिन्दू माइयाँ लॉजी में ऐसी चीजें भरी पड़ी हैं मैं उन चीजों को नहीं छोड़ सकता हूँ। जो चीज जीवन में भरी हैं वह कैसे बदल सकती हैं ?

सेवाग्राम के मकान :

शान्ता बहन — सेवाग्राम की आबादी बढ़ गई है, नए बसनेवाले सेवाग्राम में घरों की व्यवस्था कैसी हो ?

बापू — नया सेवाग्राम बसाना हो तो जगह हम देंगे पर लोग अपने घर आप बनाएँ। यदि घर बदलना पड़ा तो जो दूसरा उमर में आया वह उसमें लगा हुआ पैसा देकर घर ल लगा। जमीन पर उनका (गाँव-वालों का) हक नहीं होगा। लोग घर के लिए जमीन माँगेंगे, और

घर बसा लेंगे परन्तु साली रहने के लिए ही वे पैसे की जगह परिश्रम देकर घर लेना पसन्द नहीं करेंगे ।

हमारे हाथ में राजसत्ता नहीं है और न तो—आचार-विचार का जोर ही डाल सकता हूँ । जो सत्याग्रह मैं करना चाहता हूँ यदि पैसा हो तो सरतनत आप ही मुझे सहारा दे देगी । मगर यदि लोग मुझे समय लेंगे तो मेरा स्वप्न, स्वप्न नहीं रहेगा । अपने खेतों को उजाड़ दूंगा और लोगों को बखन के लिए जगह दे दूंगा, वे आज ही हमारे यहाँ आ जाएँ । लेकिन वे यह करने को तैयार नहीं हैं । वे चाहेंगे जमीन हमें मिल जाए, लेकिन उसके लिए मैं तैयार नहीं हूँ । मकान का मालिक मैं रहूँ (स्टेट रहे) वे यह नहीं मानेंगे—वे तो जमीन मांगेंगे ।

शान्ता बहन —गाँव में दो तरह के आदमी हैं एक तो वे जिनके पास जमीन नहीं है और जमीन को मालिक न बगते हुए भी पैसा और धर्म दोनों लगाकर मकान बनाना चाहते हैं और दूसरे वे लोग हैं जिनके पास जमीन है पर पैसा नहीं, यदि कोई घर बनाए तो वे किश्तों द्वारा उसका खपया देकर घर ले लें । ऐसे लोगों की मदद कैसे की जा सकती है ?

बापू —इसके लिए एक हाउसिंग सोसायटी (गृह-निर्माण संघ) बनानी चाहिए । घर बनाने के लिए उन्हें पैसा उधार देना होगा, लेकिन उन्हें सस्ती बरदाश्त करनी पड़ेगी । जब तक पूरा पैसा अदा नहीं किया जाएगा तब तक घर सोसायटी का रहेगा । हमें उधार वसूल करना होगा ।

शान्ता बहन —पुराने ढंगके घर चोरो के डर से बने थे । लोग पैसे गाड़कर रखते थे । यदि को-ऑपरेटिव बैंक या किसी जनता के संजाने में पैसा रखा जाए तो घर अच्छे बनने लगेंगे ।

बापू —यह पहला बंदम नहीं । वे लोग पैसे घर में दबाकर रखते हैं । सोना सरकार ने खींच लिया है, अपना दिवाला निकाला है । एक फीट में १४ डि दिए । सोना तो इस प्रकार चला गया । अब जो धन रखते हैं वह सब निकलवाना चाहिए । उसका प्रबन्ध करना चाहिए । फिर घर बनाएंगे । तो उन्हें चोर डाकू चोते का डर रहेगा ही नहीं । वे घर तो ऐसे का ऐसा ही रखेंगे । हमें तो पहल

उनका डर निकालना चाहिए। जब तक लाठी बंदूक नहीं रहती तब तक लोगो में निर्भयता का वायुमण्डल होना चाहिए। अगर वे वहाँ से आकर जंगल में रहने को तैयार हैं तो मुझे आश्चर्य के साथ ही बड़ा आनन्द भी होगा। आनिंग करना तो आसान है। वी सी मेहता ने यह काम किया है।

शान्ता बहन — मजदूर कहते हैं हमें जमीन चाहिए।

बापू — वे लोग तैयार हैं तो हमें वर्ज लोन निकालना होगा हम ऐसा करेंगे और यदि वे सहकार को आपरेशन का महत्व समझ गए हैं तो जिनके पास पैसे हैं वे पैसे दें जिससे को आपरेटिव बैंक बनाएँ। नाम मात्र को सूद देना है। पैसे का उपयोग होना आवश्यक है जिससे वे बिना हमारे की मदद के केवल अपनी बुद्धि से दहात खड़ा कर दें और पीछे हम भी पैसा डालें। जब उन्हें पता चलेगा कि पैसा सूद सहित वापस मिलगा तो पैसा डालने वाले बहुत मिल जाएंगे। सोसाइटी को रजिस्टर कराएँगे जिसमें जप्त न हो सकें। हम उन्हें तकलीफ में नहीं डालना चाहते। यदि वे सहयोग न दें तो यह काम शुरू ही नहीं करना चाहिए— नहीं तो सरकार जैसी बात होगी उनकी मालिकी नहीं रहेगी।

शान्ता बहन — मुना है कि सरकार न अनाज की पैदावार बढ़ाने के लिए ५०० रुपये देने की बात कहती है।

बापू — समझ गया मेरे स्याल में यह बुरी बात है, सरकार अपना ही काम करना चाहती है, रैथियत का नहीं। गन्ने के बारे में ऐसा ही हुआ है इतना बोया गया कि जिसकी हद नहीं।

शान्ता — लोग यह बात समझ गए हैं कि उसमें फायदा नहीं है मगर वे यह नहीं जानते कि दूसरा रास्ता क्या है।

बापू — रास्ता घटाना हमारा काम है। मकान इत्यादि का बताया मगर वह दूसरा बंदम है, उससे पहल तो उनसे (गाँववालों से) मिलें जुलें और देखें कि उनका स्त्री बच्चे साथ है या नहीं। वे ही मदद आलसी बैठे हैं अथवा काम करते हैं या नहीं, यह देखें— उनमें प्रवेश करना है। आर्थिक स्वार्थ को छोड़कर नैतिक स्वार्थ रहे तो इससे उनका मन

साफ हो जाएगा और हमें भी पता लग जाएगा कि वहाँ तब लोग हमारा साथ देने वाले हैं। सच्ची मेहनत ही पैसा है।

शांता —पैसा लौटाना है तो फिर स्वार्थ क्या ?

बापू —पैसे का लेन देन जहाँ भी रहता है वहाँ स्वार्थ की व आ हो जाती है। गुंडे कहेंगे कर तो से पीछे हम गुंडागर्दी तो कर सकते हैं। अतएव ऐसा करेंगे तो पीछे हमें कठिनाइयाँ आएँगी। दक्षिण अफ्रीका में भी गुंडबाजी चलती थी मगर वहाँ दोनों तरफ गुंडे थे।

स्त्री-शिक्षा

प्रश्न —स्त्रियों की शिक्षा किस तरह शुरू करें ?

बापू —घर घर जाकर स्त्रियों को सुख दुख देखो। उन्हें पहिचानो और उनके दुखों को दूर करो। उन्हें समय का उपयोग करना सिखाना है। वे कुछ नहीं जानतीं—झाड़ू कैसे लगाना, घर कैसे रखना आदि भी बतलाना और सिखाना होगा। स्त्रियाँ पुरुषोंकी शिक्षिका हैं। मेरी ऐसी तालीम तो मौखिक होगी। स्त्री अपने पति के लिए ही नहीं देहात के लिए भी है यह बात घर-घर में पड़ोसियोंमें और फिर देहात में समझाना है। बाद में समझ से काम लेना। आर्थिक मदद में कम पड़े। व स्त्रियाँ स्वार्थ की बातें करेंगी, उनसे बचना होगा। जो भूखी मरते हैं उन्हें कमाई कैसे करना यह सिखाना होगा।

पहले सार्वारिख व्याघ्रियाँ आएँगी और फिर सफाई सम्बन्धी तथा आर्थिक, नैतिक और राजकीय कठिनाइयाँ भी आएँगी। मेरी निगाह में राजकारण तो आखिर में आएगा। खाली आर्थिक मदद से दंठन से नहीं चलगा। डाक्टर का काम अलग है खाली दवाई देना है परन्तु शिक्षिका का काम अलग है। वह जिम्मेदारी है। उनका बजट देखना और बनाना तथा उसमें से कितना कमाया और कितना खर्च किया आदि जो देखकर उनके आय-व्यय का अनुमान निकालना है। उन्हें दूगरे धन्ये भी सिपान है। वे तो हमारे रिस्तेदार, सहकारी और साथी हैं। हमें समझना होगा कि उनके साथ कैसे चलें।

प्रौढ-शिक्षा :

शान्ता — नौजवानों से सम्बन्ध बढ़ाने और उनमें जागृति पैदा करने के लिए क्या हम कैसे बढ़ाएँ?

बापू — यह समय तो कि तुम अस्पताल नहीं हो, वरन् शिक्षा हो। शिक्षक आध्यात्मिक है। समय तो कि मुझे बिना पैसे के, नवयुवकों से काम लेना है। नवयुवको को यह विश्वास दिला देना है कि उनसे मदद लेने में मेरा स्वार्थ नहीं है इस प्रकार उनसे काम लेना है।

गृह-परिषद — घर के बारे में उससे पूछना और देखना कि परिवार का क्या हाल रखता है या नहीं। जमीन जायदाद के बारे में पूछना— बैल धरारा की देख भाल करता है अथवा नहीं क्या खाना खुराक देता है और कैसा व्यवहार करता है। हमें उसे यह बताना है कि उनके साथ (बैल आदि) प्रेम का व्यवहार करें साठी में आर न लगाएँ। वह यदि बैल चलाता नहीं ऐसा कहता है तो उसे समझाना होगा। नौजवानों और प्रौढ़ों की शिक्षा के लिए मैं (बापू) तो खेती और जानवरों की देख भाल के विषय में कहना चाहूँगा।

अंग्रेजों के जानवरों की देख भाल अच्छी होती है। जानवरों पर अत्याचार न करने के लिए यहाँ भी कानून (कौन्सिलेटी टू एनी मल्स एक्ट) है लेकिन नाम मात्र के लिए। जानवरों पर जैसी सस्तिरियाँ हिन्दुस्तानमें होती हैं वैसे कहीं भी नहीं होती। गधा भी बहुत उपयोगी जानवर है काम बहुत देता है और खाता थोड़ा है परन्तु उसका जीवन दुःख का जीवन है। नौजवानों से इस प्रकार बातचीत के द्वारा सम्बन्ध बढ़ाकर उनके कुटुम्बों के साथ मेल बढ़ाना चाहिए। यदि उसकी (नौजवान भाई को) छोटी बहन हो तो उससे कहो कि उसे पाठशाला के लिए दे दें। उससे घर के बारे में पूछो कि वह पैखाना घर आदिकी देखभाल करता है और सफाई देखता है अथवा नहीं। यह देखो और फिर उससे अपने अड़ोसी-पड़ोसियों को भी साथ लाने को कहो। सेवा

धाम में बगीचे आदि जैसी दो-चार जगह होनी चाहिए। वही पहली तालीम होगी। उनके साथ बातचीत करें और बातचीत के द्वारा ही इतिहास भगोल का ज्ञान दें। एक नाला तैरता रख दें। अधर ज्ञान की इच्छा है तो दे दें। इकट्ठा करके उन्हें सहयोग की बात सिखाना है। जो नहीं आते उन्हें बुलाना होगा। मानो कि हमारे हाथ में सत्ता आ गई—जमीन हमारे हाथ आ गई। सत्ता का अधिकार खाली पटेल और बलाटी के हाथ में है, व खाली दो ही हैं। मानो कि वे हमें मान लेंगे। जमीन हमारे हाथ में है, हम जानकार हैं। हम यदि सरकार से बीज बोएँ तो सरकार को कर भी दे दें और थोड़े समय में अधिक काम भी कर लें। हम खेती सिखाएँ तो सहयोग हो खेती एक साथ हो और सहयोग से हो। खेती हाथ में—आ जाने पर हम देखेंगे कि विलों को भी हम सुधार सकते हैं। मैं तो बदलता घना जाता हूँ इसमें मैं तुम जितना ल सकोगी सेना, तुम्हारे लिए यह ब्रह्म वाक्य नहीं है। मेरे लिए यह ब्रह्म वाक्य है। तुम सुविधा के अनुसार समझकर करो।

1. स्वाश्रयी शिक्षा

नई तालीम का अर्थ है उद्योग की मार्फत तालीम देना। यह मूल उद्योग भास-पाम के वातावरण उपज इत्यादि को देखकर चुनना होगा। उदाहरणार्थ जहाँ कपास नहीं उगती वहाँ बाहर से कपास लाकर खादी को तालीम का अरिथा बनाना ठीक न होगा। अगर खादी का उद्योग लेकर नई तालीम स्वाश्रयी सिद्ध की जा सके तो वही बीज दूसरे उद्योगों को भी लागू की जा सकती है। तालीम स्वाश्रयी बनाने का अर्थ यह है कि जैसे आज के सरकारी स्कूलों में लड़के अपने घर से खाना खाते हैं, कपड़ पहनते हैं उसी तरह नई तालीम के स्कूलों में भी लड़कों के खाने पहनने का भार माना पिता पर रहेगा। आज बल के स्कूलों में किताबों और फीस इत्यादि पर जो खर्च होता है वह बच जाएगा शिक्षक अगर आवश्यक वातावरण पैदा नहीं कर सकता तो नई तालीम स्वाश्रयी नहीं हो सकती। अगर वह वातावरण बनाने में और लड़कों की बुद्धि को ओजस्वी बनाने में सफल होता है तो शुरू से

लेकर बाहर तक की नई तालीम में सारा खर्च लड़कों के बनाए हुए कपड़े की कीमत के रूपों में से निकल आएगा।

नई तालीम में किताबों को तो स्थान ही नहीं। रुई, धुनकी, तकली इत्यादि सामान पर शुरू में थोड़ा खर्च करना पड़ेगा उसके बाद तो जो खर्च निकालना होगा वह केवल शिक्षक की तनखाह और आवश्यक स्टेशनरी तथा कोई चपरासी इत्यादि रखना पड़े तो उसका खर्च इतना ही होगा।

मानो कि एक स्कूल में ३० लड़के हैं वे खेत से कपास लाने से लेकर मूत निकालने और कपड़ा बनाने तक की सब क्रियाएँ अपने हाथों से करेंगे। हरेक क्रिया की माफ़त शिक्षक उन्हें ज्ञान देगा जिससे कि उनकी बुद्धि दिन प्रति दिन अधिक ओजस्वी होती जाएगी। परिणाम में वे लड़के खादी की क्रियाओं से नित्य नई मोध किया करेंगे जिससे कि खादी का उद्योग अधिक उत्पादक और मूल्यवान बनता जाएगा।

लड़कों का बनाया हुआ कपड़ा उनके माता पिता मुँह माँगे दाम पर ले जाएँगे। शिक्षक का यह काम होगा कि वह लड़कों के द्वारा उनके माता पिता में जागृनि पैदा करे जिससे कि वे विदेश और मिल के कपड़ों को छुएँ भी नहीं। वस्त्र-स्वावलम्बन और खादी का वातावरण पैदा हो। हमें अपना वातावरण पैदा करना ही होगा। आज जहाँ खादी पहुँची है उसके लिए भी हमें वातावरण पैदा ही करना पड़ा था। परिणाम में आज खादी को कोई उखाड़ फेंक नहीं सकता। वही चीज नई तालीम के बारे में भी कही जा सकती है।

लड़के, हमारे स्कूलों से निकलने के बाद कमाई करने के लायक होंगे हम उन्हें काम देनेका वचन नहीं देते। अगर सरकारी स्कूलों में बड़ा खर्च करके तालीम पाने वालों को भी सरकार नौकरी देनेका वचन देती। मगर हमारे लड़के सरकारी स्कूलों से निकले हुए लड़कों की अपेक्षा अधिक तेजस्वी होंगे, और आमानी से अपने लिए धंधा ढूँढ़ लेंगे।

याद रखना है कि सरकारी मदद के लिए वातावरण पैदा करना पड़ा था। तब तो सत्ता होने हुए भी कुछ कष्ट हुआ था। हमें जो वातावरण

पेदा करना है वह पुनरुद्धार है— जो मिटाया गया है उसको नए सिरे से और नए तरीके से उठाना है और हम उसको स्वराज्य पाने का शान्तिमय तरीका समझने हैं। इस तरह से करना हमें आसान होना चाहिए क्योंकि हमने ग्रामों में सही दृष्टि से तथा सच्चा प्रवेश ही नहीं किया अतएव यह आसान नहीं लगता है। अब नई तालीम चमत्कार ही है और उसमें यह शक्ति नहीं है तो और क्या है ?

बचपन से लडका-लडकी हमारे हाथों में आए और सात वर्ष तक मानी उससे भी अधिक साल तक हमारी मार्फत शिक्षा पाए और फिर भी यदि उसमें स्वावलम्बन शक्ति न आए तो समझना चाहिए कि हम उसका अर्थ पूरा पूरा ग्रहण नहीं कर पाए। जो आधुनिक शिक्षा हमें दी जाती है वास्तव में उसी के कारण हमारे मन में धुंधला होती है कि शिक्षण स्वावलम्बी हो ही नहीं सकता। मेरा बड़ा विश्वास है कि यदि नई तालीम स्वावलम्बी न हो तो शिक्षक वर्ग उसे नहीं समझता। मेरे मजदीर नई तालीम के दूसरे लक्षणों में स्वावलम्बिता उसका एक बड़ा अंग या लक्षण है। अगर यह बात लडके लडकियों के लिए सही है तो प्रेरणा शिक्षण में तो स्वावलम्बिता होनी ही चाहिए। ऐसा मानना कि प्रौढों को शिक्षण की बात ही समझाना मुश्किल है तो फिर मुझे कहना पड़ेगा कि यह पुराना भ्रम है। हमारी नई तालीम प्रौढ तालीम का तीन चार लक्षण सिखाना भी नहीं है। प्रौढ तालीम का अर्थ है कि प्रौढों को जलकी भाषा की मार्फत हम उनको शुद्ध और सामाजिक जीवनका सब शिक्षण दें। अगर यह आसानी से स्वावलम्बी न बने तो मेरी दृष्टि में बड़ा दोष है। यह भूलना नहीं चाहिए कि नए शिक्षण में सम्पूर्ण सहयोग आरम्भ से ही अमल में आना चाहिए। सहयोग का पूरा अर्थ जो जानता है उसके मन में स्वावलम्बिता का प्रश्न उठ नहीं सकता।

1

वस्त्र स्वावलम्बन :

गुड़ियाँ देकर खादी मिनने की सुविधा करनी होगी। थोड़े सालों में खादी के अर्थशास्त्र को समझाना होगा— उद्योग तुम्हारा दाम है। स्वावलम्बन करते हारो तो हारो, करते रहो।

नायकम् ने कहा इन लडकों की मार्फत आसानी से हम खादी बना लेंगे। वह बहुत सस्ती होगी। उसमें सूबीदार ब्ला रहती है, कप्ट नहीं होता। उसके साथ जब प्रौढ़ शिक्षण आता है तो थोड़े सालों में सारे का सारा प्रश्न हल हो जाएगा। कोई खर्च नहीं। सो पहले तो हम उनका अयंगम्य हजम कर लें। इसमें हारने की कोई चीज नहीं है।

बच्चों की शिक्षा :

बापू - हमारा प्रयत्न तो यही होगा कि जितने सड़के हैं सब को हम खींच लें। जो नहीं आते हैं तो समझना चाहिए कि हमारी कोई कमी है। उन्हें या उनके बाप को कोई सालच होनी चाहिए कि हमारे लडके हैं उनका शरीर तगडा हो जाएगा। सम्यक् सीखेंगे। मैं नहीं मानता कि बच्चे तोड़ना फोड़ना सीखेंगे। मैंने बहुत लडकों को सिखाया है परन्तु किसी को तूफान करने नहीं दिया। मैं ऐसी तालीम दूंगा जिसमें विध्वंसक नहीं पर त्रियात्मक त्रिया हो।

इसमें बला होती है। बच्चे जन्म से अच्छे या बुरे नहीं होते। कुछ अलग तो रहता है मगर उसे अच्छा बनाना है। इससे बच्चा पेट में से ही तालीम पाता है। बच्चे के हाथ पैर भी चलते-और हिलते समय कुछ न कुछ करते हैं। वह नहीं जानता कि वह बच्चा क्या करता है लेकिन उसकी हालचाल त्रियात्मक होती है विध्वंसक नहीं। इसी पर प्रौढ़ शिक्षण आधारित है अथवा यही उसका आधार है। प्रौढ़ शिक्षण बाद में आता है। प्रौढ़ा के कारण बच्चा के सस्वार पड़ते हैं। बच्चे ठीक तालीम पाते हैं तो गुरु से ही रचनात्मक कार्य करते हैं।

२ या २॥ साल के लडके लडकियाँ गुरु से हमारे हाथ में आ जाएंगे। उनके हाथ पाँव हमारे बताए जैसे रास्ते इस्तेमाल करेंगे तो वे कहीं तक जाएंगे मैं तो बाँध नहीं सकता। मार से नहीं प्रेम से बढ़ाना है।

शिक्षा :

पहले रंगों की पहचान होगी। अक्षर ज्ञान चित्र से शुरू करें १, २ (गिन्ती) 'अ' 'आ' आदि वर्ण चित्ररूप से सीखें। अक्षर तो चित्र ही होते हैं। तीनों ओर बाद में आएंगे (लिखना पढ़ना इत्यादि)

मगर उस बताना नहीं होगा। एक के चित्र पहले आए तो फिर सब अक्षरचित्रमय हो जाएंगे। जेल में मैंने एक प्राइमरी रीडर लिखा था। आज की तरह में तीन चार बभी नहीं सिखाऊंगा। पहले तो पढ़ना ही हाथ में आएगा। लिखना चित्र से शुद्ध होगा—चित्र कोई तोतेका बनाएगा कोई सूतका बनाएगा। इसके साथ उसकी (बच्चेकी) बुद्धि भी जाती है और पैर भी चलते हैं। उसके लिए सब खेल है। वाम और खेल दो विभाग नहीं है। वह आगे जाता है तो इसी तरह उसकी जिन्दगी खेल या काम बन जाती है। मेरे पास चन्द घटा खेल और चन्द घटा काम में दो विभाग नहीं। मैं बरसों से ऐसा चला हूँ। मुझे बभी रयाल नहीं आता कि अब खलवा समय हुआ। मेरे लिए तो लिखना भी खेल है। बारह वर्ष से ऐसा चलता आ रहा है। आज मैं तो कोशिश करता हूँ कि दोनो लिपियाँ एक साथ सीख लूँगा। यह मेरे लिए कठिन सगे मगर बच्चे को बुरा से सीखना खेल होगा और आगे चला जाएगा तो सब खेल ही खेल होगा। पर लिए सच्ची नई ताजीम यही है कि सबके खेलते खेलते सीखें। पर भाषा सीखने में जितना समय दिया उसका एक हिस्सा समय में दूसरी दस्त लिपियाँ सीख सकत थे।

मॅडम मीटेसरी ने एक भाषा में मेरे लिए कहा था कि मैं जानती हूँ (जितना) उससे अधिक यह (गाधी) जानता है। वह बात सच्ची है।

ग्राम व्यवस्था .

सार्वजनिक कोष (पब्लिक फण्ड)

प्रश्न —सार्वजनिक कोष हैसियत के अनुसार या साधारण चन्दे के तौर पर जमा करना चाहिए ?

बापू —यह (सार्वजनिक कोष के लिए धन जमा करना) अडल्ट वनफ्रेज का सा होगा। उससे भी आगे जाएँ तो कम से कम चन्दा (मिनिमम कन्वेन्शन) रखें। लडके लडकियों को एक पैसा और बडोको एक आना दना है छीर दें। ज्यादा देनेवाले हो तो दें। हमारी शक्ति पैसे पर नहीं। एक एक पैसे की भी बहुत है। करोडो को मिला कर जो शक्ति होती है उसे कोई मार नहीं सकता। वहाँ तो सरकार ने

मकान जप्त कर लिए थे, मैंने कहा जंगल में बैठे रहेंगे। साना लोग दंगे तो ठीक है नहीं तो भूखे मर जाएंगे। नतीजा यह हुआ कि बड़ा कंप बन गया, उनमें सब बड़े आए पर बड़े डरते भी थे। बड़ों के साथ लड़ना भी होगा उन्हें मैंने कहा है कि जिन्दा रहना है तो गरीबों के ट्रस्टी बनकर रहें। उनके पास से सब धन छीन लूं तो जहर बढेगा। उनसे इसी लिए कहता हूँ ट्रस्टी बनो, कमीशन ज्यादा देता हूँ चाहे चौथाई ले लें। उसमें अभिमान है।

माता —बोप (फण्ड) के साथ प्रबन्ध भी होगा ?

बापू — हाँ। उसी में तुम्हारी कला आएगी। ऐसा नहीं कि अंग्रेजों की तरह प्रबन्ध हो। वहाँ हमारा द्वारपाल ही तीन चौथाई खा जाता है। तुम्हारा प्रबन्ध इतना सादा होगा कि उसमें चोरी का मौका कम मिलेगा।



“शहर अपनी हिराजत आप कर सकते हैं। हमें तो अपना ध्यान गाँवों की ओर लगाना चाहिए।” हमें उन्हें उनकी सकुचित दृष्टि, उनके पूर्वग्रहों और बहमों आदि से मुक्त करना है, और इसे करने के लिये हमका और कोई तरका नहीं कि हम उनके साथ उनके बीच में रहें, उनके सुख-दुख में हिस्सा लें और उनमें गिला का तथा उपयोगी ज्ञान का प्रचार करें।

—मो० क० गांधी

1

शिक्षकों को स्वतंत्रता चाहिए

विनोबा

[जबिल भारत नई तालीम समिति की ओरसे सैधाग्राम में तारीख १८-१९ और २० सितम्बर को 'शिक्षकों का प्रशिक्षण' विषय पर एक विचार गोष्ठी आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता श्री ग्रामन्तरायण ने की थी। विचार गोष्ठी में शामिल हुए शिक्षकगण तारीख २० सितम्बर को ऋषि विनोबा से मिलने पटना आश्रम गए थे। उस अवसर पर पूज्य विनोबाजी ने जो विचार व्यक्त किए वे यहाँ दिए जा रहे हैं।]

विनोबाजी —अकराचार्य ने एक सुन्दर वाक्य लिखा है— 'गुरोस्तु मौन व्याख्यानम् । शिष्यास्तु छिन्न सञ्जया'—गुरु ते मौन व्याख्यान दिया और शिष्य छिन्न सञ्जय हो गए। गुरु मौन व्याख्यान नहीं बेंता और बोलता तो शिष्यो को शका उत्पन्न होती। लेकिन मौन व्याख्यान दिया तो सब शकएँ समाप्त हो गईं।

प्रश्न —संपूर्ण क्रांति के विषय में आप क्या सोचते हैं? शिक्षा का उसमें क्या सहयोग हो सकता है? शिक्षक उसमें क्या करें?

विनोबाजी —एक बार डा. जाकिर हुसैन से बाबा की बातें हो रही थी। बाबा न कहा आज हालत यह है कि आज जो तालीम चल रही है वह अगर हम लोगों को नहीं देते हैं तो लोग बेवकूफ हो जाते हैं और अगर वह तालीम देते हैं तो वे बेकार बन जाते हैं। तब उन्होंने कहा, आज की तालीम ऐसी है कि उससे लोग बेकार और बेवकूफ, दोनों हो जाते हैं। तालीम का यह वर्णन उन्होंने किया था।

तालीम के बारे में कहने का कुछ भी बाकी नहीं है। बहुत कुछ कहा है और वह सब प्रकाशित हुआ है, नितानें भी बनी है। जो कुछ बचा है वह करने का है। मेरा ख्याल है, आप सब करनेवाले लोग होंगे

या सुननेवाले हैं? सुनने की ऐसी मजा है कि एक कान से सुन सकते हैं, दूसरे कान से छोड़ सकते हैं। इस वास्ते मैं आशा करता हूँ कि आप सुननेवाले नहीं, करनेवाले भी होंगे।

आज कहा जाता है कि नई तालीम के लिए आज की सरकार अनुकूल है। भगवान जाने कौन अनुकूल है और कौन प्रतिकूल है। मुख्य बात यह है कि आपको सरकार की तरफ देखना नहीं चाहिए। सरकार आएगी और जाएगी। आचार्य रहेंगे। इस वास्ते आपको पॉसिटिविज्म की तरफ, सरकार की तरफ देखना ही नहीं चाहिए। उसकी मदद की जरूरत नहीं है। उसकी मदद माँगनी भी नहीं चाहिए। शिक्षकों को स्वतंत्रता चाहिए। जो स्वतंत्र नहीं हैं वे शिक्षक ही नहीं हैं। वे तो गुलाम माने जाएंगे।

नवर एक में प्रतिष्ठा है माता की। नवर दो में प्रतिष्ठा है पिता की। और नवर तीन में आचार्य की। उपनिषद् ने कहा है—मातृ-देवो भव। पितृदेवो भव। आचार्य देवो भव। इसे आपने भी सुना होगा।

उसमें यह भी आया है कि आचार्य शिष्यों से कहते हैं कि हमारी जो अच्छी चीजें हैं वे लेनी चाहिए और जो अच्छी चीजें नहीं हैं वे नहीं लेनी चाहिए। ऐसा स्वातंत्र्य शिष्यों को, विद्यार्थियों को उपनिषद् ने दिया है। वेद में भी वर्णन है गातुविद्। शिक्षक को गातुविद् कहा है। गातु यानी मार्ग। मार्ग दिखानेवाला। शिक्षाज्ञीचेष्ट गातुविद्। है शिक्षक, तू उत्तम शक्तिशाली, तू मार्गदर्शक है। तू मार्ग दिखा। तो शिक्षक मार्ग दिखाएँ और लोग उस पर चले।

आज क्या होता है? आज सरकार शिक्षा देती है। सरकार सत्याएँ बनाती है मार्ग दिखाती है। बिल्कुल पराधीन हो गए हैं शिक्षक। परिणाम यह हुआ है कि हम उत्तरोत्तर बेकार, गुलाम होते जा रहे हैं।

सम्पूर्ण क्रान्ति के बारे में सवाल पूछा है। सम्पूर्ण क्रान्ति का विचार मुझे अच्छा लगता है। संपूर्ण क्रान्ति में जातिभेद मिटाने की बात है। जातिभेद मिट सक्ता है, उसकी एक शक्ति है। माताहार

बन्द होना चाहिए। मान लीजिए, कोई जैन है, जो जातिभेद मिटाना चाहता है और अपनी लडकी एक हरिजनको या गिरिजन को देना चाहता है। यह हरिजन या गिरिजन मांसाहारी हो तो जैन अपनी लडकी उसके घर नहीं देगा। इस वास्ते यह बात ध्यान में रखनी होगी कि जातिभेद मिटाना हो तो मांसाहार बंद होना चाहिए। अन्यथा संपूर्ण शान्ति या समग्र क्रांति केवल बोलने की बात होगी और उससे कुछ होगा नहीं। मैं उम विचारको पसन्द करता हूँ।

प्रश्न — प्रजातंत्र में जनता और सरकार में तो कोई अंतर नहीं है। इसलिए प्रशासन से मदद न लेना किस हद तक सही है ?

विनोबाजी — प्रजातंत्र में, जनता और सरकार में बहुत अंतर है। होता क्या है ? एक एक पार्टी सामने आती है और कहती है कि हमें वोट दीजिए तो हम आपका उद्धार करेंगे। आजकी यह सरकार दस साल में गरीबी मिटा देगी, ऐसा कहा गया है। तो, आज जो गरीब है, उसे कहो कि संतुष्ट रहो, दस साल में तुम्हारी गरीबी मिटेगी। वह कहेंगा, मैं तो आज ही गरीब हूँ। यह सरकार यह करेगी, वह सरकार वह करेगी। गीता क्या कहती है ? उद्धरेत् आत्मनात्मानम् ॥ अपना उद्धार हमें खुद करना चाहिए। लेकिन आज तो जो आता है, वह कहता है, हमें वोट दो, हमें वोट दो। कोई जनता से यह नहीं कहता कि तुम्हारे उद्धार तुम्हारे हाथ में है। इसलिए गाँव-गाँव को मजबूत बनाना चाहिए। गाँव में सब लोग मिलजुल कर काम करें। गाँव व्यसनमुक्त, अदालतमुक्त हो। गाँव में कोई बेकार न हो। ये सब बातें गाँव में हो। इसलिए गाँव को समझाना चाहिए, तुम्हारा उद्धार तुम्हारे हाथ में है।

प्रश्न — आज की शिक्षा में अध्यात्म को कैसे प्रतिष्ठित किया जा सकता है ?

विनोबाजी — एक सुन्दर उपाय है। लेकिन कोई करता नहीं, सब सुनते हैं। होली के दिन सब कचरा वगैरह जला देते हैं। वैसे तय करो कि हम सारे विद्यार्थी स्कूल छोड़ देते हैं। शिक्षक सारे बेकार बन रहे हैं, ऐसा होगा तो सोचने के लिए बाबा के पास आएंगे कि बाबा,

क्या करना है जर, सब स्कूल-कालेज खाली हो गए हैं। यह उपाय है।
 बाबा तो कहेंगे, छोटे दो स्कूल-कालेज। लेकिन आज बाबा को कौन
 पूछेगा? आज तो पूछेंगे शिक्षामंत्री को।

सब व्यवस्थाएँ गलत हैं। इसलिए मैंने कहा कि एक दिन
 जाहिर कर के सब विद्यार्थी स्कूल छोड़ दें। तो फिर शिक्षा विभाग
 समाप्त होगा और शिक्षा में सुधार होगा। क्या यह हिम्मत है आप
 लोगों की? हिम्मत मर्दानों तो मदते खुदा।

प्रश्न —लेकिन क्या यह अनिवार्य है?

विनोबाजी —यह शिक्षा पद्धति सुधारने का एक उपाय है।
 अनिवार्य नहीं है। मुख्य बात यह है कि शिक्षा स्वतंत्र चाहिए। वृंसा
 आप रखिए शक्तिपूर्वक युक्तिपूर्वक सरकार के सामने कि शिक्षा स्वतंत्र
 हो, सरकार पर अवलंबित न हो।

प्रश्न —शिक्षा के द्वारा जागतिक शान्ति एक भारतीयके नाते
 इसे कैसे समझे?

विनोबाजी —भारत में पन्द्रह विकसित भाषाएँ हैं २०० अविकसित
 भाषाएँ हैं। जब मैं मध्यप्रदेश के आदिवासी क्षेत्र में घूमता था तब एक
 मभा में लोगों से पूछा, क्या गांधीजी का नाम आप लोगों ने सुना है?
 तो उन लोगों ने पूछा कौन गांधीजी? गांधीजी कौन उनको पता ही
 नहीं था। फिर पूछा जीजम आईस्ट का नाम सुना है? तो उन्होंने
 गुरन्त कहा सुना है। क्या कारण हुआ जीजस आईस्ट को जानने का?
 कारण उनको किताब मिली है। दो-सौ अविकसित भाषाओं में बाइबिल
 का अनुवाद हो गया है। इतना पराक्रम उन लोगों ने किया। हम सारे
 शिक्षकों ने मिलकर कौन-सा पराक्रम किया है? सारे आदिवासियोंके
 लिए आपने क्या दिया है? यह सारी सोचने की बात है। शिक्षकों का
 गाँव-गाँव में जाना चाहिए और गाँव गाँव को आजाद करना
 चाहिए। वहाँ गाँव की सभा बने, गाँव में कोई बेकार न रहे, गाँव
 की शिक्षा गाँव के हाथ में हो, गाँव व्यसनमुक्त हो, अदालतमुक्त हो।
 यह काम शिक्षक करें।

मैंने कहा था गाँव गाँव से जो टैक्स वसूल करते हैं, वह अनाज में वसूल हो। आज क्या होता है? अनाज गाँववालों के हाथ में पैसा व्यापारियों के हाथ में। व्यापारी सस्ता खरीदते हैं महंगा बेचते हैं। व्यापारियोंका घधा चलता है और सरकार को पैसा मिलता है। अगर सरकार गाँववालों से टैक्स के रूप में अनाज ले तो रेल्वे आदि बमंचारियों को तनखा का एक भाग अनाज में दे सकेंगी। सरकार नहती है कि हम अनाज रखेंगे तो चूहे खा जाएँगे। मैं कहा बिहिन्याँ रखो। टैक्स अनाज में लाने की बात अव्यवहार्य नहीं है। चीन में यह बात चल रही है। यहाँ आप करवाइए। बड़ी चीज है। इतना भी आप करेंगे तो बड़ी बात होगी। गाँव आजाद होंगे। गाँव के लिए सावा ने सदा दिया है यों मे— 'मक्खन खाओ पपड़ा बनाओ।'

×

बुद्ध के साथ बिपरीत रहने से ही गाँवाएँ सजीव बनी रह सकती हैं। बुद्ध हैं प्राचीन परम्परा और गाँवाएँ हैं नव सत्कार। हम नव सत्कार ग्रहण कर लंछित प्राचीन परम्परा से जुड़ रहे हैं। परिणामस्वरूप एक शास्ता भा बना रहेगा और प्राचीन परम्परा भी खटित नहीं होगी।

—विनोबा

देश की नई शिक्षा पद्धति

मोरारजी देसाई

मैं देश की शिक्षा पद्धति को लेकर कुछ अनिवार्य परिवर्तन करने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। मैंने प्रधान मंत्री का उत्तरदायित्व लेने के बाद 'राष्ट्रीय शिक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्' और 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' के प्रमुख अधिकारियों के साथ सलाह-मशविरा किया है। हम अपनी शिक्षा पद्धति में कुछ बुनियादी फेरफार करने पड़ेंगे और सौ भी एकाध वर्ष में ही। आज की हमारी शिक्षा-व्यवस्था का देश को गरीब लागो और गौबो में रहने वालो के साथ मेल नहीं बैठता इसे सभी स्वीकार करते हैं। इसलिए कोई न कोई राष्ट्र-प्राप्ति-ध्यय सामन रखकर हमें अपनी व्यवस्था पर विचार करना पड़ेगा। जो पद्धति चली आ रही है, यदि उसमें बुनियादी परिवर्तन व प्रयत्नोमें ज्यादा देर होती है तो देश का बहुत नुकसान होगा। इसके साथ ही यह भी देखना होगा कि हमारी गिन्या-व्यवस्थाका परिणाम समाज की विपमताओं को बढ़ाना न बने। आज की पद्धति उन विद्यार्थियोंको ध्यान में रखकर रूढ़ हुई है जिन्हें अनेक सुविधाएँ प्राप्त हैं। आवश्यक है कि राष्ट्र के विकास के लिए गिन्या गुरु से अन्त तक सभी तबका व लोगो के लिए किसी न किसी उत्पादक प्रवृत्ति के साथ जुड़ी हो। यदि ऐसा नहीं होता है तो शिक्षा पद्धति में परिवर्तन भी नहीं हो सकता—गांधीजी ने इस विषय पर मौलिक चिंतन किया और दुनिया के सामन बुनियादी तानीमकी रूपरेखा रखी। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका, साबरमती, आश्रम, गुजरात विद्यापीठ सेवाग्राम आदि स्थानोमें इसके सफल प्रयोग किए और बाद में सारे देश के सामने इसे रखा। १९६५ में मैंने भी इस पद्धति पर जोर दिया था और शिक्षाविदोने उसे स्वीकार भी किया था। किन्तु सरकारी अथवा गैरसरकारी सस्थाओं ने उस पर जो अमल किया उस बहुत ढीला कहा जाएगा हमने संविधानकी

दृष्टिमें प्राथमिक शिक्षाको जिस तरह सब जगह फैलाना था उसकी ओर भी ध्यान नहीं दिया। प्राथमिक शिक्षा की समस्या को किस तरह से हल किया जाए इसपर प्रजातंत्र की सपसत्ता का आधार है। हमन सात वर्ष की प्राथमिक शिक्षा के सांख्यिक कार्यक्रम को सफल बनाने के बदल नहीं पद्धति के नाम से दस वर्ष की शिक्षा का विकास करने की कोशिश की ओर नतीजा यह हुआ कि प्राथमिक शिक्षा को माध्यमिक शिक्षा के पोषक के रूप में जिस तरह ग्रहण नहीं किया जा सकता उसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा को उच्च शिक्षा के पोषक रूप में ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो ऐसे अधिकांश विद्यार्थी जिन्हें आगे नहीं पढ़ना है उनका हित नहीं सधने पाता। प्राथमिक शिक्षा का काम देशवासियोंको अपनी-अपनी मातृभाषा में व्यापक रूप में नागरिक शिक्षण देना है। सात वर्षमें एवदम अनिवार्य, प्राथमिक शिक्षा सात वर्ष के पूर्व की जा सकती है। यह सबसे पहला काम है। इस दृष्टि से सार देश के पाठ्यक्रम को एक जैसा बनाना जरूरी नहीं है। प्राथमिक शिक्षा में मिश्रित स्कूल का जो भेद रखा गया है उसे भी हटा देना चाहिए और एक सात वर्ष की समूची शिक्षा को स्वरूप पर विचार किया जाना चाहिए जिसे हम सच्चे रूप में प्राथमिक कह सकें। देश के कुछ हिस्सों में आठ वर्षों की प्राथमिक शिक्षा है जब कि कुछ जगह सात वर्ष की है। यह असंगति भी दूर की जानी चाहिए। यह काम करने के लिए कन्द्रीय सरकार का मुहताज रहना आवश्यक नहीं है। राज्य सरकारों और सांख्यिक संस्थाएँ अपने अपने स्थानीय साधनों की दृष्टि से इस प्रकार की पद्धति अपना सकती हैं। प्राथमिक शिक्षा के दौरान छुट्टियों की जो आज की प्रथा है उसे छोड़कर उराका मल जीवन को साथ बँटाया जाना चाहिए। जैसे छुट्टियाँ ऐसे समय पर ही दी जाएँ जब खेती का काम जोड़े पर चल रहा हो। उस समय विद्यार्थी अपने गाँवों में जाकर उत्पादक श्रम में हिस्सा बँटा सकते हैं और ऐसी योग्यता प्राप्त कर सकते हैं जो शाला में दे सकना सहज ही सम्भव नहीं होता। यदि छुट्टियों की पद्धति में परिवर्तन हो जाए तो विद्यार्थी अपनी जीवन व्यवस्था से जुड़ रह सकते हैं।

— निरक्षरता हमारी दूमरी गम्भीर समस्या है। हमारे देश में चौदह से पैंतीस वर्ष तक की अवस्था के कोई तेईस करोड़ निरक्षर हैं। यो स्वीकार किया जाना चाहिए कि इन निरक्षर लोगों में पढ़े लिखे लोगों से समझ कम नहीं है, ज्यादा ही है। फिर भी निरक्षरता को दूर करना है और इसके लिए अधिक से अधिक दस वर्ष का समय लगना चाहिए। देश में लगभग साठे तीन लाख शिक्षक हैं और विद्यार्थियों की संख्या दस करोड़ है। सेना पर होने वाले खर्च के बाद शिक्षा पर होने वाले खर्च का मन्तर आता है। प्रतिवर्ष इस पर पच्चीस सौ करोड़ रुपये के लगभग खर्च किया जाता है— यह छोटा-मोटा खर्च नहीं है। यदि इतनी जवदस्त राष्ट्रीय सम्पत्तिका खर्च करनेवाला पढ़ा-लिखा तबका इसके बदले में कुछ भी देने लायक न बने तो राज्य या समाज की ओर से इस खर्च का समर्थन किस प्रकार किया जा सकता है ?

शिक्षा पद्धति को सामान्य लोगों के जीवन के साथ जोड़नेके लिए आवश्यक है कि उन्हें मूलमूल और मीघे-मादे जीवनशिक्षा देनी चाहिए। पूठे समृद्धि की लालसा पढ़े लिखे वर्ग को सामान्य जनता से अलग कर देनी है। इसलिए शिक्षा का स्वरूप ऐसा हो कि शिक्षित व्यक्ति समाज के लिए आवश्यक चीजों का उत्पादन करने के योग्य बने। इसमें जीविका की अलगसे चिन्ता करना आवश्यक नहीं रहेगा और उत्पादन में वृद्धि के माय-माय सामाजिक रुमता भी बढ़ेगी।

जीवन व्यवस्था के साथ शिक्षा का मेल तभी बैठ सकता है जब हम उसे विकेंद्रित करें। सरकार उसमें कम से-कम दखल दे प्रदेश अपनी-अपनी आवश्यकता के अनुसार अपनी शिक्षा पद्धति चलाए। इतना ही नहीं हर राज्य के अलग-अलग अंचल भी शिक्षा दते हुए अपनी आवश्यकताको दृष्टि में रखें।

गांधीजी ने जब यह कहा कि शिक्षा में उत्पादक श्रम का समावेश होना चाहिए तो उनका तात्पर्य स्थानीय समाज की आवश्यकताओं को पूरा कर सकने वाली शिक्षा के विकास में था। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था ज्यादा से ज्यादा हमारी चौथाई आबादी को छूती है। पचहत्तर प्रतिशत आबादी से तो उसका कोई सम्बन्ध ही नहीं आता। आगामी दस वर्षों

में इस अनुपात की और कुछ नहीं तो उलट तो देना ही चाहिए। प्राथमिक शिक्षण और विद्वत् विद्यालय के स्नातक वत्तन्व्य दृष्टि से आगे आगे प्रौढ शिक्षण का काम आगे बढ़ाएँ। इस तरह वे प्रति वर्ष दो करोड़ निरक्षरों को साक्षर कर सकते हैं। उन्हें यह उत्तरदायित्व उठाना ही चाहिए। प्रौढ शिक्षा से विभिन्न व्यवसाय की कुशलता बढ़े इसे ही देगना है। इसी तरह जिन्होंने अपना पढ़ना बीच में ही बन्द कर दिया है उन्हें भी घर बैठे आगे पढ़ने की सुविधा जुटानी चाहिए, नहीं तो अनगढ़ लोग धीरे धीरे अपढ़ या निरक्षर हो जाते हैं। मुझे बताया गया है कि यदि चौदह वर्ष की उम्र तक प्राथमिक शिक्षण दिया जाना हो तो १९८५ तक आज की साठे छह करोड़ विद्यार्थियों की सरया को बढ़ाकर साठे आठ करोड़ तक ले जाना है। इसमें ऊपर के वर्षों में आज डेढ़ करोड़ विद्यार्थी हैं। इसे अगले दस वर्षों में साठे चार करोड़ तक ले जाना है। इसका अर्थ यह हुआ कि आगामी दस वर्षों से हर वर्ष में ५२ लाख नए विद्यार्थी प्राथमिक शालाओं में आने चाहिए। आज पिछले तीस वर्षों की औसती २४ लाख से अधिक नहीं है। और पिछले तीस वर्षों में तो वह ११ लाख से भी कम हो गई है। ये आंकड़े हमारी प्राइमरी शिक्षा की गंभीर समस्याको सूचित करते हैं। यह स्पष्ट है कि इतनी जबरदस्त सरया के लिए स्कूलों का खोला जाना कठिन है, इसलिए जरूरी है कि खती और गृह उद्योग भाँति करते हुए बालिका को वादिक शिक्षण का लाभ भी दिया जाए। और इसी प्रकार हम अपनी विशाल जनसरया को निरक्षर बने रहना बचाएँ। इस सन्दर्भ में लड़कियाँ के शिक्षण पर और भी विशेष ध्यान देना पड़ेगा।

प्राथमिक शालाओं में पब्लिक स्कूल नाम से कुछ संस्थाएँ चल रही हैं। यह असल में मुट्ठीभर भद्र कह जाने वाले समाज की शालाएँ हैं। इसलिए गरीब माता-पिता भी इनके कारण एक निरर्थक होठ में पड़ जाते हैं। जरूरी है कि सात साल का प्राथमिक शिक्षण सच्चे अर्थ में पब्लिक अर्थात् सार्वत्रिक किया जाना चाहिए। डा. कोठारी आपोग ने कॉमन स्कूल पर अमल करने की बात नहीं है। नगरपालिकाएँ या पंचायतें अपनी पाठशालाओं में जिन साधनों से शिक्षा की व्यवस्था करती

हैं उनके मुकाबले में कई गुना समृद्धि माधनो के उपयोग के द्वारा पब्लिक स्कूल देश में सामाजिक विषमता को बढ़ाते रहते हैं। इसलिए पब्लिक स्कूलोंकी व्यवस्था कम से कम प्राथमिक शिक्षण की हद तक समाप्त कर देनी चाहिए। १९६५ में मैंने यह बात शिक्षा आयोग के सामने कही थी। हमारा तथ्यांकित शिक्षित वर्ग इस भेदभाव को समाप्त करने का विरोध करता है। वह भूल जाता है कि शिक्षा की खूबी गुण-धत्ता पर आधारित है। शिक्षा देने के साधनों पर नहीं।

अलग से बालमन्दिर चलाने के बजाय प्राथमिक शालाओं में ही पूर्व प्राथमिक वर्ग चलाए जाने चाहिए। हमारा देश बाल मन्दिरों का खर्च अलग से उठाने की हालत में नहीं है। माध्यमिक शिक्षण की हद तक ग्यारहवें, बारहवें वर्गों में पाठ्यक्रम की विविधता और अलग-अलग व्यावसायिक विषयों को रखना जरूरी है। किन्तु यदि हम इस दृष्टि से ग्यारह बारह वर्ग बना डाल तो वह एक बड़ा बोझ बन जाएगा। माध्यमिक शिक्षण का उद्देश्य कोई एक व्यावसायिक शिक्षण होना चाहिए। इसके लिए अलग अलग व्यवसाय की शिक्षा मस्याओं का खोलना जरूरी नहीं है। सामान्य शिक्षा चलाने वाली संस्थाओं में भी विभिन्न व्यवसायों का तत्व बढ़ाते चले जाएँ तो यह ध्येय साधा जा सकता है।

विश्वविद्यालय में पढ़ना सबके लिए जरूरी नहीं है। इसे ध्यान में रखकर नौकरियाँ देते समय विभिन्न कसौटियाँ सामने रखनी पड़गी। हर जवान कुछ इस तरह का काम कर सके कि वह अपने काम के द्वारा अपनी आवश्यकता के परिमाण में वेतन भी प्राप्त करे। बरोहों निरक्षरोंमें प्रौढ शिक्षण का फैलाव करते हुए हम उन्हें तीन वर्षों तक कोई व्यवसाय विशेष भी सिखाएँ। यदि इस बीच में उसे कोई छोटी-मोटी नौकरी भी मिल जाती है तो वह उसे स्वीकार कर सकता है। इस तरह तरुणों में बेकारी का भय समाप्त करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बेकारी के भय में आज हमारी तरुण शक्ति निराशा के भंते में उतरती जा रही है। विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को चाहिए कि वे कम से कम छह महीने किसी धर्मिक समाज या गाँव में जाकर कोई काम सीखें। और वह भी अपने शिक्षण का अंग मान कर। राष्ट्रीय सेवा योजना के

द्वारा गरीब और पिछड़े हुए ग्राम-विकान के प्रयत्न चल रहे हैं। किन्तु वे पूरे नहीं पड़ते। वर्ष के अन्त में कोई पन्द्रह दिन का क्षिविर लगाकर राष्ट्रीय सेवा योजना मान लेती है कि अनिवार्य पूरा हो गया। इसमें देश के विकास की दिशा में कोई बड़ा परिणाम सामने नहीं आता। आवश्यक यह है कि अग्र विश्वविद्यालय का हरेक स्नातक जिस शहर में शिक्षा ग्रहण कर रहा हो उस शहर के बाग़मानों में काम करता हुआ अपने धिपयों का अध्ययन करे और श्रमजीवी वर्ग स्त्रियों आदि में मजदूरी करते हुए किसी उत्पादक प्रवृत्ति के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करे। और प्रौढ़ शिक्षण सार्वजनिक स्वास्थ्य, विभिन्न उद्योगों आदि के द्वारा बहुत अच्छे ढंग से लागू किया जा सकता है। विश्वविद्यालय की शिक्षा को जो एक सामाजिक प्रतिष्ठा मिल गई है, यदि हम उसमें शारीरिक श्रम को जोड़कर बुनियादी परिवर्तन नहीं करते तो नीचे की पाठशालाओं में भी उस तत्त्व को दाबित करना मुश्किल हो जाएगा। हमारा आज का शिक्षा जगत 'ऊर्ध्वमूलमधः शाखा' की स्थिति में है। विश्वविद्यालय की परम्परागत पोथी-पुराण शिक्षण व्यवस्था अविलम्ब बदल दी जानी चाहिए।

परिवर्तन की प्रक्रिया को तो तत्काल ही प्रारम्भ कर दिया जाना है। हमने १९६७ में स्वीकार कर लिया था कि सारी दुनिया में शिक्षा मातृभाषा में दी जाती है तब भी विश्वविद्यालय तब की शिक्षा मातृभाषा में देंगे और इन काम को १९७७ तक पूरा कर लेंगे। मुझे बताया गया है कि कोई सत्तर विश्वविद्यालयों ने इस मिश्रान्त पर अमल भी किया है, फिर भी उसकी गति मंद है जो तेज की जानी चाहिए। तद्विषयक सेवा को समाप्त करके एकाध बरस में ही माइंस टेक्नालाजी आदि शारीरिक विद्याशाखाओं पर इसे लागू कर दिया जाना चाहिए। यदि हम सामान्य जनता को साइंस और टेक्नोलॉजी का लाभ देना चाहते हैं तो यह मातृभाषा के माध्यम से हो सकता है। भारतीय धर्म परायण समाज में विज्ञान और धर्म परस्पर विरोधी न होकर एक-दूसरे के पूरक हैं। यदि विज्ञान को आध्यात्मिक शक्ति का सहारा नहीं मिलता तो वह मनुष्य के लिए उपयोगी नहीं बनता। इसलिए गरीब और पिछड़े

हुए लोगों की दृष्टि से भी विज्ञान की खोज और उसे प्रसारित करने के तरीके महत्वपूर्ण गिने जाएँ। ग्राम विकास के अनुरूप टेक्नालाजी को विकसित करना प्राथमिक कर्तव्य बन जाता है।

शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप का मैं शुरू से विरोधी रहा हूँ। राज्य को चाहिए कि वह विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता प्रदान करे किन्तु विश्वविद्यालयों को भी चाहिए कि वे इसका उपयोग पूरे संयम और उत्तरदायित्व से करें। यदि राज्य हस्तक्षेप करता है तो उसका विरोध होना चाहिए। किन्तु स्वायत्तता के नाम पर विश्वविद्यालय भी राष्ट्र की जरूरतों की अनदेखी नहीं कर सकते। इसी प्रकार शिक्षकों को भी चाहिए कि वे अपने काम की ओर विशेष ध्यान दें। विश्वविद्यालयों को राजकीय हस्तक्षेप से मुक्त रखने का यह मतलब नहीं है कि जिस व्यक्ति को राजनीति में दिलचस्पी हो और जो शिक्षा को भी सच्चे मन से अपना क्षेत्र मानता हो उसे विश्वविद्यालय के काम काज में हाथ बँटाने की गुंजाइश नहीं है। शिक्षित वर्ग में राजनीतिक और राजनीति-विहीन व्यक्ति जैसा कोई भेद नहीं है। मुख्य बात विश्वविद्यालय का सूत्र संचालन करने वाले लोग किसी राजकीय पक्ष में हैं या नहीं—न होकर यह है कि वे साधन-शुद्धि में विश्वास करते हैं या नहीं। प्रजातंत्र को अछूत मानना अवांछनीय है—इतना ही नहीं वह हानिकारक है। राजकीय पक्ष अपनी विचारधारा विद्यार्थियों तक पहुँचाएँ, यह समझा जा सकता है। मुख्य बात कि विचारधारा किम पद्धति से मर्यादा में रहकर पहुँचाई जा रही है, इसी पर ध्यान रखना है। सत्तारूढ़ दलों को समझना चाहिए कि विश्वविद्यालयों के संचालक सर्व सामान्य नियमों का उल्लंघन किए बिना राजनीतिक विचारों का प्रचार होने दे सकते हैं। किन्तु वे किसी राजकीय आन्दोलन में नहीं पड़ सकते। नियमानुसार सत्पात्रह करने का अधिकार सबको है, किन्तु उसका मनमाना उपयोग नहीं होना चाहिए और न इस तरह से होना चाहिए कि वातावरण में दोष या हिंसा फैले।

मेरी स्वीकार करता हूँ कि शिक्षा संस्थाओं और शिक्षा के दैनंदिन कार्य में शिक्षकों का हाथ होना चाहिए। किन्तु सारा का सारा संचालन

उन्ही के हाथ में हो यह भी हितकारी नहीं है। समाज के नागरिक और शिक्षक इस दिशा में हाथ बँटाएँ। आज राज्य शिक्षकों के वेतन और सेवा की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है। इसके बाद शिक्षकों का काम शिक्षा को तेजस्वी और उपयोगी बनाकर उसे अधिकाधिक इन्हीं दिशाओं में ले जाना है। जीवन की बुनियादी जरूरत पूरी हों, इतना तो वेतन हर शिक्षक को मिलना ही चाहिए। किन्तु अगर वे समृद्ध समाज से होड़ लेने लगे तो वह कैसे बनेगा। शिक्षकों के लिए विचार की स्वतन्त्रता आवश्यक है जिससे वे निर्भय होकर अपनी बात लोगों के सामने रख सकें। किन्तु अगर वे शिक्षा की संस्था को संसद या विधान सभा सरीखा प्रजातन्त्रीय रंगमंच बनाने का प्रयत्न करें तो उसे भी उचित नहीं माना जाएगा। हम प्रजातन्त्र के बाहरी स्वरूप को लेकर इतना उलझ गए हैं कि उसकी आत्मा हमारी आँखों के आगे से ओझल है। हमारे शिक्षण-संस्थान प्रजातन्त्र की आत्मा को समझने के संस्थान है। उसके बाहरी स्वरूप पर अटना अनावश्यक है।

आज हमारा अधिकाधिक ध्यान गाँवों की ओर रहे, हम निरक्षरता निवारण नरे, नगाबन्दी के विचार को फेंकाएँ, आदिवासियों और ग्रामोद्योगों का विवास करें—यही हमारी आज की शिक्षा-दृष्टि होनी चाहिए। हम इसी प्रकार गांधीजी के स्वप्न के ग्राम स्वराज्य को संकल्प-पूर्वक सिद्ध करें।

[१८ अक्टूबर की गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में दिए हुए वीक्षात भाषण के कुछ अंश]



गांधीवादी योजना की रूपरेखा

श्रीमन्नारायण

यह बात साफ तौर पर स्वीकार कर ली जानी चाहिए कि हमारी आर्थिक योजना को अब तक गांधीवादी आधार पर एक बार भी तैयार नहीं किया गया। पिछले तीस वर्षों तक महात्मा को हम राष्ट्रपिता कहकर पुकारते रहे लेकिन उसके आदर्शों और विचारों को हमने योजनाबद्ध विकास के एक अंग के तौर पर कार्यक्रम में उतारने की कभी कोशिश नहीं की। जनता सरकार असल में पहली बार नये भारत के निर्माण में गांधीवादी सिद्धान्तों की मदद लेने के लिए कृत-संकल्प हुई है। मुझे उम्मीद है कि ये लोग इस काम को बिना किसी पूर्वाग्रह के एक मिशन के तौर पर करेंगे।

यहाँ पर राष्ट्रीय अथ व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए कुछ दिशा निर्देशों का उल्लेख उपयोगी होगा जिन्हें छठी योजना बनते समय सरकार ध्यान में रख सके। यह ता स्पष्ट ही है कि गांधीजी के विचारों के अनुरूप बनी आर्थिक योजना में कृषि के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। यद्यपि हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि के विकास की आर्थिक प्रगति का आधार बताया जाता रहा, लेकिन सचार्ई यह है कि कृषि, सिंचाई, पशु पालन, डेरी उद्योग तथा कृषि उद्योगों आदि को उनकी जरूरतों को देखते हुए बहुत कम पैसा मिला। भूमि सुधारों पर भी रुक-रुक कर और बड़े ब्रमन से अमल हुआ। और इसका नतीजा यह हुआ कि छोटे किसान और भूमिहीन मजदूरोंको विकास का पूरा फायदा नहीं मिल सका।

भोजन चूँकि जीवन की सबसे आवश्यक वस्तु है, अतः भारतीय कृषि को देश के विभिन्न भागों की पोषक आहार सम्बन्धी जरूरतों को

पूरा करने नायक पर्याप्त अन्न पैदा करना चाहिए। इस लिहाज से अन्न, दालों तथा मोटे अनाज के मामले में भी अन्तर-क्षेत्रीय विषमताओं को योजनाबद्ध तरीके से दूर करना होगा। पिछले दो दशक का अनुभव हमें बताता है कि इस सिलसिले में अन्तर-क्षेत्रीय व्यापार और परिवहन के विकास के बावजूद हर क्षेत्र या उपक्षेत्र की खाद्यान्नों की जरूरत को पूरा नहीं किया जा सका। खाद्यान्नों के अलावा लोगों को सतुलित आहार उपलब्ध कराने के सवाल से दूध, फल और सब्जियों के उत्पादन की तरफ भी ध्यान देना होगा।

विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में छोटी सिंचाई योजना पर और अधिक ध्यान दिये जाने की जरूरत है। इसके अलावा अगले पाँच सालों में भारत के सभी गाँवों में पीने के पानी को उपलब्ध करवा दिया जाना चाहिए। मिट्टी को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अत्यधिक खाद में रासायनिक खाद को ठीक तरह से मिलाया जाए। खेती में अति-मशीनीकरण के बजाय प्रति एक पैदावार बढ़ाने के लिए परम्परागत औजारों और विधि में आवश्यक सुधार के प्रयत्न किये जाने चाहिए। कृषि क्षेत्रों में सहकारिता आन्दोलन को और अधिक व्यापक बनाने के लिए छोटे तथा मध्यम किसानों को और बड़ी तादाद में उनमें शामिल किया जाना चाहिए। सहकारी खेती को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। पर जमीन को सहकारी खेती के दायरे में लाने के लिए कोई जोर जबरदस्ती न की जाए। खाद्यान्नों तथा पशुओं के हमारे उत्पादन में वृद्धि के लिए मिश्रित उपज की जानी चाहिए। लोगों की प्राथमिक जरूरतों को पूरा करने के सवाल से हर क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गाँव पंचायतों को पर्याप्त अधिकार दिये जाने चाहिए ताकि वे हर गाँव या गाँवों के समूहों में फसलों सम्बन्धी कोई योजना बना सकें।

भूमिहीन मजदूरों को ऐसे सहकारी श्रमिक संगठनों के रूप में संगठित किया जाना चाहिए जो अतिरिक्त श्रमशक्ति को खेती के अलावा गाँव में ही कृषि उद्योगों में तलाश सकें। स्थानीय जरूरत के आधार पर ईंधन और कृषि औजार बनाने के लिए आवश्यक लकड़ी जुटाने की खातिर जंगलों की खेती का विश्वास किया जाना चाहिए। गाँवों में सार्व-

जनिक स्वास्थ्य के कार्यक्रम के तौर पर आवश्यक जड़ी बूटी उगाए जाने के काम को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई, खाद रोशनी, ऊर्जा की पर्याप्त पूर्ति के ख्याल से बड़े पैमाने पर गोबरगैम के सयंत्र लगाए जाने चाहिए। जैसा कि विनोबाजी ने सुझाया है लगान को साधान्न की शक्ल में वसूल किया जाना चाहिए ताकि उनका एक भंडार बनाया जा सके। अलाम कर जोतो को लगान से छूट दे दी जानी चाहिए। जमीन की मिल्कियत के दस्तावेजों को सुधार कर उन्हें बिना जरा भी देर किए ठीक कर लिया जाए।

गाँवों के सम्पूर्ण विकास के ख्याल से पशुपालन और डयरी उद्योग के विकास की वैज्ञानिक याजना का होना अत्यन्त आवश्यक है। असल में कृषि भारतीय अर्थ व्यवस्था की रीढ़ है और पशु पालन कृषि की रीढ़ है। सदियां तक गाय हमारे गाँवों की खुशहाली का मूलाधार रही हैं। उसकी वजह यही है कि वह न सिर्फ हमें दूध देती है बल्कि हमारी खेती के लिए मजबूत बल भी देती है। भारत के विभिन्न इलाकों में इसी तरह के दुहरे उपयोग के पशुधन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। हमें सफर गाँवों के जरिए अधिक दूध पैदा करने की हडबडी में स्वस्थ बैलों को बढ़ाने की जरूरत को भूल नहीं जाना चाहिए। नई तथा ऊँच जमीन को तोड़ने लिए ट्रैक्टरों का इस्तेमाल किया जा सकता है पर अभी दसियों बरस तक छोटे किसानों को जो आबादी का काफी बड़ा हिस्सा है मजबूत बैलों और बहुत कृषि औजारों पर ही निर्भर रहना होगा। जापान तक में गाय तथा बैल तेजी से बड़ी मशीनों की जगह लेते जा रहे हैं।

कृषि और पशुपालन के अलावा गाँव की अर्थ-व्यवस्था को मजबूत बनाने और लोगों को भरपूर रोजगार देने के लिहाज में कृषि से पैदा हुए कच्चे माल पर आधारित ग्रामीण तथा कुटीर उद्योग भी बहुत जरूरी हैं। योजना आयोग की एक गणना के अनुसार अगर एक आदमी गाँव छोड़कर शहर में चला आए तो उसे सार्थक काम तथा रहने की साधारण सुविधाएँ देने में पचास गुना अधिक खर्च आता है। अतः यह जरूरी है कि गाँवों से शहरों की तरफ जाने की वृत्ति को रोका जाए।

यह काम निजी या सहकारी आधार पर कृषि उद्योगों को विकसित करके और उसमें उन्हें काम देकर ही किया जा सकता है। पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना में ग्रामोद्योगों के उत्पादन के क्षेत्र निश्चित करने की जो बात कही गई है उस आधार पर उन्हें बड़े उद्योगों की असीम प्रतियोगिता के विरुद्ध संरक्षण दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए कपड़े के मामले में एक निश्चित किस्म से नीचे खादी का ही उत्पादन बढ़ाना चाहिए, खाने के तेल की पेराई, गाँव की पानी में ही होनी चाहिए, चप्पल तथा देशी जूते गाँव के मोची द्वारा ही बनवाए जाने चाहिए। गूड़, कपड़ा, घान-कुटाई, भूसा अलग करने तथा दाल बनाने के ग्रामोद्योगों को भी इसी तरह संरक्षण दिया जाना चाहिए। मकानों की सुविधा बढ़ाने के लिए गाँवों में ईंट और खपरैलों के उत्पादन को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित करना चाहिए।

इसका मतलब यह नहीं है कि कृषि उद्योगों को पिछड़ी हुई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। गांधीजी ग्रामीण कारीगरों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए आधुनिक विज्ञान और तकनीकी के प्रयोग के हिमायती थे। लेकिन वे यह जरूर चाहते थे कि पूँजीगत तकनीक और स्वचालित मशीन के देशों में अधिकतम उत्पादन और पूर्ण-रोजगार नहीं पैदा होने देना चाहिए। दुनिया के देशों में अधिकतम उत्पादन और पूर्ण रोजगार दोनों लक्ष्य पाने के लिए आज दुनिया भर के बड़े अर्थशास्त्री 'मध्य दरजे' या 'उपयुक्त टेक्नालाजी' की बात करते हैं। अतः यह नहीं समझना चाहिए, कि छोटी मशीन आर्थिक आयोजना के लिहाज से व्यावहारिक नहीं हैं। गांधीजी यात्रिव कुशलता और आर्थिक कुशलता में फर्क करते थे। यह हो सकता है कि बड़ी मशीन यांत्रिक रूप से अधिक कुशल हो पर वह आर्थिक रूप से अकुशल साबित होती है। चूंकि वह श्रमिकों की छुट्टी कर देती है और इस तरह समाज में बेरोजगारी या अर्द्ध बेरोजगारी जैसी घुराहियाँ पैदा हो जाती हैं; इसलिए सरकार का यह पहला कर्तव्य हो जाता है कि यह अपनी अर्थनीति के बुनियादी सिद्धान्त के रूप में ख़दी और कृषि उद्योगों को आवश्यक संरक्षण दे।

ऐसी बात नहीं है कि महात्मा गांधी बड़े उद्योगों या बुनियादी उद्योगों के बिल्कुल खिलाफ रहे हों। 'गांधी वादी आयोजना' में मैंने भारतीय अर्थ-व्यवस्था को मजबूत करने के स्याल से कुछ रक्षा तथा बुनियादी उद्योगों का प्रावधान किया था। गांधीजी इसके बारे में चाहते थे कि इस तरह के उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में हों। ताकि उनके माध्यम से उद्योगपतियों के सम्भावित शोषण से बचा जा सके। उनका कहना यह था कि साधारण लोगों की जरूरत की चीजें पैदा करने वाले कारखानों को विकेंद्रित आधार पर होना चाहिए।

भोजन और कपड़े के अलावा आदमी की जिन्दगी में सबसे जरूरी चीज होती है उपयुक्त निवास। पंचवर्षीय योजनाओं में शहरी क्षेत्रों में तो कम और मध्यम आमदनियों वाले लोगों के मकान बनाने की व्यवस्था की गई है पर उनमें ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों के निर्माण की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए छठी योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते और मजबूत मकान बनाए जान की व्यवस्था होनी चाहिए। इस सन्दर्भ में यहाँ गांधी जी की कल्पना के आदर्श गाँव का उल्लेख उप योगी होगा —

'एक आदर्श भारतीय गाँव का इस तरह बनाया जाएगा कि उसमें सफाई का मुमुक्षित प्रबन्ध हो। उसके मकानों में रोशनी और ताजी हवा के आने जान की पर्याप्त व्यवस्था होगी। उन मकानों को पाँच मीन के घरे व भीतर मिलने वाले सामान से तैयार किया जाएगा। मकान के बाहर दानान होगे जहाँ घर के लोग अपनी जरूरत भर की सब्जियाँ उगा सकें तथा पशु बाँध सकें। गाँव की गलियाँ और सड़कें यथा सम्भव बड़े में मुक्त होगें गाँव में सब धर्मविलम्बियों के लिए पूजागृह होगा एक सभागृह होगा पशुओं का एक सम्मिलित चरागाह होगा, एक सहकारी दुग्धशाला होगी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय होंगे जिनमें मुख्य रूप से उद्योग घट्टों की शिक्षा दी जाएगी, आपसी बगडों के निपटारे के लिए पंचायत होगी। वह गाँव अपनी जरूरत भर का साधान्न, सब्जियाँ, फल और खादी खुद पैदा करेगा। यह है मोटे तौर पर एक आदर्श गाँव की मेरी कल्पना।'

जहाँ तक परिवहन का सवाल है हमारी योजना में सड़क और वच्चे रास्तों को ऊँची प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह उन्हें आने-जाने की सुविधाएँ उपलब्ध करवाए जाने के ख्याल से ही आवश्यक नहीं है, बल्कि इससे सूदूर गाँवों तक में अधिक उत्पादन तथा व्यापार आदिको प्रोत्साहन मिलेगा। बेलगाड़ी जो आज भी ग्रामीण क्षेत्र में परिवहन का एक महत्वपूर्ण आधार है उसे पर्याप्त खोज द्वारा सस्ती और अच्छी बनाने की कोशिश की जानी चाहिए। यह प्रसन्नता की बात है कि जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय ने नई गाड़ी का एक डिजाइन विकसित करने के लिए एक अध्ययन दल गठित कर दिया है। देश के भीतर पानी के रास्ते परिवहन का भी विकास किया जाना चाहिए। इसे सस्ता और अधिक रोजगार प्रदान करने वाला होना चाहिए।

गांधीजी मजदूरों को खेती और कारखानों के स्वामित्व में सहभागी मानते थे। इस दृष्टि से मालिक और मजदूर के मौजूदा अन्तर को धीरे-धीरे मिटते जाना चाहिए। इसके साथ माय नौकरी के बजाय अपना स्वतन्त्र धन्धा करने पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए। गांधीजी का ट्रस्टीशिप का मिद्धान्त सिर्फ पूँजी पर ही लागू नहीं होता। वह धर्म पर भी लागू होता है। अमल में जीवन के सभी क्षेत्रों पर वह लागू होता है। गांधीजी ने मजदूर और प्रबन्धकों के बीच के सम्बन्धों के सिलसिले में अधिकारों और वस्तुओं दोनों पर जोर दिया था। इस लिहाज से मजदूरों को उत्पादकता से जड़ा हुआ होना चाहिए। बड़ी आगदनों और घोंस का एक भाग श्रम के रूप में दिया जाना चाहिए ताकि मजदूर धीरे-धीरे उस उद्योग या व्यवसाय में वास्तविक भागीदार बन जाएँ और वे अधिक उत्पादन के लक्ष्य में सच्ची दिलचस्पी लेना शुरू कर दें।

हमारी योजना में जनसंख्या पर नियंत्रण की समस्या भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ऐसा न हुआ तो बढ़ा हुआ उत्पादन अधिक जनसंख्या में बँटकर रह जाएगा और लोगों को इसका कोई लाभ न मिल सकेगा। लेकिन जनसंख्या पर नियंत्रण की कोशिश को ऐच्छिक ही होना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि नोजवान लोग गर्म निरोध के तरीकों का उपयोग स्वेच्छाचार के लिए न करें।

राष्ट्रीय आयोजना में दामो पर नियंत्रण के काम को भी धरीयता देनी होगी। यह कोई आसान समस्या नहीं है और इसके लिए निश्चयपूर्वक बड़े बजट उठाने होंगे। हमारा यह पहला काम होता चाहिए कि हम आम आदमी की जरूरत के उत्पादन को बढ़ाने पर ध्यान दें। अमीर लोगों के ऐंग और आराम की वस्तुओं के उत्पादन की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को बढ़ाई में रोकना होगा। जरूरी चीजों के दामो पर नियंत्रण की दीर्घकालीन नीति के रूप में सायान्नो तेल चीनी कपड़ा सीमेंट तथा कागज के पर्याप्त भंडार बनाए जान चाहिए। गहर और गाँव सब जगह लोगों के हितों की सुरक्षा के लिए एक ताकतवर उपभोक्ता सहकारी आंदोलन खड़ा किया जाना चाहिए। खर्च को रोकने के लिए घरेलू बचत का एक आंदोलन चलाया जाना चाहिए। अनावश्यक नियंत्रणों को हटा दिया जाना चाहिए। उनमें से सिर्फ आवश्यक नियंत्रण ही रहने दिए जाने चाहिए। सरकार की वर नीति में भी व्यापक परिवर्तन की जरूरत है। उदाहरण के लिए मद्रा प्रसार को रोकन का प्रयत्न दृढ़ता से किए जान चाहिए। अर्थ व्यवस्था में उच्चवरीयता वाले क्षेत्रों को ऋण की पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध की जानी चाहिए। अनुत्पादक तथा फालत खर्च और प्रत्यक्ष उपभोग में कटौती की जानी चाहिए। इसके लिए कठिन फैसले ही नहीं लने होंगे बल्कि इसके लिए एक दृढ़ राजनीतिक इच्छा की भी जरूरत होगी।

हमें महात्मा गांधी की कल्पना का नया भारत बनाने के लिए उनके इन शब्दों को लगातार याद रखना होगा —

मैं एक ऐसा भारत का निर्माण की कोशिश करूँगा जिसमें गरीब-स गरीब आदमी को भी यह लग कि इसका निर्माण मैं उसका भी महत्वपूर्ण योगदान है। वह ऐसा भारत होगा जिसमें न कोई उच्च वर्ग होगा और न निम्न वर्ग एक ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय पूरे सामंजस्य के साथ रहते हों। उस भारत में छद्मता के अभिगाप का नशीली चीजों या दवाओं के अभिगाप का कोई स्थान नहीं होगा। महिलाओं को पुरुषों के बराबर दर्जा प्राप्त होगा। चूंकि हम गेप पूरी

दुनिया के साथ शांतिपूर्वक रहेंगे, इसलिए बहुत छोटी सेना रखेंगे। हम एमे मव देशी और विदेशी हितों का पूरा ख्याल करेंगे जो देश के करोड़ों आम लोगों के हितों से नहीं टकराते। निजी तौर पर मैं देशी और विदेशी के फर्क को नापसन्द करता हूँ। यह है मर सपनों का भारत।”

अन्तमें, हमें अपनी योजनाओं को गांधीवादी आधार पर इसलिए नहीं बनाना कि इनके साथ उस महात्मा की स्मृति जुड़ी है, बल्कि इसलिए कि ये विचार समय के साथ पूरी तरह व्यावहारिक, वैज्ञानिक और उपयुक्त साबित हुए हैं। मुझे इसमें जरा भी शक नहीं है कि गांधीजी के विचार उनके जीवन में सार्थक थे, वे आज भी सार्थक हैं और आने वाले समय में भी सार्थक रहेंगे। गांधी अतीत की यादगार नहीं है। वे नो भविष्य को दृष्टा थे।



ज्ञान ओढ़ा जाता है, उतारा भी जा सकता है।
अनुभव जीने की प्रक्रिया में से समुद्र-मयन की
तरह उपजता है।

प्राकृतिक चिकित्सा का महत्व

[अखिल भारत प्राकृतिक चिकित्सा सम्मेलन का पंद्रहवाँ अधिवेशन १४, १५, १६ अक्टूबर को डॉ. श्रीमन्नारायण जी की अध्यक्षता में साबरमती आश्रम, अहमदाबाद में सम्पन्न हुआ । उसका उद्घाटन प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई ने किया । सम्मेलन में स्वीकृत प्रस्ताव पाठकों का जानकारी के लिए दिए जा रहे हैं ।]

- १- यह सम्मेलन प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई के इस आश्वासन का हृदयसे स्वागत करता है कि भारत सरकार प्राकृतिक चिकित्सा को एक स्वतंत्र पद्धति के रूप में मान्यता प्रदान करनेवाली है । सम्मेलन आशा करता है कि जिन राज्य सरकारों ने अभी तक प्राकृतिक चिकित्सा को मान्य नहीं किया है वे भी शीघ्र ही इस पद्धति को मान्यता दे देगी ।
- २- सम्मेलन की राय में प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षाओं के सभी विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में प्राकृतिक चिकित्सा का मूल विचारों को समुचित स्थान दिया जाना चाहिए ताकि गांधीजी के समय-प्रधान आदर्श को उनके जीवन में उतारा जा सकें । प्राकृतिक चिकित्सा के बुनियादी सिद्धान्तों के प्रचार के लिए रेडियो टेलीविजन व फिल्मों का भी उपयोग किया जाना चाहिए ।
- ३- प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को समय जीवन दर्शन के रूप में निरन्तर विकसित करते रहने की आवश्यकता है । इसके लिए यह जरूरी है कि भारत सरकार एक अखिल भारत प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान की स्वतंत्र रूप से स्थापना करे । सम्मेलन की राय में इस केन्द्रीय संस्थान का केन्द्र सेवाग्राम हो । इसके क्षेत्रीय केन्द्र बलवत्ता, मोरखपुर, हैदराबाद व उरली काचन में रखे जाएँ ।
- ४- भारत सरकार ने जो ग्रामीण स्वास्थ्य योजना घोषित की हैं, उनके अभ्यासक्रम में प्राकृतिक चिकित्सा को भी स्थान दिया

गया है यह सतोष का विषय है। वार्यवर्तियों के प्रशिक्षण के लिए देश भर के प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र सहायता देने को तैयार रहेंगे। किन्तु इस बात का पूरा ध्यान रखना होगा कि सरकारी ग्राम स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत अन्य पद्धतियों को अधिक महत्व न देकर प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के द्वारा ही गाँवों की जनता का स्वास्थ्य बच सचौले ढंग से सुधारने का पूरा प्रयास किया जाए।

५- अभी तक प्राकृतिक चिकित्सा के लिए भारत सरकार ने केवल एक केन्द्रीय सलाहकार समिति का गठन किया है। अब यह आवश्यक है कि प्राकृतिक चिकित्सा के लिए भी एक स्वतन्त्र अखिल भारतीय बोर्ड को गठित किया जाए। ताकि इस पद्धति का विकास गतिशील बन सके। इस कार्य के लिए समुचित धनराशि भी उपलब्ध करानी चाहिए।

६- यह सम्मेलन राज्य सरकारों से आग्रह करता है कि प्राकृतिक चिकित्सा के प्रसार के लिए प्रत्येक जिले में स्वतन्त्र रूप से कन्द्र स्थापित किए जाएँ जिनका संचालन प्रशिक्षित प्राकृतिक चिकित्सकों को सौंपा जाए।

अध्यापक-शिक्षा राष्ट्रीय विचार गोष्ठी सेवाग्राम,

१८, १९ और २० सितम्बर, १९७७

सर्वसम्मति निवेदन

अखिल भारत नई तालीम समिति तथा राष्ट्रीय संक्षिप्त अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा समुन्नत रूप से आयोजित की गई 'शिक्षक पाठ्यक्रम तैयारी की परिवर्तन' विषय पर विचार गोष्ठी १८, १९ और २० सितम्बर, १९७७ को सेवाग्राम में हुई। विचार गोष्ठी के सामने चर्चा का मुख्य विषय राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद के लिए तैयार किए गए 'अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम' की रूपरेखा पर विस्तार से विचार करना था। इसका उद्घाटन अखिल भारतीय नई तालीम समिति के अध्यक्ष डा श्रीमन्नारायण द्वारा किया गया। इस विचार

गोष्ठी में सम्पूर्ण देश के जाने माने शिक्षाविदों ने भाग लिया। उसमें शिक्षा विभागों के अध्यक्षों शिक्षा वा नेजा के प्रिंसिपलों शिक्षकों प्राध्यापकों और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अध्यापक शिक्षा के तीन पहलुओं, यथा, "अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम की परिवर्तना" समाज शिक्षा को अध्यापक शिक्षा के साथ जोड़ना" और अध्यापक शिक्षा संस्थाओं के स्वरूप में परिवर्तन" पर विचार किया गया।

इस विचार गोष्ठी की चार बैठक हुईं तथा एक और बैठक थोड़े से समय के लिए पवनार आश्रम में आचार्य विनोबा भाव के साथ भी हुई, जिनमें 'पाठ्यक्रम की रूपरेखा' के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया और निम्नलिखित बातों पर मतंक्य हुआ —

१- देश में इस समय शिक्षा का जो वातावरण है वह यह अपेक्षा करता है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में सभी स्तरों पर गांधीय मूल्य तत्काल लागू किए जाएं। विचार गोष्ठी में यह अनुभव किया गया कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि शिक्षा क्षेत्र में आज कार्य और समाज का नव निमाण करने की आवश्यकता है बुनियादी शिक्षा के प्रमुख सिद्धांत शिक्षा के सभी स्तरों पर लागू होने चाहिए।

२- शिक्षा में गांधीय मूल्यों को सम्मिलित किए जान की अविलम्ब आवश्यकता के सदर्भ में अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम के प्रारूप में राष्ट्रीय अध्यापक परिषद द्वारा उपयुक्त सुधार करने की आवश्यकता है।

विचार गोष्ठी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से यह सिफारिश करती है कि एक छोटी समिति गठित की जाए जो अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम के प्रारूप पर विस्तार से विचार करे और शिक्षा सम्बन्धी गांधीय सिद्धांतों और मूल्यों के सदर्भ में उसमें अपेक्षित सुधारों के लिए सुझाव दे।

३- विचार गोष्ठी का मत है कि अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम से देश में ग्रामीण तथा शहरी दोनों ही क्षेत्रों की आवश्यकता पूरी होनी चाहिए।

- ४- विचार गोष्ठी का यह निश्चित मत है कि उच्च शिक्षा देने वाले अध्यापकों को भी उचित प्रशिक्षण की उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि स्कूल के अध्यापकों को।
- ५- विचार गोष्ठी सिफारिश करती है कि अध्यापक शिक्षा में सुधार लाने के लिए प्रथमतः ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए जो देश की परिस्थितियों के अनुरूप देश में ही विकसित किए गए दृष्टिकोणों और तकनीकों पर आधारित हों। यहाँ, अन्य देशों में विकसित नई तकनीकों और पद्धतियों को भी आवश्यक सशोधनों और परिवर्तनों के साथ अपनाया जा सकता है।
- ६- विभिन्न स्तरों पर शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने की नीति के सदर्भ में अनौपचारिक शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया गया है। अतः विचार गोष्ठी सिफारिश करती है कि प्रत्येक अध्यापक को अनौपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
- ८- इस बात पर विचार गोष्ठी में भर्त्सक प्रकट किया गया कि सभी स्तरों पर अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों में उत्पादक कार्य और सामुदायिक शिक्षा को अभिन्न अंग के रूप में सम्मिलित किया जाए।
- ७- सामुदायिक कार्य के कार्यक्रम में परिसर के भीतर की और परिसर के बाहर की सभी गतिविधियाँ सम्मिलित की जाएँ और उन्हें पाठ्यक्रम के अभिन्न अंग के रूप में सुनिश्चित रूप में लागू किया जाए।
- ९- सभी प्रशिक्षण सत्यापन स्वयं को स्वावलम्बन सहकारिता तथा लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर एक सुसम्बद्ध समुदाय के रूप में संगठित करें।
- १०- अध्यापक शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित करते समय छात्रों के परो और उनके माता-पिताओं के महत्वपूर्ण योगदान को पर्याप्त मान्यता दी जानी चाहिए।
- ११- नया पाठ्यक्रम अपनाए जाने के लिए अध्यापक शिक्षा सत्यापन को नया रूप देने के मागों में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की गई।

- (अ) क्या एक अध्यापक शिक्षा संस्थान को अपनी निजी स्वाभाविक विशेषताएँ, अपना निजी संरचनात्मक वातावरण और अपनी नई कार्य-मदति विकसित करके अपना निजी पृथक् अस्तित्व विकसित करना चाहिए अथवा नहीं ?
- (आ) क्या प्रत्येक ऐसे संस्थान को अपनी आवश्यकताओं और मूल्यों के अनुसार अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों को आयोजित करने और उनका मूल्यांकन करने की पूर्ण स्वतंत्रता दे दी जानी चाहिए ?

इन दो विषयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई और अनेक विकल्पों का सुझाव दिया गया। इस बारे में निम्नलिखित बातों पर मतभेद हुआ —

- (अ) प्रत्येक अध्यापक शिक्षा संस्थान को राष्ट्रीय उद्देश्यों के दायरे में रहते हुए अपना निजी अस्तित्व विकसित करना चाहिए।
- (आ) प्रत्येक संस्थान को इतनी स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए कि वह पाठ्यक्रम कार्यक्रम में अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त संशोधन और प्रयोग कर सके। ऐसी स्वतंत्रता को प्रशासन से समर्थन मिलना चाहिए।

१२- विचार गोष्ठी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से यह आग्रह किया है कि वह अध्यापक शिक्षा और अध्यापक शिक्षकों की शिक्षा के विकास को उच्च प्राथमिकता प्रदान करे और अध्यापक शिक्षा संस्थानों को क्षमता के उम स्तर तक पहुँचने में सहायता दे जो स्तर में अपेक्षित सुधार लाने के लिए आवश्यक हो। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त धन देना चाहिए और इस बात पर बल नहीं देना चाहिए कि राज्य सरकार और विश्वविद्यालय भी इसके लिए उतना ही धन दें। विचार गोष्ठी ने ऐसा ही आग्रह राज्य सरकारों से भी किया है कि वे भी अध्यापक शिक्षा स्तर को ऊँचा उठाने के लिए आवश्यक धन दें। -



रहनुमाई

ऐ रहमदिल रहमान
हमको राह दिखला दे,
दुनिया में रहमदिल से भरा
दरिया बहा दे !

कैसा नजर आता जमाना
देख तो लें आज,
खिलमत पर मोहब्बत पर
सच्चाई पर हमें है नाज !

हैरान हैं कुर्बान हैं
कानून पर तेरे,
कुदरत के नजारे नजर हैं
साज सवेरे !

जगत् कहीं दोख कहीं
पवंत कहीं पानी,
बयो जग होती है कहीं
होती है कुर्बानी !

हैं खेल ये कैसा
तमाशा देखते हो तुम,
जरा कुछ नूर दिखला दो
रहम से पेश आएँ हम !

इस्तेान दुनिया के सभी
आवास मिलकर हम,
भरें दिल में रहनुमाई
लुटाएँ प्यार हम हर हम !

—मदालसा नारायण

सेवाग्राम-आश्रम-वृत्त

संकलक, श. प्र. पाडे

(माहे अक्टूबर १९७७)

“ गांधी जयंती ” के शुभ अवसर से इस माह का शुभारंभ हुआ । प्रातः फेरी, प्रायचना, अखंड सूत्र यज्ञ, गीताई पारायण, सामूहिक सूत्र यज्ञ, सर्व धर्म साथ प्रायचना तथा सर्व भाषीय भजन के कार्यक्रम से ‘बख्शी जयंती’ मनाई गई । विजया दशमी के अवसर पर बर्मशाला (बर्क-शाप) में आयुध पूजा का कार्यक्रम संपन्न हुआ । सारे विभागों से कामों के औजार लाकर सजाए गए थे । भक्ति गीतों के साथ उनका पूजन तथा प्रसाद वितरण हुआ ।

इस माह में सेवाग्राम आश्रम के पुराने मित्र और आश्रमवासी, फ्रांसके गांधी श्री शान्तिदामजी सेवाग्राम आश्रम में आकर रहे । आस पास की मस्याबा के प्रतिनिधियों ने आकर उनके साथ भावी कार्यक्रम की चर्चा की । अहिंसा और शांति का विचार विश्वमें दृढ़ करने की दृष्टिसे भिन्न भिन्न स्थानोंपर व्यक्तिगत फुटकर प्रयत्न हो रहे ऐसा श्री शान्तिदासजी ने बताया । ऐसे प्रयत्न करने वाले इन चंद लोगों को एकत्रित करके सामूहिक रूपसे इस सम्बन्ध में विचार करने की दृष्टिसे १९७८ के दिसंबर में एक सगोष्ठी आमत्रित करने का विचार दृढ़ किया गया । तथा इस दृष्टि से प्रयत्न शुरू किए गए ।

गांधी के विकास की समस्याओं को मद्दे नजर रखते हुए अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों का, जो कि एस वामा में प्रत्यक्ष सगे हैं, सम्मेलन २२ से २५ जनवरी १९७८ में सेवाग्राम आश्रम में सयोजित करल जा निश्चय किया गया है और उस दृष्टि से प्रयास भी आरंभ हो गए हैं ।

श्री जयप्रकाशजी के अमृत महोत्सव की कालावधि में सेवाग्राम के कार्यकर्ता आस-पास के देहातो में घूम और ग्रामवासियों से मिलकर खुल दिल से चर्चाएँ की ।

पूज्य अण्णा साहव सहस्रबुद्धे की ८१ वी वर्षगांठ दिनांक २३ अक्टूबर को मनाई गई। इस अवसर पर सेवाग्राम की संस्थाओं ने "वस्त्र स्वावलम्बन" की दृष्टि से प्रयास करने का संकल्प किया। इसके अनुसार २५-१०-७७ को कस्तूरबा हेल्थ सोसायटी में एक बैठक पूज्य अण्णा साहव के उपस्थिति में हुई और "ग्राम वस्त्र स्वावलम्बन" समिति की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष श्री दत्तोबाजी को बनाया गया। पूनी के कार्य से आरम्भ करने की दृष्टि से गांधी सेवा सघ कस्तूरबा हेल्थ सोसायटी तथा सेवाग्राम आश्रम प्रतिष्ठान इन संस्थाओं से प्रत्येकी प्रारम्भ में १००० रु लेने का निश्चित किया गया। इस कार्य की पूर्ण तैयारी आरम्भ हुई है।

आश्रम में इस माह में कुल दर्शनार्थी ३०८० आए। जिनमें कुल ८४ श्रुपत् भी शामिल है। ऑस्ट्रेलिया तथा जर्मनी के कुल ५ अतिथि आश्रम में रहे। भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री श्री सोनू सिंह पाटील ने आश्रम को भेंट दी।

आश्रम की स्मारक कुटियों की देखभाल पूर्ववत् की गई। बापू फुटी बम्पाउट के सड़ हुए खम्भे बदल दिए गए। शास्त्री फुटी का परिसर ठीक किया गया। सेवाग्राम में आकर बापू पहिली द्वार जहाँ ठहरे थे वहाँ प्रथम आदि निवास का स्थान अब ठीक किया गया।

आश्रम के दैनिक कार्यक्रम भी पूर्ववत् चले। सुबह के प्रायनामा की कुल औ हाजरी २३ रही। इसमें सुबह ४-२० तथा ५-३० के प्रायनामाका अंतर्भाव है। माय प्रायना की औ हाजरी ११ रही। सुबह दान की प्रायनाओं में "गांधी विचार वाचन तथा जन्म व्रतों का प्रवचन" नित्य होता रहा।

आश्रम वासियों में आश्रम प्रतिष्ठान मंत्री श्री प्रभाकरजी बाकी अस्वस्थ रहे। अन्य आश्रम वासियों का स्वास्थ्य अच्छा रहा। श्री बाबलजी मोनाशी ग्रहण के स्वास्थ्य उपचार के लिए बाहर गये। वे अब नव वापिस नहीं आए।

वार्यकर्त्ता का उत्पादन परिश्रम वार्य इस महीने में अच्छा चला।

गांधी मार्ग

गांधी-विचारके सृजनात्मक साहित्य वा मासिक
सारगर्भित लेख, लघु लेख, कहानी, नाटक, कविता,
संस्मरण एवं व्यक्ति-चित्रों से युक्त
विचारशील पाठकों एवं सर्वसाधारण पाठकों के लिए पठनीय
सम्पादक :

श्री श्रीमन्नारायण, श्री भवानोप्रसाद मिश्र

वार्षिक शुल्क : रु. १२ द्विवार्षिक : रु. २२

एक प्रतिका मूल्य १ रु.

सम्पर्क करें : व्यवस्थापक 'गांधीमार्ग' (हिन्दी-मासिक)

गांधी शान्ति प्रतिष्ठान, २२१-२२

दीनदयाल उपाध्याय मार्ग

नई दिल्ली-२

संस्था कुल

गांधी स्मारक निधि का मासिक

सम्पादक - श्री पूर्णचंद्र जैन

वार्षिक शुल्क-५ रुपये,

एक प्रति-५० पैसे

रचनात्मक प्रवृत्तियों, कार्यों, सर्वोदय संगठन एवं

राष्ट्रीय हलचलों की जानकारी देनेवाला

एक प्रभावशाली माध्यम

संपर्क करें-व्यवस्थापक, संस्थाकुल

गांधी स्मारक निधि,

राजघाट, नई दिल्ली-२

If thy aim be great and thy means small, still act, for by action alone these can increase Thee”

—Shri Aurobindo

Assam Carbon products Limited
Calcutta—Gauhati—New Delhi.

“यदि आपका ध्येय बड़ा है, और आपके साधन छोटे हैं तो भी कार्यरत रहो, क्योंकि कार्य करते रहनेसे ही वे आपको समृद्धि प्रदान करेंगे।”

—श्री अरविन्द

आसाम कार्बन प्रोडक्ट्स लिमिटेड

कलकत्ता - गौहाटी - न्यू देहली

हम केवल व्यापारिक संस्थान ही नहीं हैं

आज के गतिशील संसार में कोई भी उद्योग
समाज की आवश्यकताओं की अवहेलना नहीं
कर सकता, क्योंकि सामाजिक उत्तरदायित्व
व्यापार का आवश्यक अंग बन गया है।

इण्डिया कारबन लिमिटेड

केल्साइन्ड पेट्रोलियम कोक के निर्माता

नूनमाटी, गोहाटी-781020

सम्पादक-मण्डल :

श्री श्रीमन्नारायण - प्रधान सम्पादक

श्री ब्रजमार्द पटेल

श्रीमती मदातला नारायण

डॉ० मदनमोहन दामो

वर्ष २६

अंक ३

अनुक्रम

हमारा दृष्टिकोण

शिक्षा में आधुनिक परिवर्तन

—श्री मोरारजी देसाई ९

राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली

—श्रीमन्नारायण १९

आज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा—विचारणीय प्रश्न

—श्री रघुकुल तिलक ४८

शिक्षा की पुनर्रचना

—डॉ० सतीशचन्द्र ४४

भाषी कार्यक्रम पर सर्वसम्मति निवेदन

— ५९

सेनाप्रान्त वृत्त

— ६९

श्रद्धा गुमन

— ७१

दिसम्बर-जनवरी '७८

- 'नई तालीम' का कार्य अगस्त से प्रारम्भ होता है।
- 'नई तालीम' का मासिक शुल्क बारह रुपए हैं और एक बच्चा का मूल्य दो रुपए हैं।
- तत्पश्चात्तर वाले समय प्राप्ति अपनी सक्षमता निखाना न भूलें।
- 'नई तालीम' में ध्येय विचारों की पूरी जिम्मेदारी शिक्षक की होती है।

श्री प्रधानमंत्री द्वारा ज. भा. नई तालीम समिति, सेनाप्रान्तों लिए प्रकाशित श्री
राष्ट्रभाषा प्रेरण, वर्षों में मुद्रित

हमारा दृष्टिकोण

राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन :

अखिल भारत नई तालीम समिति के तत्वाधान में १८-१९-२० दिसम्बर १९७८ को नई दिल्ली में एक अखिल भारत राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया। उसका उद्घाटन १८ दिसम्बर को प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई ने किया और २० दिसम्बर को केन्द्रीय शिक्षा मंत्री डा. प्रतापचन्द्र खन्ना ने समापन भाषण दिया। इन सम्मेलन में राजस्थान के राज्यपाल श्री रघुकुल तिलक, कई राज्यों के शिक्षा मंत्रियों, लगभग ३० विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, कुछ सरकारी सदस्यों और लगभग १०० अनुभवी शिक्षा शास्त्रियों व बुनियादी तालीम के रचनात्मक कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। सम्मेलन के उद्घाटन के सत्र में योजना आयोग के उपाध्यक्ष डा. लकड़ावाला, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष डा. सतीशचन्द्र और राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद के निदेशक डा. मिश्रा ने भी भाग लिया। सम्मेलन के अन्त में जो सर्वानुमति का वक्तव्य पारित किया गया वह इसी अंक में अग्यत्र प्रकाशित किया जा रहा है।

यह राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन शिक्षा सुधार की तथा अन्य कई दृष्टि से ऐतिहासिक रहा। विभिन्न राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन और विश्वविद्यालय के कुलपतियों के सम्मेलन अलग-अलग होते रहते हैं। नई तालीम समिति की ओर से भी प्रतिवर्ष एक अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया जाता है। किन्तु नई दिल्ली के राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में सभी प्रकार के प्रतिनिधि उपस्थित रहे और उन्होंने चर्चाओं में सक्रिय भाग लिया। प्रधानमंत्री और केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने भी उसको विशेष महत्व दिया और सम्मेलन में अपने विचार भी विस्तार से प्रगट किए। इस दृष्टि से सम्मेलन के अन्त में जो वक्तव्य जारी किया गया, उसकी अहमियत जाहिर ही है।

सम्मेलन ने यह स्वीकार किया कि भारत की नई शिक्षा प्रणाली महात्मा गांधी के सिद्धान्तों के अनुरूप और बुनियादी तालीम के आधार पर ढाली जानी चाहिए और उसका माध्यम समाज-उपयोगी उत्पादक श्रम होना जरूरी है। बुनियादी शिक्षा के सभी आदर्शों को वालमंदिर से लेकर विद्यविद्यालयों तक लागू करना, भारत के लिए श्रेयस्कर होगा। अब तो गांधीजी के सिद्धान्तों को शिक्षा के क्षेत्र में विदेशों के लगभग सभी शिक्षा आस्थी मान्य कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि हमारे देश में भी अब बुनियादी तालीम को बिना किसी मानसिक बंधनों के स्वीकार दिया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को उपयोगी शिक्षा प्राप्त हो सके और वे भारत के अच्छे नागरिक बन सकें।

सम्मेलन ने इस बात पर भी बहुत जोर दिया कि शिक्षा का माध्यम हर स्तर पर मातृभाषा होना चाहिए और विश्वविद्यालयों में भारतीय भाषाओं द्वारा सभी विद्यार्थियों को पढ़ाने का उचित प्रयत्न करना चाहिए। भारतीय भाषाओं के माध्यम को सकलता के लिए यह आवश्यक है कि अखिल भारतीय सिविल तथा सैनिक सेवाओं में भरती के लिए जो परीक्षाएँ ली जाती हैं, उनका माध्यम अंग्रेजी के बजाय प्रादेशिक भाषाएँ ही रखी जाएँ। राष्ट्रीयकृत बैंक तथा सांख्यिक क्षेत्रों के उद्योगों की सेवाओं के लिए भी जो परीक्षाएँ ली जाती हैं उन्हें देशी भाषाओं में आयोजित दिया जाए। चुनाव के बाद जिन उम्मीदवारों को चुना जाए उन्हें बाद में हिन्दी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान दिया जा सकता है। किन्तु जब तक इन शासकीय सेवाओं में भरती होने के लिए अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य रहता जाएगा तब तक विश्वविद्यालयों में मातृभाषा माध्यम को सकलतापूर्वक संचालित करना मुमकिन नहीं होगा।

पब्लिक स्कूलों के सम्बन्ध में भी सम्मेलन में काफी चर्चा हुई। यह सभी ने स्वीकार किया कि इन पब्लिक स्कूलों को अपना काम-काज राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति के अनुसार ही चलाया चाहिए और मातृभाषा माध्यम तथा विभाषा सूत्र को लागू करने में देरी नहीं करनी चाहिए। यह भी जरूरी है कि इन शिक्षण संस्थाओं में ५० प्रतिशत स्थान समाज के कमजोर वर्गों के प्रतिभा सन्त वच्चों के लिए सुरक्षित रखे जाएँ ताकि उनमें राष्ट्रीय जातावरण का मंचार हो सके।

नई शिक्षा संरचना के सम्बन्ध में सम्मेलन की राय रही कि १०+२+३ के बजाय ८+४+३ की योजना अधिक उपयोगी होगी। भारतीय संविधान के अनुसार १४ वर्ष की उम्र तक सभी बच्चों को ७ वर्ष की अनिवार्य और मुफ्त बुनियादी शिक्षा दी जानी चाहिए। उसके बाद ४ वर्ष की उत्तर बुनियादी या माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था होना जरूरी है। यह शिक्षा विद्यालयों में दी जाए, कालेजों में नहीं। माध्यमिक शिक्षण के बाद फिर ३ वर्ष की विश्वविद्यालयीय शिक्षा का प्रयत्न किया जाए। जो विद्यार्थी चाहें वे १० वर्ष की शिक्षा के बाद मॅट्रिकुलेशन परीक्षा दे सकते हैं। शेष विद्यार्थी १२ वर्ष की शिक्षा के बाद ही सार्व-जनिक परीक्षा में बैठेंगे।

लेकिन सम्मेलन ने यह स्पष्ट राय जाहिर की कि मावधानी के साथ विस्तृत चर्चाओं के उपरान्त जो नई शिक्षा संरचना स्वीकार की जाए उसमें फिर अगले १०-१५ वर्षों तक कोई फेर बदल नहीं किया जाना चाहिए। शिक्षा-नीति में बार-बार परिवर्तन करने से तरह-तरह की मानवीय समस्याएँ पैदा होती हैं और उनसे यथासम्भव बचना चाहिए।

इस बात पर भी बहुत जोर दिया गया कि देश की राजनीतिक पार्टियाँ स्कूलों, कालेजों और विश्वविद्यालयों के कार्यों में किसी प्रकार का दखल न दें। इस सम्बन्ध में उन्हें एक आचारसंहिता बना लनी चाहिए ताकि शिक्षण संस्थाएँ दलगत राजनीति के चक्कर में न डाली जाएँ और उन्हें शान्तिपूर्वक अपना कार्य संचालन करने की सुविधा प्राप्त हो सके। हम आशा करते हैं कि सभी राजनैतिक दल इस ओर विशेष ध्यान देंगे।

हमें पूरी आशा है कि सम्मेलन की सभी सिफारिशों पर भारत सरकार, राज्य सरकारें और विश्वविद्यालय गम्भीरतापूर्वक निर्णय भी लेंगे ताकि अगले सत्र से ही हमारी शिक्षा प्रणाली में आवश्यक सुधार दायित्व किए जा सकें और नवयुवकों में नए उत्साह का वातावरण संचारित हो सके।

‘नई तालीम’ का यह ‘राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन डिग्रे राव’ ऐसे दुःखद समयमें निाल रहा है जब इसकी प्रेरणास्थली डा श्रीमन्नारायणजी इहलोक लीला समाप्त कर हमसे बिदा हो गए ।

डा श्रीमन्नारायणजी ने इस सम्मेलन का आयोजन गत १८-१९-२० दिसम्बर को दिल्‍ली में किया था । भर्षे इग सम्मेलन में उपस्थित रहनेका अवसर मिला था । सम्मेलन अपने में अत्यन्त सकल एवं ऐतिहासिक रहा । स्वयं श्रीमन्जी इस आयोजन से अत्यन्त सतुष्ट थे और चाहते थे कि उसकी सिकारिशोपर भारत सरकार, राज्य सरकारें और विश्वविद्यालय गभीरतापूर्वक निर्णय कर । इस कार्यको आगे बढानेके लिए इसकी सदस्योंकी एक समिति भी गठित की गई थी । किन्तु दुःख है कि सम्मेलनकी उपलब्धियों को क्रियान्वित होते देखने से पहले ही ने हम से बिदा हो गए ।

इस सम्मेलन के आयोजन के लिए श्रीमन्नारायणजी ने अत्यन्त सगनपूर्वक काफी परिश्रम किया था । वंसे वे ह्वारा से पीडित तो थे ही पर ऐसा प्रतीत होता है कि इस परिश्रम का उनके स्वास्थ्यपर भीतरी असर पडा । सम्मेलन की समाप्ति के बाद वे जब दिनांक २ जनवरी को वर्धा लौट रहे थे तब ट्रेन में ही अस्वस्थ हो गए और आग्रामें तत्काल सामयिक लघु उपचारके बाद भी ग्वालियर पहुँचते तब अत्यधिक अस्वस्थ हो गए और अस्पताल पहुँचने से पहले ही इहलोक से बिदा हो गए ।

इस विशेषांक के लिए सपादकीय लिखकर उन्होंने मुझे दिल्‍लीमें ही दे दिया था । ‘नई तालीम’ पत्रिका के लिए यह उनका अंतिम सपादकीय होगा । अक म दी गई सारी सामग्री के सम्बन्ध में वे निर्देश दे गए थे और तदनुसार ही सामग्री दी गई है ।

उनका यह असामयिक वियोग केवल ‘नई तालीम’ के परिवार के लिए ही भीषण आघात है ऐसा नहीं बरन प्यारे देश के लिए अरुह्य ।

है। उनके अवमानसे अनेक क्षेत्रों में एक रिक्तता उत्पन्न हो गई है जिसकी पूर्ति निकट भविष्यमें कठिन प्रतीत होती है। इसे विधिका विधान मानकर धैर्यपूर्वक सहन करनेके सिवा अब और चारा ही क्या है ?

उन्होंने जो विचारोंकी अमूल्य निधि हमें प्रदान की है वह हमें सदा प्रेरणा देती रहेगी और गांधी विचार तथा विनोबा-दर्शन से अभिभूत शिक्षा क्षेत्र के इस ज्योतिस्तंभ का प्रकाश उनके द्वारा छोड़े हुए कामोंको पूरा करने में हमारा मार्ग दर्शन करेगा। हम निष्ठापूर्वक उस पथपर अग्रसर होते रहें यही प्रभु से प्रार्थना है।

नई तासीरके इस अंकके प्रकाशनमें अथकी बार जो विलंब हुआ है उसके लिए सहृदय पाठक क्षमा करेंगे।

—मदनमोहन शर्मा

गांधी मार्ग

गांधी-विचारके, सृजनात्मक साहित्य का मासिक
सारगर्भित लेख, लघु लेख, कहानी, नाटक, कविता,
संस्मरण एवं व्यक्ति-चित्रों से युक्त
विचारशील पाठकों एवं सर्वसाधारण पाठकों के लिए पठनीय
: सम्पादक :

श्री श्रीमन्नारायण,

श्री भवानीप्रसाद मिश्र

वार्षिक शुल्क : रु. १२

द्विवायिक रु. २२

एक प्रतिका मूल्य १ रु.

सम्पर्क करें : व्यवस्थापक 'गांधीमार्ग' (हिन्दी मासिक)

गांधी शान्ति प्रतिष्ठान, २२१-२२

दीनदयाल उपाध्याय मार्ग

नई दिल्ली-२

शिक्षामें आमूल परिवर्तन

मोरारजी देसाई

[अखिल भारत नई तासीम समिति की ओरसे दिनांक १८, १९, २० दिसंबर को दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रधान मंत्री था मोरारजी देसाई द्वारा दिए गए भाषण का कुछ महत्वपूर्ण अंश]

• अध्यक्ष महोदय और मित्रों ?

मैं चाहता हूँ कि मैं किसी न किसी भारतीय भाषाओं में बोलूँ, किन्तु इस समय देश में जो गोरखघरे (घोटाखे) की स्थिति है उसी को प्रकट करने के लिए अपना भाषण अंग्रेजी में दे रहा हूँ। यदि मैं हिन्दी में भाषण देता हूँ तो २ प्रतिगत अंग्रेजीदा तथा देशका प्रतिनिधित्व करने की अहम्मन्यता वाले लोग 'अंग्रेजी विरोधी' कहकर मेरी आलोचना करेंगे। देशकी इस समय की इसी प्रकार की स्थिति में हम हैं। मेरी दृष्टि में इस स्थिति के लिए जिम्मेवार वे ही हैं। जब श्रीमनजी ने मुझसे कहा कि वे अखिल भारत नई तासीम समिति की ओर से राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं तो मैंने इस विचारका स्वागत किया और उद्घाटन के समय आप के बीच आ गया। यहाँ आने में मेरा मुख्य उद्देश्य यह था कि मैं आपको यह बताऊँ कि मुझे जब भी अवसर मिला तब हम ९ महीने की अवधि में मैंने क्या किया ? शिक्षा प्रणाली के सबंध में हमें सोचने की सक्त जरूरत है जिससे हम कुछ ऐसे निश्चित निष्कर्षोंपर पहुँच सकें, जिन्हें कार्यान्वित किया जा सके। शिक्षा सबंधी मेरे कुछ स्पष्ट और निश्चित विचार हैं। शिक्षा में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है किन्तु यह बात तब तक संभव नहीं है जब तक कि इसमें शिक्षकों और सस्था-संचालकोंका सहयोग प्राप्त न कर लिया जाए, उन्हें समझाया न

जाए। उन्हीं के सहयोग से यह परिवर्तन लाया जा सकता है। लोक-सभामें कानून पास कर लेने मात्र से यह संभव नहीं है। मैं उनको दोषी करार नहीं देना चाहता जो शिक्षा के संबन्ध में भ्रम राय रखते हैं, या शिक्षा की वर्तमान व्यवस्था के संबन्ध में भी किसी को दोष नहीं देना चाहता। यदि किसी को दोष दिया जा सकता है तो वह अंग्रेज सरकार को ही दिया जा सकता है। और विशेष रूप से मेकॉल को। किन्तु उन्हें भी कैसे दोष दें? उनके कार्य सिद्धि के लिए तो यह आवश्यक ही था। वे तो यहाँ राज्य करना चाहते थे और जनसाधारण को अपने नियंत्रण में रखना चाहते थे। भूलतः तो यह हमारा ही अपराध है कि हम उनके शासन में थे।

शिक्षा, मानवी विवासका प्रभावशाली माधन है। मानव की सभी कृतियाँ उसके द्वारा प्राप्त शिक्षा पर निर्भर हैं। इसीलिए शिक्षा हमारी मूलभूत समस्या है। यही कारण है कि जितनी शीघ्रता से शिक्षा पद्धति में परिवर्तन लाया जाना संभव हो उतनी शीघ्रता से परिवर्तन लाने को मैं उत्सुक हूँ। इस विषय में शिक्षा से सम्बद्ध अनेक लोगों से तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जैसी धन और विचार देने वाली संस्थाओं से मैं बात कर चुका हूँ।

मैं भाग्यशाली हूँ कि मैंने घर में, शाला में उचित शिक्षा पाई है और महात्मा गांधी ने तो और भी अधिक शिक्षा पाई। यही कारण है कि इस संबन्ध में मुझे विचार पूर्वक एवं वस्तु परक दृष्टि से सोचने को बाध्य किया है। हम सभी बुद्धि लेकर जन्मे हैं फिर भी एक वर्ग-विरोध बुद्धिजीवी कहलाता है। मेरी समझमें नहीं आता कि केवल एक हिस्सा ही कैसे बुद्धिजीवी कहलाता है। इस प्रकार का वर्गीकरण हो गया है। मैं तो यही मानता हूँ कि इस प्रकार के वर्गीकरण का कारण यही है कि हम हमारी बुद्धि का समुचित उपयोग नहीं करते। मनुष्य अपनी बुद्धि का समुचित उपयोग कर सके यही शिक्षा का सही उपयोग है। शिक्षा उसे इसमें सहायता पहुँचाती है। शिक्षा तो आजीवन चलनी चाहिए। आज प्रोफेसर और अध्यापक यह समझते हैं कि वे सब को

शिक्षा दे सकते हैं जब कि उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि विद्या-अर्जन कभी समाप्त नहीं होता । हम जितनी चाहे उतनी विद्या ग्रहण कर सकते हैं । यह तो एक भंडार है जो कभी खत्म नहीं होता ।

दुनिया में कुछ ही ऐसे महान लोग होते हैं जो अपने आपको शिक्षित कर लेते हैं और सब कुछ जान लेते हैं । रमण महर्षि और रामकृष्ण परमहंस जैसे महान व्यक्तियों ने अपने आपको शिक्षित किया । ऐसे शिक्षक भी थोड़े ही होंगे और व्यक्ति भी कम । रमण महर्षि ने यद्यपि स्कूली शिक्षा पाँचवे या छठे दर्जे तक ही पाई थी किन्तु ऐसा कोई विषय नहीं था कि जिस पर वे गम्भीर सलाह नहीं दे सकते थे । इतना ही नहीं उन्होंने तो पशु और पक्षियों की बोली को भी सीखा था । वे तो बिड़िया या गोरैया की भाषा भी जानते थे । किन्तु ऐसे लोग कम होते हैं । अतः शिक्षा और प्रशिक्षण की योजना बनानी पड़ती है जिससे शिक्षक और प्राध्यापक पहले स्वयं कुछ सीखें और फिर दूसरों को सिखाएँ ।

महार्मा गांधी हमें इसीलिए बहुत कुछ दे सके, सिखा सके कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा था । उन्होंने हमें ऐसा कुछ भी करने को नहीं कहा जो उन्होंने अपने जीवन में खुद न किया हो । अन्य किसी देश को ऐसा शिक्षक मिलने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है । इसी मूलभूत तथ्य को शिक्षकों और प्राध्यापकों को समझना है । मैं तो उन्हें केवल सूत्राय मात्र दे सकता हूँ । मैं उन्हें दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ क्योंकि वे भी तो उसी शिक्षा प्रणाली की उपज हैं । यही कारण है कि हमें शिक्षा पद्धति में दीर्घ परिवर्तन करने की बात सोचनी पड़ती है ।

मैं आपके सामने कुछ बुनियादी बातें रखना चाहता हूँ जिनपर आप विशेष ध्यान दें और कुछ निर्णय, निश्चित निर्णय पर पहुँच सकें । उसके पश्चात् सरकार देखेगी कि वह उन्हें कैसे कार्यान्वित कर पाती है । मैं रूपरेखा देकर और फिर जनतासे स्वीकृति प्राप्त करनेके पक्ष में नहीं हूँ । मेरी राय में यह उचित नहीं है । अतः वह निश्चयात्मक रूपरेखा मैं आपसे चाहता हूँ । मैं तब तक विश्राम नहीं लूँगा जब तक मैं इसे आपसे प्राप्त नहीं कर लेता हूँ । इसे आप मेरा आह्वान समझें । मैं स्वयं

चैन नहीं लूंगा और न आपको चैन लेने दूंगा, क्योंकि यह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। महात्मा गांधी ने स्वयं इसपर विचार किया था, इस दिशा में प्रयोग किए थे तथा हमें कुछ बुनियादी विचार दिए, दिशा दी और उनकी मोटी मोटी रूपरेखा भी दी। उन्होंने डॉ. झाकिर हुसेन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। झाकिर हुसेन, स्वयं शिक्षा में बहुत रुचि रखते थे और इसी समिति ने हमें बुनियादी तालीम दी। बुनियादी तालीम का अर्थ, मेरी समझ के अनुसार स्कूलों और कालेजों में प्राप्त होनेवाली वह शिक्षा है जो हमें अपनी जीवन प्रणाली से प्राप्त होती है। उसकी बुनियाद हमारा जीवन है अतः हमें मानव की मूलभूत आवश्यकताओं में प्रारंभ करना चाहिए। मानव की मूलभूत आवश्यकता यह है कि वह अपनी इन्द्रियों को उपयोग में लाए। यदि आप उनका उपयोग नहीं करेंगे तो वे निष्क्रिय हो जाएंगी, यदि मनुष्य निष्क्रिय हो जाता है तो वह जीवन में निरूपयोगी हो जाता है। यदि इन्द्रियों का उपयोग करना है तो उनका उचित उपयोग किया जाना चाहिए। यदि आप उनका गलत उपयोग करेंगे तो वे गलत दिशा में जाएंगे। यही यथार्थ बुनियादी तालीम है। यही कारण है कि आरम्भ से ही उत्पादक श्रम हमारे पाठ्यक्रम का आवश्यक प्रमुख अंग घोषा गया था, अन्यथा वह श्रम की गलत व्याख्याएँ उत्पन्न करता है। प्रत्येक काम जो आप कर उत्पादक हो इसका अर्थ है कि वह करनेवाले के लिए और समाज के लिए मददगार हो। अन्यथा वह उत्पादक नहीं है।

अतः हमें यह सोचना है कि छात्रों को सिखाने साधक उत्पादक काम कौन-सा है—कनाई, बड़ईगिरी या कृषि। यह सब अपनी अपनी उपयोगिता पर, देश की आवश्यकता पर तथा लोगों की प्राहिका शक्ति पर निर्भर है। महात्मा गांधी को इसमें कोई शक नहीं थी। उन्होंने कताई में तथा कपड़े से अर्थात् बुनाई में प्रारंभ किया और कहा कि भोजन के अतिरिक्त कपड़ा मनुष्य की महत्वपूर्ण प्राथमिक आवश्यकता है जिसके बिना वह कुछ नहीं कर सकता। ऋषियों ने भी कपड़े से बनी कम से कम सेंगोटी तो लगाई ही थी। अतः कपड़ा मानव की आवश्यकता है। इसकी ओर लक्ष्य दिए बिना हम जीवन में स्वतंत्र कैसे होंगे? पराव-

लम्बिता जीवन का सब से बड़ा अभिगाप है। इसीलिए बुनियादी तालीम का मूलभूत कार्य यह है कि वह शिक्षितों में स्वावलम्ब आत्म विश्वास, सत्य, निर्भयता, स्वतंत्रता जैसे मूल्यों को देने का माध्यम बने। इन गुणों की उपलब्धि के बिना हम जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। मैं देखता हूँ कि विश्व विद्यालय के सर्वोत्तम छात्र आज कल निराश हैं, हताश हैं, विफल हैं। निराशा, हताशा, विफलता, आत्म संदेह का तथा संपूर्ण आत्म विश्वास हीनता का द्योतक है। किसी भी हालत में मनुष्य क्यों निराश होता है? सत्य और निर्भयता ही मनुष्यको उन्नति की उच्चतम स्थिति पर पहुँचा सकते हैं। अनेक उपलब्धियों के लिए हम पुरस्कार करते हैं किन्तु इन गुणों के लिए किसी को पुरस्कृत किए जाते नहीं देखा गया। तब हम शिक्षा के सही उद्देश्यको कैसे हस्तगत कर सकेंगे? मैं आशा करता हूँ कि आप अपने चिन्तन के दौरान इसपर भी विचार-मंथन करेंगे। यह मथन ऐसा हो जिससे उचित निर्णय पर पहुँचा जा सके।

दो तीनों बातें ऐसी हैं जिनपर मैं आपसे विचार करने के लिए प्रार्थना करना चाहूँगा जिनमें शिक्षा के माध्यम का प्रश्न है। देश में सभी स्तर पर शिक्षा का माध्यम बदलकर मातृभाषा करना आवश्यक है। सभी शिक्षा शास्त्रियों ने महसूस किया है कि छात्रों को उनकी मातृभाषाको माध्यम से शिक्षा देने पर वे विषय को गहरी भाँति ग्रहण कर सकते हैं क्योंकि वयपन में वे उसी भाषा में सीखते हैं। विदेशी भाषा के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करना बहुत कठिन है। वह छात्र पर एक भारी बोझ है। उनकी सभी खूबियों और विशेषताओं को समझने के लिए उसे उन्हें सीखना पड़ता है और इस प्रकार विषय को सीखने के स्थान पर उस भाषाको सीखने में उत्साह काफी समय और शक्ति खर्च हो जाती है। छोटे छोटे देशों की शिक्षा ने विभिन्न क्षेत्रों में कुशल लोगों को अधिक संख्या में दिया है। क्योंकि वहाँ शिक्षा मातृभाषा में दी जाती है। यहाँ छात्र पर भाषाका बोझ अधिक है और शिक्षा का माध्यम मातृभाषा नहीं है अतः

हमें शिक्षा का माध्यम परिवर्तित कर उसे प्राथमिक से उच्चतम स्तर तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा कर देना चाहिए। प्रतियोगी परीक्षाएँ भी क्षेत्रीय भाषाओं में होनी चाहिए। अँग्रेजी का म विरोधी नहीं हूँ। विदगी भाषा हम सीखें। म अँग्रेजी में बोल रहा हूँ। हिंदी गुजराती या मराठी की अपेक्षा म अँग्रेजी में अधिक अच्छी तरह बोल सकता हूँ पर मैं आपको यह बता दूँ कि जब म अँग्रेजी बोलता हूँ तो मैं अधिक संतुष्ट रहता हूँ और अँग्रेजी में बोलना मेरे लिए श्रमसाध्य भी है। जब मैं हिंदी मराठी या गुजराती में बोलता हूँ तो अधिक धरलूपन का अनुभव करता हूँ और अधिक तजी स तथा सक्षम में बोल सकता हूँ। अँग्रेजी न हमें ब्रिटिश मनी नरीका उपयुक्त पुर्जा बनाने वाला काम ही किया है और हममें उन्होंने आभातीन सफलता प्राप्त की। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भी अँग्रेजी को अपनाकर हमने यह सिद्ध किया है कि हमने भौतिक स्वतंत्रता भल ही प्राप्त कर ली है किन्तु अँग्रेजियतकी मानसिक गुलामी से अभी हम मुक्त नहीं हुए हैं। उमसे अभी तक हम जगड़ हुए हैं। क्या हम हम नामना म मुक्त न हों?

हमारी संस्कृति में ही इतना कुछ है कि हम उमसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमें दूसरी भाषा या दूसरे राष्ट्राका मह तात्पर्य की आवश्यकता नहीं है।

विदगी भाषा हम सीखें हमें जाननी चाहिए और सम्भावित अँग्रेजी क्योंकि उससे २०० वर्षों से हमारा संपर्क रहा है और उस हमने सीखा है पर विचारणीय यह है कि क्या वह हम आत्म सम्मान की ओर ल जाएगी? क्या यह कम आश्चर्य की बात है कि हम अँग्रेजी बोलने में तो गौरव का अनुभव करें किन्तु अपनी ही भाषा बोलने में गलतियाँ करें? अतः इस पर आप गम्भीरतापूर्वक विचार करें और सोचें कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? क्षेत्रीय भाषाओं की शिक्षा का माध्यम बनाने से अनिश्चित म तो और कोई रास्ता नहीं दखता।

अँग्रेजी न भी इतनी शक्ति नहीं है पाई? महज इसी से कि उमने अपना साम्राज्य स्थापित किया और हम पर लाद दी गई किन्तु हम

साम्राज्य स्थापित करना नहीं चाहते। हमारा अत्यंत विशाल देश है अतः हमें हीन भावना का अनुभव नहीं करना चाहिए और न हममें उच्च शक्ति या हीन शक्ति होनी चाहिए। हममें केवल इच्छा शक्ति हो अन्य कोई शक्ति न हो; अतः चली आ रही शिखा गद्दिके परिवर्तनके प्रयत्नों में अधिक समय लगाया जाएगा तो देश का ही नुकसान होगा।

इस देश में भी प्रतिभाशाली लोग हैं जिनकी तुलना दुनियाके किन्हीं भी प्रतिभाशाली लोगों से की जा सकती है। विश्व भ्रमण के बाद मैं तो इस विचार का हूँ कि अन्य देशों की अपेक्षा इस देशमें प्रतिभाशाली लोग अधिक हैं।

मैं जानता हूँ कि प्रचलित परीक्षा पद्धति के भी कारण हैं। छात्रों को बुराइयों से भी मे अवगत हैं। उन बुराइयों को हमें शीघ्र से शीघ्र दूर करना चाहिए। मैं तो चाहूँगा कि सभी स्वर्द्धा-परीक्षाओंका माध्यम प्रादेशिक भाषाएँ हों। भाषाको प्रयोगका अवसर मिलने पर यह विवक्षित होता है अंग्रेजी में भी उचित इसी कारण आई है। अंग्रेजी साम्राज्य के कारण यह हम पर थोपी गई। मुक्त लोगों को यही यकीन दिलाना है, उनमें विश्वास पैदा करना है। मैं नहीं जानता कि हमें क्या हो गया है? भगवान के लिए इस पर विचार करिए और इस मलयकत सभी को सुधारने में हमारी मदद कीजिए। यह हमारे पूर्ण विकास में तथा हमारे देश के विकास में बाधक है। इस मुद्दे की अत्यधिक आवश्यकता है।

यह भी कहा जाता है कि उपाधियों को नियुक्तियों से अलग कर दिया जाना चाहिए। यह भी गलत धारणा है। हमें जाँच के लिए कुछ न कुछ नियम तो निर्धारित करना ही होगा। यदि आप शिक्षाको वैज्ञानिक और युक्ति युक्त बना देते हैं तो आपको कोई कठिनाई नहीं है। अन्यथा यदि आप उपाधियोंकी उपलब्धि को हटा देते हैं तो हर जगह प्रत्येक व्यक्ति प्रत्यासी बन जाएगा और फिर उनमें से स्वयं के लिए योग्य व्यक्ति के चुनाव का कार्य बहुत मुश्किल हो जाएगा।

परीक्षाओं को हटा देने से हम कैसे जान पाएँगे कि छात्र ने कुछ पढ़ा है। मान लीजिए कि कोई छात्र तेरह वर्षों तक स्कूल या कॉलेज

में उपस्थित रहा और उसे इसी कारण भी एच डी की उपाधि दे दी गई तो क्या उसे उचित शिक्षा माना जाएगा ? किसी न किसी रूपमें परोक्षावा होना तो अनिवार्य है फिर चाहे वह मात्तात्मक हो मायिक हो या रायिक । हाँ, वह वैज्ञानिक एवं युक्ति-युक्त हो । आजकल नकल करने की मानी है और यह आज की शिक्षा पद्धति है जिनके हम धिक्कार है । इसकी ओर भी ध्यान दिया जाना है । आज की शिक्षा हमें मग आत्म निर्भरता आत्म विश्वास एवं भय से मुक्तता नहीं देती । मानव-विकास के लिए ये गुण अत्यंत आवश्यक हैं जो शिक्षा द्वारा नहीं दिए जा रहे हैं ।

आज के पाठ्यक्रम अत्यंत प्रोक्षित बना दिए गए हैं । यह भी एक परा ही है । मैंने देखा है कि ८ वें ९ वें दर्जों में मग विषय ग्व ग्व है । मैंने देखा कि छात्र को इतनी कित्तों से जानी पड़ती है कि जिनको यह उठा नहीं पाता । मैं तो बी ए की कक्षा में इनसे आगे कित्तों भी नहीं स जाता था । मैं नहीं जानता कि ये छात्र हम लोग म भी कुछ अधिक सीखते हैं । एक बात यह और है कि शिक्षा में हर बार कुछ न कुछ जोड़ा जाता है, या तो सभी विषय या पुस्तकें जोड़ दी जाती हैं या फिर यप जोड़ दिए जाते हैं । शिक्षा सरचना म स्प अभी १० + २ + ३ है । मैं इस का जय नहीं ममन पा रहा हूँ । मेरी दृष्टि में तो तीन स्पष्ट श्रेणियाँ हैं—प्राथमिक, माध्यमिक और महाविद्यालयीन । मेरी दृष्टि में प्राथमिक ७ या ८ वर्ष होना चाहिए । मैं तो ७ वर्ष पमद करूँगा । जहाँ यह ७ वर्ष हो वहाँ ७ + १ + २ और जहाँ ८ हो वहाँ ८ + ४ + ३ हो सकता है । और फिर इस करने का क्या अर्थ है कि हायस्कूल की शिक्षा क बाद दो वर्षों म कुछ तमनीकी या औद्योगिक शिक्षा दी जाएगी । यह एकदम तुरत देना कैसे सम्भव होगा ? इससे एक दूसरा अमतोप पैदा होगा ।

आज इस बात की आवश्यकता है कि राष्ट्र के विकास हेतु शिक्षा गुरु में अत तव सभी तबको के लोगो के लिए किसी न किसी उत्पादन प्रवृत्ति के साथ जुड़ी हो जिस स के नौकरों की ओर न दोड़ें ।

आजकी हमारी शिक्षा-व्यवस्थाका देश के गरीब लोगों और गाँवों में रहनेवालों के साथ मेल नहीं बैठता इसलिए कोई न कोई ध्येय सामने रखकर हमें अपनी शिक्षा-पद्धति पर विचार करना होगा। हमारी शिक्षा कम खर्चीली हो। जरा महाविद्यालयों के छात्रों के जीवन की ओर तो देखिए विशेषतः आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों के तथा इंजीनियरिंग कालेज के छात्रों के जीवन को देखिए। वे जितना रुपया प्रतिमाह खर्च करते हैं यह केवल उनकी झक मात्र है। उनका यह खर्च हमारे जीवन के लिए यद्यपि उपयुक्त नहीं है। ऐसे लोग गाँवों में जाकर नहीं रह सकते। मेरी गय में शिक्षा-पद्धति को सामान्य लोगों के जीवन के साथ जोड़ने के लिए आवश्यक है कि उन्हें मूलभूत और सीधे-न्मादे जीवन की शिक्षा दी जाए। विद्वत् विचारियों और स्कूलों के छात्रायासों में भी विद्यार्थियों का जीवन सादा रहना चाहिए। शिक्षा का स्वरूप ऐसा हो कि शिक्षित व्यक्ति समाज के लिए आवश्यक चीजोंका उत्पादन करने योग्य बने।

पब्लिक स्कूलों का उल्लेख करते हुए प्रधान मंत्रीजी ने कहा— जब अलग अलग वर्ग के लोगों के लिए अलग-अलग तरह के स्कूल हैं तो सभी को शिक्षा के समान अवसर कैसे दिए जा सकते हैं? यद्यपि पब्लिक स्कूलों को एकदम से बन्द नहीं किया जा सकता तथापि कोई ऐसा विकल्प ढूँढ़ना होगा जिससे सभी को समान रूप से शिक्षा दी जा सके।

देश में चल रहे पब्लिक स्कूल आज समाज में विषमता को बढ़ा रहे हैं। इस तरह की व्यवस्था को पनपने से रोकना चाहिए। यह व्यवस्था वर्ग भेद को जन्म देती है जो समाज के लिए घातक है। जब तक समानता के आधार पर सभी को एक जैसी शिक्षा नहीं मिलेगी, हम नए समाज की रचना नहीं कर सकेंगे। समानता हमारी संस्कृति की देन है। अतः इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। सभी स्कूलों को समान महत्ता दी जाए। जो व्यक्ति अधिक सेवा करता है श्रेष्ठ है न कि वह जो अधिक व्यय करता है।

मुझे यह जानकर आश्चर्य होता है और धक्का लगता है कि हमारे कुछ शिक्षित व्यक्ति कहते हैं कि जननत्र भाग्न के लिए उपयोगी नहीं है। भारत में तो जननत्र तब से है जब दुनिया इनके विषय में २५०० वर्ष पहले जानती तब न थी। जननत्र का उल्लेख पूरी तरह से ऋग्वेद में मिलता है। यही कारण है कि हम सब कुछ सीखने के लिए सब जगह जाते हैं। आपने जो सीखना है वह सीखें लेकिन हमारे यहाँ जो कुछ है उसे भूँ नही। उसे हम पहले पूरी तरह सीखें और फिर अन्य बातें सीखें।

मैंने आपका काफी समय ले लिया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा उपकुलपतियों के साथ शिक्षा पर मैं पुनः चर्चा करने वाला हूँ। यहाँ भी मैं केवल उद्घाटन करने के लिए ही नहीं वरन् आपसे चर्चा करने और यह कहने आया हूँ कि आप सब कुछ ऐसे ठोस निर्णय करें गिनपर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा उपकुलपतियों के अधि-वेशनमें विचार किया जा सके तथा ससद में विचार किया जा सक।

अपनी इस अपील के साथ मैं इस सम्मेलन के उद्घाटनकी घोषणा करता हूँ।

संस्था कुल

गांधी स्मारक निधि का मासिक

सम्पादक - श्री पूर्णचन्द्र जैन

वार्षिक शुल्क-५ रुपये,

एक प्रति-५० पैसे

रचनात्मक प्रवृत्तियों, कामों सर्वोदय संगठन एवं

राष्ट्रीय हलधर्तों की जानकारी देनेवाला

एक प्रभावशाली माध्यम

संपर्क करें-ध्यवस्थापक, संस्थाकुल

गांधी स्मारक निधि,

राजघाट, नई दिल्ली-२

राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली

कुछ रचनात्मक सुझाव

डॉ. श्रीमन्नारायण

[राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन के अवसर पर प्रस्तुत सुझाव जो सम्मेलन की चर्चा के आधारभूत विषय थे]

आजादी के पहले और बाद के कई दशकों से भारत की शिक्षा-पद्धति की पुनर्रचना के सवाल पर बहस-मुवाहिरो होते रहे हैं और इस सबध में तरह-तरह के प्रयोग किए जाते रहे हैं। इस बीच अनेक समितियों और आयोगों ने केंद्र तथा राज्य सरकारों के मामले अपनी अपनी निकायिनी रखी है। इस मयके बानजूद हमारी शिक्षा-पद्धति अब भी जहाँ की नहीं पड़ी हुई है, और उसमें राष्ट्र की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होने की कोई क्षमता दिखाई नहीं दे रही है। इस वर्ष के आम चुनावों के फलस्वरूप कई दिल्ली और कई राज्यों में भी नए दल की सरकार बनी है। इसलिए यह बहुत जरूरी हो गया है कि १९६८ में स्वीकृत शिक्षा सबधो राष्ट्रीय नीति प्रस्ताव में जनता पार्टी के बुनियादी सिद्धांतों के अनुसंधान आवश्यक परिवर्तन किए जाएं। प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई और केन्द्रीय शिक्षा-मंत्री डा. प्रतापनन्द चंदर महात्मा गांधी के आदर्शों और आकांक्षाओं के अनुसार भारत में दीक्षणीय सुधार पर अपने सुर्चित विचारों का संकेत दे चुके हैं। अब प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालयीन स्तर तक की नई शिक्षा-प्रणाली का अंतिम रूप और विषय तय करने और माय ही उसपर तत्काल अमल के स्पष्ट निर्देशों की व्यवस्था में देरी करने की कोई गुंजाइश नहीं बची है।

सक्षिप्त इतिहास

हालीय वर्ष पूर्व, अक्टूबर १९३७ में, शिक्षा मंडल के रजत जयंती समारोह के अवसर पर, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का संयोजन किया गया

धा, उमकी अध्यक्षाता स्वयं महात्मा गांधी ने की थी। इस परिपद की सिफारिश थी कि पूरे देश में सात माल की निगुलर और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए और “इस अवधि में सारी शिक्षा गरीब-श्रम के द्वारा किसी न किसी उत्पादक काम के माध्यम से दी जानी चाहिए तथा जिन अन्य योग्यताओं का विकास या जो अन्य प्रशिक्षण देना आवश्यक हो, वह मग्न अभिन्न रूप से यथासंभव विद्यार्थी के परिवेश से जुड़ा हुआ हो।” वाद में जाकर हुसैन समिति ने इस पद्धति पर एक विस्तृत पाठ्यक्रम तैयार किया और इस तरह वह प्रणाली सामने आई जिसे हम बुनियादी शिक्षा या नई तान्त्रीय के नाम से जानते हैं।

इस परिपद के दौरान और वाद में भी गांधीजी ने यह बात काफी स्पष्ट कर दी थी कि “बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य किसी दस्तकारी के माध्यम से बच्चे का शारीरिक बौद्धिक तथा नैतिक विकास है।” उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि “इस शिक्षा पद्धति की सफलता की कमी-कमी इसका स्वावलम्बी रूप न होकर यह बात है कि शिक्षार्थी के संपूर्ण मानव-व्यक्तित्व को यात्रिक रीति से नहीं बरन शास्त्रीय ढंग से किसी दस्तकारी की शिक्षा द्वारा निम्नार दिया गया है।’ आगे चलकर आचार्य विनोबा भावे ने समझाया कि गांधीजी ने एक नए प्रकार के अद्वैत का—कर्म और ज्ञान के अद्वैत का—विकास किया है। इस तरह हर स्तर पर शिक्षा समाजिक दृष्टि से उपयोगी उत्पादक प्रवृत्तियों के जरिये दी जानी चाहिए और विभिन्न विषयों के ज्ञान का राष्ट्रीय आयोजना तथा विकास-कार्यों से ठीक तालमेल होना चाहिए। शिक्षण तथा रचनात्मक काम का यह पारस्परिक सामंजस्य बुनियादी शिक्षा का सार-सत्त्व है।

१९३८ में कई राज्यों की कांग्रेसी सरकारों ने अपने-अपने क्षेत्र में बड़ी उमंग और उत्साह के साथ बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्तों को दाखिल किया। किन्तु १९३९ में द्वितीय विश्व-युद्ध के आरम्भ होते ही उन्हें सत्ता छोड़नी पड़ी। फलतः बुनियादी शिक्षा को गंभीर

आघात पहुँचा और देश के आजाद होने के पूर्व १९४७ तक इस क्षेत्र में कोई उत्प्रेक्षणीय सफलता नहीं मिली। राधाकृष्णन् विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (१९४९) ने बुनियादी शिक्षा के महत्व पर बल देते हुए देश में देहाती कानूनों और देहाती विश्वविद्यालयों की स्थापना की जोरदार सिफारिश की। आगे चलकर माध्यमिक शिक्षा आयोग (१९५३) ने भी माध्यमिक शिक्षा को एक ऐसा विराग-विद्रुमाना, जहाँ पहुँचकर विद्यार्थियों को जीवन में अपनी-अपनी पसन्द के काम धंधों में लगने के योग्य बन जाना चाहिए। इस आयोग की सिफारिश थी कि माध्यमिक शिक्षा बुनियादी शालाओं से घनिष्ठ रूप से जोड़ दी जाए। १९५७ में शिक्षा मंत्रालय ने 'द फ़ांक्से ऑफ़ बैमिक एजुकेशन' (बुनियादी शिक्षा की परिकल्पना) शीर्षक से एक बहुमूल्य पुस्तिका प्रकाशित की। उसमें इस बात को दोहराया गया था कि 'जिम बुनियादी शिक्षा की कल्पना और व्याख्या महात्मा गांधी ने की वह तत्त्वतः जीवनोपयोगी शिक्षा है, और जो इसमें भी बड़ी बात यह है कि वह जीवन के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा है। इसका स्वयं अंतर्गत ऐसी समाज-व्यवस्था की रचना है जो शोषण और हिंसा से मुक्त होगी।' यही कारण है कि "उत्पादक, सृजनात्मक और सामाजिक दृष्टि से उपयोगी ऐसे कार्य को बुनियादी शिक्षा में केन्द्रीय स्थान प्रदान किया गया है जिसमें सभी जातियों, धर्मों और वर्गों के लड़के-लड़कियाँ शामिल हो सकते हैं।" यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई कि "बुनियादी शिक्षा का मूलिक उद्देश्य साधारण नहीं है। उसका उद्देश्य बच्चे के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का ऐसा विकास है जिसमें उत्पादक कार्य-कुशलता का भी समावेश होगा।" विभिन्न स्तरों पर बुनियादी शिक्षा के अमल में, बिना किसी मानसिक संकोच के, आज भी भारत सरकार द्वारा प्रकाशित इस महत्वपूर्ण पुस्तिका से मार्ग-दर्शन लेते रहना जरूरी है।

कोठारी शिक्षा आयोग (१९६६) ने गांधीजी द्वारा प्रतिपादित बुनियादी शिक्षा की परिकल्पना का पूर्ण समर्थन करते हुए कहा :

बुनियादी शिक्षा के मुख्य सिद्धान्त इतने महत्वपूर्ण हैं कि सभी स्तरों की शिक्षा-पद्धति को अपना विषय और रूपाकार उनसे मार्ग-दर्शन लेकर निश्चित करना चाहिए। यह हमारे मुझाबों का सार है, और इस बात को ध्यान में रखते हुए हम किसी एक स्तर की शिक्षा को बुनियादी शिक्षा की संज्ञा देने के पक्ष में नहीं हैं।" आयोग ने बुनियादी शिक्षा के आवश्यक तत्वों का भी निर्देश किया और उन्हें इन शब्दों में परिभाषित किया " (१) शिक्षा में उत्पादक प्रवृत्ति, (२) उत्पादक प्रवृत्ति तथा भौतिक एवं सामाजिक परिवेश से पाठ्यक्रम का अनुबन्ध, और (३) शाला तथा स्थानीय जनसमुदाय के बीच अंतरंग सम्बन्ध।" फिर भी न जाने क्यों आयोग ने यह स्पष्ट कर देने के बाद भी कि यह परिकल्पना "बुनियादी शिक्षा की उत्पादक प्रवृत्ति की परिकल्पना के समान ही है," और इसलिए इसे प्राथमिक, माध्यमिक तथा विश्व-विद्यालयीन स्तरों की "शिक्षा का अभिन्न अंग" मानना चाहिए, इसके लिए 'कार्य-अनुभव' (वर्क एक्सपीरियन्स) शब्द का प्रयोग किया।

१९६८ में भारत सरकार के शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति प्रस्ताव में इस बात को दोहराया गया कि "शिक्षा-पद्धति का काम राष्ट्रीय सेवा और विकास से प्रतिबद्ध आचारखान सुशोध्य युवक-युवतियाँ को तैयार करना है।" इसमें "शिक्षा-पद्धति को जन-जीवन से और भी घनिष्ठ बनाने के लिए उसके रूपान्तरण" की परिकल्पना थी, और "विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी के विकास और नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों के पोषण संवर्धन" पर जोर दिया गया था। प्रस्ताव में सुझाव दिया गया था कि "कार्य-अनुभव तथा राष्ट्रीय सेवा को, जिसमें राष्ट्रीय सेवा और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के उद्देश्य और चुनौती-भरे कार्यक्रमों में योगदान करना भी शामिल हो, शिक्षा का अभिन्न अंग होना चाहिए।" साथ ही कोठारी आयोग द्वारा सुझाई १०+२+३ की शिक्षा पद्धति को अपनाने की भी सिफारिश की गई थी।

अक्टूबर १९७२ में शिवा मंडल और अगिल भारत नई तालीम समिति की ओर से सेवाग्राम में राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का संयोजन किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था और उसमें कई राज्यों के शिक्षा मंत्री, कुलपति तथा देश-भर से अनेक शिक्षा-शास्त्री शामिल हुए थे। उनकी ओर से एक सर्वानुमती प्रस्ताव जारी किया गया, जिसमें यह सिफारिश की गई कि "सभी स्तरों की शिक्षा गाँवों और सहरो दोनों क्षेत्रों के आर्थिक विकास के जुड़ी ऐसी उत्पादक प्रवृत्तियों के माध्यम से दी जानी चाहिए जो सामाजिक दृष्टि से उपयोगी हों।" प्रस्ताव में तीन मूलभूत बातों पर भी जोर दिया गया था :

- (१) शैक्षणिक कार्यक्रम के एक अभिन्न अंग के रूप में कार्य-विशेष के उपयोग द्वारा स्वावलम्बन, आत्मविश्वास और श्रम की गरिमा की भावनाओं का पोषण;
- (२) विद्यार्थियों और अध्यापकों को सामुदायिक सेवा के अर्थ-वान कार्यक्रमों में प्रवृत्त करके राष्ट्रीयता तथा सामाजिक दायित्व के बोध का विकास, और
- (३) विद्यार्थियों के मानस में नैतिक तथा चारित्रिक मूल्यों की प्रतिष्ठा, सभी धर्मों की मूलभूत एकता की समझ और उनके प्रति समान आदर की भावना पैदा करना।

शिक्षा-सम्वन्धी केन्द्रीय सलाहकार समिति तथा शिक्षा-मंत्रियों और कुलपतियों के सम्मेलनों की सिफारिशों के आधार पर शिक्षा मंत्रालय ने पाँचवी पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव तैयार करते हुए १०+२+३ की नई शैक्षणिक पद्धति को स्वीकार किया और यह मतव्य भी प्रकट किया कि इस पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के पूर्व सभी राज्य सरकारों को चाहिए कि वे इसे अपना ले। कई राज्य इसे अपना चुके हैं और अन्य कई राज्यों ने दो-तीन साल में इसे अंजाम देने का वादा किया है। शिक्षा मंत्रालय ने इस बात पर भी जोर

दिया कि, "शिक्षा की विकास विषयक आवश्यकताओं और गोजगार के अवसरों में ठीक संवध होना चाहिए और 'कार्य अनुभव' को पाठ्य-क्रम का एक अभिन्न अंग होना चाहिए।" राष्ट्रीय शैक्षणिक अनु-सन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद् ने 'माइड-लाइन्स फॉर वर्क एक्सपीरियन्स' (कार्य-अनुभव की मार्गदर्शिकाएँ) शीर्षक एक पुस्तिका में कार्य-अनुभव को "शिक्षा का अभिन्न अंग" बनाने पर काफी बल देते हुए इस बात पर जोर दिया कि शैक्षणिक संस्थाओं में ऐसी चीजें तैयार की जाएँ जो शिव और स्वप्न सकें। सचिन सच कह तो शिक्षा की प्रथम दस साला अवधि के लिए परिषद् ने जो पाठ्यक्रम तैयार किया उसमें 'कार्य-अनुभव' को बहुत कम समय दिया गया है। प्राथमिक स्तर पर इसे शाला के कार्यों के लिए निर्धारित कुल समय का सिर्फ २०-२५ प्रतिशत हिस्सा ही दिया गया है। माध्यमिक तथा उच्च स्तरों पर सप्ताह के अड़तालीस घंटों (पीरियड्स) में से केवल पांच घंटे 'कार्य-अनुभव' को दिए गए हैं। इस प्रकार स्कूली स्तर पर बुनियादी शिक्षा के मूलभूत सिद्धान्तों पर वास्तविक अमल बहुत ही कम हुआ है। यह काम ठीक तैयारी के बिना लापरवाही और बिना मन के किया जाता रहा है। इसका उचित अमल के लिए पहले से जितना कुछ कर रचना चाहिए था वह नहीं किया गया।

बुनियादी शिक्षा .

अब चूंकि जनता सरकार ने गम्भीरतापूर्वक यह संकल्प लिया है कि वह राष्ट्रीय आयोजना को गांधीवादी मूल्यों के अनुरूप ढालेगी और उन्हीं मूल्यों को ध्यान में रखकर शिक्षा पद्धति की पुनर्रचना करेगी, इसलिए बहुत आवश्यक है कि महात्मा गांधी की कल्पना की बुनियादी शिक्षा को हर स्तर पर, बिना किसी हिचकिचाहट के, व्यवस्थित और ठीक ढंग से दाखिल किया जाए। मुझे इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि बुनियादी शिक्षा कोई 'गांधीवादी सनक' नहीं, बल्कि शिक्षा-क्षेत्र के अधुनातन चिन्तन पर आधारित एक ठोस योजना है। 'यूनेस्को' द्वारा नियुक्त शैक्षणिक विकास-समि

अंतरराष्ट्रीय आयोग ने भी 'लरनिंग टु बी' (जीने की शिक्षा) शीर्षक अपने प्रतिवेदन में इसे अत्यंत महत्व की बात बताया है कि "अध्यापन को विद्यालय की चार दीवारी से बाहर लेजाकर और शैक्षणिक प्रयोजनों के निमित्त अनेक प्रकार की सामाजिक तथा आर्थिक प्रवृत्तियों का उपयोग करके" हर व्यक्ति को "जीवन-पर्यन्त शिक्षा देने" की व्यवस्था की जाए। प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तरों की शिक्षा-व्यवस्था के लिए प्रतिवेदन में 'बुनियादी शिक्षा' शब्दों का प्रयोग प्रचुरता से हुआ है, जब कि स्वयं अपने देश में हम इन शब्दों से आखें चुराते जान पड़ते हैं, मानो 'बुनियादी' शब्द से हमारे शिक्षा-शास्त्रियों को एक प्रकार की चिढ़ पैदा हो गई है।

कई वर्ष पहले जब मैं न्यूयार्क में प्रोफेसर जॉन ड्यूई से मिला था तो उन्होंने मुझे अपनी यह निश्चित राय बताई थी कि शिक्षा के सम्बन्ध में गांधीजी के विचार "खुद उनके शिक्षा-शास्त्र से कई कदम आगे हैं। डाक्टर गुनार मिरडाल ने अपनी प्रसिद्ध कृति 'एशियन ड्रामा' में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि "बुनियादी पद्धति की ओर उन्मुख प्राथमिक शिक्षा, भारतीय शांताओं के पाठ्यक्रम और अध्यापन-विधि में सुधार की तत्पर आवश्यकता का आदर्श समाधान हो सकती है।" अपनी एक हाल की कृति "एजुकेशन फॉर सेल्फ-हेल्प" (स्वावलम्बन के लिए शिक्षा) में यूनाइटेड किंगडम-निवासी प्रोफेसर कैसल ने वर्धा की बुनियादी शिक्षा-योजना के संबंध में कहा है कि यह "भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही दिलचस्प चीज है और सम्भावना है कि इसके परिणाम महत्वपूर्ण निवर्तेंगे। "बुनियादी शिक्षा के सफल न होने का कारण यह नहीं है कि इसे आजमा कर देखा गया और यह विफल रही, बल्कि यह अभी तक ठीक से आजमाई ही नहीं गई है। डॉ. इवान इलिच ने तो इससे भी एक कदम आगे जाकर एक ऐसे समाज की परिकल्पना प्रस्तुत की है जिस में आज के विद्यालयों का अस्तित्व मिट जाएगा, पारंपरिक शैक्षणिक ढाँचा अतीत की चीज बन जाएगा, और घर, सड़क तथा चल-बारसाने जीवन-भर की व्यावहारिक शिक्षा देने के केंद्र बन जाएंगे।

जनता पार्टी ने सभी नागरिकों को पूरा रोजगार देने और "हर व्यक्ति को गरीबी रेखा में ऊपर ले जाकर एक दशक के अन्दर दरिद्रता का मिटा देने का वादा किया है। इसकी आयोजना-विषयक नई प्राथमिकताओं के अनुसार कृषि ग्रामोत्थान तथा लघु ग्राम्य और कुटीर उद्योगों को विकेंद्रीकृत क्षेत्र में सर्वोच्च महत्व दिया जाएगा। स्पष्ट है कि वर्तमान शिक्षा-पद्धति में क्रांतिकारी परिवर्तन लाये बिना इन राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति असम्भव होगी। जनता सरकार के चुनाव घोषणापत्र के अनुसार 'शिक्षा की विषय-वस्तु प्रवृत्ति-मूलक (फनक्शनल) होनी चाहिए, और उसे जन-जीवन से तथा जिस परिवेश में वह दी जाए उससे संबद्ध होना चाहिए साथ ही यह भी बहुत आवश्यक है कि वह सामाजिक आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य से जुड़ी हुई हो। 'कार्य अनुभव' के द्वारा शिष्याओं के मानस में धर्म की गरिमा प्रतिष्ठित की जानी चाहिए।" इस दृष्टिकोण से यह आवश्यक है कि शिष्या के प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय तक के तमाम स्तरों पर बुनियादी शिक्षा के मूलभूत सिद्धान्त सुनिश्चित रीति से अधिलम्ब दायित्व दिए जाएँ। गाँव के विकास और कृषि से संबद्ध उद्योगों के निमित्त पूरक प्रशिक्षण मण्डलों की स्थापना करना निःसंदेह समय-शक्ति और साधनों की बरबादी सिद्ध होगी। भारत-जैसा गरीब देश को यह बहुत भारी पड़ेगा। राष्ट्रीय आयोजना की नई प्राथमिकताओं की जड़ें पूरी करने के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण की व्यवस्था स्कूलों और कालजा को ही करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में शिक्षा का विविध सामाजिक-आर्थिक वायुमंडल से अभिन्न रूप से संबद्ध होना जरूरी है। इसमें शिक्षा और विकास प्रयत्न दोनों समूह और प्राणवान बनेंगे।

सांघिक प्राथमिक शिक्षा

भारतीय संविधान के ४५ वे अनुच्छेद का बहना है कि 'राज्य चौदह वर्ष की उम्र तक के सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयत्न करेगा।' इस निर्देश के अनुसार अधिकांश राज्यों ने आठवें दर्जे तक सांघिक प्राथमिक (बुनियादी) शिक्षा की

व्यवस्था कर दी है। साधारणतः प्राथमिक विद्यालयों की पहली कक्षा में बच्चे को पूरे छ साल का हो जाने पर दाखिल किया जाना चाहिए। नई शिक्षा-पद्धति में दस साल की स्कूली शिक्षा की तजवीज है। इसके बाद दो साल में समाप्त हो सकने वाली 'टर्मिनल नेचर' की व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था है। लेकिन हमारे आर्थिक साधनों को देखते हुए १६ वर्ष की उम्र तक दस साल मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना व्यावहारिक चीज नहीं होगी। गुजरात विश्व-पीठ के अपने हाल के दीक्षान्त भाषण में प्रधान मंत्री मोरारजी देसाई ने यह सुझाव दिया कि सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा की अवधि केवल सात साल होनी चाहिए। लेकिन सविधान के निर्देश को ध्यान में रखते हुए देश-भर के सभी बच्चों के लिए चौदह साल की उम्र तक ७ वर्ष की प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना वाछनीय होगा। जाकिर हुसैन समिति ने भी आठ साल की अवधि की सिफारिश की थी। इस अवधि में विद्यार्थियों को युनिटादी शिक्षा के सिद्धान्तों के अनुरूप सृजनात्मक प्रवृत्तियों के माध्यम द्वारा सामाजिक दृष्टि से उपयोगी शिक्षा दी जानी चाहिए।

शिक्षा-क्रम में उत्पादन कार्य के लिए पूरी अवधि का लगभग आधा समय दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त बच्चों को भारत की सामाजिक संस्कृति की विरासत से भी अवगत कराना चाहिए, अर्थात् उन्हें लोकतांत्रिक मूल्यों, अहिंसा, सामाजिक न्याय और सर्वधर्म-समभाव की भी शिक्षा दी जानी चाहिए। कहने की जरूरत नहीं कि प्राथमिक या युनिटादी स्तर के पाठ्यक्रमों में भाषा, प्रारम्भिक विज्ञान, गणित, स्थानीय भूगोल और आरोग्य तथा सफाई से संबंधित युनिटादी बातों— जैसे प्राकृतिक-चिकित्सा द्वारा रोग-निरोधक उपाय, जड़ी-बूटियों का उपयोग आदि— को भी शामिल किया जाना चाहिए।

यह बहुत आवश्यक है कि नए ढंग की प्रारम्भिक या युनिटादी शिक्षा ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में एक साथ आरम्भ की जाए। गाँवों और शहरों में अपनाई जानेवाली उत्पादन प्रवृत्तियाँ तो

अलग अलग प्रकार की होंगी, लेकिन 'कार्य-विशेष द्वारा ज्ञानार्जन का मुख्य सिद्धान्त', सभी स्कूलों में समान रूप से लागू किया जाना चाहिए, ताकि ग्रामीण लोगों के मन पर यह छाप न पड़े कि उन्हें घटिया किस्म की शिक्षा दी जा रही है। आरम्भ में हमने मिर्क देहाती इलाकों में बुनियादी शालाएँ खोलकर यही भूल को, उसे दोहराया नहीं जाना चाहिए। १९३८ में राज्यों में जो कार्यवाही सरकारें करती उनके सीमित आर्थिक साधनों को देखते हुए गांधीजी यही चाहते थे कि बुनियादी शालाएँ पहले गाँवों में खोली जाएँ। तीस साल की राजनीतिक स्वतंत्रता और आयोजित आर्थिक विकास के उपरान्त अब शिक्षा के मामले में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच कोई दुराभाव नहीं रहे जा सकते।

इसी वर्ष अगस्त महीने में आयोजित शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन ने मिकारिण की थी कि छठी आयोजना के अंत तक मावैत्रिक प्रारम्भिक शिक्षा (६-१४ के आयु-वर्ग के निमित्त) के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ भी उठा नहीं रखना चाहिए। बालिकाओं, अनुसूचित जातियों और जनजातियों तथा अन्य कमजोर वर्गों के बच्चों को स्कूलों में दाखिल करने की ओर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। इन महत्वपूर्ण लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हर राज्य को विकास-खंड स्तर पर तफसीलवार योजनाएँ तैयार करनी चाहिए। निर्धारित अवधि में वांछित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अनौपचारिक या पैरारम्भी शिक्षा भी रखना पड़ेगी जिसमें अंग-कालिक शिक्षण, बहु-बिंदु प्रवेश और लोचदार नीचे के वर्ग से बढ़ाने की पद्धति भी रहे।

माध्यमिक शिक्षा :

माध्यमिक शिक्षा, अर्थात् उत्तर बुनियादी शिक्षा १४ वर्ष की आयु के बाद नवी कक्षा में आरम्भ होनी चाहिए और बारहवीं कक्षा तक पाने १७ साल की उम्र तक चलनी चाहिए। इस प्रकार, माध्यमिक विद्यालयों में जिन चार वर्षों तक शिक्षा दी जाएगी, उनमें से अंतिम दो वर्ष रोजगार के अवसर सुलभ कराने वाले व्यवसायों की शिक्षा

में लगाए जाने चाहिए। चूंकि इन डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का स्वरूप ऐसा होगा जो शिक्षार्थी को तैयार करके जीवन के लिए एक निश्चित मजिल तक पहुँचा देंगे, इसलिए इन्हें पूरा तरह से लेने के बाद अधिकांश विद्यार्थी या तो अपना ही धंधा शुरू कर लेंगे या दूसरों के यहाँ चलने वाले अलग-अलग धंधों में खप जाएँगे। लेकिन जो विद्यार्थी भविष्य में किसी उच्चतर शिक्षा प्राप्त करना चाहते हों, उनकी आकांक्षा पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, माध्यमिक शालाओं में अंतिम दो वर्षों तक दो जानेवाली व्यावसायिक शिक्षा का स्वरूप ऐसा नहीं होना चाहिए जो आगे विद्यार्थियों के लिए विद्योपार्जन में कोई अवरोध या काम करे। अन्यथा ज्यादातर प्रतिभाशाली बच्चे इस व्यावसायिक प्रशिक्षण की ओर से विमुख हो जाएँगे और जो बच्चे इसे ग्रहण करेंगे उन्हें अल्पबुद्धि माना जाने लगेगा।

यह बड़े दुःख की बात है कि राष्ट्रीय धैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् ने माध्यमिक शिक्षा की +२ अवस्था का व्यावसायिक और ज्ञान प्रधान (अकादमिक) इन दो धाराओं में बाँट दिया है। व्यावसायिक धारा के विद्यार्थियों से अपना ५० प्रतिशत समय व्यावहारिक कार्य में लगाने की अपेक्षा रखी जाएगी, और शेष समय वे भाषाएँ, विज्ञान और गणित, साहित्य तथा शास्त्रीय विषयों (हर्मेनिटीज) के अध्ययन में लगाएँगे। निस्संदेह, यह बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी शिक्षापद्धति है। लेकिन परिषद् की योजना में ऐसी तजवीज भी है कि ज्ञान प्रधान धारा को चुननेवाले विद्यार्थियों से व्यावसायिक कार्य में समय लगाने की अपेक्षा ही नहीं रखी जाएगी। अपना ७५ प्रतिशत समय तो वे विज्ञान, समाज-शास्त्रों तथा साहित्य-सहित अन्य शास्त्रीय विषयों के अध्ययन में देंगे और शेष २५ प्रतिशत समय भी भाषाओं की शिक्षा लेने और सामान्य अध्ययन में ही लगाएँगे। परिषद् द्वारा पेश की गई योजना में निस्संदेह यह एक गंभीर भूल है। ऐसी योजना पढाई के कमरे में बदलते-बदलते शिक्षा-पद्धति को ही स्थायित्व प्रदान करने में सहायक होगी और बानेजों तथा स्कूलों की

और भागने का मौजूदा सिलसिला ज्यों का त्यों कायम रहेगा। इस लिए माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायोन्मुख होने की सारी चर्चा कोरा सपना बनकर रह जाएगी। स्वभावतः अधिकांश विद्यार्थी पढाई लिखाई वाली धारा चुनेंगे ऐसे युवक बहुत कम मिलेंगे जो व्यावसायिक धारा को अपना कर योगों की दृष्टि में अपने को 'मदवर्द्धि' सारित कराना चाहें।

परिपद की पुस्तिका में कहा गया है कि अकादमिक धारा के विद्यार्थियों के लिए भी 'कार्य-अनुभव' पर जोर देना अनिवार्य होना चाहिए और ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिसमें ये विद्यार्थी हर साल कम-से-कम एक महीना कामों कारखानों और स्मॉलरो में काम करना सीखते हुए बिता सकें। यदि इस चीज को अकादमिक धारा के पाठ्यक्रम के अभिन्न अंग के रूप में शामिल नहीं कर लिया जाता तो यह एक गृभच्छामान बनकर रह जाएगी इस पर अमल कभी नहीं होगा। इसलिए यादनीय यह है कि विविध व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की एक ही मुख्य धारा हो और साथ में भाषा साहित्य विज्ञान गणित समाज शास्त्रों और राष्ट्रीय विषयों (ह्यूमेनिटीज) के अध्ययन की भी व्यवस्था कर दी जाए। शिक्षा विभाग सम्बन्धी 'यूनस्को' आयोग (१९७२) की यह राय बहुत समीचीन थी 'विभिन्न प्रकार के शिक्षण—जैसे सामान्य बैज्ञानिक, तकनीकी और व्यावसायिक—के बीच की दुर्भेद्य दीवारें गिरा दी जाएं और प्राथमिक से लेकर माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा को एक साथ सैद्धांतिक तकनीकी व्यावहारिक और शारीरिक रूप प्रदान कर दिया जाए।"

विभिन्न दलों का तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण बरके माध्यमिक शिक्षा के ११ वें और १२ वें दर्जों के लिए व्यावसायिक और तकनीकी ढंग के विविध पाठ्यक्रम मावधानी के साथ तैयार किए जाने चाहिए। इन पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों को दाखिल करते हुए इस बात का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए कि स्थान विषय में विभिन्न आवश्यकताओं

क्षयकता को पूरा करने योग्य शिक्षा की जरूरत है और वहाँ किस तरह के रोजगार की गुंजाइश है, क्योंकि इनके बिना समाज की सच्ची आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती। शैक्षणिक विस्तार और आर्थिक विकास की ऐसी व्यवस्थित क्षेत्रीय आयोजना के अभाव में विद्यार्थियों को घोर निराशा ही हाथ लगेगी, और कानेजों में दाखिला लेकर भविष्य के बुरे दिनों को टालते रहने की प्रवृत्ति ज्यों की त्यों कायम रहेगी। इससे शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों को जीवन में प्रवेश करने के लिए पूरी तरह तैयार करने के ध्यान से रखे गए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की व्यवस्था का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा।

माध्यमिक शाखाओं की नवीं और दसवीं कक्षाओं में किसी विशेष ममुदाय के भौतिक पृष्ठभूमि और सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप उपयोगी ढंग की सामान्य शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। भाषा, विज्ञान, गणित, समाज-शास्त्र, साहित्य आदि मुख्य विषयों के अतिरिक्त अनेक वैकल्पिक विषय भी रखे जाने चाहिए, ताकि विद्यार्थी अपनी-अपनी रुचि के अनुसार चुनाव करके उनका अध्ययन करें। कहने की जरूरत नहीं कि इस स्तर पर भी शिक्षा का केन्द्र स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादक प्रवृत्तियाँ ही होनी चाहिए। प्रथम मार्चजनिक परीक्षा देश के सारे राज्यों में दस साल के अन्त में समान रूप से आयोजित की जानी चाहिए। व्यावसायिक पाठ्यक्रम का चुनाव आम तौर पर मैट्रिकुलेशन स्तर की शिक्षा पूरी करने के बाद ही किया जाना चाहिए। कारण, इसी उम्र तक विद्यार्थी की बुद्धि इतनी परिपक्व हो सकती है कि वह अपने भविष्य के मन्त्र में सही ममज्ञान कोई ठीक निर्णय ले सकता है।

लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि चार साल की माध्यमिक शिक्षा अविभाज्य इकाई मानी जाए; अंतिम दो वर्षों के पाठ्यक्रमों की शिक्षा की व्यवस्था भी कानेजों में नहीं, बल्कि स्कूलों में ही होनी चाहिए। भारत जैसे विकासशील देश को ऐसे विद्यार्थियों को कानेज की शिक्षा देना नहीं पुरा सकता जो माध्यमिक शिक्षा पूरी

करके उपयोगी नागरिकों की तरह जीवन-क्षेत्र में प्रवेश कर जाने का इरादा रखते हैं। ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षाओं के लिए गुंजाइश करने के उद्देश्य से कालेजों को 'कनिष्ठ' (जूनियर) और 'धरोय' (सीनियर) ऐंसे दो हिस्सों में बाँटने की व्यवस्था ठीक नहीं है और इसलिए इसको बन्द कर देना चाहिए।

सामान्य शाला पद्धति :

कोठारी आयोग की सिफारिश के अनुसार, माध्यमिक स्तर पर सार्वजनिक शिक्षा के लिए सामान्य शाला पद्धति की व्यवस्था होनी चाहिए। जाति, वर्ग या धर्म के किसी भेद-भाव के बिना सभी बच्चों को इन शालाओं में दाखिले का समान अवसर सुलभ होना चाहिए। इन सामान्य शालाओं में विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा दी जानी चाहिए और उचित अनुशासन के साथ कार्यकुशलता कायम रखनी चाहिए, ऐसी पद्धति सामाजिक समानता तथा राष्ट्रीय एकता में सहायक होगी; और इसके अंतर्गत गरीब और अमीर लड़के साथ-साथ शिक्षा पाएँगे, जिसमें समतावादी समाज के विकास में मदद मिलेगी।

बहरहाल, कम-से-कम मौजूदा पब्लिक स्कूलों से, जो सिर्फ़ ममूद वर्गों के बच्चों की पहुँच के अन्दर हैं, माफ़ कह देना चाहिए कि वे अपनी रीति-नीति बदलकर राष्ट्रीय शिक्षा-पद्धति के ढाँचे में अपने को ढालें। इस दृष्टि से उन्हें जो परिवर्तन करने पड़ सकते हैं उनमें शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषाओं को बनाने और त्रिभाषा-मूत्र को लागू करने की बातें भी शामिल होनी चाहिए। ये सरकार से कोई आर्थिक सहायता नहीं लेते, महज इसीलिए उन्हें अपने वर्तमान रूप में चलने नहीं रहने दिया जा सकता। ये स्कूल हमारी उमरकी हुई पीढ़ी को एक विदेशी भाषा के माध्यम से शिक्षा देते हैं और उनका मानसिक सपोषण विदेशी तौर-नरीकों में करते हैं। इस प्रकार उनकी प्रवृत्ति वर्ग-भेद कायम रखने की ओर बन जाती है और वे भारतीय लोकतन्त्र के बुनियादी तथ्यों के खिलाफ चलते हैं। उन्हें सामान्य राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के अनुसार समान शिक्षा की व्यवस्था तो करनी ही चाहिए, साथ ही अपने कक्षाओं के ५० प्रतिशत स्थान समाज के

अब तक माध्यमिक शिक्षा मुख्यतः मध्य और उच्च मध्य वर्गों के बच्चों तक ही सीमित रही है। अब इस स्तर की शिक्षा का नाम अधिकाधिक प्रमाण में सुविधाहीन तथा कमजोर वर्गों के बच्चों को मिलना चाहिए। इस दिशा में सत्काल कदम उठाने चाहिए, इसमें विलम्ब की कोई गुंजाइश नहीं बची है। यह काम नये तरीकों को अपनाकर रिया जा सकता है। इन तरीकों में अंश-कालिक और अनीप-चारिक शिक्षण को भी स्थान मिलना चाहिए। गावों के गरीब लेकिन प्रतिभाशाली बच्चों को बूढ़ निकालने के लिए सुनिश्चित प्रयत्न किया जाना चाहिए और उदार छात्र-वृत्तियों की व्यवस्था करके इन प्रतिभा-सम्पन्न विद्यार्थियों को सक्रिय महायत्ना दी जानी चाहिए। संक्षेप में, भारत में समाजवादी समाज की रचना के लिए माध्यमिक स्तर पर सबको शिक्षा के समान अवसर सुलभ कराने की बात अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

यद्यपि सामाजिक न्याय तथा राष्ट्रीय मेल-जोल की दृष्टि से सामान्य ज्ञाना पद्धति काफी उपयोगी चीज है, किन्तु राज्य सरकारों को चाहिए कि वे शैक्षणिक संस्थाओं को अध्यापन के तरीकों, परीक्षा-सुधार, पाठ्य-पुस्तकें तैयार करने और अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के क्षेत्रों में नए-नए प्रयोग करने के लिए निश्चित प्रोत्साहन दें। एकरूपता पर जोर देने का भरोसा यह बदापि नहीं होना चाहिए कि शिक्षा के क्षेत्र में नई-नई गोजों और अनुसंधान की प्रवृत्ति रुक हो जाए। फोठारी-आयोग द्वारा मूझाई गई स्वायत्त कालेजों की परिकल्पना में उपयुक्त सुधार और परिवर्तन करके उसे माध्यमिक शिक्षा पर भी लागू किया जा सकता है। इसके फलस्वरूप ये संस्थाएँ ऐसे नए सुधार आरम्भ कर सकती हैं जो विभिन्न दिशाओं में शिक्षा के स्तर को उठाने में सहायक हों। तात्पर्य यह कि शैक्षणिक क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप न्यूनतम रहना चाहिए।

विश्वविद्यालयीन शिक्षा :

इस बात पर आम तौर पर मतभेद है कि विश्वविद्यालयीन स्तर पर, प्रथम उपाधि पाठ्यक्रम की अवधि तीन साल हो। केन्द्रीय शिक्षा

कमजोर बगों के प्रतिभा-सम्पन्न बच्चों के लिए सुरक्षित रखने चाहिए और इन बच्चों के शिक्षण पर होनेवाला खर्च सरकार को उठाना चाहिए। हमारे अतिरिक्त इन स्कूलों को आठवें दर्जे तक कोई गुत्त नहीं देने देना चाहिए क्योंकि नौदह मान की उम्र तक निगुत्त और अनिरार्य प्राथमिक शिक्षा की सुविधा जुटाना हमारा सर्वप्रधान दायित्व है। हमने की जरूरत नहीं कि जो पन्निव स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा-पद्धति को स्वीकार करने से इनकार करें उन्हें बिना किसी रिगेष रहस-म्राहित के मद पर देना चाहिए। किन्तु ऐसा करते हुए इस बात का ध्यान रखा जा चाहिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३० में अल्पसंख्यक समुदायों को दिए गए अधिकारों पर कोई आंच न आए।

राष्ट्रीय शिक्षा अनुमोदन तथा प्रशिक्षण परिषद और राज्य सरकारों ने दम-भाना स्कूलों शिक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम तैयार किया है वह सचमुच ही बहुत शोभीला है। विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित पुस्तकों और अभ्यास पुस्तिकाओं की गणना बहुत ज्यादा है और बच्चों को अपनी पीठ पर अपने भारी बस्ते लादे जैसे-तैसे विद्यालय की ओर जाते देखकर बड़ा दुःख होता है। इनके अलावा पुस्तकीय ज्ञान पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है और उत्पादक या सर्जनरत्मक कार्य के भाग पर तो वहाँ शायद ही कुछ हो। स्कूलों के पाठ्यक्रम पर विचार करके उनमें बड़े परिवर्तन सुमाने के लिए एक रिगेष समिति की नियुक्ति करके शिक्षा मन्त्रालय ने बहुत अच्छा काम किया है। आशा है यह समिति जल्दी ही अपनी रिपोर्ट देगी और अधिकारी इसकी सिफारिशों पर शीघ्रता से अमल करेंगे। यह काम अगले अगस्तमिच सत्र के पूर्व पूरा हो जाए, यह वाछनीय है। पाठ्यक्रम के बोझ को हल्का करने का मतलब शिक्षा के स्तर को कम करना या उसकी गुणवत्ता को घटाना नहीं है। स्कूलों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे छुट्टियों की अवधि काम करके उनका उपयोग सर्जनरत्मक प्रवृत्तियों तथा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप सामुदायिक सेवा में करें।

अब नव माध्यमिक शिक्षा मुख्यतः मध्य और उच्च मध्य वर्गों के बच्चों तक ही सीमित रही है। अब इस स्तर की शिक्षा का लाभ अधिकाधिक प्रमाण में सुविधाहीन तथा कमजोर वर्गों के बच्चों को मिलना चाहिए। इस दिशा में तत्काल कदम उठाने चाहिए, इसमें विलम्ब की कोई गुंजाइश नहीं बची है। यह काम नये तरीकों को अपनाकर किया जा सकता है। इन तरीकों में अग्र-कालिक और अनौपचारिक शिक्षण को भी स्थान मिलना चाहिए। गांवों के गरीब लेकिन प्रतिभाशाली बच्चों को बंद निवाले के लिए सुनिश्चित प्रयत्न किया जाना चाहिए और उदार छात्र-वृत्तियों की व्यवस्था करके इन प्रतिभा-सम्पन्न विद्यार्थियों को सक्रिय महायत्ना दी जानी चाहिए। संक्षेप में, भारत में समाजवादी समाज की रचना के लिए माध्यमिक स्तर पर मयूको शिक्षा के समान अस्मर सुलभ करने की बात अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

यद्यपि सामाजिक न्याय तथा राष्ट्रीय मूल-जोल की दृष्टि से सामान्य ज्ञान पद्धति काफी उपयोगी चीज है, किन्तु राज्य सरकारों को चाहिए कि वे शैक्षणिक समस्याओं को अत्यन्त से तरीकों, परीक्षा-सुधार, पाठ्य-पुस्तकें तैयार करने और अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के क्षेत्रों में नए-नए प्रयोग करने के लिए निश्चित प्रोत्साहन दें। एक-रूपता पर जोर देने का नतीजा यह बन्यो नहीं होना चाहिए कि शिक्षा के क्षेत्र में नई नई न्योजी और अनुमोधान की प्रवृत्ति बढ हो जाए। कोठारी-आयोग द्वारा सुझाई गई स्वायत्त कालेजों की परिकल्पना में उपयुक्त सुझाव और परिवर्तन करके उसे माध्यमिक शिक्षा पर भी लागू किया जा सकता है। इसके फलस्वरूप ये समस्याएँ ऐसे नए सुझाव आरम्भ पर सफल होती हैं जो विभिन्न दिशाओं में शिक्षा के स्तर को उठाने में सहायक हों। तात्पर्य यह कि शैक्षणिक क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप न्यूनतम रहना चाहिए।

विश्वविद्यालयीन शिक्षा :

इस बात पर आम तौर पर मतभेद है कि विश्वविद्यालयीन स्तर पर, प्रथम उपाधि पाठ्यक्रम की अवधि तीन साल हो। केन्द्रीय शिक्षा

सलाहकार समिति के सुझाव के अनुसार सामान्य पाठ्यक्रम (पाठ कोर्स) दो साल का और विशिष्ट पाठ्यक्रम (ऑनर्स कोर्स) तीन साल का रखा जा सकता है। लेकिन यह तय करना देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों पर छोड़ देना बेहतर होगा। विश्वविद्यालय आयोग ने विश्वविद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा के महत्व पर बहुत जोर दिया है। उसका हेतु यह है कि उच्चतर शिक्षा विद्यार्थियों को मुख्यतः 'बाबूगिरी' के लिए तैयार करने का माध्यम बनकर न रह जाए। कहने की जरूरत नहीं कि विश्वविद्यालयीन पाठ्यक्रमों को संबंधित क्षेत्र के विकास कार्यक्रमों में जुड़ा हुआ होना चाहिए, ताकि उच्चतर शिक्षा पर होने वाले खर्च को एक अच्छे-त्तासे हिस्से का उपयोग युवक-युवतियों को राष्ट्रीय आयोजनाओं के अंतर्गत आवश्यक विशिष्ट कार्यों के लिए प्रशिक्षित करने में हो सके। विश्वविद्यालयों तथा विकास-योजनाओं के बीच ऐसा समन्वय स्थापित करके ही हम आज की इस अवदंस्त अमरुति को दूर कर सकते हैं कि एक ओर तो बड़ी संख्या में ऐसे पढ़े-लिखे लोग पड़े हैं जिन्हें रोजगार नहीं मिलता और दूसरी ओर उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित लोगों के अभाव में बहुत-सी विकास-योजनाओं पर अमल नहीं हो पा रहा है।

स्पष्ट है कि कालेजों और विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों को दाखिल करने में विवेक से काम लेना होगा। मसलन, इस बात का ध्यान तो रखना ही होगा कि पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं और अध्यापकों की कहां कितनी सुविधा मुलभ है साथ ही विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए प्रशिक्षित स्नातको (ग्रेजुएट) की माँग का भी खयाल रखना होगा। नई शिक्षा-पद्धति के अधीन यह आशा की जाती है कि माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के बाद कम-से-कम आधे विद्यार्थी या तो अपने प्रयत्नों से अपने-अपने निजी रोजगार आरम्भ कर लेंगे या उन्हें विभिन्न प्रकार के घघों में दूसरों के यहाँ पूरे समय का काम मिल जाएगा। पूर्वस्नातक पाठ्यक्रमों (बडर ग्रेजुएट कोर्स) में केवल उन्ही विद्यार्थियों को प्रवेश देना चाहिए जो विभिन्न ज्ञान शाखाओं

की उच्चस्तर शिक्षा के लिए विशेष रूप से उपयुक्त हों और जिनके पास उसके लिए अपेक्षित तैयारी हो। स्नातकोत्तर (पोस्ट-ग्रेजुएट) पाठ्यक्रमों में तो दाखिले को और भी सीमित रखा होगा तथा इसके लिए विद्यार्थियों के चुनाव की कसौटी और भी बड़ी रखनी होगी। इस मामले में सुयोग्य और विशेषज्ञता प्राप्त लोगो की हमें सचमुच कितनी आवश्यकता है इस पर ध्यान रखना होगा। भारत-जैसे गरीब देश के लिए यह पुमाने सागव बान नहीं है कि वह स्नातकोत्तर शिक्षा पर लबी-चोड़ी रकमें लगाए और जो लोग ऐसी शिक्षा पूरी करके निकलें वे या तो देश का अपनी प्रतिभा के लाभ में वचिन करके हमारे देशों की जरूरतें पूरी करने बाहर चले जाएँ या यह लाभ पर हाथ धरे हाना बँडे रह।

समाज के अपेक्षाकृत सुविधाहीन वर्गों के लोगो को उच्चस्तर शिक्षा की विविध सुविधाएँ सुलभ कराने के लिए अग्र कालिक शिक्षा तथा पत्राचार पाठ्यक्रमों की व्यवस्था बडे पैमाने पर की जानी चाहिए। इनमें रोजगार में लगे नौजवानों को अपनी शैक्षणिक योग्यता में वृद्धि करके अपने-अपने रोजगार-क्षेत्र में तरक्की करने का अवसर प्राप्त होगा। शिक्षा सबधी राष्ट्रीय नीति प्रस्ताव में सुझाव दिया गया है कि 'अग्र-कालिक तथा पत्राचारिय पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्रदान की जानेवाली शिक्षा को बही स्तर दिया जाना चाहिए जो पूर्ण कालिक शिक्षण को प्राप्त है।"

शिक्षा का माध्यम

अब सब स्वीकार करने लग है कि सभी स्तरों की शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। लगभग सभी राज्यों में प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तरों पर यह स्थिति बायम भी हो चुकी है। अगवाद या तो 'पब्लिक स्कूलों' और आज भारतीय समाज द्वारा संचालित स्कूलों या उन राज्यों में ही देखने को मिलते हैं जिनकी सरकारी भाषा अँग्रेजी घोषित की गई है। उच्च स्तर की तकनीकी

और विशेषीकृत शिक्षा देनेवाली अखिल भारतीय संस्थाओं को छोड़ कर अन्य सभी भारतीय विश्वविद्यालयों में अविलंब, शिक्षा के माध्यम के रूप में क्षेत्रीय भाषाओं को अपनाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। जहाँ क्षेत्रीय भाषा-भाषी लोगों के सिवा अन्य भाषाई लोग पर्याप्त संख्या में हों वहाँ हिन्दी या अंग्रेजी माध्यम वाली कुछ संस्थाएँ चलाई जा सकती हैं।

समान अवगदमिक स्तर कायम रखने के लिए बहुत ही तकनीकी ढंग की शिक्षा देनेवाले कालेजों और विश्वविद्यालयों में अभी कुछ समय और, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रखा जाए, यह बात तो समझ में आ सकती है, लेकिन कृषि कालेजों और विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम का चयन निस्संदेह एक गंभीर विसंगति है। जब राष्ट्रीय आयोजन में कृषि-विकास को उच्चतम प्राथमिकता दी जा रही हो, तब आवश्यक हो जाता है कि कृषि-शिक्षण संस्थाओं में उच्चतम स्तर की शिक्षा भी क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से दी जाए। निश्चय ही यह चीज कृषि-रसायनों तथा भारत के करोड़ों किसानों के बीच की विशाल खाई को पाटने में किसी हद तक सहायक होगी।

सभी स्तरों की शिक्षा का माध्यम तो अनिवार्य रूप से मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा ही होनी चाहिए, लेकिन सपक भाषा हिन्दी और अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी का अच्छा काम चलाऊ ज्ञान कराने का आग्रह माध्यमिक और कालेजी दोनों स्तरों पर रखना चाहिए। माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा-युक्त को समान रूप से सबको अपना लेना चाहिए और इसके प्रति अब और विरोध का भाव छोड़ देना चाहिए। हिन्दी-भाषी राज्यों में विद्यार्थियों को हिन्दी और अंग्रेजी के अलावा एक कोई आधुनिक भारतीय भाषा, बने तो दक्षिण भारत की कोई भाषा, सिखानी चाहिए, और अहिन्दी-भाषी राज्यों में क्षेत्रीय भाषा, हिन्दी और अंग्रेजी की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। मुझे पूरी आशा है कि तमिलनाडु सरकार भी इस राष्ट्रीय नीति को स्वीकार करेगी विश्वविद्यालय स्तर पर भी हिन्दी और अंग्रेजी के उपयुक्त पाठ्य-

क्रम सुलभ बनाने चाहिए ताकि राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने और दृढ़ करने के लिए विद्यार्थियों में इन भाषाओं के ज्ञान की अभिवृद्धि की जा सके।

पाठ्य पुस्तकें

राष्ट्रीय भाषाओं को विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए भारतीय भाषाओं में विभिन्न विषयों की स्तरीय पाठ्य पुस्तकें तैयार करना नितांत आवश्यक है। कुछ सान पढ़न शिक्षा मंत्रालय न विभिन्न भाषाओं में विश्वविद्यालयीन पाठ्य पुस्तकें तैयार और प्रकाशित करने के लिए हर राज्य को एक एक करोड़ रुपये की राशि प्रदान की। कुछ राज्यों में इन राशियों का बहुत ठीक उपयोग हुआ है। जरूरी हो तो इसके लिए उन्हें और रकम देनी चाहिए। जब राज्यों में इस महत्वपूर्ण काम को अधिक गंभीरता से हाथ में लेना चाहिए ताकि भारतीय भाषाएँ जिन के सक्षम माध्यम के रूप में विश्वविद्यालयीन स्तर पर अपनाई जा सकें। इसमें देरी करना उचित नहीं है। पाठ्य पुस्तकों को बार बार बदलते रहने की प्रवृत्ति में बचना चाहिए और उनकी कीमत इतनी कम होनी चाहिए जिससे साधारण हैसियत के विद्यार्थी भी उन्हें खरीद सकें। जहाँ तक नए विभिन्न भाषाओं के तकनीकी शब्द एक स होना चाहिए और जहाँ जरूरी हो कम से कम सश्रमण की अवस्था तक अंग्रेजी शब्द भी कोष्ठको में दिए जाएँ तो बेहतर होगा।

भाषा-नीति

राष्ट्रीय गृह मंत्री यह घोषणा कर चुके हैं कि भारत सरकार की भाषा-नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है सरकारी कामकाज में हिन्दी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग माय-साय होता रहेगा। प्रधान मंत्री न भी बार बार कहा है कि देश की आवादी के किसी भी वर्ग पर हिन्दी जबरदस्ती नहीं थोपी जाएगी। इसमें इस सन्देश में चलते रहने का विवाद समाप्त हो जाना चाहिए। साथ ही सभी सश्रमण लोगो को यह समझ लेना चाहिए कि भारतीय भाषाएँ अपनी पूरी

उंचाई तक तभी उठ सकती है जब आमतौर पर प्रशासनिक एवं शैक्षणिक क्षेत्रों में, उनका प्रयोग रूढ़ हो जाए।

हमारी शिक्षण-संस्थाओं के आत्यंतिक अंग्रेजी-मोह का एक मुख्य कारण यह है कि भारतीय सिविल तथा सैनिक सेवाओं में भरती के लिए ली जानेवाली परीक्षाओं का माध्यम आज भी अंग्रेजी ही है। माता-पिता स्वभावतः यह उम्मीद लगाए रहते हैं कि उनके लड़के-लड़कियाँ सरकारी सेवाओं में स्थान पाएँगे। इन सेवाओं में प्रवेश के निमित्त होने वाली प्रतियोगिताओं में सफल होने का एक मात्र रास्ता यह है कि लिखित तथा मौखिक दोनों परीक्षाओं के लिए अंग्रेजी भाषा में महारत हासिल की जाए। निश्चय बात है कि आज भी अधिकांश राज्यों में ऐसी परीक्षाओं का माध्यम क्षेत्रीय भाषाएँ नहीं, बल्कि अंग्रेजी ही है। इसलिए बहुत जरूरी है कि इन प्रतियोगिता-परीक्षाओं का माध्यम अंग्रेजी के बजाय क्षेत्रीय भाषाओं को बनाया जाए। गलत कारणों से अखिल भारतीय प्रतियोगिता-परीक्षाएँ केन्द्रीय स्तर पर हिन्दी या क्षेत्रीय भाषाओं में नहीं ली जा सकती, क्योंकि उस हालत में विभिन्न भाषाओं को इस्तेमाल करनेवाले प्रतियोगियों की योग्यता को परगने के लिए सामान्य मापदंड का प्रयोग लगभग असम्भव होगा। इसलिए उचित यह होगा कि केन्द्र सरकार हर राज्य की आबादी और जय में भारतीय सिविल और सैनिक सेवाएँ आरंभ हुई हैं तबसे उस राज्य के मकल उम्मीदवारों की संख्या, इन दोनों बातों के आधार पर उसके लिए एक 'कोटा' निश्चित कर दें। हर राज्य के निमित्त ऐसा 'कोटा' तय करने के लिए कोई बुद्धिमत्त आधार ढूँढ निकालने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए। क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित प्रतियोगिता-परीक्षाओं द्वारा उम्मीदवारों का चुनाव कर लेने के बाद इन सेवाओं के अखिल भारतीय रूप को कायम रखने के लिए उन्हें हिन्दी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान कराया जा सकता है। प्रशिक्षार्थियों को भारतीय इतिहास, गरकृति, विविधान तथा पंचवर्षीय आयोजनाओं की मोटी-मोटी बातों की भी जानकारी हासिल

करनी चाहिए। कुछ साल के अनुभव के बाद हम व्यवस्था पर फिर विचार किया जा सकता है।

भारतीय विश्वविद्यालयों को अंग्रेजी के अलावा और भी विदेशी भाषाओं के अध्ययन को प्रोत्साहन देना चाहिए। उदाहरण के लिए, कोई कारण नहीं कि स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर कक्षाओं के विद्यार्थी फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, रूसी, चीनी, जापानी तथा हमारे एशियाई पड़ोसियों की अनेक भाषाओं का अध्ययन न करें।

भारतीय भाषाओं के विकास में संस्कृत के विशेष महत्व को देखते हुए राज्य सरकारों को स्कूल और विश्वविद्यालय दोनों स्तरों पर इसके अध्यापन को और अधिक सुविधाएँ देनी चाहिए। चूँकि अधिकतर भारतीय भाषाओं का मूल संस्कृत में है, इसलिए इन भाषाओं के पाठ्यक्रम में संस्कृत भाषा का एक पत्र अनिवार्य कर देना चाहिए। इसके अलावा विभिन्न आधुनिक भारतीय भाषाओं की प्रतिरिक्त लिपि के रूप में देवनागरी के उपयोग का प्रचार किया जाना चाहिए।

नैतिक शिक्षा

राधाकृष्णन् आयोग और कोठारी आयोग दोनों ने यह सिफारिश की थी कि स्कूलों और कॉलेजों में भी एक स्तरीय तथा विभिन्न चरणों में बँटे कार्यक्रम के अनुसार नैतिक और धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, सभी शिक्षण संस्थाएँ अपना काम कुछ मिनट की सामान्य प्रार्थना, और यह न हो सके, तो मौन प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से कर सकती हैं। सभी धर्मों के प्रति समान आदर का श्रेयस्वर यातावरण तैयार करने के लिए हफ्ते में एक-दो वर्ग ऐसे शिक्षण के लिए अलग से रख दिए जाने चाहिए। आरम्भिक अवस्था में विद्यार्थियों को महान धर्म-गुरुओं, उनकी प्रसिद्ध कृतियों, और सभी धर्मों में समान रूप से विद्यमान मूलभूत शिक्षाओं से अवगत कराना चाहिए। उच्चतर कक्षाओं में विभिन्न धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन को प्रोत्साहित दिया जा सकता है। भारत तथा एशिया, अफ्रीका और अमरीका के अन्य विकासशील देशों में बहु भाषी, बहु जातीय तथा बहु-धर्मी समाज की रचना के लिए यह सब अनिवार्य है।

कक्षाओं में धार्मिक शिक्षा देने के अतिरिक्त हमारी शिक्षण-संस्थाएँ वर्ष में पाठ्यक्रमेतर कुछ प्रवृत्तियों का आयोजन करके भी धार्मिक समन्वय और सामाजिक एकरता का स्वस्थ वातावरण तैयार कर सकती हैं। आज भारत के सामने अनैतिकता का संकट उपस्थित है और इसलिए तरुण पीढ़ी के मानस पर नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा सर्वोच्च महत्व की बात है। विभिन्न धार्मिक और नैतिक विषयों का अध्ययन करनेवालों को हो नहीं, बल्कि सभी शिक्षकों को इसे अपना दायित्व समझना चाहिए।

परीक्षा-सुधार :

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ठीक ही कहा है कि "यदि विश्वविद्यालयीन शिक्षा में कोई एक ही सुधार सुझाने की बात छड़े तो यह है परीक्षा-सुधार की बात।" यह बात प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों की परीक्षा-पद्धति पर भी अधिक लागू है। मौजूदा पद्धति विद्यार्थियों की दारौरिक, मानसिक तथा नैतिक क्षमताओं को कुठित करती है। इनकी कलस्वरूप अकादमिक स्तर में गिरावट और अनुशासन में शिथिलता आई है तथा प्रमाण-पत्र, डिप्लोमा और डिग्रियाँ पाने के लिए अनुचित और अवाछनीय तरीकों का उपयोग व्यापक हो गया है। इसलिए वर्तमान परीक्षा-पद्धति में आमूल परिवर्तन अत्यावश्यक है। विभिन्न समितियों और आयोगों ने समय-समय पर इस विषय की गहरी छान-बीन करके कई सिफारिशें की हैं। लेकिन इस समस्या को ऊपर-ऊपर से हल करने की कोशिश अब कारगर होनेवाली नहीं है। 'अव-व्यवस्था' के स्याम पर ग्रेडिंग सिस्टम दाखिल करने का प्रभाव भी सतही ठहरेगा। आवश्यकता केवल परीक्षा-पद्धति में सुधार की नहीं बल्कि मंगूण शिक्षा-पद्धति में सुधार की है। यदि विभिन्न स्तरों की शिक्षा का केन्द्र उत्पादक और सामाजिक दृष्टि से उपयोगी प्रवृत्तियाँ बनाई जाती हैं और उसमें समाज की प्रत्यक्ष सेवा के कार्यक्रमों को स्थान दिया जाता है तो विद्यार्थियों का उत्तीर्ण होकर उच्चतर कक्षाओं में दाखिल

होना वर्ष के अंत में एक व्यापक परीक्षा पर निर्भर नहीं करेगा, बल्कि उत्पादक और पाठ्यक्रम के माप की प्रवृत्तियों में उनके प्रति-दिन भाग लेने पर मुनहसर होगा। ऐसी सह-पाठ्यक्रमीय प्रवृत्तियों में खेल-कूद, समाज सेवा तथा विद्यार्थियों-का सामान्य अनुशासन और आचरण भी शामिल होंगे। वस्तुपरक दृष्टि से आंतरिक मूल्यांकन का मार्ग सुगम बनाने के लिए इन प्रवृत्तियों का तफसील रखना जरूरी होगा। यदि आंतरिक मूल्यांकन के विवरण व्यवस्थित रीति से रखे जाएं और ये विद्यार्थियों, शिक्षकों तथा बाहरी परीक्षकों द्वारा जांच के लिए भेदा सुलभ रहें तो व्यक्तिगत कारणों से होनेवाली भूलों की गुंजाइश बहुत कम हो जाएगी। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों के सर्वांगीण व्यक्तित्व और उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए ध्यावहारिक-कांयों और मौखिक परीक्षाओं को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। संक्षेप में, अंतरिम काल में बाहरी परीक्षा और परीक्षकों की आवश्यकता से छुटकारा पाना भले ही व्यावहारिक न हो, फिर भी आंतरिक मूल्यांकन की पद्धति पर आज की अपेक्षा बहुत अधिक जोर दिया जाना चाहिए। यदि हमारे स्कूलों और कॉलेजों में बुनियादी शिक्षा के मूलभूत सिद्धान्त दाखिल कर दिए जाएं तो परीक्षा-मुद्धार की कठिन समस्या लगभग स्वतः ही हल हो जाएगी।

डिग्रियों और नौकरियों का विच्छेद .

अभी विभिन्न सरकारी विभाग अपने कर्मचारी लोक सेवा आयोगों के माध्यम से, मुख्यतः उम्मीदवारों की डिग्रियों के आधार पर, चुनते हैं। फलतः विद्यार्थियों में डिग्रियाँ हासिल करने के लिए सही-गलत तरीकों से परीक्षाएँ पास करने की प्रबल प्रवृत्ति देखी जाती है, क्योंकि ये एक प्रकार से नौकरियाँ पाने की सुनई होती है। कई वर्ष पूर्व-केन्द्र सरकार ने इस विषय की गहरी छान-बीन के लिए विशेष समिति नियुक्त की थी। समिति की सिफारिश थी कि भारतीय प्रशासनिक विभागों को अध्ययन के अपने पाठ्यक्रम निर्धारित करने चाहिए और उन्हीं पाठ्यक्रमों के अनुसार उम्मीदवारों की परीक्षा लेकर उनका चयन करना चाहिए। सिफारिश के मुताबिक, ऐसे विभागों को

विश्वविद्यालयों की डिग्रियाँ पानेवालों को ही चुनने का आग्रह छोड़ देना चाहिए। गैर-सरकारी नियोजकों को भी ऐसा ही करना चाहिए। ये पाठ्यक्रम उच्चतर माध्यमिक स्तर पर ग्यारहवें और बारहवें दर्जों में दाखिल किए जा सकते हैं, और इसमें पढ़ाए जानेवाले विषय विभिन्न विभागों की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार तय किए जा सकते हैं।

डिग्रियों में नौकरियों को असंगत कर देने से कालेजों और विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए अनुचित आपा-धापी बरम हो जाएगी और परीक्षाओं में प्रचलित भ्रष्ट तरीके मिट जाएंगे, इतना ही नहीं इससे सरकार को भी अपने विभागीय कार्यों के लिए बेहतर उम्मीदवार मिल सकेंगे। इस महत्वपूर्ण सुधार को संपन्न करने का एक व्यावहारिक तरीका सरकारी नौकरियों में प्रवेश की उम्र कम कर देना है। उदाहरण के लिए अगर सरकारी नौकरी में प्रवेश करने की १९ साल कर दी जाए तो आज विद्यालयों में बारह साल की बाल बालों की अधिक सुविधा के स्थान से कालेजों में दाखिला लेने की जो प्रवृत्ति दिखाई देती है यह अपने आप समाप्त हो जाएगी।

राज्य सरकारें तो मुख्यतः राजनीति-उद्देश्यों से प्रेरित होकर, विभिन्न क्षेत्रों में पारंपरिक ढंग के नये-नये विश्वविद्यालय स्थापित करने में एक दूसरे से होड़ करती जान पड़ती हैं। यह बहुत ही हानिकार चीज है और इससे देश के सीमित साधनों की बरबादी होती है। इसलिए उच्चतर शिक्षा में इस तरह की बरबादी और जड़ एकरूपता से बचने के लिए नए विश्वविद्यालयों की स्थापना पर कुछ निश्चित अकुल लगाना चाहिए। शिक्षा आयोग की यह सिफारिश बहुत उचित है कि “जब तक विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग की सहमति न ले ली जाए और घन की पर्याप्त व्यवस्था न हो जाए तब तक कोई नया विश्वविद्यालय स्थापित नहीं किया जाना चाहिए।”

उच्चतर शिक्षा के खर्च की व्यवस्था

गांधीजी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में यह राय जाहिर की थी कि उच्चतर शिक्षा का खर्च राज्य को नहीं बल्कि अपने लिए आवश्यक स्नातको को प्रशिक्षित करने के लिए विभिन्न उद्योगों और व्यावसायिक पढ़ियाँ को उठाना चाहिए। उदाहरण के लिए स्वयं गांधीजी के ही शब्दों में "टाटा कंपनी से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह राज्य की देख रेख में इंजीनियरों के प्रशिक्षण के लिए एक कॉलेज चलाए और मिल एसोसिएशन अपनी जरूरत के स्नातको को प्रशिक्षित करने के लिए कॉलेज चलाए। इस अतिरिक्त इसका भी कोई कारण नहीं है कि उच्चतर शिक्षा पानेवाले सम्पन्न विद्यार्थियों के माता पिता समाज द्वारा उनपर किए जान वाले खर्च को पूरा करने के लिए पर्याप्त शुल्क न दें। हाल में आयोजना आयोग के उपाध्यक्ष डा. त्रिपाठी ने शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में कुछ ऐसा ही विचार व्यक्त करते हुए कहा "उच्चतर शिक्षा की जो शाखाएँ समाज के लिए बहुत लाभदायक हैं और फिर भी जिनमें विद्यार्थियों के पर्याप्त सख्या में दाखिल होने की संभावना नहीं है उनको छोड़ कर हमें शेष उच्चतर शैक्षणिक प्रवृत्तियों का खर्च स्वयं शिक्षार्थियों द्वारा उठाए जाने की संभावना का पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए।

इस बात पर किसी प्रकार के मतभेद की गुंजाइश नहीं है कि आबादी के अपेक्षाकृत कमजोर वर्गों के लाभ के लिए प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र को विस्तार और समृद्धि प्रदान करने के निमित्त पर्याप्त साधन जुटाने के उद्देश्य से हमारी उच्चतर शिक्षा के वर्तमान व्यय को नियोजित ढंग से कम से कम करने की जरूरत है। विशिष्ट ढंग की राष्ट्रीय योजनाओं के लिए शीघ्र ही कार्यकारी सुलभ कराने के निमित्त उच्चतर शिक्षा का अपना अलग महत्व है इससे इनकार नहीं किया जा सकता किन्तु इस तथ्य की ओर से भी आँखें बंद नहीं की जा सकती कि भविष्य में भी वृद्धि

धो जिनकी संख्या बरोडो तक पहुँचेगी, प्रारम्भिक, व्यावसायिक और माध्यमिक शिक्षा मुलभ बनाने के लिए हमें शीघ्र ही आज की अपेक्षा बहुत अधिक धन की जरूरत पड़ेगी।

नई शिक्षा संरचना

इस प्रकार, जैसा कि इस निबन्ध में सुनाया गया है, नई शिक्षा संरचना ८+४+३— अर्थात् आठ वर्ष की अनिवार्य बुनियादी शिक्षा, व्यावसायिक तत्वों की प्रमुखता से युक्त चार वर्ष की उत्तर बुनियादी या माध्यमिक शिक्षा और चार साल की विद्यविद्यालयीन शिक्षा—हो सकती है। बोर्डारी आयोग द्वारा सुझाई गई और मामान्यतया भारत सरकार द्वारा स्वीकृत १०+२+३ की संरचना में उपर्युक्त सुझावों के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। जो राज्य अब तक सिर्फ सात वर्षों की प्रारम्भिक शिक्षा देते आए हैं उनमें यह संरचना ७+५+३ की हो सकती है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मेट्रिकुलेशन परीक्षा सारे देश में समान रूप से दस साल की शिक्षा पूरी होने पर आयोजित की जानी चाहिए।

लेकिन यह बात साफ समझ लेनी चाहिए कि सावधानी के साथ विशद चर्चा के उपरान्त सरकार एक बार जिस किसी संरचना को स्वीकार कर ले उसमें अगले दस पंद्रह वर्षों तक कोई फेर-बदल नहीं किया जाना चाहिए। शिक्षा नीति में बार-बार परिवर्तन करने से तरह-तरह की मानवीय समस्याएँ पैदा होती हैं, इसलिए ऐसे परिवर्तनों से यथासंभव बचना चाहिए।

और कुल मिलाकर देखें तो नई पद्धति और संरचना के अधीन बुनियादी शिक्षा के मौलिक सिद्धान्त की सफलता की आशा रखते हुए उसी समाज में लागू किया जा सकता है जिसमें शारीरिक तथा बौद्धिक श्रम के बीच के अंतर को कम-से कम कर दिया गया है। भारत में भजदूरी और आय की ऐसी नई नीति के अभाव में हमारी शिक्षा प्रणाली को गांधीवादी मूल्यों के अनुरूप नया मोड़ देने की संभावना निश्चित रूप से मृग तृष्णा ही बनी रहेगी। जनता पार्टी के चुनाव-

घोषणापत्र के अनुसार, करों की अदायगी के बाद न्यूनतम और अधिक-तम आयों के बीच के अंतर को कम करके १ २० पर और कालान्तर से १ १० पर लाना होगा।

प्रौढ शिक्षा .

यह मचमुच बड़ी चिंताजनक बात है कि पिछले कई दशकों के दौरान किए गए विभिन्न प्रयत्नों के बावजूद हमारी आवादी का लगभग ८० प्रतिशत भाग आज भी निरक्षर है। स्त्रियाँ के बीच निरक्षरता का प्रतिशत और अधिक है। लोगों को लोकतांत्रिक समस्याओं के संचालन में बुनियादी स्तर से सहयोग करने की मांग प्रदान करने के लिए ही नहीं, बल्कि उत्पादन कार्यक्रमों, विनियम रूप में कृषि तथा ग्रामोद्योगों से जुड़े ऐसे कार्यक्रमों के अमल में गति लाने के लिए भी आम जनता की निरक्षरता को मिटाना बहुत आवश्यक है। राष्ट्रीय विकास में गति लाने के लिए बड़ी बड़ी औद्योगिक तथा व्यावसायिक संगठनों में भी कार्यकर्ताओं को अपने काम के स्थान पर (फक्शनली) साक्षर बनाया जाना चाहिए। इस दिशा में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को आगे बढ़कर मार्ग-दर्शन करना चाहिए। साक्षरता अभियान के संगठन में शिक्षकों और विद्यार्थियों का सक्रिय सहभाग प्राप्त करना होगा। उनका सहयोग विशेष रूप से सामाजिक तथा राष्ट्रीय सेवा कार्यक्रमों के अंग के रूप में प्राप्त करना चाहिए। जैसा कि शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय नीति प्रस्ताव में इंगित किया गया है स्वयं खेती वाली करनेवाले किसानों को शिक्षण देने तथा युवकों को अपने लिए आप ही किसी न किसी रोजगार की व्यवस्था कर लाने के लिए प्रशिक्षित करने पर विशेष बल दिया जाना चाहिए।

इस संदर्भ में गांधीजी के इस विचार को ध्यान में रखना योग्य होगा कि "केवल साक्षरता कोई शिक्षण नहीं है, 'और' प्रौढ शिक्षा बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्तों पर आधारित होनी चाहिए।" केवल पढ़न लिखन और कुछ हिस्से जाड़ने का ज्ञान कराने के बदले भूमि-हीन श्रमिका, किसानों, कारीगरों तथा कारखानों के मजदूरों के उत्पादन कोशिलों का बढाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। साक्षरता से

लोगों में बेहतर नागरिकता-बोध जगाने और उनके व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन को समृद्ध बनाने की भी आशा की जाती है। शिक्षासंवर्धन यूनेस्को आयोग का मुझाव है कि "साक्षरता कार्यक्रमों को नागरिक जीवन और अपने कार्यक्षेत्र से संबंधित बुनियादी शिक्षण से जोड़ देना चाहिए।"

अगले चार बरसों में हमें साक्षरता के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक व्यापक जन-आन्दोलन की आवश्यकता होगी। इस आन्दोलन के लिए पूरे समय के कार्यकर्ता रखना बहुत व्ययसाध्य होगा। हो सकता है, यह इतना सखीला निवले कि हमारी हिम्मत इसे शुरू करने की ही न पड़े। इस राष्ट्रीय अभियान में बहुतसी स्वयंसेवी संस्थाओं, सरकारी नौकरों, वकीला, डाक्टरों और अन्य लोगों की सेवाएँ प्राप्त करनी होंगी। समाचारपत्र, रेडियो, टेलीविजन आदि जनसंपर्क के साधनों तथा दृश्य-श्रव्य उपादानों का सहो उपयोग किया जाना चाहिए। शिक्षकों और विद्यार्थियों के शिक्षण में चूँकि सामुदायिक सेवा और उत्पादक प्रवृत्तियाँ अनिवार्यतः शामिल रहेंगी, इसलिए उनके शिक्षण के अंग के रूप में उनसे इस कार्यक्रम में सहयोग लेना चाहिए। अकादमिक वर्ष के दौरान सिर्फ चार हफ्ता के लिए वे ऐसे अभियानों में शरीक हों तो यह चीज न तो वैज्ञानिक होगी और न इससे कोई प्रयोजन सिद्ध होगा। सच तो यह है कि स्वयं शिक्षा-पद्धति को आद्योपान्त कामवाजी (फमशनल), सृजनात्मक और उत्पादक, सभी कुछ बन जाना चाहिए।

भारत सरकार ने हाल में केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा मंडल का गठन किया है। मंडल ने सिफारिश की है कि पाँच साल के अंदर आवादी के १५-३५ के आयु वर्ग के बीच प्रौढ़ शिक्षा के प्रसार के लिए सभी संभव कोशिश की जानी चाहिए। इस राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों को अपने कार्यक्रमों के बीच पारस्परिक समन्वय स्थापित करना होगा।

स्पष्ट है कि कोई भी शिक्षा-प्रणाली कागज पर चाहे जितनी आकर्षक प्रतीत हो, उसका सफल कार्यान्वयन तो ठीक प्रशिक्षित ऐसे अध्यापकों के बल पर ही संभव है जो कोई बड़ा काम करने के आदर्श और समर्पण की भावना से ओत-प्रोत हों। अपने सम्पर्क में आने-वाली उदीयमान पीढ़ी के चरित्र को सही ढाँचे में ढालना अध्यापक का काम है; वे सच्चे अर्थ में राष्ट्र-निर्माता हैं। इसमें सन्देह नहीं कि विद्यार्थियों को समाज के प्रति अपना दायित्व निभाने के निमित्त प्रशिक्षित करने के लिए उन्हें कुछ भी उठा नहीं रखना चाहिए। लेकिन अध्यापकों के सामाजिक दर्जे को ऊपर उठाने और उन्हें दैनिक आर्थिक परेशानियों से मुक्त करने की जिम्मेदारी राज्य की है। ईंट-सीमेंट और लोहे-इस्पात पर जरूरत से ज्यादा खर्च करने के बजाय, प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के वेतनों में वृद्धि करना कहीं अधिक लाभकारी होगा। शैक्षणिक सस्थाओं के स्तर का निर्णय उनके भव्य भवनों के आधार पर नहीं, बल्कि उनमें नियुक्त अध्यापकों की योग्यता के आधार पर किया जाना चाहिए।

इस वर्ष सितम्बर माह में सेवाग्राम में शिक्षकों के प्रशिक्षण पर आयोजित गोष्ठी ने सिकारिश की थी कि बुनियादी शिक्षा के मुख्य सिद्धान्तों को अध्यापक-शिक्षण सहित, सभी स्तरों की शिक्षा में ओत-प्रोत हो जाना चाहिए। "सभी स्तरों के अध्यापक-शिक्षण कार्यक्रमों के अभिन्न अंग के रूप में उत्पादक कार्य और सामुदायिक शिक्षण के समावेश" पर भी गोष्ठी में पूरा मतैक्य था। गोष्ठी का सुझाव था कि "सभी प्रशिक्षण-सस्थाओं को अपने-आपको स्वावलम्बन, सहयोग और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित व्यवस्थित समुदायों के रूप में संगठित कर ढालना चाहिए।"

इसके अतिरिक्त, उत्पादक तथा सोद्देश्य शिक्षा-पद्धति के अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए शिक्षकों को विद्यार्थियों के कंधे से कंधा मिलाकर काम करना सीखना चाहिए। इस प्रकार, "सहवीर्य

करवावहूँ" का प्राचीन आदर्श बोरे ऊँने दर्शन की बात नहीं है, बल्कि फलप्रद शिक्षा के लिए सुझाया एक व्यावहारिक मार्ग है। नए अध्यापकों को कृषि तथा कुटीर उद्योगों का प्रशिक्षण देने के बजाय हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे कृषक-अध्यापकों या शिल्पी-शिक्षकों के वर्ग का उदय हो और हम अपनी शिक्षण-संस्थाओं की योग्य अध्यापकों की माँग पूरी कर सकें।

माता-पिता का सहयोग -

भारत में शिक्षा पद्धति की पुनर्रचना के काम में सभी स्तरों के विद्यापियों के माता-पिताओं का सक्रिय सहयोग आवश्यक है। आरम्भिक अवस्था से ही माता-पिताओं को घर और स्कूल दोनों जगहों में अपने बच्चा की प्रगति की ओर पूरा-पूरा ध्यान देना चाहिए, और उनके तथा शिक्षकों के बीच पूरा सहयोग होना चाहिए। इसके लिए हर शिक्षण-संस्था में सक्रिय अभिभावक-अध्यापक संघ का होना जरूरी है। दोनों का ऐसा पारस्परिक सम्पर्क शैक्षणिक स्तर को ऊपर उठाने में सहायक होगा और इससे विद्यापियों के व्यक्तित्व का विकास अधिक ठोस बुनियाद पर हो सकेगा। शिक्षापियों को अनुशासित करने और उनके सामान्य आचार-व्यवहार में सुधार लाने के लिए भी माता-पिताओं की सहायता लेने का प्रयत्न किया जा सकता है। दरअसल, हर घर को सच्चे अर्थों में शैक्षणिक विकास की बुनियादी इकाई बन जाना चाहिए। घर और शाला के बीच दो-तरफा समागम होना चाहिए और दोनों को एक-दूसरे के पूरक बनकर एक-दूसरे को समृद्ध करने का काम करना चाहिए।

खेल-कूद -

नई शिक्षा-पद्धति के अंतर्गत हमारे स्कूलों और कालेजों में खेल-कूद का विकास बड़े पैमाने पर किया जाना चाहिए। श्रौटो-स्थलों तथा अन्य मनोरंजनात्मक प्रवृत्तियों की सुविधा उदारता के साथ सुलभ करानी चाहिए। शारीरिक शिक्षण कार्यक्रमों के अधीन योगासनो का प्रशिक्षण अनिवार्य कर देना चाहिए। एन सी सी तथा ए एस एस के अतिरिक्त शिक्षण-संस्थाओं में लडके-लडकियों

दोनों के लिए स्वर्गति प्रवृत्ति को सुनियोजित ढंग से बढ़ावा देना चाहिए। इससे विद्यार्थियों में न केवल गैर-मरवारी ढंग से अनुशासन की बहतर भावना का समावेश होगा, बल्कि उन्हें विविध प्रसंगों में सामाजिक सेवा के अवसर भी सुलभ होंगे।

— पर्याप्त वित्तीय साधन की व्यवस्था

ऊपर सूनाए गए ढंग पर शिक्षा पद्धति की पुनर्रचना के लिए स्पष्ट ही अतिरिक्त वित्तीय साधनों की आवश्यकता पड़ेगी। पञ्चवर्षीय आयोजनों की दृष्टि से देखें तो हम देखते हैं कि जहाँ तीसरी आयोजना में शिक्षा पर कुल राष्ट्रीय आय का ६.८७ प्रतिशत व्यय करने का प्रावधान था चौथी में यह प्रतिशत घट कर ५ पर और पाचवी में तो ३.२७ पर आ गया। यह सच है कि यदि शिक्षा पर आयोजनाओं के अधीन और उनके बाहर खर्च की जान वाली राशियों को ध्यान में रखकर देखा जाए तो आकड़े कुछ भिन्न तसवीर पेश करेंगे। फिर भी कुल मिलाकर स्थिति किसी तरह सन्तोषजनक नहीं है। जैसा कि शिन्धुनाम्नबद्धी राष्ट्रीय नीति प्रस्ताव में सुझाया गया है हमारा लक्ष्य शिन्धुनाम्नविनियोग में उत्तरोत्तर वृद्धि करते जान का होना चाहिए और यथासंभव दीर्घ ही हम उसको राष्ट्रीय आय का ६ प्रतिशत तक पहुँचा देना चाहिए। इस दिशा निर्देश का अनुसार छठी पञ्चवर्षीय आयोजना में शिक्षा के लिए पर्याप्त वित्तीय साधन की व्यवस्था की जानी चाहिए।

आविर्कार आगामी वर्षों में शैक्षणिक सुधार की सफलता केंद्रीय जनता सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति और सकल्य पर निर्भर करेगी। यदि नई सरकार वर्तमान शिक्षा पद्धति को नए सौच में ढालने के द्वार में सचमुच गंभीर है तो उस कई साहसपूर्ण निश्चय लेन हाँ। फूँक फूँककर कदम उठाते हुए समस्या को हल करने की मत्तही इच्छा भर से काम नहीं चलेगा। जहाँ सच्ची चाह है राह तो वहाँ मिल ही जाती है।

आज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा में विचारणीय प्रश्न

श्री रघुकुल तिलक

प्रधान-मंत्री जी के प्राप्ति के बाद मेरे पास बहुत कुछ कहने को नहीं है। किन्तु अध्यक्षजी ने मुझ से कुछ शब्द कहने के लिए कहा है अतः मैं अपने को केवल कुछ ऐसी बातों पर ही सीमित रखूँगा, जिन्हें अगस्त के दो दिनों के दौरान विचार-विमर्श हेतु दृष्टि में रखना आवश्यक है।

यह कहना सही है कि हमारी शिक्षा-प्रणाली हमारी सामाजिक व्यवस्थाका एक भीतरी अंग है। समाज में जो ताकत या जो कमी है वह सब हमारी शिक्षा प्रणाली में प्रतिबिम्बित होती है। हमारा समाज अभी भी भर्त्सित तथा जाति-प्रसिद्ध समाज है, जिसमें समतल और सम्व-रूप गतिशीलता बहुत कम है। इसकी प्रति व्यक्ति आप भी बहुत कम है। यद्यपि इन सबपर सबकी समान रूप से सहमति नहीं है फिर भी इन्हें हमें दृष्टि में रखना है क्योंकि ये हमारी शिक्षा-प्रणाली में प्रतिबिम्बित होती है। साथ ही हमें यह जान लेना है कि सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा अत्यन्त सक्षम और सशक्त माध्यम है। यही कारण है कि जब हम समाज के इन अस्वीकृत तत्वों को हटाना चाहते हैं तो ऐसा करने को हमारे पास शिक्षा ही एकमात्र माध्यम है। शिक्षा को यदि सामाजिक स्थितियों को प्रतिबिम्बित करने और साथ ही उनमें परिवर्तन लाने की दुहरी जिम्मेवारी निभानी है तो उसे प्रासंगिक, सक्षम तथा नवीन होना चाहिए।

प्रासंगिकता स्पष्ट है और हमें यह पहचान लेना चाहिए कि हमारी शिक्षा प्रणाली प्रासंगिक नहीं रह गई है। जब शिक्षा की यह

प्रणाली स्थापित की गई थी तब यह प्रासंगिक थी। अंग्रेजों का उस समय एक निश्चित उद्देश्य था, वे पढ़े लिखों के महारे अपना राजकाज चलाना चाहते थे और सर्वसाधारण को अशिक्षित रखने में ही वे अपना हित देखते थे। किन्तु अब स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् अब यह प्रणाली गिकता इस रूप में समाप्त हो गई है। अब तो हमें यह प्रयत्न करना है कि अधिकतम संख्या में देशवामी शिक्षित हों। हमारे देश में आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक परिवर्तन हो गए है और हमारी शिक्षा-व्यवस्था इन तेजी से होने वाले परिवर्तनों के साथ कदम रखने में असफल हो गई है इसी कारण वह अप्रासंगिक हो गई है।

जब गांधीजी ने बुनियादी शिक्षा दी तब वे इस प्रणाली को सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना चाहते थे। यही हमें समझना है। आजकी शिक्षा को हमें अपने आज के आर्थिक सामाजिक और राजनैतिक ढांचे के अनुरूप बनाना है। प्रासंगिकता पहली बात है जिसकी ओर हमें ध्यान देना है, तब हमारी शिक्षा प्रणाली लचीली होनी चाहिए। यदि शिक्षा प्रणाली अत्यधिक कठिन और बेसोच होती है तो वह तेजी से होनेवाले सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तनों के साथ कदम नहीं रख पाएगी अतः उसका लचीला होना अत्यावश्यक है। लचीला बनाने के लिए उसका विकेंद्रीकरण आवश्यक है। लेकिन यदि उसे बहुत अधिक विकेंद्रित कर दिया जाए तो उसमें परिवर्तन करना बहुत कठिन हो जाएगा। हमारे संविधान-निर्माताओं ने शिक्षा को प्रदेशों पर छोड़ा यह उचित ही था। मैं भी इस विचार से सहमत हूँ कि शिक्षा प्रादेशिक सरकारों का विषय रहे। प्रदेशों में दूसरा और विकेंद्रीकरण होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा, क्षेत्रों और जिलों पर छोड़ देना चाहिए। तब प्रयोग करना अधिक सरल हो जाएगा तथा स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन किया जा सकना संभव हो सकेगा। अतः हमें यह देखना है कि जो भी शिक्षा प्रणाली हम अंतिम रूप से काम में लाना चाहते हैं वह अत्यधिक बेसोच नहीं हो जाती है जिससे वह समय के परिवर्तन के साथ कदम न मिला सके।

पिछले कुछ वर्षों में समाज तेजी से बदला है और आगामी कुछ सदियों तक वह सामान्य समय की अपेक्षा अधिक तेजी से बदलेगा अतः हमारी शिक्षा प्रणाली का लचीला होना आवश्यक है।

मेरा अन्तिम सुझाव यह है कि हमारी शिक्षा प्रणाली सक्षम हो। वह अपने में निहित उद्देश्यों की ओर सक्षमता से ले जाने वाली हो। हम जानते हैं कि हमारे विश्वविद्यालय युवकों को इस प्रकार तैयार कर रहे हैं कि वे रोजी पाने में असमर्थ हो रहे हैं और जैसा कि हमारे प्रधान मंत्री जी न ठीक ही कहा है कि उनमें बहुत बड़ा ज्ञान होता है और चरित्र तो बहुत ही कम। यह ऐसी बात नहीं है कि जिस पर हम अभिमान कर सकें। यह विश्वविद्यालयों की ही जिम्मेवारी है कि वे जीवन के हर क्षेत्र में समय के अनुरूप नेतृत्व दे सकें बिना विश्वविद्यालय ऐसा नहीं कर रहे हैं। अतः जो भी प्रणाली हम सोचें वह सक्षम हो अर्थात् ऐसे यत्न तैयार करने पानी हो जो वर्तमान संदर्भ में समाज के लिए उपयोगी हो।

उच्च स्तरीय शिक्षा के संदर्भ में भी यही बात है कि वह भी लचीली सक्षम एवं उपयोगी होनी चाहिए। मुझे आशा है कि इन्हीं सब दृष्टियों से चर्चाओं में विचार किया जाएगा।

मैंने प्रसन्नता है कि हमारे प्रधान मंत्रीजी चाहते हैं कि जो भी निर्णय हो उसे तुरन्त लागू किया जाए। जैसा कि अपने प्रास्ताविक भाषण में श्रीमन्मन्त्री ने सकारात्मक किया है— हमने बहुत सी उपसमितियाँ बनाईं कई कमिशन नियुक्त किए लेकिन कुछ परिणाम न निकला। हम कई सम्मेलन करने हैं समितियाँ बनाते हैं पर परिवर्तन कुछ नहीं होता। मेरा विश्वास है कि इस सम्मेलन का ऐसा परिणाम नहीं होगा वरन् इससे कुछ न कुछ उपाय अवश्य निकलेंगे। और उसपर भी ध्यान दिया जाएगा।



शिक्षा आर्थिक परिप्रेक्ष्य में

श्री लकड़ावाला

मैं दो रुकावट से ग्रस्त हूँ। एक तो शिक्षा के क्षेत्र में मेरा अनुभव विश्वविद्यालयीन स्तर तक सीमित है और वह भी विषय रूप से अर्थशास्त्र विषय तक। मेरी वर्तमान अभिरुचि योजना में है। दूसरी रुकावट यह है इस विषय के दो विशेषज्ञ मूझमे पहल बोल चुके हैं। अतः स्पष्ट है कि मेरे कहने के लिए बहुत कम रह गया है। मैं योजना से सम्बद्ध सीमा तक ही अपनी बातों को सीमित रखूँगा।

जैसा कि आप जानते हैं नई योजना में ग्रामा की आर अधिक झुकाव है, कृषि की ओर अधिक झुकाव है तथा तत्संबन्धी तकनीक की ओर अधिक झुकाव है। स्पष्टतः इन्हीं झुकावों से शिक्षा का झुकाव प्रभावित है। ऐसी स्थिति में यह भी स्पष्ट है कि हम अधिकतम महत्व प्रौढ़ शिक्षा या औपचारिक शिक्षा प्रणाली को देंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस सम्मेलन में इस समस्या पर भी विचार करण और अपने आपको केवल औपचारिक शिक्षा तक ही सीमित नहीं रखेंगे। औपचारिक शिक्षा के क्षेत्रको पार करना तो थोड़ा सरल है यद्यपि इसमें तो छात्रों को अन्य कोई विकल्प नहीं होता सिवा इसके कि वे पाठशाला में आकर अपना निर्धारित पाठ्यक्रम निर्धारित अवधि में पूरा कर किन्तु प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में और अधिक आह्वान का क्षेत्र है जहाँ शिक्षाकी प्रासंगिकता की सच्ची परख होती है और यदि वह प्रासंगिक नहीं होती तो प्रौढ़ लोग उसे स्वीकार ही नहीं करते। इस दृष्टिकोण से मैं आपसे अत्यधिक प्रार्थना करूँगा कि आप कृपया अपनी चर्चाओं में दोरान प्रौढ़ शिक्षा पर अधिक ध्यान देंगे।

जहाँ तक प्राथमिक शिक्षा का प्रश्न है, मैं साबित हूँ कि हमने गत कुछ वर्षों में काफी प्रगति की है। अब मुख्य समस्या अधिक शालाएँ प्रारम्भ करने की नहीं है बल्कि यह है कि खुली हुई पाठशालाओं में छात्र

आते हैं और निर्धारित अवधि तब शिक्षा ग्रहण करते हैं। छात्रों के केवल भर्ती होने, शालाओं में कुछ दिनों तक उपस्थित होने और उपस्थित होकर सफलतापूर्वक पाठ्यक्रमों को पूरा करने—इन सब में महान् अन्तर है। मैं देखता हूँ कि शिक्षकगण केवल भर्ती-संख्याको पूरी करने की ओर ही अधिक ध्यान देते हैं। महत्वपूर्ण तो यह है कि छात्र नियमित रूप से शालाओं में उपस्थित होकर अपना निर्धारित पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करें। बुनियादी तालीम इस प्रकार की आवश्यक हो कि वह छात्रों को शालाओं में आने, उपस्थित रहने तथा पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए आकर्षित करे।

जहाँ तक उच्च शिक्षा का विशेषतः विश्वविद्यालयीन शिक्षा का प्रश्न है गत तीन वर्षों में हमने इस मद पर काफी रुपा खर्च किया है। मैं यह जानता हूँ कि अन्य प्रगतिशील देशों की तुलना में यह राशि पर्याप्त नहीं है फिर भी गत वर्षों की अपेक्षा हमने काफी अधिक खर्च किया है। अब हम यह देखना चाहिए कि जो कुछ हमने खर्च किया है उसके अनुकूलतम और अधिकतम परिणाम हम मिल रहे हैं क्या? मैं सोचता हूँ कि हमने उच्च शिक्षा को प्रत्येक छात्रके लिए मूलतः बहुत सस्ता बना दिया है। हाँ, इस में तो मुद्दा हो सकता है कि हम गुणवत्ता के आधार पर छात्रों का चुनाव कर उनके लिए उच्च शिक्षा को रास्ता बनाएँ। उच्च शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाने की उपयोगिता तभी है जब प्रत्येक व्यक्ति उसकी पूरी कीमत चुकाने को सँयार हो। यह एक प्रकार से मुक्त व्यावसायिक अर्थशास्त्र है और दूसरा समाजवादी अर्थशास्त्र जहाँ हम प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता के अनुरूप तथा उसके द्वारा की गई समाज सेवाओं के अनुरूप देते हैं। मुझे भय है कि इन दोनों में हमने बुरी सुलह या सन्धि की है। हमने लगभग सभी को विश्वविद्यालयीन शिक्षा प्रदान करने की अनुमति देने की प्रणाली अपनाई है और उसके लिए शासकीय अनुदान देते हैं जिसका भार जनता पर पड़ता है। पर आपको ध्यान होगा कि तीन चार वर्ष पहले विदेश में भीषण हड़ताल का सामना करना पड़ा था। जब तक विद्यार्थियों से चर्चा की जाती है तब तक तीन चार दिनों तक तो महाविद्यालय और विश्व-

विद्यालय बंद हो जाते हैं। परिणामतः छात्र चिंतित हो जाते हैं और जितने दिन पढ़ाई नहीं होती है उतने दिनकी दी गई फीस के विषय में सोचने लगते हैं। पढ़ाई की फीस इतनी अधिक होती है कि हड़ताल के कारण या महाविद्यालय के बंद होने के कारण न होनेवाले लेक्चर्स के सदर्थ में वे सोचने लगने हैं।

हमारी प्रणाली में चूंकि यह मूल्य कुछ नहीं होता अतः महाविद्यालयों या विश्व विद्यालयों द्वारा न किए गए काम को कोई महत्व नहीं देता। अब हमें अविलम्ब यह सोचना होगा कि हम कबल उही छात्रों को शासकीय अनुदान दे जो प्राप्त शिक्षा से अधिक से अधिक लाभ अर्जित करते हैं। दूसरों से हम पूरी फीस वसूल कर या फिर कर्ज के रूपमें उन्हें सहायता दे जिससे कर्ज लनवाले समझ पाएँ कि जो शिक्षा वे पाएँ वह उस कर्ज के लायक है या नहीं।

अब मैं अंतमें यह कहना चाहता हूँ कि जब जब मैं इस प्रकार के सम्मेलनों में शामिल होता हूँ तब तब शिक्षा विशेषज्ञों में एक प्रवृत्ति पाता हूँ और वह है राष्ट्रीय आयमें से शिक्षा के हेतु आनुपातिक राशिक सबध की। यह कुल मिलाकर राष्ट्रीय आय के शत प्रतिशत से भी अधिक होती है। आप इस दिशा में भी योजित और जो योजित नहीं हैं दोनों पर विचार करें और उसमें भी प्राथमिकता के क्रम से विचार करें। क्योंकि विशेषज्ञों के निर्णय राष्ट्र के तद्विषयक भाग्य निर्मितिम सहायक होते हैं और उन्हींके आधार पर कार्य की प्राथमिकता एवं महत्ता निर्धारित होती है।



शिक्षा की पुनर्रचना

डॉ. सतीशचंद्र

अध्यक्ष महोदय, डॉ. चंद्र तथा इक्ठ्ठा हुए मित्रगण ! मैं यहाँ कुछ कहने की वजाय अधिक सुनने के लिए आया हूँ। प्रधान मंत्रीजी ने वृत्तापूर्वक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इस पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए कहा है कि राष्ट्रीय वरीयताओं की दृष्टि से शिक्षा की पुनर्रचना कैसे की जा सकती है? इन वरीयताओं का उल्लेख बहुत पहले डा. कोठारी की अध्यक्षता वाले कमीशन के सामने उनके द्वारा बोल जाते समय कर दिया गया है। उसके बाद भी प्रधान मंत्रीजी के साथ चर्चा करते समय भी इनका उल्लेख हो चुका है। कन्द्रीय शिक्षा मंत्री डा. प्रताप नन्द्र चदर ने भी सरकारी वरीयता का उल्लेख अनेक अवसरों पर किया है और जहाँ तक विषय रूप से वरीयताओं का संबंध है हम कह सकते हैं कि इस सम्बन्ध में कोई मतभेद नहीं रह गया है। मुझे विश्वास है कि इस सम्मेलन में भी इस विषय पर कोई बड़ा मतभेद नहीं होगा। हमारा सर्वाधिक जोर बुनियादी तालीम पर है जिसमें, हम सर्वाधिक जोर चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व निर्माण पर, गुणों पर, जीवन की मूल्यों को तथा समाजवाद पर दें। ये ये कुछ तत्व हैं जिन्हें आयोग ने भी ध्यान में रखा है। आयोग ने प्रधान मंत्रीजी तथा शिक्षा मंत्रीजी को एतद्विषयक एक दस्तावेज दिया है और हम आशा करते हैं कि उनके साथ विस्तृत चर्चा करने का हमें लाभ मिलेगा। उच्च शिक्षा ही नहीं बल्कि वास्तव में संपूर्ण शिक्षा प्रणाली के साथ वरीयता के अतिरिक्त प्राथमिक समस्या—जैसा कि तिलकजी ने कहा था—यह है कि हमारी शिक्षा प्रणाली द्वेष है। हमारी शिक्षा प्रणाली अच्छी तो है लेकिन वह बहुत कम अल्पसंख्यक लोगों के लिए मूल्यवान है। इन्हीं

अल्प संख्यकों के लिए प्राथमिक शालाएँ हैं : इन्हों अल्प संख्यकों के लिए पब्लिक स्कूल हैं और जहाँ तक उच्च शिक्षा का सम्बन्ध है यह बताया गया है कि विश्व विद्यालयों तथा विविध व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में ८० प्रतिशत स्थान तो अधिस्तम आय के दायरे वाले लोग ही रोक लेते हैं। समस्या यह है कि इस द्वंद्व ग्रासन से कैसे छटकारा पाया जाए अथवा इससे बन्धनों को ढीला कैसे किया जा सके ? यह द्वंद्व प्रणाली अन्य सामाजिक तथा आर्थिक प्रणाली में असमानता की पारम्परिक जड़ है। मैं एक छोटासा उदाहरण देना चाहूँगा। हमारे देश में ४००० से अधिक महाविद्यालय हैं। इनमें लगभग ३२०० विज्ञान या वाणिज्य महाविद्यालय हैं। विश्व विद्यालय अनुदान आयोग ऐसे महाविद्यालयों की सूची रखता है जो उसकी सहायता के अधिकारी हैं। इन अधिकारी महाविद्यालयों को हम दो एफ के अंतर्गत परिगणित करते हैं। इन ३२०० महाविद्यालयों में से केवल २७०० महाविद्यालयों ने दो एफ के अंतर्गत ममायिष्ट किए जाने के लिए प्रार्थना पत्र दिए हैं। ये महाविद्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता के पात्र हैं। आयोग इन सभी महाविद्यालयों की सहायता नहीं दे सकता क्योंकि वह तदर्थ छात्र संख्या, प्राध्यापक संख्या, दी जानेवाली न्यूनतम सुविधाएँ संबंधी कुछ मानदंड निर्धारित करता है। वह इसलिए कि आयोग का काम गुणवत्ता को बढ़ाना, मानदंड को ऊँचा करना आदि भी है, केवल सहायता करना मात्र नहीं। अतः जहाँ तक आयोग का सम्बन्ध है, इन २७०० महाविद्यालयों में से केवल २००० महाविद्यालय इसकी सहायता के अधिकारी हैं।

अब यह देलना है कि इस परिस्थिति का सामना हम किस प्रकार करते हैं। यह सच में योजना आयोग के उपाध्यक्ष द्वारा की गई टिप्पणी के मंदर्भ में कह रहा हूँ। यह सच है कि जब जब विशेषज्ञ इकट्ठा होते हैं तब तब वे अधिक अर्थ (द्रव्य) की माँग करते हैं और योजना आयोग भी विशेषज्ञों की ही एक संस्था है। वे सदा निर्णय कर सकते हैं कि हमारी प्राथमिकताएँ क्या हैं। मैं चाहूँगा कि यह सम्मेलन यह भी निश्चित करे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की प्राथमिकताएँ क्या हों।

या तो वह प्रत्येक महाविद्यालयों को अनुदान दे या मानदंड से उसका निर्णय अधिक सख्त हो ? अनुदान आयोग की अधिक मीमांसा को ध्यानमें रखते हुए ही विचार किया जाना इस गरीब देश की आवश्यकता है। हम थोड़ी थोड़ी रकम सभी महाविद्यालयों को दे सकते हैं किन्तु उससे स्तर पर हमारा कोई निबंध नहीं रह जाएगा और इससे द्वैध व्यवस्था तथा द्वेय परिणाम ज्यों के त्यों बने रहेंगे और यह थोड़ी रकम भी थोड़े ही महाविद्यालयों को लाभान्वित कर पाएगी। हमारा उद्देश्य यह है कि जितने भी महाविद्यालयों को दे सर्व अधिकतम महायत्ना दें और वह भी विशेषतः पुस्तकों और प्रसाधनों के रूपमें। किन्तु हम यह अवश्य ध्यान रखते हैं कि जिले की इराईवार और चरणवार श्रेष्ठ महाविद्यालयों की स्थापना संभव हो जिससे अधिक से अधिक सख्या में मेधावी (बुद्धिमान) छात्रों को महाविद्यालयीन अध्ययन करने की सुविधा प्राप्त हो सके। अपनाया जा सकने वाला हमारा दूसरा पर्याय या पूरक पर्याय यह है कि गरीब छात्रों को सुविधा दी जाए और इस प्रकार वे प्रतिष्ठा प्राप्त महाविद्यालयों में प्रवेश पा सकें। इन दोनों व्यवस्थाओं के लिए पैसे की आवश्यकता है और मैं सोचता हूँ, यदि योजना आयोग संकेत दे और वही संकेत दे सकता है कि कितनी राशि उच्च शिक्षा के लिए निर्धारित की जाए और यदि प्राथमिकताएँ निर्धारित की जाती हैं तो द्वैध प्रणाली में छिद्र करना प्रारम्भ किया जा सकता है।

जहाँ तक मैं देख पाता हूँ मुझे भय है कि सीमित साधनों के भीतर यह संभव नहीं है कि आशा की जा सके कि ३२०० महाविद्यालयों को समान उच्चस्तर तक उठाया जा सके। यदि धन ही तो ठीकते आवश्यक योग्यता वाले व्यक्ति उपलब्ध नहीं है। और योजना आयोग प्रयत्न कर रहा है कि उन्नत करनेके कार्यक्रमों द्वारा वर्तमान शिक्षकों का स्तर समुन्नत किया जा सके।

मैं प्रासंगिकता संबंधी समस्या के विषय में कुछ कहने की अनुमति चाहता हूँ। यह सचमुच एक गम्भीर समस्या है। किन्तु यह समस्या एक मान भारत के लिए ही विचित्र नहीं है। यूनेस्को द्वारा प्रकाशित 'लॉनिंग टू वी' नामक पुस्तक में इस मुद्दे पर विस्तारपूर्वक विशेष जोर

दिया गया है कि ऐसा नहीं है कि संसारके समुन्नत देश अपनी समस्त समस्याओं को सुलझा पाए हैं और केवल अर्द्ध समुन्नत या अनन्त देशों को ही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जितनी तेजी से समाज बदल रहा है जितनी तेजी से तकनीकी परिवर्तन हो रहे हैं उन सबकी दृष्टि से सभी देशों में शिक्षा असामयिक होती जा रही है। हमारे देश में चूँकि वह अधिक असामयिक है और इसीलिए प्रासंगिकता की समस्या हमारे यहाँ अन्य देशों की अपेक्षा अधिक कठिन है। लेकिन यहाँ की जिस समस्याको रघुकुन तिनबजी ने उठाया है उसके संबंध में मैं स्पष्ट कहूँ कि मैं नहीं जानता कि क्या उत्तर दिया जाए ? किए जानेवाले परिवर्तन तो सहज ही सुझाए जा सकते हैं लेकिन ज्यों ही उनका कार्यान्वयनकी बात आती है त्यों ही चारों ओर से विरोध होना शुरू हो जाता है।

परीक्षाओं में सुधार का प्रश्न एक ऐसा ही प्रश्न है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अनेक कमिशनो की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा में सुधार की एक योजना प्रस्तुत की जिसमें उसने अतर्गत अकादमिक प्रश्न वैसे तथा अन्य कई महो पर बल दिया। जब नई प्रणाली को काम में लाने की बात आती है तब शिक्षक तथा छात्र नई प्रणाली के प्रयोग की अपेक्षा तथा अ य प्रयोगोंकी अपेक्षा पुरानी प्रणाली का जारी रखा जाना ही अधिक पसन्द करते हैं यद्यपि वे उसके दोषों के जानबूझते हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसे सम्मेलन तथा अन्य कई माध्यमों द्वारा वैचारिक वातावरण बनाना होगा। बिना उपयुक्त वैचारिक वातावरण बनाए जो भी परिवर्तन सामने रखे जाएंगे, उन्हें कार्यान्वित नहीं किया जा सकेगा।

और मैं यह कहना चाहूँगा कि यद्यपि उपाध्यक्ष ने इस बात पर जोर दिया है कि हमने उच्च शिक्षा पर बहुत अधिक खर्च किया है मैं समझता हूँ कि उच्च शिक्षा को हम अधिक तात्कालिक बनाना है। जब हम अपने स्तरकी तुलना अन्य प्रगतिशील देशों से करते हैं तो हम पाते हैं कि ऐसा ज़रूर जरूर आवश्यक है। प्रधान मंत्री जी ने

ठीक ही कहा है कि हम छोटे देशों जितने भी विशेषज्ञ नहीं उत्पन्न कर पा रहे हैं। मानव जीवन के विविध उद्योगों के लिए इन विशेषज्ञों की आवश्यकता है और फिर विश्वविद्यालयों का स्तर भी ऊँचा नहीं है जिससे मारी शिक्षा पद्धति पर में कसावट आ सके। हम जिस मुद्दे पर चल देना चाहते हैं, वह यह है कि विश्वविद्यालयों को विस्तार की गतिविधियाँ पर अधिक गंभीर ध्यान देना चाहिए, अर्थात् वे यह सोचें कि शिक्षा के क्षेत्र में उच्च स्तर को कायम रखना मात्र ही उनकी जिम्मेवारी नहीं है बल्कि प्राथमिक, माध्यमिक एवं संपूर्ण के स्तर पर शिक्षा को ऊँचा बनाने की भी जिम्मेवारी उनकी है।

इसके अतिरिक्त ग्रामीण लोग, शहर के लोगों और विशेष रूप से अशिक्षित प्रौढ़ों— इस प्रकार संपूर्ण समाज के प्रति अपनी जिम्मेवारी का अनुभव उन्हें करना चाहिए। सरकार तथा योजना आयोग के साथ-साथ मैं भी यह कहता हूँ कि प्रौढ़ साक्षरता हमारी प्रधान प्राथमिकता है।

ये कुछ मुद्दे हैं जिनपर आयोग ने प्रधान मंत्रीजी को दिए अपने दस्तावेजों में सामने रखने का प्रयत्न किया है। हम इस सम्मेलन की वर्षाओं तथा मार्गदर्शक निर्णयों की ओर आशा भरी नजरों से देखेंगे।



बुद्धिपूर्वक किया जानेवाला श्रम ही सच्ची प्राथमिक शिक्षा या प्रौढ़ शिक्षा है।

मनुष्य न तो कोरी बुद्धि है न स्थूल शरीर है और न केवल हृदय। सम्पूर्ण मनुष्य के निर्माण के लिए तीनों के उचित और एक-रस मेल की जरूरत होती है और यही शिक्षा की सच्ची व्यवस्था है।

बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य दस्तकारी के माध्यम से बालकों का शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक विकास करना है।

अपने जीवन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग के सिद्धांत का पालन नागरिकता के गुण का विकास करनेवाली सर्वोत्तम शिक्षा है। इससे बुनियादी तालीम स्वावलंबी भी बनती है।

महात्मा गांधी

भावी कार्यक्रम पर सर्वसम्मत निवेदन -

राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन, जो अमिल भारत नई तालीम समिति द्वारा आयोजित किया गया था, दिनांक १८-१९-२० दिसम्बर, १९७८ को नई दिल्ली में सम्पन्न हुआ। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई ने किया तथा केन्द्रीय गांधी स्मारक निधि के अध्यक्ष और नई तालीम समिति के सभापति डा श्रीमन्नारायण ने इसकी अध्यक्षता की। गजस्यन के राज्यपाल श्री रघुबुल तिलक के अलावा सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के कई शिक्षा मंत्रियां, विश्व-विद्यालयों के ३० कुलपतियों, कुछ समद-मदस्या स्वयंसेवी मर्यादों-के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्रियों और देश के विभिन्न भाषा के लगभग १०० अनुभवी बुनियादी शिक्षा क्षेत्र के कार्यकर्त्ता भाग लिया। केन्द्रीय शिक्षामंत्री डा प्रतापचन्द्र चन्दर ने सभापन भाषण दिया। योजना आयोग के उपाध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद् के निदेशक, शिक्षा मन्त्रालय के वरिष्ठ अधिकारी वर्ग और प्राथमिक, माध्यमिक तथा विश्वविद्यालयीन शिक्षक प्रतिनिधियां ने भी सम्मेलन में भाग लिया।

सम्मेलन के अध्यक्ष द्वारा तैयार किए गए मुख्य विचारपत्र 'राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली कुछ रचनात्मक सुझाव' पर सम्मेलन में गहराई से विचार किया गया। तीन दिन की विस्तृत चर्चा के बाद निम्नलिखित निवेदन जाहिर किया गया —

१. अनेकों समितियों और आयोगों की रिफारिशों के बावजूद इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि भारतीय शिक्षा प्रणाली राष्ट्र की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकी है और वह जन-माध्यारण की तात्कालिक आवश्यकताओं के लिए भी सममानुबल सिद्ध नहीं हुई है। ४० वर्ष पूर्व महात्मा गांधी ने

‘सार्वभौमिक धर्म और उत्पादक कार्य पर, केन्द्रित तथा बालक के आस-पास के परिवेश से घनिष्ठ रूप में सम्बद्ध’ बुनियादी शिक्षा की एक योजना देश को सामने रखी थी। इसका अभिप्राय, ‘जीवन के लिए शिक्षा, और इससे भी आगे जीवन द्वारा शिक्षा’ देना था। बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों का, उनकी उत्पादक क्षमता और स्थानीय समाज से निकट सम्पर्क सहित उनके सम्पूर्ण व्यक्तित्व का, विकास करना था। गांधीजी द्वारा परिकल्पित बुनियादी शिक्षा एक गतिशील पद्धति थी जो निश्चित ही बदलती हुई परिस्थितियों में प्रगति और विकास करनेवाली है।

बर्षों के प्रत्यक्ष अनुभव ने यह सिद्ध कर दिया है कि भारत में पूर्व-प्राथमिक से विश्वविद्यालय तक सभी स्तरों पर शिक्षा सम्बन्धी मार्गदर्शन और स्वरूप-निर्धारण ‘राष्ट्रपिता’ द्वारा प्रतिपादित बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्तों के आधार पर ही होना चाहिए। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि शिक्षा आर्थिक प्रगति और विकास से सम्बन्धित समाजोपयोगी उत्पादक कार्यकलापों द्वारा ही जानी चाहिए।

बुनियादी शिक्षा के इन मूलभूत सिद्धान्तों को, बिना किसी भेद-भाव के, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की सभी शिक्षा संस्थाओं और समाज के सभी वर्गों के लिए लागू किया जाना चाहिए।

२. पूर्व प्राथमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक के पाठ्यक्रमों में निम्न तीन आधारभूत मूल्यों पर जोर दिया जाना चाहिए—

- (१) शैक्षणिक प्रक्रिया के एक अभिन्न अंग के रूप में कार्य-विशेष के उपयोग द्वारा स्वावलम्बन, आत्म-विश्वास और श्रम की गरिमा की भावनाओं का पोषण,
- (२) विद्यार्थियों और अध्यापकों को सामुदायिक सेवा के अर्थवान कार्यक्रमों में प्रवृत्त करके राष्ट्रीयता तथा सामाजिक दायित्व के बोध का विकास, और

(३) विद्यार्थियों के मानस में नैतिक, चारित्रिक - व मानवी मूल्यों की प्रतिष्ठा, सभी धर्मों की मूलभूत एकता की समझ और उनके प्रति समान आदर की भावना पैदा करना ।

इन पाठ्यक्रमों में हमारे देश की समन्वयकारी संस्कृति, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता पर बल देने हुए भारतीय स्वाधीनता संग्राम के संक्षिप्त इतिहास और हमारे संविधान में प्रतिष्ठित अहिंसा, लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय तथा सर्वधर्म-समभाव (Secularism) के आधारभूत मूल्यों को समाविष्ट किया जाना चाहिए ।

३. भारतीय संविधान के ४५ वें अनुच्छेद के अनुसार राज्य के चौदह वर्ष तक की आयु के सभी बालकों को निशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा मिलनी चाहिए । इस निर्देश के अनुसार सभी राज्य सरकारों को छठी राष्ट्रीय योजना के अन्त तक आठवी कक्षा तक की देशव्यापी प्राथमिक शिक्षा का प्रबन्ध करना चाहिए । बालिकाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य कमजोर वर्गों के बच्चों को स्कूलों में दाखिल करने की ओर विशेष ध्यान देना होगा । निर्धारित अवधि में इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए ऐसी अनौपचारिक शिक्षा जारी करना आवश्यक होगा, जिसमें अल्पकालिक शिक्षण, बहु-विन्दु प्रवेश तथा अगली कक्षा में चढ़ाने की लचीली पद्धति का अनुसरण किया जाए ।

जिन राज्यों में प्राथमिक शिक्षा केवल सात वर्ष तक दी जाती है, वहाँ फिलहाल वही पद्धति को चलने दिया जाए ।

छोटे बालकों की, विशेषतः कमजोर वर्ग के बालकों की, पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के दौरान जीवन के आधारभूत मूल्यों के शिक्षण की ओर आवश्यक ध्यान दिया जाना चाहिए ।

सामान्यतः शाला का ५० प्रतिशत समय उत्पादक, सृजनारम्भक और मनोरंजन कार्यों को दिया जाए, जिसमें से कम से कम आधा समय पूर्णतः विभिन्न प्रकार के समाजोपयोगी उत्पादक कार्यों में

लगे। पाठ्य पुस्तकों के वर्तमान भार और अनिवार्य विषयों की बड़ी संख्या को उचित सीमा तक कम किया जाए।

सधन शिक्षा की दृष्टि से स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार छुट्टियों में बमी और रद्दोबदल किया जाना चाहिए।

४ प्राथमिक के बाद माध्यमिक शिक्षा चार वर्ष की और यह १२ वी कक्षा पर समाप्त होने वाली हो। इस अवधि में स्थानीय और क्षेत्रीय रोजगार के अवसरों के अनुसार माध्यमिक स्कूलों में विभिन्न प्रकार के तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम चालू किए जाएँ, जिससे छात्र राष्ट्र के उपयोगी नागरिक के रूप में अपने जीवन में स्थिर होने के योग्य बन सकें। उत्पादक कार्यों के अतिरिक्त पाठ्यक्रमों में भाषा, विज्ञान और गणित, साहित्य सहित समाज-शास्त्र और मानविकी विषय शामिल किए जाएँ। विभिन्न विषयों के चुनाव में पर्याप्त छूट और लचीलापन हो। किन्तु माध्यमिक शिक्षा की एक ही समग्र धारा चले, उसमें 'शैक्षिक' और 'व्यावसायिक' जैसी किसी उपधारा का भेद नहीं होना चाहिए। जैसा कि शिक्षा सम्बन्धी यूनेस्को आयोग (१९७२) ने सिफारिश की है 'शिक्षा के विभिन्न प्रकारों में' से कड़े अलगाव को समाप्त किया जाए और प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर से ही शिक्षा एक साथ सैद्धान्तिक, तकनीकी प्रायोगिक और शारीरिक हो।'

माध्यमिक स्तर के अध्ययन के पाठ्यक्रम एक तरह 'अन्तिम' होंगे, किन्तु भविष्य में भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने की छात्रों को छूट होनी चाहिए।

५ माध्यमिक स्तर तक सार्वजनिक शिक्षा की 'सामान्य स्कूल' पद्धति होनी चाहिए, जिसमें सभी बच्चों को जाति, वर्ग या धार्मिक मान्यता के भेदभाव के बिना प्रवेश मिल सके। भारत में एक लोकतान्त्रिक समाजवादी और प्रगतिशील समाज के विकास के लिए यह आवश्यक है।

इस दृष्टि से समय आया है कि 'पब्लिक स्कूल' जो अधिकांश में धनिक वर्ग के बच्चों को शिक्षण देने तक ही सीमित हैं, वे सब

राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की मुख्यधारा में आ मिलें, जिसमें मातृ-भाषा और त्रिभाषा फार्मूला के माध्यम से ही शिक्षण देना भी शामिल है। इसके अलावा इन स्कूलों को वक्षा आठ तक कोई शुल्क लेने की अनुमति भी न दी जाए, क्योंकि १४ वर्ष की आयु तक निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाना संविधान द्वारा निर्देशित है। साथ ही, इन स्कूलों से भी ५० प्रतिशत स्थान योग्यता छात्र-वृत्तियों (Merit Scholarships) को देकर कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए सुरक्षित रखे जाएँ।

६ सक्रान्ति काल में विभिन्न राज्यों के वर्तमान बुनियादी और उत्तर बुनियादी स्कूलों को प्रोत्साहित करने और सुदृढ़ बनाने की ओर विशेष ध्यान दिया जाए। इस कार्य के लिए भारत सरकार केन्द्रीय बुनियादी शिक्षा बोर्ड की स्थापना करे। ऐसे बोर्डों की स्थापना राज्य स्तर पर भी की जाए।

७ विश्वविद्यालय स्तर पर पहला डिग्री पाठ्यक्रम तीन वर्ष का होना चाहिए। केन्द्रीय शिक्षा परामर्शदाता मण्डल न सुझाव दिया उसके अनुसार विश्वविद्यालय अपनी इच्छा से दो वर्ष का 'फास कोर्स' और तीन वर्ष का 'आनर्स कोर्स' रख सकते हैं। इस स्तर पर भी शिक्षा के विभिन्न पाठ्यक्रम, बुनियादी शिक्षा की पद्धति पर, विविध प्रकार की उत्पादक और विकास परियोजनाओं से सम्बद्ध हो ताकि विश्वविद्यालय शिक्षा वास्तव में उद्देश्यनिष्ठ बन सके।

महाविद्यालयों में प्रवेश चुने हुए छात्रों को दिया जाना चाहिए और वहाँ उपलब्ध पुस्तकालयों प्रयोगशालाओं तथा अध्यापकों की सुविधा तथा वहाँ विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए प्रशिक्षित स्नातकों की माँग आदि का ध्यान रखा जाना चाहिए। इनमें कमजोर वर्ग और अविकसित क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए समुचित स्थान सुरक्षित रखने चाहिए।

८ शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षा का माध्यम छात्रों की मातृभाषा होना चाहिए। कृषि, इंजीनियरिंग और डाक्टरों पाठ्यक्रमों समेत भारत के सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम

क्षेत्रीय भाषाएँ अपनाए जाने के लिए पूरे निश्चय के साथ तुरन्त कदम उठाए जाने चाहिए। सन्तान्ति काल में भी 'मातृ-भाषा के माध्यम से माध्यमिक परीक्षा पास करने वाले छात्रों को इन राजनीती और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने से न रोका जाए। ऐसे विद्यार्थियों की भाषा सम्बन्धी कमी को पूरा करने के लिए इन सस्याओं में विशेष व्यवस्था की जाए।

इस सारे लक्ष्य को ध्यान में रखकर आवश्यक पाठ्य पुस्तकें और अन्य साहित्य भारतीय भाषाओं में तैयार और प्रकाशित करने के लिए तुरन्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

९. स्कूलों और कालेजों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रहने का एक मुख्य कारण यह है कि भारतीय सिविल तथा सैनिक सेवाओं में भर्ती की परीक्षाओं का माध्यम अभी भी अनिवार्य रूप से अंग्रेजी है। कुछ राज्यों तक में सिविल सेवा परीक्षाएँ अंग्रेजी में होती हैं। राष्ट्रीयकृत बैंको, बीमा कम्पनियों और सरकारी औद्योगिक सस्यानों में, भर्ती अंग्रेजी भाषा के माध्यम से होती है। इसलिए यह वांछनीय है कि ये सभी परीक्षाएँ क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से हो। सरकारी सेवाओं में चुनाव के लिए विभिन्न राज्यों का उचित 'कोटा' नियत करने में कोई बड़ी गठिनाई नहीं होनी चाहिए। चुनाव के बाद उम्मीदवार इन सेवाओं के अखिल भारतीय स्वरूप को बनाए रखने के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। सेवाओं के लिए चुनाव की इस नई पद्धति में उम्मीदवार ने अपनी शिक्षा प्राप्त करने के समय जो समाजोपयोगी उत्पादक कार्य किया उस विशेष योग्यता को भी अतिरिक्त माग्यता दी जानी चाहिए। इस व्यवस्था का, अनुभव के आधार पर, कुछ वर्ष बाद पुनरावलोकन किया जा सकता है।

१०. वर्तमान परीक्षा प्रणाली का छात्रों की शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक क्षमता पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है तथा इसके परिणामस्वरूप छात्रों का स्तर गिरा है, उनमें अनुशासन की कमी आई है तथा प्रमाण पत्र, डिप्लोमा और डिग्री पाने के लिए अनुचित

तरीकों का अपनाया जाना व्यापक हुआ है। इसलिए यह आवश्यक है कि परीक्षा प्रणाली में आमूल परिवर्तन किया जाए। छात्रों के बौद्धिक विकास का ही मूल्यांकन न किया जाए वरन् समाज की अत्यपूर्ण सेवा के कार्यक्रमों सहित उत्पादक और समाजोपयोगी प्रवृत्तियों में उनके सक्रिय योगदान को भी देखा जाए। वस्तुपरक मरल तरीके से आन्तरिक मूल्यांकन के लिए इन प्रवृत्तियों का विस्तृत ध्येय रचना आवश्यक है। मंशेपत वर्तमान परीक्षा प्रणाली में ठीक ढंग का सुधार, मौजूदा स्कूलों और कालेजों में बुनियादी शिक्षा की पद्धति पर उनमें नवीनता लाकर ही किया जा सकता है।

११ विभिन्न प्रकार की नौकरियों से विश्वविद्यालयों की पदवियों का सम्बन्ध विच्छेद किया जाना भी वाछनीय है ताकि कालेजों में प्रवेश चाहने वाली वर्तमान भीड़ उल्लेखनीय सीमा तक कम हो सके। विभिन्न सरकारी विभाग तथा गैर सरकारी संस्थान भी विश्वविद्यालय की पदवी पर जोर न देकर, अपना पाठ्यक्रम निर्धारित कर प्रतियोगिता परीक्षाएँ ले सकते हैं। ये पाठ्यक्रम ११ और १२ कक्षा में भी लागू किए जा सकते हैं, जिससे छात्र, मात्र क्लक का म्यान पाने के लिए अपने अवसर बढ़ाने की उच्च शिक्षा लेने का लोभ न करें।

१२ उपरोक्त नई शिक्षा प्रणाली मिशनरी भावना वाले और निष्ठावान् सुप्रशिक्षित अध्यापकों के बल पर ही सफल हो सकती है। अध्यापकों को केवल तकनीकी व्यक्ति न माना जाए। वे ही वास्तव में राष्ट्र के सर्जक और निर्माता हैं। अध्यापकों को अपनी पूरी शक्ति छात्रों का चरित्र-निर्माण करने में लगानी चाहिए ताकि छात्र वर्ग समाज के प्रति अपना कर्तव्य निभा सकें। राज्य का यह उत्तरदायित्व है कि वह उनका सामाजिक स्तर ऊँचा करे और इन्हें अधिक चिन्ताओं से मुक्त होने योग्य बनाए।

शिक्षक वर्ग की योग्यता और कुशलता बढ़ाने के लिए बुनियादी शिक्षा के आधार पर शिक्षक प्रशिक्षण का कार्यक्रम तुरन्त बनाया जाना और व्यवस्थित रूप से अमल में लाया जाना चाहिए।

सब प्रशिक्षण संस्थाओं को उत्पादक बायें, स्वयं सेवा, -आपसी सहयोग और लोकतान्त्रिक मूल्यों पर आधारित सुमम्बद्ध समुदायों के रूप में संगठित किया जाना चाहिए।

१३ देश के सभी राजनैतिक दलों से सम्मेलन अनुरोध करना है कि वे अपने द्वारा बनाई गई उपयुक्त आचार-संहिता को आधार मानकर शिक्षा-संस्थाओं के सहज चल रहे कार्यों में कोई हस्तक्षेप न करें। 'शिक्षा मन्दिरों' के छात्रों और अध्यापकों का दलीय-स्वायत्तों के लिए अब और अधिक्त शोषण नहीं किया जाना चाहिए।

शिक्षा संस्थाओं तथा अन्य क्षेत्रों में हिंसक आन्दोलन और घेरावों को प्रशासन द्वारा दृढ़तापूर्वक रोकना चाहिए।

१४ इन सकारितों में उल्लिखित नई दिना प्रणाली का ढाँचा अब होगा ८+४+३ अर्थात् आठ वर्षों की निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, चार वर्षों की माध्यमिक शिक्षा और तीन वर्षों की विश्वविद्यालय शिक्षा। जो राज्य अभी ७ वर्षों की प्राथमिक शिक्षा देने है वहाँ शिक्षा का ढाँचा ७+५+३ का होगा। साथ ही, उन विद्यार्थियों के लिए, जो माध्यमिक शिक्षा पूरे समय प्राप्त करने की क्षमता नहीं रखते हैं, दस वर्षों की शाला शिक्षा समाप्त करने के बाद मैट्रिक परीक्षा लेने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

भारत में राष्ट्रीय एकता के लिए एक समान शिक्षा प्रणाली निरन्तर वाञ्छनीय है। परन्तु प्रदेश और क्षेत्रीय तथा जिला स्तर पर भी विभिन्न पाठ्यक्रमों को तैयार करने में अधिक से अधिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए। शिक्षा क्षेत्र में, समान शिक्षा प्रणाली पर जोर देने के कारण, नए मूल्यांकन और शोध करने में बाधा नहीं आनी चाहिए।

सरकार को एक राष्ट्रीय नीति के तौर पर शिक्षा संस्थाओं की स्वायत्तता को मान्य करना चाहिए, और उन पर अपना नियन्त्रण कम से कम कर देना चाहिए।

१५ देश भर में युद्ध स्तर पर प्रौढ शिक्षा को आयोजित करने के सरकार के निर्णय का सम्मेलन स्वागत करता है। इस क्षेत्र में

भी बुनियादी शिक्षा के मिद्वानों को समुचित ढंग से लागू करना होगा ताकि 'वायगत साक्षरता' से जन ममुदाय की केवल नागरिक चेतना समुन्नत न हो बल्कि उनकी व्यवसाय सम्बन्धी उत्पादक कुशलता भी बढे। अध्यापकों और छात्रों को अपने प्रशिक्षण के एक-अभिन्न अंग के रूप में प्रौढ शिक्षा के कार्यक्रम में भाग लेना होगा।

१६ नई शिक्षा प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू किए जाने के लिए माता-पिता के सहकारक ढंग का संगठित रूप में सक्रिय सहयोग आवश्यक है। वस्तुतः प्रत्येक घर को शिक्षा की एक आधारभूत इकाई के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। शाला और घर दोनों एक दूसरे को समृद्ध करने में परस्पर सहयोगी के रूप में कार्य करें।

१७ बुनियादी शिक्षा के आधारभूत तत्वों को प्रत्येक विश्वविद्यालय तक के सब स्तरों पर समाविष्ट किए जाने के महत्वपूर्ण प्रसंग में भारत सरकार से निवेदन है कि वह एक उच्च-स्तरीय राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन कर जिसमें शिक्षा क्षेत्र की सर्वेच्छित सेवा संस्थाओं का भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो। यह आयोग यथाशीघ्र अपने विस्तृत सुझाव सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करे।

१८ स्पष्ट ही उपयुक्त रूप में शिक्षा के पुनर्नियोजन के लिए अतिरिक्त राष्ट्रीय लागत राशि की आवश्यकता होगी। पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान कुल व्यय के मुकाबले में शैक्षणिक व्यय का अनुपात तीसरी पंचवर्षीय योजना के ६.८७ से घटकर चौथी पंचवर्षीय योजना में ५ प्रतिशत और पांचवी पंचवर्षीय योजना में ३.२७ प्रतिशत तक नीचे आ गया है। यह रुढ़ी है कि शिक्षा सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत और योजना से बाहर के व्यय दोनों को दृष्टि में रखा जाएगा तो थोड़ा भिन्न चित्र सामने आएगा। लेकिन इस पर भी सारी स्थिति सन्तोषकारी होने से पर रहती है। जैसा कि शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति प्रस्ताव में सुझाया गया है हमारा लक्ष्य, शिक्षा-कार्यक्रम में कुल राष्ट्रीय आय का ६ प्रतिशत व्यय किया जाने का स्तर यथाशीघ्र लागू होना चाहिए।

१९ सम्मेलन को पूरी आशा है कि इस निवेदन में जो विभिन्न सुझाव दिए गए हैं, उन पर भारत सरकार, राज्य सरकारों तथा विश्वविद्यालयों द्वारा गम्भीरता से विचार किया जाएगा ताकि इनके कार्यान्वयन की ओर त्वरा की भावना से नदम उठ सकें।

२० साथ ही यह भी आवश्यक है कि जो निर्णय, ध्यानपूर्वक विस्तृत विचार-विमर्श के बाद एक बार लिए जायें उन्हें आगे दस या पन्द्रह वर्ष तक न छोड़ा या परिवर्तित किया जाए ताकि राष्ट्रीय शिक्षा के सारे स्वरूप में एक स्थायित्व और सातत्य सुनिश्चित रह सके। राष्ट्रीय सहमति से निर्धारित शिक्षा का स्वरूप दलीय नहीं समझा जाना चाहिए।

२१ सम्मेलन के अध्यक्ष, सम्मेलन की सिफारिशों के प्रत्यक्ष कार्यान्वयन के लिए २१ सदस्यों की कार्य समिति (Follow-up Committee) नियुक्त करने को अधिकृत किए जाते हैं, जिसे सदस्य सहचरित करने का अधिकार होगा।



नई तालीम एक 'तन्त्र' नहीं 'विचार' है। बच्चों की तालीम एक शुभ कार्य है। इसे 'नई तालीम' नाम दिया गया है। लेकिन मैं इसे 'निरत्य नई तालीम' कहता हूँ। निरत्य नई तालीम का मतलब है, जो कल थी, वह आज नहीं है और जो आज है वह कल नहीं रहेगी। जैसे नदी का पानी। नदी बहती रहती है, लेकिन प्रति क्षण उसका पानी नया होता है। वैसे ही रोजके अनुभव के आधार पर जो निरत्य बदलती रहती है, वह है, निरत्य नई तालीम।

नई तालीम याने नए मूल्यों की स्थापना।

चिन्ता

सेवाग्राम आश्रम-वृत्त (नवम्बर, दिसम्बर, १९७७ का)

यद्यपि यह वृत्त नवम्बर, दिसम्बर १९७७ का है फिर भी प्रकाशन के लिए जनवरी १९७८ में दिया जा रहा है ।

मन् १९७८ तो हमारे लिए महाशुद्ध के रूप में प्रगट हुआ । हमारे गांधी परिवार के महाप्राण सेवाग्राम आश्रम प्रतिष्ठान के अध्यक्ष पूज्य श्री श्रीमन्नारायण जी को महामृत्युने प्राप्त लिया । उनका स्वर्गवास हुआ । सेवाग्राम आश्रम प्रतिष्ठान के लिए यह कभी भी पूर्ति न होने वाली क्षति हुई ।

ईश्वर उनकी आत्मा को चिरस्थान्ति दे यही विनम्र प्रार्थना है ।

दिसम्बर के १८, १९, २० को दिल्ली में अखिल भारत नई तालीम समिति द्वारा अखिलभारतीय शिक्षा परिषद का आयोजन किया गया था जिसकी अध्यक्षता पूज्य श्रीमन्जी ने की थी और दिन रात अथक परिश्रम करके इस प्रयास को सफल बनाया था । पूज्य बापू के शिक्षण विषयक विचारों को भारत के उच्च कोटि के शिक्षा-विदों द्वारा स्वीकार कराने में श्रीमन्जी सफल रहे यह विशेष आनंदकी बात है । मृत्यु के पूर्व श्री श्रीमन्जी ने एक बहुत ही बड़ा कार्य किया यह कहने में किसी तरह का सकोच नहीं होना चाहिए । सेवाग्राम आश्रम का सारा वातावरण पूज्य श्री श्रीमन्जी के चले जाने से शोकाकुल है ।

सेवाग्राम आश्रम में इस अवधि में कुल ११ मेहमान आकर रहे और आश्रम जीवन का अनुभव लिया । इनमें इंग्लैंड, नेदरलैंड, हॉलैंड, अमेरिका और जर्मनी की भाई बहनें शामिल हैं । विशेष अतिथियों में भारत के स्वास्थ्य मंत्री श्री राजनारायण, विश्वधर्म संस्थापक श्री बाहुल्लाह, तथा महाराष्ट्र के वित्त मंत्री श्री जोगेश देसाई थे ।

इस अवधि में आश्रम के सारे कार्यक्रम निरामित चले । नई तालीम प्रातः प्रार्थना की औसत हाजरी १२ रही, सायं प्रार्थना में औसत हाजरी १२-५० रही, सूत्रयज्ञ में हाजरी ५० रही ।

(अ) वापू कुटी में वापू के आसन की सुरक्षा का प्रवध किया गया दर्शनार्थियों के साथ आने वाले छोटे बच्चे वापू का आसन न बिगाड़ सकें इसकी व्यवस्था की गई।

(आ) वापू द्वारा उपयोग में लाई गई चीजों की दीर्घ कालीन रक्षा के लिए पूज्य श्रीमन्जी की सलाह से इन स्मारक चीजों पर वैज्ञानिक क्रिया करने के लिए गांधी राष्ट्रीय स्मारक संग्रहालय के कार्यकर्ता श्री शरद पड्या के साथ दिल्ली भेज दिया गया। आश्रम परिसर में जो सफाई कार्य प्रतिदिन चलता है वह साधकों द्वारा व्रत भावना से किया जा रहा है।

इस अवधि में कुल ४३४६ दर्शनार्थी आश्रम दर्शन के लिए आए। इनमें १।३ विद्यार्थी थे। कुल २८९ टोलियां आश्रम दर्शन के लिए आई थी। इस अवधि में एक शिविर और एक परिसयाद आश्रम प्रतिष्ठान परिसर में हुआ, दिसम्बर ४ से लेकर ८ तक समाज विज्ञान तज्ञों की सगोष्ठी यहाँ के बला भवन में सम्पन्न हुई जिसमें प्रत्यक्ष कार्य में पड़े हुए भारत के अनुभवी कार्यकर्ता शामिल हुए थे। दूसरा एक शिविर २७, २८, २९ दिसम्बर को ग्रामीण मजूर संघ द्वारा संगठित किया गया।

६ नवम्बर को राष्ट्र सत श्री तुक्डीजी महाराज के पुण्य स्थल से १५० पदयात्री एक रात के वास्तव्य के लिए आश्रम में आए थे। २५ दिसम्बर को ईजू जयंति के उपलक्ष्य में विशेष प्रार्थना का आयोजन बला भवन में किया गया था। नित्य के प्रति ३० तारीख को सामूहिक भोजन सर्व धर्म केन्द्र के गई तालीम कुटी प्रांगण में हुआ। इस माह में कार्यकर्ताओं का एक दिवसीय शिविर कार्यक्षमता के कारण नहीं हो पाया।

तूफान पीड़ितों के लिए कार्यकर्ताओं द्वारा एकत्रित की गई राशि मदद के रूप में दी गई। ईद के दिन दुर्ग (म प्र) के ज्ञानी श्री सादिक अली ने आश्रम के वापू कुटी में हज मनाया। उन्होंने पवनार जाकर पूज्य विनोबाजी से भी भेट की।

श. प्र. पांडे
कार्यालय-मन्त्री

श्रद्धा सुमन

[ठी श्रीमन्नारायणजी के अमागेयिक निधन से उनके अनेक पहेतों के मन दुर्बल होना स्वाभाविक है। उनके कुछ महत्वपूर्ण मायियों के थड़ा-सुमन यहाँ दिए जा रहे हैं।]

वे बयू तोड़कर आगे चले गए

आज श्रीमन्नारायणजी की मृत्तु की अवानक खबर मिली। आज ही वे यहाँ पहुँचनेवाले थे। लेकिन वे चले गए। दादा की उम्र ८२ है, उनकी ६५ साल की उम्र थी। बयू तोड़कर वे आगे चले गए।

गांधी-निधि के अध्यक्ष थे, वे गवर्नर भी थे, राजदूत भी थे। हिन्दुस्तान भरमें कार्य तो उन्होंने अनेक किए हैं।

सुचारुतया में शांति रखना, तटस्थ रहना यह उनका गुण था। हमेशा सत्यबुद्धि कायम रखते थे। वे हमेशा मध्यमार्ग में चलते थे। यह उनकी एक विशेष बात थी।

मेरे लिए वे सहारा थे।

ऐसे व्यक्तित्व की आज हमने खोया है। आज तो सबको है, इमामिए कुछ क्या करना? लेकिन जो इतना साधन करके, सत्य बुद्धि से परलोक गमन करते हैं, उनको निःसंशय सद्गति मिलेगी।

३-१-१९७८

विनोबा

गोवरधनदास चौखवाला

मुरत, गुजरात

१४-१-१९७८

श्री श्रीमन्नारायणजी के जाने से आप सबको भारी छोट पड़ी है। श्रीमती मवासभा बहन पर भी भारी पड़का पड़ा है। मुरखी जानकी बहन को इस उम्र में भारी आघात महसूस करने का प्रसंग आया है। श्रीमन्जी गुजरात भरमें सीटी सुनास छोड़ गए हैं और आज सब कोई उनको प्रेम से याद करते हैं।

चौखवाला के सप्रेम प्रणाम

कस्तूरबा धाम

१४-१-१९७८

मुरजी श्री श्रीमन्नारायणजी के जाने से देश को बहुत बहुत खोद पड़ी। बापूजी के रत्नारमक कार्य को घेग देने के लिए उन्होंने छुट्टी मेहनत करना औरम कर दिया था। अभी अभी जात जात के सम्मेलन भरे, काया को घिस डाला। ईश्वर ऐसे आत्मा को शक्ति बक्षेगा ही। गंधी स्वयंसेवक निधि के अध्यक्ष उनके जैसा कौन मिलेगा? आश्रम प्रतिष्ठान के अध्यक्ष भी सोचना तो पड़ेगा ही। समा बुलाने का रहेगा ही बहन मवातला बहन को मिलने के लिए आना ही है। कब आना होगा यह देखने का रहा है। हमें पास मिल गया है मेरी सेवा आश्रम को देता ही रहेगा।

अज्ञात बालक

कमुके सादर प्रणाम

श्रीमन्जी हम सोचें कि बीव प्रकाश स्तम्भ थे। देश की वर्तमान समस्याओं पर निष्पक्ष निर्भीक तथा नियोजित विचार व्यक्त करने वाले व्यक्तियों की आज कितनी कमी है। श्रीमन्जी सदैव जाग्रत थे और दूसरे भी यही कामना रखते थे।

उनके अगुआई के हमें पूरा करने में लग जाना चाहिए जिससे उनको आत्मा को शांति मिले।

७-१-७८

रामचरित्र

हरिसिंह कालेज, खड़गपुरा मुंगेर

भीमन्जी की याद में

धी - हत हुई

मन - ललित ॥

नारायण - यह कता तेरा समाधान ?

जिन्होंने बपू और बाबा की बात

से जान का धाम किया सब ओर

सर्वोदय और सरकार के बीच

बांधा सेतु

सत्कारों और रचनानों लग साधियों से

स्नेह सतु सजोए जीवन भर

राष्ट्र भाषा अब शास्त्र तात्पर्य और

कुदृष्टि हलज आदि

सभी गांधी कायके बिरबोंकी सोंचा

अपनी ज्ञान-शक्ति-भक्तसे

अवस्थितता मृदुता और शालीनता

के गुणों को प्रकाशित कर

वे सदाकी सुगाधत कर गए

उपवन यह

भजन सङ्ग्रहालय }
वर्षा ३-१-८७ }

-देवेन्द्र कुमार



If thy aim be great and thy means small, still act, for by action alone these can increase Thee "

—Shri Aurobindo

Assam Carbon products Limited
Calcutta--Gauhati--New Delhi.

"यदि आपका ध्येय बड़ा है, और आपके साधन छोटे हैं, तो भी कार्यरत रहो, क्योंकि कार्य करते रहनेसे ही वे आपको समृद्धि प्रदान करेंगे।"

—श्री अरविन्द

आसाम कार्बन प्रोडक्ट्स लिमिटेड

कलकत्ता - गौहाटी - न्यू देहली

हम केवल व्यापारिक संस्थान ही नहीं हैं

आज के गतिशील संसार में कोई भी उद्योग समाज की आवश्यकताओं की अवहेलना नहीं कर सकता, क्योंकि सामाजिक उत्तरदायित्व व्यापार का आवश्यक अंग बन गया है।

इण्डिया कारबन लिमिटेड

केल्साइन्ड पेट्रोलियम कोक के निर्माता

नूनमाटी, गोहाटी-781020

सम्पादक-मण्डल :

श्री यजूभाई पटेल - प्रधान सम्पादक

श्रीमती मदालसा नारायण

डॉ० भदनमोहन शर्मा

वर्ष २६

अंक ४

अनुक्रम

शिक्षा में ही क्षति नहीं !	—मदालसा नारायण	
मुनहवा कूल वपातपा	—	२
हमारा दृष्टिकोण	—	३
बुनियादी शिक्षा तब और अब	—श्री द्वारकाप्रसाद सिंह	७
सेवाग्राम में नहीं तालीम	—श्री सत्यनाथन्	१३
सेवाग्राम वृत्त	—	२७

फरवरी-मार्च '७८

- 'नई तालीम' का कार्य अगस्त से प्रारम्भ होता है।
- 'नई तालीम' का वार्षिक शुल्क बारह रुपए हैं और एक अंक का मूल्य दो है।
- पत्र-व्यवहार करते समय प्राइम अपनी सच्चा लिखना न भूलें।
- 'नई तालीम' में व्यक्त विचारों की पूरी जिम्मेदारी लेखक की होती है।

श्री प्रभाकरजी द्वारा व भा नई तालीम समिति, सेवाग्रामके लिए प्रकाशित जी
राष्ट्रभाषा प्रेम वर्धा में मुद्रित

शिक्षा में हो क्रांति नई !

सुख शांति समाराधन अपूर्व, दिग् दिगन्त में फैलाना है,
 शिक्षा में हो अब क्रांति नई ही, करके यही दिखाना है !
 यह पुण्य भूमि, भारत स्वदेश, सत्कार प्रवाह चिरतन है,
 एशिया खण्ड है महाद्वीप, में भारतवर्ष प्रतिष्ठित है !
 गुण-गौरव गुजन 'राष्ट्रदेव भव', भाव-रूप हो सदाचरण,
 'राष्ट्रीय ऐक्य एकता रूप, शिक्षा का हो मंगलाचरण !
 विद्यात्मक हो अध्ययन गहन, चैतन्य सजग चितन पावन,
 सम भाव हृदयमें लहराएँ, आनंद रूप हो नवजीवन !
 अंतर में हो सत्कार तरल, सब धर्मों का हो ज्ञान तिमल,
 जन मान करें, सम्मान करें, आपस में हो सदाभाव सरल !
 सत्सनेह प्रवाहित हो अंतर सर, तरल तरंगित उनत हो,
 आनंदविभोर रहें बालकगण, तन-मन स्वस्थ, समुन्नत हो !
 उद्योग-परायण शिक्षण हो, उत्पादन का हो भाव भरा,
 दिन दिन उत्साह थड़े जीवन-अवलंबन सुखमय हरा-भरा !
 उत्साही हो, सब विद्यार्थी, सहयोगी हो, तेजस्वी हो,
 निर्मल, उज्ज्वल, जागृत, उद्यत, निर्भय हो सभी मनस्वी हो !
 जीवन को स्याई-सर्वो को वे समझें वृद्धता धरें सभी,
 बुनियाद सुदृढ़ हो जीवन की यह लक्ष स्पष्टता धरें सभी !
 उत्क्रान्ति प्रदायक हो शिक्षा, हो प्रगतिशील जीवन सुंदर,
 सकल्पवान वृद्ध धैर्यवान हो तरुण राष्ट्र-दर्शन सुंदर !

— मदासना नारायण —

दिल्ली

३१-१२-'७७

सर्वोदय के शिक्षा पुष्प श्रीमन्जी के प्रति श्रद्धाजलि—

सुनहला फूल कपास का*

झर गया

सुनहला फूल

कपास का

हाथ फटेगी कैसे रातों

कौन बनेगा दियना-धातों

बिछुड़ गया वपिता से गायक—

प्रिय जीवन — निवास का ।

शात मुद्र का सा मुख-मण्डल

मन था-अमृत बरा बमण्डल

तन था ऐसा पावन जैसे —

दोहा तुलसीदास का ।

कितनी आस्थामय थी भाषा

‘रोटी का राग’ ‘अमर-आशा

‘रजनी में प्रभात का अदुर’—

स्वर बाणो-विलास का ।

भक्ति विनोद प्रति थी गहरी

गांधी के सपनों का प्रहरी

था जो रथ सर्वोदय का, पथ—

रचनात्मक प्रयास का ।

हुई शिशिर में कसी धरखा

मौन हुआ साँसों का चरखा

हाथ कटेगा कस धामा ?—

शिक्षा के विकास का ?

एक आश्रमवासी सेवाग्राम

* साधु चरित सुभ चरित नपायू । निरख विसद गुणमय फल जायू ॥

जो सहि दुख परछिन्न दुरावा । बदनीय जहि जग जस पाया ॥

—श्री रामचरित मानस

— श्रीमन्नारायणजी के काव्य संग्रह

हमारा दृष्टिकोण

पुनरीक्षा समिति का विवरण :

। एम. सी ई आर. टी द्वारा दसवी कक्षा तक की पाठशालाओं के लिए तैयार किए गए पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या पुस्तक तथा पाठ्य पुस्तकों पर ईश्वरभाई पटेल पुनरीक्षा समिति का विवरण भारत सरकार के शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा जनचर्चा हेतु प्रकाशित किया गया है। समिति को निम्नलिखित पुनरीक्षा करने को कहा गया था—

- (१) क्रमवार और विषयवार उद्देश्य जो 'दसवर्षीय पाठशाला' के लिए पाठ्यक्रम सम्बन्धी एन सी ई आर टी के दस्तावेज में अभिन्न अंग के रूप में सबद्ध किया गया है।
- (२) एन सी ई. आर टी पाठ्यचर्या पुस्तक तथा पाठ्य पुस्तकों की इस पुनरीक्षा के परिप्रेक्ष्य में सूक्ष्म परीक्षण करना। तथा
- (३) अध्ययन की योजनाओं का सूक्ष्म परीक्षण करना तथा इस बात की जाँच करना कि क्या (कोई उपयुक्त) अध्ययन की योजना या समय पत्रक या दोनों में कोई उपयुक्त आपरिवर्तन नहीं किए जाने चाहिए तथा कर्मचारियों का उपयुक्त ढाँचा सुझाया जाए।

'समिति' को नई योजना के व्यवस्था के सिद्धान्त प्रस्थापन की पूरी स्वतंत्रता थी।

३० सदस्यों की इस समिति के अध्यक्ष उपबुलपति थे तथा सभी प्रदेशों के माध्यमिक शिक्षा बोर्डों के अध्यक्षों के साथ केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केन्द्रीय विद्यालय संगठन के डिप्टी कमिशनर, वाउन्सिल आफ इडियन स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा के मंत्री, अध्यापकों के दिल्ली

स्थित यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि, दिल्ली के पालक शिक्षक असोसिएशन के प्रतिनिधि तथा तीन अन्य शिक्षाविद् इसमें समाविष्ट थे। अन्य सभी एन सी ई. आर टी. के अधिकारीगण थे।

समिति ने जो सुझाव दिए वे संक्षेप में इस प्रकार हैं—

१ प्रादेशिक सरकार, स्थानीय अधिकारियों तथा शिक्षा और परीक्षा बोर्डों को पाठ्यक्रम योजना में स्थानीय एवं विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप स्वतंत्रता होनी चाहिए जिससे उसमें यथार्थता एवं लचीलापन आ सके, वह सामाजिक दृष्टि से उपयुक्त हो, उत्पादक हो तथा सामाजिक सेवा के अनुरूप हो। उसका शालेय पाठ्यक्रम में केन्द्रीय स्थान हो। इस योजना को कारगर बनाने के लिए कक्षा १ से ४-५ तक १० प्रतिशत समय दिया जाए, कक्षा ५-६ से ७-८ तक प्रति सप्ताह ६ घंटे के हिसाब से कुल ३२ घंटे, कक्षा ९ से १० तक ६ घंटे प्रति सप्ताह के हिसाब से कुल ३२ घंटे समय दिया जाए। ()

सामाजिक उपयोगी उत्पादक कार्यों को पूरे विषय का स्तर दिया जाए। भाषा को बोठारी कमीशन की सिफारिश के अनुरूप महत्व दिया जाए। कक्षाओं में पढ़ाई २॥ से ३ घंटे से अधिक न हो। भाषा को छीटकर पहली दूसरी कक्षा में बाई पाठ्य पुस्तक न हो, तीसरी चौथी पाँचवी कक्षा में भाषा की एक पाठ्य पुस्तक हो, गणित की एक तथा स्थितिगत अध्ययन के लिए एक पुस्तक हो। अध्यापकों के लिए भी अध्यापन हेतु मार्ग दर्शिका हो। समय सारिणी लचीली हो। अन्य पाठ्य पुस्तक कम की जा सकती हैं विज्ञान की एक और नागरिक-शास्त्र तथा इतिहास की मिलाकर एक तथा उनकी पृष्ठ संख्या कक्षा ५, ६, ७, ८ के बालकों की उम्र के आधार पर रखी जाए। गृह-कार्य के स्थान पर कक्षा में ही अपनी देखरेख में कार्य कराए जाने की सिफारिश की गई है। स्वाध्याय हेतु सचित्र पुस्तिका का प्रकाशन वाछनीय है। (२)

गणित और विज्ञान के वैकल्पिक पाठ्यक्रम रहें और उनके पाठ्य-विषय निर्धारित रहें। २ के स्तर पर प्रवेश हेतु गणित या विज्ञान विषयक उपलब्धियों को उन विषयों के विशेष पाठ्यक्रमों हेतु बरीयता दी जाए।

इतिहास, नागरिक शास्त्र तथा भूगोल क्षेत्रीय पाठ्यक्रम के आधार पर पढ़ाया जाए। अन्य वैकल्पिक विषयों में कला क अन्तर्गत संगीत, नृत्य, चित्रकला में से तथा गृह-विज्ञान, कृषि, अर्थशास्त्र, परिनिष्ठित भाषाएँ आदि में से किसी एक का अध्ययन किया जाए।

17. पाठ्य पुस्तकानी कामगरी ऐसी रह जो विषय सबधी आवश्यक जानकारी देने की दिशा में उपयोगी हो। क्षेत्रीय आवश्यकतानुरूप उपयुक्त शिक्षका का निर्धारण हो तथा उत्पादक कार्य पर अधिक बल दिया जाए। शिक्षक और छात्रों में उपयोगी तथा आवश्यक ताल मेल की आवश्यकता पर भी भर दी गई है।

18. उपर्युक्त सभी कल्पनाएँ सचमुच उत्साहवर्द्धक हैं। फिर भी यदि हम पाठ्य-चर्या पर अधिक निबटस अध्ययन करत हैं तो हम उसमें कल्पनाओं और उनके कार्यान्वयन में अधिक स्पष्ट असंगति पा पात हैं कक्षा। 19. 19-20 में सामाजिक उपयोगिता क उत्पादक कार्य में सप्ताह में केवल 6 घंटे ही निर्धारित किए गए हैं। उत्पादक कार्य क संयोजन का जिन्हें प्रत्यक्ष अनुभव है व एकदम यह कह दग कि कार्य और सामग्री उत्पादन की दृष्टि से सप्ताह में 6 घंटे का समय कोई सतोपजनक परिणाम नहीं द सकेगा। होगा यह कि 6 घंटे का समय 6 तासिकाओं में परिवर्तित कर दिया जाएगा और तयान्वित अच्छी पाठशालाओं में तो इतना भी समय नहीं दिया जाएगा। अतएव यदि इस दिशा में हम सचमुच गंभीरता पूर्वक सोचत ह तो इस कार्य क लिए उपयुक्त आवश्यक समय दिए जाने की आवश्यकता पर विचार करना होगा।

भाषाएँ, विज्ञान तथा गणित को पाठ्यचर्या को तो नवोन्मेषिनी कहना नठिन ही है। वे सभी विषयवार ऐसी पाठ्यचर्या हैं जो आजकल सवसाधारणतः परीक्षावाली निर्धारित अध्यापन प्रणाली में उपयोगमें आती हैं। उनमें पूर्णकरण के लिए नठिनाई स ही कुछ गुंजाइश होती है। यदि शिक्षा को कार्यशील बनाना है, जैसा कि उसक उद्देश्य में निर्दिष्ट है— तो उसकी रूपरेखा एकदम भिन्न प्रकार की होनी आवश्यक है। नयानुभव, सामाजिक जीवन तथा सामुदायिक उन्नति, स्वास्थ्य

तथा सामुदायिक सफाई जैसे अन्य कार्यक्रमों से जन तथा कार्य नुपलता की उपनधि होनी चाहिए। हमारी पाठ्यचर्या के डीके यह बताएँ कि बार्मा-नुभव तथा शिक्षा अनुभव कैसे हर वदमपर एक दूसरे से गुंथे हुए और एक दूसरे से विश्वस्त तथा एक दूसरे से पुष्ट है।

पुनरीक्षा समिति ने इस दिशा में कोई गंभीर प्रयास किया है ऐसा नहीं दिखाई देता। जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक मुझे भय है कि समाजोपयोगी उत्पादक कार्य की बल्बमा कामजवर ही रह जाएगी।

पुनरीक्षा समिति के गलत गठन के कारण ही ये तथ्य अन्य कई कमियाँ रह गई हैं। लोगों का किस प्रकार चयन किया गया है इसका उल्लेख मैंने ऊपर जान बूझकर किया है। यदि समिति ऐसे ही सदस्यों की बने कि जिन्हें यास्तविक बल्बमा ने अनुरूप कार्य-शिक्षा का शालेय स्तर तक का अनुभव नहीं है और यदि स्वेच्छिक संगठना के उपयुक्त प्रतिनिधित्व की व्यवस्था न की गई हो तो क्या परिणाम हो सकते हैं यह स्पष्ट ही है।

यदि जनता सरकार सचमुच शिक्षा में परिवर्तन लाने के लिए उत्सुक है तो उन्हें कार्य के उपयुक्त व्यक्तियों को चुनना करना चाहिए।

बज्रमोई पटेल



१२१ श्री द्वारिकाप्रसाद सिंह

आज से छ महीने पहले मुझे श्री वज्रभार्द्वाजी ने राष्ट्रीय शिक्षण भवन में आकर व्याख्यान देने के लिए निमन्त्रित किया कि बुनियादी शिक्षा के बारे में मैं अपने विचार दूँ। सुनकर मर मन में भव उठे यह कसा देता है जिसमें लोग गांधीजी के सानिध्य में रहे उनके विचारों का अनुभव करते रहे फिर उन्हीं के गिप्य विनोबाजी को सुनत आए फिर भी बुनियादी शिक्षा के सत्वजन को नहीं समय। फिर मैं इसमें क्या बता सकता हूँ, कैसे समझा सकता हूँ?

मैंने सोचा देश की वर्तमान शिक्षा के प्रति इतना आग्रह है। महाविद्यालय विश्वविद्यालय में सबेदनशीलता असतोष की भावनाएँ व्याप्त हैं जिससे विघटनकारी प्रवर्तन हो रहे हैं समाज अपनी संस्कृति से जो कि सर्वव्यापक उत्तम उदाहरण मानी जाती है दरबिनोर होता जा रहा है, ऐसे वातवरण में दश व सामने एक ही राह है और वह है बुनियादी शिक्षा की। बापू की दश निर्माण की तपस्या मानव सृजनार्थ दिए हुए मानवमूल्य से अहिंसक शक्ति से नए मूल्य से नए समाज की स्थापना हो सकती है।

१९६८ में एक अधिकृत शिक्षा-आयोग ने निवेदन प्रस्तुत किया कि प्रत्येक स्तर पर (प्राथमिक माध्यमिक, उच्च) बुनियादी शिक्षा की विशेषताओं को व्यापक रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। एन सी, ई आर टी तथा शिक्षा विज्ञान के द्रन उस पर गहराई से सोचा है और सभी ओर से एक ही निष्कर्ष स्वीकृत हुआ कि बुनियादी शिक्षा में ही देश की स्थिति बदलने का सामर्थ्य है। उसकी देश में व्यापक रूप से फैलाने में शिक्षक ही अपसर होकर कार्य कर सकता है। अतः ट्रेनिंग कॉलेज के विद्यार्थी जो शिक्षक बनने वाले हैं उनसे मिलने का तथा उनके समक्ष अपने विचार रखने के लिए मुझे यह मौका दिया गया इसलिए मैं आप सबका हार्दिक

आभारी हैं। सन् १९३८ से मैं बुनियादी शिक्षा के काम में लगा हुआ हूँ। इस राजेन्द्रप्रसादजी ने मुझे गदानन्द आश्रम में बुनार कहा था तुम इस शिक्षा में आ जाओ। तब मैं एक होईस्वर्ग में शिक्षण का काम करता था फिर भी निष्ठावन्त शिक्षक के नाते मैं उसमें आ गया। इस काम के सत्रमिने में राज्य सरकार के उच्चतम ओहदो पर, एवं साधारण कार्यकर्ता की हैसियत से काम किया। अतः ये सब विचार मेरे निजी जीवन के अनुभव हैं।

बुनियादी शिक्षा का विकास— यह विषय बहुत व्यापक है और कम से कम ५ व्याख्यान उससे लिए चाहिए फिर भी तीन व्याख्यानों के लिए इन विषय का तीन खंड में विभाजन करेंगे।

(१) अपने देश में बुनियादी शिक्षा का विकास।

(क) बुनियादी शिक्षा की पृष्ठभूमि

(ख) कल्पना की आरम्भ की स्थिति

(ग) प्रयोग की स्थिति

(२) १९४७ के बाद बुनियादी शिक्षा के विकास का प्रथम चरण।

(क) स्पष्ट दर्शन

(ख) योजना

(ग) उपलब्धियाँ निवारण

(३) १९५९ से बुनियादी शिक्षा में गिरावट के कारण और निदान, आजादी के बाद शिक्षा की स्थिति, आज की स्थिति तथा जे पी की संपूर्ण क्रान्ति में उसकी व्यवस्था।

पृष्ठभूमि — यह मानें कि नई शिक्षा की कल्पना गांधीजी की निजी मौलिक कल्पना थी। बहुत लम्बे समय से १९ वीं सदी के मध्य से हमारे समाज सुधारका ने देश में आधुनिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति में सुधार करने के बारे में सोचा था तथा प्रयत्न किए थे। उन्ही सुधारकों की सूची में गांधीजी भी हैं।

गांधीजी ने भारत के गाँवों को देखा था, किन्तु बिहार के—बपारन में गाँवों को नजदीक से देखा और जाना। उन्होंने गाँवों में अत्याचारों

का नया चित्र देखा। बूढ़ रिपोर् के बाद भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ था। उन्होंने देखा कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली से गांव टूटते जा रहे हैं और गांवों के टूटने से देश जी नहीं सकता। और बापू ने शिक्षा में चरमा हाथ में लिया। उनकी दृढ़ भावना थी कि ब्रिटिश साम्राज्य चरम से ही हटाया जा सकता है।

गांवों की आर्थिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिस्थिति एकदम बिगड़ती जा रही थी। इस समस्या का हल करने के लिए राष्ट्रीय विद्यालय चलाने का प्रारम्भ हुआ था ताकि भारत के यवका को सच्ची शिक्षा मिल सके। स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लेनेवाले यवक जिन्होंने कालेज को छोड़ दिया था उनकी शिक्षा के लिए ऐसे ढंग के विद्यालय की आवश्यकता थी जिनमें बिहार गजरात काशी विद्यापीठ तथा रवीन्द्रनाथ के गाति निकेतन आदि के नाम आते हैं।

१९२० से १९३० तक के दक्षिणी अफ्रीका के अपने निवास के दरम्यान गांधीजी के मन के शिक्षा विचार मर्मिमान हुए थे उन्हीं के विचारों के अनुसार उपर्युक्त विद्यापीठ चले थे। उन विद्यापीठों से जो ग्नातक निकले वे स्वावलम्बी सहयोगी स्वस्थ तथा सामाजिक जिम्मेवारी की समझने वाले नागरिक थे। इन्हीं दिनों गांधीजी 'हरि जन' में राष्ट्रीय शिक्षा के बारे में लेख लिखते थे। ये लेख अँग्रेजी में होते थे। श्रीमन् नारायणजी ने बापू से पूछा कि ये अँग्रेजी में लिख हुए लख नितन लोग पढ़ सकते हैं? आप एक राष्ट्रीय सम्मेलन बलाइए। १९३७ जन की २२-२३ को वर्धा में एक सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में देश भर के शिक्षाविदा शिक्षामन्त्रिया तथा शिक्षका न भाग लिया। कुल मिलाकर इसमें ८०-८५ लोग थे। सभी न गांधीजी के विचार सुन। शिक्षा में श्रम काम तथा उद्योग के महत्व के बारे में गांधीजी न अपन विचार बताए। बापू का यह स्पष्टीकरण जोरदार रहा।

आज हमारे १५ लाख विद्यार्थियों के १५ लाख मस्तिष्क और तीस लाख हाथ निष्क्रिय बना दिए गए हैं। एम ए करने के बाद भी उनका जीवन में नैराश्य के सिवा कुछ नहीं रह पाता। निष्क्रिय शिक्षा

के नेराश्यपूर्ण ३० लाख हाथ और १५ लाख मस्तिष्क से देश का विकास नहीं हो सकता। हर हाथ को काम मिले हर मस्तिष्क को चिंतन मिले वही सच्ची शिक्षा है, और तभी देश का विकास हो सकता है।

सम्मेलन में बापू ने कहा “मैं दस साल तक अराजकता (Anarchy) सहन कर सकता हूँ किन्तु एक मिनट के लिए भी ब्रिटिश शासन नहीं सह सकता हूँ। ब्रिटिश साम्राज्य देश को हिन्दू साम्राज्य के लिए तैयार नहीं कर सकता। उसे हटाने के लिए एक मात्र प्रभावी साधन है शिक्षा। उसके स्वरूप सम्बन्धी उन्होंने चार सिद्धांत निश्चित किए थे—”

(१) देज यदि स्वनत्र हुआ तो लोकतन्त्र की खरी कसौटी यह होगी कि लोग शिक्षित हो तथा अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक हों। जनतन्त्र का विकास मछली जिला से होता है। प्रयत्न नागरिकता के लिए प्राथमिक जिला अनिवार्य होनी चाहिए। एक टोकरी में आम है। उसमें एक भी आम गिराव होगा तो सारे आम खराब हो जाएंगे। वैसे ही एक गरागती व्यक्ति सारे समुदाय को चैन से नहीं जीने देता। छोड़ जानेवालों की सरकार की रिपोर्ट पढ़ी होगी। १९६४ में मिडल क्लास तक पहुँचते पहुँचते ६९% सातवी तक पहुँचते पहुँचते ८१% और माध्यमिक तक पहुँचते पहुँचते ८०%, इसके बाद के मालूम नहीं कितने छोड़ जाते हैं। यह है छोड़ जानेवालों की स्थिति। जब तक शिक्षा नि शुल्क नहीं होती तब तक गरीब के बच्चे नहीं पढ़ सकते। समन्वित समाज रचना के लिए, जनतान्त्रिक समाजवादी व्यवस्था के लिए बच्चों को न्यूनतम शिक्षा देना अनिवार्य है।

(२) जो भी शिक्षा १४ साल की आयु तक दी जाए वह नि शुल्क हो, अनिवार्य हो और अपनी मातृभाषा में हो। किन्तु पाँचवी कक्षा में अंग्रेजी की शिक्षा अनिवार्य करा दी जाए। पाँचवी से अंग्रेजी शिक्षा की अनिवार्यता की बात का भाजंत्री साइकल ने जोरदार विरोध किया। उनका कहना था कि जहाँ शतप्रतिशत लोगों को अक्षरज्ञान नहीं है वहाँ पाँचवी से ही अंग्रेजी सीखने सिखाने से क्या फायदा?

(३) शिक्षा, स्वावलम्बी हो :— छात्र तथा शिक्षक मिलकर परिश्रम करेंगे। उससे जो कुछ आर्थिक प्राप्ति होगी उससे शिक्षकों का वेतन तथा विद्यालय का खर्च निबलना चाहिए। १९४६ में इसमें परिवर्तन किया गया।

राष्ट्रीय शिक्षा बनाने की योजना तय हुई। उस योजना को बनाने का भार एक समिति को सौंपा गया। उस समिति के अध्यक्ष डा. जाकिर हुसेन थे। उस समिति के सदस्य देश के श्रेष्ठ चिंतकों में से थे। उनका नाम था :—

(१) डा. जाकिर हुसेन	सभापति
(२) श्री स्वाजा गुलाम संयदेन	सदस्य
(३) श्री काका कालेलकर	"
(४) श्री किशोरीलाल मशरवाला	"
(५) श्री के. सी. कुमारप्पा	"
(६) श्री कृष्णदास जाजू	"
(८) श्री विनोबाजी	"
(७) श्रीमती आशादेवी	"
(९) श्री आर्यनायकम्	संयोजक सदस्य

समिति ने २-२॥ महीने में अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट के पाँच हिस्से थे—

(१) स्वास्थ्यवर्धक त्रिम्याशीसता :— देश को स्वस्थ रखने के लिए स्वस्थ जीवन-यापन करना पड़ेगा। पाठ्यक्रम ऐसा हो कि अपने तथा अपने परिसर की स्वच्छता तथा स्वस्थता के विषय में जाग्रत बने तथा उसे स्वच्छ और स्वस्थ बनाने में अपना योगदान दे।

(२) सामुदायिक जीवनयापन :— धर्म, जाति, रहन-सहन विचार, खानपान इनमें विविधता में एकता कैसे हो, उसमें समता, एकता कैसे प्रस्थापित करे इसका बराबर खयाल रखें।

(३) उत्पादक कार्य :— रिपोर्ट में वस्त्रस्वावलम्बन, भोजन स्वावलम्बन, लकड़ी और लोहा, खेती, खादी और शिल्प के उद्योगों—

जिनमें प्रशासनिक कठिनाई न हो— की प्रियाओं और मापदंडों को बताया ।

(४) समाज सेवा :— छात्र श्रमिक हो विन्तु वह व्यक्ति-निष्ठ न बने यह देसना होगी । उसीसे मनुष्य का संतुलित विकास होता है ।

(५) मानसिक विनाश :— छात्र के मस्तिष्क, का संतुलित विकास हो ।

शिक्षा तीन प्रतिवेगों के आधार पर चलेगी । शिक्षा के केन्द्र में बच्चा होगा । बच्चे का समाज, बच्चे के जीवन के लिए उद्योग और बच्चे के चतुर्दिक् व्याप्त प्रकृति ये तीनों उसकी शिक्षा के समर्थ साधन होंगे । उद्योग का स्रोत प्रकृति है । समाज के अवलम्बन से उद्योग चलेगा । प्रकृति के उपयोग में चिन्तन, शोध और विज्ञान की ओर मुड़ना होगा । क्रियाशीलता की व्यवस्था में पारस्परिक श्रम, सहयोग, संस्कार इत्यादि की आवश्यकता होगी । उक्त तीनों आधारों के माध्यम से तरह तरह के ज्ञान-विज्ञान बच्चों को सहज रूप से मिल जाएंगे ।

योजना तैयार हुई । गांधीजी के विचार से यह तब किया गया कि जिन प्रान्तों में कांग्रेस का प्रशासन है वहाँ यह नई शिक्षा प्रयोगमें लाई जाए । इसीलिए आसाम, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, बम्बई और मद्रास में नई शिक्षा के प्रयोग की पृष्ठभूमि तैयार हुई ।

१९३८ के जून महीने में १५ दिन का एक शिविर सेवाग्राम में आयोजित हुआ । उस शिविर का आयोजन हिन्दुस्तानी तालीम संघ ने किया । उस शिविर में विनोबाजी, काका काललकर, किशोरीलाल मशरुवाला, आर्यभायकम्जी, आशादेवी, जाजूजी जैसे महानुभावों का साथ शिविरार्थी को मिला । कार्यकर्त्ताओं के शिविर से लौटने के बाद कांग्रेसी प्रान्तीय सरकारों ने बुनियादी शिक्षण का काम शुरू किया ।

नई शिक्षा का दर्शन तो स्पष्ट था । फिर भी उसके अनुसार काम करना कठिन था । मुझे ही कताई, बुनाई में निष्णात बनने में तीन साल लगे ।

बुनियादी शिक्षा का काम मुश्किल से एक साल चला होगा कि १९३९ में द्वितीय विश्वयुद्ध छिड़ा। कांग्रेस मन्त्रिमंडल ने युद्ध प्रारम्भ होते ही त्यागपत्र दे दिया। इस प्रकार बुनियादी शिक्षा के प्रयोग काल में अनुकूलता के लक्षण नहीं दिखाई पड़े। किन्तु बेडछी, गांधीग्राम आदि स्थलों पर जो प्रयोग हुए उससे साबित हुआ कि इस दशक की इसी योजना के साथ जीना होगा।

१९४७ विकास का प्रथम चरण है, जिसके अन्तर्गत बुनियादी शिक्षा का स्पष्ट दर्शन, योजना तथा उपलब्धियाँ और सिफारिशों के विषय का समावेश होता है।

१९३८ से १९५८ तक के २० वर्षों का इतिहास बुनियादी शिक्षा के विकास के मध्याह्न का इतिहास है।

अंग्रेज शासकों ने बुनियादी शिक्षा की भारीबी की समझा। ग्रेट ब्रिटन के शिक्षा शास्त्री सार्जेंट ने उसका स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि इसी शिक्षा से देश बनेगा। किन्तु उसमें एक बात खटवती है और वह यह कि आप इस शिक्षा में स्वावलम्बन की बात न रखिए स्वावलम्बन को हटा दीजिए। गांधीजी ने कहा सारी शिक्षा योजना का प्राण स्वावलम्बन ही तो है। उस हटाना नामुमकिन है। स्वावलम्बन ही इस शिक्षा की कसौटी है अन्तः परीक्षा है। स्वावलम्बन के बिना पाठशाला निरूपयोगी है।

एक प्रसंग याद आ रहा है। १९३९ में चंपारन में मैं बुनियादी शिक्षा का प्रयोग कर रहा था। गांधीजी के समक्ष पाठ देता था। स्कूल के बच्चे नगधडग, धूलि धूसरित, मटमेल थे। मैं ३३ लड़कों को कुएँ पर ले गया, हाथ मुह, धुलाया, पोछा, गांधीजी ११ बजे आए किन्तु मरा सफाई का काम चलता रहा। लड़कों को स्वच्छ करके लाया और बताई-बायें शुरू हुआ। गांधीजी ने समीक्षा की—'दि लक्षण कायमें निपुण किन्तु बताई ठीक नहीं।' बलभस्वामी ने जब उस टिप्पणी का विरोध किया तब गांधीजी ने कहा था मैं आदर्शों में मुलह नहीं कर सकता।

१९४० से १९४५ तक का समय सत्रमण काल था। बिहार में ७२ बुनियादी विद्यालय, २ ट्रनिंग स्कूल और उत्तर बुनियादी स्कूल खुले।

विहार में इस प्रसार योजना की यह विशेषता थी कि विहार के एक कोने में चम्पारन जिले के बृन्दायन क्षेत्र में २८ बुनियादी विद्यालय चल रहे थे, वहाँ विहार के सभी जिलों में बुनियादी विद्यालय स्थापित किए गए और सभी जिलों में उत्तर बुनियादी और ट्रेनिंग स्कूल खोलने का निश्चय किया गया। बेंगलूर, धुलिया आदि में बुनियादी शिक्षा के स्कूल खोलने की योजना बनी। उत्तर प्रदेश में तो एक ही रात में सभी स्कूल बुनियादी शिक्षा के स्कूल बना दिए गए।

स्वतंत्र भारत की राष्ट्रीय शिक्षा बुनियादी शिक्षा है ऐसा प्रयोगों पर से महसूस हुआ। भारत सरकार ने भी राज्य स्तर पर योजना बनाई। उस योजनानुसार राज्य की प्राथमरी शिक्षा बुनियादी शिक्षा रहेगी यह भी तय हुआ। बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षा-प्रतिष्ठान की स्थापना हुई जो बुनियादी शिक्षा के लिए साहित्य के निर्माण में मदद करता था। ट्रेनिंग कालेज के लिए उन्होंने कुछ सुझाव दिए। (१) परीक्षा महा-विद्यालयों में सूचनात्मक सामग्री (instructional materials) होने चाहिए तथा उनका आदान-प्रदान हो सके, ऐसी व्यवस्था आवश्यक है। (२) प्रशिक्षण महाविद्यालयों के लिए उसका एक सेवा-क्षेत्र होना ही चाहिए। उस सेवा क्षेत्र में बच्चों के घरों की सफाई, खुला रंगमंच, बालक मंदिर, उद्योग, महिला मंडल, सादगी आदि का, समावेश होगा।

भारत सरकार के निर्देशन के अनुसार राज्य-सरकारों ने नई तालीम का पहला कदम उठाया। राज्य सरकारों ने अपने प्रशिक्षण विद्यालयों और महाविद्यालयों को नई तालीम की तरफ मोड़ा। नए प्रशिक्षण विद्यालयों के लिए उनके पास नई तालीम के अनुभवी शिक्षक नहीं थे इसलिए राज्य सरकारों ने अपने कुछ चुने हुए शिक्षकों और निरीक्षकों को नई तालीम में प्रशिक्षण के लिए सेवाग्राम भेजना शुरू किया। हिन्दु-स्तानी तालीम सच ने राज्य सरकारों को इस काम में बड़ी मदद की।

सन् १९५७ से १९५९ के मार्च तक केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों ने नई तालीम की दिशा में दृढ़तापूर्वक पहला कदम उठाया।

इसी बीच १९५५ में भारत सरकार ने देश में नई तालीम का जो कार्य चल रहा था उसके मूल्यांकन के लिए एक समिति बनाई जिसके निम्न लिखित सदस्य थे ।

(१) श्री जी रामचन्द्रन	संयोजक
(२) श्री रामशरण उपाध्याय	सदस्य
(३) डॉ सैयद अन्सारी	सदस्य
(४) डॉ एम डी पाल	सदस्य
(५) श्री जे सी बोस	शिक्षा मन्त्रालय भारत सरकार

इस समिति ने वेसिक शिक्षा के बारे में सात स्तर पर सुझाव दिए । ये सात स्तर इस प्रकार हैं — (१) भारत सरकार, (२) राज्य सरकार, (३) जनता, (४) बुनियादी तालीम के शिक्षकों के प्रशिक्षण कॉलेज, (५) विश्वविद्यालय (६) माध्यमिक विद्यालय (७) प्राथमरी बुनियादी तालीम विद्यालय ।

उस दृष्टि में भारतीय बुनियादी शिक्षा का प्रचार वैसे हो, उसके प्रसार के लिए क्या क्या उपाय करना जरूरी है उसके सम्बन्ध में सुझाव दिए गए थे जिससे शिक्षा-मन्त्रालय निश्चित कल्पना स्पष्ट हो सके ।

इस प्रकार कार्य का आरम्भ हो गया, जिससे ३ अनुभव स्पष्ट रूप से सामने आए —

(१) यह शिक्षा जनता के जीवन से अलग नहीं होगी, जनजीवन के आधार पर होगी । जो व्ययक्त्य दिए गए हैं, या सिनाए जाएंगे वे वास्तविक जीवन से ही सबद्ध होंगे न कि केवल स्कूली ।

(२) इस शिक्षा के कारण काम करने वाले हरिजन, ब्राह्मण जो एकसाथ नहीं आते थे, उनमें भेद कम होने लगे । गांव के लोगों में भी मनोरंजन में सांस्कृतिक जीवन के प्रति आस्था जाग उठी, संगीत और नाटकवा उसमें समावेश होने लगा । इस प्रकार सांस्कृतिक प्रवृत्तियों पर जोर दिया गया ।

(३) उत्पादकता — इस निष्ठा की मज्जे बड़ी विरोधता यही है कि विद्यार्थी उत्पादक इरादे बन गया। निष्ठा के माध्य उत्पादन द्वारा स्वावलम्बी जीवन की यह कल्पना बिल्कुल अभिनव थी।

इस तरह से बुनियादी शिक्षा निश्चित रूप में प्रयोग में लावार हो गई। गुहाई द्वारा टिप्पण (आगम) में अच्छा काम हुआ। शितीश राय चौधरी के द्वारा यमान में ठीक से नहीं हुआ। उड़ीसा में, बिहार में उल्लेखनीय कार्य हुआ। उन सबसे प्रयासों में कुल ५३५ स्कूल खुले, ७४ प्रशिक्षण महाविद्यालय, ७४ महाविद्यालय खुले। १९५७ में सर्वोच्च महाविद्यालय की स्थापना की गई। दिल्ली में जामिया मिलिया ने अच्छा काम किया। उत्तर प्रदेश में डा. अब्दुर्रहमान खान के नेतृत्व में काफी सफलता मिली। पंजाब, राजस्थान में, असफलता रही। मध्य प्रदेश में काफी विकास हुआ वहाँ तो बापू थे ही। शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएँ अच्छी तरह सफल हुईं। इस प्रकार गिनोबा जी, रविशंकर शुक्ल मिनापचन्द दवे बाणीनाथ तिवारी, डा. दिवेकर इन लोगों ने बुनियादी शिक्षा के प्रसार में सहायनीय कार्य किया। भद्रास में भी सरकारी या निजी सरकारी स्तर पर अच्छा कार्य किया गया।

इस सिलसिले में सारे प्राथमिकी स्कूलों को बुनियादी बनाने की योजना बन रही थी। राज्य-सरकारों ने प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण महाविद्यालयों द्वारा एक-अनस्थापन (Orientation) पाठ्यक्रम चलाने की आवश्यकता को महसूस किया। अतः सेवाग्राम द्वारा यह व्यवस्था की गई। जिसमें सारे देश के लोग आकर २-३ महीना का प्रशिक्षण लेने लगे। ये लोग राज्य स्तर पर उसी प्रकार का एक पाठ्यक्रम चलाते थे। इस तरह से चार क्षेत्रों में यह कार्य बँट गया पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और एक जाल की तरह अनुस्थापन का काम चलने लगा।

उसी समय विभिन्न प्रान्तों में नई तालीम के उपलक्ष्य में सम्मेलन होते थे उससे भारत की सारी संस्कृतियाँ समेटकर राष्ट्रीय स्तर पर एक विशाल भारतीय संस्कृति का रूप मूर्तिमान हो रहा था। भारत

सरकार न भी एक राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की। जिसमें बुनियादी शिक्षा पर संशोधन कार्य करने के लिए फ़ैलविन क्लाइड, बेजामिन, सुलेमान जैसे लोग विदेशों से आते थे और गांधीजी के तत्वज्ञान का अभ्यास करते थे। यह बुनियादी शिक्षा के इतिहास का एक गौरव युग, एक स्वर्ण युग था। उस समय की जब मैं याद करता हूँ तो भीतर से आज भी उल्लास उमड़ आता है।

१९५८ में विनोबाजी ने इस मौलिक कार्य को मद्दे नज़र कर क 'अपना मत लिखा था कि अब बुनियादी तालीम का भविष्य निश्चय ही उज्ज्वल है। पर रामचन्द्रन समिति की रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ कि कार्य गलत दिशा में चल रहा है। प्रायमरी बुनियादी स्कूल में पढ़े हुए बच्चे जब माध्यमिक विद्यालय में आते थे तो उनका साधा हुआ जीवन उपयोगी नहीं होता था और उद्योग भी बंद हो जाता था। अतः केवल प्रायमरी स्तर पर चलनेवाली शिक्षा निरुपयोगी है। जहाँ विज्ञान में माध्यमिक स्कूलों में भी उसका काम चलता था वहाँ भी उन विद्यार्थियों को महाविद्यालयों में प्रवेश नहीं मिलता था। अतः डा. राधाकृष्णन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण बुनियादी संस्थाओं का आरम्भ हुआ किन्तु वहाँ से डिप्लोमा लेने वाले छात्रों को डिग्री के लिए प्रवेश नहीं मिलता था। अन्य बातें भी थीं। यदि शिक्षक अपना काम निष्ठा से करेंगे तो भारत के नागरिक भी उपयुक्त बनेंगे। और फिर शिक्षक वैसे ही बनेंगे जैसे कि प्रशिक्षण महाविद्यालय होंगे। परन्तु उन्हीं के काम में गिरावट आने लगी।

निष्ठा से काम करनेवाले शिक्षकों का व्यवहार कैसा होना चाहिए इसके सम्बन्ध में बिहार के विद्यालय के एक शिक्षक को समझाते हुए कहा था कि खादी की कल्पना अलग ही है। नौकरी की पूर्वगर्त में खादी पहनना भले ही न हो, खादी के बारे में मैं हृदय परिवर्तन भी नहीं कर सकता पर जरूर कह सकता हूँ कि यह वस्त्र साधारण वस्त्र नहीं है, इसके अंदर में पीछे तो एक भावना है। अहिंसा की विचारधारा के लिए जीवनयापन करनेकी प्रणाली को अपनाना यही खादी पहनने का लक्ष्य है। उमकी विचार धारा है :—(१) सादा जीवन बिताना, (२) नियमित

धम करना, (३) योग्य वतवि करना, (४) नशा सेवन न करना, (५) समन्वयपूर्ण जीवन, (६) अमंग्रह, (८) हफ्तेमें दो घंटे गमाज सेवा करना। उनके लिए अनिवार्य नहीं कि खादी पहनकर ही उसका महत्व समझना चाहिए, खादी न पहनकर भी खादी के संस्कार मनमें रह सकते हैं। चरखे का उपयोग, तो व्यवसाय के विकेन्द्रीकरण के लिए है।

मेरा तो खादी के साथ सीधा संबंध है इसलिए मैं उसके बारे में स्पष्ट रूप से बता सकता हूँ। रही विकेन्द्रीकरण की बात। अंबर चरखे की कमाई से स्त्रियों को काम मिला। हररोज चार घंटे काम करने से ४ गुंडिया बनती हैं, उनसे ९ गज कपड़ा बनता है, गाल में ७०००० गज। उतना कपड़ा गांव की ग़रीबी दूर करने में मदद करता है। इसीलिए चरखा धड़ा का म्यान मेंता है।

आपके निर्धारित पाठ्यक्रम में खादी का महत्व ग्रहण कर के अपने संस्कारों की विशेषताओं को कायम रख सकते हैं पर वे जड़ (rigid) न हों तबोले (flexible) होने चाहिए। जिंदगी के लिए जिन तत्वों को नहीं छोड़ा जा सकता वे महत्व हैं — (१) सादा जीवन, (२) स्वस्थ जीदन, (३) सहयोगी जीवन, (४) समन्वित जीवन, (५) सांस्कृतिक एकता, (६) फौदुम्बिक भावना, (८) विश्व पारिवारिक जीवन।

कोई भी राष्ट्र इन विचारों को छोड़कर जिंदा नहीं रह सकता।

सभी अच्छाइयों को बावजूद भी प्रशिक्षण में गिरावट आने से उसका भविष्य अच्छा नहीं रहा। आचार्यों के भरसक परिश्रम के बाद भी उनमें अपार नश्य छिड़ गया।

तब भारत सरकार ने निश्चय किया कि अपने देश में शिक्षा की दो दो प्रणालियाँ एक साथ नहीं चल सकती अतः एक समन्वित पाठ्यक्रम बनाना होगा। प्रत्येक राज्य का एक ही पाठ्यक्रम होगा, १८ राज्यों ने प्राथमरी व बेसिक तत्वों का समन्वय करके एक पाठ्यक्रम बनाया।

समीक्षा इस प्रकार हुई कि उसमें बहुत ही अच्छी बातें हैं। १९५९

कै जनवरी से ३ राज्यों में उसपर अमल किया गया, वहीं उसका पटन का क्षण था। पूरी ईमानदारी से बनाई हुई अच्छी योजना की शुरुआत थी वहीं जमका लय हुआ।

आम जनता की धारणा है कि यह शिक्षा असफल हो गई, पर उसकी उपलब्धियाँ भी हैं और वे बुनियादी शिक्षा की असफलता के बावजूद भी महत्वपूर्ण हैं। इन दो दिनों में आपने बुनियादी शिक्षा का २० वर्षों का इतिहास देखा आज उसकी उपलब्धियाँ देखेंगे जो आपको प्रेरणा दे सकें।

बुनियादी शिक्षा की उपलब्धियाँ तीन खंडों में देखने मिलेंगी।

(१) स्वास्थ्य सफाई— लोगों को सफाई के महत्व का भान हुआ। लोग साफ-सुथरे रहने में गौरव महसूस करने लगे। स्वच्छताका असर जनस्वास्थ्य पर भी पड़ा। वंशभूषा में परिवर्तन हुआ किन्तु लोग सादगी से रहते थे। महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को पारंपरिक जीवन से अलग एक नई दृष्टि मिली। एक ऐसी नई बात जैसे पहले कभी बताई नहीं गई थी, कभी सोची नहीं थी। उदाहरणार्थ पटना के विद्यालय के बच्चे ७० एकड़ का मैदान बिना नौकरों के साफ करते थे। बड़े बड़े अमीरों के लड़के श्रम की ओर उन्मुख हुए, उनके घरों में जैसे दर्जनों नौकर काम करते थे। सादिपनी आश्रम में कृष्ण सुदामा एकत्र जीवन बिताते थे उसी प्रकार बुनियादी विद्यालयों में गरीब अमीर एक साथ काम करते थे यह एक महान क्रांति थी। इस प्रकार की वृत्ति और वातावरण धीरे-धीरे बनता जाता था, देहातो में मलमूत्र विसर्जन की बड़ी समस्या थी। देश के पाँच लाख गांवों में बसने वाली स्त्रियों की दयनीय स्थिति थी, नई बहुएँ शौच के लिए बाहर नहीं जा सकती थीं। उसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्या किया जाए यह सोचा गया और कुछ उपाय भी किए गए। उसीके कारण सर्वोत्तम सुलभ शौचालय; आधुनिक मुविद्याओं के साथ बन जा आज भी विहार में उपयोग में लाए जाते हैं। स्वास्थ्य के बारे में यह एक महत्वपूर्ण कार्य है।

(२) स्वास्थ्य-व्यवस्था और श्रम का महत्व :— श्रम के काम में सज्जा का भाव जीवन से मिट गया। सुबह की प्रार्थना से लेकर सायंकाल

की प्रार्थना के समय तब वाम किया जाता था। राजा जनक की हल चलाने की कहानी रामायण में है और बम्बुनिस्टो का हँसिया और हथौड़ा भी श्रम का प्रतीक है। १९५३ का साल श्रमोत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। शृषि बागवानी, सागवानी, फलरक्षण, फल उत्पादन, मधुमक्खी पालन, गोपालन, कुकटुपालन, घताई, रगाई, छपाई, सिलाई, गलीचे दरियो की बुनाई आदि उद्योगों के जरिए ३ लाख ३० हजार की आय हुई। बिहार सरकार ने तब किया कि ऐसे उत्पादन का ५०% फायदा विद्यार्थियों को, और ५०% स्कूल को मिलेगा। बिहार में सरकार के पास ३५ लाख रुपये जमा हो गए। गाँव साफ हो गए, श्रम उत्पादन की दिशा मिल गई।

(३) सांस्कृतिक जीवन — सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के परिवर्तन में गांधीजी रुकल हुए थे। बगंभेव, छूआछूत, छोटे बड़े के भेद मिटे और अपनेपन की भावना पनपी। चपारन, बेंडछी, मछलीपट्टन आदि जहाँ जातिभेद ऊँचाई पर था वह यम हुआ।

मनोरंजन के लिए देहातो में सांग शहरों में जाते थे, पर देहातो की मोदम डलियों के कार्यक्रमों को देखने, सुनने के लिए देहात के लोग इकट्ठे होते थे। अतः सिनेमा के उत्तेजक गाने जो कि शहरों के प्रभाव से गाये जाते थे बद हुए क्योंकि लोगों ने मनोरंजन के लिए शहरों तक जाना छोड़ दिया। सिनेमा गीतों की जगह भजनो, समूह गीतों ने संगीत ने ल ली।

मेकैल ने कहा था, हमें भारतीयों को ऐसी शिक्षा देनी है जो रफ्त और देह से भारतीय हो विन्तु मस्तिष्क और विचार में अंग्रेजियत रखते हों। इस व्यापक अंग्रेजियत के प्रसार का विरोध बुनियादी शिक्षा के इन विभिन्न कार्यक्रमों से अहिंसक रूप से हुआ। प्रार्थना सभाएँ बनाई गई, बच्चा व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। बलेरिज नं० ७९ स्कूलों का निरीक्षण कर के कहा आत्म ज्ञान का बोध इस शिक्षा का महत्वपूर्ण भाग है। बिहार के इस १९४३ के कार्यक्रम के बारे में स्टुवर्ट ने रिपोर्ट लिखते समय कहा था कि इस शिक्षा व्यवस्था से उत्पन्न आत्म-विश्वास, स्वावलम्बन ये गांधीजी की आत्मा के परिणाम हैं।

गिरावट कैसे आई? — ऊपर की महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बावजूद शिक्षा में गिरावट कैसे आई वह विचारणीय है। ममन्वित पाठ्यक्रम के द्वारा धीरे धीरे स्कूल के कार्यों में परिवर्तन होने लगा। उसके निरीक्षक निरीक्षण में विभिन्न प्रकार की सूचना देने लगे जैसे सफाई बंद करो, 'प्रार्थना बंद करो आदि। कताई नहीं हो सकी क्योंकि उनके लिए व्यवस्था भी नहीं थी। अतः विद्यार्थी विवश होकर पारंपारिक स्कूल में जाने लगे। लोगों में भी निराशा फैल गई और बुनियादी शिक्षा का अर्थ का भविष्य बिलकुल निराशाजनक रहा। वैसे भी आदर्श को निर्माण करना आसान है उसे जीवन में उतारना कठिन होता है। गलत लोगों के हाथ में शिक्षा जाने से काम अमफल होने लगा। फल-स्वरूप ६०-६८ तक तो यह बिलकुल बंद सी हो गई। इसी काल में कोठारी कमिशन की रिपोर्ट निकल गई। उसमें उन्होंने लिखा है कि केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के बुनियादी शिक्षा के प्रयास आज उसके ढाँचे के रूप में ही हैं, उनकी आत्मा मर गई है।

आज की वर्तमान स्थिति — आज तो बुनियादी शिक्षा का नामो-निशां नजर नहीं आ रहा है। बिहार में जहाँ सबसे अच्छा काम हुआ था वहाँ आज एक भी नलास नहीं रहा। कितने ही उच्च शिक्षित प्रशिक्षितों को अन्यत्र काम नहीं मिलता है। इस प्रकार जो बुरी परंपरा चल रही है उसमें आमूल परिवर्तन होना चाहिए। जे. पी. की संपूर्ण क्रान्ति की घोषणा हो चुकी है। उस पार्श्वभूमि में बुनियादी शिक्षा के बीज पनप सकते हैं। बेकारी, शिक्षित विद्यार्थी, राजनेताओं की नीति तथा देश की दुर्दशा की स्थिति में इस बुनियादी शिक्षा से सहारा मिल सकता है।

हमारे पंतप्रधान श्री मोरारजी देसाई ने अपने कार्यकाल के प्रथम भाषण में कहा है— पहले बच्चों को आदमी बनाओ बाद में उन्हें दूसरी बातें सिखाओ। इस कथन को तथा जे. पी. की संपूर्ण क्रान्ति को सफल करने के लिए बहुत ही संगठित प्रयत्न करने चाहिए। बुनियादी शिक्षा के नवनिर्माण का काल है। उनके लिए कुछ सुझाव इस प्रकार हैं :—

(१) भारत सरकार बुनियादी शिक्षा को कार्यान्वित करने की घोषणा करे।

(२) राज्य स्तर पर भी बुनियादी शिक्षा को क्रियान्वित करने की घोषणा की जाए।

(३) सरकार द्वारा राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा सस्या की स्थापना होनी चाहिए। जिसमें उच्च स्तर के प्रशिक्षित, अनुभवी लोग हों।

(४) राज्य सरकार विश्वविद्यालयों का निर्माण करे।

(५) स्कूलों के लिए जो पाठ्यक्रम बनाया गया उसे १९८७ में नये संदर्भ में प्रस्तुत करना चाहिए। स्कूलों में कार्यशालाएँ हों जिन में प्रत्येक विद्यार्थी बारह घंटे काम करे। काम की समय-मर्यादा इतनी हो कि जब तक वह खुद कमा नहीं सकता।

(६) बुनियादी शिक्षा के लिए उपयोगी साहित्य की निर्मिति योजना सरकार द्वारा बनाई जाए।

(७) प्रशिक्षण कालेज द्वारा जो शैक्षणिक साधन बनाए जाएँ उनका स्कूल स्तर पर तथा महाविद्यालय में भी उपयोग हो।

(८) उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय ऐसे बुनियादी महाविद्यालयों से आए हुए विद्यार्थियों को पूरे विश्वास से प्रवर्ध दें।

(९) जनता इस में पूरी तरह से सहयोग दे।

ईश्वर करे और हमारी इस योजना को क्रियान्वित करने की सुझुझि सरकार को मिले ताकि दश की कामयाबी पलट हो जाए।

।। ग्राइस्ट की मृत्यु के बाद ३०० वर्ष के बाद ईसाई धर्म फैला, भगवान बुद्ध के निवाण के बाद ३५० वर्ष बाद बौद्ध धर्म पनपा। बीज के अकुरण में संकड़ों साल लगते हैं। इस प्रकार बुनियादी शिक्षा के बीज का चालीस साल हुए हैं। वह ५५५५५५ स्वायत्तम्बी, स्वाभिमानी, श्रमनिष्ठ सहयोगी, नागारक तैयार करेगा। उससे लोकतन्त्र आधारित, समता पर आधारित एक विशाल हरीतिमा फैलेगी। नये मानव से नया ससार रोशन होगा, दम में गांधी शिक्षण भवन मार्गदर्शन करेगा। अस्तु

(गांधी शिक्षण भवन, बम्बई में १४-१५-१६ फरवरी १९७८ को दिए गए व्याख्यान का सारांश)



सेवाग्राम में नई तालीम

श्री सत्यनाथन

भारतीय स्वातन्त्र्य संग्राम का एक बालक 'नई तालीम' है जिसकी सेवाग्राम में प्रगति इस संग्राम के उबार भाटे के साथ अनमिल थी। गांधीजी ने इस संग्राम का तथा शिक्षा योजना का दिशानिर्देश किया था तथा इन दोनों को बदलने वाली परिस्थितियों के अनुरूप इन्हें ढाला था।

सन् १९३७ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ९ प्रदेशों में शासनसूत्र सभावा अतः वह शिक्षा के लिए भी जिम्मेवार बनी। वह अनिवार्य शिक्षा तथा दारुबंदीको लागू करने के लिए वचन दद थी। गांधीजी ने इसे अमल पाया कि शिक्षा मददान की कमाई की बगई पर आधारित हो। ऐसे समय पर मारवाडी शिक्षा मंडल वर्धा अपनी रजत जयन्ती मना रहा था। इस उत्सव के एक अंग के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा की समस्याओं पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित किए जाने की योजना पर विचार किया गया। यह सम्मेलन दिनांक २२-२३ अक्टूबर १९३७ को वर्धा में हुआ तथा इसमें भारत सरकार तथा अन्य प्रादेशिक सरकारों के शिक्षा मंत्रियों तथा प्रमुख शिक्षा शास्त्रियों ने भाग लिया। गांधीजी ने अपने अध्ययनीय भाषण में हस्त उद्योगों द्वारा शिक्षा को आत्म निर्भर बनाने की अपनी योजना को समझाया। उचित विचार विमर्श के पश्चात् गांधीजी की कल्पना सम्मेलन द्वारा स्वीकृत की गई। तत्पश्चात् मार्च १९३८ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा (गुजरात) के ५१ व अधिवेशन में इस सम्मेलन की सिफारिशें स्वीकृत की गईं और उसी के तत्वावधान में एक स्वायत्त मस्यौदा 'हिन्दुस्तानी तालीमी मध' का गठन हुआ। इन मस्यौदों को राष्ट्रीय शिक्षा की योजना को आग बढाने का काम सौंपा गया। इस मस्यौदों के सविधान के अनुरूप इस निम्नलिखित कामों का अधिकार था —

- (अ) बुनियादी तालीम के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम तैयार करना
- (ब) बुनियादी तालीम की समस्याओं का संचालन एवं निरीक्षण

(क) अध्यापकों के प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन, सहायता एवं निरीक्षण

(ङ) उपयुक्त साहित्य का निर्माण एवं प्रकाशन

(ख) आवश्यक शोध कार्य का किया जाना

(ग) आन्दोलन का आयोजन

(घ) प्रादेशिक तथा निजी संस्थाओं द्वारा संचालित बुनियादी तालीम के कार्यक्रम के स्वीकार हेतु आवश्यक कदम उठाना।

संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अनुसार हिन्दुस्तानी तालीमी संध ने सेवाग्राम में तथा अन्य कई प्रदेशों में सन् १९५९ तक नई तालीम का काम प्रारम्भ किया। इसके पश्चात् वह सर्व-सेवा संध में विलीन हो गया।

नई तालीम के सेवाग्राम के कार्य को तीन अवस्थाओं में बाँटा जा सकता है —

(१) बुनियादी शिक्षावस्था : १९३९ - १९४४

(२) समग्र नई तालीमवस्था - १९४४ - १९५२

(३) ग्राम स्वराज्य— नई तालीमावस्था : १९५२, १९५२

(१) बुनियादी शिक्षावस्था: (१९३९-१९४४) -

हिन्दुस्तानी तालीमी संध ने अपना प्रमुख कार्यालय सेवाग्राम में इस हेतु स्थापित किया था कि जिससे कार्यक्रम संचालन हेतु गांधीजी का मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। संध की २३, २४ अप्रैल १९३८ को हुई इसकी पहली बैठक में संध ने सेवाग्राम में प्रायोगिक बुनियादी पाठशाला प्रारम्भ करने का निश्चय किया, किन्तु यह निर्णय सितंबर १९३९ में ही एक डिस्ट्रिक्ट कौंसिल शिक्षक तथा चार छात्रों के साथ क्रियान्वित हो सका। संध की बैठक से पहले या पाठशाला के प्रारम्भ होने से पहले योजना को कार्यान्वित किए जाने के लिए प्रदेशों द्वारा प्रशिक्षित अध्यापकों की माँग की गई। इसके लिए वर्षा में २१ अप्रैल १९३९ को शिक्षकों तथा निरीक्षकों के लिए एक अल्प कालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किया गया था। सन् १९४१ तक जब दूसरा बुनियादी सम्मेलन दिल्ली के पास जामिया नगर में हुआ तब तक सेवाग्राम की यह पाठशाला चौथी

वक्षा के स्तर तक की पाठशाला हो गई थी। उक्त सम्मेलन के लिए दिए गए अपने संदेश में गांधीजी ने इस बात पर बल दिया था कि "पूरा प्रयोग बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप और सघिके वही न वही किया जाना है।" अपने सीमित साधनों के भीतर इस प्रयोग को सेवाग्राम के कार्यकर्ताओं द्वारा उसके सही रूप में करने का प्रयत्न किया गया।

देशपर जब तूफान के बादल उमड़े तब १ अगस्त १९४२ को जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है आवासीय बनियादी पाठशाला तथा प्रशिक्षण शाला नई तालीम भवन— केवल प्रशिक्षण महाविद्यालय ही नहीं था, किन्तु एक ऐसा घर था जिसमें शिक्षक और छात्र आत्मीय भाव से एक साथ रहते, काम करते एवं अध्ययन करते थे। क्योंकि जैसा कि डॉ. झाकिर हुसैन ने निर्दिष्ट किया है "सच्ची शिक्षा वह है जो प्रेमपूर्वक दी जाती है।" आप देखेंगे कि शिक्षा की पुस्तक के पहल पृष्ठ पर ही 'प्रेम' शब्द लिखा हुआ होगा।

इस भवन का दूसरा उद्देश्य यह था कि उस का आधार 'सत्य' होना चाहिए। इसी उद्देश्य से वहाँ की दैनिक प्रार्थना, उपनिषद् से ली गई थी जिस का अनुवाद इस प्रकार है— मैं केवल सत्य ही बोलूंगा, सत्य मेरी रक्षा करेगा, सत्य मेरे शिक्षक की रक्षा करेगा।

इस प्रार्थना को सुनकर इस भवन का उद्घाटन करते हुए बापू ने आशीर्वाद दिया था— "यह प्रार्थना आपकी रक्षा करे।" कुछ दिनों बाद ही वे जेल में थे।

(२) समग्र नई तालीम अवस्था (१९४४-१९४७)

१९४२-४५ तक का समय इस लघु समाज और राष्ट्र के लिए अधिकार और नैराश्रय या उदासी का था। किन्तु यह समय वैसा ही अण्डे-मेवन का था जैसे अधिकार में धरती से अकुर फूट निकलता है। इस समय में नई तालीम की विचार धारा धीरे-धीरे बाह्य और सेवाग्राम के मस्तिष्क में रूप ग्रहण कर रही थी। नई तालीम योजना के जनक गांधीजी भी उस योजना के आशय या मूढार्थ के विषय में चिन्तन कर रहे थे। मन् १९४४ में जब वे जेल से बाहर आए तो 'नई तालीम' के तथा उसके उद्देश्य या क्षेत्र के विषय में उनकी नई दृष्टि थी।

गुरु में जैसा कि सोचा गया था यह योजना केवल अनिवार्य शिक्षा अर्थात् ७ से १४ वर्ष तक की उम्र के लिए ही थी। गांधीजी 'नई

(क) अध्यापकों के प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन, सहायता एवं निरीक्षण

(ड) उपयुक्त साहित्य का निर्माण एवं प्रकाशन

(ख) आवश्यक बोध कार्य का किया जाना

(ग) आन्दोलन का आयोजन

(घ) प्रादेशिक तथा निजी-संस्थाओं द्वारा संचालित बुनियादी तालीम के कार्यक्रम के स्वीकार हेतु आवश्यक कदम उठाना।

संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अनुसार हिन्दुस्तानी तालीमी संघ ने सेवाग्राम में तथा अन्य कई प्रदेशों में सन् १९५९ तक नई तालीम का काम प्रारम्भ किया। इसके पश्चात् यह सर्व-सेवा संघ में विलीन हो गया।

नई तालीम के सेवाग्राम के कार्य को तीन अवस्थाओं में बाँटा जा सकता है—

(१) बुनियादी शिक्षावस्था : १९३९ - १९४४

(२) समग्र नई तालीमवस्था : १९४४ - १९५२

(३) ग्राम स्वराज्य— नई तालीमवस्था : १९५२, १९६२

(१) बुनियादी शिक्षावस्था: (१९३९-१९४४) :

हिन्दुस्तानी तालीमी संघ ने अपना प्रमुख कार्यालय सेवाग्राम में इस हेतु स्थापित किया था कि जिससे कार्यक्रम संचालन हेतु गांधीजी का मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। संघ की २३, २४ अप्रैल १९३८ को हुई इसकी पहली बैठक में संघ ने सेवाग्राम में प्रायोगिक बुनियादी पाठशाला प्रारम्भ करने का निश्चय किया, किन्तु यह निर्णय सितंबर नवम्बर १९३९ में ही एक डिस्ट्रिक्ट कोशिल शिक्षक तथा आर छात्रों के साथ क्रियान्वित हो सका। संघ की बैठक से पहले या पाठशाला के प्रारम्भ होने से पहले योजना को कार्यान्वित किए जाने के लिए प्रदेशों द्वारा प्रशिक्षित अध्यापकों की माँग की गई। इसके लिए वर्षा में २१ अप्रैल १९३९ को शिक्षकों तथा निरीक्षकों के लिए एक अल्प कालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किया गया था। सन् १९४१ तक जब दूसरा बुनियादी सम्मेलन दिल्ली के पास जामिया नगर में हुआ तब तक सेवाग्राम की यह पाठशाला चौथी

सेवाग्राम आश्रम-वृत्त

(जनवरी, फरवरी, १९७८ का)

आश्रम प्रतिष्ठान परिक्षेत्र में इस अवधि में पूर्णतया शोक की छाया ही फैली रही । उधर आंध्र प्रदेश के अवनिगुड्डा क्षेत्रमें सूफान तथा जलप्रपात द्वारा जो मानव हुआ और जो मानव सहार हुआ वह भी अति भयानक था । इस तरह १९७८ का प्रारम्भ ही शोकग्रस्ता से हुआ । फिर भी आश्रम का काम पूर्ववत् ही चला । आश्रम प्रतिष्ठान के मंत्री श्री० प्रभावरीजी ने पूरे तीन माह तक अहोरात्र अन्याहत परिश्रम कर अवनिगुड्डा क्षेत्र के पुनर्रचना के कार्य में सहयोग दिया । आश्रम प्रतिष्ठान की ओरसे श्री सूर्यनारायण मूर्तिजी तथा श्री चरणदास भी इस क्षेत्र में सहायता कार्य के लिए गए थे ।

स्वर्गीय आचार्य श्रीमन्नारायणजी की आत्माकी चिरशान्ति के लिए आश्रममें तथा १३ जनवरी को विशेष प्रार्थनाओं का आयोजन किया गया और दिवंगत आत्मा की स्मृति में आश्रम प्रांगण में वृक्षारोपण भी किया गया ।

इस अवधि में ७६१० दर्शनार्थी आश्रम देखने आए जिनमें २३३ टोलियाँ भी शामिल हैं । विद्यार्थी वर्ग की उपस्थिति विशेष प्रशंसनीय रही । इस अवधि में हॉलैंड एन्स, जापान, कॅनेडा, जर्मनी, अमेरिका से कुल मिलकर २१ विदेशी अतिथि आश्रम में दर्शन तथा अध्ययन हेतु रहे ।

जनवरी २२ से लेकर २५ तक “ग्रामाभिमुख विज्ञान” इस विषयपर एक अन्तर्राष्ट्रीय परिसंवाद आश्रम प्रतिष्ठान परिक्षेत्र में मगन सप्रहालय की ओरसे आयोजित किया गया । इस परिसंवाद में कुल ३२ विदेशी वैज्ञानिक तथा ५० भारतीय वैज्ञानिकाने भाग लिया

और दारिद्र्य रेखा के निचले स्तर वालों के लिए विज्ञान का उपयोग किम तरह हो सकता है इस संबंध में चर्चाएँ की। श्री देवेंद्रभाई गुप्त ने अपने साथियोंकी मदद से इसका सुन्दर आयोजन किया था।

आश्रम के नित्य कार्यक्रम नियमित रूपसे चले। प्रातः प्रार्थनाओं में कुल औसत उपस्थिति ६.५ रही, तथा सायं प्रार्थना में औसतन १४.५ लोग ही रहे। दोपहर के सूनयज्ञमें ८.५ उपस्थिति रही।

स्मारक कुटियों की रक्षाकी दृष्टि से इस अवधि में बापू के बैठने की गद्दी और पात के सामान की सुरक्षा को ध्यानमें रखते हुए एक बारीक रस्सी से यह स्थान घेर दिया गया। इस व्यवस्था को आश्रम प्रतिष्ठान के उपाध्यक्ष पू० चिमनलाल भाईजी तथा मंत्री श्री प्रभाकरजी ने मजूरी दी। अब बापूके गद्दीकी पूरी सुरक्षा तो हुई है किन्तु दरनायियोंके लिए भी कोई असुविधा नहीं हो पाई। बापू द्वारा उपयोग में लाई गई स्मारक वस्तुओंमें से दिल्ली के गांधी संग्रहालय के पास दीर्घकालीन सुरक्षा उपचार करने के लिए बापू के कपड़े दिये थे वे सारे उपचार के बाद वापिस लाए गए हैं। अब सफाई की चीजें तथा धातुकी बनी चीजोंको थोड़ी थोड़ी करके दिल्ली भेजी जाएंगी जिसकी प्रतिकृतियाँ बनवाकर तथा उनपर दीर्घकालीन सुरक्षा उपचार कराकर वापिस सेवाग्राम आश्रम में रखी जाएगी।

शं. प्र पांडे

५६

संस्था कुल

गांधी स्मारक निधि का मासिक

सम्पादक - श्री पूर्णचन्द्र जैन

वार्षिक शुल्क-५ रुपये,

एक प्रति-५० पैसे

रचनात्मक प्रवृत्तियाँ वार्यों सर्वोदय संगठन एवं

राष्ट्रीय हस्तशिल्प की जानकारी देनवाला

एक प्रभावशाली माध्यम

संपक करें-व्यवस्थापक, संस्थाकुल

गांधी स्मारक निधि,

राजघाट, नई दिल्ली-२

गांधी मार्ग

गांधी विचारक सृजनात्मक साहित्य का मासिक

सारगर्भित लेख, लघु लेख, कहानी, नाटक, कविता,

संस्मरण एवं व्यक्ति-चित्रों से युक्त

विचारणीय पाठको एवं मवसाधारण पाठका के लिए पठनीय

सम्पादक

श्री भवानोप्रसाद मिश्र

वार्षिक शुल्क रु १२

द्विवार्षिक रु २२

एक प्रतिका मूल्य १ रु

संपक करें व्यवस्थापक 'गांधीमार्ग' (हिंदी मासिक)

गांधी शान्ति प्रतिष्ठान, २२१-२२

दीनदयाल उपाध्याय मार्ग

नई दिल्ली-२

If thy aim be great and thy means small, still act, for by action 'alone these can increase Thee."

—Shri Aurobindo

Assam Carbon products Limited
Calcutta--Gauhati--New Delhi.

"यदि आपका ध्येय बड़ा है, और आपके साधन छोटे हैं, तो भी कार्यरत रहो, क्योंकि कार्य करते रहनेसे ही वे आपको समृद्धि प्रदान करेंगे।"

—श्री अरविन्द

आसाम कार्बन प्रॉडक्ट्स लिमिटेड

कलकत्ता - गौहाटी - न्यू देहली

हम केवल व्यापारिक संस्थान ही नहीं हैं

आज के गतिशील संसार में कोई भी उद्योग समाज की आवश्यकताओं की अवहेलना नहीं कर सकता, क्योंकि सामाजिक उत्तरदायित्व व्यापार का आवश्यक अंग बन गया है।

इण्डिया कारबन लिमिटेड

केल्साइन्ड पेट्रोलियम कोक के निर्माता

नूनमाटी, गोहाटी-781020

हिंदुस्थान शुगर मिल्स लिमिटेड का विभाग मेसर्स उदयपुर सीमेंट वर्क्स की शुभ कामनाएँ

उच्च धेनी का 'शक्ति' छाप सीमेंट जिसका उपयोग बड़े पैमाने पर सब तरह के नवनिर्माण कार्य के लिए मजबूती तथा विश्वसनीयता के साथ किया जाता है।

व्यवस्था एवं बिक्री कार्यालय—

फैक्टरी,
पो आँ बजाज नगर
(सी एफ ए)
जि उदयपुर (राजस्थान)
फोन दक्क ३६ और ३७
उदयपुर २६०६

शहर कार्यालय,
६० नया पत्तेपुरा
उदयपुर ३१३००१
फोन ४४९, ग्राम 'श्री'
उदयपुर

नयी तालीम



संयोजक
प्रौढ़-शिक्षा अंक

प्रौढ़ शिक्षा पर गांधी जी के विचार
प्रौढ़ शिक्षा पर विनोबा जी के विचार
हिन्दी का विकास क्या हो ?

—जयप्रकाश नारायण



भारतियेल भायत नयी तालीम अमिति

वर्ष २६
अप्रैल
नवम्बर

अंक

प्रधान संपादक — श्री के० अक्षयचलम्

संपादक मंडल — श्री द्वारिका सिंह

श्री बज्रमार्ग पटेल

श्री काशीनाथ त्रिवेदी

श्री ज्योति भाई बेष्टाई

सम्पादक — डा० देवेन्द्र दत्त तिवारी

संपादकीय १

शुद्ध विषयेयुं ज्ञान शक्तिं न लभयेत् ४ पू० विनोबा

श्रीष्ठ शिक्षा पर चापीजी के विचार ३

श्रीष्ठ शिक्षा पर विनोबाजी के विचार ८

हिन्दी का विकास क्या हो १० श्री जयप्रकाश नारायण

हमें स्कूल को क्यों समाप्त करना है ११ अनु० डा० देवेन्द्र दत्त तिवारी

उत्तर प्रदेश और श्रीष्ठ शिक्षा १५ श्री द्वारिका प्रताप माहेश्वरी

समाजोपयोगी संपादक कार्य के द्वारा शिक्षण २० श्री बज्रमार्ग पटेल

राष्ट्रीय श्रीष्ठ शिक्षा कार्यक्रम-एक रूपरेखा २२ शिक्षा एवं समाज उत्थापन-समाजवादी भारत सरकार, नयी दिल्ली

श्रीष्ठ शिक्षा नीति वक्तव्य ३२ शिक्षा तथा समाज उत्थापन, मंत्रालय, भारत सरकार

मानवसंश्लेषण साक्षरता दिवस ३५ ज्ञान ई० पाठ्य, उप निदेशक, यूनेस्को

श्रीष्ठ शिक्षा की समस्या है ४१ श्री बाबूराम मधवाल

नयी तालीम

शिक्षाको प्रशिक्षणको एवं समाज शिक्षा के लिए

सम्पादकीय

प्रौढ शिक्षा का राष्ट्रीय कार्यक्रम इतिहास की पुनर्जागरिता

दिसम्बर १९७३ में प्रौढ शिक्षा का राष्ट्रीय नीति घोषित की गयी और प्रौढ शिक्षा को सर्वाधिक महत्व देने पर बल दिया। इसके पूर्व जो ध्यानपूर्ण सभी उनमें सामाजिक शिक्षा और विकास का बल दिया गया था किन्तु इस बार का प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम मुख्यतः साक्षरता केन्द्रित है। नीति वक्तव्य के अनुच्छेद ३ में कहा गया है कि प्रौढ शिक्षा में समाज के आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से वंचित लोगों को साक्षरता प्रदान करने पर बल देना चाहिए। यह बात भी संकेत रूप में कही गयी है कि यह कार्यक्रम सीखने वालों के जीवन में सम्बन्ध होना चाहिए।

प्राथम्य के तहत १० करोड़ लोगों को साक्षर बनाने का बड़ा धाराी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्ष १ अक्टूबर १९७३ को यह कार्यक्रम औपचारिक रूप से अखिल भारत के रूप में चलाया गया तो प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई ने ठीक ही कहा कि इस प्रकार का लक्ष्य निर्धारण ठीक नहीं है और उन्होंने यह सुझाव दिया कि १५ वर्ष से ऊपर के लोगों को भी इस कार्यक्रम में लिया जाय। वैश्वीय शिक्षा मन्त्री जो उस समय समा में उपस्थित थे। यह सुझाव स्वीकार कर लिया। इस ही कार्यक्रम की मुक्ता और भी बढ़ जाती है।

राष्ट्रीय नीति के घोषणापत्र में यह भी कहा गया है कि कार्यक्रम को जन आन्दोलन के रूप में चलाते की आवश्यकता है। घोषणा का अर्थ महत्वपूर्ण कि यह है कि कार्यक्रम विकेंद्रित रूप में संचालित किया जाय और सबसे निचे जननीयता पुनर्स्थापित कर भी जाय। इससे किसी की आपत्ति नहीं हो सकती कि निरक्षरता देश के लिए बुरा विपदा है किन्तु जिस जन आन्दोलन की बात घोषणापत्र में कही गयी है उसका कोई स्वरूप नहीं दिखाई दे रहा है। यह स्पष्ट है कि जन आन्दोलन सरकारी तब और लोकतांत्रिकी द्वारा नहीं चलाया जा सकता। यदि इसे जन आन्दोलन का रूप देना चाहे तो इस योजना का कम से कम सरकारी तब के क्षेत्र में नहीं चलना पड़ेगा। आज यह कार्य ऐसे सरकारी अधिकारियों के हाथों में दिया जा रहा है जिनकी सचता अनुपस्थिति और सेवाभावना में ही लोगों को है। यह कहा जा सकता है कि सरकारी तब की समता योग्यता तथा सेवाभावना पर भी लोगों को संदेह है किन्तु इन संदेह में सतर्कता कम है और यदि है तो फिर विकेंद्रिकरण की बात घोषणापत्र में की के पहले ही होनी चाहिए थी। आवश्यकता इस बात की थी कि राज्य मन्त्रालय, खास सभी स्तरों पर सरकारी स्थापनों का सहयोग लेकर कार्यक्रम को जन-आन्दोलन के रूप में चलाया जाय।

जनवरी १९७८ में राष्ट्रीय कार्यक्रम की विस्तृत योजना सामने आई। जिन अनुमानों पर योजना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है अब ये ही आधारहीन हो तो योजना की सफलता संवेहास्पद हो जाती है। योजना में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 'कार्यक्रम जन आन्दोलन का रूप लेता है यह इस बात पर निर्भर रहेगा कि नगरपालिका और विद्यापीठ वहाँ तक इस कार्यक्रम से प्रतिबद्ध किये जा सकते हैं। आम शिक्षण संस्थाओं का जो वातावरण विभिन्न प्रदेशों में है और उनके समाचार प्रति दिन अखबारों में आते हैं, उसे देखते हुए यह स्पष्ट है कि आम का पुनर्क स्थापित या अनुचित रूप से नष्ट हो चुका है, उनकी समस्याओं का समाधान होने का कोई बम्बोरी प्रयास किसी रिश्ते में नहीं हो रहा है। अतः पुनर्क का सहयोग एक काल्पनिक आधार माना जा रहा है।

योजना की आर्थिक व्यवस्था के मसल पर ५०) पर प्रोड शिक्षक से कार्य चलाने की योजना है। ग्रामीणों को विकास कार्य के प्रति उत्साह एवं प्रेरित करना, विकास-कार्यों को माध्यम बनाकर साक्षरता में सक्षम करके कोई सरल कार्य नहीं है। यह निश्चित है कि ५० व० पर कार्य करने वालों से सक्षम की पूर्ति नहीं होगी और केवल पढ़ी-लिखी छात्रों को भेजे जाते रहेंगे जैसा अब तक का इतिहास रहा है।

प्रोड शिक्षा के शिक्षकों, प्राधिकाधिकारियों आदि की प्रशिक्षण की भी व्यवस्था योजना में है। किन्तु जिस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है वह न केवल अपर्याप्त है बल्कि एक रचनापूरी बात है। उ० प्र० में मार्गल स्कूलों में प्रशिक्षण दिया गया है। यह सर्वविधित है कि मार्गल स्कूलों के पास प्रोड शिक्षा का कोई जानकारी नहीं है। यों नहीं करने ही विषय की जानकारी नहीं है। उच्च स्तरीय प्रशिक्षण की व्यवस्था उ० प्र० में साक्षरता निदेशक समन्वय में की गयी है। वहाँ जो कुछ प्रशिक्षण मिलता है, उसकी भी जानकारी लोगों की है। उनको स्वयं से ही साक्षरता के बारे में चले चल रहे हैं यह भी भोग जानते हैं। अब प्रशिक्षण की वह स्थिति है जो योजना की प्रगति के साक्षर में अनुमान लगाया जा सकता है।

साक्षरता की संघर्षी का काम जहाँ केन्द्रीय सरकार के निर्देशावली में हो रहा है, कुछ राष्ट्रीय ऐतिहासिक-साहित्यिक अनुसंधान परिषद दिल्ली तथा कुछ प्रदेशों के राज्य सरकार केन्द्रों पर। यह बिना विषय है कि जो कुछ भी सामग्री सामने आ रही है वह परम्परागत विधियों पर आधारित है। उपलब्ध साहित्य की सही समीक्षा की जाय तो साक्षरता तब तक सामने आयेगी। इसका एक कारण यह भी है कि साक्षरता की संघर्षी के पीछे वैज्ञानिक दृष्टि एवं वैज्ञानिक चेतना नहीं है। भारतीय 'निरक्षर' को बर्दाश्त में रखकर साक्षरता तैयार किया जा रहा है। निदेशकों को यह नहीं मालूम कि भारतीय 'निरक्षर' उनसे अधिक मजबूती माना मोल सजता है उनसे अधिक बल से जाने पावों की प्रतिष्ठा करना सजता है और उसे भोक भोजन और भोक सभ्यता का सबसे बड़ा अड्डा मानता है। रूप से उपलब्ध निदेशक यह समझते हैं कि यहाँ की प्रोड शिक्षा की समस्या मुख्यतः 'विश्व को साक्षर बनाने' है न कि साक्षरता को आधार बनाने की। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि कार्यक्रम पर नये विचार न दिया गया तो प्रोड शिक्षा के इतिहास की केवल पुनरावृत्ति होगी।

स्व० धीरेन्द्र मजूमदारजी अब नहीं रहे

स्व० धीरेन्द्र मजूमदार के कितना बड़ा था पीता मे अवसान कृष्ण द्वारा निरूपित स्थितप्रज्ञ की परिभाषा को समझता था । एक उन्मुख निर्भीक चिंतक और विचारक बनता, पावा, कर्मका एकक, अद्वय आतिशायी कलम और हुदास दोनों के एक साथ बनी, यह है शरीर में यह महान् व्यक्तित्व जो २१ मई, १९७५ को ७७ वर्ष की अवस्था में हमने सर्वे के लिये भौतिक रूप से अस्त हो गया । किन्तु उनके विचार उनके अद्वय प्रवचनों द्वारा अवश्य लोगों को प्रेरणा दे चुके हैं । उनकी पुस्तकें 'समग्र ग्राम सेवा की ओर' 'नयी तालीम' और उनके अनेक लेख आज भी प्रेरणा के स्रोत हैं ।

१९२० मे अलहबाद आन्दोलन मे बागो हिन्दू विश्वविद्यालय के इन्विजिनिंग के द्वितीय वर्ष के छात्र के रूप में उन्होंने अपना आत्मिक जीवन प्रारम्भ किया और आचार्य जे० बी० कुपासानी के साथ रचनात्मक कार्यों में लग गए । १९२४ मे उनके द्वारा स्थापित रबोवा आश्रम, १९४६ मे स्थापित सेवानुरी, १९५२ मे स्थापित छात्रीघर (नू गैर) उनकी साधना एवं तपस्या के जीवित स्तम्भ हैं । १९४५ मे अखिल भारत स्तर पर के सम्मेलन तथा १९५२ में सर्वे सेवा सच के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने देश का रचनात्मक कार्यों में नेतृत्व किया ।

१० वर्ष की अवस्था में उन्होंने सहायक कार्यों में श्रमा के लिये और घर की सहाय में गाँव-गाँव घूमे और आति की दीप-दिल्ला प्रभावित रही ।

नयी तालीम तथा सहोदय परिवार उनके विषय में अत्यन्त प्रवीण और विवेक है । पूर्य विनोबाजी के एषों में '११० धीरेन्द्र मजूमदार करते थे' काति की नहीं जाती हो जाती है, काति की इसी अनिवार्यता के पक्ष में वे अपनी मतिम लोगों से भी आह्वान देते रहे । हम ऐसे महान् व्यक्ति के प्रति असीम आदरमय अर्पित करते हैं ।

पत्रिका के प्रकाशन के सम्बन्ध में

अखिल भारत नयी तालीम समिति ने 'नयी तालीम' पत्रिका अग्रिम में वाराणसी से प्रकाशित का निश्चय किया । प्रारम्भिक कठिनाइयों के कारण पत्रिका के प्रकाशन में विलम्ब हुआ है । अभी भी प्रकाशन सम्बन्धी औपचारिकताएँ पूरी नहीं हो पाई हैं । तद्विषय यह अकस्मात् पाठकों की सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं । भाषा है पत्रिका मरिच्य में नियमित रूप से प्रकाशित होती रहेगी । पत्रिका की व्यवस्था का दायित्व अब उत्तर प्रदेश नयी तालीम समिति ने लिया है । अतएव इसका वार्षिक्य सेवानुरी (वाराणसी) में था क्या है । हमें खेद है कि यह अकस्मात् अन्तरात से सूची बाह्य की सेवा में प्रस्तुत हो रहा है । अन्तिम में इसका प्रकाशन नियमित हो, इसका हम पूरा ध्यान रखेंगे ।

सुद्र विषयेषु ज्ञानशक्ति न क्षपयेत्

चिन्तोषा

वाचनार्था जो कई चर्चाएँ एनी ऐनी ? जो गमो-गम विचार के आद्वय नहीं होती। ये नांव करते हैं कि कई विषय ऐसे हैं जिसका विषय हम करता पाहिण। मरे विषय में उनको निगलत है कि मैं आलोचना करता हूँ तो सोम्य भाषा में नहीं तो परतल ही नहीं। मेरे विषय में यह निगलत नहीं है। जब बहुत अक्षरत हमो है तभी मैं किसी की आलोचना करता हूँ और वह जो तटस्थ दायों में। मोक्षता आधीन के बारे में मैंने ऐसी ही आलोचना की थी। दश। और जो ज्ञान भावे, जिस पर जिस या तो सोम्य आलोचना की या नहीं ही की। यह मेरी कमजोरी भी हो सकती है या फिर तात्पर्य।

मेरी व्यक्तिगत बात छोड़ दोस्त। अहिंसा और नैतिक आलोचना का एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि समाचारमय चिन्तन नहीं करता। दावा का उच्चारण और ज्ञानी पत्रों नहीं करनी चाहिए ऐसा नैतिक आंदोलन माननेवाले मानते हैं। जहाँ जो मुग है उसे ग्रहण कर मना पाहिण। जहाँ गुणों का ग्रहण मानने दिया होय लगभग हो जाने हैं। जब लोग बेचने हैं और उह बट देने हैं तो वे बट जाते हैं। विपरीत इतर, जब दीव नहीं देखते, तो फिर गुणों के अतिरेक मुद्रय न अंतर प्रयोजन कर हम उतना बान पकड़ कर उतना दीव दूर कर पाते हैं। दोनों के अतिरेक किसी के अंदर प्रवेश करना नहिण है। मैं दीवार के माग में पना में क्यों प्रवेश करूँ, जब कि दरवाजे और बिजड़ियों से प्रवेश मेरे लिए खुला हुआ है।

कार्यकर्ता नहीं समझते कि यह एक बहुत बड़ा नैतिक आंदोलन हमने खड़ा दिया है। यह छोटी-छोटी बातों से सगम नहीं। हम उसे छोटे आंदोलनों में बट कर अपनी शक्ति धीरे धीरे खो रही करनी है। अगर सिवायक और तकलीफें हाती रहें और उहें सजावर दूर करनी जाय तो सरकार की पकड़ मजबूत होती जायेगी। और जिसकी अच्छी सरकार होती, हमारा बान उतना ही बहिण होगा। बारहों तम वाद्यन मुक्त समाज कैसे बनेगा ? आप सरकार के पक्ष में हैं और सभी समुष्ट हैं। मजबूर के राज्य की विस्तार हमारे सामने है। यह बहुत अच्छी सरकार थी। फिर भी सक्त भाषा और सब जो सक्त आन्वासा है ऐसा मानना पड़ता।

तो हमें छोटे छोटे मतलबों पर अपना ध्यान अतिरिक्त दिया और शक्ति नहीं लगायी पाहिण। यह बान करनेवाले तो बहुत से भोग हैं। तुमसीदासजी ने भी कहा है रामायण के कि बांधे की तो बहुत हैं पर छुड़नेवाला सिक राम ही है। इसका मतलब यह नहीं कि हमें सेवा नहीं करनी चाहिए। सेवा अवश्य करनी चाहिए, ऐसी सेवा बिनाम पात्रिण कोश (चक्रवर्तम सानत) जाग्रत होती जाये। ऐसा हो कि आपकी पास से ही हम आपको सतम करना चाहते हैं।

महाभारत की घटना है। महाभारत युधिष्ठिर भीष्म के पास पहुँच प्रणाम करने किया। भीष्म कुछ हुए।

किर भीष्म के पूछा गया कि वितामहकी भाषणी मुगु किस प्रकार होनी चाहिए कर पाहिण। इस प्रकार किसी भी महाकाय में नहीं जाया। भीष्म वितामह ने यत्ना दिया कि बिना तब जरूरी प्युग होगी। इस तरह हिंसक सभाई में भी न होने वाली अहिंसक रवैया अपनाया। फिर हम तो अहिंसक आंदोलन ही छूट हुए हैं। तब हिंसक रवैये की ओर क्यों जायें ? हमें अपने निरोधियों और सहयोगियों के अंदर प्रवेश कर उहें पूछना चाहिए कि तरीका क्या हो सकता है। इस प्रकार हम सफल होंगे इसमें मुक्त तनिक भी संदेह नहीं। मैं इसी बात की दृष्टि से रख कर नेताओं और बट बट लोगों के साथ करता हूँ जो मुझसे मिश्रते हैं। यह मेरी दृष्टि है, जो मैंने आपसे सामने रख दी। मैं नहीं जानता कि इसका आप लोगों का क्या क्या समझ न होगा। फिर भी संतुष्टि नहीं है यही मेरा दृष्टिकोण है। हमें छोटी छोटी बातों से बट कर अपनी शक्ति नहीं खानी है। वस मैं इस बारे में इतना ही कह कह सकता हूँ। यह भी ठीक, जब कि कार्यकर्ता बार बार मुझसे पूछते हैं।

प्रौढ़-शिक्षा पर गांधीजी के विचार

[१९४२ के प्रवा में प्रौढ़ शिक्षा समिति की बैठक हुई थी, उसमें प्रौढ़ शिक्षा के संबंध में बापूजी ने कुछ प्रश्नों पर हुआ था। वह नीचे दिया जा रहा है, जिसमें प्रौढ़ शिक्षा पर बापू के विचार पाठकों को साम्मुख हो सकें। वर्षों की मुक्त बरतें हुए बापूजी बोल]

“भाषने प्रश्नों का जवाब देने से पहले मैं प्रौढ़-शिक्षण के बारे में अपने विचार भाषने सामने रख दूँ। मैं प्रौढ़ शिक्षा के बारे में विचार करता ही रहता हूँ। मुझे करना ही चाहिए। आज भी मैं सोच रहा हूँ। मेरे दिमाग बहुत सक्रिय भीज है। मैंने उल्टे पेट से प्रश्न करने के लिए सुझावों को स्वागत किया है। मैंने यह भी दृष्टि रखी है कि सेवाधर्म नहीं है। मैंने मित्र मित्र सराए हैं, उनके विचारों और वाक्यों को अगर इस दृष्टि से देखें तो प्रश्नों को रोजाने के काम में शिक्षा में तो मुझे यह प्रिय लगता है। मैं जब इस काम को इस दृष्टि से देखता हूँ, तो पाता हूँ कि इसमें हम प्रौढ़-शिक्षण का सीधा सम्बन्ध है। यही तो प्रौढ़ शिक्षण है। मैंने सर्वोच्च में प्रौढ़ शिक्षण की व्याख्या की है—एकदम एंग्लो-इंडियन इन एंग्लो-इंडियन फार लाइफ, यानी प्रौढ़ शिक्षा जीवन भर के लिए नहीं, जीवन के लिए है, और दूसरे यह कि वह अक्षरज्ञान देने के लिए नहीं है। जब हम इस दृष्टि से प्रौढ़-शिक्षण पर विचार करते हैं, तो यह सब चीजों को घेर लेती है। अगर आज मैं खाली होता, तो इसीसे लेकर बैठ जाता। मैं आज का उद्योग भूख का, अगर-जान भूख का, उस इस पर खड़ा हूँ कि काले को मैंने विचारना था। मैं राष्ट्रीय तो नहीं भूत गया हूँ लेकिन एक बार मदन के प्लेब की मेहमात्री ऐसी आई थी कि सारा सदन सतप हो गया था। फिर सदन में भाग नहीं थी। (यह श्राव नहीं थी, ईश्वर की मेहरबानी थी, नहीं तो आज सदन का तोपनिधान भी नहीं रहता।) जिस तरह वह रोग

मदन से निकला गया, वैसे ही ग्राहमों से भी। जब जोहानिस्म ने निजाला गया, तो मैंने खुद भी उसमें हाथ बटाया था। लेकिन कितनी सज्जन से, बिलाली हुई से, कितने धर्म से, बिलाली लोगों से यह गिटाया गया कि फिर नहीं नहीं आया। हमारे पास में यह हुआ जाता है तो लोग कहते हैं कि देखी का बोध है। इस तरह की मर्यादा प्रौढ़ शिक्षा का काम है।

प्रश्न क्या बात में प्रौढ़ शिक्षा के लिए कोई अलग कार्यकर्ता होना चाहिए या समस्त धर्मसेवक ही प्रौढ़ शिक्षा का काम भी करेंगे? प्रौढ़ शिक्षा का कार्यकर्ता पूरा समस्त देनेवाला होगा या नहीं?

उत्तर इस प्रश्न के दो प्रकार के उत्तर हो सकते हैं। जो कार्यकर्ता समस्त धर्मसेवक की दृष्टि से पास में जाता है और प्रौढ़ शिक्षा नहीं जानता, यह धर्मसेवक नहीं है। प्रौढ़ शिक्षा को अगर सब सम्पादनात्मक से कि प्रौढ़ शिक्षा का अर्थ व्यापक है, वह धर्म सेवकों को घेर लेती है तो कोई सामी नहीं रह जाती। वह किसी धर्म भावों का काम नहीं है। अगर एक भावों जाता है, तो बड़ी दूसरे का काम नहीं रह जाता। मैं तो आदर्श बना देना चाहता हूँ। आदर्श को पहुँचाने का प्रयत्न करें। दरमस्त देना जाने तो जहाँ शिक्षण के लिये एक साधन आदमी है, वहाँ दूसरे आदमी का स्थान नहीं है। जब उन साधन आदमी नहीं मिलता, तो तब जो मिले उसी को लेवें। अच्छा प्रौढ़ शिक्षण जब हमारे हाथों में आ जायगा, तो वह धर्मसेवक भी होगा। अपनी सामग्री यह कार्यकर्ता मुद तैयार करेगा। यह अच्छा आदमी नहीं होगा, जो कड़वा मुद तैयार लेवक चाहिए। उसे तो प्रौढ़ विचार नहीं

वहूँगा। प्रोढ-शिक्षण देनेवाला तो जादूगर होगा। वह तो अपनी जादू की साठी से सब कुछ पैदा करेगा। यह कहेंगे मुझे आपसे एव थोड़ी नहीं चाहिए। उस चिन्ता समय देना है यह वह जान लेगा। प्रोढ-शिक्षण जो भी कुछ करता है प्रोढ-शिक्षा या ही नाम है। उसने किए दूसरा नाम रह ही नहीं जाता।

प्रोढ-शिक्षा के कार्यकर्ता को तैयार करने के लिए कितना समय लगाना चाहिये और उसकी शिक्षा का क्या रूप हो?

इसमें आप से कहूँ कि हाथ के मारपट होने वाले चोरे उद्योग किसाने हैं, चोरी भी खेती, थोड़ा सामान्य ज्ञान देना है, तो आपको सतोष नहीं होगा चाहिए। लेकिन मुझे आपसे यह पूछना चाहिए कि ट्रेनिंग का कारण क्या है। एषो पहले तो जो ट्रेनिंग लेने आया है, उसकी योग्यता आपको जाननी चाहिए। मैं उससे पहले तो यह जान सूना कि जिसका से लया है या नज़ाक लगाने आया है। और जब उसे आया ही रहा, तो जो ज्ञान उसे आज तक मिला है वह उसको भूलकर ही मेरे पास आया। और उसने प्रति मेरा यह जवाब होगा कि उसे बुद्धि का ध्यायाम भिन्न नुका है अब खरीद का ध्यायाम चाहिए। उस बुद्धि का उपयोग भी करूँगा, लेकिन विरुद्ध दिशा में। मैं उनके हाथ के चरखा रंगना और नहूँगा कि दुष्टों से जितना निवारण सको निवारण। और उस चरखे के मारपट ही उसे देहाली बनाऊँगा। दूसरी ओर मेरे पास एक निरक्षर देहाली आता है। यह उत्साह है, चरखा चलाता है, उसे मैं दूसरी तरह का काम दूँगा। जो भी मेरे पास आये, और जिस किसी प्रकार के होवे, उन्हें ले लूँगा। लेकिन यदि किसी को देखकर देहाली के मन में यह भाव नहीं होगा चाहिए कि वह किसका देहा है और मैं कितना नीचा हूँ। क्योंकि देहाली के दिल में तो एक प्रकार की बाह्यनिक शायना का

बई है कि मैं छोटा हूँ, यह बड़ा है। इसलिए मेरी पहली शिक्षा यही होगी कि तुम दोनों एक हो। एव के पास एक ज्ञान है और दूसरे के पास दूसरा ज्ञान है, इसलिए दोनों को मिलाकर चलाना है। और जिस दिन पी-एच० डी० सोव लेगा कि अगर वह देहाली न रहा तो शहर मिट जायगा, उसी दिन सहरो का भन्त समझो। मैंने आपसे ध्यावहारिक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। मैं जो दृष्टि देना चाहता हूँ।

प्रश्न विन्नु कार्यकर्ता की शिक्षा की अवधि क्या हो?

उत्तर कोई भी अवधि नहीं है, निरवधि है। मैं आपको मालूम है मैं मुझे कि उसे कहीं तक सिखाएँ। जब सब वह स्वावलम्बी नहीं बनता, उसे सिखाना है और समझाना है कि शिक्षा पूरी नहीं हुई। वह हमारे पास पड़ा रहेगा। उसने बित्त को अगर हमसे नहीं बीठा है तो हमारी भूल होगी। मेरा क्या ही यह है। मैं अनुभव से आपको यह बताता हूँ। मेरे पास तो आदमी निरक्षर तैयार होता है। कोई जीवन भर भी रहता है, कोई बी दिन में बना जाता है। अनुभव से, विचार से मैं इस नीति पर आया हूँ कि कुछ अवधि में मार्ग। कोई आये तो भले, नहीं आये तो भले। जिसको लें, हम साफ साफ कहें कि अवधि में हम नहीं मानते। जो सच्चा है, स्वच्छता से, शुद्धता से, सबई से काम करता है, पूरा समय देता है, उसका अज्ञान दिन प्रति दिन घटता रहता है। जो सब तैयार हो जाए तब यह अपने आप रह सकता है। मेरी सरफ में बनाने वाला होके, तो कहूँगा कि कार्यकर्ता जब तक स्वावलम्बी नहीं होता, तब तक रहे, फिर उसे भले ही एक्कीस वर्ष रहता पड़े। जगत की तो हमें आदित्य मार्ग बताया है। हम इस्तावैट (दिवालिवा) तो हमेशा ही हैं। लेकिन एव बार बीज अच्छा जब गया, तो आदित्य वेद जरूर निकलेगा। यह हमारा आदर्श रहे। और जैसे

उसने आना रयेने कि वह सवाई से चले, बंसी सवाई होने भी रहती है।

प्रश्न : स्वायत्तता का सारा अर्थ क्या है ? जो प्रौढ़ बाने को और अपने परिवार को बाँट या उससे अधिक घटे व्यय करने पाता है, उसके लिए स्वायत्तता का रूप क्या होगा ?

उत्तर : वह आठ घंटे काम तो करना है, लेकिन परिवार का प्रतिपालन करता है, वह वहना विनम्र है। हम ज्ञान की दृष्टि से देखें, तो जानेंगे कि वह स्वायत्त भी नहीं है, विचारों है। मजदूरी में जो खुद है, जो जान है, जो सतोष है, जो वह नहीं जानता। मजदूरी उसकी गुलाबी की मिथानी है। मजदूर भूमिपर हो, उसमें जान हो, उसमें सतोष हो, सभी वह आजादी का मिथान बनाता है।

प्रश्न : क्या शिक्षा मुख्य वेला है, उनकी शिक्षा का साम्य भी बताई-बुनाई होगा ? और तब सेती के दिनों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे समय कहा पावेंगे ?

उत्तर : तुम्हारा मतलब यह है, न कि जो आदमी आठ घंटे सेती की मजदूरी करता है वह क्या रहेगा, बताई-बुनाई के लिए समय कैसे निकालेगा ? लेकिन ध्यान में यह रहना है कि जो आठ घंटे मजदूरी करता है, वह बौद्धिक शिक्षा सेने के लिये लागा रहता है। वह मेरा अनुभव है। मैं दाल्टन शर्म में काम करता था। पहले पहले मीद जाती थी। लेकिन मीद के बाद कुछ करने के लिये लागा हो जाता था। सच्चा आदमी तो अवसर जागता है वह तक काम करता है। और शिक्षण लिये सेती का धंधा मुख्य कहते हो, वह उसका मुख्य धंधा नहीं, मुख्य बुतलभी है। वह सेने के साथ बल बन जाता है। सेने के साथ एक टुकड़ा मूखी रोटी खाकर सेने में चल देता है। मधुसूदन दास की बात जानते हो न ? जब उसने देखा कि देहाती मीद बल के पीछे बल हो रहे हैं,

वही जानवर भी रहते हैं, वही आदमी भी रहते हैं, उनमें कोई अविधान नहीं है, तब उसने समझा कि सिर्फ, सेती सेती से हमारा मुक्त बड़ा नहीं हो सकता। मुख्य धंधा सेती होने से अगर मुक्त बड़ा होगा, तो हिन्दुस्तान को बहुत ऊँचा होगा चाहिए। लेकिन बंसा नहीं है। सभी जेते हरेक काम में ईश्वर को देवता है, प्रौढ़-शिक्षा का कार्यकर्ता भी बंसे ही देवता है। किसान को वह शिक्षाएँ बल सेने रखना है आदि। उसे उसके हाथों की शक्ति का विकास करना है, उसके मस्तिष्क की शक्ति का विकास करना है। जो सिर्फ, मस्तिष्क का विकास करता है वह सतान है। आज जो प्रौढ़-शिक्षण है, वह तो मिथान है ही नहीं। मैं पहले बस्तुकारी गिराऊंगा। उसे सीस सेने के बाद अक्षरज्ञान होगा।

प्रौढ़-शिक्षण की उत्पत्ति में बताता हूँ। मैं एक दिन भी आयत्तायकम् से बाहर कर रहा था। उपर से एक बूझ बना जा रहा था, साथ में बल भी था। मैंने भी आयत्तायकम् से बाहर, ७ से १४ की छत्र तक काव शिक्षाने वाले हैं, लेकिन उस बूझ को भी शिक्षा है। बूझ में तो सो करके बड़ी बुझ। यही प्रौढ़-शिक्षा बुझ हुई। मैंने उससे पूछा, बूझ, पूछा पूछता है, उसका बतौला क्या मातृ है ? अगर उस बूझ को मैं हूँ हूँ, तो वह प्रौढ़-शिक्षा न होती। उसे तो समझाना है कि इसका क्या अर्थ होता है। वह कोई बड़ा कार्यकर्म नहीं, लेकिन यही प्रौढ़-शिक्षा है।

कमेटी ने जो प्रौढ़-शिक्षण की व्याख्या देवदर की थी, उसमें दोषहर की बैठक में पाथीजी ने घोड़ा सा सुधार किया... यह शिक्षा जीवन के लिए और जीवन मरने लिए है। आज का मंड्रिफुटेड शिक्षण निषय सेता है उसने भी नाम में नहीं जाता। लेकिन हमारे यहाँ जो कुछ शिक्षाएँ, वह शिक्षा यहाँ से जाते समय यही नहीं रहेगी। प्रौढ़-शिक्षा एक भी चीज ऐसी नहीं देता है जो नाम की नहीं है। उसे जो सिखाना है वह घर-घर

जानकर सिखाएगा। ७ से १४ वर्ष की बुनियादी तालीम के लिए भी यही है। अच्छा घर पर जो काम करता है, वह करता उसके लिए स्वराज्य भी बूझी है, बुद्धि के विकास का साधन है। दूधवा रोब घर जायगा तो या बाप पूछेंगे कि माय हमारे लिए क्या जाए ? प्रौढ़ शिक्षण में तो हमें ऐसा शिक्षण मिलने वाला है, जो जीवन भर के लिए है। प्रौढ़ शिक्षण में आत्मस्य का स्थान नहीं।

इसके बाद जब गांधीजी ने साधने कमेटी का वह निमग्न ग्रामों कि मनी रचनात्मक संस्थाएँ किसी न किसी से प्रौढ़ शिक्षण का काम करती हैं और उसमें मदद है तो उन्होंने कहा सब संस्थाएँ मदद तो करती हैं। लखित पपा शिक्षाही है। वह शिक्षा है ऐसा मेरे जैसा आदमी तो नहीं बहूना। मैं तो बहूना कि इन संस्थाओं की विधि प्रवृत्तिवा जो पड़े मिलानी हैं, वे पड़े हो शिक्षा में लाहू हैं। प्रौढ़ शिक्षा का नाम है इस पक्षों में प्राण डालना। आज यदि हम समझें कि हम अपने इन नामों से प्रौढ़ शिक्षा में मदद है, तो प्रौढ़ शिक्षा को मार दिना समझिए। कादो का काम गांधीजी

सब और परछा सब दोनों जबह पसता है। लेकिन गांधीजी सब के काम को ऐसा ध्यावरन बनाता है कि चर्चा सब भी कहने लगे कि हमारे काम को गांधीजी सब द्वारा प्रोत्साहन मिलता है। इसी तरह तेज पानी भी शिक्षा का वाहन है। वह शिक्षा का वाहन बनकर ही गांधीजी सब के सामने आती है। लेकिन अगर आज हम कहे कि दूसरी संस्थाएँ भी प्रौढ़ शिक्षण का काम करती हैं, तो गांधीजी सब का काम बंद कर देना पड़ेगा। यह प्रौढ़ शिक्षा को विचित्रता है। इसका संग्रह मर्यादित नहीं बल्कि व्यापक है। कानरा, प्लेग आदि नाशक शक्तिमा भी शिक्षा के अन्त में पोषक (निपेटिब) बन जाती हैं। आज हम जो काम कर रहे हैं, कदा तो है, शिक्षा ही है लेकिन बड़े व और पर। उसका विचार नहीं है तालीम से करना है। प्रौढ़ शिक्षण तो जीवन कला सिखाने की बात है जीवन कला सीख गये तो मनुष्य बन गये। उससे शिक्षण कर सकते हैं। इसे कल्पना का ही विचार समझो। बलवान को कोई नहीं पहुँचा है। सब में पहुँचूँ या नहीं कैसे यह एकदा है, और हमने भी कैसे आशा रख सकता है।

मद कर सकते हैं। यानी हमारी चाहिए कि जो कमिया है उनकी हम दूर करें।

ग्रीक शिक्षा में भाव लोग व, स, य पढ़ाना शुरू करते हैं। सवाने लोगों को दिन में समय नहीं है, इसलिए हम रात में ऊह बताते हैं। यह हमारे योग। और हमारी पक्ष साक्षरता की जारी रखते हैं अथवा हुआ क्षेत्र। इस प्रक्रिया के लिये पुस्तकें भी जाती हैं। और फिर बरबादी होती है।

चाहिए यह कि हम सवानों के जीवन की पूर्ति करें। यह तभी होगा जब हम स्वयं अपने जीवन में हिंसा करेंगे। हिंसा के का मतलब यह नहीं है कि सवाना यदि भाठ पटा खस करता है, तो हम भी उसने बाव भाठ पटा पम करें, सारा समय उसके साथ सवायें। हम चाहिए कि उसने व्यवसाय में काम लेते हुए उसके जीवन में जो कमिया है उनकी शिक्षा दें।

देहात के लोग अपने हाथों से काफी परिश्रम करते हैं। और फिर हमके बाद उनकी आँखें भी दिन भर मज्जि की दुनियाँ में डूबती हैं। मनएव बाँवों का भी काफी अभ्यास बनाये रख होता रहता है। उनकी अवचेन्द्रिय को अचेतावत जतना अभ्यास करते हैं और गहरी निद्रता। तो हमारी चाहिए कि उनकी जो इन्द्रिया काँधी परिश्रम करती हैं उन्हें फिर न भ्रम दें, बल्कि उन इन्द्रियों से ही उनके विकास में काम लें जो अचेतावत काम में नहीं आती। मेरे नहने का मतलब यह हुआ कि पढ़ने सिखाने की अपेक्षा सफाई की अवचेन्द्रिय हाथ ही काम करने पर अधिक ध्यान देना चाहिए। गहर के भाग ज्यादा पड़ सके हैं, इसलिए जहाँ सराव हो जाती है। गहर से मास सराव और देहात में काम खराब।

क्या पत्रिका काम यह भी एक सवाल है। हम उसे बहुत कुछ समझ इन की बात सोचते हैं। यह सब नामुमकिन है। जैसे कि उसे विज्ञान सिखाना है या यह समझ नहीं हो सकता। उसे साक्षर करना है तो सरलता

और सुयमता पर भी ध्यान देना चाहिए। मैं लिपि सिखाने का एक तरीका बनाया है, जिससे दो महीनों में कोई पढ़ना सिखाना जान सकता है। यह प्रयोग मैंने जेल में किया था। वह सब लोग तो उस वक्रे में खम्मा तक अपना काम समाप्त कर लेते थे, किन्तु रसोदवा लोग ३ बजे प्रातः तक वक्रे खल तक काम करत थे। दोपहर को भोजन के बाद ऊन्हें कुछ ऐसा समय मिलता था, जब हम ऊन्हें कुछ मिलता करत थे। मैं यह प्रयोग करने ऊवर गया। क्योंकि वे हलुन थे। महीने के महीने में ऊन्हें पढ़ना भी गया।

तो मेरे नहने का अर्थिप्राय यह है कि लिपि में भी सुयमता के दृष्टिकोण से सुधार चाहिए। ग्रीक शिक्षा में साक्षरता तो होती थी चाहिए किन्तु पढ़ने-लिखने पर उनका और न दीजिए। ग्रीक को केवल जबरान देने से ज्यादा लाभ न होय। बलएव धर्म के माध्यम से जितना प्रदान करने का भी खयाल रखना चाहिए। ग्रीक-शिक्षण के लिए तात्कालिक आवश्यकताओं पर तथा अपनी व्यवहारिक बुद्धि के प्रयोग से भी काम लेना चाहिए। जेल में एक बार बहुत सक्रियता बढ गई थी। मैंने ऐसे समय में मज्जरदानी को मज्जीबानी बना दिया और उसके भीतर बैठकर काम करना शुरू दिया। इससे एक दृष्टि भी लोगों को मिली।

एक विशेष बात पर अवश्य ध्यान रखिए। यह पत्र कि भाव का शाव भाव ही दीजिए, जिस शाव प्रभाव को भाव करती समझते हैं वही भाव दीजिए।

हमने भाव लोगों का ध्यान मुख्यतः बार भावों पर बाँट दिया है। एक तो यह कि हमारी ग्रीक-शिक्षा का उद्देश्य यह रहे कि वह शिक्षा पूर्ण शिक्षा हो। दूसरा यह कि शिक्षा प्रदान करनेवाले लोग लोगों के दैनिक कामों में हिंसा सेज हुए अपना काम करें। तीसरा यह कि थोड़ी ही पढ़ाई पर ध्यान दें और उस पर ज्यादा जोर न दें। और चौथी बात यह कि जो बात भाव बतायें भाव की ही समझा हो।

विद्यार्थियों के लिए डिग्री नौकरी के लिए केवल एक पात्रगोटे है। अधिकांशतः तथा माता पिता की भी शिक्षा तथा डिग्री के प्रति यही प्रवृत्ति है। विद्यार्थियों और अध्यापकों में इसमें कुछ अन्तर भी होने बिना उससे स्थिति की सामान्य तहकीर में कोई फर्क नहीं पड़ता।

ऐसी सही तहकीर के अन्तर्गत न बुनियादी ढंग का कोई वैश्विक सुधार सम्भव नहीं है जब तक कि (१) या तो शिक्षा का प्रसारण कर दी जाय या (२) शिक्षा नौकरी से अलग-थलग कर दी जाय अर्थात् डिग्री और नौकरी में कोई सम्बन्ध न रहे। रोजगार देने वाले सरकारी अथवा गैर सरकारी, अपने काम छपा की जरूरत की देखते हुए अपनी परीक्षाएँ स्वयं संचालित करें। सेवा में होने के पक्षपात के अपने वहाँ काम करने वाली को अपने आवश्यकतानुसार सेवागत शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था को करें। शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में ऐसा बुनियादी परिवर्तन एकदम यही किया जा सकता। यह एक सम्बन्धी प्रक्रिया होगी जिसे विद्यालय और रोजगार देने वालों को पारस्परिक मान के लिए, पारस्परिक सहयोग से अथवा क्रिया-प्रति-क्रिया करना चाहिए।

डिग्री को प्राप्त करने या विचार ऐसा क्या या अनिवार्य नहीं है। वर्तमान स्थिति में यह अत्यन्त सम्भव है। डिग्री का विरूप क्या होगा? केवल एक प्रमाण-पत्र जिसमें यह लिखा होगा कि कोई विद्यार्थी जितने वर्ष कालेज में रहा है, जितने पढ़े वह कक्षाओं में उपस्थित रहा है और जितने घंटे उसने पढ़ाये, कक्षागत, कार्यालय और मैत्री आदि में पाए शिक्षा है तथा जिन विषयों में उसकी रुचि रही है। यह उसकी अपनी रोजगार देने वाले का काम होगा कि वह विद्यार्थी की रुचि और योग्यता का सुनान करे। यदि किसी विद्यार्थी ने जितनी काम-पढ़ने में लगने की योजना बनाई है, तो विश्वविद्यालय और अन्य सम्भव ज्ञानार्जन के साधन जैसे वर्कशॉप, कार्यालय, फार्म आदि उसकी सहायता इस बात के लिए करें कि उसे अपने रोजगार के लिए आवश्यक ज्ञान तथा विशेष उपकरण हो जाए।

मुझे पूरी आशा है कि इस नये वैश्विक कार्यक्रम से उन विद्यार्थियों को जो आन्दोलन में अग्रगण्य कर रहे हैं सहायता मिलेगी, और जो अपने को उच्च तम परीक्षा में बैठने के लक्ष्य बनाने के लिए अपनी नमियों को पृथक् करने तैयारी करना चाहते हैं उन विद्यार्थियों को उच्च तम परीक्षा के लिए निर्णय न अनुसार के कालेज में वापस आने में। इसका अर्थ यह है कि उन विद्यार्थियों के लिए न्यूनतम व्यवस्थापित न अतिशय के प्रतिपक्ष से छूट दी जायेगी जिनकी संख्या बिहार में कालेज और विश्व-विद्यालय के विद्यार्थियों की ८० प्रतिशत है। न केवल उपस्थिति का अर्थ एक अनिवार्य अध्यापकता होगी, प्रत्युत वे विद्यार्थियों का अवसर होगा जो स्वतंत्रता प्राप्त न बनाने पहली बार राष्ट्रीय महत्व की अवसर समझाया जा सकेगा रहे हैं और इसका बीरोचित स्वरूप कर रहे हैं। वास्तव में अधिकारियों के लिए उपस्थिति के विषय को लागू करना असम्भव होगा क्योंकि उसके सामने पूरे विद्यार्थी समाज का विरोध होगा।

विश्वविद्यालय के अधिकारियों को इसे की दृष्टि में रखना होगा कि वर्तमान आन्दोलन स्वयं में एक सचित्र शिक्षा है और जो इसमें सम्मिलित हैं वे बहुसंख्य शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। सामूहिक विचार-विमर्श तथा प्रशिक्षण-सिविर इस शिक्षा के एक अंग मात्र हैं। इसके अतिरिक्त, इस कार्यक्रम से उन्हें आज की महत्वपूर्ण समस्याओं को पहचानने में सहायता करने में सहायता मिलेगी। अशांति, युद्ध स्थिति, बेरोजगारी—ये मुद्दाइयाँ जिनसे लड़ने के लिए यह आन्दोलन है—की समस्याओं पर विचार-पत्र सामूहिक विचार-विमर्श के लिए प्रसारित किए जाएँगे।

सारी विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के लिये प्रमाण-पत्रों तैयार करनी पड़ी है जिसमें आवश्यकताओं और सहायता की सूची बनाई जा सके। जैसे ही प्रस्तावनाओं पर उत्तर प्राप्त हो जायेंगे, उनके बावें-कप तैयार कर दिया जायेगा और यह कार्यक्रम लागू कर दिया जायेगा।

हमें स्कूल को क्यों समाप्त करना है

अनुवादक—देवेन्द्रदत्त तिवारी

[इवान इलिच की प्रसिद्ध पुस्तक 'छो स्कूलिंग सोसाइटी' का अनुवाद हम 'नयी तालीम' में इस विषय पर करते हैं कि इसका इतिहास के बिना ही बोलीवारी विचारधारा से मिलने लगते हैं। यह अनुवाद सर्वाधिकार सुरक्षित है।]

अधिकांश विद्यार्थी विरोधपूर्ण रूप से जो वे चीन हैं वहन हो यह जान लेते हैं कि इन उनके लिए क्या करते हैं वे स्कूल (substance) और प्रक्रिया (process) के बीच अंतर करते हैं। एक बार जब इनके विषय में आसक्ति हो जाती है तो एक मया एक प्रस्तुत किया जाता है—जितना अधिक इलाज (treatment) होगा उतना ही अच्छा परिणाम निकालेगा, अथवा दूसरे शब्दों में, इलाज को बढ़ाने से सफलता मिलती है। इस प्रकार से विद्यार्थी को यह शिक्षा दी जाती है कि वह शिक्षण को सामाजिक समझने, देखने के आगे व के को ही शिक्षा समझ ले, शिक्षा को योग्यता समझ ले और प्रवाह-मुक्त जीवन को मौलिक अधिव्यक्ति की समझ समझने की भूल करे। इसी वजह से इन प्रकार शिक्षित की जाती है कि वह सेवा की दृष्टि से स्वयं पर रहने पर। इसी प्रकार चिंतनशील उपचार को प्रत्यक्ष स्वस्थ की देख माल, माल सेवा की सामाजिक जीवन का उन्मूलन, पुनर्निर्माण की दृष्टि को मुरदा, मरिचक तैयारी की राष्ट्रीय मुरदा और निरन्तर अनुचित प्रतिरोधिता को उत्पन्न करने माना जाता है। स्वास्थ्य, सामाजिक, जीवन सम्मान स्वस्थता और सज्जनमय प्रणाली की परिभाषा यह मानी जाती है कि वे उन सम्भावनाओं की उपलब्धि हैं, जो इन उपचारों की पूर्ति के लिए अपने को अधिष्ठित मानती हैं और इन सम्भावना का उन्मूलन इन बात पर निर्भर करता है कि अवसरानुसार स्कूलों और अन्य प्रशासनिक प्रतिस्थापन (agencies) के प्रत्यक्ष के लिए अधिष्ठित सम्भावना दिख जायें।

इन दिनों में मैं यह बताऊंगा कि मूल्यों का संस्थापन अनिवार्य रूप से शारीरिक रूप, सामाजिक व्यवस्था, तथा मनोवैज्ञानिक निष्पक्षता की ओर से जाता है—ये विषयवस्तुओं अथवा पक्ष तथा आधुनिकता के दुर्दशा के बीच पहलू हैं। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि किस प्रकार अधिष्ठान की यह प्रक्रिया उस समय सेज हो जाती है जब अधिष्ठित आधारभूतता या मान्यता मौलिक वस्तुओं की धारों में परिवर्तित की जाती है, जब स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यक्तिगत गरिबी, व्यक्तिगत हित अथवा मनोवैज्ञानिक उपचार को सेवाओं का 'इलाज' के परिणाम के रूप में परिभाषित किया जाता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरा विश्वास है कि अधिष्ठित के विषय में जो अधिकांश अनुमान हैं उसकी प्रवृत्ति मूल्यों के और अधिक संस्थापन का सम्मेलन करने की ओर है। किन्तु हमें इन स्थितियों को परिभाषित करना चाहिए जिससे विस्तृत उत्तरी स्थिति उत्पन्न हो सके। हमें ऐसी तकनीक के सम्भाव्य प्रयोग पर अनुमान करना चाहिए जिससे ऐसी सम्भावनाएं जो व्यक्तिगत, सज्जनमय एवं स्वस्थता का परिणाम हैं और ऐसे मूल्यों के विकास में सहायक हो किन पर तकनीक को का अनुमान कोई निष्कर्षण न हो। प्रशिक्षित अधिष्ठित-साधन प्रतिस्थापन के रूप में हमें अनुमान करने की आवश्यकता है।

मैं अनुमान के सम्भाव्य और आधुनिक सम्भावनाओं की परस्परस्थिति परिभाषा का व्यापक प्रदान करना चाहता हूँ जो हमारी विवेकशक्ति और हमारी भाषा से सम्भव है।

इस हेतु मैंने स्कूल को अपना उदाहरण चुना है। इसलिए मैं राज्य की (जो एक सम्पत्ती की तरह है) अथ नौकरगादी की एजेंसियों के सम्बन्ध में अवस्थाओं चर्चा हो सकती है—उपमात्मा परिचार, दल सेवा चर्चा तक नौकी मापन आदि। स्कूल की छिपी हुई अवस्थाओं के बारे में विवेचन से यह स्पष्ट होगा कि समाज की स्तुति बिहीन बनाने में सामाजिक विचार का काम होगा। जैसे एलिफैंट शीशु राजनीति, सुरक्षा घण और समाज में ऐसी समस्त प्रक्रिया से काम होता जाता। स्कूल के सम्बन्ध में मैंने बताया है।

मैं इस प्रपत्र निबन्ध में अपना विवेचन इस बात का समझने के प्रयास से प्रारम्भ करता हूँ कि किसी स्तुतिपुत्र समाज को स्तुतिबिहीन करने का क्या क्या होगा। इस प्रपत्र में यह समझना सरल है कि इस प्रक्रिया से सम्बन्ध उन पाँच विभिन्न चर्चाओं को क्यों चुन रहा हूँ जिन पर मैं आगामी अध्यायों में चर्चा करूँगा।

न केवल शिक्षा प्रत्युत स्वयं सामाजिक उत्तर भी स्कूल के रूप में रूप चुके हैं। एक ही सेवित धर्म में अमीर और गरीब दोनों को शिक्षित करने का सच मोटे तौर से बराबर है। अमेरिका के बिहो २० वर्षों के सम्बन्ध उपलब्ध और गरीब बच्चों में प्रति विद्यार्थी वार्षिक खर्च एक ही सीमा में आता है। कभी-कभी गरीबों के घर में ज्यादा बँटता है। १० वर्षों और अमीर एवं समाज उन स्तुति और असमानता पर निन्द करते हैं जो उनके जीवन की शिक्षा निर्धारित करते हैं उनकी शिक्षा-प्रतिष्ठा का निर्माण करते हैं और उनके लिए यह परिभाषित करते हैं कि क्या उचित है और क्या नहीं। इसी का परिणाम है कि गरीब और अमीर दोनों ही स्वयं अपना दान करत अनुसूचित/अनुसूचित वर्ग समझे हैं और स्वयं सीखने पर जो उनका विश्वास नहीं

है। यहाँ तक कि सामाजिक समझने की अवस्था में अधिकारियों से चला नहीं मिलता तो ये उसे अवस्था (aggression) या विद्रोह (subversion) मानते हैं। दोनों ही वर्गों की स्थापित समाज पर निर्भरता का अभाव इतना हो जाता है कि स्वतन्त्र रूप से वे प्राप्त अवस्थाओं को वे स्वेच्छ की दृष्टि से देखते हैं। आत्म नियन्त्रण और सामाजिक नियन्त्रण का बलता हुआ प्रभाव जीवन के उत्तरपूर्व की अवस्था में देखा देता है। अधिक प्रचारात्मक (typical) है। हर गणतन्त्र में वेचन शिक्षा प्रत्युत पूरे समाज को स्तुतिबिहीन करने की आवश्यकता है।

कल्याणकारी नौकरगादी समाज की भेदना पर प्रोफेसर, राजनीतिज्ञ, आर्थिक एकाधिकार का दावा रखती हैं और इस प्रकार वे समाज का मानदण्ड निर्धारित करती हैं कि क्या मूल्यवान है और क्या बाधक है। यह एक एकाधिकार की बरीबी के अनुनाकरण के रूप में है। हर छोटी छोटी अवस्था में शिक्षा की प्रति के लिए समाज की स्थापना के रूप में उत्तर मिलता है। इस बात की अनुकूलि देखी है कि गरीबों के एक नये वर्ग का गृहण हो और गरीबों की एक नयी परिभाषा बने। इस रूप पूर्व में शिक्षा के अन्तर्गत में जन सेवा और नयी मरना तथा अपने पिता द्वारा दत्तकाल जाना एक सामान्य बात थी। वेचन आत्मा की आवश्यकताएं चर्चा नामक समाज के बिम्बे रहनी थी। अब घर पर जीवन प्रारम्भ करना और समाज करना या ही गरीबों का यह समाज में विशेषाधिकार का (privilege) प्रतीक है। अमीर और मृत्यु दासों तथा अन्न देखाता करने वाला के सम्मानव अवस्था के अन्तर्गत आ गए हैं।

एक बार जहाँ बुनियादी आवश्यकताओं समाज द्वारा संज्ञात्मक रूप से उत्पादित वस्तुओं के रूप में बदल जाती हैं वही तो उन मानदण्डों से परिभाषित होती है जिसे समाज के अन्तर्गत दृष्टानुसार बदल सकते हैं। गरीबों से यह उन लोगों का अवस्था होता है जो उपलब्ध के किसी महत्वपूर्ण समय में निष्ठापित कारण से पीछे रह जाते हैं। मेरे, गरीबों के हैं बिहो तीन वर्गों की स्तुति

* एनरोम जो रजतान, ड्रिफ्ट इन एलोनेट्री एंड टैनेट्री एनरोम एनरोमिडर, सेटल बिहो एनरोम कर्मरिज १९६२ १९६८, यू० एच० ऑफिस आफ एनरोम ऑफिस ऑफ प्रोफेसर एनरोम इन्ट्रान्स यू०, १९६६,

शिक्षा नहीं मिली और न्यायों में गरीबों के हैं बिना
कारणों के भी स्त्री-शिक्षा नहीं मिली ।

गरीब समाज में सदैव अक्षरहीन रहे हैं । सत्समाज
केतमात्र पर बढ़ती हुई निर्भरता उनकी असहाय स्थिति
में एक नया पहलू जोड़ देती है—मनोवैज्ञानिक निष्पि-
यता और अपनी केतमात्र स्थिति करने की अक्षमता ।
एशिया के जैसे पड़ोसों पर जमींदारों और व्यापारियों
द्वारा निर्यातों का शोषण किया जाता है । इसके परि-
णाम एक बार जब के समाज में बंध जाते हैं तो वे
राजनीतिक क्षेत्रों पर आक्रामक हो जाते हैं और स्कूली
शिक्षा के प्रभाव में पड़ जाते हैं । नयी (moder-
nised) गरीबी परिस्थितियों के प्रति उनकी असमर्थता
के साथ उनके व्यक्तिगत पुरुषार्थ के समाज को जोड़
देती है । गरीबी का यह नया रूप विश्वव्यापी भयानक है
और वर्तमान अर्थविकास के मूल में है । यह अवश्य है
कि यह विभिन्न जगहों में अमीर और गरीब दोनों में
अभिन्नता होती है ।

यह बात की तीव्रतम अनुभूति अमरीका के लोगों
में होती है । अब वहाँ भी गरीबी का उपचार इसके
अधिक खर्च पर नहीं किया जाता । जमा कही भी
गरीबी का इलाज इतनी आधुनिकता, औषध, निर्यात
और अधिकाधिक माँगें नहीं उत्पन्न करता और अब
कही भी यह बात इतनी स्पष्ट नहीं होती कि गरीबी एक
एक बार जब गरीबी रूप धारण कर लेती है, तो केवल
गरीबों के मन पर बिस्मय जाने वाले उपचार की प्रति-
रोधिता बन जाती है तथा सत्समाज कांति की अपेक्षा
करती है । आज अमरीका में जाते हुए भी और प्रगती
प्रोत्साहन प्रभाव के ऐसे स्तर की आशावादी बन सकते
हैं, जो पीछिया पूर जिसे छोड़ा भी नहीं जा सकता था
और जो पीछी दुनिया के अधिकांश लोगों को विस्तृत
केतमात्र लपटा होगा । उदाहरण के लिए, अमरीका के
में गरीब एक गैर-निम्नोच्च अधिकांश पर वह गरीबी
कर सकते हैं कि वह उनके बच्चों को १० वर्ष के उम्र
तक स्कूल पहुँचाएँ, या एक डॉक्टर पर गरीबी कर
सकते हैं कि वह उन्हें बरताने में एक निश्चित सेवा

जिमनी बीमता साठ डॉक्टर प्रतिदिन (लगभग ५०० डॉ०)
होती छद्मता में बहुत से लोगों के तीन मास के बेतरन में
बगल में । विन्तु ऐसी देखभाल उन्हें और अधिक आश्रित
बना देती है, और उन्हीं उत्तरोत्तर इस बात के लिए
आवश्यक बना देती है कि वे अपनी जिन्दगी अपनी अनु-
भूतियों के इर्दगिर्द और अपने क्षमताओं के अनुसार अपने
समाज में समाहित पर सकें ।

अमरीका के गरीब उस दुर्दशा की बातों की अति-
शीघ्र स्थिति में हैं जो आधुनिक युग में सभी गरीबों के
लिए भयानक है कि अब एकबार इन संस्थाओं की
शोकेक्षण सीढ़ियाँ समाप्त हो यह विश्वास दिया देती
है कि उनमें जाचार नैतिक दृष्टि से आवश्यक हैं तो
गरीबों की कोई राशि बर्तमानवादी संस्थाओं की स्वभाव-
गत विनाशकता दूर नहीं कर सकती । अमरीका के
अन्यत्र के गरीब अपने अनुभवों से उस भूत को
स्पष्ट कर सकते हैं जिसपर एक रक्त-दीप्ता समाज का
सांसारिक विधान आधारित है ।

सुश्रीम कोर्ट के न्यायाधीश विविध श्री० ब्रजलाल
ने कहा था कि 'जिसी संस्था को स्थापित करने का एक
ही तरीका है, और वह है, उसके लिए मन की व्यवस्था
करना ।' इसका उपनिष्ठाव भी सत्य है । उन संस्थाओं
की जो इस समय शिक्षा और बर्तमान की व्यवस्था
करती हैं, डॉक्टर से चिकित्सा करने से ही, भागे की
यह गरीबी बनाने की प्रक्रिया रोनी जा सकती है,
जो वास्तव में संस्थाओं के बहुत करने वाले पारम्परिक-प्रभावों
का परिणाम है ।

यह बात उस समय सब में रहनी चाहिए कि जब
हम सही-सही सहायता के कार्यक्रमों का सूचीकृत करें ।
उदाहरण स्वरूप १९६३ और १९६८ के बीच २०,०००
साठ डॉक्टर ६० लाख बच्चों के अभावों की प्रतिपूर्ति
करने के लिए अमरीका के स्कूलों में खर्च किये गये
थे । कार्यक्रम 'टाइटल वन' के नाम से जाना है । ऐसा
सार्वजनिक सर्वोच्च सार्वजनिक कार्यक्रम शिक्षा के क्षेत्र में
अन्य कहीं भी नहीं कराया गया फिर भी कोई सामंजस्य
मुद्धार इन वस्तुओं के सींगों में नहीं दिखाई पड़ा ।

गण्य आय के घरो से आने वाले उनके सहपाठियों से तुलना किये जाने पर यह पता चला कि वे और पिछड़ गये हैं। इसके प्रतिदिन इस कार्यक्रम के दौरान प्रोफेसरल विरोधों ने यह पाया कि एक करोड़ ऐश बच्चे और बड़ गये हैं जो आर्थिक एवं शैक्षिक दृष्टि से वंचित हैं। प्रतीय घन की और अधिक माय करने के समर्थन में जब और अधिक कारण सुनाए हैं।

साबुद इसके कि अधिक सर्वांगीण इलाज किया गया, गरीबों की शिक्षा के सुधार की पूरा अक्षमता को हीन तरीकों से स्पष्ट किया जा सकता है।

1—१०,००० लाख डॉलर ५ लाख बच्चों की जातिविषयों (performance) को सुधारने के लिए एक मापनीय मापन में मरणांत है, या

२ एक आयोजना से लब्ध किया गया विभिन्न पाठ्यपत्रों, वेदुतर प्रशासन, गरीब बच्चों पर धन की और केंद्रित करने तथा और अधिक अनुसंधान को आवश्यकता है और इसके सफलता मिल जाएगी।

३—शैक्षिक क्षति का इलाज उस दिशा से नहीं किया जा सकता जो स्कूल में होती है।

पहली बात तो यह है। अवश्य ही सत्य है अवश्य ही सत्य है। स्कूल के बचत से 'सच' हुआ है। ऐसा सचमुच उन स्कूलों की गया जिनमें अधिकतर अनुविधायक बच्चे थे, किन्तु वह गरीब बच्चों पर ही गड़ी सच हुआ। वे बच्चे बिल्कुल लिए धन दिया गया था उन बच्चों ने धन धन माये थे जो इन स्कूलों में जा रहे थे। इस प्रकार धन का उपयोग सरसमपूर्ण देखना, प्रचार और सामाजिक भूमिका के ध्यान और साथ ही साथ शिक्षा पर धन देने हुआ। ये सभी धन ही अनिच्छित रूप में शैक्षिक उपादानों, पाठ्यपत्रों, शिक्षकों, प्रशासकों तथा इन स्कूलों के अन्य प्रमुख व्यक्तियों से और जहाँ जहाँ बचत से जुड़े हुए हैं।

अतिरिक्त धन ही स्कूलों की यह अवसर मिला कि शिक्षा अनुदान के अभाव में उन अमीर बच्चों में सतर्पण के लिए प्रयत्न करें जो इन दृष्टि से अनुविधायक से कि उन स्कूल में गरीब बच्चों के साथ पढ़ना पड़ना था।

यह भी हर हालत में सत्य हो सकता है कि धन अयोग्यतापूर्वक व्यय किया गया। किन्तु स्कूल व्यवस्था की अयोग्यता का किन्हीं अवधारण अयोग्यता की ही हार मान देती है। स्कूल अपनी संरचना (डिज़ी) के साथ ही उत्तर सुविधाएँ केंद्रित करने का विरोध करते हैं जो अन्धरा सुविधाप्रस्त हैं। विना पाठ्यपत्रों, अलग कक्षाएँ, लम्बी अवधि और अधिक भेदभाव उत्पन्न करती हैं और अधिक धन पर।

द्वितीय देने वाले प्राचीन इस बात के बाकी नहीं हैं कि वे स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यापार से २०,००० लाख डॉलर विमुक्त करने की अनुमति दें जैसा कि वे संसार के लिए कर सकते हैं। वर्तमान प्रशासन यह विश्वास कर सकता है कि वह शिक्षकों का कोष पढ़ने पर खर्चता है। मध्यमवर्गीय अमीरों के लोगों का कोई मुकाम नहीं होगा यदि यह प्रोग्राम काट दिया जाए। गरीब माया खोचत है कि उनका मुकाम होगा, किन्तु उससे भी अधिक वे इस बात की मान कर रहे हैं कि जो धन उनके बच्चों के लिए है उस पर निपटारा रखा जाए। बचत करने का एक हर सतर्पण तरीका, और आज है, नाम बढ़ाने का भी यह है कि पढ़ाई अनुदान की व्यवस्था की जाए जैसा मिलन प्रारम्भ और दूसरों ने प्रस्तावित किया है। इनसे ऐसा उस तक पहुँचना जिसकी मितना है, जिससे यह अपनी इच्छानुसार शिक्षा का अपना नाम खरीद सकता है। यदि इन प्रकार की क्रेडिट (credit) ऐसी तरीकें तथा भीतित कर दी जाय जो स्कूल की पाठ्यपत्रों में फिट बैठती है, तो उपचार की समानता की व्यवस्था अधिक हो गयेगी, किन्तु इसका सामाजिक अधिकारों की समानता में घुटि नहीं होगी।

यह स्पष्ट है कि समान धन के स्कूलों में भी एक गरीब बच्चा धन ही सभी अमीर बच्चों के स्तर पर पहुँच सके, यद्यपि वह समान स्कूलों में भी जाने हैं, और एक ही उम्र में शिक्षा प्रारम्भ करते हैं। फिर भी गरीब बच्चा की वे अवसर अधिकृत नहीं हैं। मध्यमवर्गीय बच्चा की आर्थिक रूप

से मिल जाते हैं। प साम धर पर बातचीत और पुस्तकों से लेकर छुट्टियों में यात्रा और अपने निपट में एक अनग गनुभूति तक मिलते रहते हैं और बच्चों के लिए सुखम होते हैं जो उनका स्कुल और स्कूल के बाहर दोनों ही जगह खाने-पाने लगाते हैं। अतः गरीब विद्यार्थी सामान्यतः एक एक पीछे रहेगा जब तक वह स्कूल पर अपनी प्रगति

अथवा पानाजन के लिए निग्रह करता है। गरीबों को इसलिए पैसा चाहिए कि वे कुछ चीजें लें न कि अपनी बिना अनुपात की तथाकथित बर्तिया के उपचार का का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए

कमरा

उत्तर प्रदेश और प्रौढ़ शिक्षा

हारिकप्रसाद माहेश्वरी

उत्तर प्रदेश और निरक्षरता का आकार

विगत चार दशकों से अपने देश तथा प्रदेश में निरक्षरता उन्मूलन के कारण प्रयास किये गये किन्तु उन चार दशकों के बादबुद्ध भारत में साक्षरता का प्रतिशत जो कि वर्ष १९४७ में १४ था वर्ष १९७१ तक लगभग ३४ तक ही हो पाया। वर्ष १९७१ के आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश का साक्षरता प्रतिशत लगभग १२ था जो सर करीब २४ होगा। इस प्रतिशत में पुरुषों की साक्षरता का प्रतिशत लगभग ३२ तथा महिलाओं का १० है। अगर भारत के अन्य प्रदेशों से अपने प्रदेश के साक्षरता प्रतिशत की तुलना की जाय तो ज्ञात होगा कि उत्तर प्रदेश का १२ वा स्थान है अर्थात् २२ प्रदेशों में से केवल ४ प्रदेश ऐसे हैं जो अपने प्रदेश में साक्षरता में कुछ कम हैं। इसमें यह स्पष्ट है कि साक्षरता की दृष्टि से उत्तर प्रदेश बहुत नीचे स्तर पर है। हमें इस बिना में गम्भीरता पूर्वक विचार करना है।

उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इस समय लगभग १० करोड़ होगी। इस संख्या में १५ से ४९ तक की उम्र की वर्ग में निरक्षर पुरुषों तथा स्त्रियों की जनसंख्या लगभग साठ लाख करोड़ से अधिक जाये है जिसमें करीब ४ करोड़ निरक्षरों की संख्या हो जायेगी ही है। अगर

निरक्षरों की इस पूरी संख्या में सीधे की भांति के निरक्षर शब्द वास्तविकों को और जोड़ दिया जाय तो यह समस्या करीब ६ करोड़ निरक्षरों की साक्षर बनाने के रूप में उत्तर कर सामने आती है।

राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा नीति के अनुसार अगर हम १५ से ३५ वर्ष-वर्ष के सभी पुरुषों का उच्च समूह सामने लें तो यह ज्ञात होता है कि इस वर्ग में से कुल निरक्षरों की संख्या लगभग १ करोड़ ८० लाख आती है जिसमें से करीब ७२ लाख पुरुषों की संख्या होगी और शेष लगभग १ करोड़ ८ लाख स्त्रियों की।

यह है उत्तर प्रदेश की निरक्षरता का आकार और स्वल्प जिसको ध्यान में रखते हुए हमें निरक्षरता व मूलन की योजना पर विचार करना है।

उद्देश्य

राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा नीति के अनुसार साक्षरता एवं प्रौढ़ शिक्षा दोनों के कार्यक्रम चलाने हैं तथा साक्षरता इन कार्यक्रमों का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इस नीति निर्देशक विज्ञान की ध्यान में रखते हुए प्रदेश की प्रौढ़ शिक्षा योजना के तीन उद्देश्य होंगे —

१—निर्धारित वयस समूह की साक्षर बनाना।

२—निष्कारित तथ्य समूह को ऐसी जानकारीया, बीजान और ज्ञान प्रदान कराना, जिससे कि वे अपने जिन व्यवसाय में लागे हुए हैं उसमें बेहतर बनते हुए अपने स्तर को और अच्छा बना सकें तथा सामाजिक स्तर को और उन्नत कर सकें ।

३—उनकी दक्षियों, व्यवहारों और अभिवृत्तियों में ऐसे बाह्यीय और स्वयं परिवर्तन लाना जिससे वे जागरूक और विवेकशील नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों और दायित्वों को समझ सकें, उनका निर्वाह कर सकें, समाज के उत्साह और अवसरों में भाग ले सकें तथा वर्तमान विज्ञान तथा तकनीक-प्रधान परिवर्तनशील विश्व के नागरिक के रूप में समझदारों के साथ अपनी भूमिका भरा कर सकें ।

इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रोष्ठ विज्ञान व सम्बन्धित कार्यक्रम अनिवार्य शिक्षा की उपाय व्यवस्था के अन्तर्गत प्रावीण्य होवे, जो मुद्रण पठने-लिखनेवालों की सुविधाओं, आवश्यकताओं, समस्याओं आदि पर आधारित होवे हैं तथा जिसके अन्तर्गत इन पढ़ने-लिखनेवाले पढ़ें अथवा दक्षियों की सुविधासुसार स्थान, समय व पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाती है । बहने की आवश्यकता नहीं कि वे आयोजन सम्पादन, सुसज्जित तथा व्यवस्थित हो होंगे ही, औपचारिक शिक्षा-व्यवस्था की तरह उन पर सख्तात्मक तथा व्यवस्थात्मक प्रतिक्रिया हावी नहीं होगी । संक्षेप में, पाठक अथवा प्रतिभागी, अधिकार अपनी राय दे, जहाँ पढ़ना चाहेंगे, 'कहाँ' पढ़ना चाहेंगे और 'जो' पढ़ना चाहेंगे, इन सिद्धान्त के अनुसार उनकी विज्ञान का आयोजन किया जायगा ।

हमने अभी आपके सामने १५ से ३५ वर्ष वर्ष के प्रौढ़ों के तथ्य-समूह की जो चर्चा की है, उसके सम्बन्ध में यही यह स्पष्ट कर देना भी आवश्यक है कि उनके पढ़ाने-लिखाने में यथोचित निरक्षर महिलाओं, निर्धन वर्गों, ग्रामीण तथा लहरी मरीचों, धर्मिकों, देवगीन मजदूरों, छोटे किसानों तथा निम्नियों की भी आवश्यकता ।

प्रौढ़-शिक्षा एवं साक्षरता-केन्द्र

१५ से ३५ वर्ष-वर्ग के निरक्षरों की हमने जो समस्या १ करोड़ ८० लाख तथ्य जापने सामने रखी है, उसकी

ध्यान में रखते हुए, और इन बातों को ध्यान में रखते हुए कि हमें ५ वर्ष में इन्हें साक्षर बना देना है, ८० प्रतिभागी प्रति केन्द्र के हिसाब से तो ६ लाख केन्द्रों की आवश्यकता पड़ेगी होगी है, किन्तु उत्तर प्रदेश के पर्यन्त तब तक नहीं पड़ेंगे तो ध्यान में रखते हुए लगभग ७ लाख साक्षरता-केन्द्र आवश्यक होवे, यानी १४० लाख केन्द्र प्रति वर्ष । और अगर ५ वर्ष के ध्यान पर, हम निरक्षरता-उन्मूलन की अवधि १० वर्ष मान कर चलें, तो १ करोड़ ८० लाख की संख्या के लिए ७० हजार प्रतिवर्ष केन्द्रों की आवश्यकता होगी ।

पाठ्यक्रम तथा पठन-पाठन सामग्री

जहाँ तक पाठ्यक्रम का सम्बन्ध है, प्रोष्ठ प्रतिभागीयों के लिए यह उनकी अनुभूत आवश्यकताओं, दक्षियों तथा समाज और राष्ट्र की आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित करना होगा । उस पाठ्यक्रम में पर्याप्त लचीलापन रहेगा । यह आवश्यक होगा कि विज्ञान स्तर पर जो अधिकारी, पब्लिक तथा केन्द्रों के शिक्षक हों, वे अपनी-अपनी स्थानीय समस्याओं को एकत्र कर पाठ्यक्रम में समाविष्ट करते-करते रहें । लेकिन एक सामान्य पाठ्यक्रम को विवेकपूर्ण की समिति द्वारा तैयार कराकर जिलों में सार्वजनिक हेतु भेजना आवश्यक होगा ।

इस पाठ्यक्रम का प्रमुख विषय साक्षरता और प्रौढ़-शिक्षा होगा । साक्षरता के अन्तर्गत भाषा और गणित की शिक्षा प्रदान की जायगी तथा प्रौढ़-शिक्षा के अन्तर्गत प्रतियोगिता की स्थिति दक्षियों, अनुभूत आवश्यकताओं, दैनिक समस्याओं, व्यावहारिक दक्षताओं, सामाजिक दृष्टियों, जीवनशैली परम्पराओं, अपवित्रता स्वास्थ एवं सफाई, पौष्टिक आहार, सज्जित मोचन, धिनु-पालन नर्चरी माताओं की देखभाल, पारिवारिक जीवन की गुल समृद्धि, परिवार बलान, पेंप-जन, सज्जनक रूप, नागरिक नैतिक एवं अधिकार, राष्ट्रीय विकास की योजनाओं तथा आर्थिक-साधन एवं व्यक्तित्व के सर्वांगीण और समुचित विकास आदि से सम्बन्धित ज्ञान और जानकारी प्रदान की जायगी । इस सबका उद्देश्य प्रशुद्ध यह होगा कि प्रतिभागी एक ओर तो माया में

कोशल तथा दैनिक गति की जानकारी प्राप्त कर सकें तथा झुगरी और भे खुली, समृद्ध, समृद्ध और समृद्ध जीवन व्यतीत करने के लिए अपने को समर्थ और सक्षम बना सकें। इसके अतिरिक्त, सर्वोपरि यह कि वे अपने अपने परिवार, अपने परिवेश, समाज, देश और अपनी दुनिया के सदन में एक अच्छे व्यक्ति, अच्छे भाई या बहन अच्छे पति या पत्नी, अच्छे सहयोगी और पड़ोसों तथा एक जागरूक, वैमान और विवेकशील नागरिक बन सकें और इस प्रकार अपनी समस्याओं के समाधान स्वयं ढूँढ़ते हुए न केवल अपनी जीविका के रख को उन्नत बना सकें, बल्कि जीवन के स्तर को भी उन्नत कर सकें, जिससे उनके माध्यम से समूचे समाज और राष्ट्र का समुचित विकास हो सके।

श्रीधर के लिए जिस पठन-पाठ्य सामग्री की आवश्यकता होगी, वह भी उनकी रुचियों, आवश्यकताओं तथा समस्याओं और उनके विषय पर आधारित होगी जो उनकी सांस्कृतिक उपयोगिता से सम्बंधित होंगे और उनमें पढ़ने तथा ज्ञानार्जन की रुचि भी निरंतर विकसित करते रहने।

श्रीधर शिक्षा के कार्यक्रमों के अन्तर्गत रोचक ढंग से ज्ञान प्रदान करने के लिए यह भी आवश्यक होगा कि सोलर, पार्ट, फोथ वार्ड, चित्र-बोर्डिंग, कटपुस्तिका, माट्रा कार्टाज, वादविचार प्रतियोगिताएँ, भ्रमण, शैक्षिक भ्रमण, माट्रा, प्रदर्शन आदि का प्रयोग किया जाए, जिससे जो कुछ जानकारी देय हो वह दृश्य रूप में प्रतिभाषियों के मानस के सामने रहे और वह ठोस रूप से उनके ज्ञान का अंग बन सके।

शिक्षक भ्रमण अनुदेशक

आइये हम इस पर विचार करें कि हम इस कार्य के लिए कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी। यदि हम १५ से २५ वर्ष-वर्ग के लिए १,४०,००० केन्द्र प्रति वर्ष खोलते हैं तो हर साल १,४०,००० शिक्षकों की आवश्यकता होगी और यदि २ वर्ष के स्तर पर निरक्षरता उन्मूलन की अवधि १० वर्ष मान ली जाए तो हर साल ७०,००० शिक्षक आवश्यक होंगे।

ये शिक्षा अबका अनुदेशन यथासम्भव स्थानीय होंगे, हार्ड स्कूल विन्तु बेरोजगार होंगे, अथवा न-प्राप्त अध्यापन, सेवारत अध्यापन तथा अन्य उपयुक्त स्थानीय व्यक्ति होंगे, विन्तु वरीयता प्रसिद्धित हार्ड स्कूल बेरोजगारों को दी जायेगी।

प्रशिक्षण

श्रीधर प्रोड शिक्षा का यह कार्य मानकों को दी जाने वाली शिक्षा से अनेक दिशाओं में भिन्न होगा, इसलिए इस कार्य के लिए नियुक्त शिक्षकों का पाठ्य प्रशिक्षण भी अत्यन्त आवश्यक होगा। इस प्रशिक्षण में सर्वेक्षण, जन-सम्पर्क, केन्द्रों का चयन, पठन-पाठन-सामग्री का उपयोग, प्रोड मनोविज्ञान, विभिन्न स्थानीय उपलब्ध सुविधाओं और सामग्री के पुटाने, आवश्यकतानुसार स्थानीय समस्याओं से सम्बंधित साहित्य की रचना, उपस्थिति तथा आस्था-प्रजिका करना, आवश्यक दृश्य उत्पादनों का उपयोग, प्रबोधनात्मक प्रोड-कथाओं में प्रति-क्षण-अभ्यास, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन तथा मुन-मन-दली, चेतना-बोधों के गहन भाषि की ज्ञान-कारियाँ तो सम्मिलित होगी ही, प्रोडों को पढ़ाने के लिए पचा, वास्तविक विचार विमर्श जैसी उन शिक्षण-पद्धतियों में जो प्रमुख रूप से प्रशिक्षण दिया जायगा जिनमें प्रतिभाषी सीखने की प्रक्रिया में स्वयं साक्षीदार हो, शिक्षण शिक्षा की प्रक्रिया उतनी ही है, जितनी कि स्वयं सीखने की अवधि वह प्रतिभाषी-केन्द्रित हो शिक्षक-केन्द्रित नहीं, जिससे उनमें आत्म-विश्वास की भावना उत्पन्न हो, स्वावलम्बिता का भाव आगत हो तथा निष्कर्ष उनमें लिए लोक न होकर अधिकार सिद्ध हो। प्रशिक्षण में इन प्रयोगों के अलावा प्रोडों को पढ़ाने की विधि, ध-व-मूल्यांकन तथा परीक्षण की तकनीक आदि भी सम्मिलित होगी।

शिक्षण

प्रोड-शिक्षा के इस कार्यक्रम में शिक्षक स्वतः जितना पढ़ा-लिखा सकेगा तथा अन्य जानकारी प्रदान कर सकेगा, उतना ही पर्याप्त नहीं होगा। प्रोड शिक्षा के अन्तर्गत प्रतिभाषियों के व्यावसायिक ज्ञान की बढ़ोतरी,

स्वाम्य सुधार सहचारिता, सेवी सिपाई आदि स सम्बंधित तबनीकी जानकारीसे ले लिए उसे जिले के भण्डारान्तर के सम्बंधित सिपाया के अधिकागिया और बिगपशे से भी सम्पन्न करना आवश्यक होता जिससे कि उन्हें आमंत्रित कर वह उनकी साक्षरता-वेद पर वातांकन करते, प्रदान आदि किया करते तथा मौखी पर से आकर वाप होते हुए भी दिखा सकें। इस दृष्टि से उसे एक समन्वय (कोऑर्डिनेटर) की भूमिका अदा करनी होगी।

पर्यवेक्षण, परीक्षण और मुख्य फल

साक्षरता केन्द्रों के प्रभावी संचालन के लिए उनका समय-समय पर पर्यवेक्षण भी आवश्यक होता है। जो केन्द्र प्रायः सरकार द्वारा चलाये जायेंगे उनका पर्यवेक्षण सरकारी पर्यवेक्षक करेंगे तथा जो केन्द्र स्वच्छिन्न सत्ताओं द्वारा चलाये जायेंगे उनके पर्यवेक्षण का दायित्व उही सत्ताओं पर होगा। किन्तु हमका यह साध्य नहीं होता चाहिए कि सरकारी तथा गैर सरकारी प्रयासों में कोई सहयोग न हो।

साक्षरता तथा प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रमों का मूल्यांकन भी बड़ा आवश्यक है। मूल्यांकन की यह प्रक्रिया योजना के प्राथमिक क्षेत्र अन्तर्गत तबनी होगी। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत एक क्षीर तः शिक्षक स्वयं प्रत्येक प्रतिभावी की प्रगति का ऐता-लेखा समय-समय पर ऐता रहेगा दूसरे पर्यवेक्षक समस्त प्रतिभागियों की प्रगति का साम-हित अंकन भी करता रहेगा और अन्त में उन उद्देश्यों और स्तरों के सम्म में साक्षरता केन्द्र पर दिये गये कार्यों का समग्र रूप से मूल्यांकन भी किया जायगा जिससे यह पता हो सके कि निर्धारित उद्देश्य और स्तर तक हम किस सीमा तक पहुँच रहे हैं और जहाँ तक नहीं पहुँच सके हैं उनके लिए हमारे क्या रचनायें कर मुकाबल हैं।

प्रमाण-पत्र

प्रौढ़-साक्षरता तथा प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के विभिन्न परीक्षण और मूल्यांकन के परधान सारा समग्र बड़े प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र भी दिया जायगा वास्तविक होगा किन्तु वे स्वयं उक्त विषय तथा योगों के लिए प्रस्ता

का प्रोत्त न कर सकें। जिस वषर्गों के वास्तव-मानिनाएँ, जो किसी प्रकार से औपचारिक शिक्षा से वंचित रह गये थे और जो शिक्षा की मुख्य धारा में प्रवेश पाना चाहेंगे, उनके लिए तो ऐसे प्रमाण-पत्र और भी अधिक उपादेय सिद्ध होंगे।

अनुगमन

साक्षरता तथा प्रौढ़ शिक्षा के कार्य-क्रमों के अन्तर्गत प्रतिभागियों को जो योग्यता और पान प्रदान किया जायगा उसको बनाय रखने तथा उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि और विकास की अत्यन्त आवश्यकता है। इसके लिए अनुगमन कार्य जरूरी होगा। हम कार्य के निमित्त सरल भाषा में लिखी हुई पुस्तकें एवं पत्रिकाएँ पुस्तकालय पुस्तक सेवे समर्थ, रेडियो-टेलीवीजन चर्चा मण्डल सम्पन्न बोली आदि के अयोग्य आवश्यक होंगे।

गैर-सरकारी संस्थाओं का योगदान

प्रौढ़ शिक्षा का वर्तमान कार्यक्रम एक वृद्ध कार्य-क्रम है और इसे ३ वर्ष या अधिक से अधिक १० वर्ष की अवधि में पूरा किया जाना है। स्पष्ट है कि इस तथ्य की प्राप्ति के लिए सरकारी संस्थाओं द्वारा ही नहीं हो सकती। अतएव हम कार्य के प्रदेय की गैरसरकारी संस्थाओं तथा अन्य उत्तरदायी व्यक्तिगत मध्यमों एवं प्रयासों की भी सहस्रता अपेक्षित होगी। जो भी साक्षरता एवं प्रौढ़ शिक्षा का कार्य एक ऐता विविध रूप है जिससे सदा की आवश्यकता होती है ही सरकारी तन्त्र के नियम और बाधन बाधन-रतियों की दृष्टि होतें हुए भी, प्रायः बाधक बन जाते हैं। इस बाधन-रतियों के संचालन की व्यवस्था में आवश्यकता-नुसार लक्ष्योत्पन्न होना आवश्यक होता है किन्तु सरकारी नियमों के कारण यह लक्ष्योत्पन्न प्रायः सम्भव नहीं होता। इसके अतिरिक्त इतनी विभिन्न योजनाओं के विचार-विवरण का भार प्रायः सरकार पर ही छोटा भी नहीं जा सकता, सर्वोच्च संस्थाओं तथा अन्य संचालन-सेवायें व्यवस्थाओं और व्यक्तियों द्वारा भी इस शिक्षा में योग्यता और संचालन सेवा की आवश्यकता से प्रति-होकर अपनायत पत्र-व्यवहार किया जाना होता और सभी

निरक्षरता-अमूलन के इस अगिषाव ने कुछ उल्लेखनीय उत्पत्ति हो सकती है।

बोर्ड तथा समितियों का गठन

प्रौढ-विद्या-कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए यह भी आवश्यक होगा कि एक राज्य-स्तरीय प्रौढ-विद्या बोर्ड का गठन किया जाय और साथ ही जिला-स्तरीय प्रौढ-विद्या-समितियों का तथा तथा न्यून समितियों का, गांव और बाई समितियों का, तथा बड़े बड़े व्यावसायिक संस्थानों की प्रौढ विद्या समितियों का भी गठन किया जाय।

सुदृढ़-प्राप्ति

इस प्रकार, यदि प्रवेश में प्रौढ-साक्षरता एवं प्रौढ-विद्या के कार्यक्रमों का मसत स्तरों पर पूरे मनोयोग के साथ विधिवत् रूप से कार्यान्वयन किया जाय तो, भाषा है कि १३-२५ वर्ष-वर्ष की प्रौढ महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत २०-३२ तक पहुँच सकता है, और प्रौढ पुरुषों की साक्षरता का प्रतिशत तो ५ वर्ष में लगभग दस-प्रतिशत सम्भव हो सकता है। बढ़ने की आवश्यकता नहीं कि यह उपलब्धि सर्वथा उल्लेखनीय होगी।

समाजोपयोगी उत्पादक कार्य के द्वारा शिक्षण

बैजू भाई, मंत्री, अखिल भारत नयी तालीम समिति

इस वर्षीय स्कूल पाठ्यक्रम पर गठित की ईश्वर भाई एटेल समिति तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में राष्ट्रीय पुनरीक्षण समिति (जिसमें अल्पश आ० आत्मक एम० आदि-विद्यार्थी हैं) ने स्पष्ट रूप से समाजोपयोगी उत्पादन कार्य की स्कूल की शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षा का आवश्यकता स्पष्ट स्वीकार किया है। उन्होंने सर्व-ग्राह्य कहा है कि बीकाने की प्रविष्ट समाजोपयोगी उत्पादन का है वे माध्यम से विकसित की जानी चाहिए।

ईश्वर भाई एटेल समिति ने इस विचार की व्याख्या करने का प्रयास किया है तथा आ० आदि-विद्यार्थी समिति ने अपनी पूर्ण सहमति व्यक्त की है। व्याख्या इस प्रकार है :— समाजोपयोगी उत्पादन कार्य से अभिप्रेत है कि वह प्रमाण के लिए सोद्देश्य, सार्वक, ऐसा हाथ का कार्य हो जिसने किसी वस्तु का समाजोपयोगी उत्पादन बनना सेवा-कार्य द्वारा हो सके। सोद्देश्य उत्पादक कार्य तथा सेवा-कार्य का समाज की आवश्यकता से अनुसृत होना तथा शिक्षार्थी के लिए सार्वक होनी। ऐसा कार्य

संभव नहीं किया जाना चाहिए। नियोजन, निरूपण तथा श्रमिक स्तर पर विस्तृत पूर्वतैयारी आवश्यक है जिससे वह भूकृत वैधिक हो। जहाँ भी सम्भव हो, उपलब्ध विकसित बीकाने तथा ग्रामों का तथा माधुनिक तकनीकी का उपयोग, उपनीत पर आधारित विरासतीय समाज की आवश्यकताओं का ध्यान कराने में सहायक सिद्ध होगा।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने आगामी वर्ष से अपने से संबंधित स्कूलों में समाजोपयोगी, उत्पादक कार्य को अनिवार्य कर दिया है। परिषद् ने १ से ६ जुलाई १९७० को स्कूलों के लिए समाजोपयोगी, उत्पादक कार्य पर आधारित पाठ्यक्रम हेतु निर्देशिका तैयार करने के लिए एक कार्यशाळा का आयोजन किया है। राष्ट्रीय वैधिक शोध तथा प्रशिक्षण परिषद् ने भी १५ से २२ जुलाई तक समाजोपयोगी, उत्पादक कार्य का पाठ्यक्रम तैयार करने हेतु एक कार्यशाळा आयोजित की है। प्रस्तावित कार्य-प्राप्ति से इन कार्य के प्रति सासन के उद्देश्य की

सम्भीरता परिलक्षित होती है। मैं इस कदम का हृदय से स्वागत करता हूँ।

ऐसे सभी लोगों को जिन्हें हमारे देश की सही स्त्रुल की शिक्षा को समझित करने और विकसित करने में अभिरुचि है, समाजोपयोगी उत्पादक कार्य पर आधारित उपयुक्त पाठ्यक्रम विकसित करने पर सम्भीरतापूर्वक विचार करना होगा। दुर्भाग्य से देश में किसी भी विश्व-विद्यालय में, स्नातकोत्तर स्तर पर पाठ्यक्रम विकास की एक स्वतन्त्र विषय के रूप में सम्भीरतापूर्वक स्थापित करने का प्रयास नहीं हुआ है। ईश्वर माई समिति तथा आदिदेशिया समिति द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम के मार्गदर्शक प्रारूप भी इस दिशा में हमारा मार्गदर्शन नहीं कर पाते हैं। अखिल भारत नवी छात्रीय समिति सेवाग्राम ने हान में हो 'कार्योन्मुख विद्यालयों तथा महाविद्यालयों की स्वरूपना' नाम की एक पुस्तिका प्रकाशित की है। इस पुस्तिका में कार्य के द्वारा शिक्षा के दिशा निर्देश के साथ ही इस विचार पर आधारित पाठ्यक्रम का संस्था भी प्रस्तुत किया गया है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद तथा राष्ट्रीय धर्मिक और तथा प्रतिभाल परिषद द्वारा आयोजित कार्य-पालाओं में उपयुक्त राष्ट्रीय शिक्षा समितियों द्वारा प्रस्तुत शिक्षा निर्देशों का भरपूर उपयोग किया जायगा और ये प्रस्ताव अपना पाठ्यक्रम भी संवार करेंगे।

इस समय जब कि राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्यक्रम की योजना बनाने तथा ईश्वर माई समिति द्वारा संवार निर्देशों के आधार पर समाजोपयोगी उत्पादक कार्य की सभी संवार करने का काम प्रारम्भ किया जा रहा है, इस अवस्था में अन्तर्निहित वैश्विक पहलुओं पर विचार करना उपयोगी होगा। उदाहरणार्थ, क्या हम वर्तमान

औद्योगिक धर्मिक कार्य के अन्तर्गत समाजोपयोगी उत्पादक कार्य को परिलक्ष्यता करते हैं? वर्तमान में औद्योगिक शिक्षा का स्वरूप क्या है—अ इसमें ज्ञान और सूचनाओं पर आधारित पाठ्यपुस्तकों से विषय-वस्तु सी जाती है।

आ—सीखने की प्रक्रिया के समय सभी विद्यार्थियों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है।

इ—आवाहन का मूल्यांकन मुख्यतः अंत में परीक्षा के रूप में होता है।

क्या हम मानते हैं कि समाजोपयोगी उत्पादक कार्य भी एक अलग विषय है, जैसा कि कार्य-अनुक्रम के सम्बन्ध में किया गया था। या हम समाजोपयोगी उत्पादक कार्य की शिक्षा का माध्यम स्वीकार करें तो पाठ्यक्रम का स्वरूप कार्यपरक शिक्षा का होगा। कार्यपरक शिक्षा क्या है? कार्य से शिक्षा कैसे प्राप्त होगी? सामुदायिक कार्य शिक्षा का भाष्यन कैसे बनेगा? कैसे ज्ञान, कुशलता तथा अभिरुचि का सम्बन्ध किया जायगा? शिक्षा यानि यह कोर्स सीन क्यों में (मिडिल और हाई स्कूल) अग्रगण्य पाठ्यक्रम का जड़ बनाया जा सकता है?

एक दूसरा महत्वपूर्ण प्रकरण भी है। क्या हम सामाजिक कार्यों को समाजोपयोगी उत्पादक कार्य से भिन्न मानेंगे? अच्छा नहीं? उदाहरण के लिए क्या बचन योजना कार्यक्रम को समाजोपयोगी उत्पादक कार्य की सूची में जोड़ेंगे? ईश्वर माई पटेल समिति ने इसकी परिस्थिति देते समय सीरी-अम पर बल दिया है। क्या हम इसे स्वीकार करते हैं? ये और अन्य अनेक मुद्दे, क्या संवदन, शिक्षण-प्रशिक्षण, शिक्षक-पुनर्वर्गीकरण के सम्बन्ध में विचार करना होगा और उसके अनुरूप ही स्कूल का काम बनाना होगा।



राष्ट्रीय प्रौढ़-शिक्षा-कार्यक्रम - एक रूपरेखा

शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, १९७८

इस लेख का उद्देश्य प्रौढ़ शिक्षा पर भारत सरकार द्वारा किए गये नीति बलवत्तम को कार्यक्रम में परिणत करने की दृष्टि से क्रियात्मक विवरण की रूपरेखा प्रस्तुत करना है। किन्तु प्रभाव यह नहीं है कि कार्यक्रम के लिए जनघर और अपरिवर्तनीय मार्ग-दृष्टिक रेखाएँ निर्धारित की जाएँ। प्रस्तुत उद्देश्य यह है कि विभिन्न विषयों की ओर की जाए। इसको दोहराना आवश्यक है कि उद्देश्य यह है कि १५-३५ आयु वर्ग के लगभग १००० लाख निरक्षरों के लिए ऐसे प्रौढ़-शिक्षा के कार्यक्रम जिनमें साक्षरता एक लक्ष्यार्थ बन हो, इस दृष्टि से व्यवहारित किए जाएँ जिनसे लगे स्वमेरित हानाई के कोशल प्राप्त हो सकें और वे अपने और अपने आतापरण के विकास में आत्म-निर्भर और सक्रिय भूमिका भूषा कर सकें। सक्षमतामय और कार्य नीति का विवरण प्रौढ़-शिक्षा के नीति बलवत्तम में दिया गया है और उसे इस लेख के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

कार्यक्रम के स्तरीयता

राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा-कार्यक्रम का बुनारम्भ २ अक्तूबर, १९७८ को होगा। सभी व्यावहारिक दृष्टियों से अब से लेकर मार्च, १९७९ तक की अवधि समय तैयारी की अवधि होगी। तैयारी का काम निम्नलिखित चीजों में होगा।

(१) सर्वप्रथम लगभग ५ लाख के स्तर पर १९७८-७९ में कम से कम १५ लाख तक ले जाने के लिए कार्यक्रम में डीठ कदम उठाना।

(२) रा. प्रौ. शिक्षा का अनुमान चलाने के लिए उपरिक्त आशय बनाना।

(३) निम्नलिखित महत्वपूर्ण अनुभवों के आधार पर कुछ विशेष अध्ययन तैयार करना, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में निम्नलिखित अनुभवों को ध्यान में रखते हुए प्रभाव रा. प्रौ. शिक्षा-कार्यक्रम के नियोजन और निष्पादन पर पड़ेगा।

(४) कार्यक्रम के विभिन्न अंगों में विस्तृत नियोजन हेतु विशेषज्ञ टोलियों की नियुक्ति। इसमें प्रत्येक राज्य और युनियन टैरीटरी के लिए विस्तृत योजनाओं की तैयार करना भी सम्मिलित होगा।

(५) प्रशासन एवं सम-वय के लिए तथा कार्य-प्रणालियों तथा उनके रूपों में आवश्यक सुधार करने के लिए आवश्यक ढाँचे की स्थापना करना।

(६) सरकारी और अर्ध-सरकारी विभिन्न अधिकारियों को, जो कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे, चुनना और उनका वांछित स्तर का सहयोग प्राप्त हो के लिए आवश्यक कदम उठाना।

(७) वांछित योग्यताओं को, विशेषकर साक्षरता एवं पढ़ाई में, स्पष्ट करने के लिए आवश्यक प्रयत्न करना। ये योग्यताएँ सभी क्षेत्रीय कार्यक्रमों का अंग होंगी।

(८) राश्यों के विविधतायुक्त एवं आवश्यकता पर आधारित विवरण। अधिपम सामग्री तैयार करने की समता का विकास करना, साथ ही कार्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए उन्हें उचित सामग्री उपलब्ध करना।

(९) प्रशिक्षण-विधियों का विकास करना, प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए संयुक्त तैयार करना तथा विभिन्न स्तरों पर कार्यक्षेत्रों की प्रशिक्षण देना।

(१०) मूल्यांकन तथा मानिटरींग एवं आवश्यक प्रायोगिक अध्ययन के लिए सुव्यवस्था व्यवस्था करना।

तैयारी का काम १९७८-७९ के अंत तक पूरा नहीं हो पाएगा। रा. प्रौ. शिक्षा के प्रारम्भ करने के बाद कम से कम एक वर्ष तक लगभग उन सब विमुक्तों पर कार्य करना होगा जिनका उत्तेजित उपर किया गया है। वास्तव में एक वर्ष में तैयारी का काम को सहायता सहायता पर

साधारित होगा, परन्तु वे भी राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत रहेंगे।

पूर्ववर्ती वर्ष की उपलब्धियों के स्तर के आधार पर वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे। तैयारी के कामों में समय की अनुमानित उपलब्धता भी सम्मिलित होगी। कार्यक्रम की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि प्रथम दो वर्षों में किन्तु प्रकार कार्य प्रारम्भ किया जाता है और इस प्रयास इस बात के लिए किया जाएगा कि १९८३-८४ से अन्त तक १५-१५ आयु वर्ग की पूरी जन संख्या साक्षर हो सके। लक्ष्यों का वितरित प्रयोग इस प्रकार है —

वर्ष	वार्षिक लक्ष्य लाख में	सुचारित लक्ष्य लाख में
१९८३-८४	१५	१५
(तैयारी का वर्ष)		
१९८४-८५	४.५	६.०
१९८५-८६	६.०	१५.०
१९८६-८७	१८.०	३३.०
१९८७-८८	१२.०	२५.०
१९८८-८९	३६.०	१००.०

यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि ये प्रस्तावी लक्ष्य हैं, और वास्तविक सफलता के कार्यक्रम गठित करने पर भी की जा सकती है और इस बात की ध्यान में रखकर कार्यक्रम को गठित करना होगा।

उद्देश्य यह है कि १९८३-८४ तक १५० लाख लोगों के लिए प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों को गठित करने की समर्थता का निर्माण हो जाए। इस लक्ष्य वास्तविक होता है कि कार्यक्रमों में विविधता लाई जाए—उद्देश्य यह भी होता है कि एक ऐसे साक्षर जन के लिए उचित समान की स्थापना की जाए जिसमें आजीवन शिक्षा जीवन का एक अनिवार्य अंग बन जाए।

अनुकूल वातावरण बनाना

एकसेपरेट बर्थ निरंतरता प्रोग्राम के परिणाम तथा लक्ष्यों के अनुसंधान, जहाँ निरंतरता दूर करने के कार्यक्रमों की सफलतापूर्वक विमानित किया गया है यह बताते हैं कि हमने बड़े कार्यक्रम को चलाने के लिए एक अनुकूल

वातावरण बनाने के लिए व्यवस्थित प्रयास अवश्य किया जाना चाहिए। कदाचित् और को छोड़कर किसी अन्य देश के सामने साक्षरता की समस्या इस पैमाने की नहीं रही जैसी हमारे सामने है। साथ ही साथ ही कोई ऐसा देश हो जहाँ जागरूकता और ज्ञान के प्रति इतना आसक्ति हो जितना हमारे देश में है। वास्तव में रा प्रौद्योगिकी का मैंने हम सभी लोगों को प्रेरित करने की आवश्यकता यह है कि उनमें आसक्ति और निरंतरता की भावना उत्पन्न की जाए। प्रशासनिक तथा शिक्षण दोनों में यह योग्यता की है कि प्रौद्योगिकी को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जायगी। समय में समयमय सभी राजनीतिक दलों के नेताओं में कार्यक्रम का पूर्ण हृदय से स्वागत किया है और समर्थन का आवश्यक दिशा है। यह आकांक्षी जा रही है कि जीवन के अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले नेता भी जैसे डॉक्टर, शिक्षक, व्यापार और उद्योग विधायी तथा नवप्रवृत्त—इस समर्थन का अनुसरण करेंगे। इस सर्वमं में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मूल्यांकन किस्मों, टी बी, रेडियो, समाचार-पत्र, प्रचार-पोस्टर इत्यादि के द्वारा किया की जा सकती है। इसके लिए कुशल एवं समन्वित प्रयास की आवश्यकता होगी जिसमें सरकारी और निरसरकारी माध्यम एकजुट होकर कार्यक्रम के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए काम करेंगे। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विधियों—विचार सम्मेलनों एवं विचार-भेंटियों का आयोजन, स्कूलों और कॉलेजों में विषय-साक्षरता-दिवस चलाना आदि का भी आशय दिया जा सकता है। उन विभिन्न विधियों का, जिनके द्वारा एक वातावरण बनाया जा सकता है, विचारपूर्वक अध्ययन करना होगा और सहायक उसके अनुकूल आवश्यक कदम उठाने होंगे।

दृष्टिकोण

जबसे देश के सामने बरीबी और निरंतरता की द्वि-बादी समस्याएँ हैं। इनमें से एक बहुत बड़ी आबादी की अभाव और उपोपनि की स्थिति में लोगों के लिए विचार करती है और दूसरी विकास के दरवाजों को खोलने में बाधा पहुँचाती है और बरीबी में अपनी स्थिति पर काम

पाने की योग्यता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है ।
 वस्तु में घरीबी और निश्चरता एक ही विषय समझा
 के दो पहलू हैं और बिना एक के समाधान से लिए
 तत्काल सफल बनाना दूसरे या समाधान निबानने
 से लिए सफल करना निश्चय ही हम पर-पुत्र करेगा
 और निराशा का कारण होगा । इस कारण रा प्रौद्योगिकी
 का भी सामाजिक आर्थिक विकास की प्रक्रिया से उच्च
 बुनियादी परिवर्तन लाने के साधन के रूप में सीधे ।
 चाहिए—बुनियादी परिवर्तन उस स्थिति में जिसमें गरीब
 विकास कार्यों के बिना प्रतिकूल टाक व रूप में सब
 रहते हैं । इन्हें बिना स सौकर विचार कार्यों के वे द
 में सक्रिय भागीदारी के रूप में जाना है । सीधे की
 प्रक्रिया में स सारता पर धन है कि तु इतना ही पर्याप्त
 नहीं है इससे इस बात का महत्व पर भी धन है जिससे
 गरीबी और निश्चरता की नाम क्षमता का उत्तम हो
 और वह अपनी दुर्गा की अधिकधिक क्षमता हो ।

परम्परा के अनुसार सीमित तथा व्यापक दृष्टिकोण में
 भेद माना जाता है । कार्यक्रम को गुणात्मकता तथा
 व्यापकता पर महत्व आधारित है । रा.प्रौ. वि.का.
 एक ऐसा व्यापक कार्यक्रम है जिसमें एक सीमित कार्यक्रम
 के नियोजन और विभाजन का कुछ भी सम्मिलित है ।
 वास्तव में सीधे बातों की आवश्यकताओं से कार्यक्रम
 को समझकर हुए रा.प्रौ. वि.का. परम्परागत सीमित
 दृष्टिकोण से अधिक लाभ सह जाता है । साथ ही यह
 मानकर चलना होगा कि इतने बड़े पैमाने का काम अभी
 ही सफल है जब रा.प्रौ. वि.का. की जन भागीदारी के
 रूप में इसका भाव ।

प्रौद्योगिकी नियोजन में आवश्यक प्रश्नों में से एक
 सीधे बातों के माध्यम से सम्मिलित है । यद्यपि प्रारम्भ
 में प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों में आप लगे से लिए उत्पत्ति
 का सार है । यदि उनकी कार्यक्रमों में बिना बहुत दिनों
 तक नहीं रह जाती और वे कार्यक्रम से खस हो जाते हैं ।
 महिलाओं तथा अनशुचित जातियों एवं जन जातियों के
 रूप में यह समस्या विशेष रूप से सम्बन्धी है । यह सब है
 कि यदि कार्यक्रम में सफलतापूर्वक सम्पन्न एवं विषय वस्तु
 तथा विधियों की सीधे बातों की समस्याओं तथा जनसत

भाव-योजनाओं से सम्बद्धता है तो सीधे बातों के निरंतर
 सहयोग से हेतु पूर्वाभ्यासों की पूर्ति हो जाएगी । इसके
 अतिरिक्त जनसत अभ्यस के सगठन से लिए अनुसूच
 बातावरण की रचना भी प्रभावी प्रत्युः का सीधे हो
 सकती है । यह सब फिर भी सदाविरत प्रयास न हो । अतः
 इस विषय पर और विस्तार से सोचने की आवश्यकता है ।

एक समय में ही प्रौद्योगिकी के कार्यक्रम से
 सशक्ति गिशा की व्यवस्था से सशक्त एक बड़ी प्रौद्योगिकी
 की समस्या हल नहीं हो जाएगी । अतः माओवाद शिक्षा
 का परिपक्व और उच्च अनुसूच प्र प्रारम्भ प्राविधान को
 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कार्यक्रम का नियोजन एवं सशक्ति
 उपारी वरत समय दृष्टि में रखना होगा । इस दृष्टि से
 रा. प्रौ. वि. का. पाठ सत्रों के बा. समाप्त नहीं हो
 जायगा । अतः रा. प्रौ. वि. का. के प्रारम्भ से
 ही व्यवस्थित अनुसूचणायक व.प्रक्रम चलाने होंगे ।
 इसके अत्यंत प्रत्युः के व्यापक उत्पादन तथा प्रसार
 और सबाव की प्रक्रिया में सत्ताधारी की सम्मिलित विद्या
 जाएगी । प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों की विकासप्रयत्न कार्यों के
 साथ साथ चलाना बाधनीय होगा ।

यह महत्वपूर्ण है कि प्रौद्योगिकी या रोजगार को ऐसी
 नियोजन कार्यनीति में सम्मिलित रूप से सम्मिलित किया जाए
 जो सधन शोषण निवोजन और रोजगारी मुक्त विकास
 कार्यों द्वारा गरीबी को दूर करने पर धन है ।

प्रत्येक राज्य विभिन्न अधिकरणों को सीधे बातों की
 तुलनात्मक प्राथमिकता को निश्चित करेगा । सीधे तौर से
 यह सकेत किया जा सकता है कि स्थानीय स्तर के साधारण
 नियोजन की आवश्यकताओं कारण स्वैच्छिक अधिकरणों
 का प्राथमिकता दी जानी चाहिए । स्वैच्छिक अधिकरणों
 के अतिरिक्त कार्यक्रम को कार्यक्रम में परिणत करने
 के लिए स. अधिकरणों को भी निश्चित करना होगा ।
 इनमें नेहरू युवक सेवा निवृत्ति विद्यालय विभिन्न प्रकार की
 रोजगार देने वाली संस्थाएं आदि सम्मिलित हैं । सरकार
 का कार्य इन विभिन्न अधिकरणों में सतत रूप से स्थापित
 करना और व्यवधानों को दूर करना होगा । सेवा के प्रत्युः
 से सत्ता में सरकार को सतत परी निम्नकारी छेनी
 पड़ती । यहाँ भी ऐसा करना आवश्यक हो नहीं प्रारम्भ में

कुछ चुने हुए जनपद और चुने हुए जनपद के कुछ कार्यपत्र विकास सड़ लिये जायेंगे। उद्देश्य यह होगा कि प्रयास को एक सुपरिभाषित क्षेत्र में केन्द्रित किया जाए और तब कार्यक्रम का प्रसार किया जाए।

प्रचलित में विभिन्न अभिवर्धन अपने ऐसे कार्यक्रम बनाएंगे जो उन्हें अत्यन्त आवश्यकता सम्बद्ध और व्यावहारिक प्रतीत होंगे। सभी दशाओं में, यह समझ लेना आवश्यक है कि कार्यक्रम नीति व्यवस्था की रूपरेखा को बदलने के लिए लिये जायेंगे। अव्योक्ति होने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों की दियाएँ निम्नलिखित होंगी —

- विविध अनुसरण के साथ साक्षरता।
- परम्परागत कार्यपरक साक्षरता।
- किसी प्रमुख विकास कार्य क्रम में सहायक कार्यपरक साक्षरता।
- सामाजिक एवं कृषिगत क्षेत्रों की साक्षरता।
- गरीबों को संगठित करने और उन्हें पैतृगोत्र एवं बाणकक करने के लिए साक्षरता।

संसाधनों का विकास

नीति-व्यवस्था में जो सहायक-व्यवस्था स्थिति स्पष्ट की गई है उसका मर्म १० प्रो. वि० का० के लिए एक सहायक आधार की बगला और उसका विकास करना है। सहायक-आधार में बहुविध और आवश्यकता पर आधारित सामग्री की तैयारी सम्मिलित होगी चाहिए जिससे विभिन्न स्तर के कार्यकर्ता सक्षम की सहायता से अपनी बुद्धि बढ़ाकर सकें और कार्यक्रम की गतिशीलता प्रदान करने के लिए मूलभूत एवं दोष की व्यवस्था का समावेश किया जा सके। राष्ट्रीय स्तर पर प्रोड-लिवा-निष्ठानत तथा केन्द्रीय सरकार के विभिन्न अधिकरण एवं स्वैच्छिक अधिकरण राष्ट्रीय सहायक ग्रुप के रूप में कार्य करेंगे। सहायक विकास में महत्वपूर्ण स्थान राज्य सहायक केन्द्र (राजको) का है जो, राष्ट्रीय सहायक-ग्रुप के सहयोग में और वार्य क्षेत्र से निरंतर सम्पर्क रखते हुए सहायक-विकास का केन्द्र स्थल बन सकता है। राजको का एक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि वे सहायक-आधार का

जनपद या प्रोजेक्ट स्तर पर विकेंद्रित करा सकें। वे वस्तु सहायकों से अवलोकन स्तर नाम नहीं करेंगे, प्राप्त ऐसी विभिन्न सहायकों और व्यक्तियों को जो सहायक-विकास में योगदान कर सकते हैं, सहजुबत करने में उद्देश्य से सम्बन्धितक प्रतिक्रिया करा करेंगे। राजको की उपयोगिता उनके द्वारा विकसित प्रोड-लिवा तथा प्राविधिक क्षमताओं पर निर्भर करेगी तथा इस बात पर भी निर्भर करेगी कि उसमें अपने सेवित क्षेत्रों में सहायकों तथा व्यक्तियों के सहायकों में सम्बन्ध स्थापित करने की वित्तीय क्षमता है और कितना समय उनमें सम्पत्ति राज्य सरकारों से मिला है। जो कुछ भी हो, कार्यक्रम के लिए सहायकों का सम्बन्ध मुख्यतः जनपद, प्रोजेक्ट स्तर का शायित्व है। सहायक विकास का साथ अत्यन्त महत्वपूर्ण होने के कारण केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों तथा अन्य अधिकरणों द्वारा सहज हो सभी आवश्यक भाषिक तथा प्रशासकीय समर्थन उपलब्ध कराया जाना चाहिये।

सहायक विकास के कार्य में जनता का सक्रिय सहयोग सब विवरण लोगों का सहयोग जिनके लिए यह कार्यक्रम मुख्यतः बनाया जाएगा, सहायक प्रचार की विवक्षनीयता के लिए भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यही बात नीति-व्यवस्था को सरलता में निहित है और उसमें स्पष्ट भी की गई है। इस प्रकार के सहयोग के लिए विविध उपाय करने होंगे। इनमें कुछ निम्नलिखित हैं :—

- सीखने वालों की आवश्यकताओं को समझने के लिए सुनियोजित सर्वेक्षण।
- प्रोड-लिवा सीखने वालों की सहज प्रतिनिधित्व प्राप्तकर विविधों तथा सामग्री की वारतविक जांच एवं परीक्षण।
- ऐसे स्थानों पर जहाँ राज्य जनपद सहायक केन्द्र पर काम करने वाले कार्यकर्ता प्रायोगिक के साथ सोचते हैं और काम करते हैं, बहुधा सम्मेलनों और दिवसों का आयोजन करना।
- सक्रिय प्रायोगिक मध्यमकों का पता लगाना और उन्हें कार्यक्रम की ओर उन्मुख करना जिससे उनके सम्पर्क से प्रोड-लिवा सीखने वालों की व्यवस्था और सम्बन्ध समस्याएँ सामने आती रहें।

—ऐसे व्यक्ति को का व्यवस्थित सहयोग को प्रामोक्ष्य के साथ रहते हैं और भाग करते हैं ।

पोर्टलैंड सीमेंट के सहयोग के अतिरिक्त यह आवश्यक है कि सहायन देश चाहे राज्य स्तर स्तर का हो या जनपद स्तर का, अपने काम में सहयोग और उसकी समीक्षा निरीक्षणों तथा प्रौढ शिक्षा के शिक्षकों से भी प्राप्त करें । इसको व्यवस्थित ढंग से स्थापित करने के लिए बिना प्रस्ताव में फंसे, समुचित प्रयत्न करना होगा । आवश्यक बात स्मरण रखने की यह है कि रा० प्रौ० वि० का० सीमेंट के शोधन की आवश्यकताओं से वृत्तीय रूप के सम्पर्क ही, और इसके लिए यह आवश्यक है कि विशेषज्ञों तथा प्रशासकों और सीमेंट के वास्तविकीय सम्पर्क स्थापित किया जाए ।

सहायन के विभिन्न अंग निम्नलिखित हो सकते हैं —

शिक्षण छात्राज्य छात्राग्री

इस सम्बन्ध में प्रारम्भिक कार्य सीमेंट वालों की आवश्यकताओं का पता लगाना होगा । विद्युत पाठ्यक्रम जिसमें अथवा दाती का साथ साथ प्रत्यापित अधिगम परिणामों का भी प्रवेश होगा, सुनिश्चित सीतन की आवश्यकताओं के आधार पर निश्चित करना होगा । साधारण परीक्षा के परीक्षा, पाठ्यक्रम के आधार पर, शिक्षण सहायक सामग्री तथा सीमेंट की सामग्री बड़ी मात्रा में हो तैयार करनी होगी । नीति वक्तव्य में सीतन की भाषा में सहायता की प्रस्ताव प्रदान करने का प्रयत्न किया गया है । इस बात को बिना भयानक सीमा तक ले जाते हुए, यह समझ होगा कि सीमेंट की प्रक्रिया की आवश्यकता की भाषा में व्यवस्थित किया जाए और वहाँ आवश्यक हो सीमेंट के लिए ऐसे केन्द्र बनाए जाएँ जिससे वे सीमेंट भाषा में समझा प्राप्त कर सकें । अतिरिक्त यह राज्य सहायन के द्वितीय या तृतीय शालिक भाषाओं, बोलियों में सामग्री तैयार करने की आवश्यकता का पता पड़ेगा कि जनपद प्राथमिक स्तर पर भी सामग्री तैयार की जा सके ।

प्रशिक्षण

शिक्षण वर्गों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी होगी, वे निम्नलिखित हैं

—राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के मुख्य कार्यकर्ता ।

—विशेष संज्ञा जैसे पाठ्यक्रम रचना, शिक्षण ज्ञानार्जन-सामग्री को तैयार करना, प्रशिक्षण, मूल्यांकन इत्यादि के लिए प्रोफेशनल एवं विशेषज्ञ ।

—जिला प्रोफेसर तथा विकास सहायक स्तर के कार्यकर्ता ।

—क्षेत्रीय निरीक्षक ।

—प्रौढ शिक्षा केन्द्र के शिक्षक ।

प्रौढ शिक्षा का विदेशासय, यूनेस्को तथा राज्य राष्ट्रीय अधिकारियों की सहायता से विधियों तथा प्रशिक्षण का अनुभव तैयार कर रहा है । राष्ट्रीय, राज्य तथा जनपद स्तर के मुख्य कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है । राज्य सहायन-केन्द्रों की प्रोफेसर तथा अन्तर्गत स्तर के कार्यकर्ताओं एवं निरीक्षकों के प्रशिक्षण का समन्वय करना चाहिए तथा प्रौढ शिक्षा-केन्द्रों के शिक्षकों के प्रशिक्षण के कार्यक्रम की जिम्मेदारी क्षेत्रीय स्तर पर कार्यक्रम के नियन्त्रण के लिए निर्दिष्ट अधिकारियों की होनी चाहिए । प्रशिक्षण की भाषा, एकाधिक तथा आवश्यक प्रशिक्षण पर तुलनात्मक बल, प्रशिक्षण विधियों इत्यादि सम्बन्ध में विभिन्न विद्यार्थी सोचने होंगे । जब तक अनिवार्य न हो, तब तक नयी प्रशिक्षण संस्थाएँ न सोचो जाएँ । वर्तमान प्रशिक्षण संस्थाओं की रा० प्रौ० वि० का० में खोए हुए विभिन्न वर्गों के कार्यकर्ताओं की प्रशिक्षित करने की क्षमता का विनाश करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए । इस सन्दर्भ में विदेश-विद्यालय तथा अन्य उच्चशिक्षा भी संस्थाएँ महत्वपूर्ण योगदान कर सकती हैं । सामान्यतः जो अधिकार प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदार हैं उन्हें ऐसी विभिन्न संस्थाओं तथा व्यक्तियों से, जो सहायक प्रशिक्षण कार्यकर्ता के संपन्न में सहयोग दे सकते हैं सहायता प्राप्त करने की दृष्टि से सम्पर्ककर्ता के रूप में काम करना चाहिए ।

मानिटरिंग, मूल्यांकन तथा अपडाइड रिसर्च

अन मिश्र के कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से बहुतों की एच एच एनएल सूचनाओं की आवश्यकता रहती है। इस चरण में व्यवस्थित मानिटरिंग तथा मूल्यांकन के महत्व को कम नहीं किया जा सकता। इनमें पूरे कार्यक्रम में प्रभाव करना चाहिए और समय समय पर आवश्यक कार्यक्रम में सहोपन करने को दृष्टि से वे पुष्टीपूर्ण हो सकते हैं। अनपडाइड, अपडाइड तथा समन्वित कोषकार्य की व्यवस्था भी महत्वपूर्ण है जिससे रा. प्रौ० वि० का० के अनुभवों से व्यवस्थित रूप से विश्लेषण हो सके और मध्यम के लिए मार्ग निर्देशन मिल सके। के०ड को तथा राज्य की सरकारों को व्यवस्थित मानिटरिंग में स्थायी रूप से रहनी है। विश्वविद्यालय तथा उच्चशिक्षा की सरकारों और उनके को मूल्यांकन तथा अपडाइड कोषकार्य में महत्वपूर्ण भूमिका भरा करनी होगी। मानिटरिंग तथा मूल्यांकन-तक व्यवस्था तथा प्रोजेक्ट स्तर पर भी गठित होने चाहिए क्योंकि मुख्यतः वहाँ पर कार्यक्रम में सहोपन के हेतु पुष्ट-विवरण का प्रयोग किया जाएगा।

'सिद्धान्त'-अन्वितकरण

भीति वक्तव्य में उन विभिन्न अधिकारियों का उल्लेख है जिसका प्रयोग शिक्षण व्यवस्था में किया जाएगा और जो रा० प्रौ० वि० का० में सरकार के साथ जिम्मेदारी बाँटने में मिलान की जिम्मेदारी देने में प्रभावी बात उन समन्वित स्थितियों की उपपन्नता होगी चाहिए जिनमें कार्यक्रम गठित करने में सहस्रमूलक पद्धति की और कार्यक्रम के प्रति आस्था एवं प्रतिबद्धता का भाव हो। विभिन्न प्रकार के लोग जिन्हें शिक्षण की जिम्मेदारी दी जा सकती है निम्नलिखित होंगे।

(अ) अध्यापक

अध्यापकों के कार्य सम्बन्धी अनुभवों की ध्यान में रखा जाए और उनकी बहुत सी स्पष्ट सीमाओं के बावजूद, विशेष रूप से औपचारिक व्यवस्था के अन्तर्गत एकाधिकार-धन पर चर्चा, अध्यापक ही रा० प्रौ० वि० का० के

शिक्षण-प्रबन्ध की व्यवस्था करने वाले मुख्य भविष्य होंगे। मध्यम व्यवस्थाओं में प्रौ० वि० का० के शिक्षक के अनिवार्य वास्तविकता में रहना होगा, इस समय प्रा. पुष्टि एवं स्वच्छता ही रहेगा। उन लोगों में भी, जो इस जिम्मेदारी को स्वेच्छा से लेना चाहते हैं, ऐसे लोगों का चुनाव करना पड़ेगा जिनसे वास्तव में इस कार्यक्रम के प्रति निष्ठावादी होने की आशा की जा सकती है। उचित होगा कि इस कार्य के लिए ५०-६० प्रति भाग दिया जाए। स्कूल के अध्यापकों का सहयोग प्राप्त करने में सुविधा हो सकती है, यदि उनके प्रौ० वि० का० के सफलता का समर्थन प्राप्त किया जाए।

(ब) विद्यार्थी

चाहे राष्ट्रीय सेवा योजना के अंग के रूप में इसे उचित रूप से समायोजित कर लिया जाए, और चाहे अन्य किसी उपयुक्त विधि से, उच्चशिक्षा के विद्यार्थी प्रौ० वि० का० केन्द्रों के गठन में बहुमूल्य भूमिकाएँ निभाने सकते हैं। इसके लिए इस स्तर की छात्राओं के अध्यापकों को भी समान होगा। शैक्षिक सर्वे की वर्तमान दायें विधियों के लिए व्यवस्था, प्रमाण-पत्र आदि के बारे में पुनः सोचना आवश्यक होगा। इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों का सहयोग स्वेच्छिक होना चाहिए किन्तु विश्वविद्यालय के मार्ग दर्शकों को एक सहायक बनना होगा जिसमें विद्यार्थियों को इस कार्य के सहयोग मिल सके और वे इसे सहायक समझें।

(स) छापील नवयुवक

बहुत से बेरोजगार या अल्प रोजगार में लगे छापील नवयुवक हैं जिन्हें थोड़े बहुत शिक्षा की मिली है। उन्हें अपने शैक्षिक स्तर के आवश्यक उन्मुख हेतु साधकता के नियोजित प्रविष्टि देकर तथा मोटिवेशन देकर इस जिम्मेदारी में लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त गाँव के नवयुवकों को भी जो किसी प्रकार के रोजगार में नहीं लगे हैं और जिन्होंने कुछ शिक्षा प्राप्त की है, प्रौ० वि० का० के सफलता के रूप में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। स्थितियों और जन जातियों के कार्य की बड़ी सुविधा हो सकती है यदि उन्हीं में से लोगों को लेकर उन्हीं को प्रौ० वि० का०

केन्द्र चलाने का नेतृत्व दिया जाय। ऐसे लोग अपने काम-पथ में सजे रह सकते हैं और उन्हें आर्थिक बन्धोपा दिया जा सकता है। बैरोम्पार या अल्परोजगार वाले व नव-पुरुष भी, जो इस काम की पूर्णजातिव आधार पर सेते हैं ६ से १० मासुवग के बन्धो का रहस्य बन्धो के लिए मनोव्यापारिक शिक्षा से हो के चलाने की जिम्मेदारी हो सकते हैं। इससे न केवल प्रोढ़ शिक्षा व शिक्षा को वा एव मध्यम उपपुत्र तथा मित छात्रा, प्रत्युत इसल छात्रोण क्षेत्र में एव नये प्रसार के नेतृत्व का सुजन होवा और साथ ही राष्ट्रीय बैरोम्पारो को काम करने में भी सहायता मिलेगी।

(ब) नृत्यक अवकाश सेवा निवृत्त सैनिक

इस वर्ग के लोग राष्ट्रीय तथा नगर-क्षेत्रो दोनों ही के मूल-वर्गों भूमिका अथवा नृत्य सकते हैं। सैनिकनृत्य कार्य-चारियों की अपनी कामदानी बलाने की आवश्यकता होती है, समान रूप से यह भी महसूसपूर्ण है कि उन्हें अपने को व्यस्त रखने के लिए काम की भी आवश्यकता पड़ती है। यद्यपि नीति बलवत्त में बलित अवकाशियों के अनुरूप कार्यक्रम चलाने की कठिनी क्षमता के सम्बन्ध में कुछ स्पष्ट सीमाएँ हैं तथापि उन्हें अपने अनुभवों की सुविधा है। साथ ही इस बात का भी साक्ष मिल सकता है कि मानव में वे सम्मान की दृष्टि से देने जाते हैं।

(ई) क्षेत्रीय स्तर के सरकारी तथा अन्य कार्य क्रम

यह सम्भव है कि ऐसे कार्यकर्ता जैसे ग्राम स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ग्राम-पेरिका दाल सेविका, ग्रामसेवक, सहकारी समितियों द्वारा पचायतो के कार्यकर्ता आदि।

(क) क्षेत्रीय-स्तरीय सामाजिक कार्यकर्ता

विशेषरूप से गरीब लोगों में काफी सख्या ऐसे लोगों की है जो सामाजिक विकास में अपना योगदान करने की इच्छा रखते हैं। ऐसे लोगों की क्षमता का उपयोग किया जाय और उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए विशेष व्यवस्था की जाय।

क्रियात्मकता के अभिव्यक्ति (प्रज्ञा-सीमा)

रा. प्रौ. वि. का. की जिम्मेदारी निम्नलिखित के लिए

सरकार को स्वयंसेवक चुनना होगा। समीक्षा के आधार पर ऐसे कार्यकर्ताओं को जो सरकारों अभिव्यक्तों द्वारा चलाए जा रहे हैं नये मिरों में बदलना पड़ेगा। यह उपयोगी प्रतीत होता है कि प्रजाप देश में सभी जनपदों में सभी भागों में कार्यक्रम की हलके रूप में चलाने के प्रारम्भ में बर्षवत् दोनो म प्रयास को संश्लिष्ट रखा जाय। शिक्षा मन्त्रालय के कार्यक्रमों और उ के विभागत की पर्याप्त रूप से बढ़ाना होगा जिससे विभिन्न अधिकारियों का सहयोग व्यापक रूप से मिल सके। जो कुछ भी हो, ऐसा जन-प्राप्तोत्पन्न जो हलकी यन्त्री मायावी की प्रभावित करेगा, एक मन्त्रालय तथा विभाग द्वारा चलाया नहीं जा सकता दूसरे मन्त्रालयों एवं विभागों की सम्मिलित करने का हर प्रयास होगा चाहिए जिससे वे सब प्रोढ़ शिक्षा कार्यक्रम के चलाने की जिम्मेदारी में भाग ले सकें। दूसरे मन्त्रालयों, विभागों को इस प्रकार के कार्यक्रमों के निर्माण में कार्यपरक साक्षरता एक अवश्य हो, चलाये के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। साथ ही वे सब शिक्षा-अधि-चारियों द्वारा चलाए गए सामाजिक कार्यक्रम में भी योगदान करें। इन मन्त्रालयों विभागों के लिए यह आवश्यक होवा कि वे अपने बजट प्राविभाग की सीमाओं में कुछ परन्तुपि प्रोढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए मन्त्रालयों के निर्धारित करें। चाहे यह कार्यक्रम क्षेत्रीय योजना का अथवा और चाहे किसी अन्य अभिव्यक्ति द्वारा संचालित हो, राज्य-सरकार की सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित होगी। सभी व्यावहारिक दृष्टियों से यह कहा जा सकता है कि कार्यक्रम का क्रियान्वयन पूरे तौर से राज्य-सरकारों की जिम्मेदारी होगी। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों को उन प्रोढ़ शिक्षा कार्यक्रमों का जो वे विगत वर्षों में चला रही थी, पुनर्मुखान्वयन करना होगा और उन्हें धरोपित और पुनर्दृष्ट बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे। यद्यपि सम्बन्ध तथा क्रियान्वयन की मुख्य जिम्मेदारी राज्य-सरकारों की होगी, क्षेत्रीय सरकार न केवल नीति-निर्धारण और सामान्य मार्ग-दर्शन-पूरी के निश्चित करने से सम्बन्धित होगी, बल्कि यह भी देखेगी कि राज्य सरकारों द्वारा नीति बलवत्त के अनुसार कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है।

प्रौढ शिक्षा का कार्यक्रम जो राष्ट्रीय एवं विषय वस्तु से सम्पन्न एवं विभिन्नता को महत्व देता है, स्वेच्छिक उपकरणों की सहायता से सर्वोत्तम रीति से क्रियान्वित हो सकता है। इस समय स्वेच्छिक छात्राओं का सहयोग कुछ सीमित था है और सर्वप्रथम इस समय प्रौढ शिक्षा के क्षेत्र में काम करनेवाले स्वेच्छिक अधिकारियों अपना ऐसे अधिकारों का, जिनमें काम करने को क्षमता है सहयोग प्राप्त करने के लिए उपस्थित प्रयास करना होगा। दूसरे, इस बात का भी प्रयास करना होगा कि नये अधिकारियों के उद्भव के लिए परिस्थितियाँ सशुभ न हों, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ ऐसे अधिकारण कम हैं। स्वेच्छिक अधिकारियों की सहयोगी भूमिका को मान्यता देना आवश्यक है और यह वांछनीय होगा कि निर्णय लेने के हर स्तर पर उनके परामर्श लिया जाए, विशेष रूप से उन मामलों में जो इन अधिकारियों के कार्य को प्रभावित कर सकते हों। साथ ही अनुदान देने की विधियों का पुनरावलोकन करना होगा।

रा० प्रौढ शिक्षा का एक जन-भाग्योत्थन का रूप लेता है या नहीं यह इस बात पर निर्भर करेगा कि जिस घोषणात्मक मन्त्रको तथा विचारों को इस कार्यक्रम के प्रति निष्ठान् बनने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। पुनरावलोकन के लिए यह कहा जा सकता है कि नेहरू मुक्तकण्ठों की कार्य-प्रतिष्ठा का पुनरावलोकन किया गया और उनके प्रयास को प्रौढ शिक्षा पर केंद्रित किया गया। इसी प्रकार ऐसे मन्त्रमूला और नवप्रतिष्ठा विहीने जपने वाला पुरा कर भी है और जिसके मत में इस कार्यक्रम में बाध देने की भावना है। इस प्रयास में स्वाभाविक सहयोगी होंगे। विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा की संस्थाओं के विचारियों का वर्ष भरका सहयोग है। बहुत सभ्य समय से संवैधानिक रूप से विश्वविद्यालयों ने समाज से सम्पर्क रखने की वांछनीयता पर बल दिया है। राष्ट्रीय औद्योगिक-कार्यक्रम विश्वविद्यालयों तथा कानूनों के सामने एक चुनौती को प्रस्तुत कर रहा है जिसे स्वीकार करने अपना कर्तव्य समझ कर सकते हैं और उन शिक्षा की मुख्य धारा में प्रवेश कर सकते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि प्रौढ-शिक्षा को केवल एक विषय का विषय न समझा जाए, प्रस्तुत इसम पूरे समाज के सदस्य, जिससे जिस भी भी

निश्चय ही सम्मिलित हैं, सब ऐसे क्षेत्र में रहे हैं कि विश्वविद्यालय इस प्रकार के बड़े योगदान की तैयारी कर रहे हैं और तदनुसार अपनी प्राथमिकताओं में भी आवश्यक सुधारण कर रहे हैं।

रोजगार देने वालों को चाहे डाइरेक्ट सेक्टर के हो या इन्डियन, अपने न्यायनताओं में प्रौढशिक्षा प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका देना करनी चाहिए। शासनांगर में यह उचित होगा कि रोजगार देने वालों के लिए प्रौढ शिक्षा कार्यक्रमों को बलान्तर अधिकार्य कर दिया जाय। इस मौक़े पर स्पष्टता तथा सहयोग एवं अन्य रोजगार देने वाले अधिकारियों के माध्यम से प्रयासों द्वारा न दिया जा सकता है। एनिक डेक्टर तथा निर्माण के कार्यों में सरकार को इसके लिए अलग बजट का प्राविधान कर नेतृत्व प्रदान करना चाहिए। परिणामस्वरूप काम के पक्षों से कमो और कुछ अधिक व्यय का पर्याप्त दूरकार कार्य-रत्ताओं के काम में गुणात्मक सुधार के रूप में तथा विशाल-कार्यों में उनके सश्रिय सहभाग के रूप में मिलेगा। संवैधानिक सेक्टर में काम करने वालों की शिक्षा सुविधा-पूर्वक ही आ सकती है यदि कार्यक्रमों में युनिवर्सल सश्रिय रूप से सम्मिलित की जा सकें।

स्वाधीन विकास जैसे नवप्रतिष्ठाएं तथा पञ्चायती-राज सरकारों औद्योगिक शिक्षा तथा सामाजिक शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान करती रही हैं। इन अधिकारियों को जो नागरिक और विशाल कार्यों में सम्मिलित हैं, यह सुविधा है कि उनका जलता से सम्पर्क है—उनकी दैनिक समस्याओं से तथा उनकी आवश्यकताओं से। मत उनसे यह आशा करनी चाहिए कि वे रा० प्रौ० शि० का० के विद्यालय में सहयोग देंगे।

नियोजन प्रशासन एवं निरीक्षण

यह प्रश्न अबसर है जब सरकार ने गिरदार आबादी के इतने बड़े माप के लिए एक नियोजित प्रौढ-शिक्षा-कार्यक्रम बनाने का निश्चय किया है। इतने बड़े कार्यक्रम के नियोजन तथा उसके क्रियान्वयन के लिए बहुविध मोहों का समर्थन प्राप्त करना होगा जैसे सामाजिक कार्य-कर्ता, परिवर्तन नियोजन विवेकज्ञ, प्रत्यक्ष विवेकज्ञ, निरन्तर विवेकज्ञ, शिक्षा विशेषज्ञों की अतिरिक्त टोनिदा

तथा प्रौढ़ शिक्षा के विस्तार। नियोजन का व्यापार्य व केवल केंद्र और राज्य की सरकारों द्वारा होना है, बल्कि स्थानीय निकायों स्वेच्छिक अधिकारों, विश्वविद्यालयों, शिक्षकों व संगठनों द्वारा भी हो। सरकार को विभिन्न स्थितियों सम्पत्ति और संगठनों के सहयोग के लिए नेतृत्व प्रदान करने वाली भूमिका बजा करनी है। यह भी आवश्यक है कि राज्य तथा जनपद स्तर पर समुचित मजिस्ट्रेट सम वष और सत्रेयल की दृष्टि से स्थापित किये जाएं। राज्य की सरकारें राज्य प्रौढ़ शिक्षा परिषदों की स्थापना की सम्भावना पर विचार कर सकती हैं और इसी प्रकार की परिषदें जनपद स्तर पर स्थापित की जा सकती हैं।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए केंद्र, राज्य तथा क्षेत्रीय स्तर के प्रशासकीय ढांचे निम्नलिखित अपर्याप्त हैं। ऐसे प्रशासकीय ढांचों का जो इस कार्यक्रम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होंगे सफेद देने के लिए सम्बन्धितपूर्वक अध्ययन प्रारम्भ कर दिया गया है इस समय केवल मोटी आंखें नहीं दी जा रही हैं।

केंद्र सरकार

प्रौढ़ शिक्षा विभाग को ही नई जिम्मेदारियों को देखते हुए मन्त्रालय की व्यवस्था उचित रूप से सुदृढ़ की जाएगी। प्रौढ़ शिक्षा के निदेशालय को अपने काम कलाप का पूर्ण विस्तार करना होगा और इस दृष्टि से कि वह प्रभावित भूमिका बजा कर सभी सहे आवश्यक सुविधाएँ प्रदान की जाती चाहिए।

राज्य-स्तर

ऐसे राज्य स्तरीय प्रशासकीय तथा नियोजन यन्त्रिणी की स्थापित करने के लिए तुरत कदम उठाने की आवश्यकता है जिसमें एक स्वतन्त्र निदेशक या अतिरिक्त निदेशक हो जो शिक्षा निदेशक के अधीन कार्य करे। राज्य-स्तरीय संगठन के लिए आवश्यक सहायक स्टाफ भी देना होगा। प्रत्येक राज्य सरकार राज्य तलिकाय के शिक्षा विभाग में प्रौढ़ शिक्षा के कार्य को करने के लिए एक पूर्ण विभिन्न की स्थापना पर विचार करे जो अच्छा होगा।

जनपद तथा ब्लॉक स्तर

कार्यक्रम के लिए पूर्ण वष जनपदों में सहायक स्टाफ के साथ एक अतिरिक्त शिक्षा शिक्षा अधिकारी की आवश्यकता होगी। प्रशासन और निरीक्षण की दृष्टि से तथा आवश्यक टेक्निकल सहायता की दृष्टि से भी आवश्यकता होगी। प्रत्येक प्रोजेक्ट के लिए स्टाफ की पर्याप्तता पर ध्यान देना होगा।

स्वेच्छिक अधिकार

राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय स्वेच्छिक अधिकारों, राज्य सभासम ईम्न आदि को आवश्यक समर्थन देना होगा जिससे वे राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में योगदान करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक क्षमता स्थापित कर सकें।

इसने बड़े कार्यक्रम में सुपरविजन तथा मार्ग-दर्शन हेतु, पूर्णतः प्रबन्ध होना चाहिए। सुपरवाइजर परम्परागत रूप से निरीक्षण नहीं होना चाहिए बल्कि वह विशेष रूप से चुना हुआ प्रोफेशनल होना चाहिए जिसे काम में अधिकृत हो और जो प्रौढ़ शिक्षा क्षेत्र के वृत्तों को काम में सुविधा प्रदान कर सके। स्वेच्छिक सस्थाएँ स्वतन्त्र रूप से सुपरविजन व्यवस्था स्वयं बनाना चाहेंगी। उन क्षेत्रों में जहाँ कार्यक्रम सरकारी अधिकार्य द्वारा चलाया जा रहा हो, यह देखना होगा कि प्रौढ़ शिक्षा के लिए पूर्ण सुपरविजन व्यवस्था रखना आवश्यक होगा या सहे प्राथमरी स्कूल सुपरवाइजर से सम्बन्ध रखना। इस विषय पर कठोर तथा राज्य-सरकारों द्वारा विस्तार से विचार होना चाहिए।

सरकारी तथा स्वेच्छिक अधिकारों के सामने एक बहुत बड़ी नयी प्रौढ़ शिक्षा के शिक्षकों के प्रोफेशनल स्वयं के अभाव की है। विश्वविद्यालयों में इस प्रकार के स्टाफ को तैयार करने की वर्तमान सुविधाएँ अत्यन्त सीमित हैं और उनके विस्तार की आवश्यकता है। सरकार, विश्वविद्यालयों तथा स्वेच्छिक अधिकारों द्वारा प्रोफेशनल विकास हेतु विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण, कार्यक्रम चलाते होंगे। प्रशिक्षण के अतिरिक्त प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में सहे प्रोफेशनल कार्यकर्ताओं के देहन ढांचे के

सम्बन्ध में भी विचार करना होगा। जहाँ तक सम्भव हो, यह सुनिश्चित करना वांछनीय होगा कि प्रौढ शिक्षा-संस्था में जो लोग प्रवेश करें वे उसी व्यवस्था में बड़े और उन्नति करें न कि वे बाहर चले जाने के लिए विवश हों।

राष्ट्रीय प्रौढ शिक्षा का अर्थ और लक्ष्य

विगत वर्षों का अनुभव यह बताता है कि विभिन्न प्रकार के उद्योगों के कारण यह आवश्यक हो जाता है कि राज्य सरकारें प्रौढ शिक्षा के लिए निर्धारित धनराशि को वांछित शिक्षा को देने, कार्यक्रमों में लगाती हैं या विकास के माध्यम से। अतः यह आवश्यक है कि ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे प्रौढ शिक्षा के लिए निर्धारित धनराशि इस प्रकार न ली जा सके। साथ ही यह भी ध्यान में रखना है कि राज्य में कार्यक्रमों के निष्पन्न एवं शिक्षाप्रदान की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर ही रखनी चाहिए। केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी ऐतिहासिक अधिकारों से व्यापक सहयोग प्राप्त करना, नये कार्यक्रमों का प्रारम्भिक परीक्षण आदि होती है।

धनराशि की व्यवस्था के अतिरिक्त, उसकी पर्याप्तता पर बल देना आवश्यक है। योजना आयोग तथा योजना के विधेयकों का एक प्रमुख दृष्टि निम्न पर रहना है कि प्रति सीखने वाले पर, केन्द्रीय तथा राज्य स्तरीय प्रशासकीय व्यय, मूल्यांकन, मान्यता, लेख तथा नये प्रयोगों के सर्व को विकास कर, ५५ वं अध्याय। प्रत्येक वर्ष के अन्त की गणना धन-सहायक का आधार पर की है, न कि उस संस्था का कार्यक्रम को अन्त तक सफलता पूर्वक पूरा करेगी। ऐसे सफल सीखने वालों की संख्या पूरी संख्या की लगभग ३ होती। अतः यह मानना अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है कि प्रति सीखने वाले पर व्यय

७० रु० से कम नहीं होगा। केन्द्रीय तथा राज्य-प्रशासकीय, मूल्यांकन व्यय आदि पर व्यय लगभग उस कुल व्यय का २० प्रतिशत होगा जो प्रति सीखने वाले की दर से गिराता गया है। इन गणनाओं के आधार पर पर्याप्त धन आवंटन करनी होगी।

प्रौढ शिक्षा कार्यक्रमों के संगठन के रूप के अतिरिक्त प्रारम्भ के ही नवसाक्षरी तथा उन लोगों के, जिन्होंने औपचारिक व्यवस्था में शिक्षा प्राप्त की है, अनुसरण और निरंतर शिक्षा को चलाने के लिए व्यवस्था करनी होगी। इस प्रकार के कार्यक्रमों के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा नहीं की गयी है किन्तु यह तर्क सगत होगा कि कुल व्यय का लगभग २० प्रतिशत इस कार्य के लिए रखा जाए।

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

गरीबी और निरक्षरता की सीमाएँ राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर दूर तक जाती आती हैं। एक देश के अनुभव और सुझावों से परस्पर आदान प्रदान एवं निरंतर सहायता द्वारा दूसरे देश को लाभ उठाना चाहिए। सम्भवतः इन अपने व्यक्ति तथा मानवीय संसाधनों को पूरे तौर से ध्यान में रखते हैं जो वास्तव में बहुत सीमित नहीं हैं जब राष्ट्र के माध्यम का इतना महत्वपूर्ण प्रश्न सामने है। रा० प्रौ० वि० का के निर्धारण एवं शिक्षाप्रदान में दूसरे देशों तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के अधिकारों को परस्पर सम्मान तथा समानता के आधार पर सहयोग देने के लिए अतिवृद्ध होना आवश्यक है। रा० प्रौ० वि० का० के उद्देश्य किन्हीं भी अप्रत्याशित रूपों में हो, हमें अपना कार्य उन देशों से, जो इस क्षेत्र में अप्रत्याशी रहे हैं और जिन्होंने इस क्षेत्र में विशेष योगदान दिया है विवेक पूर्वक सीखने की आवश्यकता से प्रारम्भ करना चाहिए।



प्रौढ़-शिक्षा

नोटि बक्तव्य (दिसम्बर, १९७८)

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

शिक्षा की प्रक्रिया से लोगों की अव्यक्त समस्या को प्रकट करना संभव तथा सामाजिक नियोजन का एक महत्वपूर्ण बिन्दुबिन्दु है। वर्तमान सरकार जब मार्च, १९७७ में सत्तारूढ़ हुई तभी से उसकी दृष्टि में यह बात सर्वोपरि रही है। एक ओर जहाँ १४ करोड़ तक प्राथमिक शिक्षा को सामग्रीय बनाने का पूरा प्रयास होना चाहिए, वहीं दूसरी ओर धार्मिक सुविधा प्रौढ़ों तक भी प्रसारित होनी चाहिए जिससे वे अपनी धार्मिक व प्रेमियों की सुधार तक और अपनी क्षमताओं को पूर्ण रूप से विनियमित कर सकें।

२. सरकार ने निरक्षरता के विच्छेद सुनिश्चित, सुनियोजित तथा अद्वय्य रूप से करने का निश्चय किया है। निरक्षरता सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तनों में अपनी सभी गूँथिका प्रदान कर सके। साक्षरता प्रत्येक व्यक्ति के भविष्य के भविष्य अनिवार्य रूप से रूप से मान्य होनी चाहिए।

प्रौढ़-शिक्षा के सम्बन्ध में वर्तमान चिन्तन निम्नलिखित अनुमानों पर आधारित है।

(क) - निरक्षरता व्यक्ति के विकास और देश की सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति के लिए अत्यन्त सम्भोदनायक है।

(ख) - स्कूली शिक्षा और शिक्षा सप्ताहार्थक नहीं हैं, प्रारम्भिक शिक्षा की प्रक्रिया बढ़ावा देना और जीवन की परिस्थितियों में ही चलनी है।

(ग) - ग्रीष्मकाल, रात्रि, और जौन। वे तीनों अवसर हैं और इनसे वे प्रत्येक सभी वर्गों को जोड़ा जा सके और दूसरे से सम्बन्धित रहता है।

(घ) - विद्या की प्रक्रिया में, शिक्षा लोग सगे हुए हैं, सामान्य रूप से वयस उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि वयस।

(ङ) - निरक्षरता तथा निर्धन लोगों के ऊपर उच्चतर साक्षरता, पत्र-पत्र विचार-विचार और शिक्षा द्वारा अपनी स्थिति में सुधार प्राप्त कर सकते हैं।

३. प्रौढ़-शिक्षा में समाज के आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से वयस वर्ग के लोगों का साक्षरता-कौशल प्रदान करने पर बल देना चाहिए। किन्तु ऐसे लोगों में बहुधा साक्षरता और उसके अनुसरण - कार्य-क्रमों में निरक्षरता सम्मिलित होने के लिए सत्रों का अभाव रहता है। इस सम्बन्ध में शिक्षाने की प्रेरणा देने पर बल देना चाहिए। साथ ही साक्षरता-कार्य-क्रमों में बोलने की भाषा के प्रयोग और आचार्यन के सामूहिक रूपों पर भी बल देना चाहिए। सत्रों का कार्य-क्रम में भाग लेने वालों की दृष्टि-क्षमता पर भी विचार करना है कि वे अपने जीवन को बदल सकते हैं और इस पर कि प्रौढ़-शिक्षा के कार्य-क्रम, उद्देश्यों की प्राप्ति में उनकी कार्य-क्षमता बढ़ाने में सहायता करेंगे। इसके अतिरिक्त ऐसा साक्षरता का कार्य-क्रम, जो बोलने वालों की काम करने और जीवन-साधन करने की दृष्टि से असम्भव हो अथवा साक्षरता की बुनियादों और देश की विचार-सम्बन्धी सामाजिकताओं से असम्भव हो, उन्हें सक्रिय प्रतिभागी बनाने में समर्थ नहीं हो सकता और न ऐसा कार्यक्रम शिक्षा तथा उन्नति का साधन बन सकता है। अतः प्रौढ़-शिक्षा जहाँ साक्षरता-कौशल पर बल देती है वहाँ उसे

—शिक्षण वास्तविकताओं तथा वातावरण से सम्बन्ध होना चाहिए,

—कार्य की अवधि, समय, स्थान, शिक्षण-प्रबन्ध आदि के सम्बन्ध में मध्य होना चाहिए,

—पाठ्यक्रम, शिक्षण तथा शिक्षण की सामग्री और विधियों के सम्बन्ध में बहुविध होना चाहिए,

—और सगठन के सभी पक्षों में सुव्यवस्थित होना चाहिए,

४ प्रौढ शिक्षा में सर्वोच्च प्राथमिकता निरक्षर लोगों को दी जानी चाहिए। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् को प्रथम में साक्षरता के क्षेत्र में सफलताओं किसी प्रकार संतोषजनक नहीं रही हैं। १९४७ में साक्षरता की दर १४% थी जो १९७१ में ३३.८५% (०-४ के आयु वर्ग की छोड़कर) हो गई। फिर भी साक्षरों के बढ़ने और पुनर्ले प्रयासों की अर्द्धसमरता के कारण निरक्षर लोगों की संख्या १९५१ में २४०० लाख से बढ़कर १९७१ में १०६० लाख हो गई। १९७१ की जन-गणना के अनुसार १४ वर्ष से ऊपर निरक्षर लोगों की कुल संख्या २११० लाख है जिसमें ६८२ लाख १५-१५ आयुवर्ग में हैं और यह संख्या इस समय लगभग १००० लाख है। साक्षरों के १५-३५ आयुवर्ग के इस बड़े भाग को शिक्षित करने के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम प्रस्तावित जाना चाहिए और यह कार्यक्रम ५ वर्ष के भीतर व्यापक रूप से चलाया जाए। इसका अर्थ है कि शिक्षा, अनुसंधान, व्यक्तियों और जन-जातियों के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार करने होंगे। उन क्षेत्रों पर, जहाँ निरक्षरता अधिक है, विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी।

५ जहाँ अनुसूचित २ और ३ में उल्लिखित संरचना पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वही एक बात को भी रेखांकित करने की आवश्यकता है कि कार्यक्रम को एक जन-संयोजन के रूप में देखा जाए। सगठनात्मक दृष्टि से यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि बड़े क्षेत्रों पर कार्यक्रम चलाने के पूर्व तयारीपूर्ण तैयारियाँ कर ली जाएँ। जिसमें का ध्यान और जहाँ सम्बन्धित करना, पाठ्यक्रम तथा शिक्षण

सामान्य सामग्री तैयार करना और प्रशिक्षण—ये अतीत में प्रौढ-शिक्षा-कार्यक्रमों की दुर्घटना के मुख्य क्षेत्र रहे हैं। कार्यक्रम चलाने के पहले इन क्षेत्रों में संतोषजनक तैयारी आवश्यक हो जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त यह न समझना चाहिए कि प्रौढ शिक्षा केवल वैयक्तिक व्यक्तियों के कामों है। प्रौढ शिक्षा विकास के सभी क्षेत्रों में अन्विष्टता के रूप में समझी जानी चाहिए, विशेष रूप से जहाँ विकास के उद्देश्यों की प्राप्ति में सामाजिक होने वाले लोगों का भाग लेना सम्भव महत्वपूर्ण हो। प्रौढ-शिक्षा मानवोत्थान की पूर्वावश्यकता यह भी है कि सभी अधिकारों सरकारों, स्वैच्छिक, निजी, तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उत्थान, औद्योगिक शिक्षा की सहायता आदि इस मानवोत्थान को बढ़ावा दें। स्वैच्छिक अधिकारों की विशेष भूमिका भरा करनी है और उनका पूरा सहयोग प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे। शिक्षण-कार्य शिक्षकों, विद्यार्थियों तथा वैयक्तिक स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाना चाहिए। यह अच्छा होगा यदि वैयक्तिक या कमरौचदार वाले नवयुवकों की जिम्मे प्रौढ-शिक्षा-कार्यक्रमों को संचालित करने की अवकाश है, आवश्यक शिक्षण विषय जाए और सब उन्हें ऐसे कार्यक्रमों को संचालित करने का उत्तरदायित्व दिया जाए। समस्याओं के प्रभावों और व्यक्तित्व विशेषण के लिए कार्यक्रमों में निर्देशन, मूल्यांकन तथा प्रयोगात्मक क्षेत्र के लिए अनाविहित व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसे अनुसंधान कार्यक्रमों को, जैसे पठन-समय का प्रकाशन एवं वितरण, संचालित ज्ञानार्जन और सामुदायिक शिक्षा, विशेष महत्व देना चाहिए।

६. इसने बड़े कार्यक्रम के सगठन के लिए पर्याप्त वार्षिक और प्रशासनिक समर्पण की आवश्यकता होगी। इस कार्यक्रम के लिए जिसमें साक्षरता और वातावरण-सम्बन्धी तथा सामाजिक शिक्षा सम्मिलित होगी और जो लगभग ३००-३५० घंटे या लगभग ३ सप्ताह के लिए, वार्षिक प्राविधान करना होगा और मध्य व्यक्तियों की भी ध्यान में रखा होगा। आवश्यक सहायकों की आवश्यकता सरकार, स्थानीय निकायों, स्वैच्छिक अधिकारों, व्यवस्था

तथा उद्योग आदि को करनी होगी। इस बात का एक मर्यादा अनुमान लगाया होगा। कि उस प्रोफेशनल और प्रदासकीय दमन का विस्तार और समता क्या होगी जो इस कार्यक्रम के लिए आवश्यक होये और उस इस दमन को स्थापित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे।

निराशरीरों के लिए इतना बड़ा कार्यक्रम समर्पित करने के अतिरिक्त यह आवश्यक है कि विशेष वर्गों के लिए उनकी विशेष आवश्यकताओं के अनुसार विशेष कार्यक्रमों की व्यवस्था की जाए। उदाहरणार्थ, निम्नलिखित वर्गों के लिए विशेष कार्यक्रमों की आवश्यकता है।

—पुरुषों में जाग करने वालों के लिए जिससे वे अपने कौशल को उजागर कर सकें और प्रत्यक्षतः में अपने उचित अधिकारों की प्राप्ति के लिए अपने को सक्षम बना सकें तथा प्रत्यक्षतः में भाग ले सकें,

राजकीय कर्मचारियों के लिए जैसे न्यायालय के अधिक, क्षेत्र के सेवा-विस्तार कार्यक्रमों तथा नीति एवं सेवा के कर्मचारी, जिससे वे अपनी योग्यता बढ़ा सकें;

—व्यावसायिक उद्योगों के कर्मचारियों के लिए जैसे बैंक

तथा बीमा कम्पनियों के कर्मचारी, जिससे वे अपने काम में और दक्ष हो सकें;

बुद्धिजीवी-वर्ग के लिए जिससे वे पारिवारिक जीवन की समस्याओं तथा समाज में स्थिति के स्थान को अच्छी तरह समझ सकें।

इन लोगों के लिए और इसी प्रकार के अन्य वर्गों के लिए कक्षा-प्रशिक्षण के द्वारा, पत्राचार कौशल प्रदान सामूहिक साधनों द्वारा अथवा इन सभी को मिलाकर कार्यक्रमों को चलाया जा सकता है।

यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि प्री-शिक्षा के कार्यक्रम का क्रियान्वयन विकेंद्रित हो। यह भी आवश्यक होता कि समयमय एवं उचित रूप के लिए अधिकारों की स्थापना की जाए।

केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी-शिक्षा-परिषद की स्थापना इसी उद्देश्य से की है। इसी प्रकार की परिषदों की स्थापना राज्य - स्तर पर भी होनी चाहिए। विभिन्न अधिकारियों के कार्यों के समन्वय तथा उनका सहयोग प्राप्त करने की दृष्टि से उपयुक्त व्यवस्था की जानी चाहिए।

अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता-दिवस

जॉन ई० फोन्स

उपमहानिदेशक, यूनेस्को

यह बड़े मानाद का विषय है कि यूनेस्को में हम लोग अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में परम्परा के अनुसार पर्व मनाते हैं और उन नर - नारियों की सज्जदगता से अपने की तुल्यता करते हैं जो साक्षरता के विश्व सम्मेलन में लगे हुए हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो अन्तर्राष्ट्रीय जगत मना रहा है, उस निर्णय का परिणाम है जो निरक्षरता समाप्त करने हेतु पठित विज्ञान-मन्त्रियों के उस विषय-सम्मेलन में लिया गया था जो १९६५ में तेहरान में हुआ था। यह दिवस इस बात का अवसर प्रदान करता है कि हम अब तक के किये गए कार्यों को समर्थ, प्रविष्ट की ओर और अपने सपने की ओर मजबूत बनाएँ।

अपर हमें अब तक की माना के फावले को नापना हो, तो है निष्पक्ष रूप से यह कहेंगे कि यह परिणाम असतोषजनक है। यह स्पष्ट है कि काम बहुत बड़ा है और अब भी बहुत कुछ करना है, फिर भी हम मानते हैं कि निरक्षरता की दूर की जाय और यह कि सहायक की उपलब्ध किये जा सकते हैं।

वास्तव में मानव बहुत तेज़ी से प्रवृत्ति के निरक्षरों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। आज उन की संख्या अनुमानतः ८० करोड़ होती। प्रत्येक ३ मिनटों में से एक न तो पढ़ सकता है, न लिख सकता है और न निश्चित रूप से धरम हिसाब लगा सकता है। निरक्षर विधियों की संख्या, जो निरक्षर आबादी का ७०% होगी, निरक्षर दुर्गों की संख्या से अधिक होती है बढ़ रही है। यह धमकाया लोगों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक रहता है। विकासशील देशों में निरक्षरता अत्यधिक व्याप्त है। बहुत से देशों में ८० प्रतिशत निरक्षर हैं। यह

मासपर्व की बात नहीं है कि निरक्षरता के लोग वही हैं जहाँ विद्यु - मूल्य, कुपोषण, बेरोजगारी और गरीबी हैं। दूसरे शब्दों की दृष्टि बहुत ऊँची है। उद्योग प्रधान देश भी निश्चय ही इसके बचे नहीं हैं। इन देशों में निरक्षरता, स्थान परिवर्तनशील काम करने वालों तथा उनके परिवारों अथवा स्थानीय आबादी के कुछ टुकड़ों की जो यद्यपि बाहरी तौर से साक्षर हैं किन्तु अपनी दैनिकीय समस्याओं से सहायता के लिए न तो पढ़ने का प्रयोग करते हैं और न लिखने का, प्रभावित करती है।

इससे भी गम्भीर बात यह है कि अनेक समाजों के निरक्षरों की एक बहुत बड़ी संख्या आबादी के पुष्पा-वर्ग की है। जब इस राज्य की उम्मेदा करना असम्भव है कि बहुत से देशों ने वास्तविक बड़े शिक्षा प्रसार के बड़े प्रयास के परिणामस्वरूप के छकेत पुष्ट मान की लिये पाएँ, समा-कथित तीसरी दुनिया के देशों में १-१९ लाख वर्ष के स्कूल न जाने जाते बच्चों की संख्या १९८२ में १३ करोड़ ४० लाख हो जाएगी जिसमें ३ करोड़ ५० लाख बच्चीका में, १ करोड़ एशिया में, और १० लाख लैटिन अमेरिका में होने। यह भी मानना होगा कि आधुनिक शिक्षा के अब तक बहुत कम बच्चे स्कूल में एक पाते हैं और बहुत बड़ी संख्या ऐसे अज्ञान के साव (नूल छोट होती है जो जीवन की दैनिक वास्तविकताओं में उत्तमकर समाप्त हो जाता है। विकासशील देशों में केवल बात इतनी नहीं है कि बढ़ती हुई आबादी की संख्या एक लम्बे समय तक अज्ञान-संख्या से भागे बढ़ती रहेगी, बाव यह भी है कि शिक्षा के बन्दों में विस्तार के विषय दैनिक संपत्ति के बढ़ते हुए व्यय का घटन मर्यादित बढ़ता जा रहा है और इस प्रकार उच्चपरीय और बहुपरीय सहायता का आवेदन बढ़ता जा रहा है।

निर, बुनियादी एवं निरंतर सभी बासी विद्या एक
ऐसा बुनियादी मातृ अविचार है जिस पर और अवि-
चार निवार करते हैं। ऐसी बुनिया, जिस पर इस अविचार
को उपेक्षा की जाती है और इस प्रकार यहाँ व्यक्तिता
और उनके सम्बन्ध समाजों का विकास अवश्य होता है,
एक निराशा, नाशयुक्त और समाज की बुनिया ही हो
सकती है।

इस परिस्थिति को ही हम इस तथ्य की उपेक्षा नहीं करनी
चाहिए कि निराशा का निवारण में कुछ प्रयत्न, यह
विश्वी भी कम नहीं हो हुई है। एक बड़े पैमाने पर
साधारण का प्रसार सम्भव है। हम लोगों की एक समस्या
यह है कि इसमें से बहुत से इस तरह विश्वास नहीं
करते और न इसके अनुसार कार्य ही करते हैं।

किन्तु हम लोगों का चाह हम इस बात से बचना चाहिए
कि बहुत सी सरकारों और राष्ट्रीय संगठन निराशा का
विक्षेप स्वरूप में लगे हैं। नये ढांचे, राष्ट्रीय तथा
स्थानीय कार्य समितियों, निरंतर विचारों पड़ने लगे हैं।
सोच, नये प्रयोग तथा सुधार-योजनाएँ आजीवन विद्या
के जीवन में और विद्या के समस्त पुनरुत्थान के सन्दर्भ में,
इस बात की सुनिश्चित करने का प्रयास है कि औपचारिक
विद्या-अध्यापन में अतीवधारित आगमन से अधिक प्रभावी
रूप से सम्भव हो जाए।

मह. यूनेस्को तथा अ. विज्ञान अविचारों को
राष्ट्रीय कार्यक्रमों की सहायता करने और उनमें नये
विचार देने का प्रयत्न सदस्य है। मैं यहाँ पर एक ० ए०
बी०, आई० ए० बी०, इन्फो० ए० बी०, यू० ए०
बी० पी०, युनिस्क तथा द्वितीय सत्रों के प्रति अपना
सम्मान ज्ञापित करना चाहता हूँ।

एडिस्वोरिगेट्स परसे मिट्टे की प्रोशान जिसे यूनेस्को
की सहायता मिली थी और जो १९६६ और १९७४ के
बीच १६ सत्रों राष्ट्रीय में सम्पादित गया था, अंतर्राष्ट्रीय
सहयोग का एक प्रयत्न ही उत्साहक है।

यद्यपि कार्यक्रम में सबसे नहीं अधिक भाषाओं
पर काम चलाकर है जिसका प्रारम्भ से सोचा गया
था, और वास्तव में अविचारों तथ्य के कि कुछ बगल

में सम्पादन परिलक्षण दृष्टिगत सत्य के अनुसरण नहीं
निश्चित, तद्विषय प्रयत्न और अनुभव अवश्य प्राप्त हुए।

उत्तरे जो विद्या प्राप्त हुई वह उन लोगों के लिए
प्रेरणा का स्रोत है जो साधारण विद्यार्थी में लगे हैं।
यह प्रोशान के विचारों में जो अनुभव मिले उनके आधार
पर नये आन्दोलन सामय गये हैं जिसका सम्पादन
तथा पुनरुत्थान दृष्टि से सम्पादित परिणाम निश्चित है।

१९७३ प्रसार विद्ये में कुछ वर्षों में, बहुत से देशों में
अपनी विद्या - व्यवस्था अविचार तथा अनादर तथा प्रो-
साधारण - विद्या के प्रसार में दृष्टि करने, निराशा के
प्रतिफल में काफी बड़ी करने में सफलता प्राप्त की है।
मैं इस सूची में अलजीरिया, भारत, ईरान, माली,
म्यान्मार, यमन, जम्वीका, क्यूबा तथा सोमालिया को
रखता हूँ।

इसलिए यह स्वाभाविक है कि यह वर्ष नेरोबी की
भारत कार्योत्तरे के निराशा के विपक्ष स्वरूप हीव करने
पर विशेष धन दिया और एक प्रस्ताव पास किया जिसमें
सदस्य - राष्ट्रों के कहा गया कि 'ये अपने साधारण के
कार्यक्रमों का अधिक ध्यान के साथ अनुसरण करें और
आन्तरिक अन्तर से आग्रह दिया गया कि यूनेस्को के
बासी कार्यक्रमों के 'निराशा के विपक्ष समिपान में
जायी ऐसी सार्वजनिक' अविचारों में मान लें जो वर्षों
(biennium) की प्रतीक्षा नहीं कर रहा है। यह सदस्य
राष्ट्रों द्वारा लीये जमाये गये साधारण के कार्यक्रमों की
उत्तरे एव सुदृढ़ करने के लिए नई कार्य कर रहा
है। जहाँ वह अपनी अविचार की योजनाओं का सम्पादन
है मैं यह कह सकता हूँ कि हम लोग ऐसे कार्यक्रमों के
बारे में सोच रहे हैं जो सुसंगत उन राष्ट्रों के लिए हैं
जिनकी साधारण की आवश्यकताएँ विशेष रूप से प्रा-
प्त हैं और जहाँ साधारण - अविचार एक राष्ट्रीय
राजनीतिक सत्य की परिस्थिति है।

हमें आशा है कि हमारे सहायतापरक कार्य राष्ट्रीय
तथा स्थानीय स्तर से विभिन्न क्रिया कलाओं द्वारा अविचार
निकलना चाहें। हम यह भी आशा करते हैं कि हम
साधारण तथा साधारण के बीच के विचारों के क्षेत्र में

काम करने वाली राष्ट्रीय सत्त्वामों का पास बिना है जिससे सूचनाओं तथा अनुभवों के आदान-प्रदान में सुविधा हो और एक क्षेत्र के विभिन्न देशों के बीच बिनके विकास-स्तर तुलनीय है या समरसता एक प्रकार की है, पारस्परिक सहायता के कार्य कलाओं की उन्नति में भी सुविधा हो। शिक्षण तथा प्रशिक्षण-कार्यों के लिए मस्ती-वीरिया साधनों की और राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय बैंकों की स्थापना की बात भी सोची आ रही है। हमनीय शासक-शिक्षण सम्बन्धी सहायक साधनों के विषय-परि-शिष्टियों में सत्पादन की, जब समरसताओं से अलग है तो अर्थात्मात्र सत्पाद शैक्षिक सुविधाओं के समाय के कारण और भी कठिन हो जाती है।

साक्षरता-कार्यक्रम का दूसरा भी प्रभाव बस्तुतः उसी ही वक्रता है जब बिचक के उसी राष्ट्र अपनी भावकता एवं साधनों के अनुसार इसमें सम्मिलित हों। इसी बात को ध्यान में रखकर जनरल काफ़ेड ने उसी प्रस्ताव में बाइसेमलर जनरलको यह निर्देश दिया था कि वे साक्षरता-कार्यक्रम के समाने और एक अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता कोष स्थापित करने की सम्भावना का अध्ययन करें। 'अध्ययन' का अर्थ है—एक नये मान्योत्पन्न के लिए जनमत के वातावरण का परीक्षण करना। इस भोजन देखा कर रहे हैं और इस सम्मेलन में जनरल काफ़ेड के दूसरे सम्मेलन में निष्कर्ष प्राप्त करेंगे। क्या ऐसा अन्तर्राष्ट्रीय चौड़ाई विद्यमान है जिससे उन्नतपक्षीय या बहुपक्षीय सहायता के वास्तविक वृद्धि की जा सकती है? क्या इस चौड़ाई का प्रथम प्रारम्भ समान है बुनियादी साक्षात्कारों और व्यक्तित्व के आदर पर और साथ ही निम्न राष्ट्रों की यही सामाजिक भावना और सदस्यों के पारस्परिक हितों पर आधारित है?

मैंने पहले कहा था कि १२ वर्षों के अनुभव से हमें कुछ शिक्षा है और ऐसे विद्वानों की ओर सकेत किया है निम्नलिखित छात्ररत्न - कार्यक्रम के सत्रांश में एक नये छात्राध्यक्ष प्रयास की प्रेरणा मिलनी चाहिए।

संश्लेषण यह बात कुछ ही यही है कि सर्वाधिक विदेशीय धोखाधड़ी, अर्थशास्त्रीय समस्याओं के सर्वाधिक विदेशी प्रस्ताव तथा प्रत्यक्षकारी समस्याओं का सर्वाधिक

साधनायुक्त सहयोग अतोगत्या अर्थ है जब तक आरम्भ से ही राष्ट्रीय राजनीतिक संकल्प स्पष्टतः अविच्छिन्न न हो। और यह संकल्प श्रद्धेय समाज की अपनी कार्यशीली में परिस्थित होना चाहिए। यह संकल्प पूरे सभी आवश्यक मानवीय, भौतिक तथा धार्मिक साधनों की शक्ति करेगा और लोगों की गहराई से इस बात की अभ्युक्ति कराने सहायक होगा कि साक्षरता-शिक्षण समाज की बढसने में एक अग्रगण्य साधन बन सक्ता है।'

इससे यह पुरे दौर से स्पष्ट हो गया है कि साक्षरता-कार्यक्रमों में सम्पूर्ण मानव को विकास के केन्द्र में रखना चाहिए । साक्षरता के कार्यक्रम को केंद्रीय है एक मनुष्य को, कृषि क्षेत्र के एक वैसिहुर को केवल प्रभावित बढाने एक मोक्षिक साधनी को समर्थ करने और व्यक्ति विकास के चर्चे से पढ़ना निखाना और गिनती सिलाले है, स्वाधी नहीं होने और यन्त्रों सांस्कृतिक समस्याएं मनुष्य करीब ।

साक्षरता कार्य स्वभावतः कार्यपरक तथा बहुविध होना चाहिए। अर्थात् यह ऐसा हो जिससे समाज के सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्ष एक पूर्णता का ध्रुव में बंध सकें। इसमें सम्पूर्ण मानव केन्द्रित होना चाहिए क्योंकि इसका उद्देश्य उसके वातावरण को सवाय वास्तविकता के आधार पर उसे मनी वैदिक व्यवस्थाओं के हत करने में सहायता देना है। हम लोगों के विचार में कार्यपरक साक्षरता की मौलिकता अनुष्ठान की पद्धति से पढ़ी प्रेरणाओं और चरित्र की आवश्यकताओं को अनुष्ठान करने में सहायता पहुँचाने के दृष्टी मयात में है। सम्बन्धित समाजों के जीवन तथा साक्षरता में सम्बन्ध, कार्यकर्ता के व्युत्पन्न में, सहयोगी संस्थाओं के जीवन में तथा उन व्योमों के जो शिक्षण के रहे हैं और जो के रहे हैं, परस्पर सम्बन्धों के समग्र में, परित्याग होना चाहिए।

एक लीबरा बिदु मावी साभरता कायंरम के निर
बलन महवबुन है ओर रह है बनता न मागीनार
बनना ।

निष्कारता से सदन के लिए खोरदार मायोधन
प्रारम्भ किया गया। तभी से हम लोगों ने यह प्रयत्न

किया कि साक्षरता-अभियान की सफलता निश्चयनैह १५
 बात पर निर्भर करती है कि किस सीमा तक समाज
 इसके मागीदार बनता है। यह सहभाग सूचना के उभय-
 पक्षीय प्रवाह पर बल देता है जिससे निरंतर व्यक्ति अपने
 अनुभवों और विचारों को अभिव्यक्त करते हुए, विचार-
 शक्ति तथा सार्वजनिक मस्तिष्क को विकसित करते हुए
 तथा अपने सांस्कृतिक अस्तित्व पर खर देते हुए, प्रारम्भ
 से ही अपने शिक्षण की जिम्मेदारी महसूस करने लगता
 है। इस सम्बन्ध में यूनेस्को की इस बात की प्रशंसा है
 कि साक्षरता कार्यक्रमों में राष्ट्रीय प्राथमिक एवं सस्कृतियों
 के प्रयोग में इतर समिवृद्धि हुई है।

साक्षरता कार्यक्रमों में जनता के सहभाग का अर्थ
 स्पष्ट है। और इसके निकलने वाला यह कर्म महत्व का
 दिखने मही है कि स्थानीय स्तर पर निम्न विकेंद्रित
 हो। उक्त वैयक्त भावना का प्रतिकार करने के लिए जो
 पहले के अविकसित साक्षरता-कार्यक्रमों की विशेषता हुआ
 करती थी, समुक्त राष्ट्रीय स्तर पर, एक्सेपेरिमेंटल कन्वैन्ट-
 रशी प्रोग्राम की समिति के साथ इस बात का अनुवासन
 की कोशिश की है कि अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग राष्ट्रीय
 एवं स्थानीय सक्रियता एवं जिम्मेदारी को कभी हतोत्साह
 नहीं करता।

चौथा पाठ जो सोचा गया वह ठेहरान में आयोजित
 विशालमन्त्रियों के सम्मेलन की, जिसकी हम बारहवीं बारत
 पाठ बना रहे हैं रिपोर्ट में विश्लेषण है। यह यह है कि
 साक्षरता का कार्यक्रम सब से अलग मही किया जा
 सकता। इसे आजीवन शिक्षा की प्रक्रिया और विकास की
 योजनाओं में छोड़ना और समन्वित करना पड़ेगा।

यह साक्षरता का कार्यक्रम पर्याप्त रूप से विनाश
 कार्यक्रमों तथा सामाजिक, सांस्कृतिक और सांस्कृतिक गुणों
 से जुड़ जाता है तो मुझे पूरा विश्वास है कि यह स्थिति
 के मुताबिक एक महत्वपूर्ण मूल्यांकन बना कर चलता है।
 ऐसा समझना आनामन के एक नये दृष्टिकोण की प्रतीक
 करता है, ऐसा दृष्टिकोण जो समन्वित होने वाले लोगों
 को उत वतनीही पर निरन्तर के प्रयोग करता चाहते हैं,
 एक प्रयासों निरन्तर के चलते। इस का अर्थ यह भी है

कि संबंधित विभिन्न बुनियादी तकनीकी सेवाओं में पर-
 स्पर परामर्श करने और स्थायी रूप से मिलजुल कर कार्य
 करने की प्रवृत्ति बनाई जाय जिससे औपचारिक तथा
 अनौपचारिक शिक्षा-अवस्थाओं में निरन्तरता और सम्यता
 बनी रहे।

इन चार बुनियादी बिन्दुओं में में बहुत से बातें
 अनुभव और चोटना चाहेंगे, किन्तु समवायुताए कुछ
 बिन्दु ही प्रस्तुत करूँगा। मैं सोचता हूँ कि साक्षरता-
 कार्यक्रमों का साक्षरता कार्यक्रम के अन्तर्गत या
 सुव्यवस्थित रूप में रहे जाएँ। पियेटर, बस-पुस्तकालय,
 लोक-समीक्षा, समाचार-पत्र तथा स्थानीय प्राथमिकों में
 पाठ्य सामग्री जिसमें विषय-वस्तु परामर्शों की प्राप्ति-
 स्थितियों और कर्मियों के अनुकूल हो-ये साक्षरता-
 कार्यक्रम के अनुसरण की विधियाँ हैं जिससे मयसांशरी
 को नये मजबूत ज्ञान का प्रयोग करने, अधिकार प्राप्त करने
 और बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

हम लोग यास मीडिया के योगदान के बारे में भी
 सोच रहे हैं, विशेष रूप से यह बहुत से मीडिया का एक
 साथ प्रयोग किया जाता है। उम्मत तकनीकी पर आधा-
 रित नये संश्लेषण सामग्री से बहुत से अवसर सामने आ
 रहे हैं और कहे-कहे लक्ष्य में कार्य हो रहा है।

जैसे मैंने प्रारम्भ में कहा था, हम जानते हैं कि हमें
 क्या करना चाहिए और उससे भी अधिक हम यह जानते
 हैं कि जो आवश्यक है उसे कैसे करना है।

तो फिर प्रयास करने अवर्थात क्यों है और परिणाम
 इसके निराशाजनक क्यों हैं? मैं सोचता हूँ ऐसा इस
 लिए है क्योंकि, जैसा चिन्तन करण के साथ है—अधि-
 कार्य लोग यह माना नहीं करते कि कोई अव्यवस्थित प्रवृत्ति
 की जा सकती है। भाषा और विज्ञान को कभी है।

इसके अतिरिक्त एक बड़ा बड़ा देखा इस समय उप-
 रिक्त लोगों को छोड़कर, यह अनुभव नहीं करते कि
 साक्षरता का प्रयास वास्तव में उन्हें मरती सुविधापूर्व
 स्थिति में सुरक्षित रखने के लिए वास्तव में आवश्यक है।
 यह भी सचता है कि कुछ मेला यह भी सोचते हैं कि
 आवश्यक साक्षरता सार्वजनिक हो सकती है। या बहुत

की समझाए उत्पन्न कर सकती है।

जब इन परिस्थितियों में, चिनबारी वहाँ से कुछ हेली और रोसानी की वधाएया व महापद्म साहसाह द्वारा प्रस्तुत साहसिक उद्वेग को नयी प्रेरणा वहाँ से मिलेगी ?

हीन बप के भीतर ही हम सोच तुल्य विकास दमक प्रारम्भ करते और जैसा बुनको के दार्सेक्टर काल की सम्राट् महार एम' बो वे (Amardou Mahtar M' Bow) इकनामिक और सोशल काबिल के 63वें अधिवेशन में कहा था, द्वितीय वुनस्टेट नेसनल डिवेन के दौरान प्राप्त हुए अनुसंधानों के आधार पर, हमें तुरन्त वह कार्यवैसी परिभाषित करनी होगी जो अन्तर्राष्ट्रीय समाज की नयी आवाजाओं की पूरा ध्यान में रहेगी।

क्या हम ऐसे मत नरन के आधारों की आशा कर सकते हैं—ऐसी नैतिक अनुमति की, एक ऊर्ध्वमुख सोहार्द मानना की जो बहुपक्षीय व्यवस्था को और बस प्रदान कर सकती है (बनोकि उमयवसीय सहजता की संज्ञा वह अधिक अच्छी है), जो हमारे विकास दमक में साक्षरता बड़े रूप में मिल सके ? कदाचित् ऐसा ही। इन बातों है कि भी हम को और उनके समान अन्य गैरा हूर वह प्रयास करेंगे जिससे ऐसा हो। मेरा सुझाव है कि एक और साक्षरता की समुच्च की बुनियादी भाव शक्तियों की पूर्ति करने वाले कर्मजान केन्द्र बिन्दु के बोलना चाहिए और दूसरी ओर अनुच्च के बुनियादी परिवारों की बढ़ती हुई क्षमता से।

इसके अतिरिक्त मैं समझता हूँ कि दो बातें निश्चय अधिष्ठ में निराशरता को कम करने में एक वास्तविक मया मोड़ दे सकती हैं। दोनों ही समाज की बलों से एक प्रभावी मान के उद्भव को और संवेत करती हैं—ये बल हैं परिवार तथा स्थानीय समाज।

पहली बात का उद्भव रोजगार की आवश्यकता से होता है। समझ समी देशों में जहाँ जैसे करोड़वार नव-युवकों की समस्या बड़ी है और जैसे-जैसे बहुत ही कार्पिक व्यवस्थाओं की परम्परागत भावों में रोजगार देने की

क्षमता कम होती है, वैसे वैसे ऐसी स्थिति में लोग मामले को अपने हाथों में ले लेंगे। स्थानीय समाज अपने सदस्यों के लिए सामग्र्य कार्य बलाप आयोजित करेंगे। स्थानीय सक्रियता और प्रवास बढ़ेंगे और आत्मनिर्भरता के लिए समझ से साक्षरता की मान स्थान उत्पन्न होगी और उच्च को पूर्ति के साधन भी निश्चित होंगे।

दूसरी बात उमयवध अधिक सक्रियता होगी—सभी राष्ट्रियों से अधिक गति देने वाली। यह ऐसे लोगों से आएगी जो सभी प्रकार से वंचित हैं, केवल साक्षरता से ही नहीं। मैं भिन्नो की बात करता हूँ। आवाज ऊपर उठेगी 'हम सोच विकास में जान लेना चाहते हैं और हममें योगदान करना चाहते हैं। बहुत से लोगों के लिए वह जीवन मरण का प्रश्न है। और पुनः, विश्व के दुखों, धारवीय स्तर पर समाज को भागे बढ़ाने और उनके विकास के लिए जोर से काम नहीं कर रहे हो। हम विश्व की गरिमा, साक्षरता के साधन की मान करती हैं जिससे हम अपनी पूरी भूमिका बजा कर सकें।'

मैं जो कह रहा हूँ वह यह है कि निराशरता के विपक्ष अधिवेशन उन भाषेया अब किया इसकी मांग करेंगी।

यूनेस्को को इन सभी बातों को सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए और जहाँ गी रोसानी विश्वास है उसका योगदान करना चाहिए।

अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हम लोगों की अपने कार्य का सुव्यापक करने का और सन्धि पर विश्वास करने का अवसर देता है। इसमें हम अपनी उपलब्धियों को मनाते हैं और प्रवासों को प्रोत्साहित करते हैं तथा नवी सक्रियता को प्रोत्साहन देते हैं।

सदस्य राज्यों की ओर से ॥ दोहम्मदरजा बहुत ही नारेन्दर कल्पकाया पुरस्कारों के लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। पुरस्कारों के लिए अधिवेशन ईरान के शाह-दाह और यूएन एमकार की सरकारों के कारण सम्भव हो सके हैं। हम यहाँ एक बार पुनः इन सरकारों के प्रति, समस्त राष्ट्र सच को उद्देश्य मुक्त समर्थन देने के

लिए तथा मानवीय सौहार्द के इस सुन्दर उदाहरण के लिए, हार्दिक आभार प्रकट करते हैं।

समुक्त राष्ट्र संघ तथा ट्राइटेक्टर जनरल की ओर से हर इम्पोर्टन्ट हार्दिक प्रिण्डेबल अक्षरक पहलवी और एम्बर नेशनल पुरी के सदस्यों को, जिन्होंने बावजूद अपने धन्य कार्यों की व्यस्तता में नमाऊन की समोसा करने और पुरस्कार-विजेताओं और सम्मान प्राप्त करने वालों का चयन करने में सर्वश्रेष्ठ अपने कोशिश और निष्ठा का परिचय दिया है, धन्यवाद देना चाहता हूँ।

मैं ऐसे अनेक प्रतिनिधियों का स्वागत करता हूँ जिनकी उपस्थिति इस वक्त में एक नवीनता है। जब से साक्षरता-पुस्तकार की स्थापना हुई है, पहली बार छपारोह में ऐसे लोग उपस्थित हैं जिनकी कुछ मात्र पूर्व ऐसे साक्षर-स्थो-पुष्टो में गणना की जाती थी जिन्हें कुछ भी अक्षर-ज्ञान नहीं था। मैं उनसे यह कहना चाहूँगा कि पूरा अन्तर्-द्वीप समार उनके प्रयास में आनन्द हीन छवि रहता है। मुझे माया है कि उनकी इस छपारोह में उपस्थिति से उन्हें नविनता में भी पढ़ने-लिखने की कला पर अधिकार प्राप्त करने में परिश्रम करते रहने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

अपने उदाहरणों पर परिलानों के लिए जो उन्होंने प्राप्त किये हैं, पुरस्कार - विजेताओं को मेरी हार्दिक बधाई है। शिक्षकों और सीने वाले की दृढ़ता तथा कुशलव्यवस्था

जो उन्होंने दिखाई है और जो त्याग उन्होंने किया है, व्यर्थ नहीं गए। वे लोग एक ऐसे दुनिया के अग्रदूत हैं जिसने अभी बलान की श्रृंखलाएँ नहीं तोड़ी हैं और जो ज्ञान की प्यासी हैं जिससे वह अपनी अभिव्यक्ति कर सके और विकसित हो सके। अपने प्रयासों में सगे रहने के लिए हम लोगों को, जो यूनेस्को में है, इनसे बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। इससे हमें यह माया होती है कि करोड़ों स्त्री-पुरुष अब इतिहास के कोने में नहीं पड़े रहेंगे।

यह मेरे यूनेस्को की ओर से विश्व के सभी राष्ट्रों के मत-करण से अवील करवा जाएगा। हर एक को अपने उद्देश्यों और कार्य देखी की परिभाषित करना है और मानवीय, आर्थिक तथा बौद्धिक सवाधानों को, जिनकी साक्षरता-कार्यक्रमों में इतनी कमी है, जुटाना है। उन्हें वह राजनीतिक इच्छा प्रदर्शित करनी है जो 'इरादों' की घोषणाओं की व्यावहारिक कार्य - बलाप में बदलती है। साक्षरता - कार्यक्रमों के लिए निर्धारित बजट के साथ सामंजसिक व्यवस्था के सदस्य से परीय रिश्तेदारों-भाध्य-बहार में किया जाय। जो राष्ट्र इस प्रकार का कदम उठाएँ, उसके नागरिकों की प्रतिक्रिया प्रेरणा-प्रद होगी और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उस राष्ट्र का स्थान बहुत ऊँचा हो जाएगा।

प्रौढ़-शिक्षक की तलाश है

(बाबूराम अग्रवाल, सहायक शिक्षा निदेशक, वीरपुर हाउस, मदनग)

प्रौढ़ शिक्षक की तलाश है। प्रौढ़ों को पढ़ाना है। प्रौढ़ों की उम्र १५ से १५ के बीच में है। इनमें कुछ तो हैं। पहिलाएँ भी हैं। अधिकांश गाँव में रहते हैं। कुछ शहर में रहते हैं।

ये प्रौढ़ वे लोग हैं कि जब इनकी पढ़ने की उम्र थी, तब पढ़ते नहीं पढ़ा। गाँव में प्राइमरी स्कूल था। तीन-तीन, चार-चार मास्टर थे। पढ़ने के लिए समय था। तब पढ़ते नहीं पढ़ा और न इनके मा बाप (स्वयं निराक्षर) ने इनके पढ़ने पर कोई ध्यान दिया। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके परिवार में प्रौढ़ों से निराक्षरता जलो का रही है, घर में कभी कोई विताव नहीं आई।

ये निराक्षर प्रौढ़ बचपन में खेलते रहे या बरीबी के कारण घर भयबा क्षेत्र पर माँ-बाप के साथ काम करते रहे। छोटे भाई-बहिन को पिलाते रहे। जानवर चराते रहे। बैल घर रोटी पहुँचाते रहे। घास छीतते रहे। बीबी बनाते रहे। शहर में बुकान भयबा घरों में भोकरा करते रहे। माँ।

कुछ लोग स्कूल गये, तो इनकी गरीबी के कारण मास्टर ने तब पर ध्यान नहीं दिया। ये कहा। या ९ से भागे न बन सके। इन्हें स्कूल का भीरव वातावरण पसंद नहीं आया। स्कूल के सख्त अनुशासन में तो इनका बस घुटता था। ये मास्टर की डाँट और मार के डर से स्कूल से भागते रहे और बाहर दूसरी दण्ड खेचते रहे या बाप में बचकर चुराते रहे। कुछ को भी स्कूली अनुभव इतने दुःख रहे कि इन्हें पढ़ने ही के बिना हो गई।

यह है इनके बचपन का इतिहास। अब ये जगती में रोनी रोटी कमाने में जुटे हैं। पेट भरना भूमिगत पड़ रहा है। घर दन्ते पढ़ने की कुतरत कहीं है। ये निराक्षरता के भारी हो गये हैं। इन्हे साक्षरता का मोचित और अनग्न समझ में नहीं आता है। ये अब यह भी सोचने

लगे हैं कि इनके पढ़ने की उम्र निकल गई है। खुदें सीते भी कहीं पड़ते हैं।

ये प्रौढ़ व्यवसाय, कालि, धर्म और सम्प्रदाय के आधार पर विभिन्न वर्गों में बंटे हैं जिनमें आरक्षी प्रतिद्वन्द्विता, डेय, मजदूर और समाज समता रहता है। घर एक बात इन सब में एक सी है। यह यह कि ये शरीर और निराक्षर हैं और इसलिए इनकी सामाजिक स्थिति बहुत नीची है। ये उपेक्षित और साक्षित हैं, दलित और पीडित हैं। न तो किसी बात में कमी इनकी राय मांगी जाती है और न किसी निर्णय में इनकी सामाजिक क्रिया जाता है। इनमें कुबरे, धेतिहर मजदूर, छोटे किसान और छोटे-छोटे बन्ने में लगे लोग हैं। ये जीवन पर हर बात के लिए दुखरे पर निर्भर रहते हैं। निराक्षरता और गरीबी के कारण पच-पच पर इनके काम पड़ते हैं और जबह जबह वे ठगे जाते हैं। ये मारम-निर्भरता को चुके हैं। इनमें आर्य विराज नहीं रह गया है। ये अपनी दुर्बला को अपनी निवृत्ति साधकर रूपचाप स्वीकार कर चुके हैं। औरों की हानत और भी बचकर है।

प्रौढ़-शिक्षक की तलाश है की तब दोन-हीन प्रौढ़ों को इस प्रकार पढ़ावे कि इनकी सामाजिक और सामाजिक स्थिति सुधर सके। इन प्रौढ़ों में इनकी स्थिति, इनके सफ्टों, इनके अधिकारों, इनकी समस्याओं और इनकी सम्भावनाओं के प्रति चेतना बसल करनी होगी। इनमें आत्म-विश्वास और स्वाभिमान बगाना होगा। इन्हें व्यावहारिक ज्ञान विद्या ज़रूरी दिखे इनकी व्यावहारिक दक्षता बढ़े और ये अपने दैनिक कार्य सुपलतापूर्वक सम्पादित कर सकें। इन्हें छवि एवं जसोय की उन्नत विधियों, कानूनी अधिकारों, न्यूनतम वेतनों श्रद्धा-सुविधाओं, विकास कार्यक्रमों, स्वास्थ्य एवं विस्तार-केमों आदि की जानकारी कराई जायेगी। इन्हें साक्षर बनाकर

इहें पढ़ने की आवश्यकता नहीं आयेगी। इनमें पढ़ने का शौक पैदा करना होगा। ज्ञान और जानकारी जीवन में हर काम के लिए जरूरी होती है। साक्षरता ज्ञान का एक प्रमुख और स्थायी साधन है। गरीबों की प्रबुद्धता और सक्रियता ही यह सुनिश्चित कर सकेगी कि वो विभिन्न नीतियों, कानून और योजनाएँ उनके साथ के लिए अंजाम पा रही हैं, उनका साथ इन्हें मिले। इसके लिए इन्हें साक्षर और शिक्षित बनाना जरूरी है।

श्रीष्ठ शिक्षक की तलाश है जो उक्त प्रकार से सर्वोपयोगी लोगों को प्रबुद्ध एवं सक्षम बना सके और जो उन्हीं की मदद से समाज में रहता हो वहाँ के लोगों के बीच उसे काम करना है। वहाँ (गाँव/मूल्यों में) सबका अपनी कुछ स्थिति हो, अपना कुछ भय हो। कुछ लोग सबको बात मानते हैं। सबने गाँव में जनसेवा के कुछ काम किये हैं। गाँव गाँव, मूल्यों में शिक्षा केन्द्र खुलेंगे। एक केन्द्र पर १० प्रोड करने और एक शिक्षक पठायेगा। रोज दो घण्टे पढ़ाई होगी। कन्ट्रोल समय और स्थान पढ़ने वाली की सुविधा पर होगा। एक केन्द्र १० पढ़ाने वाले। महिलाओं के केन्द्र अधिक सुलभ। महिला शिक्षक अधिक चाहिए।

श्रीष्ठ शिक्षक की तलाश है जिसमें निम्नलिखित योग्यताएँ हो।—

—वह ऐसे व्यक्ति पर के लोग के नहीं, बल्कि जनसेवा की भावना से इस कार्यक्रम में भाग चाहता हो और इस कार्यक्रम की कमिटाइयों को समझता हो। उसे बेतन नहीं, बल्कि सम्मान २०-२५ मासिक मानदेय मिलेगा।

—वह सच्चा और ईमानदार हो। झूठ का सहारा न ले। उसे छोटी बेवड़ा और बेपर्वाई को पढ़ना पड़ेगा।

—उसके दिव्या, सदन, व्यवसाय और व्यवस्था की भावना हो।

—उसे समझता और सामाजिक मूल्य में विश्वास हो।

—वह बुद्ध-सहस्री एवं शाही हो और भावों, मूल्यों और मानवताओं की स्थापना एवं रक्षा के लिए सक्षम कर सके।

—वह अपने विचारों का हो। ईमानदार हो। दूसरों की बात ध्यान से सुनता हो। विचारों में परिवर्तन के लिए तैयार रहता हो। कल्पनाशील हो। व्यावहारिक हो। पढ़ाई कर सके।

—वह प्रोत्साहन के दायरे, भावनाओं, भावनात्मकताओं एवं समस्याओं को समझता हो। वह जानता हो कि प्रोड कैसे होता है। उसे प्रोड शिक्षा के विद्यार्थी, विधियों और विचारों का ज्ञान हो।

—उसे निरंतर प्रोत्साहन की समझ हो कि ये सीख सकते हैं।

—उसे इस कार्यक्रम की सफलता की आशा हो।

—उसके हृदय में गरीबी के लिए व्यापक हो। वह गरीबी को दूर करने के लिए उन पर दया नहीं, उनसे व्यापक करे।

—वह विनम्र हो। प्रोड को छोटा ग समझे। उन्हें आदर दे। गुरुका सम्मान करे। गुरु शिष्य की भावना न हो। मित्र मित्र का सम्मान हो। प्रोड निरंतर और गरीब बन रहे, पर कई बातों में वे शिक्षक से अधिक जानकारी और अनुभव हो सकते हैं। शिक्षक को उनसे सीखना। शिक्षक और प्रोड दोनों एक साथ मिलकर सीखेंगे।

—वह कम से कम कक्षा ८ पास हो। उसे पढ़ने का शौक हो। उसने खूब पढ़ा हो। वह रोज खसबार पढ़ता हो। वह बावर्द्ध हो। कक्षा-वर्ग में कुशल हो। प्रवृत्तिपूर्ण अच्छी कक्षाएँ और समझाएँ सुना सके। बौद्धिक चेतना सज्जता हो। व्यवसायिक प्रोड को हुंसा सज्जता हो। शिक्षक उपदेश नहीं देगा। श्रम नहीं करेगा। समाज और परिवर्तनों से केंद्र को बचाना देगा वहाँ प्रोड हुंसा केसों, गायों केसों, एवं गायों और सीखेंगे। सीखना एक जीवनोपयोगी, सर्वोपयोगी एवं रोचक अनुभव होगा। प्रोड में एक तत्त्व-संज्ञा एवं विवेकानात्मक दृष्टिकोण का विकास होगा।

—उसे विभिन्न विचार-कार्यक्रमों की जानकारी हो। वह अधिकारी और नेताओं से बात कर सके। विभिन्न विकास-कार्यक्रमों को केन्द्र पर लाकर उनकी जाँच कर सके और विभिन्न विचारों से मिलने वाली सुविधाओं को ज्ञान करने में प्रोड की सहायता कर सके।

—वह प्रोडों की रास्ता ही न बताये, उन्हें रास्ते पर चलना भी सिखाए।

—भावनात्मकता पढ़ने पर वह प्रोड के साथ भावना, व्यवसाय, भावनात्मकता दण्डर आकर उच्चता काम कर सके।

—वह प्रोडों की बौद्धिक प्रगति का मूल्यांकन कर सके और उसका विकास कर सके।

—वह सर्वोपयोगी एवं अन्य अधिकारियों से बराबर संपर्क बनाये रखे। वह केन्द्र की प्रगति और दृष्टिगतों में उन्हें सज्जता बताये और उनसे मार्गदर्शन लेता रहे।

—बात में, वह ऐसा हो कि प्रोड को उसके पास जाना अच्छा लगे, उसकी बात सुनना अच्छा लगे और उसके बात करना अच्छा लगे। *

उत्तर प्रदेश नयी तालीम समिति के उद्घाटनार्थ

‘नयी तालीम’ पत्रिका

के प्रकाशन पर हार्दिक शुभकामनाएँ

उत्तर प्रदेश गाँ० स्मारक निधि सेवापुरी * वाराणसी

गुठी, ऊनी, रेणुमी, सादी, रबन, तारपीन का तेल, सूती, चपड़ा, चमड़ा जामान, रिशतलाई, साबुन, रोम, कुम्हारों बर्तन तथा आवश्यक चीजों के उत्पादन एवं विहोता।

जिल्ला स्तर — दीदी बाग बाराणसी, सोहरा, दुर्ग, विर्गपुर बाहर, बसप्रकाश नगर, बलिया, कमठा (देवरिया) मुन्तानपुर, करछना, मोरवा (सुल्तानबाद) गोहाद, मगरोड (हमीरपुर) गाँधी भवन सचनक धावस्तो (बहराच) शाखापुरी (पीलीभीत) मोरा धनीना (बहारनपुर) धावपुरी, धनीना, कोसानी (बनधोरा) तथा बहराच

उत्तर प्रदेश नयी तालीम समिति के उद्घाटनार्थ

‘नयी तालीम’ पत्रिका

के प्रकाशन पर हार्दिक शुभकामनाएँ

गाँधी भवन महात्मा गाँधी मार्ग

लखनऊ

दीदी सचनानय, पुस्तकालय एवं वाचनालय गाँधी विचार के सर्वप्रथम, पुस्तकों एवं विचारों के लिए सुयोग्य माया से प्राप्त पुस्तकें, चित्र, एवं चोटों के प्रकाशन एवं विहोता।

समाज की चमरौटियां

स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय
 समाज की ये चमरौटियां हैं,
 जहाँ अस्पृश्य नौजवानों की
 मणसे अक्षय
 एक पस्ती पहाई जाती है।
 वहाँ ऐसे कारोबार रहते हैं
 जिनके हाथ-पैर नहीं चलते
 और जिनको निर्धन ज़मान चलती है।
 उन्हें काम-काज को फूल समन्द नहीं,
 उन्हें बहार के फूल समन्द नहीं,
 वे मर-दबोय हैं जैसे कृष्ण बाला ही,
 वैसे ही ज़िन्दगी के उन पर कोई निशान नहीं।

०६३

नयी तालीम



अन्तर्राष्ट्रीय शासक वर्ष

ग्रौढ़ शिक्षा की प्रगति

अखिल भारत नयी तालीम समिति का प्रस्ताव

शुनिषादी शिक्षा शंकाएं और समाधान

ग्रौढ़ शिक्षा का विकास

हमें बहुत क्यों समाप्त करना है



अखिल भारत नयी तालीम समिति

मार्च १९६६
दिसम्बर
जनवरी

अंक ३
३

प्रधान सम्पादक	—	श्री के० प्रध्यापतम्
सम्पादक मण्डल	—	श्री द्वारिका सिंह
		श्री बन्धू माई पटेल
		श्री नानो नाथ त्रिवेदी
		श्री ज्योति माई देसाई
सम्पादक	—	डॉ० देवेन्द्र दत्त तिवारी
सह सम्पादक	—	श्री चन्द्रशूदन

सम्पादकीय

आन्तराष्ट्रीय बाल वर्ष

ग्रीक शिक्षा की प्रगति

अन्तराष्ट्रीय बाल वर्ष

श्री सद्गुण शर्मा

पृष्ठ १

अखिल भारत नवी तालीम समिति का प्रस्ताव

३

कुनिबादो शिक्षा संकाय और समाधान

बांधी जी

४

ग्रीक शिक्षा का विकास

श्री जीवन नाथ

५

हमें स्कूल नवी समाप्त करना है

अनुवादक डॉ० देवेन्द्र दत्त तिवारी

१०

आदरणीय धीरेन्द्रा की स्मृति में

दिनोबा

११

ग्रीक शिक्षा

कोठारी शिक्षा आयोग की रिपोर्ट

१६

दिसम्बर — जनवरी, ७८-७९

नवी तालीम का वार्षिक पुस्तक—बारह रुपये तथा एक अंक का मूल्य दो रुपये है ।

पत्र व्यवहार के लिए सुधी पाठक कृपया अपनी ग्राहक पहचान अवश्य लिखें ।

पत्र व्यवहार के लिए पता — सम्पादक नवी तालीम, सेवापुरी, (वाराणसी)

नवी तालीम में व्यक्त विचारों का सम्बन्ध पूर्वतया लेखक का है ।

सम्पादकीय

अन्तर्राष्ट्रीय बाल-वर्ष

१९५६ में समुक्त राष्ट्र संघ ने बच्चों के कुछ अधिकारों की घोषणा की थी जिसकी परिणति इस नियम में हुई कि १९७६ को अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष घोषित किया जाय। इस प्रकार ॥ वर्ष मनाने का उद्देश्य यह होता है कि प्रत्येक बाल बचपन पर सभी राष्ट्र समुचित ध्यान दें।

स्पष्टि यह है कि गरीबों के अनेक अधिकारों में एक अधिकार यह भी है कि वह देशी सत्ताओं की आज देती है जिससे गरीबी में निरन्तर बढ़ती जाय। जब बच्चों को पौष्टिक भोजन नहीं मिलेगा तो उनकी शारीरिक तथा मानसिक विकास नहीं हो सकेगा और सबसे दुखद बात यह है कि संस्थान का विकास अव्यवस्था हो जाता है जिसके दुष्परिणामों से जीवन भर मुक्ति नहीं मिल सकती, अतः ही आज में कितना भी पौष्टिक भोजन क्यों न दिया जाय। आज देश में प्रतिवर्ष १२००० मरते हो जाते हैं और १४ करोड़ बच्चे (१-५ आयु वर्ग के) राग के लक्षणों से मुक्त दिखाई पड़ते हैं। इनमें ५० प्रतिशत वर्ग ५ करोड़ बच्चे रक्तमार्ग के दोष से ग्रस्त रहते हैं।

यद्यपि गरीबी के कारण बच्चों का समुचित विकास असम्भव है, फिर भी गरीब माता पिता की स्वास्थ और सफाई की कुछ जानकारी हो आज तो बच्चों के विकास में सुधार सम्भव है। शिक्षकों का इस क्षेत्र में विशेष योगदान हो सकता है। सभी की से कहा जा कि सफाई सुनिश्चिता शिक्षा का प्राण है। यदि शिक्षा से सम्बद्ध लोग इस समस्या की ओर ध्यान नहीं देते तो शिक्षा का प्रविण्य बच अव्यवस्थापूर्ण हो जायगा, क्योंकि जब ऐसे बच्चे विद्यालयों में जायेंगे जिनमें संस्थान और शरीर के विकास में अवरोध के कारण कोई सुधार सम्भव न हो सकेगा तो शिक्षकों के लिए बहुत कुछ करना होगा न रह जायगा। इसलिए आवश्यक यह है कि शिक्षक वर्ग शिक्षा में सभी शक्ति विचार करके कोई योजना क्रियान्वित करें जिससे गरीब और दाम के अग्रणी बच्चों का जीवन सुखमय हो सके और सभी देश का अधिकार उन्नत हो सके।

प्रौढ़ शिक्षा की प्रगति

राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा योजना की घोषणा के अन्तर्गत वर्ष १९७५-७६ मुख्यतः तैयारी का वर्ष है और यह समाप्तमय है। तैयारी नई शिक्षाओं से होती थी—प्राथमिक व्यवस्था, मिश्रण सामग्री, प्रशिक्षण की व्यवस्था, माता-पिता तैयार करना आदि। अभी तक प्राथमिक व्यवस्था का प्रश्न है प्रौढ़-शिक्षा-अधिकारियों की विभिन्न स्तरों पर नियुक्तियाँ हुई हैं। राज्य स्तर पर प्रौढ़ शिक्षा-समितियों का गठन भी हुआ है। किन्तु सर्वाधिक महत्वपूर्ण तैयारी विकेंद्रित व्यवस्था की भी विषये क्षेत्रीय, जनपद, तहसील तथा ग्राम स्तर पर समिति बनाई करके और विभिन्न अधिकारियों के कार्यक्रमों में समन्वय की व्यवस्था करना अनिवार्य था। प्रौढ़ शिक्षा-कार्यक्रम की तैयारी में यह बड़ी कमजोर रही है। इसलिए आगे क्या होगा कहा नहीं जा सकता।

जहाँ तक वादग्रहण और विचारण सामग्री सेवार करने का प्रश्न है, इस दिशा में कुछ वादग्रहण निर्धारित हुआ है और विचारण सामग्री भी सेवार की गई है। किन्तु यह प्रौढ़-विचारण की सामग्रियों को देखते हुए न केवल अपर्याप्त है प्रत्युत अनुपयुक्त भी है। कारण जैसा कीछारी समीक्षण ने कहा है कि प्रौढ़-ज्ञानार्जन व्यक्तिगत प्रक्रिया है। कोई एकक या वादग्रहण या विचारण सामग्री निर्धारित नहीं की जा सकती। एक ही प्रौढ़ विचारण के ३ पर विभिन्न योग्यताओं सामग्रियों में प्रौढ़ आपणें। एक जैसी सामग्री सबके लिए उपयुक्त नहीं हो सकती। स्थानीय स्तर पर वादग्रहण तथा विचारण-सामग्री सेवार करने की सामग्री उत्पन्न करना आवश्यक था।

प्रतिक्षण की जो व्यवस्था की गई है, वह तो अपर्याप्त सम-तोषजनक है। जो विषय में जानकारी नहीं है, वे प्रतिक्षण वे रहे हैं, जिनकी कार्य में रुचि नहीं है वे प्रतिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। प्रौढ़-विचारणों के लक्षित चुनाव पर दल दिया गया था, वह प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है।

जहाँ तक वातावरण सेवार करने का प्रश्न है, इसका भी कोई कारखाने से निर्माण नहीं हो सका। जन-आन्दोलन के लिए अदृष्ट चेतना तथा प्रतिरोध में उत्पन्न आवश्यक था, किन्तु दुर्भाग्यवश राजनीतिक परिस्थिति में अनुकूल न होने के कारण वातावरण नहीं बन सका।

सेवारी के सम्बन्ध में अतिरिक्त बात यह है कि यद्यपि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने लक्ष्य शिक्षा की संस्थाओं को इस कार्य में मदद के निर्देश दिए हैं किन्तु विश्वविद्यालयों पर कोई प्रभाव नहीं हो सका है। इन परिस्थितियों को देखते हुए यहाँ कहना पड़ता है कि सेवारी के वर्गों की स्थिति अपराजनक नहीं है।

अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष

यदुनाथ शर्मा

पहली जनवरी से ११ दिसम्बर, १९७८ तक अन्तर्राष्ट्रीय बालवर्ष मनाने की दुनिया भर की देशों में सँघारियाँ हो रही हैं। आमतौर पर सरकारें ही इसमें अग्रभूमि करेंगी, ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन सरकारी काम करने का अपना एक ढंग होता है, वे अपनी ओकरखाही पर श्रितना मरोटा करती हैं उतना जनता के ऊपर नहीं करतीं, फिर चाहे वह सरकार लोकशान्तिविक हो वा एक-विचारकारी। इस दृष्टि से सम्भव है कि अन्तर्राष्ट्रीय बालवर्ष की वहाँ एक सरकारी प्रदर्शन नाम म बन जाय। सरकारी तन्त्र की एक विशेषता यह है कि वहाँ हर बात विमल से हुमा करती है। केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को सूचना देती, फिर राज्य सरकारें जिला परिषद, नगर परिषद, ताबुका बचावत और अन्त में ग्राम पंचायतों तक सूचनाएँ पहुँचायेगी और सम्भव है, अन्तिम कड़ी तक दूसराएँ पहुँचने - पहुँचने दिसम्बर ११७८ या तो वा बायेला अवस्था भीत जायेगा। क्या इस अन्तर्राष्ट्रीय बाल-वर्ष से आम जनता का कोई सम्बन्ध नहीं है? जगता इस वर्ष क्या हुआ नहीं कर सकती?

जनता अवश्य ही कुछ कर सकती है और जनता के काम करनेवालों को इस दिशा में अपना अधिकतम दिशाना चाहिए। गांधी तथा सर्वोदय विचार में अन्तर्गत एकले वाली का दावा अन्तर्गत सगठन होने का है। वे मानते हैं कि वे लोक पक्षि की जागृत, उदबुध तथा सगठित रूप देने में जुटे हुए हैं। अतः उनका दायित्व अधिक बढ जाता है। सभी हस्त में एक सम्जन ने कहा कि 'द बिनेट रकट्टो इन द बर्ड्स इज डेप द-बर्ड्स'—दुनिया में सबसे बड़ा उद्योग अंगर है तो मारकाट का है। सुधदा और व्यवस्था के नाम पर बहुत सब आज हो रहा है और दिन-ब-दिन उसमें वृद्धि हो रही है। अंगर में सरकारें बातवर्ष मनानेगी और अंगर व्यवस्था बनने में पंता भी

बन करती रहेगी। सरसक के नाम पर बनने वाले उद्योगों में जो सचें आज होता है उसका भौतजन प्रत्येक व्यक्ति के पीछे सगमम ५००) २० हैं लेकिन दूसरी तरफ दुनिया की बाकी भावार्थों की बापिक गाप इतने बाधी है। मानव विचारशील प्राणी माना जाता है। जीवन की आ विवदति को देखकर, उसे दूर करने की दिशा में कुछ कदम उठेंगे?

एक कदम यह हो सकता है कि यू० एन० ओ० के महासचिव तथा अपने राष्ट्र प्रमुखों के बाध इस आगम के निवेदन अपने अपने हस्ताक्षर करके भेजें। वे माँग करें कि सेना तथा पुलिस पर होने वाले सचों की बाध प्रतिशत घटाया जाय। कम और अमरीका सावनास निमाँ से जो सचें कर रहे हैं उसको अंगर इस तरह घटाया जाय तो दुनिया-भर के कस्बाएँ कार्यरत अपने गुणाव रूप से चल सकते हैं। लेकिन छोटे सेरा भी अपने दरवाजा सचें को घटाने के सिने लँघार न हो तो जनता नैतिक दबाव बने बेसी पर नहीं पड़ेगा। ऐसा हस्ताक्षर अमिधान अंगर इस वर्ष में चले तो सम्भव है कि नया मानव रहेगा।

दूसरी बात है अवस्था वृद्धि की। जनसंख्या वृद्धि को अंगर न रोका जाय तो मानव कस्बा की कोई योजना नहीं बन पायेगी, इतना ही नहीं मानवीय मूल्य भी ध्वस्त हो सकते हैं। इस सम्भावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अंगर पैदा होने वाला मालेक नया मानव येरी रोटी छीनेवा, येरा कपड़ा चीन लेगा, येरे घर में ऊँट की तरह घुसकर खुसे हो एक दिन बाहर निवास देगा, ऐसी स्थिति हो जाय तो मानव मानव की सगा नहीं, बैरी मानने लगेगा। यह ही अगली अवस्था हो जायेगी। समय से अंगर सस्था सगठित की वा सके तो बड़ी सुधी की बात है, अंगर नहीं सगता है तो रोटी जिस तरह इलाज करवाता है वैसे इलाज करवाने की लँघारी रखने में

अवश्यही है। दुनिया की आज की जनसंख्या ४०० करोड़ के करीब है और जनसंख्या - वृद्धि अगर आज की तरह बेरोकटोक होती रहती तो सम्भव है कि पचासवीं के अन्त तक यह ८०० करोड़ न हो जाय। ऐसा हुआ तो प्रकृति का समुत्पन्न बिगड़ जायेगा और पृथ्वी वीरान हो जायेगी। वैज्ञानिक, व्यासजी की बातें तो से हमको भायाहूँ कर रहे हैं। यह रहे हैं कि सन्ध्या वृद्धि रोक लो, नहीं तो यह समुत्पन्न से भी एक संभावक बरसकना संभव होगा। तब नये बच्चे का स्वागत नहीं होगा और आदमी मर जाय तो लौग कहेंगे, भगछा हो क्या एक जना हमारे लिए के हुंटी। यह तो अमानवीय निश्चित होगी। दूसरे बच्चों के जिन मानवीय मूल्यों का विनाश हमने किया के सब मूल्य बर्बाद हो जायेंगे। स्वायत्तता-समता एका ध्युता के लिये कोई अवकाश नहीं रहेगा।

महिलाओं की दृष्टि से ये दो बातें अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं, विश्व स्त्री-शक्ति-सम्मेलन की संघारो में बहने लगा है। बहुपारिणीतियों के अन्वय को हम परा छोड़ दें, लेकिन सर्वसामान्य स्त्री-अर्थ अपने को बड़ा अहमर्ष वा रही है। ऐसी कौन माता होगी जो अपने बालकों के सर पर तलवार टेंगी देखना चाहेंगी? जिसने अपनी सम्मान के चम की आया मेदनाओं को लड़ा और कृत्रिमों का अनुमन किया वे अपनी सम्मान पर मृत्यु का साध जाना कभी बर्बाद नहीं कर सकेंगी। उनको अपनी आवाज

बस-बद करके दुनिया की सभी सरकारी से बहना चाहिए कि अगर संप्रभुत्व आज बाल-वस्थाएं चाहते हैं तो उन्हें लिये पॉन्ड फोसटो फास्फोरस के कार्य पताओ और इसी राशि बाल-वस्थाओं के लिए उपलब्ध करो। यह लही विषय में परना ब्रह्म होगा।

सदा हुआ मातृत्व प्रविष्टि अस्थापार ही मानना चाहिए। ऐसी कोई सत्ता गायन ही होगी जो अपने बालकों को दारिद्र्य, विषमता, भ्रष्टाचार, गुलामी तथा बंद की परोहर देना चाहेंगी। उताओं की उम्मा मर्वादा से अधिक हो तो उनकी छीन से देखाऊँ ल गयीं हो उनको। अतः जैसा कि गांधीजी ने माइरेट सेंसर ॥ कहा था—“अद्वैत पक्ष को न कहने की शक्ति उसने मानी चाहिए” गांधीजी की स्त्री-शक्ति की वस्त्रवा ऐसी थी। ना कहने की सत्ता-इही शक्ति उनमें आ जाय तो सत्ता सत्ता मर्वादि करना संभव होगा। लेकिन सरासरी शक्ति की कचोटी के नाश पर जनसंख्या-वृद्धि के लिए कारण नहीं बनना चाहिए। इस बोध से बच कर भी वह जसोरी कर लवती है। विश्व स्त्री-शक्ति-सम्मेलन का काम करते हुए इन बातों के बारे में समान की सामधान करने का काम की करना चाहिये। ऐसा करता है बाल-वस्थाओं के बारे में स्त्री-शक्ति कमो और सत्तावधानी नहीं कर सकती।

अखिल भारत नयी तालीम समिति

दिनांक ११ अगस्त १९७८ को सेनाग्राम में हुई अखिल भारत नयी तालीम समिति की बैठक में पारित प्रस्ताव—

‘दिनांक १६७७ में दिल्ली में हुए राष्ट्रीय विद्या सम्मेलन के बाद से भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा और प्रौद्योगिकी शिक्षा इन दोनों के परिष्करण की दिशा में किये गए प्रयासों के निष्पत्ति के पश्चात् समिति उसका स्वागत करती है। ममानव ने प्राथमिक शिक्षा के सर्वे सामान्यीकरण तथा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी शिक्षा के कार्यक्रम की योजना को इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि १५ (विकसित) से २५ वर्ष की आयु के बीच के लगभग १० करोड़ अधिलिखित उसमें समाविष्ट हो जाते हैं। सभी प्रदेश तथा देश की बहुत बड़ी संख्या में ईर्ष्यासक्त समाप्त भी इस दिशा में प्रादेशिक तथा शिक्षा स्तर पर योजनाओं को विकसित करने के लिए प्रेरित की गई हैं।

विश्व विद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उच्च शिक्षा की प्रगति के लिए की गई सिफारिशों पर भी यह समिति सज्ज है।

‘शिक्षा की प्रगति हमारी प्रत्येक स्तर पर उपलब्धकारी शासकीय के सम्यक अध्ययन के पश्चात् समिति अनुभव करती है कि सरकार द्वारा किये गये उपर्युक्त प्रयास यद्यपि स्वागतार्ह हैं फिर भी वे वांछित सामाजिक परिवर्तन नहीं ला सकेंगे क्योंकि सरकार शिक्षा को प्रणाली में ही परिवर्तन माने। कार्य की उच्च बरीयता नहीं देती। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी शिक्षा कार्यक्रम इस तरह नहीं बनाया गया है कि वह सब संभावित समुच्च के जीवन की दीनविन समस्याओं को सुलझा सके। जो छात्रों और सामान्य जनता के साथ उसका संबंध है। उसी प्रकार,

सामाजिक उपरोधी उत्पादक कार्य यद्यपि मुनिपायी तालीम दर्शन से विभाजित है फिर भी सम्पूर्ण शाखा प्रणाली के विषयानुसूची होने से कारण उनमें बहुत कम अंतर हो जाएगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उच्च शिक्षा के नीति निर्धारण सम्बन्धी सुझाव भी कागज पर ही रह जाने सम्भव है क्योंकि देश में विश्वविद्यालय भी कक्षाभिमुखी रहे हैं। जब तक उच्च शिक्षा, कमबोरी तर्ग के लिए कानूनी की सुविधा का लाभ बाधक अधिक दृष्टि से सामान्य विचार नहीं बनाई जाती, तथा जब तक मोहरी पाठों की शक्तों से समाविष्टों का सम्बन्ध विच्छेद नहीं होता तब तक उच्च शिक्षा अनुत्पादक और परामर्शी या परोपकारी ही बनी रहेगी।

‘इसलिए यह समिति भारत सरकार से पुरजोर अपील करती है कि वह शिक्षा की वाय की जीवन की वास्तविकता तथा छात्रों और प्रामाण्य जीवन की सामाजिक उत्कर्ष और प्रगति के साथ जोड़े। संघ के प्रति कार्सीन अधिवेशन में भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति विषयक प्रस्ताव शिक्षा नीति में परिवर्तन करने वाला हो न कि केवल शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर उसके ढांचे या सामग्री में परिवर्तन लाने वाला या दोनों में कुछ परिवर्तन सुझाने वाला मात्र हो। समिति आशा करती है कि भारत सरकार उस जनता को सामाजिकशास्त्र और मरणात्मा की ओर पूरा ध्यान देगी जो जीवन चाहती है, काम करना चाहती है। जनता शोषणहीन प्रजातन्त्रीय समाज चाहती है, तथा ऐसी शिक्षा प्रणाली चाहती है जो उसके आविर्भाव और मरण-प्राप्ति में निरुत्थरक प्रभावक हो। वह शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति के प्रस्ताव का शिक्षा के आदर्शों के अनुसरण होना

आवश्यक है। समिति परिवर्तन समय से साने सम्बन्धी निम्नलिखित सिद्धांत एवं मुक्तिप्राप्त सुझावों हैं—

(अ) प्रत्येक शिक्षा संस्था को पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन सम्बन्धी स्वायत्तता।

(आ) दोन मूलभूत मूल्यों पर जोर ॥ वे पहले अध्ययन पाठ्यक्रम।

(i) मातृ-निर्गौरवता, आत्म-विश्वास तथा औद्योगिक कार्यक्रम के अन्तर्गत काम द्वारा अपनी प्रतिष्ठा।

(ii) समाज सेवा के सर्वप्रथम कार्यों में शामिल किये जाने के माध्यम से छात्रों में राष्ट्रीयता और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना का निर्माण।

(iii) वैज्ञानिक और पारिवारिक मूल्यों को मन में बैठाना तथा धर्मों की एकता तथा सब धर्मों का समान रूप से मान्य करने की आवश्यकता को उचित रूप से समझना।

(द) विकेन्द्रीकृत शासन, जिसमें सरकार का कम से कम हस्तक्षेप हो।

(ई) उच्च शिक्षा में बांधी विचारों का अध्ययन, महिला और शान्ति छोड़।

(उ) शौकरी की शक्तों से उत्पादियों का सम्बन्ध बिच्छेद। साथ ही जो उद्योग, व्यवसाय तथा सरकार में आया चाहते हैं उनके लिए उत्पादि रहित पाठ्यक्रम प्रणाली।

‘शिक्षा की प्रगति का पर्यवेक्षण और मूल्यांकन करने तथा समय-समय पर उसकी प्रगति का सैद्धांतिक-बोला प्रस्तुत करने और मार्गदर्शन करने के लिए

(ऊ) वैज्ञानिक स्वायत्त राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन जिसके अधिकारों का अर्थ है वैज्ञानिक संस्थाओं के हों।

‘इसी प्रकार की परिषदें प्रादेशिक स्तर पर भी बनीं की जाएं।’



बुनियादी शिक्षा : शंकायें और समाधान

गांधी जी

[सर्वप्रथम में गांधी जी की पंचहत्तरवीं वर्षगांठ मनाई गई। इस अवसर पर तालीमी राष्ट्र के प्रतिनिधि गांधी जी से मिलने आये। उन्होंने गांधी जी से बुनियादी शिक्षा के सम्बन्ध में जो बातें की, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण संकलित बातें यहाँ दी गई हैं।— सम्पा.]

शंका। यदि बालक और बालिकाओं, दोनों के लिए पर्याप्त स्थान न हो तो तो क्या मात्र बालिकाओं के लिए ही बेसिक पाठ्याभ्यास संकेतक उचित है?

समाधान : (गांधीजी ने कोई आपत्ति नहीं उठाई। उन्होंने कहा) मान नीति के लिए करोड़ों बालक

बाते हैं। क्या हमें स्थानाभाव के कारण उनको शिक्षा देने में इन्कार कर देना चाहिए? मैं मुझसे कहता हूँ कि मैं इन्कार नहीं करूँगा। यदि आवश्यक हुआ तो मैं उन्हें एक गुँथ की छाया में बिठा दूँगा और उनके हाथों में बाँध दूँ। तब सारा ध्यान हीरे-सीमे उनके द्वारा उनको शिक्षा देना आवश्यक कर दूँगा।

(ग्रीक शिक्षा की चर्चा करने पर बायीं ओर से यह महसूस किया। स्पष्टतः बुनियादी तालीम के क्षेत्र में वृद्धि होनी चाहिए। उसके प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन के प्रत्येक चरण पर शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा का समानता होना चाहिए। उन्होंने कहा—) वैदिक स्कूल के सम्पादन को अपने जीवन की प्रत्येक स्थिति में सम्पादन सम्पन्नता चाहिए। जैसे ही हमारे व्यक्ति—एबी कक्षा पुष्ट—उसके सम्पूर्ण से कार्य जैसे ही उसे अपने मन से पूरना चाहिए—मैं इसे क्या शिक्षा दे सकता हूँ?

शिक्षा : क्या उसका इस प्रकार शिक्षा देना। विद्या विधान का सूत्रक न होगा ?

समाधान : नहीं। मान लीजिए, एक ऐसे बूढ़े से मेरी मेंट होती है जो गन्ना और मजदूरी है। अपने पाप को ही वह अपनी दुनियाँ समझता है। ऐसे व्यक्ति के प्रति मेरा वह कर्तव्य होगा कि मैं उसे स्वच्छ रहने की शिक्षा दूँ, उसकी मजदूरी दूर करूँ और उसके मानसिक स्थिति का विकास करूँ। मुझे उसके यह करने की आवश्यकता नहीं है कि मैं उसका सम्पादन हूँ। मैं तो उसके मस्तिष्क के साथ भीतल सम्पर्क स्थापित करने की चेष्टा करूँ और इस प्रकार उसका विश्वास प्राप्त करूँ। वह हमारी अनिर्दिष्ट बातों की मते ही उत्पन्न करे, लेकिन मैं हार स्वीकार नहीं करूँ। मैं अपना प्रयत्न सतत जारी रखूँ। जब तक मैं उसे अपना मित्र नहीं बना सकूँ। एक बार उपसर्ग मिलने पर वेप की पूर्ति होती रहेगी।

मुझे बच्चों पर ही उनके जन्म से ही दृष्टि रखनी होगी। मैं तो एक बच्चा और माँ के बच्चा और यह कहूँगा कि शिक्षा का काम तो इसके पहिले से ही आरम्भ हो जाता है। उदाहरणार्थ यदि रानी गर्भवती हो जाती है तो माता देवी उसके पास चारों ओर कहेगी मैं बँसी की माता हूँ जैसी तुम बननेवाली हो। मैं अपने अनुभवों

के आधार पर तुम्हें यह बता सकती हूँ कि तुमको अपने अन्तर्गत शिक्षा तथा स्वयं अपने स्वार्थ की सुरक्षा कैसे करनी चाहिए। वह उसके प्रति को यह भी बतायेगी कि सबका अपने पलों के प्रति क्या कर्तव्य है और उन्हें गर्मस्व शिक्षा की देखभाल में क्या भाग लेना चाहिए। इस प्रकार वैदिक शिक्षा का सम्पादन जीवन के सम्पूर्ण क्षेत्र पर अपना प्रमुख स्थापित कर देगा। ग्रीक शिक्षा को स्वभावतः उसके कार्य-क्षेत्र का अंग बन आसनी।

ग्रीक शिक्षा का कुछ कार्य अनेक स्थानों में हो रहा है। वह अधिनायक मिलवाली और उत्ती स्थिति के बड़े बड़े नगरों के लोगों के हाथों में केन्द्रित है। वास्तव में बाप को किसी ने रख नहीं दिया है। केवल 'दीन भार' की शिक्षा और राजनीति पर मायरा से मुझे सतोष नहीं हो सकता। मेरी रचना की ग्रीक शिक्षा में दुश्मन और स्वयं को शुद्ध नागरिक बनाना होगा, बच्चों के लिए साथ बच की शिक्षा का पाठ्यक्रम बनाने की अपेक्षा। ग्रीक शिक्षा का पाठ्यक्रम बनाना और उसके कार्य को सुम्पवर्षित करना सम्भव कठिन है। बीबी (प्रारम्भिक शिक्षा और ग्रीक शिक्षा) का सामान्य केन्द्रीय उद्देश्य राष्ट्रीय उद्योग के पाठ्यक्रम से शिक्षा देना होगा। बुनियादी तालीम के क्षेत्र पर ग्रीक शिक्षा ने कृषि को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होगा। अन्तराज की शिक्षा को भी स्थान मिलेगा पर बहुत ही बाले मौखिक हो शिक्षा प्राप्त होगी। विद्यार्थियों की अपेक्षा सम्पादन के उपयोग के लिए अधिक प्रसक्त होगी। हमें बहुमतवालों की यह शिक्षा देनी होगी कि वे सम्पन्नताओं के साथ और इसी प्रकार सम्पन्नता के सम्पन्नताओं के साथ केला व्यवहार करें। ग्रीक शिक्षा का उचित और सच्चा रूप यह है जो अपने परोक्षियों के साथ मित्र पुत्र कर देने की शिक्षा देता है और अनुभवता तथा साम्प्रदायिकता की बट बटता है।

प्रौढ़ शिक्षा का विकास

जीवन मायक

अंग्रेजी के भारत में आने के पूर्व यहाँ प्राचीन आचार्यों के मार्गदर्शन में एक उत्तम और सुव्यवस्थापित शिक्षा-प्रणाली प्रचलित थी। ई.पू. ६०० से ई.पू. ३०० के बीच इस प्रणाली में व्यवस्थापनानुसार परिवर्तन हुए पर व्यवस्था बनी रही। ई.पू. ३०० से ई.पू. १८५७ और ई.पू. १८५७ से ई.पू. १८६७ के बीच सामाजिक शिक्षा की स्थिति सीधे-सीधे रहो। जब ब्रह्मको की शिक्षा की ऐसी दवा दी तो प्रौढ़ों की शिक्षा पर कीमती ध्यान देना ? ई.पू. १८६७ से ई.पू. १९०० तक शिक्षा की स्थिति में उत्तरीतर सुधार हुआ और ई.पू. १९०० में शिक्षा को दिया और कार्यक्रम निश्चित किये जा गये। ई.पू. १९३७ में प्रथम बार सरकारी होने का बिल-संस्कार के इस और विशेष ध्यान दिया।

शिक्षा-व्यवस्था पतन की दृष्टि में मध्यम प्रायः सबसे अधिक बताया जाता हुआ। इस कारण यह स्वाभाविक था कि शिक्षा-प्रणाली का जोरदार आन्दोलन शुरू हो। प्रौढ़ों की शिक्षा का प्रारम्भ सबसे पहले मद्रास में ही हुआ। वहाँ हरिजनो के लिये प्रौढ़ - छात्राएँ खोली गयीं। किसान और मजदूर की इन शालाओं में आते थे। मद्रास के बाद बंगाल और सगुल-प्रान्त में भी प्रौढ़-छात्राएँ खोली गयी थी पर अनेक कारणों से अव्यक्त रही।

सबसे पहला कारण यह था कि प्रौढ़ों की शिक्षा का काम प्राथमिक शालाओं के शिक्षकों से ही लिया जाता था। ये बच्चों के स्कूल में दिन-रात बिना-विच्छेदों के जा आते थे और प्रौढ़-छात्राओं के आकर नींद भेते थे। कहीं-कहीं दली शिक्षकों की डाकपत्रों में भी काम करना पड़ता था।

एक शालाओं में प्रौढ़ों की पढ़ाई-लिखाई के लिये बड़ी साहित्य काम में लाया जाता था जिसे प्राथमिक छात्राओं के बच्चे पढ़ते थे। प्रौढ़ों के लिये विशेष प्रकार के साहित्य की आवश्यकता है, यह विचार केवल ईसाई धर्म-प्रचारकों

के मन में जाता था। ईसाई धर्म-प्रचारकों का ध्येय प्रौढ़ों में ईसाई-धर्म के प्रति आस्था जमाना हो था, परन्तु यह काम तब तक सफलता से नहीं चल सकता था जब तक उनमें निष्पक्ष-पक्षों की सामान्य योग्यता न होती। अपने स्वयं की पुन के लिये उन्होंने भारत की प्रमुख भाषाओं में बाइबिल के अनुवाद प्रकाशित किये। पाठकों के विचार में इनकी छात्राओं में भी सावधानी बरती। सरल भाषा और मोटे टाइट में छोटी-छोटी पुस्तकें तैयार कीं। प्रमुख भाषाओं के अतिरिक्त 'कोडिओ' में भी ये अनुवाद किये गये और देश के प्रमुख नगरों में स्थापित 'मिशन' प्रेसों में छापे गये।

ईसाई पाठों के प्रारम्भ में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के साथ प्रौढ़ शिक्षा का आयोजन पड़ी-पड़ी में हुआ। इस आयोजन में उपयुक्त पाठन-सामग्री पर ध्यान दिया गया और पुस्तकालयों की स्थापना की गयी। ई.पू. १९१९ में बंगलूर में प्रौढ़ों की राखि 'पाठशालाओं' को भी गयी। परिष्कृत पुस्तकालय भी स्थापित किये गये। 'मिशन' नामक एक पत्रिका प्रकाशित की गयी। इस तारे कार्य का लेख बंगलूर के तत्कालीन दोवाक सर एम० क्रिस्चियनरैंग को दिया जाता है।

नव सातहों के लिये साहित्य - गृहजन्म का विविध कार्य विहार में ई.पू. १९३६ में शुरू हुआ। वहाँ के तत्कालीन शिक्षा मंत्री डा० रमेश चन्द्र ने ऐतिहासिक चारे 'ईश्वर धर्म धर्म' के साथ काम शुरू किया। 'महमूद-सिरोज' के अन्तर्गत प्रौढ़ों के लिये तो पुस्तकें तैयार करायी गयीं। इस माना की प्रथम दो पुस्तकें थी- 'राजेश्वर हिन्दी प्रान्त-भर' और 'राजेश्वर खिबर'। इनके द्वारा प्रौढ़ों को अक्षर-ज्ञान कराने और भाषा - रहित चलन धारों के द्वारा सामान्य-वृत्तान्त बजाने का सरल प्रयत्न किया गया। भाषा की लेख पुस्तकों में सेती, पञ्चपावन, स्वास्थ्य, महा-

पुरो की जीवनो, आविष्कारों की तथा गृह-उद्योग, कृषि सम्पत्ति, परिवर्तनमार्ग की उद्देश्यता तथा नागरिकता आदि विविध विषयों पर प्रौढ़ नर-नारियों को ध्यान में रखकर छायावी दी गयी थी।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद देश में विकासोन्मुख परिवर्तन की गति तीव्र हुई। पञ्चवर्षीय योजनाओं द्वारा सर्वोत्तम प्रगति का मार्ग प्रणयना गया। वैज्ञानिक, औद्योगिक, सांख्यिक तथा स्वास्थ्य आदि विविध विकास आयक्रम बनाये गये।

यह विचारधारा स्वतन्त्रों हुई कि पञ्चवर्षीय योजनाओं में छायाधारण के हित सुख व उद्देश्य से निर्धारित विकास-कार्य की रूपरेखा है, जिनके रत्न बनता के हाथों के स्वयं से ही उभरने और समय वाक्य देग की छायापूर्ण का बहुरंग चित्र स्पष्ट हो जायेगा। यदि चित्र में रत्न करने वाले हाथों की कार्यकुशलता न बनाया गया तो तफ-मला कोमो दूर रहेगी।

हाथों की कार्यकुशलता उन्हें संचालित करने वाले मस्तिष्क के सहकार पर निर्भर है। मस्तिष्क का बड़ी सहकार अनुपम को मनुष्य बनाता है, ईशान्वित जीवन की शीत ज्ञानों वाली निरमलता से उसे मुक्त करता है, प्रज्ञा क्षमता, सामुदायिक और सौन्दर्य के साक्षात्कार से उसका प्रवेश कराता है, श्रेष्ठतर समाज-व्यवस्था के निर्माण में उसे प्रेरित करता है और मावी आयोजन के सिला-घात की सामर्थ्य प्रदान करता है। लोक-रीति नीति लोकोत्तम और लोकसत्ता तथा ऐसे ही अन्य उपाराय मुक्तानुपम से वे सहकार आपन्न करते रहे हैं।

सांसाजिक महत्त्व के सम्प्री को निष्पक्ष और साम-पिक भाकलन शिक्षा के व्यापक आयोजन के बिना अतथ्य है—एक मान्यता से प्रेरित होकर विभिन्न देशों में शिक्षा के आयोजन तब एक आरम्भ किये जा चुके थे।

इनसे साम उठाकर अपने देश में बंसी ही योजनाओं का सुवर्णत विद्या जाये, हृष्ट विचार से देश के जाने माने शिक्षा-शास्त्री चीन, मलया, इंडोनेशिया, फिलिपाइन, यमो और अमरीका आदि देशों की यात्रा करने गये। विदेशों में प्राप्त अनुभव के आधार पर उन्होंने यह बात

प्रकट किया कि प्रौढ़ शिक्षा समाज शिक्षा का ही अंग है, बसक नर नारियों को पूर्ण विकास-वास्तव नागरिक के रूप में प्रभावकारी व्यवहार-प्रणाली में दीक्षित करने के लिए समाज-शिक्षा का आयोजन बड़े पैमाने पर किया जाना चाहिये, प्रौढ़ शिक्षा केवल अल्प प्रौढ़ों के लिए ही आवश्यक नहीं है, प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य साक्षरता का प्रसार मात्र नहीं है नये विचारों को आत्मसात् करने की क्षमता उत्पन्न करना ही समाज-शिक्षा का उद्देश्य है और समाज शिक्षा का यहो महत्त्व है जो अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का है। जिस तरह प्राथमिक स्तर के बालक-बालिकाओं के लिये वैज्ञानिक ढंग से सिखे गये समुक्त साहित्य का गृहण परम आवश्यक है उसी तरह समाज शिक्षा में लिये गये साहित्य-गृहण का विविध अनुष्ठान जरूरी है।

इन शिक्षाविदों ने उन देशों का चित्र भी उपस्थित किया जहाँ कमबद्ध आर्थिक नियोजन की नीति अपनायी गयी है, जहाँ समाज-व्यवस्था की मिश्रित कर्म बदलने के चल चल रहे हैं जहाँ नागरिकों को नये सधिये डाकने की जरूरत पड़ी है और सर्व-साधारण की शिक्षा या 'इनिंग' जरूरी हो गयी है, जहाँ वैतकी बढ़ रही है और प्रौढ़ शिक्षा ने प्राथमिक शिक्षा का रूप ले लिया है। उस समुदाय की शिक्षा की आवश्यक हो गयी है जो काम-साज में लग है, जिसकी सधियार की परिस्थितियाँ जवा है, वाली है, जो कामकाज के सिलसिले में एक दूसरे के पूरक होता जा रहा है। लोगों को गुरुत है समय का पूरा पूरा लाभ उठाने की सिला देनी जरूरी हो गयी है; व्यवसायिक क्षमता बढ़ाने और जीवनमान उठा कर है। उद्देश्य से भी लोगों को शिक्षा दी जा रही है। मूल, सफ़े, अ-पे और सुपारसधो में सत्रा काटन बलि प्रौढ़ों के लिए विशेष प्रकार की शिक्षा आवश्यक हो गयी है। स्कूल और कलेज से शिक्षा वाक्य निरसने वाले शिक्षा-विदों को अपनी रधि और योग्यता का काम हुंते में कलियाई का सम्पन्न करना पड़ता है। उनके लिए विभिन्न देशों में ऐसे केन्द्रों की स्थापना की गयी है जहाँ उन्हें उचित मार्गदर्शन मिलता है और उनका कुशलता का समय किसी उपयोगी काम को सीखने में शीतता है।

सरकारी नौकरी में प्रवेश या जाने वाले अपने काम की योग्यता बनाया ही प्राप्त नहीं कर लेते। सरकारी काम-काज की जटिलता परिकल्पना की गति और महत्वपूर्ण पर आसोन व्यक्ति से अपेक्षित कार्यकी मर्यादा—इन बातों का ध्यान रखते हुए समय समय पर 'इन सर्विस ट्रेनिंग' दी जाने लगी है।

श्रीद्धी की शिक्षा के इन विशेष सेवा क अतिरिक्त, समाजों की जाति, राजपद की सुरक्षा, सकलकोनी धर्ममत गणनी का विकास, अनिवार्य से रखा, पीने के पानी की व्यवस्था, सरकारी नर्मचारियों की सहामता और विभिन्न विकास कार्यक्रमों में जन सहयोग आदि के लिए विशेष प्रकार की शिक्षा प्रणय अनिवार्य हो गया है। ऐसा प्रणय होने पर ही उस वातावरण का निर्माण हो सकेगा जो राष्ट्रीय प्रगति के लिए अनिवार्य है।

एक विशेषण को सामने रखकर 1938 से 1947 तक श्रीद्धी शिक्षा अध्याय समाज शिक्षा के विभिन्न पहलुओं की जांच विभिन्न राज्यों में हुई और सत्ता हस्तांतरित होने के बाद उन पर मनोयोगपूर्वक अगल किया गया। यद्यपि नर नारियों के लिए समाचार पत्र, किस्में और पुस्तकें तैयार करने की शिक्षा म जोरों से काम शुरू हुआ श्रीद्धी के लिए पुस्तकें तैयार करने के लिए लेखकों को आमन्त्रित किया गया। स्वाभ्यन्त सभाओं को अनुदान देकर इस क्षेत्र में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। अल्पकालीन दिवसों में काम करने के लिए अतिरिक्त परिश्रमिक देकर शिक्षकों की सेवाएं प्राप्त की गयीं। 'मिटरली हाउस' सञ्चालन से उठाया, बिहार एजुकेशन सोसाइटी की ओर से हिन्दी और मराठी में पाठ्य प्रकाश और रोपनी मध्यप्रदेश सरकार की ओर से हिन्दी और मराठी वैमानिक दीपक आदि पत्र पत्रिकाएँ श्रीद्धी के लिए छापी गयीं। मोटे टाइप में 16 पृष्ठों तक की सूक्तों रचीन पुस्तकें एवं निर्धारित पत्र के आधार पर की गयीं। श्रीद्धी की शिक्षा देने वाले शिक्षकों के मार्गदर्शन के लिए पद्धिपत्र तैयार की गयीं। संवाधान से इस क्षेत्र में आने वाले व्यक्तियों और मर्यादों के लिए मार्गदर्शक साहित्य विनयन: बम्बई और मध्यप्रदेश राज्यों में प्रकाशित किया।

श्रीद्धी शिक्षा की योजनाएँ विभिन्न राज्यों में बसाई गयीं इनमें मध्यप्रदेश सरकार द्वारा आयोजित समाज शिक्षा योजना को विशेष महत्त्व प्राप्त हुई। मध्यप्रदेश में उत्कालीन गृह-मन्त्री द्वाराकायदा मिथ उत्तम योजना के 'जलक' कहे जाते हैं। उनका नारा था—'सोशल रिकन्स्ट्रक्शन यू सोशल एजुकेशन'। श्रीद्धी शिक्षा अध्याय समाज शिक्षा के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश, बिहार, बम्बई और मध्यप्रदेश में सरकारी अथवा गैर-सरकारी प्रयत्नों के फलस्वरूप प्रकाशित साहित्य पर ध्यान देने में एक विचार बोध की आयोजित की और यह मत प्रकट किया कि मध्य-प्रदेश राज्य के समाज-शिक्षा विभाग के अन्तर्गत काम करने वाले साहित्य केन्द्र में श्रीद्धी के विचार से विविध विषयों पर हिन्दी और मराठी में जो साहित्य प्रकाशित किया है वह उपलब्ध और उपयुक्त है।

इस साहित्य की विशेषता यह थी कि इसके लेखन, मुद्रण, बिक्रय और विषय-वस्तु में पक्षी सुझ-बुझ से काम लिया गया था। नूतनपूर्व मध्यप्रदेश द्विभाषी-राज्य था, अतः द्वारा साहित्य हिन्दी और मराठी में एक साथ छापा गया था। यह साहित्य इस निर्देश के साथ बिना-सूझ बाँटा जाता था 'पक्षी और दूसरे की पक्षी दो'। श्रीद्धी का हिन्दी-मराठी वैमानिक दी रणो में मोटे टाइप के लोको पर छापा जाता था और प्रति भक की एक सप्तक प्रतिपां छपती थीं। शेष साहित्य नी पाठकों की सत्ता में उपयुक्त मुद्रण पद्धति से छपता था।

मार्ग सरकार ने नव साक्षरों के साहित्य-सृजन को प्रोत्साहित करने के विचार से नीचे तिली योजनाएँ शुरू की थीं :

(१) १९५० में शिक्षा मन्त्रालय ने द्वारा तालीम-ओ तरकमी नई दिल्ली का अधिक सहायता देकर पुस्तकें तैयार करायीं। अस्था में १७० पुस्तकें तैयार कीं, जिसमें से प्रत्येक की दस हजार प्रतियाँ छापी गयीं। इन पुस्तकों की प्रतियाँ राज्य सरकारों की बाँटी गयीं ताकि वे अपनी भाषाओं में पक्षी पुस्तकें तैयार कर सकें।

(२) १९५३ में शिक्षा मन्त्रालय ने साहित्य दिवस

[illegible]

(३) १९५४ में पिना राजस्थान के तब मालगुने के विप प्रमुख भारतीय भाषाओं में रचित सर्वोच्च साहित्य को प्रस्तुत करने के विचार से एक पाठ्यक्रम शुरू की थी। इस योजना अद्य भी चल रही है। इसके अन्तर्गत प्रति वर्ष पाँच-पाँच से नवह तक गुरुवारों पर आयोजित हैं। योजना को चलते हुए १८ आयोजित हो चुके हैं। इसको दो गुरुवार देते के अनिवार्य अथवा गुरुवार। सुमन की १९वीं प्रिय गुरुवार दिनांक विवरण के लिए मंत्री प्रकाश है।

(४) नव तारा जलता व मिठा पुष्पक तारा वरन
॥ मन्त्र-म म गुरेयो के मन्त्रम ह लीन प्रतिबोधित न
साधोमि की साधु ॥ १ ॥ इति भगवत कथा नि ॥
तमिल भोर उरु न रविन पुनः ॥ १ ॥ पुरस्कार मिता ॥
पुन हृष्ट धारोम भानधाम की मासाय मन्त्रायनी की एव
कान्ते के तिल मारन मरकार ॥ कुछ अनुमयान मन्त्राय
साधित की या ॥ प्रतिशालक मन्त्राय साधन मन्त्राय
मन्त्रायनी की जित नर मेरु के बाद नर माधो के मिला
उनी मन्त्रायनीक साधार वर माहि-य तवार विवा जाइ ॥

(२) भारत सरकार की प्राथमिक तद्गतता से निजी सहायता न ही दी जा सके व पुनः प्रशासन की है। इनके मुख्य ॥ राजा मरीचर (राज मरीच) और हिमालय विजयराज (राज मरीच) को है। यह दोनों विषयकोष हैं।

(६) १९५७ में मास्टर सरकार ने राष्ट्रीय पुस्तक योजना की स्थापना इस अभिप्राय से की थी कि पहले सभी के साधनमय सहयोगी पुस्तकालयों और सचिवालयों को राष्ट्रीय पुस्तक गलत हो सके।

१९५१ में भारत में ऐसे लोगों का प्रतिशत १६९ था जो केवल एक निवास करने थे। १९६१ में यह प्रतिशत २४० हुआ और १९७१ में २६४४। पञ्चवर्षीय क्रम में जो भी वृद्धि हुई है। १९६१-७१ के बीच १९-२४ लाख वृद्धि का साक्षर स्त्री युवा की संख्या १७६ करोड़ बढ़ी है। पश्चिमी योनि

के अन्वयन शीघ्र सिखा के निदे देते बरौद लाप का
 प्राथमान है जब कि शीघ्री योजना में यह प्राथमान ८
 बरौद भव्य हो गा ।

श्री ११११ का दायित्व राय सरदारों का है तो श्री
कृष्णजीय। वाचनक प्रारम्भ होना है कुछ वरके
उत्तर के लिए आज यह अवसर देना है। ८१ को मंगल
२०० वर्षीय मन्थन श्री ११११ व विभिन्न वाचनक
प्राप्त है।

विष्णु के पुत्र यशो के श्री गंगा व कापवना के
संसारना प्रसार पर उत्तमा इन गद्दी सिद्धांत रहा है
जिन्ना गृहनिर्माण की विद्या पर श्री विद्यापियों के
गवनाम रहा छद्म और उत्तम समाज की विवरण सूचना
भाव-वचनाओं में सूचना हो ।

वायस एजन्सल लिटरेसी प्रोद्यम १९१७-१८ में पाठ्यपुस्तक योजना के अन्तर्गत शिक्षा विभाग द्वारा बनाया गया था। इनके सहायक निदेशिका लिखानों को गांधीजी के विचारों के साथ ही साथ उनकी अत्यन्त शक्तिशाली प्रेरणा का प्रयोग किया जाता है। अतः इनके माध्यम से ही अत्यन्त बड़ा प्रभाव पड़ा है। यह योजना अत्यन्त सफल और प्रसारमान्य तथा विशाल प्रभाव के द्वारा १९४७ जिलों में अनुसूचित जातों के समायोजन में रही है। १९४७-४८ में इनके माध्यम से १५ लाख शिक्षितों को लाभ पहुंचाया गया था।

[illegible]

उपयुक्त विधि न अवलोकनार्थक विद्या काव्य का चलावे
 व सिध उपयुक्त साहित्य की आवश्यकता निरंतर बढ़ती
 जा रही है। ऐसे साहित्य व विद्या और प्रकाशन का
 निव उपयुक्तता का क साम साम विनी काय म की
 अभियान चलाये जाने चाहिये। एक बार साधार हो जाने
 क बाद ऐसे हनी उपयुक्त पुन निरंतरता व अ घरे से म
 दन जावे एक विध उह उपयुक्त पदन सामग्री सदा
 तार मिलनी चाहिये। योकी व सिध उपयुक्त साहित्य की
 आवश्यकता बढ़ती जायगी और यह आवश्यक होगा कि
 ऐसे साहित्य के निरंतरता की सुवाद व्यवस्था की जाय और
 आवश्यकतानुसार पत्र और अन्त पुस्तकालय स्थापित
 किये जाय।

हमें स्कूल क्यों समाप्त करना है

अनुवादक—देवेन्द्रसिंह सिन्धु

[इवान इलिच की प्रसिद्ध पुस्तक 'डी-स्कूलिंग सोसाइटी' का अनुवाद हम क्रमशः मधी ताओम में इसमिए प्रकाशित कर रहे हैं कि इवान इलिच के विचार सावधानी विचार-धारा से मिलते-जुलते हैं। यह अनुवाद सर्वाधिकार सुरक्षित है।] [मतास से आते]

यह सब निर्णय तथा समूह राष्ट्रों दोनों ही के लिए है, किन्तु दोनों में यह विभिन्न रूपों में व्यक्त होता है। ज्ञान की नये प्रकार की गुरीबी निर्णय राष्ट्रों में अधिकतर लोगों को अधिक प्रत्यक्ष रूप में किन्तु अधिक इसके रूप में प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए लैटिन अमरीका में दो तिहाई बच्चे पाँचवी कक्षा पास किये बिना ही स्कूल छोड़ देते हैं। किन्तु स्कूल छोड़ने वाले इन बच्चों की वह बुद्धि नहीं होती जो सामान्य राष्ट्र अमरीका में होती है।

मान बुनिया में बहुत कम राष्ट्र ऐसे हैं जो पुराने प्रकार की गरीबी के विचार हैं वह गरीबी अधि टिकाऊ किन्तु कम प्रभावितों से बरी हुई होती थी। लैटिन अमरीका के बहुत से देश आर्थिक विज्ञान तथा प्रतिपत्ति को बिना में अक्षर हो चुके हैं जबकि ज्ञान की नयी गरीबी की ओर बढ़ चुके हैं। वहाँ के नागरिकों में अमीरों की तरह सोचना और गरीबों की तरह बिना रहना सीखा गया है। वहाँ के कानूनों के अनुसार १ से १५ वर्ष तक की स्कूली शिक्षा अनिवार्य है। न केवल अमेरिका दक्षिण अमेरिका का ज्ञान में भी व्यापार लक्ष्य लक्ष्य अमेरिका के पक्षों से पर्याप्त शिक्षा की परिभाषा करता है, यद्यपि अमरीका जैसी लक्ष्य शिक्षा प्राप्त करने का अक्षर बहुत कम सम्प्राप्ति में कुछ लोगों को दियेगा। इन देशों में अधिकतम में लोग स्कूल-प्रति हो चुके हैं, अर्थात् उनमें उन लोगों के सदस्य में हीन भावना। पक्षों है किन्तु अक्षर स्कूली शिक्षा प्राप्त करने की बुद्धि है। स्कूली शिक्षा के लिए उनका पाठ्यपत्र उनके सोहे सोपान की बुद्धि से प्राप्त करता है : एक तो

इससे कुछ घुने हुए लोगों की शिक्षा के लिए निरक्षर अधिनायक सावजनिक धनराशि की व्यवस्था की जाती है और दूसरे अधिकांश लोग इस प्रकार के सामाजिक नियमों के प्रति अपनी अधिकाधिक स्वीकृति प्रदान करते हैं।

यह एक विचित्र स्थिति है कि यह विश्वास कि सर्व-साम शिक्षा सर्वथा आवश्यक या अनिवार्य है, उन देशों में अधिक दृढ़ है जिनमें बहुत कम लोग स्कूली शिक्षा प्राप्त कर सके हैं या कर सके हैं। फिर भी लैटिन अमरीका में अधिकांश अधिनायक और बच्चे स्कूली शिक्षा के विभिन्न रास्तों पर चलने का प्रयास करते हैं। अनुपाततः राष्ट्रीय बचत की वह धनराशि जो इन देशों के स्कूलों और विद्यालयों पर खर्च की जाती है, समूह देशों की तुलना में अधिक होती किन्तु यह धनराशि अधिकांश लोगों के लिए पार वर्ष की भी स्कूली शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए निरक्षर अक्षर है। फीदेल कास्ट्रो (Fidel Castro) ऐसा समझते हैं कि वे स्कूल-विहीनता की ओर जाना चाहते हैं जब वे यह वास्तविकता देखते हैं कि १९५० तक बच्चा में विद्वानिवालय समाप्त हो जाएगा क्योंकि बच्चा में पुरा जीवन ही एक घण्टिक अनुभव होगा। किन्तु बच्चा अन्य लैटिन अमरीका के देशों की तरह, ग्रामर और हाई स्कूल स्तर पर, ऐसे नाम कर रहा है जैसे एक परि-यापित 'स्कूली छात्र' की व्यवधि से पुनर्जात सभी के लिए निविदात लक्ष्य निश्चित विद्या गया हो और वह लक्ष्य केवल छात्रों के अक्षर के कारण वितरित हो रहा हो।

बहुते हुए इसास के दो बोधे—एक जैसा वास्तव में अमरीका में है और दूसरा जैसा लैटिन अमरीका में आका-

जित सपना आशयित हैं—एक दूसरे के पूरक हैं। उत्तरी अमरीका के गरीब बारह वर्ष के बालक से सही तरह पब्लिक है जिसकी कमी के कारण सेंटिन अमरीका के गरीब बच्चे विछड़े समझे जाते हैं। न तो उत्तरी अमरीका में और न सेंटिन अमरीका में गरीबों को अनिवार्य स्कूलों में प्रवेश मिल पाती है। लेकिन दोनों स्थानों में स्कूल के अतिरिक्त के कारण ही गरीब अपनी शिक्षा पर निरभर नहीं रह पाता और हतोत्साह तथा मजबूर हो जाता है, हार्थमैनिक शिक्षा का इलाज प्राप्त करने के लिए विषय में सभी अवस्था पर स्कूल का प्रभाव शिक्षा विरोधी है। स्कूल को यह माना जाता है कि यह शिक्षा में विशेषज्ञता रखता है। स्कूल की असफलता को सीधे इस बात का प्रमाण समझते हैं कि शिक्षा बहुत कीमती है, बहुत पेशीबी है, छद्म रहस्यमय है और बहुधा दुष्प्रभाव कार्य है।

स्कूल सेवा केन्द्र है, उसमें आदमी लगते हैं और शिक्षा के प्रति जो सम्भावना है उसको भी लता है। साथ ही अन्य समस्याओं की विलक्षण कार्य करने के प्रति हतोत्साहित करता है। काम, मजदूरी, राजनीति, गृहरी जीवन यहाँ तक कि पारिवारिक जीवन पूर्व निर्धारित आदतों और ज्ञान के निरुद्धता पर निर्भर करता है, बचपन इसका कि ये सब सब शिक्षा के साधन बन जायें। एक साथ ही स्कूली तथा उन समस्याओं का मुख्य जो स्कूलों पर निर्भर करती है बाजार को बाहर लगाया जाता है अर्थात् बाह्यिक आवश्यकताओं से उनका सम्बन्ध नहीं रहता।

अमरीका में प्रति व्यक्ति स्कूली शिक्षा का खर्च सती सती से बढ़ा है जिस तेजी से विकसित का। लेकिन बाहरों तथा शिक्षकों द्वारा जो जड़ता हुआ इलाज है उसके परिणाम भी बड़े ही प्रतिकूल हैं। विछड़े बच्चों के ४२ वर्ष से ऊपर की उम्र वाली पर विविधता के व्यवसाय गुना बढ़ है जबकि प्रचाराय से आयु केवल ३ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। संसिक कर्ष के वृद्धि के विषय परिणाम हुए हैं। अन्यथा प्रसिद्ध निवर्तन को १९७० को यह आवश्यकता देने के लिए बाध्य न होना पड़ता कि प्रत्येक बच्चे को सीप हो पढ़ने का अधिकार (Right to Read) स्कूल छोड़ने के पूर्व मिलेगा।

अमरीका में यह शिक्षा के लिए जिसमें शिक्षकों के अनुसार काम तथा हार्ड स्कूल में सबसे समान शिक्षा विधेयी, प्रतिवर्ष ८०० अरब डॉलर (१ डॉलर = लगभग ८५०) की आवश्यकता पड़ेगी। यह ३६० अरब डॉलर की उच्च धनराशि दुबला है जो इस पर खर्च किया जा रहा है। स्वाभाविक, शिक्षा तथा कल्याण विभाग और पतोरिहा विनविद्यालय के द्वारा तैयार किये गए स्वतंत्र अनुमानों के अनुसार वर्तमान ४२० अरब डॉलर के अनुमानों के स्थान पर १६७४ तक यह धनराशि १०० अरब डॉलर हो जायेगी। इन आंकड़ों से वह बड़ा भारी व्यय नहीं सम्मिलित है जिसे 'उच्च शिक्षा' कहा जाता है और जिसके लिए भाग बड़ी तीव्रता से बढ़ रहे हैं। अमरीका, जिसने १९६६ में लगभग ८०० अरब डॉलर 'प्रतिरक्षा' पर खर्च किये थे, जिसमें विनवर्तनीय की लड़ाई का व्यय भी सम्मिलित है, समान स्तरों शिक्षा देने के लिए बाह्य में गरीब है। स्कूली अर्थ-व्यवस्था के लिए नियुक्त राष्ट्रपति की समिति को यह पूछने का बराब कि कैसे पढ़ते हुए बच्चों का प्रबन्ध किया जा सकता है या कीते से कम किया जा सकता है, यह पूछना पारिवर्तिक से इस खर्च से बचा जा सकता है।

कम से कम यह ही मानना ही पड़ेगा कि अनिवार्य समान स्तरों शिक्षा अधिक दृष्टि से समान नहीं है। लेकिन अमरीका में प्रत्येक 'डेपुट्ट विद्यार्थी पर उच्च धनराशि का ३६० से १२०० गुना हार्थमैनिक धन व्यय किया जाता है जो उच्च साधारण नागरिक पर व्यय होता है जो विनवर्तन तथा सम्पत्तय के बीच में स्थित है। अमरीका में अन्तर कम है किन्तु वेद अधिक है। सम्पन्नतम सभ्यता १० प्रतिशत अनिवार्य बच्चे बच्चे के लिए प्राइवेट शिक्षा का प्रबन्ध करते हैं और साधारण अनुदानों से उनकी सहायता करते हैं। इस अतिरिक्त वे साहचरिक धनराशि के प्रति सालक १० गुना अधिक प्राप्त करते हैं' यदि विनवर्तन १० प्रतिशत बच्चों पर किए गए प्रति मानक खर्च से उसकी तुलना की जाए। इससे मुख्य कारण यह है कि बच्चे बच्चे सभी अवधि तक स्कूल में रहते हैं' विनविद्यालय को शिक्षा का एक बड़े स्तरों शिक्षा के एक वर्ष से बेहिसाब अधिक खर्चा होता है, और अधिकांश

विरहविशालय कम से कम प्रशस्ति कर से, करो (Tax) से प्राप्त धनराशि पर निर्भर करते हैं।

अनिवार्य शिक्षा से समाज में ध्रुवीकरण हो रहा है। इससे एक अन्तर्राष्ट्रीय जाति व्यवस्था में विश्व के विभिन्न राष्ट्रों में केंद्र नीच का मेरुमान बढ़ता है। जाति व्यवस्था की भाँति देशों का मूल्यांकन किया जाता है। उनकी ऐंभिक प्रतिष्ठा इस आधार पर निर्धारित की जाती है कि उनसे नागरिकों के कितने औसत वर्ष स्कूलों शिक्षा में व्यतीत किये हैं। इस मूल्यांकन का सम्बन्ध प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रीय उत्पादन (GNP) से परिच्छिन्न रूप से सम्बन्धित है जो और भी अधिक स्पष्ट है।

स्कूलों की वित्तगति स्पष्ट है। बढ़ता हुआ व्यय उनकी पर में और बाहर परबाध करने की क्षमता को बढ़ाता है। इन वित्तगति की सामाजिक प्रश्न बनाना चाहिए। सामान्यतः सब यह स्वीकार किया जाता है कि यदि हम भौतिक सामानों के उत्पादन को पर्याप्त धारा की प्रतिकूल दिशा में नहीं मोड़ते हैं। भौतिक बालाघरल भौतिक सामा-यिक प्रदूषण से सीधे ही स्पष्ट हो जायगा साथ ही यह भी स्वीकार करना चाहिए कि सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन को बड़ी प्रभाव का जतरा स्वास्थ्य, शिक्षा तथा बाल्याल विभाग द्वारा प्रजन्मि प्रदूषण से है। यह स्थिति स्व त्व शिक्षा और कल्याण के प्रतिरोध और प्रतिक्रिया उदासीन का उप-परिणाम है।

स्कूलों की कृति बढ़ती ही विनाशकारी है जिसकी शक्तानोंकी क्षामु उतने प्रत्यक्ष रूपसे नहीं। विश्व में हर जगह स्कूलों पर व्यय छात्र सक्षम और कुल राष्ट्रीय उत्पादन (GNP) की प्रवेदा तीव्रतर बति से बढ़ा है। हर जगह स्कूलों पर व्यय अभिभावकों, लम्बायकों तथा विद्यालयों की प्रत्याशाओं की पूरा नहीं करता। हर जगह इस स्थिति से यह प्रेरणा तथा अर्थ व्यवस्था हतोत्साहित हो जाती है जो इसे पैमाने पर बिना स्कूल के शिक्षा नियोजित करने से सम्बद्ध होती है। अमरीका विश्व के सामने यह प्रमाणित कर रहा है कि किसी भी देश में पाठ्य प्रतियाँ पैसा नहीं हो सकती यदि वह एक ऐसी स्कूल व्यवस्था का साथ बहुत कर सकें जो इस व्यवस्था के केवल अस्तित्व से ही स्वयं सृजित

भागी के रूप में हमारे सामने प्रस्ता है क्योंकि एक सफल स्कूल व्यवस्था प्रता पिता तथा विद्यालयों की बात के लिए तैयार करती है जिसे एक और बड़ी शक्तों की स्वतंत्र व्यवस्था के गर्वोच्च महत्व को समझ सकें, जिसका तथे जैसे जैसे वेदिकमान बढ़ता है जैसे-जैसे उच्च प्रशासकों की शिक्षा की मांग बढ़ती है और सुलभता कम होती जाती है।

अब हम इसके कि यह कहा जाय कि समाज स्कूलों विद्यालयों की रूप से व्यवस्था है, हमें यह मानना चाहिए कि सिद्धांततः यह नितांत असंगत है और यह कि इसका प्रयास करना बौद्धिक दृष्टि में एतित सही है सामाजिक दृष्टि से ध्रुवीकरण की जगती है और इस राजनीतिक व्यवस्था के प्रति आस्था दृष्ट करने वाली है जो इसे बढ़ावा देती है। अनिवार्य स्कूलों शिक्षा के सिद्धांतों की कोई आर्थिक सीमाएँ नहीं हैं। ह्वाइट हाउस ने अभी हाल में एक बन्धन उदाहरण प्रस्तुत किया। वास्तविकता में 'मैथिचिनिस्म' जिन्होंने राष्ट्रपति के पद के अग्रदूतों की अहंता अजित करने के पूर्व भी निषेध का इलाज किया था, राष्ट्रपति को यह सत्सुति की थी कि ५-८ वर्ष के सभी बच्चों की परीक्षा हम दृष्टि से की जाय जिससे ऐसे बच्चों छुट्टी या सकें जिनकी प्रभुसिपा विषममूल है और उनके अनिवार्य इसाज की व्यवस्था की जाय। यदि आवश्यक हो तो उनकी पुनर्शिक्षा की व्यवस्था विशेष सराफों के की जाय। बच्चों हाउस से प्राप्त इस समुत्पन्न को भी निषेध के समीक्षा के लिए स्वास्थ्य शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग को देना। भारत में पक्ष से विधित होने के पूर्व ही बच्चों को रोय से बचाने के लिए दक्षी-तिविर धमाला स्कूलों व्यवस्था का तर्क सगत दुष्टार होय।

समान शिक्षा का अवसर सम्पूर्ण एक राष्ट्रीय और सम्भव मध्य है किन्तु इसे स्कूल शिक्षा में अवरूप कर देना मेधा ही भ्रम है जैसा मोक्ष को गिरजापर के समरूप कर देना। स्कूल आज के सर्वोत्तरा का विषय पक्ष है जो तकनीकी युग के गरीबी के सामने मोक्ष के निरबन्ध आस्थातन प्रस्तुत करता है। राष्ट्र राज्यों से इसे स्वीकार कर लिया है और सभी नागरिकों को एक धनी बड़ पाठ्यपत्रों से भाष दिया गया है जिसके द्वारा उन्हें सभी तरह कमबद्ध स्थितियाँ

प्राप्त होते हैं जैसे पुराने समय में दीक्षा के कर्मनाम्न और सम्पन्न परोपकारिता हुआ करता था। आधुनिक राज्य ने यह धार्मिक अपने ऊपर ली। सिवा है कि वह अच्छे हरादे वाले आचार्य अधिचारियों और काम की आवश्यकताओं के माध्यम में अपने शिक्षार्थों के निर्णय को लोगों के ऊपर उसी तरह से सार है जैसे स्पेन के राजा अपने धर्म-दासियों को विवेकाओं तथा धार्मिक स्वाध्यायों के माध्यम से पर्यवेक्षित साक्षात् करते थे।

बी सतावीं पुर्व अमरीका में एक वर्ष के एकाधिकार को समाप्त करने के आन्दोलन में विश्व का नेतृत्व किया था। अब हमें स्मृत के एकाधिकार को सर्वोपार्थिक रूप के समाप्त करने की आवश्यकता है जिससे एक ऐसी व्यवस्था समाप्त हो सके जो पलायन को भेदभाव के विषाक्त सम्बन्ध करती है। आधुनिक राजकीय समाज के अधिकारों के मानन की पहली चारा कुछ बंधों ही होती होती। अमरीका के संविधान के प्रथम संशोधन में है 'शिक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में कोई कानून नहीं बनाया जा सके किन्तु कोई अनिवार्य प्रणाली नहीं होगी।

स्कूल की इस प्रकार समाधि को प्रभावी बनाने के लिए हमें कानून की आवश्यकता है जो ऐसे शासकों के को-ही में, जो किसी पाठ्यक्रम की पूर्ण उपस्थिति पर आधारित होते हैं किन्तु वे भेदभाव मतभेद या प्रवेश को बाधित करे। इस कारण का मय यह न होना कि किसी विशेष कार्य या भूमिका को लिए योग्यता सम्बन्धी नियामक प्रतीक्षा न हो जाए। लेकिन इससे यह अवश्य होना कि इस समय ऐसे व्यक्ति के लिए, जिसने सर्वांगिक सामाजिक भवन वर्षों के कोई कोशिश प्राप्त कर लिया है या जैसा सर्वथा सम्भव है, जिसने एक दिवसीय प्राप्त कर लिया है जिसका सम्बन्धित कोशल या काम से कोई सम्बन्ध नहीं है, जो अद्यतन पक्षपात है कि वह सम्भव हो जाए। जब नागरिकों को यह कारण मिलेगा स्कूल के जीवन की किसी बात से यह काम के अवश्य न माना जाएगा, तभी स्कूल की वैधानिक स्थापित मनोवैज्ञानिक दृष्टि से प्रभावी होगी।

स्कूलों शिक्षा से न तो ज्ञान बढ़ता है और न न्याय की प्रतीक्षा होती है क्योंकि शिक्षा के लिए को प्रमाणपत्रों

में सपेटी है। सामाजिक तथा सामाजिक भूमिका की निम्नोदारी स्मृति शिक्षा में विरोध हो जाती है। सीसने का अर्थ यह है कि कोई नया कोशल या नवी दृष्टि प्राप्त की जाय, जब कि क्लोप्रति उस अस्मिता पर निर्भर करती है जो दूसरों का है। बारबार सीसना शिक्षा का परिणाम है किन्तु काम के कारण में निती वर्ष या भूमिका के लिए चुनाव अधिकारिक उपस्थिति की सहाई पर निर्भर करता है।

सहाय्य उन परिस्थितियों का चुनाव है जो सामाजिक में सहाय्य होती है। परिस्थितियों का वाद्यक्रम बनाकर भूमिका निर्धारित की जाती है। इन परिस्थितियों को विचार्यों को भगना है यदि उसे क्लोप्रति चाहिए। स्कूल इन भूमिकाओं, सीसने को नहीं, शिक्षा को जोड़ता है। न तो यह तर्क संगत है और न मुक्तिवाद। सम्बन्ध नहीं है क्योंकि यह सम्बन्धित गुणों का योग्यता को भूमिका से नहीं जोड़ता, बल्कि उस प्रक्रिया को जोड़ता है जिससे यह समझ आता है कि वे कुछ अंगित गिने जाते हैं। यह मुक्तिवाद या वैज्ञानिक नहीं है क्योंकि स्कूल जनताओं के लिए शिक्षण सुरक्षित रखता है जिसका सीसने का हर एक कदम सामाजिक नियमों की पूर्वाभुमिदित प्रणाली के अनुकूल होता है।

वाद्य क्रम का प्रयोग सर्वदा सामाजिक भेद-निर्धारण के लिए हुआ है। कभी-कभी ऐसा काम के पूर्व भी होता है। काम हमें किसी जाति या सम्पन्न वंश-परम्परा के जोड़ता है। पाठ्यक्रम एक कर्मकाण्ड का रूप ल सकता है, या कर्मकाण्ड पवित्र बीसों का, भयवा युद्ध या शिकार में निरन्तर बढ़ादुरी के कारणों का अथवा प्रत्येक पूर्व की राजकुमारों पर निर्भर प्रदति भी हो सकती है। सामाजिक स्कूलों शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तिगत जीवन के इतिहास से भूमिका निर्धारण को अनन्य करना था। इसका उद्देश्य यह था कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक वर के लिए समान अवसर मिले। जब भी बहुत से लोग इस भ्रम में रहते हैं कि स्कूल इस बात को निर्धारित करता है कि सम्बन्ध अंगित उपलब्धियों पर कदम का विश्वास रहे। किन्तु अब-

सरो को समान करत ने बलाय स्त्री की व्यवस्था ने उन पर
एवाधिकार कर दिया है ।

पाठ्यक्रम से योग्यता को अलग करने के लिए, अनुप्य
के सीखने की इतिहास की जीव को निषिद्ध कर देता
बाह्ये जैसे उसके राजनीतिक प्रभाव, गिरिजाधर ने उप-
स्थिति, दश परम्परा, दान रचनाय या जातिगत वृद्धि
के बारे में पूछताछ नहीं की जाती । ऐसे कानून बनने
बाह्ये जिनमें पूर्वाज्ञित स्त्री शिक्षा पर आधारित भेद-
भाव बलित हो । यह ठीक है कि कानून उसके प्रति पूर्वा-
ग्रह को नहीं समाप्त कर सकते जिन्होंने स्त्री शिक्षा नहीं
प्राप्त की है और न उनका सहोदर यह है कि वे किसी काठिन्य
से विवाह करने के लिए किसी को बाध्य करें । किन्तु वे
अनुचित भेदभाव को निरस्तहित कर सकते हैं ।

एक दूसरा प्रमुख भ्रम जिसपर स्त्री व्यवस्था निर्भर
करती है, यह है कि बहुत सा सोजना शिक्षा का परित्याग
है । यह ठीक है कि शिक्षा विशेष प्रकार के जागरण में
सहायक हो लेकिन अधिकतर लोग अपनी अधिकतर ज्ञान

स्त्रुस ने बाहर प्राप्त करते हैं जहाँ जैसा कुछ समुद्र देशों
में है स्त्रुस उनका अधिकांश जीवन के लिए वन्देवराण के
स्थान हो गए हैं ।

अधिकतर जीवन वास्तविक होता है और अत्यंत
सोचदेवराण प्रभावार्जित को शिक्षा कार्यक्रमित ॥ परिणाम
नहीं है । सामान्य बच्चे अपनी प्रथम भाषा वास्तविक
व्यस सीखते हैं, और यदि मा-बाप उनका ऊपर ध्यान
देते हैं तो और सीखता से सीखते हैं । बहुत से लोग जो
बुझरी भाषा अच्छी तरह सीखते हैं वे विविध परिधि-
तियों के परिणामरक्षण कोष पाते हैं, न कि प्रमद
शिक्षण के कारण । ऐसे लोग अपने पितामह के पास रहने
प्ये जाते हैं, या वे यात्रा करते हैं अथवा किसी विदेशी
से प्रेम करने लगते हैं । पढ़ने में प्रवाह को बहुधा ऐसी
पाठ्यदेवराण शिक्षा का परिणाम होता है । बहुत से लोग
को व्यापक रूप से पढ़ते हैं और ज्ञान के लिए पढ़ते हैं,
यह सोचते हैं कि ऐसा पढ़ना उन्होंने स्कूल में सीखा ।
किन्तु जब उनको प्रश्न किया जाता है, तो उनका यह ज्ञान
दूर हो जाता है ।

कमल



आदरणीय धीरेन्द्र की स्मृति में

विनोद

भाप कोशों ने सायद वेटर में जड़ा होगा, धीरेन्द्र दा की मृत्यु हुई। धीरेन्द्र दा को शोक नहीं आया? वे विनोद में कहते थे कि बाबा से मैं एक दिन बड़ा हुआ और मैं बाल छोटा हूँ। एक दिन का मतलब है कि बाबा का जन्मदिन ११ सितम्बर का है और उनका १० सितम्बर का है। बाबा ने बर्ष पूर्ण करने के २४ में प्रवेश कर रखा है। धीरेन्द्र दा की ११-१२-१३ के गये। कृष्णराज उनसे मिलने १८ तारीख को गया था। शाम को एक घण्टा भर उनके बात की और उठी बत्ती उन्होंने कह दिया कि 'बाबा की मेरी प्रणाम कह देना।' उसके बाद १९ तारीख को वे बेहोश हो गए और २१ तारीख को गए। कीर्ति-कीर्ति ७८ की उम्र थी। कम तोड़ करके वे चले गए। इस प्रकार कम होकर भीमन् की भी गए। कम तोड़ने वालों का क्रम तोड़ना जारी है। मैं समझ करता हूँ कि यहाँ कोई कम नहीं होवेगा। धीरेन्द्र दा तो बाबा के साथ दशों रहे। एक ॥ बाद एक साथी छोड़े जा रहे हैं। हमको सबको बाबा है ही, यह उनकी बात है। लेकिन आने के पहले प्रार्थनाप्रार्थना करते जाना चाहिए। बाबा तो रोक धुप का पूर्ण प्रयोग होने से पहले करता है और भगवान से कहता है, मैं सुखी से तेरे पास आऊंगा। अगर तू मुझे इसका काम देना तो मैं सेवा करता, ऐसी प्रार्थना से रोक करता हूँ। इसलिए हर एक को जाना छोड़े ही है।

धीरेन्द्र दा ने बहुत बड़ी बात कही है—'अति भी नहीं जाती, होती है।' और रचनात्मक काम, सेवा-कार्य करते रहना चाहिए। एक-एक जिला लेकर उसमें सब तरह का रचनात्मक कार्य करता चाहिए। इसको उन्होंने मार्गोज्ञान नाम दिया है। मार्ग के कोशों के पास हमको जाना चाहिए। उनके पास जो ज्ञान है वह उनको परम्परा से प्राप्त हुआ है। वे निरन्तर तो हैं लेकिन निरन्तर होने

पर भी निरन्तर नहीं, मार्गक हैं। उनके पास आकर हम-को काम करना चाहिए। इस तरह एक-एक जिला लेकर काम करेंगे तो हमको मार्ग मिलेगा।

धीरेन्द्र दा मार्ग सोचते-सोचते गए। १८ तारीख को 'बाबा से प्रणाम कह दो' कहना और १९ तारीख को बेहोश हो जाना, २१ तारीख को चले जाना। यह छोटी बात नहीं है कि जगत में प्रणाम कहकर चले जाना। [बाबा का क्या घर जाता है और आए रहते हैं]।

भगवान सबको सन्तति दे, ऐसा कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने निरन्तर सत्कार्य किया है।

उनकी मृत्यु से बाबा की बुद्धि बरकर हुआ इसलिए कि वे बाबा के पहले चले गए। (अथ) वास्तव में बाबा को पहले जाना था, उनकी बात में जाना था। इसलिए बुद्धि हुआ। लेकिन जिसका प्रारम्भ समय होता है उसको जाना ही पड़ता है। धीरेन्द्र दा की सन्तति मिलेगी और वे भगवान के पास निरन्तर रहेंगे, इसमें मुझे कोई शक नहीं।

दो शब्द हैं—क्याचित्नाह, बकाचित्नाह। फल फिलनाह यात्री भगवान ने फल हो जाना। बकाचित्नाह यात्री बाकी रहता, भगवान के साथ बातचीत करना। ऐसे धीरेन्द्र दा भगवान के साथ बातचीत करते हैं। हम जितने साथी हैं वे सब भिन्न-भिन्न के भगवान के पास बैठकर के बातचीत करेंगे। जैसी जगह वहाँ बैठक हो रही है वैसे ही बैठक वहाँ होये। बाबा ने जाहिर ही किया है 'जैसी कारनामी कब्जा'—हिन्दी में उसे कब्राना कहते हैं। भगवान के पास पहुँचकर फिर दुनिया की सेवा ॥ लिए ऊपर से नीचे जाना। अखिल बाबा है—'हरिता जग तो मुक्ति न माये।' (अथ) हरि के लेकर मुक्ति नहीं मांगते। बुद्धराज महाराज ने कही कहा है—'न सगे मुक्ति न

सम्पदा, तुका हमने पसंदाओ सुखें घासाये आम्हाही ।' मुक्ति मागते नहीं, सत्याग्र की इच्छा करते हैं और केवल मक्ति की कामना करते हैं । यही लिखा है अमरिषा में, 'मुक्ति निस्पृह जितो' । (यथु) नामधेया का पहला श्लोक है—'जो मुक्ति की कामना करने नहीं, रसमय भाषो हो भवति ।' इस मक्ति चाहते हैं, मुक्ति चाहते नहीं । मक्ति रसमय है । तो बाबा ने जो बात किया है—बाबा मरेगा, शालू नहीं कब मरेगा, जब आरम्भ लग होगा सब मर जाएगा । मरेगा तो ऊपर जाएगा । 'नक्षत्रवेगिनं वधो' में

मिल जाएगा ।

धोरेन मार्द वा मुख्य विचार वा, मार्गलोचन करना । तो सब लोग एक-एक जिला लेकर गांव-गांव में जाकर लोगों के पास पहुँचें और उनको एक परिवार बनाने की बात कहें । इसी मार्ग वा चिन्तन मनन करें तो यह मार्ग सोचन की प्रक्रिया हम सबको, जो जीवित हैं उन सबको करनी चाहिए ।

अब इसके बाद दो मिनट मोन होगा और फिर विष्णु-सहस्रनाम का पाठ होगा ।

१७-२२

प्रौढ़ शिक्षा का क्षेत्र

(कोठारी आयोग की रिपोर्ट से)

17.1 स्कूल की पढ़ाई के साथ ही शिक्षा समाप्त नहीं हो जाती, बल्कि यह एक जीवन-व्यापी प्रक्रिया है । आज के समय की तेजी से बदलते हुए संसार और समाज की बढ़ती हुई जटिलताओं की सम्पन्ने की आवश्यकता है । जो लोग परिष्कृततम शिक्षा पा चुके हैं, उन्हें भी लगातार सीखते रहने की जरूरत है, अन्यथा वे पिछड़ जायेंगे ।

17.2 उच्च समाज की, जो आर्थिक विकास, सामाजिक क्रान्ति और प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षा की प्राप्ति करने का निश्चय कर चुका हो, कार्यनीति का मुख्य आधार यह होता है कि यह अपने नागरिकों की विकास-कार्यक्रमों में स्वयं अपनी इच्छा से स्विकृत्य और कुशलता से भाग लेने की शिक्षा दे । उच्च समाज में तो ऐसा करना विशेष रूप से आवश्यक हो जाता है जहाँ बहुवर्षिक शोध स्तर में न पढ़ सके हों और जो शिक्षा की जा रही हो उसकी तात्तव्य विकास की जरूरतों से न भँझती हो । जमीन जोतने वाले किसान को अपनी जमीन या मशीन चलाने वाले कामगार को अपनी मशीन की विशेषता समझ लेनी होगी और उत्पादन सम्बन्धी वैज्ञानिक प्रक्रियाओं की कुछ जानकारी प्राप्त कर लेनी होगी

ताकि वह सफ़र तरीके अपना सके और उनमें सुधार कर सके । अनुसंधान-विषय या जोर-जबरदस्ती मात्र से बढ़ती हुई अवस्था को नहीं रोका जा सकता । लोगों को लगातार बढ़ती हुई जन संख्या के परिणाम समझने होंगे, जीवन के नियमों की जानकारी प्राप्त करनी होगी और परिवार-नियोजन के कार्यक्रमों के प्रति अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी समझनी होगी । कोई भी राष्ट्र केवल पुष्टि और सेवा पर अपनी सुरक्षा का धार नहीं छोड़ सकता, राष्ट्र की सुरक्षा बड़ी सीमा तक उसकी जनता की शिक्षा, गतिविधियों के बारे में उसकी जानकारी, परिण और अनुशासन की भावना तथा सुरक्षात्मक उपायों में प्रभावकारी रूप से भाग लेने की उसकी योग्यता पर निर्भर होती है ।

17.3. इस दृष्टि से, प्रगतता में प्रौढ़ शिक्षा का कर्षण यह है कि यह प्रत्येक व्यक्ति को उस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दे जिस प्रकार की शिक्षा वह चाहता है और जो उसकी व्यक्तिगत समृद्धि, व्यावसायिक प्रगति तथा सामाजिक और राजनीतिक जीवन में प्रभावकारी रूप से भाग लेने के लिए आवश्यक हो ।

17.4 सामान्य स्थितियों में प्रौढ़ शिक्षा ने कार्यक्रम यह मानकर बनाए जाते हैं कि सभी लोग साक्षर हों। पर भारत में, जहाँ 70 प्रतिशत लोग पढ़ लिख भी नहीं सकते, निरक्षरता को समाप्त करना स्वभावतः राष्ट्रीय चिन्ता का तारकालिक विषय बन गया है।

17.5 प्रौढ़ शिक्षा का रोज बहुत विस्तृत है—इतना विस्तृत किन्ना कि सब ओर है। इसकी आवश्यकताएँ सामान्य स्कूली पढ़ाई से भिन्न हैं। यह इस पर निर्भर है कि अनेक एजेंसियों में, विशेषकर विश्वविद्यालयों, सांख्यिक संस्थाओं और पुस्तकालयों में उसे कितनी सहायता मिलती है। प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रमों को प्रभावकारिता प्राप्त प्रशासन तन्त्र पर निर्भर होती है।

17.6 भारत में प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित बातें होनी चाहिए

- निरीक्षण का निरूपण,
 - निरंतर शिक्षा,
 - प्रशासनिक पाठ्यक्रम,
 - पुस्तकालय,
 - प्रौढ़ शिक्षा में विश्वविद्यालयों का योगदान, और
 - प्रौढ़ शिक्षा का संगठन और प्रशासन।
- इस अध्याय में हम इनकी चर्चा करेंगे।

निरक्षरता का निर्मूलन

17.7 कार्रवाई की आवश्यकता—360 करोड़ निरक्षर और बड़ जान से सन् 1951 की अंशेला सन् 1961 में भारत में निरक्षर हो गया था। सन् 1966 में सन् 1961 की अंशेला 2 करोड़ निरक्षर और बड़ था। प्राथमिक शिक्षा के अक्षतपुत्र निरक्षर और अनेक साक्षरता अभियानों और कार्यक्रमों के बावजूद ऐसा हुआ है। यद्यपि साक्षरता का प्रतिशत सन् 1951 में 16.6 से बढ़कर सन् 1961 में 24 और सन् 1966 में 28.6 हो गया है तो भी तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या ने सर्वमोक्ष साक्षरता के लक्ष्य की प्राप्ति के अवसरों में देर की और पीछे चलेते विषय है इसके जो शिक्षा मिलती है वह स्पष्ट है, कि साक्षरता को हस्तगत से बढ़ाने के

परम्परागत तरीके लगभग व्यर्थ हैं। यदि इस प्रवृत्ति को बदलना है तो गंभीरता सांख्यिक राष्ट्रीय प्रयास की जरूरत है।

17.8 निरक्षरता के लिए व्यक्ति को, और राष्ट्र को बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। यद्यपि बहु, इस निरन्तर व्यक्ति का व्यय हो जाता है और उससे होने वाली हानि के प्रति जड़ हो जाता है। आयुर्विज्ञान जीवन की परिस्थितियों में अनेक व्यक्ति को निरक्षरता ठहरा कर उसे होने जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य कर देती है। उसके लिए उचित वापसी की कोई समाधान नहीं पड़ती। प्रजातान्त्रिक सरकार और वाणिज्य बजार जैसी परिष्कृत सामाजिक प्रक्रियाओं से वह अलग समय पड़ जाता है। अनेक व्यक्ति, वस्तुतः, स्वतन्त्र नागरिक नहीं हैं। सामूहिक प्रक्रिया के रूप में निरक्षरता व्यक्ति और सामाजिक प्रवृत्ति को अनेक बार देती है तथा व्यक्ति उत्पादित, जनसंख्या, निष्पन्न, राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा तथा स्वास्थ्य और सफाई के सुधार को दुष्प्रभावित करती है। योजना आयोग के सदस्य, प्रो० बी० के० सार० बी० राय के शब्दों में, "प्रौढ़ शिक्षा और प्रौढ़ साक्षरता के बिना न तो उस विस्तार और गति में व्यक्ति और सामाजिक विकास संभव है जिसकी हम आवश्यकता है, और न ही हमारे व्यक्ति और सामाजिक विकास को वह तत्त्व, गुणानुकूल अवस्था मिल सकती है जो मूल्य और हितकारिता की दृष्टि से उसे सार्थक बनाए। इसीलिए, व्यक्ति और सामाजिक विकास के किसी भी कार्यक्रम में प्रौढ़ शिक्षा और साक्षरता को प्रथम स्थान मिलना चाहिए।"

17.9 उपयुक्त सामाजिक संस्थाओं से मदद लेनी पड़ती है। स्वतन्त्रता प्राप्ति से पहले भी किसी न किसी रूप में, इन्हें स्वीकार किया जाता था। पर इस विषय में अब तक जो मुख्य कार्यसूची अपनाई गई है वह यह है कि 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के अवश्य के विचार पर ही बन दिया जाए। यदि इसे प्रशासकीय ढंग से सन् 1960 तक कार्यान्वित किया जा सके, जहाँ कि एक बार समझा गया था जो वह समस्या बहुत बरत हो जाती। पर

अनेक कारणों से, जिनकी व्याख्या सम्भव की गई है, अभी तक यह कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं हो सका है और हम अधिकारिक सन् 1976 तक प्रत्येक वर्षों को पाच वर्षों की ओर सन् 1986 तक सात वर्षों की प्रभावकारी शिक्षा दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्राथमिक शिक्षा की पद्धति अभी तत्काल अधिकांशतः प्रभावशून्य और निष्फल ही रही है। बहुत से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने या तो काम चलाने योग्य साक्षरता प्राप्त नहीं कर पाते या बाद में प्रीम ही किए निरक्षर हो जाते हैं। निरक्षरता को समाप्त करने के लिए यदि हम केवल इसी कार्यक्रम पर निर्भर रहे तो सन् 2000 तक भी इस सदय को प्राप्त नहीं कर पायेंगे। इसलिए यह स्पष्ट है कि अब हमें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के कार्यक्रम के विकास के लिए इसे सहाय के मुठ जाना चाहिए और सामूहिक निरक्षरता के निवारण के लिए समाज और सीमा अभियान करना चाहिए।

17.10 अभिप्राय यह नहीं है कि सामूहिक निरक्षरता के निवारण के लिए अब तक सीमा कार्यक्रमों किया ही नहीं गया। माल्द ने, प्रोड शिक्षा के निम्नलिखित चरणों के इतिहास से पता चलता है कि राज्यों के वा स्थायी आधार पर अनेक साक्षरता अभियान बड़े उत्साह से संचालित किए गए थे पर कुछ वर्ष बाद उदासीनता और प्रयत्न-मरहा के कारण विफल गए। इसके अनेक कारण हैं। वे अभियान इतने छोटे पैमाने पर चलाए गए थे कि उनके आधार पर निरिपक्ष प्रगति नहीं हो सकती थी और न ही वे बड़े प्रयास के लिए प्रेरणास्पद थे। वे छुटपुट अभियान थे जिनमें समन्वय का अभाव था—सरकारी विभाग, स्वैच्छिक एजेंसियां, शिक्षा संस्थाएं और व्यक्ति एक-दूसरे से मिलकर काम करने के बल्के अधिकतर अपना ही राग जमावते थे। वे अभियान प्रायः कल्याणों से शुरू किए जाते थे—प्रौढों की आवश्यकताओं और रुचियों को ध्यानपूर्वक समझे बिना, जगता में शिक्षा के प्रति रुचि या पढ़न लिखने की सामान्य व्यापक विना, और अनुवर्ती कार्य की पर्याप्त व्यवस्था किए बिना, अमान में कोई स्थायी परिणाम प्राप्त नहीं किए जा सकते। इसीलिए वे निरर्थक रहे और यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं है।

17.11 साक्षरता-कार्यक्रमों का दीर्घकालीन समर्थन और उन्हें सोहोष्य बनाना इस बात पर निर्भर करता है कि कुछ बुनियादी तथ्यों को स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया जाए। उदाहरणार्थ, यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि निरक्षर लोगों की भारी संख्या, जिसमें ही कार्यक्रमों पर तैयार होता है, ओलोमीकरण और कृषि के अनुनिष्कीकरण की गति और सामान्यतः देश की आर्थिक प्रगति को अवरोध कर देती है। यदि यह मान लें कि 15—44 वर्ष का आयु-वर्ग कार्यकारी दल है, तो इसमें 14.4 करोड़ लोग, या इस आयु-वर्ग का 67.4 प्रतिशत, ऐसे हैं जो अवपक्ष हैं। इसके अतिरिक्त, अवपक्ष लोग परिवर्तन का विरोध करते हैं और जीवन की पारम्परिक पद्धतियों से चिपके रहते हैं, जबकि सामाजिक जीवन के आयुनिष्कीकरण की मांग है कि स्वीकृत जाये कि नवीनकारी परिवर्तन लाया जाए। युग-मायना के साथ सामूहिक निरक्षरता की समस्या नहीं बैठती, क्योंकि आज वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति की जीवन की पद्धति और रहन-सहन के स्तर को निर्धारित करती है। नए विचार और नए तरीके उन लोगों के मन में प्रभावकारी रूप से पैदा नहीं जा सकते जो उन्हें ग्रहण करने और उनसे लाभ उठाने के अक्षम न हों। परिवार-नियोजन हो या स्वच्छता के स्तर को उन्नत करने की बात, सामाजिक सुरक्षा का कोई कार्यक्रम हो या कोई ऐसा आन्दोलन जो जीवन के प्रति दृष्टिकोण से या जीवन-पद्धति में परिवर्तन की मांग करता है, लोगों की समझ में आना चाहिए। इसी प्रकार, यह भी समझ लेना चाहिए कि अवपक्ष लोग वास्तविक प्रजातन्त्र नहीं बना सकते। सशक्त नागरिक जीवन में और महत्वपूर्ण निर्णय करने में लोगो का योगदान मिले यही प्रजातन्त्र का सार है। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 26 में कहा गया है कि शिक्षा का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है, और यह बात जितनी आज के संस्कृति पर लागू है उतनी ही भविष्य के। हमारे देश में जितने शिक्षा की अपनी महान परम्परा पर गर्व है, निरक्षर लोगों की भारी संख्या उपहास की बात है। ये सीधे सादे और स्पष्ट तथ्य हैं जिन पर मतभेद नहीं है। फिर भी, यह समझ लेना जरूरी है कि

निरक्षरता-न्यूनन को विद्यालया के अनुकूल गृह अवि-
यान तक अविनय रहेगा। अब तक राष्ट्रीय नेताओं को
इस बात का पूरी विद्वान न हो जाए कि जनपदों के
छगूह को शिक्षा का आर्थिक और सामाजिक प्रगति तथा
राष्ट्रीय जीवन की गुणवत्ता पर तोषा प्रभाव पड़ता
है। इस विद्वान के प्रभाव का प्रभाव यह है कि ओढ़
विज्ञा के किसी कार्यक्रम के प्रति अब तक कोई राजनीतिक
प्रतिबद्धता नहीं है। कुछ हद तक हमारा को विद्यालय
द्वारा कारण हो सकती है। निरक्षरों को सच्चा इतनी
महिक है, इसके लिए वित्तीय साधन और वित्तियत को
स्वच्छ है। इसी अधिक अवैध है कि परस्पर प्रतियोगी
प्रणाली के समुक्त इस समय को अप्राप्त मान कर छोड़
देने अपना समय के और प्राथमिक शिक्षा के सामंजस्य
विकास के मरोठे इसका हम छोड़ देने की प्रवृत्ति स्वाभा-
विक ही है। इस रविवे के कोई सह्यता नहीं मिलती।
हमारा विचार है कि निरक्षर के साथ और समर्थता
के इस समस्या का समाधान करना चाहिए। हमारा विचार
है कि इसके प्रति उदासीनता का दण्ड तो मिलेगा ही।

17.12 इस प्रत्यक्ष स्थिति का अन्त करन के लिए
हम सिफारिश करते हैं कि निरक्षरता को समाप्त करने के
लिए एक राष्ट्रीय स्तर की नीतिगत नीतिगत अविधान
बनाया जाए। अविधान इसलिए आवश्यक है कि हमारे
पास साधनों का समाप्त है और इस समस्या को सुलभ
करना पड़ती है। वह अविधान राष्ट्रीय जीवन में इसके
अविधान महत्व के प्रति आस्था के प्रेरित होना चाहिए
और देश के सामाजिक तथा राजनीतिक नेतृत्व को इसका
घबड़ा और शेरदार समर्थन करना चाहिए। केन्द्र, राज्य
और स्थानीय सरकारों, सभी सरकारी एजेंसियों, सभी
स्वैच्छिक एजेंसियों और गैर-सरकारी समस्थानों एवं
उद्योगों, निरक्षरविद्यालय से लेकर प्राथमिक स्कूल तक की
सभी शिक्षा संस्थानों, और इन सबके मजदूर, शिक्षित
नगरवासी को इसमें भाग लेना चाहिए। इसके हल्के
स्तर का प्रवास इसे अपेक्षित प्रेरणा और गति प्रदान
करने में असमर्थ रहेगा। यह अत्यन्त कठिन कार्य है।
इसके लिए समर्थन का प्राप्ति, वित्तीयपूर्ण घटकन, सभी
सम्बन्धित एजेंसियों का निकटपूर्ण सहयोग और कार्य-

कर्ताओं के अनेक प्रयत्न और त्याग अपेक्षित है। यह कार्य
पूरा हो सकता है, यह ने कान्ति के तरकात बाद इसे
पूरा कर लिया था। कुछ निरक्षर कठिनों के प्रयास ने
अपने देश के लिए सार्वभौम शासकता-मान से कहीं
अधिक प्राप्त किया। सोचो मे उपमन्यु और राष्ट्रीय
जीवन का भाव जाग्रत हुआ और वे सामाजिक क्रांति
में भाग लेने के लिए तैयार हो गए। भारत में परिवर्तित
कोई मिला पसर है, पर स्तर की तरह एक कोरदार
प्रयास किया जाए तो वह राष्ट्रीय महत्व का वैश्विक अनु-
भव सिद्ध होगा।

17.13 सुझाव—शासकता-कार्यक्रम में सकलता-
प्राप्ति की अनिवार्य शर्त यह है कि इसकी योजना प्रान्त-
पुर्वक बनाई जाए और इसके लिए अपेक्षित संपादनी बहुत
पड़ते ही कर ली जाए। सामूहिक कार्यक्रमों के संचालन,
सामग्री की संपादनी, कर्मियों के प्रशिक्षण और कुछ अन्य
अपेक्षाओं में समय बचता है। हम देश के सभी भागों में
एक-साथ राष्ट्र-वासी कार्यक्रम शुरू करने की बात नहीं
सोचते। पर यह बखब है कि जनसम्य सुविधाओं का ध्यान
रखते हुए प्रत्येक राज्य का एक के बाद दूसरा क्षेत्र लेकर
धीरे-धीरे सारे राज्य और फिर सारे देश में कार्यक्रम का
विस्तार किया जा सकता है। क्षेत्र-विशेष के वैश्विक
विकास की अवस्था, जन-सहयोग और घटकन की कार्य-
कुशलता के आधार पर विभिन्न समय में विभिन्न क्षेत्रों
में पूर्ण शासकता प्राप्त करना संभव होगा। निरक्षरता का
उन्मूलन में समय एक अनिवार्य तत्व है। समस्या को हल
करने में 10 या 15 वर्षों से अधिक समय लगे तो इसका
उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। हमारा विचार है कि
जीवनाच्छन्न प्रवर्तकों से राष्ट्रीय शासकता के प्रतिघत को
मजबूर कर 1971 तक 60 और 1976 तक 80
तक समाप्त हो सकता है। इन मध्यों की प्रगति के लिए
निस्संदेह बहुत मर्यादा प्रयास और सघन अपेक्षित है, पर
वे अव्यावहारिक नहीं हैं। हम सिफारिश करते हैं कि देश
भर से निरक्षरता को समाप्त करने के लिए हर
समय कीशिव को जाए और देश के किसी भी भाग में,
चाहे वह कितना ही पिछड़ा हुआ हो, इसके लिए 20 वर्षों
से अधिक न लें।

17.14 साक्षरता की अवधारणा—केवल पढ़-लिख लेने की योग्यता प्राप्त कर लेने को हम साक्षरता नहीं मानते। साक्षरता अभी साध्य होती है जब कामक्षम हो। साक्षर को साक्षरता के साधनों में पर्याप्त कुशल बनाया हो दृष्ट नहीं है, बल्कि उपयुक्त जानकारी प्राप्त करने के योग्य भी उसे होना चाहिए ताकि वह अपनी रुचि के काम और ध्येय को पूरा करने में सक्षम हो सके। निरक्षरता सम्मूलन के संरक्षक में यूनेस्को द्वारा विह्वलन में (1965) आयोजित शिक्षा मंत्रियों के विश्वसम्मेलन का यह निष्पत्ति था कि साक्षरता को साध्य मानने के बढ़ते समुदाय को सामाजिक, नागरिक और आर्थिक योगदान के लिए तैयार करने की ऐसी प्रणाली समझना चाहिए जो साक्षरता प्रशिक्षण की उन प्रारम्भिक सोचाओं को बाध पायी है जिसमें पढ़ने लिखने मात्र की शिक्षा शामिल है। रहन रहन के स्तर को उन्नत करने में सतृप्त काम आने वाली जानकारी को प्राप्त करने के अवसर व रूप में पढ़ना लिखना सीखने की प्रशिक्षण का उपयोग किया जाना चाहिए। पढ़ना लिखना केवल प्रारम्भिक सामान्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि कुशलता से काम करने, उत्पादित बढ़ाने, नागरिक जीवन में अधिक उपयोगी बनने और अपने पास काम की दुनिया को ज्यादा अच्छी तरह समझने के लिए होता चाहिए। अतः उसे मूलभूत मानव संस्कृति का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। इस इन सम्मेलन के विचारों से सहमत हैं। साक्षरता कार्यक्रम धरकों को वसतिगार करने और इन योग्य बनाने के लिए होने चाहिए कि वे अपने अक्षर ज्ञान का उपयोग अपने की शिक्षा के लिए कर सकें। उन्हें इस बात के लिए प्रेरित करें कि निरक्षर शिक्षा की उस योजना का लाभ उठा सकें जिससे यहाँ हम मान कर रहे हैं। इस दृष्टि से, साक्षरता कार्यक्रम में ये तीन अनिवार्य तत्व होने चाहिए

- (1) यह क्या समय "कार्यप्रारित होना चाहिए। ऐसी प्रवृत्ति और रुचि जागृत करना तथा ऐसी कुशलता और जानकारी प्रदान करना जगता स्वेय होना चाहिए जो व्यक्ति को उस काम में निरक्षरता प्राप्त करने में सहायक हो जिसमें वह सक्षम है।

(2) अवगड ब्याक्त को उससे ऐसी मदद मिलनी चाहिए कि वह बहु-वर्षीय राष्ट्रीय समस्याओं में रुचि ले सके और देश के सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन में प्रभावकारी भाग ले सके।

(3) उसके पक्ष-व्यक्ति अवगड व्यक्ति को पढ़ाई लिखाई और गणित में इतनी कुशलता प्राप्त हो जानी चाहिए कि उसके आधार पर यदि वह चाहे तो अपना-आप या अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से अपने-आप अपनी शिक्षा जारी रख सके।

इस प्रकार साक्षरता कार्यक्रम की तीन अवधारणाएँ होती हैं। प्रारम्भिक अवस्था में पढ़ाई लिखाई और गणित का सामान्य ज्ञान तथा समूह समाज से सम्बन्ध रखने वाली नागरिक और राष्ट्रीय समस्याओं की तथा शिक्षार्थी के अपने व्यवसाय की सीधी बहुत जानकारी, शामिल होगी। दूसरी अवस्था शिक्षार्थी के प्रारम्भिक ज्ञान और कुशलता को गहनता प्रदान करेगी। प्राप्त साक्षरता के सहारे वह व्यक्तिगत समस्याओं को हल करने और जीवन में समृद्ध बनाने में सक्षम हो सकेगा। यद्यपि को निरक्षर शिक्षा के किसी-न किसी कार्यक्रम में जुड़ा देने का काम सीमावर्ती अवस्था में होना चाहिए।

17.15 निरक्षरता की वृद्धि को रोकने के कार्यक्रम—निरक्षरता को समाप्त करने की दिशा में पहला कदम यह होना चाहिए कि निरक्षरों की बढ़ती हुई संख्या को इस प्रकार रोका जाए—

- साक्षरीकरण स्कूल शिक्षण का विस्तार कम से कम 5 वर्ष के लिए 6-11 वर्ष के आयु वर्ग के लिए किया जाए,
- 11-14 वर्ष के आयु वर्ग के उन बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा दी जाए जहाँ या ही स्कूल में पढ़ नहीं सके या पढ़ाई पूरी करने से पहले ही स्कूल छोड़ देंगे,
- 15-30 वर्ष के आयु वर्ग के उन युवा प्रौढ़ों को अनौपचारिक सामान्य और व्यावसायिक शिक्षा

दी जाए जिन्होंने स्कूल से कुछ वर्षों शिक्षा प्राप्त की है, पर वह इतनी पर्याप्त नहीं है कि उन्हें स्वाधीन साक्षरता की अवस्था तक पहुँचा सके। अथवा आस पास की परिस्थितियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें सुयोग्य बना सके।

17 16 अथवा सात में हमने 6-11 वर्ष के आयु-वर्ग के लिए सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को पूर्ति के कार्यक्रमों पर विचार किया है। हमने यह विचार रखा भी की है कि प्रारम्भ में 11-14 वर्ष के आयु-वर्ग के लिए कुछ वर्षों की अवकालिक शिक्षा को स्पर्धवात्मक स्पर्धक माध्यम पर हम जाना से की जाए कि उपयुक्त परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाने पर उसे अनिवार्य कर दिया जाएगा। हम यह भी जरूरी समझते हैं कि ये सुविधाएँ 15+ वर्ष के उच्च आयु वर्ग को भी दी जाए जिनकी स्कूली शिक्षा अपूर्ण है। स्कूली पढ़ाई की सुविधाओं के विस्तार को स्कूलों की धारण क्षमता के विचार के साथ-साथ उठाए गये थे। तब, निरक्षरता को मिटाने के मुख्य माध्यम होंगे।

17 17 कार्यनीति—साक्षरता की योजना। देश में स्पष्ट विधि की आवश्यकता और उचितता के अनुकूल ही बनाई जानी चाहिए। इस अन्वय में इस स्थिति का विश्लेषण करने का विचार नहीं है क्योंकि इस दायित्व के भार का अनुमान इस तथ्य से ही लगाया जा सकता है कि वर्ष 1961 की गणना के अनुसार, देश में 15+ आयु वर्ग के 18 9 करोड़ व्यक्ति हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा (19 प्रतिशत) शहरी क्षेत्रों की साक्षरता (47 प्रतिशत) अधिक है। साक्षरता के मापद्वय में देश के एक क्षेत्र की साक्षरता दूसरे क्षेत्र की साक्षरता से बहुत कम है—दिल्ली में 42 7 प्रतिशत से लेकर नेपा में 18 प्रतिशत तक। देश के विभिन्न भागों में स्त्रियों और पुरुषों की तथा विभिन्न सामाजिक वर्गों की साक्षरता में भी अन्तर है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में शिक्षा की प्रेरणा भी भिन्न है और शिक्षा के विकास और उपलब्धकरण जैसी अनेक बातों पर निर्भर है। स्पष्ट है कि इस समस्या को सुल-

झाने के लिए कोई एक या सरल तरीका नहीं हो सकता, अनेक विधियों की अति विविधता आवश्यक होगी तथा सुधार के उपाय ऐसी स्थानीय सुविधाओं पर निर्भर होंगे जो या तो उपलब्ध हों या उपलब्ध हो सकें। हम समझते हैं कि हम कुछ सामान्य सिद्धान्तों की ओर ही संकेत कर सकते हैं।

17 18 देश में निरक्षरता को मिटाने के लिए हम एक विविध कार्यक्रमों की सिफारिश करते हैं, जिसे सुविधा के लिए हम

(ए) ध्येयनात्मक पद्धति, और

(स) सामूहिक प्रदर्शित कह सकते हैं।

इन दोनों पर आधारित कार्यक्रमों का प्रारम्भ करें, उन्हें एक दूसरे का पर्याय न माना जाए।

17 19 ध्येयनात्मक पद्धति—ध्येयनात्मक पद्धति विशेष रूप से उन वर्गों के लिए उपयुक्त है जिन्हें सामाजी के अन्तर्गत जा सकता है, जिन पर नियंत्रण रखा जा सकता है और जिनमें साक्षरता के महान् कार्य के लिए प्रेरित किया जा सकता है। इन वर्गों की विविध आवश्यकताओं का पता लगाया जा सकता है और उन्हें पूरा करने के लिए सोई-संगत साधन उपलब्ध बनाया जा सकता है। इन वर्गों को समझना प्रशिक्षण माध्यम है और इनकी साक्षरता के लिए सगाई गई पूजा में परिणाम की प्रतिक्रिया और सामर्थ्य होवे। ध्येयनात्मक पद्धति का एक और लाभ यह है कि इसके साक्षरता कार्यक्रमों के अन्तर्गत ऐसा प्रशिक्षण भी शामिल किया जा सकता है जो ध्येय-साधक और श्रुतिक कर्म को बढ़ावा दे।

17 20 उपलब्धता के लिए, हम निम्नलिखित तीन सुझावों हैं जहाँ ध्येयनात्मक कार्यक्रम तत्काल बनाए जा सकते हैं और सबसे लाभ उठाया जा सकता है।

(1) औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थाएँ एक बहुत बड़े कार्यक्रमों पर जोर दे सकती हैं जिनमें लगभग 40 प्रतिशत निरक्षर होते हैं। यह समस्या इतनी बड़ी है कि इस पर ध्यान देना जरूरी है। हम सिफारिश करते हैं कि बड़े-बड़े कार्यों में तथा वाणिज्य, उद्योग, ठेकेदारी और

अथ समाप्ति में काम देने वालों को यदि आवश्यक हो तो कानून द्वारा इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए कि वे अपने सभी निरक्षर कामगारों को उनकी नौकरी बनाने के तीन वर्ष के भीतर इसका साक्षर बना दें कि वे अपना काम खला सकें। कामगारों को शिक्षित करने की पूरी जवाबदारी उनके निवेशकों की ही होनी चाहिए जो उन्हें किसी स्वीकृत कार्यक्रम के अनुसार शिक्षा देने की छूट दिया करें। निरक्षरों को प्रोत्साहन देने की व्यवस्था भी उन्हें करनी चाहिए और शिक्षा प्राप्ति के लिए यमौर खर्च के लिए प्रेरित करना चाहिए। उनकी शिक्षा पर होने वाला सारा खर्च सरकार को उठाना चाहिए और अध्यापकों वृत्तकों तथा पढ़ने को अन्य सामग्री की व्यवस्था करनी चाहिए। इस बात में हमें तब तक भी संदेह नहीं कि सम्प्रसारण निवेशता अपने कामगारों को शिक्षित कर सतत स्वयं सामर्थ्यवान् होने।

- (2) हम सिफारिश करते हैं कि सामाजिक क्षेत्र में विद्यालय औद्योगिक उद्यमों को पहला कदम परीक्षा उठाना चाहिए और इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को गति देनी चाहिए।
- (3) व्यक्ति और सामाजिक विकास की सभी योजनाओं का एक मानवीय पक्ष है। उससे ऐसे लोग नाचे सक्षम के सम्बन्धित हैं जिन्हें स्कूली शिक्षा नहीं मिली। इसीलिए यह एक सत्य है कि उद्योग ऊर्ध्व वाणिज्य स्वास्थ्य, शिक्षा आदि किसी भी क्षेत्र के विकास को प्रभावित करने कामगारों की विशेषकर निरक्षर कामगारों की शिक्षा उठाना अत्यन्त आवश्यक है।
- (4) सामाजिक कल्याण के विचार से लोगों को व्यक्तिगत रूप से शिक्षित करने के लिए सरकार ने जो कुछ योजनाएँ चलाई हैं, उदाहरण के लिए आर्य और प्रामोयोग योजना की आदी उदाहरण

योजना अथवा सामुदायिक विद्यालय विद्यालय की अनुपयुक्त पोषण और बात कल्याण कार्यक्रमों की योजना। जिनसे कई लोग स्थितियों का सम्बन्ध है। हमारा सुझाव है कि मान्यता कार्यक्रम को इस प्रकार की सभी योजनाओं का अनिवार्य रूप बनाया जाना चाहिए।

ये उदाहरण किसी तरह अन्तिम नहीं हैं। साक्षरता कार्यक्रमों की योजना बनाने वालों को अन्य उदाहरण खोजने चाहिए और उन्हें विकसित करना चाहिए।

17 21 सामूहिक पद्धति-सामूहिक पद्धति का सार यह है कि निरक्षरता को मिटाने के लिये देश भर में उपलब्ध सभी शिक्षित स्त्री-पुरुषों का एक बल संगठित किया जाए और साक्षरता अभियानों में उसका प्रभावकारी निवेश किया जाये। यह परंपरा पद्धति तो नहीं है परंतु प्रेरित है। जनसांख्यिक पद्धति अपनी आंतरिक सीमाओं में सिमटी हुई है। सक्षम बल के रूप में इसका उपयोग प्रचलित है। सामूहिक पद्धति विषय ही कारण ही सकती है। सामूहिक पद्धति को देश में उसके समीप सफलता मिलती है। अक्षय बल से और छोटे पैमाने पर ग्राम शिक्षण मुहिम के रूप में यह पद्धति गहाराष्ट्र में कार्यान्वित की जा चुकी है। निरक्षरता को मिटाने के लिये इस मुहिम में गांव की स्थानीय देश शक्ति का व्यवहार और अध्यापकों तथा स्थानीय शिक्षित नर नारियों का सहयोग लिया। इस योजना पर बहुत ही कम खर्च हुआ और जो लाख हुए वे साक्षरता के मान से कहीं अधिक थे। इस मुहिम के आयोजकों ने इसकी तयारी में यह कई कुछ कमियाँ और अनुवर्ती काम की कमजोरियों की ओर संकेत किया है। इन दोषों का उपचार किया जा सकता है।

17 22 निरक्षरता को मिटाने के लिये सामूहिक आंदोलन प्रशासनिक और शैक्षिक दोनों ही सामर्थ्य से बाहर है। ऐसा आंदोलन निम्न ही देश के राजनीतिक और सामाजिक नेतृत्व का दायित्व है। निरक्षरता राष्ट्रीय विकास में रुकावट बनती है—यह विश्वास राष्ट्रीय मामलों से सम्बन्धित क्षीमस्व व्यक्तियों के मन में जितना उठ होना उतनी ही सफलता इस पद्धति को मिलेगी। सफलता इस बात पर भी निर्भर है कि ऐसे व्यक्ति हैं

विश्वास को लोगों के दिल में कहा तक उत्तार सकते हैं और जनमें किसना प्रबल उत्साह और प्रेरणा जगा सकते हैं। हमारा विश्वास है कि यदि राष्ट्र-देसवासियों को साक्षर बनाने के लिए श्रुतिविश्वास है और इस काम के अनुसृत प्रयास और त्याग करने की तयारी है तो भारत निकट भविष्य में ही साक्षर राष्ट्र बन सकता है।

17.23 ग्रीक शिक्षा-समाज एक स्वेच्छित प्रक्रिया है जिसकी मूल प्रेरक शक्ति व्यवस्था की अपनी अंतःश्रेणी है। साक्षरों, शिक्षाविदों और प्रशासकों को यह स्पष्टतः जान लेना चाहिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा और एकता उत्पादित और जनसंख्या नियंत्रण, सामाजिक स्वास्थ्य और सामाजिक व्यवस्था-व्यवस्था प्रोत्साहित तथा प्रवर्धित द्वारा ही संभव होना। प्रत्येक शिक्षा या यह पक्षों पर यह बात साफ़ एकाएक इसकी स्पष्ट होगी कि ऐसी शिक्षा देने के लिए यह स्वेच्छा से कई पक्षों दे सके—इसलिए, यह जरूरी है कि साक्षरता कार्यक्रम ऐसे होने चाहिए कि वे बच्चों को साक्षर बनाने के लिए और उनकी प्रतिष्ठित परिस्थितियों तथा वातावरण से स्पष्टतया सम्बन्धित हों।

17.24 सामूहिक साक्षरता का अभियान अधिकतर सभी विधियों की स्वेच्छित सेवाओं पर निर्भर होता है जिनमें सरकारी कर्मचारी सामाजिक उपकरणों के उपयोग, बनीन, बायटर इन्फोमर और अन्य लोग शामिल हैं। पर इस अभियान का प्रमुख भार स्कूल और कालेजों के अध्यापकों पर पड़ना और उनके संगठन का प्रमुख व्यक्ति सभी प्रकार की शैक्षिक संस्थाओं पर पड़ना। इस सिफारिश करते हैं कि उपर्युक्त प्राथमिक, माध्यमिक उपर्युक्त माध्यमिक तथा व्यावसायिक स्कूलों और विद्यालयों को पूर्ण स्नातक संस्थाओं के विद्यालयों के लिए अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत रूप से, जिसकी चर्चा हमने अग्रिम की है, प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक उद्देश्य जाना चाहिए। जल्द ही आवश्यक यह भी है कि भविष्य में पर सभी प्रकार के व्यवस्थापक प्रोत्साहित की जाए और इस अभियान में अनिवार्य भाग लें। ग्रीक शिक्षा उनके सामाजिक व्यवस्था का अंग होनी चाहिए। उन्हें ऐसा करने में सहायता देने के लिए यह आवश्यक है

सकता है कि जो लोग स्कूल के सामाजिक कार्य से वह छूट दी जाए या प्रोत्साहित कार्य के लिए वारिधितिक दिया जाए। जब भी आवश्यकता पड़े, उनकी सेवाएं प्रोत्साहित सम्बन्धी कार्य में लिए उपलब्ध होनी चाहिए। विद्यमान व्यवस्था को साक्षरता कक्षाएं बनाना सभी शैक्षिक संस्थाओं के लिए आवश्यक होगा चाहिए और उन्हें अपने निकट के निहित क्षेत्र में निरक्षरता को समाप्त करने की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। क्षेत्र का आकार स्कूल के उन अध्यापकों और विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर निश्चित किया जाना चाहिए जो साक्षरता कार्य के लिये उपलब्ध हों।

17.25 स्कूल के लिये कार्य—ग्रीक शिक्षा को यदि जिम्मेदारी का अर्थ यह होगा कि स्कूल के कार्य और दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया जाए। उसका मुख्य कार्यक्षेत्र स्कूल के बच्चे तक ही सीमित नहीं होगा। बल्कि वह शारीरिक स्थानीय जनता उसकी परिधि में आ जायेगी जिसको यह सेवा करता है। उसे समुदाय के जीवन के दृष्टि से कार्य करना होगा। बच्चे स्कूल में बच्चे उसका रूप बदलकर जनता का स्कूल हो जायेगा। ऐसी स्थिति में उसे समुदायिक जीवन के केंद्र और विस्तार सेवाओं के महत्वपूर्ण आधार के रूप में सज्जित और तैयार करना होगा। अन्य व्यवस्थापक सामग्री के अभाव में, उन्हें पुस्तकालय, रेडियो, प्रदर्श, रसदार, भाष्य और ग्रीक शिक्षा की अन्य सामग्री रखनी होगी।

17.26 साक्षरता कार्यक्रमों की सफलता के लिए आवश्यक शर्तें—साक्षरता का एक धर्म रहा आवश्यक है। ग्रीक साक्षरता का कोई भी अभियान पूरा योजना और सतत सेवाओं के बिना नहीं चलाना चाहिए। यद्यपि हमारा सुझाव यह नहीं है कि किसी कार्यक्रम को आरम्भ करने से पहले प्रत्येक क्षेत्र का वर्गीकृत अध्ययन और सर्वेक्षण अवश्य है, तथापि हमारा विश्वास है कि यदि नीचे लिखी अपेक्षाएँ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखा जाये तो साक्षर होना और निराशा नहीं होगी

(1) किसी भी कार्यक्रम को आरम्भ करने से पहले लोगों में रुचि जगाने और उनकी समायोजन प्राप्त करने के लिये सभी सामाजिक, सामाजिक

और अन्य नेताओं को तथा सभी सरकारी विभागों को जुट जाना चाहिये।

- (2) जिन प्रौढ निरक्षरों को कार्यक्रम में शामिल करना हो उन्हें मनोवैज्ञानिक दृष्टि से तैयार करना चाहिए और उनमें प्रेरणा जगानी चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि साक्षरता का उनके लिए क्या अर्थ होगा और उन्हें विश्वास दिलाना चाहिए कि साक्षरता प्रगति के लिये वे को प्रयास और स्थाय करेवे, यह उन्हें गहरी किया जावेगा।
- (3) लोगों के मन में हड़ निश्चय बनाने, उसे बनाये रखने तथा कार्यक्रम के दौरान और बाद में उन्हें सहारा देने के लिये सामूहिक संचार साधनों का व्यापक उपयोग करना चाहिए। साक्षरता कार्य की सफलता के लिये अनुकूल पाठ्यावरण बनाने और उसे बनाये रखने के लिए रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, पापण और अन्य साधनों का उपयोग किया जाना चाहिए।
- (4) प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम के लिए आवेक्षित सामग्री पहले से ही तैयार कर लेनी चाहिए और अभियान शुरू करते समय उचित पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। इसमें पाठ्य-पुस्तकों और अन्य पाठ सामग्री, चार्ट, नक्शे, निर्देश-पुस्तकें और अन्य दौलिक सामग्री तथा कार्यक्रमों के लिए गृहमयक सामग्री बांटी होनी चाहिए।
- (5) साक्षरता कार्यकर्ताओं को योजना स्थानीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर संचालनी से बनाई जानी चाहिए। पहले शिक्षने में कुछ बनाने के बिना निरक्षर व्यक्तियों को उनके व्यवसाय के सम्बन्ध में जानकारी और कुशलता बढ़ाने में भी सहायता मिलनी चाहिए, वे अपने समुदाय, देश और सहारा की महत्वपूर्ण समस्याओं के प्रति जागरूक हो जाएं और उन्हें जनसंख्या नियंत्रण जैसे गृह-

त्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका देना आवश्यक जान पड़े और देश के जीवन और संस्कृति में समझने में सहायता मिले।

- (6) साक्षरता कार्यक्रम ऐसे हों जिनमें सबसे अधिक निरक्षर शिक्षा देने के लिये सहायित रहें। साक्षरता को सर्वाधिक सफलता तभी मिलती है जब व्यक्ति अपनी समस्याओं को स्वयं ही सुलझाने के लिए अपनी जानकारी का उपयोग करना सीख जाता है और स्वयं, पुस्तकालय तथा सत्रात्मक जैसे ज्ञान-वृद्धि के साधनों से लाभ उठाने सक्षम है। योजनाबद्ध अनुवर्ती कार्यक्रम साक्षरता अभियान का अनिवार्य अंग है।
- (7) यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि साक्षरता कार्यक्रम, जैसी रूपारी एकलपना है, केवल व्यापकता के अन्तर्गत नहीं चलाए जा सकते। व्यापकता के अर्थ को इस प्रकार सहारा मिलना चाहिए
- (क) विश्वविद्यालयों और उद्योग, कृषि, जन-स्वास्थ्य, सहायिता, सामुदायिक विकास आदि विभागों की विस्तार-नेतृत्वों के द्वारा लोगों को व्यावसायिक जानकारी कुशलता और बढतिपों की विस्तार करने में सहायता मिलनी चाहिए, और
- (ख) नागरिक जीवन और राष्ट्रीय विकास के अङ्गत्वे कार्यक्रमों के प्रति प्रौढ निरक्षरों को चेतना बढ़ाने के लिए सामूहिक संचार साधनों और विशेषतः साक्षरता कार्य के उपयोग किया जाना चाहिए।
- (8) यदि पुस्तकालयों की स्थापना नहीं की गई और अच्छी पाठ सामग्री तथा संचार पत्र संचालन में विस्तार रहे तो साक्षरता-कार्यक्रमों के प्रभाव स्थायी नहीं होंगे।
- (9) सोच समझकर बनाई गई कार्य योजना में स्थानीय नागरिकों, अन्य अधिकारियों तथा

नेताओं का पूर्ण प्रतिपाद्य समितित होना चाहिए। कार्यक्रम से सम्बन्धित व्यक्तियों को कार्रवाई विस्तार से समझा दी जाए और यह भी बता दिया जाए कि विशेष रूप से उन्हें क्या करना चाहिए।

- (10) जो रिटायर् और शिक्षित व्यक्ति पढ़ने के लिए अपने नाम दें, उन्हें शिक्षण पद्धतियों और प्रौढ़ों से व्यवहार करने के बारे में अल्पकालिक प्रशिक्षण दिया जाए। उनके लिए निरर्थक पुस्तकों और अन्य सहायक सामग्री को भी व्यवस्था की जानी चाहिए।

- (11) प्रशासन और वेल्फेयर के लिए एक कार्यपुस्तक सफाई अपेक्षित है। सर्वोच्च संस्थाओं का सहयोग सुनिश्चित होना चाहिए तथा सततता पूर्ण मूल्यांकन और अनुमोदन का जग मौ मिलना चाहिए।

- (12) सशक्त साक्षरता अभियान को समाप्ति के बाद जो कार्रवाई करनी हो उसका समन्वय भी योजना में होना चाहिए। साक्षरता कार्यक्रमों में जाए केन्द्र बानों को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि शिक्षा जारी रखने के लिये वे एक दूसरे की सहायता करें और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये अध्ययन-सत्रों, सत्राओं, बसों या गरीब राज सत्रों की स्थापना करें।

- (13) साक्षरता कार्यक्रमों की सफलता के लिए सार्वजनिक प्रतिबद्धता, समर्पण और उत्साह अत्यावश्यक है। कार्यक्रम की सफलता पर सार्वजनिक प्रशंसा, प्रतिनिधियों की जिम्मेदारता पर सार्वजनिक जिम्मेदारता, प्रशिक्षण के सुधार में सार्वजनिक सहयोग, उद्घाटन कार्यक्रमों को सार्वजनिक प्रोत्साहन—ये सभी बातें अत्यन्त महत्व की हैं। समाचार पत्रों, साप्ताहिक और राजनीतिक नेताओं, विद्वानों और अन्य सभाओं की सहायता से जन-सहयोग और समर्थन को बनाए रखना आवश्यक है।

17.27. स्त्रियों में साक्षरता—स्त्रियों में साक्षरता को स्थिति विशेष दुखदायी है। सन् 1961 की जनगणना से पता चलता है कि सहरी क्षेत्रों में 34.5 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 8.8 प्रतिशत स्त्रियाँ साक्षर हैं। यह संवेगान्व है कि जब तक स्त्रियाँ साक्षर नहीं हो जाती, सामाजिक स्थानान्तरण की कोई आशा नहीं। फिर भी, यद्यपि स्त्रियों को साक्षर बनाने के नगण्य प्रयत्न हुए हैं। इस सबसे जोरदार निष्कर्ष नहीं कर सकते कि स्त्रियों में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की स्त्रियों में, साक्षरता बढ़ाने के लिये साहसपूर्ण सुविधाएँ और प्रभावकारी कदम बहुत जल्द उठाने चाहिए। इस रिपोर्ट में इन कारणों पर विस्तारपूर्वक विचार करने की आवश्यकता नहीं है जो स्त्रियों के बीच साक्षरता कार्यक्रम चलाने में बाधक हैं। यह सर्वविदित है कि स्त्रियों में शिक्षण की प्रणाली ही होती है, स्त्रियों के बीच साक्षरता कार्यक्रम चलाने में सामाजिक बाधाएँ बाधक होती हैं, स्त्रियों को अवकाश कम ही मिलता है और वे निश्चित ही सब समय की प्रतीक्षा में बैठी नहीं रह सकतीं जब उन्हें पढ़ने की फुर्सत हो। स्त्रियों के लिये अध्ययन सत्रों की समस्या सबसे कठिन है। कुछ कठिनताएँ तो हमारे इस मुद्दे से दूर हो सकती हैं कि उन्हें पढ़ाने का काम स्कूल के बच्चों की सीमा जाए। बच्चे घर-घर जाकर स्त्रियों को उनकी सुविधा के समय में पढ़ा सकते हैं। घर-घर जाकर स्त्रियों को पढ़ाने वाले इस 'छोटे अध्ययन' का सामाजिक विरोध भी नहीं होगा।

17.28. भाषा की बातें हैं कि स्कूलों में अध्यापक अध्यापिकाएँ नियुक्त की जाएँगी और स्कूलों द्वारा केवल छात्रों को निरंतर स्त्रियों को पढ़ाने की विशेष जिम्मेदारी उन्हें सौंपी होगी। फिर स्त्रियों की शिक्षा अबूरी रह गई है उनके लिये 'सह पाठ्यक्रम' बनाने तथा शिक्षा और उपर्याओं से कुछ संशोधन में उन्हें सारे प्रशिक्षण देने की व्यवस्था केन्द्रीय सचिव कक्षाओं को द्वारा सार्वजनिक शिक्षा योजना में है वह हम सशक्त जान पड़ती है। हमारा यह भी सुझाव है कि ग्रामीण स्त्रियों को पढ़ाने और स्थानीय स्त्रियों में प्रौढ़ शिक्षा के प्रसार के लिए 'ग्राम गुरु' की नियुक्ति की जानी चाहिये। जहाँ तक

हो प्राप्त रहन ऐसी स्थानीय स्त्रो ही होनी चाहिए बिन्हे प्रौढ शिक्षा काम के लिए कुछ बेतन दिया जा सके । वह प्रगतिगत होनी चाहिए और प्रौढ शिक्षा के नए तरीके सीखने के लिए उस समय समय पर दुबारा प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए । सहरी श्रमों की स्थितियों के बीच सावधानता प्रसार सरकारी पब्लिक मोबी और सेवानिवृत्त व्यक्ति कर सकते हैं ।

17 29 रेडियो, टेलीविजन और दृश्य-श्रव्य साधना का योगदान—हमारा विचार है कि निरक्षर और अशिक्षितों की भारी संख्या राष्ट्र जीवन और उसके विकास के लिये बहुत बारीर बाधा है । इसलिए उनी गिना म देख करना सतरा मोन लेना है । यह भी स्पष्ट है कि निरक्षरता धीरे धीरे ही मिट सकती है । अधिकतम राष्ट्रीय प्रयास के लिये के फलस्वरूप देश के कुछ ही मासों में सम्पूर्ण साक्षरता के लिये दो दशक लग सकते हैं । इससे अतिरिक्त यह भी देखा गया है कि साक्षरता का उपयोग करने में जो पढ़ना है उसका चुनाव करो म और जो पढ़ा गया है उसे समझने में समय सक्षता है । जिहे लभ्ये समय तब विधिवत् गिना मिली है उहे भी पठन-समता का नाम बढ़ाने के लिये शैक्षिक परिपक्वता की जरूरत पड़ती है । फिर भी दोनों को शिक्षित करने का काम तब तक रुका नहीं रहना चाहिए जब तक कि वे साक्षर न हो जाय, बल्कि यह काम साक्षरता कार्यक्रम तब तक, उसके साथ साथ और बाद में भी होना चाहिए । इसी उद्देश्य से हमने तैयारिग की है कि सामुहिक सार-साधनों और चिकनी तथा अन्य दृश्य श्रव्य साधनों का पूरा पूरा साथ बढाया जाए । भारत में मिनेमा रेडियो शिक्षा पिय पिय और इस प्रकार के अन्य साधन पहले से ही निरक्षर और साक्षर दोनों को शिक्षित कर रहे हैं । इन गिना और अगिना के बीच चुनाव नहीं करता है, बल्कि चुनाव ऐसी गिना जः राष्ट्रीय विकास और एतता के लिये आवश्यक है तथा यह जो सेवक सामोद समोर-जन व निरक्षरों को है म बीच करना है । दोनों के साथ सहर और उनसे प्रीति सतर को सुधारने के लिए अनुसूच जाजायण तथा तथा जाजकारी और कुत्तता प्रान करन के लिये सामुहिक सार साधनों का उपयोग

सहायक माध्यम के रूप में होना चाहिए । इस दिशा में हमारा विचार यह था कि प्रौढ शिक्षा के लिए रेडियो और टेलीविजन सेवाओं के उपयोग के सम्बन्ध में व्यापक सिफारिशें प्राप्त की जायें । परन्तु ए० के० चट्टा की अध्यक्षता में सूचना और प्रसारण मन्त्रालय द्वारा स्थापित समिति की रिपोर्ट ने हमारा काम बहुत हल्का कर दिया है । इस सम्बन्ध के सम्बद्ध परामर्शों में शिक्षा है कि विभिन्न प्रौढ शिक्षा कार्यक्रमों के लिये रेडियो और टेलीविजन का क्या विशेष उपयोग किया जाय । प्रौढ शिक्षा के क्षेत्र में रेडियो और टेलीविजन के उपयोग के सम्बन्ध में सूचना और प्रसारण समिति द्वारा की गई सिफारिशों का हम सामान्यतः समर्थन करते हैं । हम समिति के सहमत हैं कि टेलीविजन निरक्षर प्रौढों के लिये अधिक उपयुक्त साधन है । अपेक्षाकृत कम शिक्षित स्त्रियों को और अनपढ़ों को सामान्य शिक्षा देने के लिए टेलीविजन और रेडियो दोनों का उपयोग किया जा सकता है और किया जाना चाहिए, इनका उपयोग बढावन बढ़ाने और समाज को बदलने के साधन के रूप में भी किया जाना चाहिए । आधुनिक जीवन की परिस्थितियों में जनता की प्रगति और संचि निश्चित करने में रेडियो, टेलीविजन और विविध का योग महत्वपूर्ण हो सकता है इसलिए यह आवश्यक है कि उनका उपयोग मानवीय और राष्ट्रीय हित में किया जाय । बहुसंख्य जनता को उपयोगी जानकारी देने और उन्हें यह समझाने के लिए इसके बढा और रोई साधन नहीं हो सकता कि देश बढा चाहता है और किस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए और समय कर रहा है ।

17 30 अनुवर्ती धार्य—सारे अभियान स्वभावता समाप्त हो जाते हैं पर साक्षरता अभियान समाप्त नहीं होता । यदि गिना प्राप्ति की प्रविधा किसी न किसी रूप में जारी न रहे तो साक्षरता-अभियान का उद्देश्य ही समाप्त हो जायगा । प्रायः वस्तु की जाने जाती यह विज्ञा अनुभव से सिद्ध हो चकी है कि साक्षरता कार्यक्रम के बाद निरक्षरता घीम ही पुन जा भरती है । सीमित विज्ञान साधना और प्रगतिग पात्रियों में अभाव में जब निरक्षरों को पढ़ाने के लिये विद्यापियों और अध्यापकों की

वैज्ञानिक सेवाओं का उपयोग करना आवश्यक हो जाता है तब यह आग का प्रदल हो जाती है। जीवन के विधी उद्देश्य की पूर्ति के लिए समस्तार उपयोग करने पर ही प्राप्त साक्षरता की बनाने रखा जा सकता है। हम यह सुझाव दे चुके हैं कि साक्षरता कार्यक्रमों की प्राथमिक व्यवस्था के रूप में शिक्षा प्राप्ति को रखा जाना करना कितना जरूरी है। वास्तव में सामाजिक शिक्षा सामूहिक तयार सामग्री तथा अन्य ऐसे साधनों की सहायता से गुरु की अपनी चाहिए जिनसे लोगों को जीवन के सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक सम्म का ज्ञान हो सके। साक्षरता की आवश्यकता और उसके अभाव में होने वाली हानि या अनुभव निरक्षर को ही होना चाहिए। पढ़ना मिलना सीखने हुए उद्योग किए यह जानना भी जतना ही आवश्यक है कि प्राप्ति ज्ञान का उपयोग वह किस तरह कर सकता है। निरक्षरों को पढ़ाने के लिए विद्यापियों और शिक्षित स्वयं सेवकों को परिस्थितियाँ ही समान; पढ़ता है परंतु वे प्रयोगों को बहुत ही कम भावें बड़ा पाते हैं। वे पढ़ना पढ़ना और गिनती शिक्षा सकते हैं और निरक्षर का उनके अक्षिणत और मायिक जीवन की कुछ समस्याएँ भी समझ सकते हैं। इस प्रारम्भिक अवस्था के बाद अध्ययन नियमित अम्मा पढ़ी द्वारा स्कूलों में होना चाहिए और नवसाक्षरों की घेरी बीच विविध प्रकार की ऐसी मनोव्यापिक विधा की और प्रयुक्त शक्तों चाहिए जिसकी वर्षा हम आगे करेंगे। प्रौढ़ों को यह सिखाया कि अनौपचारिक और सामक लिए वे पुस्तकालय का उपयोग किस तरह कर साक्षरता कार्यक्रमों का प्रयुक्त सब होना चाहिए। ज्ञातम यह कि हम इस बात पर बल देना चाहते हैं कि अनुवर्ती कार्यक्रम साक्षरता कार्यक्रम से भिन्न नहीं है। अनुवर्ती कार्य के अति वाय तदय साक्षरता-कार्यक्रम में ही निहित होने चाहिए। यह समझना बहुत है कि अनुवर्ती कार्य विधि के अन्तर्गत परीक्षित पाठ्यक्रम साक्षरता अध्ययन की समाप्ति पर और पढ़ने के पढ़ना निरन्तर छेदने से पर ही शुरू किए जाने चाहिए। साक्षरता के हवीनीय कार्यक्रम के रूप में ही ऐसे सब होने चाहिए जो साक्षरता को स्थायी और उपयोगी बनाने में लिए जरूरी हों। साक्षरता का एक

बार शुरू हो जाने पर उसे प्रौढ़ शिक्षा के विविध रूपों में ऐ किसी न किसी एक रूप के साथ समाविष्ट कर देना चाहिए और सीखने की प्रक्रिया एक बार शुरू हो जाने में उसे जारी रखने के लिये प्रोत्साहन देना चाहिए।

17.51 हमने सुझाव दिया है कि साक्षरता और प्रौढशिक्षा कार्यक्रमों की योजना में अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सामग्री भी तयार की जानी चाहिए जो आवश्यकता पड़ते ही गुप्त हो सके। नवसाक्षरों के लिए पाठ्य पुस्तकों में पसन्द तथा विविध प्रकार का अध्ययन—जैसे सूचना पत्र, पत्रिकाएँ, पुरितकाएँ, निम्न कृषि विज्ञान अवकाश मिल्य या प्रयोगों की तब के किसी विषय के किसी पत्र के बारे में उपयोगी सूचना हो—सामयिक सहाय की सामग्री हैं। अध्यापक स्वयं सबको भी बड़ी सहाय के लिए सहायक विद्यम पुस्तकों तथा ऐसे ही अन्य साहित्य के गुजन का भी बड़ा हो यह है। बात सबसे, माहल छिमे प्लेस पट्टियाँ और विविध प्रकार के अन्य द्रव्य अध्ययन तयार करना बहुत आवश्यक है। यह विद्यमान कार्य है। इसके लिए बहुत सूक्ष्म बुद्ध और सतर्क चाहिए। यदि सामग्री तयार न हुई तो साक्षरता कार्यक्रम रुक जायेंगे। सामग्री तयार करने का काम बहुत से स्तर होना चाहिए। कम से कम निरक्षरों तथा उनके व्यावसायिक या अन्वयसायिक अध्यापकों के लिए पुस्तकों को तयार करनी को चाहिए। माया सम्म की कारणों से और प्रत्येक भाषा में पुस्तकों की भारी मात्रा के विचार से प्रत्येक राज्य में साहित्य गुजन के लिए एक सतम अनुभाग की स्थापना जरूरी हो जाएगी। स्थानीय समस्याओं हितों का ध्यान रखने से वे पुस्तकों खर्चक हो सकेंगी। यह सुनिश्चित करने के लिए अन्तराज्य सहयोग होना चाहिए कि जो साहित्य तयार किया जाए वह राष्ट्रीय नीतियों का प्रसार करे और राष्ट्रीय स्तरा तथा देशभक्ति की भावना को सहाय करे। अन्तराज्य सहयोग से कुछ भाषाओं में उत्साहन सागत को घटाने में भी मदद मिल सकती है। हमारा विचार है कि साक्षरता और प्रौढ शिक्षा में कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित साहित्य के गुजन के लिए राज्यों और विभागों के बीच सहयोग स्थापित करने का काम शिक्षा मन्त्रालय की करना चाहिए।

निरन्तर शिक्षा

17.32 महत्त्व—समय बीतते-बीतते निरन्तरता

समाप्त होनी चाहिये और स्कूल-पद्धति द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उसकी पुनरावृत्ति न हो। राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति में प्रौढ़ शिक्षा का कार्य निरन्तर चलता है। द्रुत परिवर्तन ज्ञान की पृष्ठभूमि के विचार से मनुष्य को निरन्तर सीखते रहना होना चाहिए यह पूर्णता से है। सीखते रहना सभ्य जीवन की रीति है।

17.33 अब यह सिद्धान्त सर्वमान्य हो गया है कि शिक्षा की आधुनिक पद्धति के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की और विभिन्न स्तरों की पूर्णकालिक शिक्षा की ही व्यवस्था नहीं होती बल्कि उसमें पाठ्यक्रम और अध्यापन के ऐसे बहुविध प्रकार सम्मिलित होते हैं जो पूर्णकालिक स्कूली शिक्षा के अनिर्दिष्ट प्रौढ़ों के व्यक्तिगत, व्यावसायिक सामाजिक और भयं हितों का साधन में सहायक होते हैं। इस दृष्टि से प्रौढ़ शिक्षा ऐसी उपज और फल है जिसके लिए विविधतया नामांकित अध्यापन केवल रोपण और वर्षण का काम करता है। यह आवश्यक की बात नहीं है कि विकसित समाजों में प्रौढ़ शिक्षा, शिक्षा का सर्वाधिक तेजी से बढ़न वाला अंग बन गई है।

17.34 सामान्य शिक्षाविशेष—भोटे स्तर पर निरन्तर शिक्षा की पद्धति ऐसी होनी चाहिए जो दो विभिन्न स्तरों के लोगों के लिए उपयुक्त हो। इनमें पहला वर्ग उनका है जो दीर्घकालिक व्यवसायों में या विविध ऐंजिनिंगों द्वारा विविध विषयों में आयोजित तदर्थ शिक्षा की कक्षाओं में मध्यकालिक अध्यापन के लिए दूसरों के साथ विश्वर समूह बना सकते हैं। ये ऐंजिनिंग हैं—विकास से सम्बन्धित विभाग, विश्वविद्यालय, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, तकनीकी, व्यावसायिक और कृषि शिक्षा संस्थाएँ या विदेश मंत्रियों और स्टेन्डिड संस्थाएँ। दूसरा वर्ग उन लोगों का है जिन्हें अपने घर उस समय के बीच बचना है जो उन्हें इस उद्देश्य से मिले, घर जो अपनी सुविधा के अनुसार सहायता चाहते हैं। प्रौढ़ शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो विविध उद्देश्य पूरे करे और प्रौढ़ों के ऐसे विभिन्न समूहों के काम आए जिनके वैश्विक स्तर ही मिन नहीं हैं, बल्कि जिनको व्यावसायिक एवं सांस्कृतिक महत्वादाशाएँ और सांस्कृतिक मामलों में प्रति दायित्व-

भाव भी एक दूसरे में मिन हैं। हम पहले लोगों का उत्तेजक कर चुके हैं, जिन्हें प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के पूर्व ही स्कूल छोड़ देना पड़ा, और सुझाव दे चुके हैं कि उन्हें इस स्तरकी शिक्षा पूरी करने योग्य बनाना चाहिए। ऐसे लोग जो हैं जो विविधतया शिक्षा को पूरा करना चाहते हैं और अनेक विषयों में, जिनमें विज्ञान, शिल्प विज्ञान और कृषि शामिल हैं, विश्वविद्यालयी डिग्री लेना चाहते हैं। ऐसे भी हैं जो सेवों, कारखानों, फ़ैक्टरियों, वाणिज्य संस्थानों में काम कर रहे हैं, और ऐसे जो अपने ही घरों में बने हैं और अपनी कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण चाहते हैं। उनके व्यवसायिक स्तरों पर कार्यरत व्यक्तियों को भी अपने ज्ञान को ताजा करने और अपने विशिष्ट क्षेत्र में हुए नव-चिन्तन और नई रीतियों की जानकारी प्राप्त करने की जरूरत होती है। विशेषरूप से सभी स्तरों के अध्यापकों को, जिनमें विश्वविद्यालय के अध्यापक भी शामिल हैं, जवहर विषय चाहिए कि वे ज्ञान के बढ़ते हुए सीमानों में परिचित रह सकें। यही बात वकीलों, बाजारों, व्यापार व्यवसायों, उद्योगप्रमुखों और व्यवसायों के अन्य शीर्षक व्यक्तियों पर भी लागू होती है, ऐसे लोग भी हैं जो केवल 'स्वतन्त्र सुधार' कुछ न कुछ सीखना चाहते हैं, उदाहरणार्थ, कोई विदेशी भाषा, या चित्रकला, या समीप या आन्तरिक सुरक्षा, पाकशास्त्र, पुष्प-विद्या, या कोई ऐसा काम जो उनके व्यवसाय से सम्बन्धित नहीं है। प्रौढ़ शिक्षा को सब की सब और आवश्यकता के अनुकूल बनाना जाना चाहिए। महत्त्व की बात यह है कि बहुविध विषयों के विचार से तैयार किए गए प्रच्छेद और कल्पनापूर्ण पाठ्यक्रम ही अध्यापन की प्रेरणा देने वाले सफल साधन बन जाते हैं।

17.35 हम शिक्षाविशेष करते हैं कि सभी प्रकार की और सभी स्तरों की वैश्विक संस्थाओं को प्रोत्साहन और सहायता दी जाए कि काम के निर्मित पटों को छोड़कर ऐसे समय में किन वैश्विक पाठ्यक्रमों की व्यवस्था कर सकें, करें, और बदले द्वारा उन सब लोगों के लिए खोजें जो शिक्षा प्राप्त करने में योग्य हैं और जिला पाने के

लिए इच्छुक हैं। इन दृष्टिकोण को सतार-भार में समर्थन मिला है, पर हमारे देश की परिस्थितियों के विचार से तो स्वीकार करना अत्यन्त आवश्यक है, यद्यपि उचित शिक्षा या प्रशिक्षण प्राप्त किए बिना ही जीवन आरम्भ करने के लिए देश की ऐतिहासिक परिस्थितियों ने बहुतों को विवश किया है। इसलिए हमारा सुझाव है कि उन लोगों के लिए, जो सैद्धांतिक समस्याओं से वैज्ञानिक काम को व्यवहार के कुछ घटो के बीच अवस्था अन्य सुविधानलक्ष समर्थ में हो जा सकते हैं, एक समान-तर शिक्षा-पद्धति अपनाई जाए ताकि वे भी उस प्रवाह-धर्म विधोवाधो और विधिओं के लिए अर्हता प्राप्त कर सकें जिनके लिए सैद्धांतिक समस्याओं के नियमित विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। देश के विभिन्न भागों में छात्रकालीन कालेज का जो विकास हुआ है, वह हमें प्रामुख है। हमें शायद है कि विभिन्न भागों में चलने वाले छात्रकालीन कालेज ऐसे वातावरण में अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करेंगे जिनमें अध्ययन की प्रेरणा मिल, नियमित शिक्षा पद्धति में बाहर के लोगों को नाममात्र की हानिरी दर्ज करते परीक्षामो प्रवेश की पात्रता खरीदने के योग्य नहीं

बनाये। भाष्यमिह स्कूलों और कालेजों को ही नहीं, सभी समस्याओं को निपेक्षक व्यावहारिक, तकनीकी और कृषि संस्थाओं को काम के नियमित घटो के बाद अद्य-कालिक शिक्षा की व्यवस्था करने चाहिए।

17 36 सैद्धांतिक समस्याओं को ऐसे तर्क-वाटपक में प्रणाली होना चाहिए जो लोगों की अपनी समस्याओं को समझने और उन्हें हल करने में तथा व्यापक ज्ञान और अनुभव प्राप्त करने में सहायता दें। संसाधन के लिए भूमि प्रणय, उर्वरकों का प्रयोग, मुर्गी-पालन, कलो-पालन, छिन्नुपालन, पोषण, उपवर्ग सम्बन्धी सक्षित वाटपक्यों के नाम मिलाए जा सकते हैं। ऐसे कार्यक्रमों की समावधानों अलग हैं जहाँ की सज्जों तरह योजना बनाई जाए और सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों, कालेजों, तकनीकी संस्थाओं और स्थायीय नेताओं का सहयोग मिले। इन वाटपक्यों की आशोक्षित करना ही पसंद नहीं, पक्षों की बाध है-सोचों में अध्ययन, जो प्रवृत्ति कक्षाओं और विभिन्न वाटपक्यों में दृष्टि लेने वालों के समूह संगठित करता।

—कमल:

अखिल भारत नयी तालीम

कार्यकर्ता सम्मेलन

२५, २६ तथा २७ मई १९७६

को

पश्चिम बंगाल में होगा।

सम्मेलन के निश्चित स्थान की सूचना बाद में दी जायेगी।

सम्मेलन में भाग लेने हेतु प्रतिनिधि अपना शुल्क रुपये आठ प्रत्येक की दर से श्री बजू भाई पटेल, मंत्री, अखिल भारत नयी तालीम समिति, राष्ट्रीय शिक्षण मन्दल, नूतन, बम्बई।

४००५४ को भेजकर रेलयात्रा या रियायती फार्म भेजावे।

जब तक लाखों बरोणों लोग
 भूख और अज्ञान से ग्रस्त हैं
 तब तक मैं उस आदमी को
 गद्दार मानता हूँ
 जो उन गरीबों के दो पैसों से
 भीखकर उनकी ओर कोई ध्यान नहीं देते।
 मेरे विचार के अनुसार हमारा
 सबसे बड़ा राष्ट्रीय पाप है
 आम जनता की ओर हमारी उपेक्षा
 और हमारी अवनति का
 एक कारण यही है।
 बिलौरी भी राजनीति करते रहो
 उसका कोई लाभ होने वाला नहीं है।
 जब तक कि भारत की आम जनता
 अच्छी तरह शिक्षित नहीं होती।
 उन्हें उच्च शिक्षा नहीं मिलता
 और उनकी फिक्र नहीं की जाती।

—महात्मा विवेकानन्द



नयी तालीम

विश्वविद्यालय प्राणियों में अस्तित्व
सामाजिक परीक्षाएं
ग्रैंड शिक्षा की पृष्ठभूमि
हमें स्कूल क्यों समाप्त करना है
पूर्व बुनियादी या नर्सरी शिक्षा



अखिल भारत नयी तालीम समिति

पृष्ठ २७
पत्रवरी
मार्च

अंक

प्रधान सभापति— श्री के० ब्रह्माचर्य

सुभाषक महल— श्री द्वारिका सिंह

શ્રી. વજુ માઈ પટેલ

श्री कलशोनाथ त्रिवेदी

શ્રી જ્યોતિ શર્મા બટેલ

सम्पादक श्री हव.प्र. दत्त त्रिवारी

सह सम्पादक श्री बन्धुप्रसाद

सम्पादकीय

पृष्ठ ६

विराजविद्यालय प्राङ्गणों में लसतोज

सांख्यिक परीक्षाएँ

सम्पूर्णतः स संस्कृत विश्वविद्यालय का प्रीत शिक्षा केंद्र

॥०॥ वेवेण्ड दस तिथारी ३

श्रीकृष्ण सिंघा की वृद्ध भूमि

डा० सीताराम आदसवाल ५

शिक्षा में धार्मिक शिक्षा का स्थान

पञ्चावली सासप्रीवासा ६

हमें सबूत क्यों समझना करना है

શ્રા. લેલે-દસ તિયારો ૮૨

¹ मोक्ष शिक्षा कोठारी महिला माध्यम की रिपोर्ट

24

मौढ शिष्याः ये व्याख्यातवन्ति

सुप्रीम न्यायालय २२

पूरं बुद्धिदायी या नमोरो विद्या

श्रीमद। त्रैलोक्य-चन्द्रिका २१

| दीर्घ पर प्रतिबन्ध

१९

ਫਰਵਰੀ ਮਾਸ '੭੬

मरी ताहीम का वार्षिक गृहक वारद रुपये तथा एक अंक का मुन्ध दो रुपये है ।

नवी ताचीस वैसाहिक धनिका दी, इशका मय जवस्त वी मारण्य होसा हे ।

१५ व्यवहार के लिए सभी पाठक सुपना अपनी साहस कह्या अवश्य लिखें ।

नयी द्वासीय से व्यक्त विचारों का साहित्य प्रभंतया लेखन का है ।

नयी तालीम

विद्यार्थी, प्रशिक्षकों तथा शासक विचारों के लिए

विश्वविद्यालय प्रांगणों में असंतोष

देशीय विद्या मन्त्री डा० प्रतापचन्द्र ने मोहताजा में बताया कि वह कहना चाहते हैं कि अधिकांश विश्वविद्यालयों में असंतोष है और संसिद्ध कार्य आत व्यत है। उन्होंने आँखें देते हुए कहा कि देश के १०२ विश्वविद्यालयों में केवल ३३ अतः तोष और सम्बन्धों से प्रभावित रहे। देशीय विद्या मन्त्री एक सम्बन्धित क विज्ञान और अनुसंधान स्थिति हैं। किन्तु जिस प्रकार अन्तःस्थ सम्बन्धों से प्रभावित है उससे यह प्रतीत होता है कि मोहताजा ही ऐसे स्थिति पर भी जिस प्रकार प्रभाव अन्तःस्थ है। माननीय विद्यामन्त्री की के समस्त को आँखें प्रस्तुत गिये गये हैं उन पर उन्हें विश्वास बरता है। कभी कभी हम किसी विशेष परिस्थिति से रहकर गलत बातों को वास्तव में नहीं समझते लगते हैं।

ये आँखें विश्वविद्यालयों के सुसंस्थितों और अधिकांशों के देखे होये और इनमें अधिकांश वे हैं जो सामान्य के दृष्टिकोण हैं। इनका अपना न तो कोई प्यारिल है और न कोई लक्ष्य। ऐसे लोग जैसे ही आँखें भेजते हैं जिनसे छात्रों में लोग यह समझें कि विश्वविद्यालय पूर्णतः से अनुसंधान हैं और कम से कम पढ़ना पढ़ाई, सम्बन्धों और अन्तःस्थ की सुविधा की जाती है। स्थिति कुछ बेसी ही है जैसे पुलिस प्रशासन व्यवस्था को सरकार में कभी इस आधार पर प्रस्तुत करता है कि पुलिसवालों पर बहुत ही बटवारा या तो बर्ग ही नहीं की जाती या लोग इस दुष्टि से दर्ज कराने हैं नहीं जाते कि लोग बवाल में पड़े।

वास्तविक स्थिति यह है कि ३३ या लगभग इतने ही विश्वविद्यालय ऐसे और होंगे जिनमें छात्रों के सम्बन्धों और विश्वविद्यालय प्रशासन की दुर्गन्धों के कारण संसिद्ध वातावरण भरत-भरत रहा होगा। कुछ विश्व-विद्यालय ऐसे हैं जिनमें देर से सत्र प्रारम्भ हुए किन्तु परीक्षाओं सम्बन्ध से अन्तःस्थ की बड़ी आ कर दी जा रही है। सामान्य-छात्रों की छात्रों के सम्बन्धों की दृष्टि रखा जा रहा है। शिक्षण कार्य अत्यन्त विरुद्ध स्तर पर चल रहा है। प्रकाशक अपनी चरम सीमा पर है। ऐसी स्थिति में यदि माननीय विद्या मन्त्री को यह सम्बन्ध है कि केवल एक विद्या-विश्वविद्यालय सम्बन्धित हैं और ७९ विश्वविद्यालय ठीक से चल रहे हैं तो यह दृष्टान्त को सामने देखकर सुबुद्धि वाली नीति अपनाते यानी बात भरितार्थ होती है।

यह प्रभावता की बात है कि सांख्यिक चयनक्रिया के सम्बन्धों से सम्बन्ध होने के पूर्व प्रभावमन्त्री को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने इस बात पर लिखा व्यक्त की कि विश्वविद्यालय सम्बन्धों के अन्तःस्थ की सहृदों में फले हुए हैं और अन्तःस्थ अवस्था की स्थिति व्याप्त है। यह सम्बन्धों में नहीं जाता कि विद्या मन्त्री के सम्बन्धों पर निश्चाय दिया जाय या कीदनात्मक है।

दसमः समाधान कहा है? यह प्रश्न आज देश के सामने है। मोहताजा के अन्तःस्थ सम्बन्धों से सम्बन्धों को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने इस बात पर लिखा व्यक्त की कि विश्वविद्यालय सम्बन्धों के अन्तःस्थ की सहृदों में फले हुए हैं और अन्तःस्थ अवस्था की स्थिति व्याप्त है। यह सम्बन्धों में नहीं जाता कि विद्या मन्त्री के सम्बन्धों पर निश्चाय दिया जाय या कीदनात्मक है।

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय का प्रौढ़-शिक्षा केंद्र

छा० देवेन्द्र चंद तिवारी

जीवन के ज्ञानाजन करने और ज्ञानार्जन कराने की दृष्टि प्रारम्भ से ही रही है। इसीलिए वैश्विक प्रसारण का क्षेत्र मुझे कभी रचिहार नहीं लगा। विश्वविद्यालय में आने के पूर्व अनेक सामाजिक कार्यकर्ताओं, राज्याओं और व्यक्तियों को प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए मैं अभिप्रेरित कर चुका था। स्वयं भी कम से कम दो प्रौढ़ों को शिक्षित करने का काम भी कर चुका था। दोनों प्रौढ़ों के लिए दो निम्न निम्न माली भवनाने पड़ें थे। एक सामाजिक चेतना का परिपूर्ण था, जबकि वह विरलर था। मैंने उसे समाचार पत्र के माध्यम से पढ़ने की प्रेरणा दी। जब पढ़ना आ जाता है तो शिक्षा कर अपनी मां को कहने की क्षमता का विकास करने में कठिनाई नहीं होती। था वह पहले से अक्षर पढ़ता है और सोचा बहुत अपनी कामकाज बनाने के लिए जिस भी लेता है। उसमें एक भावविशेषता है और यदि वह अक्षर पढ़ पाए रहता तो कदाचित् कोई परीक्षा भी पास कर लेता।

दूसरा व्यक्ति भी मेरे निजी सम्पर्क में ८२ वर्ष रहा। वह मेरा मोहन बाना था और पुरा शिक्षाव्यवस्था के बाधुओं से निरवगात था। एक दिन मैं सबसे कहा कि तुम दूसरी को तब बता दोगे ही कि मैं क्या करता हूँ, शाने पर कितना खर्च करता हूँ। उसकी यह बात लग गई और उसने अगल आज तथा कुछ बहुत सोच लिया। मायाएँ उसने नहीं छोड़ी, लेकिन 'टपाटर' को 'टपाटर' और 'बोनी' को 'बग' लिखकर काम चला लेता था और मैं उसे समझ लेता था।

मैंने ये दो उदाहरण हमारे दिलों में हैं कि प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वालों को यह स्पष्ट हो जाना कि

प्रौढ़ों की प्रेरणा का स्रोत निम्न-निम्न होते हैं, जिनमें एकोनव्यक्त नहीं होती और हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हर प्रौढ़ जिस रूप में शिक्षित करना चाहते हैं, उसकी प्रेरणा का स्रोत कहाँ है। दूसरी बात यह है कि प्रौढ़ों की निर्धारित पाठ्यक्रम का धारो नहीं बन सकता। कुछ ऐसे भी निरुक्त धारों में जो कोई परीक्षा देना चाहते हैं लेकिन यह सम्भव रास्ता है और बहुधा इसमें कोई उल्लेख भी नहीं होने वाला है। पढ़ाने का मात पर रहना चाहिए कि वह अपनी काम की अच्छी तरह से कर सके, ऐसी शिक्षा उसे भी लाभ। बहुतों के लिए और समान्य रूप से यह किस्म का अच्छा काम निरुक्त सकता है।

मैंने विश्वविद्यालय में जब इस प्रकार के कार्यक्रमों को करना शुरू तो एक दिन विश्वविद्यालय के एक प्रतिष्ठित एवं विद्वान विप द्वारा यह भी सुनने को मिला कि प्रौढ़ शिक्षा का उच्च शिक्षा का क्या सम्बन्ध है और दोनों को एक साथ जोड़ना उचित नहीं है, जब कि प्रौढ़ शिक्षा की 'राष्ट्रीय नीति को ध्यान में रखकर' तथा 'प्रौढ़ शिक्षा का राष्ट्रीय कार्यक्रम' बन दोनों अभिलेखों में प्रौढ़ीय सरकार ने विश्वविद्यालयों के विभाग दामित पर बल दिया है। 'प्रौढ़विद्यालय के राष्ट्रीय कार्य को रूप देना' में केन्द्रीय सरकार में कहा है —

"For too long the universities have theoretically espoused about desirability of contact with the community. The NAEP Provides a challenging situation for the University and college to overcome their seclusion and to

enter the main stream of mass education".

इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस कार्यक्रम से विश्वविद्यालयों को सम्बन्धित करने के लिए अनेक सुझाव अपने एतद्विषयक परिपत्र में दिये हैं। विश्वविद्यालय में प्रोढ़-शिक्षा इकाई की स्थापना की बात भी उही गयी है। तदनुसार विश्वविद्यालय में कुम्पटि की सम्पन्नता में एक परामर्शदात्री-समिति ब्रिटीश की गई है और प्रोढ़-शिक्षा को विद्याचार्य के पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने के लिए भी कदम उठाये गये हैं। इस सच्य का उल्लेख इसलिये किया गया है कि अग्री विश्व-विद्यालय के लोगों को इस बात का आभास नहीं है कि प्रोढ़-शिक्षा उच्च शिक्षा से किस प्रकार सम्बन्धित है। विद्यालय: शिक्षा एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है इसलिये निरन्तर प्रोढ़ भी कभी उच्चशिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। सन्तान में जो 'ओपन विश्वविद्यालय' (Open University) है उसमें प्रवेश पाने के लिये केवल २१ वर्ष की सीमा का ही एक प्रतिबन्ध है। मर्यादा कोई भी उम्र में प्रवेश के सकता है और आज उच्च विश्वविद्यालय में ७०,००० छात्र-छात्राएं हैं।

सैलिक-अनुसन्धान की दृष्टि से प्रोढ़ों को सीखने-विज्ञाने, सम्प्रेषण आदि के सम्मन्ध में खोप की आवश्यकता है जो विश्वविद्यालय ही कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालयों को यह समझना है कि प्रोढ़-विद्या का सामर्थ्य उसी प्रकार है जिस प्रकार उच्च-शिक्षा का आवश्यक क्षेत्र में।

इस सम्पर्क में विश्वविद्यालय के प्रोढ़ शिक्षा क्षेत्र को पहचानो बता देना आवश्यक है। पहले मैंने यह सोचा कि अधिकारियों के अधिकार का प्रयोग करके बचाएँ बनाई जायें। इस पर अधिकारियों ने आदेश निर्यस्त किये कि जो बर्बकारी इन बन्दाओं से साम्य उठाना चाहें वे विद्यालय-विभाग में उपस्थित हो किन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। फिर मैंने बर्बकारी सभ के पदाधिकारियों और विद्यार्थियों का सहारा लेना उचित समझा। अब जब बात हुई तो यह बंधा कि पहले दिन जब हमारी गयी छात्राओं / ४

वर्षा हो रही थी और बिजली भी नहीं थी, लगभग २५ बर्बकारी भीषते हुए बाहर बैठे रहे। उनसे बात किया और उन्होंने इन कथाओं में रुचि दिखाई और दूसरे दिन जाने कहा।

दूसरे दिन सख्या बढ़ गई। कुछ विश्वविद्यालय के और कुछ बाहर के लोग भी आए। कुछ बच्चे भी आए जो किसी कारणवश शिक्षा से वंचित रह गये हैं, दवायि बोधला प्रोढ़ों की शिक्षा के लिए ही को रखी थी।

इस प्रकार १ बच्चे ग्राहमरी मायु वर्ग के और २४ प्रोढ़ सचमन्न निरक्षरता की परिधि में तथा लोग ऐसे हैं जो बू. हा. स्कूल से ऊपर भी शिक्षा पाये हुए हैं, किन्तु आगे पढ़ने की उनमें इच्छा है। विभिन्न मायु-वर्गों की इस कथा रचना में यह बात स्पष्ट हुई कि प्रोढ़-शिक्षा का जो भी केन्द्र हो उसमें इस बात पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सकता कि वे किसी निश्चित मायु के हो या केवल निरक्षर ही हों। यह इस बात का भी संकेत करता है कि सबकी आवश्यकताएं, उपलब्धियाँ और सामर्थ्य भिन्न-भिन्न हैं और सबको एक ही कक्षा में नहीं रखा जा सकता है।

अतः पहले ही दिन बार यू.ए. में कथाओं की बात देना पड़ा। समस्या यह भी थी कि अनेक ही केंद्रों इस समस्या का समाधान कर सकेंगे। मेरे छात्रों और छात्राओं ने मेरी कठिनाई को समझा। एम. एड. कक्षा के विद्यार्थियों ने मेरी परेशानी समझ कर अपना सहयोग दिया। एक-एक ग्रुप को उन्होंने सहायता दिया। इन छात्र छात्राओं का कोई पूर्व अनुभव नहीं था। यदि होगा भी तो अपने व्यवसाय पर वे अपने से छोटे से सहायक व्यवसाय ही होता। इनमें से एक छात्रा ने तो प्रोढ़ों की भाषा में ही दोस्त-चाल कर उनसे तादात्म्य कर लिया। परिणाम यह हुआ कि प्रतिदिन सख्या तथा उपस्थिति बढ़ने लगी।

मेरे पास कोई साधन नहीं था। अपनी सामर्थ्य-हीनता के कारण परेशानी भी थी। देव में करोड़ों रूपया प्रोढ़-विद्या पर व्यय किया जा रहा है। किन्तु यदि कोई काम अच्छे ढंगसे प्रारम्भ किया जाय तो उसके लिए कोई मोटा-

हा नहीं है। उ० प्र० के प्रौढ़ शिक्षा विभाग के सरकारी अधिकारियों ने बताया कि अगर ये इस प्रकार के केंद्र को सहायता देने का कोई प्राविधान नहीं है। यू० जी० सी० ने मुझे यह बताया कि २५०० डॉ० की अनारक्षित योग रूप में स्वीकृति की गई है कि तु विश्वविद्यालय ने इसी इसकी कोई योजना नहीं है। एन० एच० एच० के अन्दर इस प्रकार के काम करने का दायित्व है कि तु, उधर से भी कोई ठोस सहयोग नहीं है।

कुछ प्रशासित स्कूल, भाग, पुस्तकों के ऊपर खर्च की गयी है, उसकी भी व्यवस्था नहीं हो पायी है। प्रौढ़ शिक्षा विश्वविद्यालय के दायित्व का एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ, कि तु विश्व विद्यालय परितर में इसका आकाश भी नहीं है।

मुझे एक श्रम और परेशान कर रहा है, वह पाठ्यक्रम से सम्बन्धित है। केन्द्र को पता है कि वह स्पष्ट हो रहा है कि कोई पूर्ण विरहित पाठ्यक्रम काम नहीं बना और पाठ्यक्रम प्रायः प्रौढ़ से परामर्श करके तैयार बनाया होगा। जहाँ तक शिक्षण विधि का प्रश्न है, चूंकि हम लोग एक-दूसरे इसकी सहाय से सम्बन्धित हो गये, अतः किसी विधि या सुविधिपल रूप से क्या चलाने की उम्मीद भी हम लोग नहीं कर पाये। कुछ परम्परागत विधि, कुछ समाचार पत्र, कुछ पत्र-व्यक्तियों का प्रयोग करके काम चलाया जा रहा है।

अपेक्षित विवरण से यह प्रतीति स्पष्ट है कि राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा योजना के कार्यक्रम में जो ५० डॉ० के एक प्रौढ़ शिक्षक से काम कराने की बात कही गयी है, वह निश्चित अल्पवर्ष है और एक प्रौढ़ शिक्षा केंद्र पर एक शिक्षक से किसी भी अवस्था में काम नहीं चल सकता है। जो दिल्ली में बैठकर योजना बनाते हैं और लोग में काम करने के लिये बिना के पास समय नहीं है, वही एक प्रौढ़ शिक्षक से केंद्र चलाने की बात कर सकते हैं।

मैं तो मेरे इस बात की विज्ञापित है कि इस केन्द्र की स्थायी और अस्थायी रूप से इस प्रकार बताया जाय। यह बन सके तो लगभग २००-१०० प्रौढ़ जाने अपने सरकारी नियमों में क्या यह प्रयोग, प्रयोग ही यह बताया जा विरविद्यालय सहाय सेवा के द्वारा कार्यक्रम को अपना बना लेंगे। यह प्रश्न चिन्हा सामने है।

कुम्भपति, भाषा में बड़ी गाय सुकल की नये प्रयोगों में यह रहती है। समाज-सेवा-कार्यों में उनकी उत्पन्न है। उद्योग-धर्मों से सम्बन्धित शिक्षा है मुझे विश्वास है कि काम प्रकार से भी इनका समर्थन इस कार्य के लिए प्राप्त होगा।

छात्र छात्राओं के प्रति मैं हृदय से कहना चाहूँ कि मेरी इस सन्तान को साकार करने में वे निस्वार्थता से परिश्रम कर रहे हैं और अपना समय भी रहे हैं।



प्रौढ़ शिक्षा की पृष्ठभूमि

डा० सोलापूर जयसङ्गाळ, शिक्षा विभाग, सतत विश्वविद्यालय

सन् १९७१ की जनगणना के अनुसार भारत में पाठ्यपत्रा संख्या २२ प्रतिशत है। दूसरे पक्षों में भारत में लगभग ७० प्रतिशत लोग निरक्षर हैं। यदि भारतीय मोडर्न को प्रतिपाली और दुष्ट बनाना है तो हमें भारत को निरक्षरता के अन्तिम से मुक्त करना होगा।

प्रश्न यह है कि भारत में निरक्षरता की मात्रा इतनी अधिक क्यों है? भारत में लक्ष्मों का जन के पूर्व शिक्षा

की स्थिति काफी अच्छी थी। निरक्षरता की मात्रा भी कम थी। प्रमाणितकर १८२३ ई० में प्रकाशित ईस्टइंडिया कंपनी की एक रिपोर्ट का विष्णुसिंह सदा उल्लेखनीय है "विद्या की दृष्टि से सभार के किसी भी भाग देश में शिक्षा की दशा इतनी अच्छी नहीं है जिसकी चिट्ठा भारत के अनेक भागों में है।"

जन्मीसवी शती में दूसरे और तीसरे दशक में भारतीय

१. देश-विदेश की प्रमुख प्रौढ़-विद्यालय प्रचार वि० सङ्गठन एवं प्रकाशन, इलाहाबाद, १९४८, पृ० १५.

जनता गरीबी और अक्षरता से पीड़ित न थी। ३ जून १८१४ को प्रयाग के गवर्नर जनरल ने अपने पत्र में लिखा था। 'विद्या की जो प्रणाली बहुत पुराने समय से भारत में यहाँ के आचार्यों के अधीन जारी है उसी सबसे बड़ी प्रणाली यही है कि देखे ४८०० वर्ष के अधीन जो मद्रास में वादरी रह चुके हैं, वही यही का इस देश (इन्डिया) में भी प्रचलित किया गया है, अब हमारी राष्ट्रीय सरकारों में इसी प्रणाली के अनुसार शिक्षा दी जाती है क्योंकि हमें विश्वास है कि इससे माया का हिलाना बहुत सरल तथा सौकर्यपूर्ण हो जाता है।'

भारतीय शिक्षा जन सामान्य में विश्व रूप में प्रचलित की इसका वर्णन हन उस प्रतिवेदन में भी मिलता है जो भारत में 'हरिश्चन्द्र' ने सन् १८८२ में प्रेषित भारत सरकार के शिक्षा आयोग (हर्बर्ट स्पेंसर) के सम्मुख प्रस्तुत किया था। शिक्षा आयोग की प्रस्तावनों के प्रश्नों का उत्तर भारतीयों ने लगभग २०,००० पन्नों में अंग्रेजी भाषा में लिखकर भेजा था। अपने शाब्दिक भाषांतरों में अंग्रेजी राज्य की स्थापना से पूर्व परिवर्तन-सदृशता के तथ्यों में प्राचीन परिपाटी की शिक्षण व्यवस्थाओं के बड़ी सदा में होने का उल्लेख किया था।

भारतीय हरिश्चन्द्र ने प्राचीन परिपाटी की वैदिक व्यवस्थाओं का सात धर्मियों में वर्गीकरण किया था जो कि निम्नलिखित हैं।

१. षट्साले, जिनमें नागरी, बंसी या महाजनी ब्रजभाषा, पञ्चांग, मौलिक गणित, जोड, बाकी, मुक्ता, नाग मुद्र तथा सुन्दर मुद्र निष्कासक सिखाया जाता था।

२. सङ्कत पाठशास्त्र जिनमें खोतिय, व्यास, वसिष्ठ काव्यशास्त्र गणना आता था।

३. वेद, मीमांसा वेद व आदि की शिक्षा देने वाली पाठशालाएँ।

४. महाजनी पाठशाला जिनमें देखी व्यापार, बलिष्ठ तथा वहीलता निष्ठा सिखाया जाता था।

उपर्युक्त धर्मों की पाठशाला में में प्रायः हिन्दू विद्यार्थी ही पढ़ते थे।

५. मातृव बिम्बे भारतीय शिक्षा और पढ़ाई सिखाया जाता था। इनमें हिन्दू और मुसलमान दोनों विद्यार्थी पढ़ते थे। अंग्रेजी राज्य की स्थापना के बाद इन मतभेदों की वजह से वे पढ़ाने लगे थे, क्योंकि अंग्रेजी सरकार ने फारसी की जगह अंग्रेजी को राजभाषा बना दी थी।

६. अरबी साहित्य, व्याकरण, गणित, दर्शन आदि की शिक्षा देने वाले मकतब।

७. कुशाग्र हिकम करने वाले मकतब।

यदि प्राचीन परिपाटी को ऐतिहासिक व्यवस्था मानती रहती तो भारत में निरक्षरता की वृद्धि न होती। लेकिन विदेशी शासकों की नीति थी कि भारत के लोगों को दबा कर रखा जाए और उन्हें ऐसी शिक्षा न दी जाए जो उनके मन में राष्ट्रीय चेतना और वैराग्य उत्पन्न करे। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी शासकों ने ईसाई धर्म के प्रचार के लिए प्रयास किया। सामाजिक क्षेत्रों की विदेशी शासकों ने उपेक्षा की और नगरों में रहने वालों को ऐसी शिक्षा प्रदान की जाने लगी जो उन्हें विदेशी शासकों के प्रति निष्ठावान बनाती थी। सन १८५७ से १९१९ ई० तक ब्रिटिश शासकों ने धनसाधन व की शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया। पसत कुछ स्वयंसेवी संस्थानों ने अपने प्रयास से कुछ संस्थाएँ खोलीं। बंगाल राज्य में एक सामाजिक पुस्तकालय की स्थापना सन् १८१० में की गयी। इसी प्रकार बंगाल में भी वैद्यमन्त्र लोको के प्रयास से कई प्रौढ़ पाठशालाएँ स्थापित की गयी।

प्रौढ़ शिक्षा के सम्बन्ध में दूसरी ऐतिहासिक लिपि है १८१९। १८२९ से लेकर १८४० तक की अवधि में राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा का एक व्यवस्थित स्वरूप विकसित होता है। यह स्वरूपीय है कि प्रथम विश्व युद्ध १९१४ में समाप्त हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत के लोगों ने देश की आजादी के प्रति एक नया उत्साह उत्पन्न हुआ। फलतः भारत में साक्षरता प्रसार के प्रयास भी होन लगे।

१. वर्षी ५०-५५-६० २. रणतः भारत, साप्ताहिक परिशिष्ट, ३. सितम्बर सन् १९७८, पृ० ८

गांधीजी और प्रौढशिक्षा

गांधी जी ने जीवन के सभी पक्षों पर समुचित प्रकाश डाला है। उन्होंने प्रौढ शिक्षा के महत्त्व की सब समझ बर्षों की जब मोक्ष केवल साधारणता पर ही ध्यान दे रहे थे। यह उल्लेखनीय है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद प्रौढ साधारणता पर अधिक ध्यान दिया गया। इसका कारण यह था कि जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद प्रौढ शिक्षा और शिक्षा, वाणिज्य सभी हुआ था। फलतः युद्धों और पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से ही लोगों को नयी जानकारी प्राप्त होती थी। यद्यपि लोग निरक्षर थे, उन्हें साधारणता, साधारणता समझा गया।

इससे पहले नहीं कि प्रौढ शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अर्थ साधारणता है। लेकिन केवल अक्षर ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। इस सन्दर्भ में गांधी जी का निम्नलिखित कथन ध्यान देने योग्य है।

“दाशम्य मेरी राय में हमारे अक्षरज्ञान वरदान और मजिद होने का कारण निरक्षरता इतना नहीं है जितना कि धन है। इसलिए कदम लोगों की शिक्षा के लिए भी मुझे लगना अत्यावश्यक है। एक अक्षरज्ञान केवल एक अक्षरज्ञान के लिए ही पर्याप्त है। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि उन्हें पर्याप्तता का ज्ञान नहीं करा जाए। ... नहीं, इसकी तो मैं अधिक कीमत मानता हूँ कि शिक्षा के एक साधन के रूप में मैं इसे हमारी जरूरत नहीं देखता।”

यह बात गांधीजी ने सन् १९३० में नहीं की और आज भी यह पूर्णतः सत्य है। प्रौढ साधारणता प्रौढशिक्षा का साधन है न कि साध्य। लेकिन अक्षरज्ञान लोगों ने प्रौढ साधारणता को ही प्रौढ शिक्षा मान लिया था। यद्यपि १९०० में जब भारत ने अधिकांश प्रारम्भिक शिक्षा के शिक्षकों ने साधारणता का अर्थ प्रौढ साधारणता के अर्थ-सम सम प्रौढ शिक्षा पर ध्यान दिया जाने लगा।

प्रौढ शिक्षा का अन्तर्गत सामान्य के पूर्वार्ध में, विशेष-कर सामान्य सामान्य के अन्तर्गत लोगों की आवश्यकताओं

पर ध्यान रखते हुए ऐसे विषयों को प्रौढ शिक्षा के कार्यक्रम में स्थान देना आवश्यक है जो व्यक्ति और समाज की दृष्टि से उपयोगी हैं। इस सन्दर्भ में गांधीजी का यह कथन महत्वपूर्ण है कि निरक्षरता से अधिक आवश्यक है धन के अभाव को दूर करना। दूसरे शब्दों में, गांधीजी ने यहाँ एक ऐसे तथ्य की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है जो प्रायः हम भूल जाते हैं। यह तथ्य है साधारणता और शिक्षा का अन्तर। इसी आधार पर यह कहा जा सकता है कि एक साधारण व्यक्ति अक्षरज्ञान हो सकता है और एक निरक्षर व्यक्ति को शिक्षित माना जा सकता है यदि हम शिक्षा को सही अर्थों में स्वीकार करें।

महात्मा गांधी य अनुसार, शिक्षा यह है जो व्यक्ति विचारने वाली हो ‘सा शिक्षा या विमुक्तये’ .. ऐसी शिक्षा जो उसे व्यक्ति को शिक्षित माना जा सकता है। यह शिक्षा ही जीवन की पुस्तक के विषयी है।

अब यह स्पष्ट है कि गांधीजी दुर्लभ यह लेने की क्षमता को ज्ञान का पर्याप्त नहीं मानते थे। सच्चा ज्ञान जीवन में जीवन प्रोग्राम और जीवन के लिए प्राप्त होता है। यही कारण है कि नई तकनीक की व्याख्या करते हुए उसे ज्ञान के स्तर जीवन पर्यन्त चलन वाली शिक्षा के रूप में स्वीकार किया गया। ज्ञान ही नहीं, नई तकनीक का ज्ञान और अक्षरज्ञान पर आधारित नरके भारतीय संस्कृति से अलग। अक्षरज्ञान में समाहित किया गया और व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में सत्य और अक्षरज्ञान को महत्वपूर्ण स्थान दिया।

संक्षेप में भारत में प्रौढ-शिक्षा

१९ अक्टूबर सन् १९४० को भारत जब स्वतंत्र हुआ तब भीनाता अनुत्तर सामान्य आजाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री नियुक्त किये गये। उन्होंने प्रौढ शिक्षा के स्थान पर सामान्य शिक्षा के अर्थ में प्रयोग पर ध्यान दिया। इसका कारण अज्ञात यह था कि प्रौढ शिक्षा के अर्थ में साधारणता पर बहुत से देश प्रौढ के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास पर जो ध्यान देने लगे। शिक्षा मंत्री भीनाता

२. महात्मा गांधी, अन्तर्गत सामान्य सामान्य, अक्षरज्ञान, १९६३, पृ. ७४

१. रामनाथ गुप्त, शिक्षण और संस्कृति (गांधीजी), उत्तर प्रदेश गांधी स्मारक निधि, काशी १९६६, पृ. २३

अबुल कलाम आझाद ने यह स्पष्ट घोषणा की कि प्रौढ़ शिक्षा के अन्तर्गत सामाजिक चेतना के विकास पर भी बल दिया जाय। फलतः समाज शिक्षा का एव पत्र पुनर् कार्यक्रम बनाया गया जो इस प्रकार है।

१. साक्षरता प्रसार

२. स्वास्थ्य तथा सफाई के नियमों के ज्ञान का प्रसार

३. वयस्क व्यक्तियों के आर्थिक स्तर की उन्नति

४. नागरिकता की भावना, अधिकारों तथा दायित्वों के प्रति जनता में जागरूकता को प्रोत्साहन देना, और

५. सामाजिक बदलि की आवश्यकताओं के अनुकूल स्वस्थ मनोरंजन की व्यवस्था करना।

इसमें सन्देह नहीं कि समाज प्रौढ़ शिक्षा का यह कार्यक्रम समग्र जीवन को प्रभावित करने वाला या क्योंकि इसका सम्बन्ध व्यक्ति और समाज की आवश्यकताओं से सीधा गया था।

सन् १९५२ के आसपास जब भारत में सामुदायिक विकास की योजना बनाई गई तब उसमें समाजशिक्षा को प्रमुख स्थान दिया गया और इसके लिए समाजशिक्षा अधिकारियों की नियुक्ति की गई। लेकिन जल्दा तब यह सामुदायिक विकास की योजना का परिणाम आभासीत न हुआ। सामुदायिक विकास की योजना में प्रदर्शन और प्रचार की ओर आवश्यकता से अधिक ध्यान दिया गया। जागृकी योजनाएँ और उनके सम्बन्धित उपबन्धों के माफ़े अधिकतर ध्यान ही मने।

भारत की परिस्थिति और कुछ समय बाद चीन से जुड़ करणा पड़ा। इसका प्रभाव भी अब कल्याण की योजनाओं पर पड़ा। आर्थिक अभाव के कारण समाज शिक्षा की प्रगति में बाधा पड़ी। सन् १९७१ की जनगणना के अनुसार पर यह बात हुआ कि १९५१ से लेकर १९७१ की अवधि में भारत में साक्षरता की वृद्धि केवल १२.९७ प्रतिशत हुई जो कि वस-व्यवस्था वाली जातियों के लिए १९५१ से लेकर १९७१ की अवधि में साक्षरता की प्रगति देखें तो यह केवल १.३१ प्रतिशत हुई।

१. ओपर मुखर्जी, भारत के शिक्षा, भाषाई वृद्धि रिपोर्ट, बरौदा, १९६०, पृ. २५३

नवी तालीत / ५

जब यह स्पष्ट है कि भारत में निरक्षरता और ज्ञान की समस्या का समाधान केवल सरकारी प्रयासों से नहीं हो सकता। इसके लिये प्रत्येक शिक्षित नर नारी को प्रयास करना होगा।

प्रौढ़शिक्षा का राष्ट्रीय कार्यक्रम

समाज शिक्षा की संरचना में निम्नलिखित मान्यताओं का स्वरूप हो चुका है। इसने बाद प्रियदर्शन साक्षरता (कल्याण), अनवरत शिक्षा [कॉन्टिन्युअस एजुकेशन] तथा धनोपार्जन शिक्षा [नान पार्मेस एजुकेशन] होने लगी। इन नवीन संरचनाओं के मूल में यह भावना प्रमुख थी कि रोमिष्ठ समय के लिये प्रदान की जाने वाली धनोपार्जन शिक्षा तोत्र गति से होने वाले सामाजिक परिवर्तन के उद्देश्य में अपूर्ण होती है। फलतः शिक्षा में दिया और दस्तकारी का समावेश करके इसे जीवनोपयोगी बनाने पर बल दिया गया। साक्षरता के कार्यक्रम की भी क्रियारूप रूप दिया जाने लगा।

यह उद्देश्यहीन है कि हमारे देश के परिधान में ५ से १५ वर्ष के बाल, बालों के बालों एव बालिकाओं के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्राविधान है। अतः १२ वर्ष और उसके ऊपर की आयु के व्यक्तियों के लिए चाहिए कि निरक्षर हो अपना साक्षर ऐसी प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था होनी जो उनमें देश प्रेम, संवृद्धि का अनुकूलता के साथ-साथ अच्छे नागरिक बनने की प्रेरणा प्रदान करे।

भारत सरकार की वर्तमान जनता सरकार ने यह अनुभव दिया कि जब तक देश में अज्ञान और निरक्षरता का बोझ बाला रहेगा तब तक समाज के पीछे और दुर्लभ वर्ग का संरक्षण नहीं संभव। यह स्मरण है कि करोड़ों और अविद्या एक दूसरे के पूरक हैं। यदि हम अपने देश से करोड़ों को हटाना है तो ऐसी प्रौढ़ शिक्षा की योजना बनानी होगी जिसका सीधा सम्बन्ध समाज के नीचे और दुर्लभ वर्ग से हो। इतना ही नहीं प्रौढ़ शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम में जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की ध्यान से रचना होगी और शिक्षा की ऐसी पद्धति अपनायी होगी जो लोकमन और मनोरंजन दोनों में सहज हो।

भारत की सांस्कृतिक संपदा अपार है। कबीर, नानक दादू, रैदास आदि स १ बरने युग के सही बर्णों में प्रौढ़ शिक्षा के। इन्होंने जनता को भाषा में सत्य का उद्घाटन किया और सच्चाई से जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा प्रदान की। एन्तों की सरल भाषियों को हमें फिर से प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम में सम्मिलित करना होगा। राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से भी यह आवश्यक है कि हम सभी वर्गों की मूल एकता को जब जन के मन में घर दें। राम, रङ्गो, कृष्ण, कबीर को लेकर कबीर ने विश्व नवमानववाद का प्रसार किया था वह मात्र भी सभी लोगों के लिए, चाहे वे साधारण हो अथवा निरक्षर, उपयोगी है।

अन्त में एक बातको देना चाहता हूँ। प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम एक प्रकार का साज या बज है। यदि कोई व्यक्ति इस कार्यक्रम को व्यक्तिगत लाभ का साधन

बनाता है तो यह राज्य के प्रति एक अपराध माना जायगा जब्त त्रयेक शिक्षित व्यक्ति का यह नैतिक दायित्व है कि वह कम से कम एक विस्तर व्यक्ति को साधारण अवस्था बनाए। इसका हो नहीं, अपने पास पब्लिस में भी मोक रखन तथा मनोरञ्जन के ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करे जो सामाजिक दूरी को घटा कर सभी वर्गों के लोगों में मध्ये सम्बन्ध विकसित करने में सहायक हो।

प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम की सफलता बिना जन सहयोग के सम्भव नहीं है। इसमें सरकारों को भाग्य बल कर कार्य करना होगा और सरकार को चाहिए कि यह इनकी आर्थिक सहायता करते हुए परीक्षण से समय-समय पर मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन प्रदान करे। यदि प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम में सरकारी तन्त्र की प्रधानता होगी तो इसकी सफलता में संदेह होगा सामाजिक है।



शिक्षा में धार्मिक शिक्षा का स्थान

अन्धविश्वास और साधुजीविका

धर्म और शिक्षा दोनों ही जीवन के प्रेरक और व्याख्याता हैं। एक किया है तो दूसरा उसका आधरवत है। धर्म दोहरा सम्बन्ध स्थापित करता है—“पहला मनुष्य और ईश्वर के बीच, और दूसरा ईश्वर की सत्ता होने के कारण मनुष्य और मनुष्य के बीच।” मनुष्य और मनुष्य के बीच सम्बन्ध तभी स्थापित हो सकता है जब हम पूरी धर्मिता से दूसरों की प्रशंसा करें। यह तभी सम्भव है, जब हम मम, पवित्र, स्थान और निष्पक्ष हों।

धर्म का उद्देश्य मानव सभ्यता और सभ्यता के उद्भव के साथ ही हुआ है। एक समय था जब धर्म जीवन में सब वर्गों पर पूरी तरह हाव हाव हुआ था। उसने व्यक्ति और समाज को अन्धकार से हटाकर सत्य की ओर, अन्धकार के हटाकर ज्ञान की ओर और अन्धकार से हटाकर प्रकाश

की ओर मोड़ने का प्रयत्न किया। जीवन में इतना महत्वपूर्ण स्थान रखने पर भी आज धर्म वैज्ञानिक प्रगति, आर्थिक उत्थान, कुछ स्वार्थियों के कुचक्र तथा ऐसे ही कल्पित अन्धविश्वासों से प्रभाव रखने वाला हो गया है। जो धर्म कभी विश्वधर के देशों की शिक्षा संस्थाओं में अग्रगण्य भाग आज हटकर दिया गया है।

धर्म और शिक्षा में सम्बन्ध —

प्राचीन काल में शिक्षा का वैश्व आध्यात्मिक था। धर्म ने मानव हृदय का परिष्कार किया और शिक्षा ने बुद्धि का। धर्म, मानव जीवन के भौतिक और आध्यात्मिक पहलुओं से सम्बन्धित है तो शिक्षा भी व्यक्ति के आध्यात्मिक और नैतिक जीवन पर प्रभाव डालती है। यदि शिक्षा

द्वारा मानव के व्यवहार ॥ नृशमता से परिचित साया जा सकता है तो आदर्श शिक्षा धार्मिकता और व्याख्या-
त्मिकता धर्म द्वारा ही मिलती है। मनुष्य को शौचि
सुख शांति की जितनी आवश्यकता है, उतने ही अधि-
मानसिक सुख दान्ति की। मनुष्य सिद्धांत ही धर्मवान हो,
जितना ही एवम् सम्पन्न और समृद्ध हो, परन्तु यह
भी मानसिक शांति के लिए भटवता सेवा गया है। स्पष्ट
है कि शांति के लिए उन्हे धार्मिक शिक्षा मनी मिली।
मनु ने धर्म के इस सहाय बताया है—

७ धार्मिक शिक्षा से अत्यन्त भारतीयाँ ॥ जीवन शुद्धता को और बढ़ा । उन्होंने मन्त्र से देवत्व प्राप्त किया वित्त में भी उच्चनैतिक के महापुरुषों जैसे मायावा महाबोर, चौतम बुद्ध, महात्मा गांधी आदि में राजकी समय का स्वागत कर तथा सत्य, अहिंसा, अहिंसा, सत्य आदि को अपनाकर अपना जीवन बरहित के सिमे उत्तम कर दिया । पण्डितों को प्रज्ञा दिया और उनके प्रभाव से वित्त ही व्यक्तियों का जीवन सुधर गया । इन महापुरुषों के जीवन से जन हृदय में श्रद्धा उत्पन्न पड़ी । उनके प्रभाव से छोटे तथा बड़े सभी नरों में मठी, मदिरा और मादक्यों की स्थापना की गयी ।

हमें स्कूल क्यों समाप्त करना है

अनुवादक डॉ. देवेन्द्र दत्त तिवारी

[इवान इलिच की प्रसिद्ध पुस्तक 'डिस्कल्डिंग सोसाइटी' का अनुवाद हम क्रमशः 'नयी तालीम' में इसलिए प्रकाशित कर रहे हैं कि इवान इलिच के विचार गांधीवादी विचारधारा से मिलते-जुलते हैं। यह अनुवाद सर्वाधिकार सुरक्षित है।]

(गलाक से आगे)

अब भी प्रशिक्षण ज्ञानार्जन आकस्मिक रूप से होता है और ऐसी क्रियाओं का उपपरिणाम है जो कार्य-व्यवस्था (Leisure) की परिभाषा में आते हैं। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि सुनिश्चित शिक्षण से सुनियोजित ज्ञानार्जन को धाम नहीं होता है और न यह समझना चाहिए कि दोनों में सुधार की आवश्यकता नहीं है। दस-बत्ती प्रेरणायुक्त विद्यार्थी, जो एक नवीन विषय की उस सीखना चाहता है उस विषय से पर्याप्त लाभ उठा सकता है, जो अब पुराने ढंग के उस शिक्षक से सम्बद्ध है जो पढ़ाई, हेतु, प्रत्येक और गुण रटकर छिलाता था। स्कूल के इस प्रकार के रट्टु शिक्षण को अब बहुत कम और प्रतिष्ठाहीन कर दिया है। फिर भी बहुत से कोशल ऐसे हैं जिनपर एन. प्रेरणायुक्त और सामान्य अतिरिक्त शिक्षणों कुछ ही महीनों में अधिकार प्राप्त कर सकता है, यदि उनका शिक्षण परम्परागत ढंग से किया जाय। ये प्रतीक (कोई) और उनके योग द्वितीय तथा तृतीय भाषा ज्ञान के लिए उनका ही उत्तर है जिसका सामान्य शिक्षण और पढ़ने के लिए और उतना ही सत्य एवं विशेष प्रणाली के लिए है जैसे बीजगणित, कम्प्यूटर, (प्रोग्रामिंग) रासायनिक, विद्युत्चुम्बक या हाथ के कोशल के लिए जैसे टाई करना, पकड़ बनाना, मिट्टी का काम करना, तार सजाना, टी.वी. या मुरम, मोटर चलावा या पम्पुची की बसा सीखना।

कुछ मागवो म, ज्ञानार्जन के उस वायव्य में, जिसका पर्य एन. विषय की बात स करता प्राप्त करना हो अभिहित होने के लिए किसी दूसरे कोशल की दक्षता भी नयी तालीम/१२

आवश्यक हो सकती है किन्तु उसके ऐसी प्रक्रिया पर निर्भर होना आवश्यक नहीं है जिनके द्वारा ये कोशल छोड़े गये थे। टी.वी. की परम्परा के लिये साक्षरता तथा कुछ गणित का पूर्णज्ञान आवश्यक है, पम्पुची की कला के लिये अच्छी तैयारी और मृदाविज्ञ के लिये दोनों का बहुत कम पूर्णज्ञान चाहिए।

ज्ञानार्जन का कोशल नाश जा सकता है। एक अति-प्रेरित औसत श्रम के सीखने के लिये उपयुक्त समय और सामग्री का अनुपात सरलता से ज्ञाया जा सकता है। अमरीका में एक दूसरी गश्चिन योरोप की उच्चतर श्रेण भाषा सीखने का खर्च चार से छ सौ डॉलर के बीच में आता है और किसी प्राथम भाषा सीखने के लिये दुगुना समय लगेगा। फिर भी यह खर्च न्यूयार्क नगर में १२ वर्ष की स्कूली शिक्षा पर होने वाले व्यय की तुलना में बहुत कम होया (उपार्ध विभाग में कार्यकर्ता के लिये अनिवार्य बीम्या) वह नवमय पन्द्रह हजार डॉलर होया। नि.स. वेह न केवल शिक्षक प्रत्युत औपधि निर्माता अपन व्यवसाय के इस आवेकनिक प्रसरो प्रचलित कर सुरक्षित रखते हैं कि उनके लिये प्रशिक्षण बहुत सस्ती है।

104

इस समय स्कूल बहुत सा संशिकर घन हविषा सेते हैं। शिक्षण की द्रिज को स्कूली खर्च से कम सस्ती है जब उन पनिको का विशेषाधिकार है जो स्कूली बिदा की उपाय कर सकते हैं और जिन्हें या ता सेवा या बडे उपाय-पति सेवाकालोन प्रशिक्षण के लिये भेजते हैं। अमरीका में शिक्षा के अधिक खपसे स्कूल बिहीन होने के कार्यक्रम म प्रारम्भ में द्रिज प्रशिक्षण के लिये शायन अत्यंत सीमित

होवे। किन्तु अन्तर्विशेषता विज्ञान के लिये जीवन में किसी समय में भी जनता के सच पर संकटों को जताने में से किसी एक को जन के शिक्षण को चुनने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए।

मनो को किसी कोशल - निराशा केन्द्र पर सैद्धांतिक केंद्रित केवल तरीकों को नहीं बल्कि सभी वय के लोगों को एक सीमित माया में मिल सकता है। मैं यह सोचता हूँ कि प्रविध्य में हर नास्तिक को उसके जन्म पर ही इस प्रकार की केंद्रित एक संश्लेष-वास्तवोपदेष्टा या या संश्लेष केंद्रित काट के रूप में मिल जाय। इसीको के प्रति सहानु-भूति की दृष्टि में, जो अपनी बालिक सहानुभूता आरम्भिक जीवन में प्रयोग में नहीं ला सकते, ऐसी व्यवस्था की जा सकती है कि बाद में दृष्टांत केंद्रित काट प्रयोग में लाने वाली को व्याप्त मिलता रहे। ऐसी केंद्रित है ऐसे कोशल चिन्तकी मांग अधिक होगी, अपनी सुविधा के अधिक मन्त्रों के, अधिक कोशल से और अधिक सम्यक् विधि से प्राप्त कर सकेंगे और स्कूल के दूरे पारंगत प्रभावों से भी बच सकेंगे।

पेटेंट्स कोशल—शिक्षकों की अधिक विनोद तक नहीं रही। किसी समाज में कोशल की मांग उसके प्रयोग पर निर्भर करती है। दूसरी ओर को कोशल का प्रयोग कर सकते हैं, वे उसे सिखा भी सकते हैं। किन्तु एक समय जो ऐसे कोशल का प्रयोग करते हैं जिनकी माय अधिक है और जिनके लिए मूर्ति में अध्यापक की आवश्यकता है, उन्हें इस बात से हतोत्साहित किया जाता है कि वे उसे दूसरों को भी सिखाए। ऐसी स्थिति या तो उनके शिक्षकों द्वारा उत्पन्न की जाती है जो साक्षरों पर एकाधिकारी रहते हैं या मूर्तियों के द्वारा जो अपने व्यावसायिक हितों की परिणामों के माध्यम पर किया जायगा, न कि उस स्टाफ के आधार पर जो उनके पास है और न उस शिक्षा के आधार पर जो वे काम में लाते हैं। काम के अध्यापन केवलतर सर्वविध जिये जा सकते हैं, बहुधा उन लोगों के लिये ही जिन्हें वास्तविक रोजगार से लगने के सर्वाधिक समझ आता है। वास्तव में इसका कोई कारण नहीं है कि वे कोशल—शिक्षण—के प्रकाश करने के स्थान पर ही मनो न हो। इससे रोजगार देने वाला

और उसने सहकर्मी, जो शिक्षण भी देगे और नाम ही उन लोगों को नाम भी दये, जो अपनी सैद्धांतिक केंद्रित का इस प्रकार प्रयोग करना चाहते हैं।

१९३६ में न्यूयार्क में प्रकाशित के प्रथम क्षेत्र में स्पेनिश शिक्षाने हेतु संकटों अध्यापकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं जिससे वे स्पेनिश लोगों से सम्वाद स्थापित कर सके। मेरे मित्र मेरी भावना में एक स्पेनिश पेंडिंगो स्टेशन से यह बोधना की कि हूनिम (न्यूयार्क में नीची लोगों की आवाही) से मूल भाषा—भाषियों की आवश्यकता है। दूसरे दिन लगभग २०० टोल एयर (दोस वयों से कम उम्र वाले) उनके कार्यालय का सामना दृष्टांत हो गए और उन्होंने उनमें से ४० को चुन लिया। उनमें से काफी संख्या यहाँ स्कूली शिक्षा लिए हूनों (ग्राफ आउटस) की थी। उन्होंने उन बच्चों को यू.एन. कारेन सद्विह दृष्टीभूत संयुक्त के प्रयोग में प्रविष्टित किया। यह संयुक्त स्नातक प्रविष्टित माता पिताओं के प्रयोग के लिए बनाई गयी थी। एक सत्राह के भीतर उनके शिक्षक (हीन एयर) आराम निर्भर हो गए और प्रत्येक ने चार ऐसे न्यूयार्क के रहने वाले को शिक्षा के लिये चुना जो स्पेनिश कोशल चाहते थे। ६ महीने के भीतर विद्यालय पूरा हो गया। कांक्रिम स्पेनिश में यह यह बात कि जबके १९३७ गिरिलायो में कम से कम तीन लोग ऐसे थे जो स्पेनिश कोशल सकते थे। कोई भी स्कूल इस प्रकार का कार्य पूरा नहीं कर सकता था।

कोशल के बिलको की कमी का कारण साक्षरों के विस्थापन है। प्रवास-पत्रिकारण बाजार का, गोरसवाया है और केवल स्कूली मस्तिष्क ही इसे व्यवहार में ला सकता है। कोशल कला के अधिकतर स्कूलों अध्यापक मन्त्रों सिल्लाकारों और व्यवसायों को अपेक्षा कम नियुक्ता कम नीतिगत और कम प्रवृत्तिवादी रहते हैं। बहुत से हाई स्कूल के शिक्षक स्पेनिश का फासीवी भाषा उत्तमो अच्छी तरह नहीं बोलते जितनी अच्छी तरह उनके विध्य ६ महीने के उपयुक्त अध्यापन से बाद बोल सके हैं। न्यू-टोरिको में एजितविशालों ने जो प्रयोग किए हैं उनके सन्ने मिलता है कि बहुत से टोल एयर, यदि उन्हें उचित प्रोत्साहन दिया जाय और साधन भी दिए जायें तो अपने

श्रौद्ध शिक्षा कोठारी शिक्षा आयोग की रिपोर्ट

(समान से अन्तिम)

1737 औद्योगिक कामगारों की शिक्षा—सब
छिन्न उद्योगों के कामगारों को शिक्षित करके क लिए
अवधारण पद्धति नीचे कार्यक्षेत्र करने की आवश्यकता
पर हम पहले ही जान दे चुके हैं और यह सुझाव भी दे
चुके हैं कि वह तीन वर्षों की अवधि में बनाया जाय।
हमने यह सुझाव भी दिया है कि उनकी शिक्षा निम्नो
तोषो और शिक्षा विभाग व सहयोगात्मक प्रयास के
रूप में होनी चाहिए। निम्नोक्त समय वगैरह विधाय
और प्रोत्साहन से तथा शिक्षा विभाग शिक्षा कार्यक्रम
द्वारा करें अध्यापकों और पुस्तकों की व्यवस्था करें
यही तालीम/१४

तथा अन्य प्रकार की सहायता दें। उत्पादन बढ़ाने में
अधिक वय के महत्त्वपूर्ण योगदान को देखते हुए उनके
काम पर प्रोत्साहन होने के साथ ही उनकी शिक्षा समाप्त
न होने दी जाय। हम शिक्षा से करते हैं कि कामगारों
को भी शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि उनका ज्ञान, कारी
गरी समस्त हो जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण व्यापक
हो अपने व्यवसाय के प्रति उनमें शक्तिव्य साधना पैदा हो
और वे अपने काम में जागे रहें। उनके लिए विशेष
अवकाशिक और 'सेमिनर' कार्यक्रम चलाये जाय ताकि
वे क्रमशः पठकर्मियों को बनवाते जाय।

1738 इस विषय में एक महत्त्वपूर्ण उपाय यह

होगा कि औद्योगिक कामगारों के लिए ऐसे विशेष पाठ्य-क्रम चलाए जाए जो बुल्लता और स्तर के विचार से स्कूल के नियमित विद्यार्थियों के उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रमों के समतुल्य हों। शरतानों के बराबर, धरातलवादी और व्यवहार बुद्धि का समाचार तथा जीवन में किसी निश्चित व्यवसाय में म अने हुए स्कूलों ने निश्चित किछोर—इन दोनों की भाषा प्रकृतियों और महत्वाभावों का अन्तर समझना आवश्यक है। स्कूलों से निकल कर विद्यार्थी जैसे जैसे उच्चतर शिक्षा सम्प्राप्तों में पहुँचते जाते हैं भाषा पुष्टि के साथ यह अन्तर घटने लगता है, पर माध्यमिक स्तर उसका जो अन्त्य महत्त्व है वह कामगारों के लिए ऐसे पुनः-पुनर् असाकानिक और समाचार पाठ्यक्रमों द्वारा व्यक्त होता चाहिए जिनमें उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा विशिष्ट व्यावसायिक और अन्य हितों पर बल दिया गया हो।

17 **डॉ० मेन्दीप माधवमिक** विश्व बोध द्वारा गुरुवार 11/11/2023 विद्या के कार्य प्रारम्भ हुआ चाहिए। समाज के समस्त भौतिक सत्त्वों को भी अपने कामगारों के लिए कक्षाओं का आयोजन करने की क्षमता है। परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रोत्साहित करने की दृष्टि करनी चाहिए। विवेक रूप से तैयार होने वाले कार्यक्रमों के अन्तर्गत जलाने व नष्टकालिक कार्यक्रमों से कामगारों को और भी सहमता मिलेगी जो उनके हितों के सम्बन्ध सामान्य, तकनीकी, प्रभाव विपद और अन्य प्रकार की शिक्षा के विविध क्षेत्रों में उन्हें उपयुक्तता के स्तर तक के ध्यान में समर्पण है।

17.40 कागजारों की शिक्षा, प्रिन्सा मन्त्रालय तथा घर और रोजगार मन्त्रालय का समुक्त दायित्व होना चाहिए। कोलोनिअल कागजारों के लिये शिक्षा के सङ्ग-भारत्मक पक्ष का दायित्व कम और रोजगार मन्त्रालय का होना चाहिए जो विभिन्न समुहों के लिए कक्षाओं की व्यवस्था करे, शिक्षा के लिए उचित समय पर छोड़ दें, प्रश्नों के लिए कमरे, पुस्तकालय, वाचनालय और नहीं सम्भव हो प्रयोगशाला आदि की सुविधाएँ दे तथा सबसे बड़े घर यह है कि जो प्रवृत्ति दिखाएँ, उन्हें प्रोत्साहित दें।

श्रम और रोज़गार मन्त्रालय, निषेधा विरुद्ध विधान, साम्यवादी शिक्षा बोर्ड और तन्मयी शिक्षा के प्रगामी विद्यार्थियों में परामर्श करके औद्योगिक कामगारों के लिए अनेक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों की तैयारी है। यह सब कुछ शिक्षा मन्त्रालय करे। अन्त्या-पक्ष, पाठ्यपुस्तकों तथा अन्य सुविधाएँ भी शिक्षा मन्त्रालय को देनी चाहिए और सामान्य तथा तन्मयी शिक्षा की पयोगी सुविधाओं से कामगारों की शिक्षा के लिए जो भी सुझाव मिल सके, ठिकारी चाहिए।

1741. औद्योगिक क्रांतिकारों के निम्न प्रमुख शिक्षा की योजना सर्वोच्च स्तर और सोशलिस्ट मान्यता बनाती थी। जो वस्तुमान कार्यक्रम एक सामान्यतापूर्ण रूपों भ्रम नीतियों और इसी प्रकार की अन्य बातों अन्वेषण सामरता और मनोरञ्जन के कार्य-प्रणाली पर ही ध्यान देते हैं उनसे पाए जाने वाले अन्वेषण इन कार्यक्रमों से न रहे ऐसा प्रतीत होता था। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिये कि अधिकाधिक कामगारों को उत्त्पन्न तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा मिले ताकि वे उद्योगों में व्यवसायिक पद ग्रहण करें। इस उद्देश्य के विचार के कामगारों की शिक्षा को सामान्य, व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा की मुख्य धाराओं से वृद्ध नहो संभवता वा सकता। जैसा कि हम अन्वेषण चार दशक पहले हैं सामान्य और व्यावसायिक शिक्षा के स्कुलों, कॉलेजों, माध्यमिक शिक्षा बोर्डों, विश्वविद्यालयों और तकनीकी शिक्षा संस्थाओं से औद्योगिक कामगारों की शिक्षा का अधिकाधिक दायित्व लेना चाहिये।

1742 विशेष कार्यक्रम और सस्थाएँ—यह सम्भव नहीं है कि स्कूल और कॉलेज पद्धति के अन्तर्गत अवकालिक पाठ्यक्रम शोध शिक्षा को विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा कर सके। उनसे से कुछ के लिए विशेष छात्राओं की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए समान न्याय बोर्ड द्वारा खोजी गई सस्थाओं के सुव्यवस्थित कार्यक्रमों की ओर ह्वाला प्वाल दिया जा रहा है। जहाँ जिसके विषयों की विविध सामाजिक सेवाओं का प्रतिक्रिया देने में निष्पक्ष सस्थाएँ सहित पाठ्यक्रम आलोचित करती हैं और अन्य समान सेविनाओं के रूप में विषयों को

शिक्षण की प्रवृत्ति प्रबल होगी। यंगी ही महत्वपूर्ण बात यह है कि जन्मी सहायता के लिए स्तर में दिखाई नहीं होगी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो पाठ्यक्रमों को बर्बाद बना देनी चाहिए ताकि अशक्तानिष्ठ विद्यार्थियों के लिए उन्हें पूरा करना अपेक्षाकृत सरल हो जाय।

जिनकी भारी संख्या में हो सके प्रतिक्षण दिया जाय। इसका अनिवार्य यह हुआ कि सहित पाठ्यक्रमों के केन्द्रों को सहाय्य कई गुना अधिक होनी चाहिए और पुनी हुई सैद्धांतिक समस्याओं—जैसे कलेजों, हाई स्कूलों, अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रशिक्षण के लिए स्टाफ बढ़ाया जाय और अन्य आवश्यकताएँ पूरी की जाय। प्राचीन समस्याओं और संसूत राज्य के विद्यार्थियों का हमने जो ध्यान दिया गया है हम उसमें प्रभावित हुए हैं। एक तरह से यह विद्यार्थी के संसार के लोक हाई स्कूलों की तरह काम करते हैं और खुद हुए प्राचीन दलों को छोटी देर के लिए नहीं रखकर उन्हें सामान्य और व्यावहारिक दोनों प्रकार की शिक्षा देते हैं। जैसा होना चाहिए इन समस्याओं में शिक्षा का रूप उद्देश्यपूर्ण होता है और उसमें कृषि और ग्राम शिक्षा पर ध्यान दिया जाता है। कुछ ग्राम संस्थाएँ, ग्राम पंचायत समितियों के प्रयागों और पंचायतारियों के दलों के लिए ऐसे संक्षिप्त पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करती हैं जिनसे उन्हें अपने पक्षों की विधेय-रियों की और नागरिक संस्थाओं को निर्णय पर पहुँचने की लोकतन्त्रिक कार्यविधियों को समझने में सहायता मिले। हमारा मुद्दा है कि विद्यार्थियों और ग्राम संस्थाओं के काम की धार-धार समीक्षा होगी चाहिए ताकि वे प्राचीन समाज के लिये उपयोगी हो। इन समस्याओं का स्टाफ उच्चतम कोटि का और विशेष रूप से प्रशिक्षित होना चाहिए। यह जरूरी है कि यह संस्थाएँ कृषि प्रदर्शन छात्रों और विद्यार्थियों के बीच के साथ मिलकर काम करें। ऐसी और संस्थाओं की आवश्यकता है, पर एकमात्र विस्तार नहीं तथा सीमित रखा जाय जहाँ तक संभव स्टाफ और अन्य सहायक सेवाएँ उपलब्ध हो।

17.43 पंचायतों के लिए अशक्तानिष्ठ पाठ्यक्रमों के प्रायोगिक व वैज्ञानिक संस्थाओं के पास वास्तविक साधन होने चाहिए, यह सुनिश्चित करना केन्द्र और राज्य सरकारों का काम है। इन नई सेवाओं के लिए, उन संस्थाओं के पास अनिवार्य स्टाफ, पर्याप्त पुस्तकें, शिक्षण सामग्री और सहायक साधन, पुस्तकालय और प्रयोगशालाएँ होनी चाहिए। अशक्तानिष्ठ विद्यार्थियों को पढ़ाने की प्रभावितता मिलेगी। इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि

नयी धामीन/१६

उनमें सीखने की प्रवृत्ति प्रबल होगी। यंगी ही महत्वपूर्ण बात यह है कि जन्मी सहायता के लिए स्तर में दिखाई नहीं होगी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो पाठ्यक्रमों को बर्बाद बना देनी चाहिए ताकि अशक्तानिष्ठ विद्यार्थियों के लिए उन्हें पूरा करना अपेक्षाकृत सरल हो जाय।

पत्राचार पाठ्यक्रम

17.44 कोई ऐसा तरीका न होना चाहिए जिससे शिक्षा उन लोगों को करने में सक्षम हो सके जो पढ़ने के लिए अपने ही प्रयत्नों पर निर्भर हैं और जब समय मिलता है, पढ़ते हैं। हमारा विचार है कि पत्राचार या दूरशिक्षा पाठ्यक्रम इन स्थितियों में ठीक है।

17.45 पत्राचार या दूरशिक्षा पाठ्यक्रम अच्छी तरह मानगई और जाची हुई तकनीक है। संसार के दूसरे देशों, जैसे अमेरिका, स्वीडन, कनाडा, जापान और आस्ट्रेलिया के अनुभव से हमें प्रोत्साहन मिला है कि व्यापक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस तरीके में दूर-पूरा ध्यान रखने की सिफारिश करें। यह साक्ष्य निर्मूल है कि पत्राचार पाठ्यक्रम नियमित स्कूलों और कालेजों द्वारा भी कई शिक्षा से घटिया वर्गों की शिक्षा का रूप है। भारत के भीतर और बाहर प्राप्त हुए अनुभवों से जो परिणाम निकले हैं, उन पर विचार करने से पत्राचार शिक्षा प्रणाली को धन मिलता है।

17.46 इसमें सन्देह नहीं कि पत्राचार प्रणाली में अध्यापक के प्रेरक-व्यक्तित्व का अभाव रहता है। पर प्रेरणा देने वाले अध्यापक दुर्लभ हो गए हैं। पत्राचार प्रणाली में पठन की सीखने की प्रवृत्ति प्रबल होती है। इस प्रणाली में अध्यापक से व्यक्तिगत और निजी सम्बन्ध स्थापित हो जाता है, जिसके पत्राचार द्वारा सफल एवं सक्षम चर्चा और ज्ञान को प्रोत्साहन मिलता है। वास्तव में विद्यार्थी और अध्यापक के बीच व्यक्तिगत और उद्देश्य सम्बन्ध के अभाव में प्रभावकारी शिक्षा सामने नहीं होती। अनेक उदाहरण और अधिकार्यभूत कालेजों में अध्यापक और विद्यार्थी के बीच कोई सार्थक सम्बन्ध स्थापित नहीं हो पाता। इसी एक बात से हम प्रश्न ली क

वैश्विक मूल्य को समर्थन मिलता है कि पत्राचार प्रणाली में पढ़ने-के लिए मुख्य प्रकाश विद्यार्थी को स्वयं करना है और उसे विविध अभ्यास और परीक्षाएँ निश्चित रूप में देनी होती हैं।

17.47. पत्राचार प्रणाली का अर्थ विभिन्न विद्यार्थी और सम्पादकों का सादान् प्रदान नहीं है। इन प्रणाली का एक अनिवार्य पक्ष यह है कि विद्यार्थी और सम्पादन पराकाष्ठा—सोचें समय के लिए हो सही—मिलते रहते हैं और विशेष रूप से तैयार किए गए कार्यक्रमों में, विशेष प्राप्ति, वेधनार और सामूहिक परीक्षाएँ शामिल हैं, मान लेते हैं। जिन्होंने विज्ञान और तकनीकी विषय लिए हो, उन्हें छात्राह के अंत में या छात्राह के बीच प्रयोगशाला और बर्तनार में जाने देना चाहिए। अनेक प्रकार के अन्य साधन पत्राचार कार्यक्रमों को समृद्ध बना सकते हैं। एक ही क्षेत्र में रहने वाले और समान विषयों में रुचि रखने वाले पत्राचार पाठ्यक्रम के विद्यार्थी स्वाभाविक रूप से मिल सकते हैं और एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। यह बहुत जरूरी है कि उन्हें सम्मान प्राप्त विद्यार्थियों का दर्जा दिया जाय। पुस्तकालय तथा सैद्धांतिक किस्में देखने, विभिन्न विद्यार्थी के रेकार्ड चुनने जैसी अन्य सुविधाओं का लाभ उठाने दिया जाय।

17.48. शिक्षा ॥ कुछ लोगों में ऐसे पत्राचार या पुस्तकालय कार्यक्रम, जो क्रमबद्ध पढ़ाई के विद्यार्थी पर तैयार किए गए हो, बहुत ही लाभदायक हो सकते हैं। यद्यपि ऐसा है कमबद्ध आवश्यकियों के परिणामस्वरूप स्थिति में बहुत अच्छे होते हैं जब विद्यार्थी को नये विषय से परिचित कराया जाता है और उसे उचित मूलभूत व्यवहारणाओं को समझना होता है कि पत्राचार पाठ्यक्रम में क्रमबद्ध पढ़ाई का प्रयोग लाभदायक हो सकता है।

17.49. रेडियो और टेलीविजन के सम्बन्धित कार्यक्रमों का सहारा पत्राचार पाठ्यक्रमों को मिलना चाहिए। सभी लाभ सम्भव नहीं हो पाया है कि कार्यक्रमवाणी का निर्यातित निरवविद्यालय स्थापित किया जाय, तथापि सम्भवतः के विभिन्न क्षेत्रों के अनेकानेक मूलभूत और मूल्य विषयों को रेडियो और टेलीविजन उद्घाटित कर सकते

हैं। इस पक्ष जरूरी सम्झते हैं कि पत्राचार पाठ्यक्रम चलाने वाले निरवविद्यालयों और अन्य एजेंसी-तयों को जाकाधनाली तथा टेनीविजन ॥ साथ मिलकर काम करना चाहिए और ऐसे रेडियो तथा टेनीविजन कार्यक्रम तैयार करने चाहिए जो पत्राचार पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों के लिए मूल्यवान् हों। दिवसीय निरवविद्यालय द्वारा संगठित पत्राचार पाठ्यक्रम के अनेकानेक महत्वपूर्ण विषयों पर विविध रूप से तैयार की गई पाठ्यार्थों और पत्राचारों को 'प्रसारित' करके सुधारम्भ किया जा सकता है।

17.50. निरवविद्यालय की विधियों की प्राप्ति ॥ लिए विद्यार्थियों को तैयार करने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। उन विषयों की सम्पुष्ट शिक्षा के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम के अन्तर्गत महत्वपूर्ण कार्यक्रम मायो जित किए जा सकते हैं जो उद्योगों, कृषि और अन्य क्षेत्रों में नये कामगारों को उत्पादन बढ़ाने में मदद दें। कुछ विषय विशेष पाठ्यक्रम सम्बन्धित किए जा सकते हैं, जिन प्रकार हैं—रखन हथ निर्माण और वायवारी वास्तुविज्ञान लेखरी, बीजक हथ, व्यवसायिकी, इकोनॉमिरी, व्यवसाय प्रशासन, व्यव निर्माण और स्मृति रीटिंग, सर्वेक्षण, सम्मिलन, वणिज, वीट, पात्र, स्वयं यात्रिकी, वाणिज्य कला, इलेक्ट्रॉनिरी, रेडियो—टेनीविजन सम्बन्धित और प्रसारण, सहायक उपस्था, व्यवसायिक पुनर्वासिक विषय, कोटोविक इलेक्ट्रॉनिरी और स्वयंसाय पोषाक बनाना और निरविकार्य विषय, वातावरण सम्बन्धित, प्रशीतन, कोषवारी और दीशाली उपशीत, वातावरण प्रवन्ध, होटल प्रवन्ध, फैक्टरी प्रवन्ध और कार्यकारी प्रशासन, द्वार कम्पनी प्रशासन, कोटोवारी, ठाले बनाने का व्यवसाय, पोषिक और प्रवन्ध सम्पत्ति, देना लोगों से विचार पूर्वक सम्बन्ध अच्छे पत्राचार पाठ्यक्रम अपनी माय स्वयं पैदा कर लगे जो उत्पादन को अत्यधिक पद्धतियों के लिए लोगों का सर्वोप प्राप्त करने में सहायक होंगे।

17.51. पत्राचार पाठ्यक्रम उन लोगों के लिए भी होने चाहिए जो सामूहिक और बलात्मक विषयों का अध्ययन द्वारा जीवन को समृद्ध बनाना चाहते हैं जिनसे—

पापाए दर्शन, इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, साहित्यालोचन, मनोविज्ञान आदि। ये विषय वस्तुनः विशेष उपयोग के लिये हैं, और मते ही ये आर्थिक उन्नति में विशेष सहायक न हों, बौद्धिक और कलात्मक स्तर को उठाने और जीवन दृष्टि के रूपान्तरण में ज़रूर सहायता करते हैं।

17 52 यह स्पष्ट है कि हम पत्राचार पाठ्यक्रमों का आयोजन करते वक़्त ऐसी विषयविधानय ही नहीं होनी चाहिए। पत्राचार पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करना कृषि, उद्योग, गृहकारिता, स्वास्थ्य जैसे सहकारी विकास-विभागों की विस्तार सेवाओं का भी एक महत्वपूर्ण कार्य होना चाहिए। शिक्षित और नवजागरूक तब जो जानकारी और जनन तकनीक के विभाग पहुँचाना चाहते हैं उनके लिए पत्राचार पाठ्यक्रम मूल्यवान् स्रोत सिद्ध होगा।

17 53 हम यह भी सिफारिश करते हैं कि स्कूलों के कक्षधारकों के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम के विशेष कार्यक्रम शुरू किए जाय ताकि वे जिन विषयों को पढ़ाते हैं उनके बारे में मई जानकारी से तथा शिक्षण के नये तरीकों और तकनीकों से परिचित रहें। यह उपाय स्कूलों की एक निराशापूर्ण स्थिति में और भी ज़रूरी हो जाता है, जिसमें अध्यापकों को काम करना पड़ता है, जहाँ पुस्तकालय की सुविधाएँ कम होती हैं तथा बौद्धिक सर्वाँ नहीं होते। अध्यापक जो भी पढ़ाते हैं उनके बारे में इसके माध्यम से जानकारी और कार्य नई बुद्धिधर्मों से प्रेरणा भी पहुँच सकते हैं।

17 54 अन्य मन्त्रालयों के सहयोग से शिक्षा मन्त्रालय का राष्ट्रीय ग्रह कार्यक्रम परिषद को स्थापना करनी चाहिए। इस परिषद को अनेक कार्य संचालने का प्राधिकार मिलना चाहिए जिनके एजेंडायों को मान्यता देना और मूल्यांकन करना भी शामिल हो। परिषद को उन चीज़ों का पता लगाना चाहिए जिनमें पत्राचार पाठ्यक्रम सामर्थ्य हो सकते हैं। यह या तो परिषद स्वयं स्थापित करे या जन्म ज्ञान के लिए सरकारी विभागों, निदेशविद्यालयों, शिक्षा - बोर्डों, स्कूलों तथा - संस्थाओं और नये मानव/१८

मैरिटरकारी एजेंसियों की सहयता करें। पत्राचार द्वारा शिक्षा देने के अनेक कार्यक्रमों का लगातार मूल्यांकन भी परिषद को करते रहना चाहिए।

१७ ५५ पत्राचार पाठ्यक्रमों की लागत के विषय में कुछ मतभेद हैं। एक विचार है कि पत्राचार कार्यक्रमों का यदि अधिक नज़दीकी उतनी ही लागत आती है जितनी स्कूल, कालेज और अन्य संस्थाओं की नियमित पढ़ाई पर आती है। चूँकि पत्राचार विद्यालयों की संख्या बहुत अधिक होती है, इस पर आश्वासन दे दी जाते वक़्त निम्नलिखित शिक्षा की अपेक्षा निम्नलिखित ही कम खर्च आना चाहिए यह दूसरी धारणा है।

निम्नलिखित चीज़ों में इस पर होने वाले लागत - व्यय की तुलना सरल नहीं है क्योंकि सम्भवतः अलग - अलग हैं। यह बात उल्लेखनीय है कि इसमें विद्यार्थी की संख्या-वृद्धि के साथ - साथ पर्यवेक्षण स्टाफ की आवश्यकता नहीं बढ़ती और उल्लेख स्टाफ का सात प्रिदायियों की बहुत भारी संख्या तक पहुँच जाता है। विद्यार्थी पहले के साथ-साथ काम भी करता है और कमाता भी है। यदि वह उत्पादन करने वाला कामधार है तो उत्पादन में भी गृहयुक्त होता है, यदि पत्राचार पाठ्यक्रम व्यवस्था से सम्बन्धित जानकारी और कारीगरी को उल्लत करने में सक्षमता केन्द्र है, यदि पत्राचार पाठ्यक्रम व्यवस्था के सम्बन्धित जानकारी और कारीगरी को उल्लत करने में सहायक होता है तो विद्यार्थी अपना काम पहले से नहीं अच्छा कर सकेगा। उसके लिए ज़रूरत से किसी इमारत और उपकरण की, सेल के भेदान और ब्यापारगामा की, छात्रावास और विशेष ट्यूटलों की, विशेष पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं की आवश्यकता नहीं पड़ती।

१७ ५६ हम यह सिफारिश करते हैं कि प्रादेशिक सम्पीदवारों के लिए, वे चाहें कहीं काम कर रहे हों, यह सम्भव होना चाहिए कि वे देश के माध्यमिक शिक्षा बोर्डों और निदेशविद्यालयों की कोई या सभी परीक्षाएँ दे सकें। बहुत से सम्पीद निवार वाले व्यक्त (कम आय के लोग भी) विशेषकर लड़कियाँ और स्त्रियाँ देश के माध्यमिक शिक्षा बोर्डों और निदेशविद्यालयों की कोई या सभी परीक्षाएँ नहीं दे सकते क्योंकि वे उपस्थित सम्बन्धी चीज़ों को

पूरा नहीं कर पाते। कोई कारण नहीं कि उन्हें इन परी-
क्षाओं की तैयारी के लिए अपने प्रयत्नों पर निर्भर रहने
के लिए प्रोत्साहित न किया जाय।

पुस्तकालय

१७.५४ इन अध्याय में विभिन्न भाषों में हमने
पुस्तकालयों की आवश्यकता का उल्लेख किया है और
हमारा विश्वास है कि एक अच्छे पुस्तकालय पद्धति, जो
पुस्तकों को सबसे पास पहुँचा सके; प्रौढ़ शिक्षा पद्धति का
मूलभूत भाग है। इसके बिना, विशेष कर सामान्य क्षेत्रों
में जहाँ पुस्तकें बाँटना कठिन है, प्रौढ़ों में पढ़ाई की
मात्रा बढ़ने की कोई आशा नहीं है। योजना आयोग के
कार्यकारी समूह देशभर में सके समाने पर पुस्तकालय
स्थापित करने की विचारित की है। हम सामान्यतया
इस विचारित से सहमत हैं।

१७.५८ पुस्तकालय सहायकार समिति (१९६०)
की रीपोर्ट में पुस्तकालयों का जाल बिछाने की मुक्त
निर्धारितों को भी हम समर्थन करते हैं। दिल्ली में एक
राष्ट्रीय वैश्वीय पुस्तकालय, प्रत्येक राज्य में एक राज्य
कैन्द्रीय पुस्तकालय और जिला, सब और गणराज्य स्तर
पर पुस्तकालय इनमें शामिल हैं। इस तरह ऐसा जाल
जा सकता जिससे देशभर में व्यापक पुस्तकालय विकास
और समन्वित सेवाएँ स्थायी हो जायगी।

१७.५९ स्कूल पुस्तकालयों की सार्वजनिक पुस्तकालय
पद्धति के साथ समन्वित कर देना चाहिए। हमने इस
बात पर जोर दिया है कि स्कूलों की प्रौढ़ - शिक्षा और
विस्तार सेवाओं का केन्द्र बनना चाहिये। इस उद्देश्य से
शाला - पुस्तकालयों की विकसित किया जाय और इस
कार्य में उनकी सहायता की जाय।

प्रौढ़ शिक्षा के साधन की तंग्रह काम में लाने के लिए
पुस्तकालयों के पुनर्गठन की आवश्यकता है। उन्हें ऐसी
पाठ्य सामग्री का भंडार रखने की जरूरत पड़ेगी जो नव
पाठशाला की भीरे भीरे सामान्य परम्परा बर्नकर बर्नर द्वारा
मूल्यमान आवश्यकता देने वाली, क्लेसाइज्ड उच्च स्तर की
पुस्तकें तक ले जाए। पुस्तकालयों में ऐसी पुस्तकें और
पाठ्यसामग्री की भी आवश्यकता पड़ेगी जिसका ब्यस्को

की ग्राह्यताएँ जरूरतों और दृष्टियों की प्रत्यक्ष सम्मन्ध
हो। जहाँ सम्भव हो, पुस्तकालयों में टेपरिकार्डों, फ़ोटो-
कोन विकारों, फ़्लैशों और अन्य उपयोगी साधनों का
संग्रह रहना चाहिए। पुस्तकालयों का उपयोग वे सभी
नोच करके जो अंतर्कालिक विद्या वा रहे हैं, जिन्होंने
पनापार पाठ्यक्रम ग्रहण किए हैं और जो अपने ही
प्रयत्नों पर निर्भर हैं। यह जरूरी है कि पुस्तकालय-
उपकरण में इन सबकी आवश्यकताएँ पूरी हो।

१७.६० जैसा स्वभावतः होता है, पुस्तकालय पुस्तकों
का भंडार ही नहीं होता चाहिए, वे गतिशील हों, बयस्को
को सिधित करें और सहे माकूट करें। ऐसा करने के
अनेक जाने-माने उप हैं। एक उन जो इस देश में प्रौढ़
शिक्षा की प्राचीन परम्परा के अनुरूप है, वह है शालाओं
को इकट्ठा करके उन्हें कोई दक्षिण पुस्तक या कविता
पढ़कर सुनाना। नापण, बर्न - मन्तिना और पुस्तक
बतव मुक्त किए जाय और पुस्तकालय को बयस्को का
केन्द्र बनाने के यत्न किए जाय। सदाहरण के लिए हम
बिस्वी पब्लिक लाइब्रेरी द्वारा दिए गये उपयोगी कार्य का
उल्लेख करते हैं जिसने लोगों का बिना पुस्तकों की और
आकर्षित ही नहीं दिया, बल्कि पुस्तकालय की विविध
सार्वजनिक कार्यकलापों का पवित्रीय केन्द्र बनाने का भी
प्रयास किया है।

प्रौढ़ शिक्षा में विश्वविद्यालयों का योगदान

१७.६१ महत्व—विश्वविद्यालय के बारे में यह कल्प-
ना अब पुरानी हो चुकी है कि वह विद्वानों का ऐसा
संकुचित खैसिक समुदाय है जो ज्ञान का गुजन और प्रका-
शन करता है तथा अपने रसों को सांस्कृतिक बनाता है।
वे दीवारों से उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों और भव्य प्राची-
णों के बीच खंडी थी, वह चुकी है और सब दोनों की
परस्पर 'गर्भ' की दृष्टि से विश्वविद्यालय के जीवन को
जब 'गर्भ' के जीवन से अन्तरी तरह सम्बद्ध किया जा
सकता है।

१७.६२ यह कल्पना हुआ दृष्टिकोण उन विश्वविद्या-
लयों में रच्य है जहाँ विश्वविद्यालय की चहार दीवारों
के बाहर विद्यार्थियों के सामान्य पनाचार पाठ्यक्रमों में

ऐसे और पाठ्यक्रमों की मांग पैदा कर दी है। राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा प्रोड शिप्रा विभाग की स्थापना स्वागत योग्य है और उससे बड़ी मांग है। इन अनुभव करते हैं कि हमारे देश के विश्वविद्यालयों को प्रोड शिक्षा का अधिकाधिक भार उठाना चाहिए।

१७ ६२ वाक्यक्रम—विश्वविद्यालय का काम है अपने रोहित समुदाय को उसके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक विकास में मदद देना। अपनी विशेष एजेंसियों के द्वारा यह लोगों को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के कुछ विशेष क्षेत्रों पर स्वरूप प्रभाव डाल सकता है। इस विषय में आगे बढ़ने का एक महत्वपूर्ण तरीका यह है कि सामाजिक और आर्थिक समस्याओं के बारे में नए वैज्ञानिक निष्कर्ष और नए विचार लोगों तक पहुंचाए जाएं। इसी प्रकार विभिन्न व्यवस्थाओं के मुख्य मुद्दों का निष्कर्ष की पुनर्गति के विभिन्न कार्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा प्रभावकारी ढंग से बनाए जा सकते हैं। मध्याह्न की पुनर्गति का विशेष उल्लेख भी इस प्रसंग में उचित होगा। इसकी वस्तुतः इसकी अधिक है और यह समस्या इसकी व्यापक है कि प्रभावशाली नेटवर्क के लिए देश विश्वविद्यालयों की ओर इस आशा से खेला कि वे मध्याह्न की पुनर्गति में उन्हें मिलान की गई रीतियों, मधोम पद्धतियों, शिक्षा के अभिन्न दृष्टि और सम्बंधित ज्ञान ज्ञान में विकास से पूरी तरह अवगत कराए। कुछ मूलभूत राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति जन समुदाय में स्वस्थ प्रवृत्ति जमाने में विश्वविद्यालय सहायता से सक्षम हैं। वे ऐसे वाक्यों को का माधोवन भी कर सकते हैं जो राष्ट्र के नेताओं और जनता को नागरिक और राजनीतिक जन जीवन की जानकारी दें और राष्ट्रीय जीवन की पुनर्गति देने वाली कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं पर विचार करने के लिए व्यावहारिक ज्ञान और व्यापक अनुभव का साम भी उन्हें दें। राष्ट्रीय धर्मरहित तथा जनता की भावों और सामाजिक व्यवहार के स्तर को उठाते हैं और उन्हें सहायता देनी चाहिए। विश्वविद्यालय अपनी क्षमता को ठोके और पवित्र समाज के आशाओं को भी बहाल कराए। इस व्यापक प्रयत्न पर हम पहले ही यह चुके हैं कि क्या राष्ट्रीय २०

देश से निरक्षरता का उ मूलन करो और इस उद्देश्य से नेताओं को शिक्षित करने में विश्वविद्यालयों को क्या सहायता देनी चाहिए।

17 64 विश्वविद्यालय ऐसे तरीके स्वयं निकाय सकते हैं जिनके द्वारा अपने छात्रों के अनुसार समुदाय के लक्ष्य सेवास संपादित की जा सकें। साथसाथीन कक्षाएं प्रायः ऐसे व्यक्तियों के लिए आयोजित की जाती हैं जो कहीं नौकरी करते हों और जिन्हें परीक्षाओं की तैयारी करनी हो। व्यावसायिक लाभ के लिये विशेष अध्ययन महसिया और अल्पकालिक विशेष पाठ्यक्रमों के आयोजन की भी आवश्यकता है। साथ ही विविध विस्तार कार्यक्रम भी आवश्यक हैं। इनमें भाषण, दान, प्रदर्शन, सांस्कृतिक तथा मनोरंजन आदि कार्यक्रम शामिल हैं। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालयों को समाज सेवा निधियों का आयोजन भी करना चाहिए और विकास तथा निरक्षरता कम करने के बहुत कार्यों के लिए स्कूलों और अन्य सामाजिक सेवासों की देखभाल के लिए राशियों को अपना लेना चाहिए। ऐसे अनियमित तरीके हैं जिन्हें विश्वविद्यालय अपनी विस्तार सेवा को प्रभावशाली बनाने के लिए अपना सकते हैं।

17 65 प्रशासन और शिक्षा—योजनाबद्ध प्रोड शिक्षा कार्यक्रमों को ध्यानपूर्वक चालू करने और उनकी उपलब्धियों को सुधारन के लिए विश्वविद्यालयों के पास एक कार्यक्रम तय होना चाहिए। हमारा सुझाव है कि प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक प्रोड शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जाय जिसमें प्रोड शिक्षा कार्यक्रमों की तैयारी करो तथा इनके विश्वास के सम्बंधित सभी विभाग शामिल हों। जब कुलपति इस बोर्ड का अध्यक्ष हों। बोर्ड की नीति निर्धारित करने चाहिए और योजना बनानी चाहिए। संचालन के लिए अनेक विभागों के सम्मिलित प्रयास का दिना निर्देश करना चाहिए और कार्यक्रमों की सफलता का सुधारन भी करना चाहिए। हमारा विचार है कि देश के कुछ विश्वविद्यालयों को प्रोड शिक्षा विभाग स्थापित करने चाहिए। इन विभागों का उद्देश्य होना चाहिए प्रोड शिक्षा के क्षेत्र में नियंत्रण और अध्ययनों की प्रगति देना। शिक्षा सभासदों और मनोविज्ञान

के अन्य सम्बन्धित विभागों के सहयोग से प्रौढ शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं पर अनुसंधान कार्यक्रम करना साथ-साथ करना तथा विस्तार सेवा के अन्तर्गत शिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रौढ शिक्षा बोर्ड का सहयोग देना और उनकी कार्यक्षमता में सहायता देना।

17 66 बच्चे की आवश्यकता नहीं कि विषय-विद्यालयों द्वारा स्वीकृत प्रौढ शिक्षा कार्य के लिए उन्हें विशेष विषय-विद्यालयों और उपकरण आदि विषय-विद्यालयों। विस्तार सेवाओं को आरम्भ करने के लिए विषय-विद्यालयों के साथ-साथ सम्पर्क होगा। यह ठीक है कि जयिकाय कार्य स्वच्छिन्न आधार पर होगा। यह वि-विद्यालयों को कुछ क्षतिपूर्ति-स्टाफ और विशेष पुरस्कारों को माध्यम-गता भी पड़ती है। इसके अलावा यह सम्बन्ध-साधन परिवर्तन के उपयुक्त साधन शिबिर उपकरण और अन्य शैक्षणिक साधन शामिल हैं। हमें विश्वास है कि प्रौढ शिक्षा कार्यक्रमों के लिए विषय-विद्यालयों की भी गई सहायता प्रथम सामग्री होगी।

संगठन और प्रशासन

17 67 हम पहले ही देख चुके हैं कि प्रौढ शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ कार्य की मुख्य समस्याएँ रही हैं—एक समग्र योजना और विभिन्न स्तरों पर विभागों तथा स्वच्छिन्न एजेंसियों के समन्वय का अभाव।

17 68 राष्ट्रीय प्रौढ शिक्षा बोर्ड—इन पुष्टियों को ध्यान में रखते हुए यह कार्य-समिति की समन्वयिका समन्वयी रिपोर्ट में के बीच सम्बन्ध शिक्षा बोर्ड की स्थापना की सिफारिश की गयी थी। जून 1965 में प्रौढ शिक्षा समन्वयी राष्ट्रीय समन्वयिका या राष्ट्रीय प्रौढ शिक्षा और साक्षरता बोर्ड बनाने की सिफारिश की गयी थी। हम इसी प्रकार के राष्ट्रीय प्रौढ शिक्षा बोर्ड की स्थापना की सिफारिश करते हैं जिसमें सभी सम्बन्धित मन्त्रालयों और एजेंसियों के प्रतिनिधि हों। इससे स्थापना के लिए शिक्षा मन्त्रालय आरम्भिक चारपाई पर चलता है। उक्त बोर्ड के साथ इस प्रकार होगा।

(1) मनोवैचारिक प्रौढ शिक्षा और प्रशिक्षण के सम्बन्धित सभी मामलों में केन्द्रीय और राज्य सरकारों को सहायता देना और उनके विभागों को योजनाएँ और कार्यक्रम बनाना।

(2) जहाँ आवश्यक है साहित्य तथा अन्य शिक्षण सामग्री के संचय और अपेक्षित प्रशिक्षण कार्य-क्रमों के लिए एजेंसियों और सेवाओं को स्थापना को बढ़ावा देना।

(3) विभिन्न मन्त्रालयों तथा सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों के बीच सम्बन्ध सुनिश्चित करना।

(4) समग्र समग्र पर इस दिशा में हुई प्रगति को समीक्षा करना। उच्च परिवर्तन और सुधार के लिए सुझाव देना और।

(5) अनुसंधान कार्य-प्रणाली और मूल्यांकन को प्रोत्साहन देना।

समग्र स्तर पर भी इस तरह के विकास स्थापित किए जाने चाहिए। जिस स्तर पर समिति स्थापित की जायगी जहाँ जिस परिपक्वता पर हों-इसके अन्तर्गत के रूप में कार्य करे। उनकी सहायता के लिए सहायता और साम-साधनों की कृपया समिति हो। इस स्तर पर स्कूलों को समन्वयित करने के रूप में नियमित किया जाय।

17 69 प्रौढ शिक्षा—एक पूर्णतया उलटवर्तनी-कार्य—हम इस बात पर बल देना चाहते हैं कि प्रौढ शिक्षा की बहुविधता, उसकी व्यापकता और विविधता को देखकर यह नहीं समझ लेना चाहिए कि यह किसी एक मन्त्रालय के अन्तर्गत एक विभाग का काम है जो प्रशासनिक रूप से समालोच्य है। यह जरूरी है कि इसे अनेक विभागों का कार्य माना जाय। योजना बनाने के स्तर पर ही नहीं कार्य-समिति के स्तरों पर भी उसके कार्यक्रम बनाने और उसका प्रसार करने में विभागों के लिए कोई स्थान नहीं है। हम समझना चाहते हैं कि प्रशासनिक उदासीनता के कारण इस क्षेत्र में कार्य को बहुत हद तक क्षति पहुँची है। यह ठीक है कि प्रौढ शिक्षा मुख्यतः शिक्षा मन्त्रालय का कार्य है पर ऐसी आवश्यकता की अवधाना जरूरी है जिसे समग्र प्रशासनिकता का व्यावहारिक सहयोग सुनिश्चित हो।

17 70 स्वच्छिन्न एजेंसियाँ—इन दोनों में कार्य करने वाली स्वच्छिन्न एजेंसियों को हर प्रकार का वित्तीय और तकनीकी सहाय्य दिया जाना चाहिए। प्रौढ शिक्षा ऐसा क्षेत्र है जो स्वच्छिन्न प्रणालियों के लिए बहुत अनुकूल है। इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है। उनकी सफलता में स्वच्छिन्न प्रणालियों का बहुत बड़ा हाथ होगा।

—समाप्त

प्रौढ़-शिक्षा में आत्मानुभूति

सुषमा मिश्रा,

विद्याभ्यासे (एड०एड०) में अध्ययन करते हुए एक दिन प्रोडो को सिखाते करने में भाषाओं की ने एकाएक मुझे लगा दिया। मैं पहले से इसके लिए बिलकुल तैयार नहीं थी। जो कुछ अनुभव था, अच्छे को ही पढ़ाने का था। इस सम्बन्ध में मैं अपने अनुभव निम्न रखी हूँ। इसमें किसी प्रकार की कृतितता नहीं है।

मेरा यह अनुभव है कि बच्चों को तो धार से डाढ़ रपट कर निम्नलिखित किया जा सकता है और उन्हें पढ़ाने के लिए अनेक विधियाँ हैं। उनके ज्ञानार्जन के स्तर में बहुत से शोध, अनुसंधान भी हुए हैं, किन्तु प्रोडो के साथ वही सख्ती नहीं अपनायी जा सकती है, क्योंकि वे न तो सहज निपटारा के योग्य ही होते हैं और न उनका मानसिक दृष्टिकोण ही विषय बनने के लिए उचित प्रेरित करता है। प्रोडो ने कवि उत्पन्न करना भी एक समस्या है। उनकी अनेक समस्याएँ रहती हैं।

एक दिन विभाग में हमें देर से घरना पड़ा, देखा कि हमारे विभाग के अध्यक्ष सहोदय प्रोडो को एकत्रित कर पड़ा रहे हैं। मेरी भी इच्छा पढ़ाने की हुई थी, मैंने भी बर्तमाना कम से ही पढ़ाना प्रारम्भ किया। प्रोडो ने अनेक प्रकार के प्रश्न किए। एक ने कहा—'बुद्ध की कालिदास से सीधे पढ़ने आते हैं। सर दर्द कर रहा है।' के बच्चे वही माँदे रहते थे ही। मैंने सहानुभूतिपूर्वक कहा सोचा भाराम कर मो, फिर ठीक हो जायगा। दूसरे ने कहा—'महान की। लोकता नाही था।' मैंने समाधान करते हुए कहा कि कोहें के पास जाओ तो ठीक दिखाई देगा। वे प्रश्न ज्ञान बात की ओर भी संकेत करते हैं कि प्रोडो की व्यक्तिगत समस्याओं को समझना पहले आवश्यक है।

इन सब प्रश्नोंपत्तरो से मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ दूसरे दिन जब मैं विषयविचारसय गयी, तो मेरे भाषाओं की ने कहा कि तुम रोब बनास लिखा करो, मैं प्रतिदिन ब्यास लेने लगी। साथ ही साथ मेरे मन में एक और भावना उत्पन्न हुई। मेरे प्रति एक सरकारी अस्पताल में डाक्टर हैं। अस्पताल में ४५५-डाक्टर, कम्पाउण्डर और स्वीपर-हैं। मैंने उनमें से स्वीपर के परिवार को पढ़ाने का विचार किया। मैंने सबसे कहा कि तुम और तुम्हारी औरत दोनों प्रतिदिन काम को हमारे पास लाया करो। पहले दिन तो उसकी स्त्री ही आयी। उसने मैंने पूछा, 'रघुनाथ क्यों नहीं आया।' उसने कहा—'उनके घरम लापट था कि साहब से हम लौते पड़ें।' मैंने कहा कि कौरे इसमें लचाने की क्या बात है, कम से कम अपना नाम तो लिखवा सीस जायगा। किसी तरह वह आया और पढ़ने को राखी हुआ। दूसरे दिन वह स्वतः भाषा और बहुत ही मज्ज भाष से बोला 'साहब का बच्चा।' ठीक है तुम हमारे पास लाया करो और जिध तरह पढ़ोगे, हम पढ़ाएँगे। ऐसा मैंने सबसे कहा। उन्हें मन्तर लिखने का एक तरीका मैंने अपनाया। मैंने कहा—'अधर बनाने आता है?'

उसने उत्तर दिया—'कोड़ी पोरी साहिब।'।

मैंने कहा—'अच्छा, पहले इस प्रकार खुदा बनाओ' 'कोहें पर बदाते हुए।'।

उत्तर—'बनाय देहमी साहिब।'।

मैंने कहा—'उसी से एक पूल्हा और बनाओ।'।

उसने उत्तर दिया—'बनाय दिहमी साहिब।'।

मैंने कहा—'दोनों के बीच एक पाई लीजो।'।

उसने उत्तर दिया—'खीच देहमी साहिब।'।

कहा—मैं उसके ऊपर एक टोपी उड़ा दो, सब तुम्हारा बँटवारा हो गया। इसी तरह से हर एक अंतर का बोध देने उठे बताया। धीरे-धीरे साठ-बत्त दिन में यह नाम आदि मिलने लगा। कुछ दिनों में रामायण आदि की किताब भी कुछ-कुछ पढ़ने लगा। मैंने जन्हीं की बोली में बोलकर पढ़ाने का काम किया और कर भी रही हूँ, मैं देखती हूँ कि उनसे तादात्म्य कर लेने पर हर विषय सहज हो जाती है।

धीरे धीरे लोगों की रुचि बढ़ रही है। हर वर्ग, हर योग्यता के लोग आ रहे हैं। तीन महिनाएँ भी आने लगे हैं बिना किसी पूर्व प्रशिक्षण के हमने अपने आचार्य के निर्देशन में कार्य प्रारम्भ किया है। उनका कहना है, “बस करके सीखना ही, सबसे मज्जा प्रशिक्षण है। कार्यक्रम की सोचविमता ही हमारा प्रमाण है।”

३

पूर्व बुनियादी या नर्सरी शिक्षा

सुभाष चन्द्र बोस, स्वतंत्रभारत

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी छह वर्ष से ९ वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा की सम्पन्न व्यवस्था न करने में और न गाँवों में हो सकी है, यद्यपि अनौपमिक परिस्थितियों के बच्चों के लिये बड़े बहुरों में परिभाषी पद्धति के काम-काज में लगे हैं। किन्तु ये सामान्य विदेशी पद्धति से प्रभावित हैं एवं सर्वोच्च भाषा पर अधिकार देती हैं, और ये सामान्य कामकाज का साधन बन गई हैं। बड़ी हुई भाषाओं और शिक्षा के लिए बड़ी हुई मात्रा की देखभाल के काम में लगे हैं और गाँवों में तो काम नहीं है। सात वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा है। परन्तु भी अवधारणा है और ये सामान्य भी जीवन-समस्याएँ ज्ञान या प्रीमियम की शिक्षा देकर ही छोड़ दी जाती हैं। नर्सरी और प्राथमिक शिक्षाओं में शिक्षा सरोपबलक नहीं है। संघर्षकाल के सरकार स्थायी होते हैं। शासन के परिणाम निम्नलिखित प्रारम्भ के सात वर्ष के बच्चों में देखा जा सकता है। इस अवधि में ही उनके सामाजिक विकास की स्थायी नींव बानी जा सकती है। बतएव यह आवश्यक है कि ज्ञान-मन्दिरों की स्थापना अथवा शिक्षा की व्यवस्था सम्पूर्ण देश में। पूर्व बुनियादी अथवा ज्ञान-मन्दिरों की शिक्षा का स्वल्प प्रमाण बच्चों और माता-पिता के लिये की शिक्षा के

विषय, सर्वे सुव्यवस्था तथा सामाजिक विकास का होना चाहिए।

पूर्व बुनियादी या नर्सरी शिक्षा के सम्बन्ध में शासन सर्वथा उत्साही रहा है, बहुत साधन में इसे कुछ विशेष मोड़ देने का प्रयत्न नहीं किया है। इस कार्य में अधिकतर और सरकारों व्यक्तिगत या स्वयंसेवकों की ही पहल रही है और उन्होंने अपनी अपनी क्षमता के अनुसार पूर्व बुनियादी या नर्सरी बसाए लगे हैं। वस्तुतः ये सामान्य शासन की मुद्राएँ नहीं हैं और बहुरों में चलने वाली मान्यताएँ, नर्सरी या किन्हीं नर्सरी शिक्षाओं की प्रतीति की स्थापना है। इन सामान्यों में गुरुक, पोताक, सामाजिक आदि के लिए अधिकतर माध्यमिक व्यवस्थाएँ लगी हैं बहुत करती हैं। इन शिक्षा सामान्यों का बहुत-बहुत पूर्ववर्तन सहज हो रहा है। इन सामान्यों में उच्च-मध्यम वर्गीय मनोवृत्ति एवं आचार व्यवहार प्रचलित हैं। सामाजिक व्यवस्था में ऐसी शिक्षा सामान्य अनुपयोगी एवं सर्वोच्च सिद्ध होती है। सामाजिक परिवर्तण एवं देश की सामाजिक, सामाजिक एवं सामाजिक मान्यताओं से ये प्रति दूर हैं। हातकला, चित्रकला, सौंदर्य आदि विषय इन सामान्यों में शिक्षाएँ आते हैं, परन्तु सामाजिको

दृष्टिकोण का अभाव इनमे थाया जाता है और ये सब केवल मनोरंजनात्मक कार्य बन कर रह जाते हैं। प्रत्यापकों की दृष्टि इस दिशा में स्पष्ट करनी होगी निरुत्तरता आदि समाजोपयोगी हो और बच्चों में उनके द्वारा धर्म के प्रति आदर की भावना एवं उचित उत्पन्न हो।

शिक्षा का उद्देश्य शिक्षा का मूल उद्देश्य बच्चों के ऊपर छोड़े हुए गुणों एवं प्रतिभा का प्रकाशोत्तरण करना ही होना चाहिए, तथा शिक्षा जीवन के लिए होने की चाहिए और शिक्षा द्वारा शिक्षार्थी का सर्वांगीण विकास परिलक्षित होना चाहिए साथ ही शिक्षा औद्योगिकीय पर्यावरण में युक्त महिमात्मक समाजवादी समाज के निर्माण की महत्त्वपूर्ण कड़ी बननी चाहिए। अनुसृत संसद कानून में प्राप्त सरकारी या प्रभाव गृहाण एवं स्थायी ढंग का होता है, ये ही सरकार माने चलकर उनके जीवन जीने का आधार बन जाते हैं। शिक्षाओं की शिक्षा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि उसने द्वारा बच्चों के शरीर, मन, भावना और आत्मा का समुचित विकास सम्भव हो सके। अतएव शिक्षाओं की पांच इन्द्रियों दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, रस, गन्ध का विकास समुचित रूप से किया जाना चाहिए। शैक्षिक मूल्य के ज्ञान और अनुभव के ये ही द्वार हैं। विद्यार्थी की शिक्षा के लिए इन पांचों इन्द्रियों का उपयोजन आवश्यकता पूर्वक किया जाना चाहिए। शिक्षक को इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि जैसे जानक कालिका के शरीर छुई हुई पत्तियों को योगदाओं, प्रतिभाओं का प्रकाशोत्तरण करता है और प्रत्येक बच्चे को ज्ञान में उसकी उचित मोर प्रत्यक्ष के अनुसार विभक्त होने की सुविधा प्राप्त कराना है। एवं ही माटी के बर्तनों को हाथों से नहीं होना बल्कि हर प्रकार अपन रूप में ही विभक्त होना। अतएव शिक्षक बच्चों में जोमा-दामा, सर्वांगीण टाइम टयुन होना चाहिए। धर्म, विज्ञान, योग, आर्थिक के क्षेत्रों के विभिन्न विद्यालयों की माटी नगरिकों के लिए उपयुक्त होनी चाहिए।

साक्षात्कार का संगठन एवं वातावरण भी और पहलों में से से परिचारी पर एक शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए, जिससे विद्यार्थी को घर से दूर न जाना पड़े

शिक्षाशास्त्र में आई वर्ष से ६ वर्ष के बच्चों को प्रवेश मिलना चाहिए और कक्षाएं खुली हवादार, साफ सुथरी होनी चाहिए। बच्चों में गर्तरी भासाई, प्राईमरी चालाओं से सम्बन्ध की जा सकती है। वर्तमान प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की संख्या आवश्यकता से अधिक है। अतः इनमें से शिक्षक पूर्व बुनियादी कक्षाओं में पढ़ाने के योग्यता से जांचे जा सकते हैं। ग्राम पंचायतों द्वारा भी पूर्व बुनियादी कक्षाएं खोली जा सकती हैं और ज्ञान पंचायतों पूर्व बुनियादी कक्षा में चलाने के लिए स्कोलरशिप को प्रोत्साहित कर सकते इसके लिए शासन उन्हें ऐसा करने की सुविधा प्रदान करे जिसमें इन कक्षाओं का व्यय भार ग्राम पंचायतों सहित कर सके। इसी प्रकार प्रीट्ट सिद्धांतों के साथ भी पूर्व बुनियादी कक्षाएं खोली जा सकती हैं जो भी ही बच्चों के लिए शिक्षक को १५० ६० प्रतिभाएं देकर दिया जा सकता है। बच्चों के प्राइमरी बुनियादी स्कूलों, हाईस्कूलों तथा एग्रेग्रीगेटेड कक्षाओं के साथ पूर्व बुनियादी कक्षाएं खोली जा सकती हैं। ये पूर्व बुनियादी विद्यार्थी नियुक्ति कर सकते हैं। इससे व्यय कम होगा। परन्तु इसने लिए सरकारी विभागों में परिवर्तन करना पड़ेगा। इससे अन्तर्गत हरय सेबो संस्थाओं, साक्षर, रोटीरी क्लब इत्यादि सर्वोदय मण्डलों रखन स्वरूप संस्थाओं वार्ता समितियों, ग्राम-उद्योग शाखाओं द्वारा शासन की पहल से तथा सार्वजनिक संस्थाओं की पहल से सम्मिलित रूप से योग्यता की पहल से पूर्व बुनियादी कक्षाएं खोली जा सकती हैं। शासन, की ओर से कारखानों मिलों आदि पर मद प्रतिभाएं लगाया जाय कि ये संस्थाएं अपने सम्बन्धियों व बच्चों के लिए पूर्व बुनियादी कक्षाएं चलाएं। ऐसी कक्षाएं खोली क समीप हों और प्रभावशाली नम संचालित मेलकूद का भी मायान रखें। शिक्षा कक्षाओं के अन्वेषण रूप में लिए गीय के प्रतिभाएं वेलात्मक मध्यपर एवं अध्यापिकाओं की नियुक्ति करना उपयोजी होगा।

प्रत्येक शिक्षाशास्त्रों में ५०-६० तक विद्यार्थी होने चाहिए, जिन्हें कक्षाएं खुली हुई आकार में बड़ी, साफ सुथरी हवादार और रोशनीदार होनी चाहिए। शिक्षाशास्त्र का मायामा छत्रा का रोम कद वा पैदान हो, बड़ी

जल सेमझूझ ला। सामान हो। यह संदान देइ, फूल पोथी
से सुशोभित होना चाहिए। गर्मियों में शालग्राम जानवर, पाथी
बादि का सामोप्य शिवाजी के लिए किया जाता चाहिए।
इन्के द्वारा बच्चों में स्नेह, दया, देइ-पौथी की देख-रेख
की कोमल भावनाएँ, मृदु और मिठी, हम सबका
चरण पोषण करती हैं बादि भावनाएँ पैदा की जा सकती हैं।

बस सामानों का वातावरण भाव-रसायक, प्रफुल्लित
करने वाला साफ सफा एवं स्वास्थ्य होना चाहिए।
विद्यार्थी की यह प्रवृत्ति से शायद, मिठी पाने से स्वर्ण तथा
पुन-पौथी को सुन-से सुन, रस, रस बादि पाथी इन्द्रियों
के द्वारा साफ समझ एवं ज्ञान प्राप्त कर सकता है।
बच्चों में संवेदनशीलता और कोमलता की भावना बचाने
के ये ज्ञान प्राकृतिक साधन हैं। इन्हीं के द्वारा बच्चों
में भावना, देइ-पौथी तथा मनुष्य मान के प्रति स्नेह और
रस की भावना बवाई जा सकती है। प्राविमान, वाचक,
रसज्ञ, ओषधज्ञ, पशु-पक्षी सभी ईश्वर की मूर्ति
हैं। सभी में विभिन्न स्तर की देइता है। इन भाव-
नाओं का निर्माण शिक्षा कर सकता है। इसी परिवेश
में लोकता, लोकता, सामाज्य, पुराण उपनिषद् की
कथाएँ साफ सफाई में बतलाई, सिखाई जानी चाहिए।
पृथ्वी की सब चीजें महापुरुषों की जीवनी मति उत्पन्न
करती हैं बचकर बच्चों में सब चीजों के प्रति आदर और
आदर भावना बवाई जा सकती है। जानाओं से धार्मिक
प्राज्ञावाचक पैदा करना आवश्यक है। अतः सब चीजों की
भाषा, पत्र बादि से ही कथानों का कार्य आरम्भ
किया जाना चाहिए। धर्म, मित्रता, लातिपाति, ऊँच-
नीच भावना आदि को सुखपूर्व से समझाना, उनमें उत्तम
मुक्तिपैदा करना भी आवश्यक है। अभ्यास की इसे
सुखसाधक करना चाहिए।

शिव सामानों का वातावरण शिक्षा और शिक्षा-
र्थों के बीच परस्पर प्रेम आदर एवं अन्तर की भावना
ला होनी चाहिए। शिव सामानों में भय अतिशय विराट्, हिंसा
जैसा, ऊँच-नीच की भावना कदापि पनपनी नहीं
चाहिए। समानता। अतिशय, स्नेहमय वातावरण होना
आवश्यक है। शिक्षा की यह महत्त्वपूर्ण दायित्व हो
जाता है। शिक्षा की भावनाओं में सुख संवेदनशील
भावना शिव सामानों का मर्म है।

पाठ्य विषय—

स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा—सभी शिव सामानों

में शिव के पाठी की तथा शीतलपत्ती की व्यवस्था आव-
श्यक है। बच्चों को इनका ठीक ठीक उपयोग करने की
आदत बनानी चाहिए। स्वच्छता का इनका ध्यान
अच्छा करना, स्वास्थ्य की दृष्टि से स्वच्छ जल और
शीतलपत्ती की आवश्यकता तथा उसका सही उपयोग उन्हें
समझाने में अभ्यास चाहिए। उनमें व्यक्तिगत सफाई
हाथ, नाक, कान, मुँह, जल, नाला बादि साफ करना
शिक्षाया जाय और नियम इनकी सफाई द्वारा उन्हें
अभ्यास कराया जाय। शीतलपत्ती, गुलाबपत्ती, कला जल
का संदान बादि शारीरिक स्थानों को स्वच्छ रखने का
अभ्यास भी उन्हें कराया जाय। इसकी उपयोगिता की
उन्हें बताया जाय। सफाई का शिव के जीवन पर स्थायी
प्रभाव होता है। बच्चे ही वास्तव में अन्तर मूर्ति भी
हो पाते हैं।

अतः यह कहना आवश्यक होता कि बच्चों में स्वास्थ्य-
प्रद आदतें बनाना शिव शिक्षा का आवश्यक अंग है।
समस्त रहे कि केवल कक्षाविधि बतलाकर या सिखाकर
ये इन सभी बातों की कहना पर्याप्त नहीं है। इन सबको
व्यावहारिक रूप से शिक्षकों द्वारा किया जाना चाहिए,
और शिक्षार्थी से कराया जाना चाहिए। सभी बच्चों
पर इन आदतों की छाव पड़ेगी। उदाहरणस्वरूप यदि
शिक्षक, बच्चों की खुली हवा और सफाई के बारे में
बतलाता है, परन्तु कक्षा की सब जिदकियाँ बन्द हैं और
साफ हवा कक्षा के बाहर जा ही नहीं सकती है, कक्षाओं
में बच्चों के आने लगे हुए हैं, कमरे में, बिजली के तार,
साथ सबी पर धूल गरी हुई है, ऐसी दशा में केवल मान
कहने का कोई असर नहीं पड़ेगा। व्यावहारिक रूप
से बिजली प्रतिविद्य बच्चों द्वारा प्रशिक्षणी चाहिए।
बच्चों और शिक्षक द्वारा सफाई करानी चाहिए। सभी
शिक्षक के कहने का असर होता और बच्चों में सफाई की
आदत पैदा होगी। इसके साथ ही बच्चों के हाथ पाँवों में
सफाई कराया, पंखों में सफाई करवाना बादि, कार्यक्रम
भी सामानों के रचनात्मक कार्यों का अंग बनाया जा
सकता है, ये ही उपयोगी रचनात्मक कार्य हैं। इन्हीं
के द्वारा बच्चों की क्षमताएँ नए उपयोग किया जा
सकता है। शरीर में स्वस्थ से तथा स्वास्थ्य के साधन
में व्यावहारिक ज्ञान देकर बालक की क्षमताएँ का
उपयोग किया जा सकता है। शरीर तथा

समय समय मौसमों से संतों में से जाकर बनाओं, फलों, फूलों के रंग, उनके नाम आदि का ज्ञान कराकर उनमें कोमल मोहनाएँ बघाना, मिट्टी, पानी, गोबर आदि का अनुभव कर इनकी समीपता भी जितना का आवश्यक बस होना चाहिए। जानवरों, कीड़ों, बाघ, भैंस, बकरी, घोड़ा, चित्ती, कुत्ता आदि जिनसे भी ज़रूरत पड़ेगी उनसे भी समीपता बघाना आदि से जानना का ज्ञान करवाना, समय कोमल मोहनाएँ बघाना उनमें सुवेदन भीमता देना करना एवं कुशल शिक्षक का काम है। इसी प्रकार प्रकृति के परिवर्तन हेतु जलचर, पक्षचर एवं जलचर के बिना तथा जिनसे भी रस आ सकते हैं। पशुओं के होने मायना, शास्त्र, स्वर्ण, रूप, रस, गंध का विकास के उपरोक्त मुख्य साधन हैं। इसका माध्यम भाषा शब्द और कार्य ही है। इन प्रकार इन अनुभवों से बुद्धि और ज्ञान का विकास किया जाना चाहिए। भाषा बोधने का शब्द और वर्णिक साधन यही है। विकास सहज रूप से होता जाना चाहिए। इसमें भय, प्रशंसा या डराना का पुट न हो। पशु जालानों की लाली निहाला भाषा भाषा में ही दी जाना।

॥ शिक्षाविद ऐसा मानते हैं कि ६ वर्षों तक नहीं की जाय के बाद ही बच्चों को हिसाब और गणना सिखाना चाहिए। किन्तु अधिप्रायक किन्तु की प्रवृत्ति का मायस्थ पढ़ना सिखना ही मानते हैं। इसविषय ६ वर्ष के बाद पढ़ना सिखना शुरू करने से अधिप्रायक अधीर हो जायेंगे। किन्तु इसका सत्य है कि केवल विषय ज्ञान पर बल देने की अपेक्षा, समग्र जीवन के लिए शिक्षा देना अधिक उपयोगी होगा, इस पर ध्यान देना चाहिए। अतः भगवान् ज्ञान के क्षण महापुरुषों की बीजनी कविता पाठ पढ़ाएँ, सरल गणित, सामान्य ज्ञान, स्वास्थ्य रक्षा आदि का ज्ञान और अनुभव योग्य एवं व्यावहारिक रूप से कराया जाना चाहिए। किन्तु इन सब के लिए पहले बच्चों की आत्मिक तैयारी कर लेना आवश्यक है। पूर्ण बुनियादी शिक्षा कक्षा की कुछ विशेष बातें शिक्षक को ध्यान में रखने योग्य हैं जो इस प्रकार हैं—बालक के विद्यालय में भय और बल का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इससे उनकी सरल, शैल और भी सहज प्रवृत्ति न कुटिल हो जाती है। इस

पद्धति में शिक्षा, खेल, पढ़ाई निषाई रचनात्मक कार्य, स्वास्थ्य कार्य आदि सभी कार्य समग्र समय विषय के होकर एक समीपित रूप से बालक की विद्यालयता को बल देने की प्रक्रिया माना है। सभी विद्यालय कार्य समीपित करते हैं। उनके माध्यम से बालक खेल को अनुभूति प्राप्त करते हुए आनंद प्राप्त करें। इस प्रकार विद्यालय शुष्क या आरक्षक माध्यम नहीं होगा। खेल-क्रीडा की प्रक्रिया से बालक सब कुछ मनाने में ही रीति लेगा।

रचनात्मक कार्य — रचनात्मक कार्य पूर्ण बुनियादी शिक्षा का आधार है। अतः रचनात्मक कार्य करने की प्रवृत्ति पर बल देना चाहिए और इस कार्य के प्रति बच्चों के हृदय में आदर और स्नेह की प्रवृत्ति बगानी चाहिए। उद्देश्य यही होना चाहिए कि बच्चों का रचनात्मक कोमल भाव हो। इसके साथ ही हमें यह भी कि रचनात्मक कार्य उत्साह हो और समीपितभी हो ही और समग्र समय के वातावरण के अनुकूल हो। ऐसा बालक है कि रचनात्मक कार्य कई क्षणों में शुरू किए गए हैं। परन्तु इनके पीछे जो बुद्धि होनी चाहिए उसका समीपित ज्ञान है। कई प्रकार के रचनात्मक कार्य जैसे मायक कला, धातु कला आदि कार्य क्षणों में दिये जाते हैं परन्तु के समीपित उपरोक्त ही होते हैं। ये समय बिताने या टाइम टेबुल के अब माना गए हैं या ये यात्रिक रूप से किए जाते हैं या इनका उपयोग मनोरंजन मात्र के लिए किया जाता है। यहाँ पर यह कहना सचित होना कि अब रचनात्मक कार्य पर बल दिया जाता है तब उत्साह कदापि महसूस नहीं है कि पुस्तकीय ज्ञान या बोद्धिक ज्ञान या उसके विकास का अनुभव किन्तु बाधना। पुस्तकीय ज्ञान रचनात्मक विकास एवं आत्मिक विकास सभी विद्या के महत्वपूर्ण अंग हैं और समीपित बुद्धिकोश से इसका प्रयोग किया जाना चाहिए और सामान्य के परिवर्तन में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है इसको निम्नतम नहीं करना चाहिए।

शारीरक समीपित में बच्चों के स्तर पर सुन्दर, लक्ष्य करने और बल किन्तुओं द्वारा ज्ञान का अनुभव प्राप्त करते हैं। पशुओं इन्द्रियों द्वारा अनुभव आत्मिक, भावनात्मक, शारीरिक ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त करता है, इनके

हवन से ही उसे अनुभव की प्राप्ति होती है। ग्रामीण समाज में बच्चे पेड़, पोपे, सन्दी, फलफूल के बगीचे आदि देखकर उनके विदास को देखकर अनुभव पाते हैं। पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े जानवर आदि की हलचल, उनका स्वभाव आदि देखते सुनते हैं और इससे उनके अनुभव विकास एवं ज्ञान की सामग्री बनती है। बच्चे गावों में खेती बर्द घीरी, लोहारगोरी, मकड़ी का काम, मिटटी के बर्तन ईट बनाया आदि काम देखते हैं और उनके विषय में सुनते हैं तथा ध्यावहारिक ज्ञान पाते हैं। अंतर्गत उत्तर कहा जा चुका है बच्चों में प्रेम भाव जोमल साधना, क्रूरता न करना, माय, मैल बकरी, पोडा, कुत्ते, बिस्ती आदि जानवरों के प्रति स्नेह भाव बढ़ाना, विधियों बुराई आदि के प्रति प्रेमभाव बढ़ाना इन सब की सेवा करना, पालन पोषण करना, उनकी उपयोगिता को समझना, खेलों में फूल पत्तों सरसों की पौली कासिया, नीले पीले सफेद फूल, हरियारी आदि की पोसा बेसकर प्रकृति के लीज का अनुभव करना, घुड़न बन्द, सारों की देखकर लीजर्म बोध करना आदि ज्ञान ध्यावहारिक रूप से बच्चों को दिया जाना चाहिए। बहुत सम्भावक इसे सूझ बूझ के साथ कर सकता है। परन्तु इसके लिए सम्भावक को विविष्ट प्रतिधुलि दिना जाना चाहिए। सम्भावक के अतिरिक्त घर में यह स्पष्ट छाप हो कि शिक्षा केवल माय पुस्तकीय ज्ञान नहीं है, परन्तु व्यवहारिकता और क्रियाशीलता के माध्यम से बच्चों की मानसिक पृष्ठभूमि को अनुकूल शिक्षा दी जाय और बच्चों का ज्ञान वला, मात्र पला और क्रिया पला सभी की बगाने की क्रिया ही सम्पूर्ण शिक्षा है। परन्तु इस प्रकार के अनुभवों की सम्भावना सहज में कम होती है। इनकी पुष्टि और प्राप्ति सहज में बच्चों को करना आवश्यक प्रतीत होता है। इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि अच्छी शिक्षा का यह सहजगुण साधन है। नहीं तो पाहरी शिक्षा मात्र पुस्तकीय होनी और व्यावहारिकता तथा समाज से दूर होकर रह जायगी।

रचनात्मक कार्यों में बर्तन घोलना, आडू लपाना सफाई करना, लसरी घोल, कापन आदि ने टुकड़े को टुकड़े की टोरी में मालना, बुझा साक करना, कापवानी, मदी लालीय / १५

बगीच की सफाई करना आदि कार्यों के संस्कार देना आवश्यक है। शिक्षक को इन कार्यों के महत्व एवं आवश्यकता को बच्चों को बतलाते हुए इन रचनात्मक कार्यों को कराना चाहिए। शिक्षा में धर्म के महत्व को बढ़ावे से जातिभेद की भावना भी दूर होगी और आरोग्य लाभ भी होगा। इससे बच्चों की बुद्धि का विकास होगा और उनमें स्वच्छता, व्यवस्थितता की भावें पैदा होगी। इसी परिच्छेद में शिक्षक का कार्यों द्वारा बच्चों में कुछ चारित्रिक गुणों का भी आरोपण कर सकता है। निम्नो का पालन साक्षात्पालन, उत्तरदायित्व की भावना बगाना, ठीक समय से काम करना, समय मद्ध न करना परस्पर सहयोग एवं सहायता की भावना बगाना आदि नैतिक गुणों का भी आरोपण शिक्षक की सूझ बूझ से करना सम्भव है। इसी प्रकार मोला विरोधा, सुई में धाया रानना, सक्को काटना, म्साको और पीसी का धर्षा करण करना, कापन के आकर ने टुकड़े कैंची द्वारा काटना, कापन धिपकाना और चिपकारी, र्यों का उपयोग, गालू मिटटी से खेल तथा लठ्ठे आकार बनाना आदि कार्यों में रचनात्मक कार्यों हैं। शिक्षार्थी में समारोपणीय एवं नैतिक गुणों का सज्जन करना शिक्षक का कार्य है। शिक्षक के लिए यह चिन्तन का विषय है एवं व्यावहारिक चुनौती है। उपरोक्त सभी बातों का व्यावहारिक ज्ञान शिक्षक के प्रतिष्ठान का जय बगाना जाना चाहिए।

सामूहिक कार्य—सिधु बलाओं में कुछ कार्य व्यक्तिगत रूप से और कुछ कार्य सामूहिक रूप से किए जाते हैं। सामूहिक कार्य का प्रभाव बच्चों के जीवन पर अच्छा पड़ता है। उनमें सामूहिक कार्य से सहयोग सेवामात्र कापन कार्य करने की आदत पैदा होती है। इसलिये वे सब कार्य जिनका लक्ष्य बहने भी क्रिया गया है उनसे सामूहिक रूपसे बचाया जाना चाहिए। जैसे बजिनद, कबिता पाठ, नृत्य संगीत, खेलगीत, लोक नृत्य, बजिन, हस्तकला, मिटटी का काम, खेलकूद, व्यायाम आदि की सामूहिक कार्यों में करते हैं। सिधु बलाओं में वे कार्य सामूहिक रूप से किए जाते हैं परन्तु यहां पर केवल यही बहना उचित है कि इन कार्यों द्वारा भी

यन्त्रों की नैतिक शिक्षा होनी चाहिए और उनमें शारीरिक गुणों का संवर्धन होना चाहिए। सामूहिक कार्यों द्वारा शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चों में एक साथ मिलकर काम करने की आदत बालें, सेन-सेन, छात्रोप, सेवा, अनुशासन सिखाए, छात्रोपगती न करने, पोशाक धोने करने आदि की आदतें बालें। पवित्र नागरिक धर्म पनपाने के बहुमूल्य साधन सामूहिक कार्य एवं खेलरूप के संदान ही होते हैं। शिक्षक को बहुत ही धृक्-बुद्ध के साथ इन नागरिक आवश्यकताओं को जगाना है। शिक्षक के प्रशिक्षण में इन मूल्यों को क्रियाशील बनाने के उपरोक्त साधन सम्मिलित बिन्दे जायें चाहिए।

गहरी साधुर्भूत बुद्धिवादी कलाओं के कार्य का समग्र दार्ष्टिक्य ही पद्य का होना चाहिए जिससे वास्तव एवं विषय का समग्र भी सम्मिलित है। कालों में पद्य के अनुसार मूल, नवका, पद्य, मठर आदि तथा मनन, भाव आदि को एकत्र कर कालों के लक्ष्य को व्यवस्था की जा सकती है। इन दोनों कालों को नियमित रूप से किया जाय। इन शास्त्रों की ये आवश्यक प्रकृति है। इसी प्रकार साहित्यिक कालों में कालों को कदाभी कालों में भी पद्य आवश्यक है। अन्तर्गत यह अधिकृत गद्य-भीय इन से कहानियाँ कही जाती चाहिए। कहानियाँ इनके आकर्षक रूप से कही जाय कि कालों में ही होकर उन्हें सुनें। कहानी कहना, विधान करना, व्यवहार करना, गद्य करना, गद्य वातावरण बनाना, या केवल में ही प्रकृति है। विधान कालों के आवश्यक रूप है। उनके द्वारा विधानों के लक्ष्य, मन एवं लक्ष्य को द्वारा-द्वारा विधान विधान है, उनके अन्तर्गत और गहरी गद्य वातावरण प्रदान होता है। आकर्षक एवं आकर्षक स्वाभाव की दृष्टि से ये आवश्यक है। अनेक प्रकार की अनोखी-अनोखी कहानियाँ, दूसरे देशों के शासकों की कहानियाँ, साहित्यिक कालों-कालों की कहानियाँ आदि विविध प्रकार की कहानियाँ कालों चाहिए। इन कहानियों द्वारा कालों के लक्ष्य की दृष्टि होती है, उन्हें और उनके लक्ष्य को विधान विधान है, कालों का अनोखी होता है, उनकी कल्पना आदि को बढ़ावा विधान है। इसके साथ ही उन्हें छोड़ने, भक्ति, पद्य, गद्य, गद्य आदि कालों का दोष कहानियों द्वारा किया जा सकता है।

शिक्षक — यह सत्य है कि उपर्युक्त बहुत से क्रिया-कलाप छात्राओं में किए जाते हैं। कुछ आलोचक, कहे कि इन विचारों में कोई नवीनता नहीं है यह भी सत्य है। खेलकूद, रचनात्मक कार्य, व्यायाम, पाठ्य विषय सभी कार्य न्यूनाधिक सभी ऐसे छात्राओं में किए जा रहे हैं। परन्तु छात्राओं की प्रगति ततोद्यत्तक नहीं मान्य होती है। उनमें बहुत कुछ कमी का अनुभव होता है। यही बात यह है कि हमारी सारी छात्राएं इन छात्रों को अलग-अलग विषय के रूप में देखती समझती हैं। वे सोच यह दृष्टिकोण अपना नहीं पाए हैं कि शिक्षण एक समग्र वा समन्वित कला है। शिक्षण एक समन्वित कार्यक्रम है, इसका भी उन्हें बात नहीं है। खेल द्वारा ही शिक्षण के विविध कार्यक्रमों को प्राप्त प्रदर्शन करना होना, यही शिक्षण की सबसे बड़ी कला है। अतः सम्पूर्ण शिक्षण क्रिया एक समन्वित, समायोजित प्रक्रिया है, इसका माध्यम शिक्षक को सतत होना चाहिए और यही दृष्टिकोण उच्चरी प्रेरणा का प्रीत होना चाहिए और माना प्रकार के नए विचारों उपायों को सोचना और प्रयोग करते रहना चाहिए। इससे शिक्षक के जीवन में ताजगी आएगी और जिसका कार्य के प्रति इसका उत्साह बना रहेगा। बहुत कुछ धर्म के बाद शिक्षण, शिक्षण की अन्त पारणाओं या भूमि उद्देश्यों की मूल आत्मा है और यद्यपि सारे विषय कार्य करने लगता है। इससे शिक्षक के जीवन में चलाता और उत्साह विहीनता आने लगती है। शिक्षक की सक्रिय होत हुए भी अपने व्यक्तित्व एवं प्रचलन को प्रत्यक्ष रूप से बाह्यक मानिकामों पर भावना नहीं चाहिए। शिक्षक को शिक्षार्थी का मार्ग निर्देश करना चाहिए, उनके खेल की प्रवृत्ति एवं उत्साह को समायोज्ययोगी बनाना चाहिए। उनमें अच्छे पाठ्यक्रमों के गुणों का उपयोग करने का प्रयत्न करना चाहिए। शिक्षकों में मनुष्यवृत्ति स्पष्ट निर्देशन हृत्पुत्र रहन यदि गुणों का होना आवश्यक है। वस्तुतः पूर्व इतिहासी कलाओं के शिक्षण कार्य के लिए अपेक्षाकृत महिला शिक्षिकाओं का होना सामान्य होता है, क्योंकि शिक्षक में माता का धार, माता की ही सहनशीलता, दया, धर्मा, त्याग, समय, निःस्वार्थ सेवा आदि गुण आवश्यक हैं। महिलाओं में यह गुण अधिक माना

गोबध पर प्रतिबन्ध

के० अरुणाचलम्

देश में समी समय से यह गाय चली आ रही थी कि सविधान के राज्य निर्देशक तत्व के अनुसार गोवध पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए। इसके लिए १९७६ में विनोबाजी ने साधारण अनशन का भी अपना विचार घोषित किया था। किन्तु तत्कालीन सरकार के शास्य-तान पर उन्होंने इसको एक वर्ष के लिए स्थगित कर दिया था। इसके परिणामस्वरूप पश्चिम बंगाल और केरल को छोड़कर देश के सभी राज्यों ने कानून पास करके गाय के दूध पर प्रतिबन्ध लगा दिया। इसी बीच संसदीय तथा जन, रा. राज्यों की सरकारों ने परिवर्तन माना और सभी प्रतीक्षा के बाद विनोबाजी को फिर प्रोत्साहित करने पर ही कि वह इन दो राज्यों में भी प्रति-बन्ध नहीं लागू जात है तो वे १ जनवरी १९७६ के धार-रण अनशन प्रारम्भ करेंगे। इस पर काम स्वराज्य के कार्यकर्ताओं के समेजन में उनके यह अनुरोध किया कि उन दोनों सरकारों को कानून बनाने के लिए राखी करने के लिए वे उनके कुछ और समय हैं, और विनोबाजी ने ११ दिन का और समय दिया। इस बीच कार्यकर्ताओं ने इन दो राज्यों में भीषण की, किन्तु समकें कुछ परि-णाम न निकले।

अतः विनोबाजी को २२ मार्च के अपना अनशन प्रारम्भ करना पड़ा। उनकी उम्र, स्वास्थ्य और बीमारी के कारण इससे देश में बहुतों को बड़ी चिन्ता हुई और राज्यों में बसन्तता मिलने पर दिल्ली में इसके प्रभाव किए जाने लगे कि सत्ताधारी दल को विनोबाजी के साथ बचाने हेतु उनकी यात्रा की रूढ़ि के लिए कुछ करना चाहिए। प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई को भी तथा कि देश को विनोबाजी को छोड़ा नहीं चाहिए और इसके परिणाम स्वरूप, अपनी व्यक्ति के स्वास्थ्य, व होने यह साहसपूर्ण निर्णय लिया कि सविधान में उचित संशोधन किया जाय। इसके घोषणा सत्र में २६ मार्च

को २ बजे अथवाज्ञ की गयी। उसने बड़ा कार इसी सत्र में सविधान संशोधन हुए भी बादा धर्माधिकारों और भी दिल्ली में कई सत्रों, दल नेताओं से। पुरी परिस्थिति से अवगत कराई तबको ए लिए राखी कर लिया या कि विनोबाजी को लिए कोई निर्णय तत्काल लिया जाना गाय को भी रखा होना।

सत्र के प्रधानमन्त्री द्वारा दिये गये भी दावा, धर्माधिकारी, भी राक्षस भी बार० के० वरिष्ठ के अनुमोदन पर अपना अनशन समाप्त कर दिया। इसके बाद सत्याग्रियों को बड़ी राहत हुई। किन्तु राष्ट्र के समर्थकों का उत्तरदायित्व भी, वह पड़ा। कानून बनाकर अपना धर्म पुरा कर दी, भी आगे बढ़कर अपना, कर्तव्य पूरा करता होना कर्मचारी, पुरुषों की, देशवास जवला को बराली बड़े होने पर उनकी रक्षा का भार बराला। कुछ वर्षों की मायेवा, यह कहा, बाता है गया सूख जाने, पर गाय, भी, भी, भीन धर्म और और प्रति बाम २ रुपये का प्रतिनिधि अब इसकी व्यवस्था करना समाज का धर्म है उसका उध समय काम उठाया जबकि यह और खेती करने तथा भार बोने के निवे सरकार के लिए बड़ी गायों की बेबमान एक ताली समरवा होनी, किन्तु यदि स्थानीय समुदाय इस ठा ठोते हैं, तो यह भार बट जाता है। किन्तु यह स्थानीय स्तर पर संगठन का है। मोरारजी प्रधानमंत्री बनने के लिए कार्यकर्ताओं को पर इस काम को सपष्ट के प्रभाव शक्ति सजानी होनी।

गोबध पर प्रतिबन्ध

के० अरुणाचलम्

१११११

देश में लम्बे समय से यह माँग चली रही थी कि सविधान के राज्य निर्देशक तत्व के अनुसार गोबध पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए। इसके लिए १९७६ में विमोचनी ने मांगरण अवधन का भी अपना विचार प्रोत्साहित किया था। किन्तु तत्कालीन सरकार के आस्था-वन पर उन्होंने उसको एक वर्ष के लिए स्थगित कर दिया था। इसके परिणामस्वरूप पश्चिम बंगाल और कोरस की, छोड़कर देश के सभी राज्यों ने कानून पास करके राज्य के बम पर प्रतिबन्ध लगा दिया। इसी बीच केंद्रीय तथा उन ही राज्यों की सरकारों ने परिवर्तन मांग और लम्बे प्रतीक्षा के बाद विमोचनी को फिर मोदरा करनी पड़ी कि यदि इन दो राज्यों में भी प्रति-बन्ध नहीं लग जाता है तो वे १ जनवरी १९७९ से आभ-रण धनवान, प्रारम्भ करेंगे। इस पर काम स्वराज्य के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन ने उनसे यह अनुरोध किया कि उन दोनों सरकारों की कानून बनाने के लिए चेकी करी के लिए वे उनकी कुछ और समय दें, और विमोचनी ने ११ दिन का और समय दिया। इस बीच कार्यकर्ताओं ने इन दो राज्यों में कोरिया की, किन्तु उन्हें कुछ परि-णाम न मिले।

यह विमोचनी को २३ मार्च से अपना अवधन प्रारम्भ करना पड़ा। उनकी उम्ह, स्वास्थ्य और बीमारी के कारण इसी देश में बहुतों को बड़ी चिन्ता हुई और राज्यों में अवधनता निम्न पर दिल्ली में इसके प्रयास किए जाने लगे कि सत्ताधारी बल की विमोचनी के साथ बचाने हेतु उनकी मांग को रूति के लिए करना चाहिए। प्रयास सभी की मोरारजी देसाई को भी लगा कि देश की विमोचनी को छोड़ना नहीं चाहिए और इसके परिणाम स्वरूप, अपनी अनिच्छा के बावजूद, उन्होंने यह साहसपूर्ण निर्णय लिया कि सविधान में उचित संशोधन दिया जाय। इसकी घोषणा सचद में २६ मार्च

को २ बजे अपराह्न की गयी। उससे कहा गया कि सर-कार इसी क्षण में सविधान संशोधन बिल लायेगी। इसके पूर्व श्री दादा धर्माधिकारी और श्री राधाकृष्ण बजाज दिल्ली में कई साधनों, दस नेताओं से मिले जुले थे और पूरी परिस्थिति से अवगत कराके उनकी इस बात के लिए राजी कर लिया था कि विमोचनी को बचाने के लिए कोई निश्चय सरकार लिया जाना चाहिए और इसके साथ ही रक्षा होगी।

सचद में प्रयासशील द्वारा दिये गये आश्वासन तथा श्री दादा धर्माधिकारी, श्री राधाकृष्ण बजाज और श्री भार० के० पांडेय के अनुमोदन पर विमोचनी ने अपना अनघन प्रारम्भ कर दिया। इससे उनके हजारों अनुयायियों को बड़ी राहत हुई। किन्तु साथ ही गोरक्ष के समर्थकों का उत्तरदायित्व भी बढ़ गया है। सरकार कानून बनाकर अपना धर्म पूरा कर ले, किन्तु जनता भी भी अपने बचकर अपना कर्त्तव्य पूरा करना होगा। बड़े और कमबोरा, पल्लुओं की, देवमान, जनता की करवी है और बड़े होने पर उनकी उत्साह का मार जनपर है। इस पर कुछ वर्षों की धारणा है, यह कहा जाता है कि सत्ताधारण तथा सुल जाने पर साथ ही हीन वर्ग और कीर्ती है। और प्रति साथ २ वर्षों का प्रतिदिन व्यय माता है। इसकी व्यवस्था करना समान धर्म है क्योंकि उसने उसका उस समय साथ उठाया जबकि वह दूध देती थी और खेती करने तथा भार होने के लिये बैल बेती थी। सरकार के लिए बड़ी पायों की देखभाल एक बड़ी वित्तीय समस्या होगी, किन्तु यदि स्वामीय समुदाय इस काम को उठा लेते हैं, तो यह भार बट जाता है। किन्तु यह प्रश्न संसदीय स्तर पर संघटन का है। गोरक्ष कानून को प्रभावी बनाने के लिए कार्यकर्ताओं की स्थानीय स्तर पर इस काम को सक्रिय करने में अपना समय और शक्ति समानी होगी।

नयी तालीम से सम्बन्धित प्रपत्र ४ का विवरण

१- प्रकाशन का स्थान :	मेवापुरी, बाराणसी, उत्तर प्रदेश
२- प्रकाशन अवधि :	द्विमासिक
३- मूद्रक का नाम :	श्री पन्नेलाल मिश्र
राष्ट्रीयता :	भारतीय
पता :	बिदाई मृदण स्थली, पदेनी, बाराणसी
४- प्रकाशक :	श्री लक्ष्मण कुमार कर्ण
राष्ट्रीयता :	भारतीय
पता :	लखनऊ, उत्तर प्रदेश नयी तालीम समिति मेवापुरी बाराणसी
५- सम्पादक :	सर्वे श्री से० मधुसूदनम्, डारिका सिंह, कजुसाई पटेल काशीनाथ त्रिवेदी ज्योतिबाई देसाई, देवेन्द्र लाल तिवारी पम्पुसदास
राष्ट्रीयता :	भारतीय
पता :	उत्तर प्रदेश नयी तालीम समिति मेवापुरी (बाराणसी)
६- पत्रिका के मालिक का नाम व पता :	संजिव भारद्वाज नयी तालीम समिति, मेवापान, बघा, बहामपुर

मैं मधुसूदन कर्ण यह घोषित करता हूँ कि मेरी जानकारी और विवेक से अनुसार उपर्युक्त विवरण सही है।

उ० अक्षयकुमार कर्ण
प्रकाशक

अक्षय कुमार

नयी तालीम पत्रिका का कार्यालय मेवापान से मेवापुरी स्थानान्तरित हुआ। इस कारण प्रत्यक्ष बिगत दो अकों में पत्रिका का नाम और अकों का प्रथम अक्षर उपा है। सुधी पाठक हमारे इस मूल के लिए क्षमा करें और बिगत अकों में दिमागत संशोधन करने पढ़ें:-

मंगलकामना

कोई कृति खो नहीं सकती
और न कोई मंगल व्यर्थ जायगा,
मले ही आशायें छोन ही जायें
और शक्तियाँ लबाब दे दें
हे बीरात्मन ! तुम्हारे उत्तराधिकारी अवश्य जनमेंगे
और कोई सत्कर्म निष्फल न होगा ।
यद्यपि मले और ज्ञानवान कम मिलेंगे
किन्तु जीवन को बागदोर उन्हीं के हाथों होंगी ।
पह भीड़ सही बातें देर से समझती है,
तो मो चिन्ता न करी, मार्ग दर्शन करते जाओ ।
तुम्हारा साथ वे देंगे जो दूरदर्शी हैं,
तुम्हारे साथ शक्तियों का स्वामी है ।
भागीरथों की वर्षा हीमी तुम पर
ओ महात्मन् तुम्हारा सर्वमंगलमय हो ।

—स्वाप्नी खिलेकाभक

नयी तालीम



सम्मेलन विशेषांक

राष्ट्रीय शिक्षा नीति
 अखिल भारत नयी तालीम सम्मेलन
 शिक्षा की राष्ट्रीय नीति का प्रारूप १९७६
 गांधी कुटी का संदेश
 राष्ट्रीय प्रगति शिक्षा : एक प्रयोग



अखिल भारत नयी तालीम समिति

वर्ष २७
 अप्रैल-मई
 अनुसूचक

अंक

५, ६

प्रधान सम्पादक — श्री वे० अरणावतम्

सम्पादक मंडल — श्री द्वारका सिंह

श्री यजुसाई पटेल

श्री बाबू बाबू शिवेदी

श्री ज्योतिबाई पटेल

सम्पादक — डा० देवेन्द्रदास त्रिवारी

सह सम्पादक — श्री चन्द्रभूषण

सम्पादकीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति	पृष्ठ १
भारत मातृभूमि तभी तानीय सम्मेलन का १९७६ का विवरण	३
भारत मातृभूमि तभी तानीय सम्मेलन १९७६ सर्वसम्मति निवेदन	५
सम्मेलन में पारित राष्ट्रीय प्रौढ शिक्षण कार्यक्रम सम्बन्धी प्रस्ताव	७
अन्तर्राष्ट्रीय मादक	श्री वे० अरणावतम् ८
शिक्षा की राष्ट्रीय नीति का प्राकट्य [१९७६]	११
हमें स्कूल की पढ़ी समझना करना है	डा० देवेन्द्रदास त्रिवारी २१
गांधी कुटी का संदेश	२५
राष्ट्रीय प्रौढ शिक्षा एक प्रयोग	डा० रामचन्द्र सिंह २७
वर्तमान समय में शैक्षिक विचार का महत्व	श्री० कमला शिवेदी ३१
सब ज्ञात क्यों से सुबारी शिक्षा	श्रीमती जमा सिन्हा ३३
अनौपचारिक शिक्षा कुछ विचार किन्तु	श्री प्रमानन्द सिंह ३७
शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति का प्राकट्य	डा० भास्कर आदिशेखरे ४१
भारत की राह पर श्री प्रमानन्द जी	श्री देवेन्द्रकुमार ४७

अग्रज — गुलार् ७६

तभी तानीय का आधिकारिक रूप से स्थापित एक शक्ति का रूप है।

तभी तानीय डॉ०-कार्यक्रम पत्रिका है इसका यही अवसर है प्रारम्भ होता है।

यह व्यवहार ने लिए सुधा पाठक रूपमा अपनी छात्रक सख्या अवसर मिले।

तभी तानीय में व्यक्त विचारों का आधिकारिक रूप से स्थापित होता है।

नयी तालीम

सम्पादकीय

शिक्षकों, प्रशिक्षकों एवं समाज शिक्षकों के लिए

राष्ट्रीय शिक्षा नीति

सबसे पहले ध्यान देने के लिये राष्ट्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप प्रस्तुत किया गया। १९६६ में प्रथम बार केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को घोषणा की थी। उस समय शिक्षा का विषय राज्य के अन्तर्गत था, अतः कुछ राज्य सरकारों ने भी शिक्षा नीति विषयक कुछ चिन्तन किया था। यतः कुछ वर्षों में देश में अनेक महत्वपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तन हुए हैं जिससे लोकजीवन के विकास और ज्ञान की कमी सिखी गयी है और शिक्षा का रूढ़ि है। किन्तु यह ध्यान दिलाने की जरूरत पड़ती है कि शिक्षा नीति का प्रमुख समस्याएं क्या हैं जिन पर विचारण और मार्गदर्शन की आवश्यकता है जो बहुत बड़ी कड़ेगा कि विद्यालयों, विश्वविद्यालयों का अभाव और अत्यधिक शिक्षा लागत, शिक्षा का खर्च और स्वायत्तता के सम्बन्ध में होना, अतिशय की, शिक्षा की राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय द्वारा शिक्षा की उपेक्षा, शैक्षिक नीति का अभाव शिक्षा नीति प्रणाली। लोक जीवन में सामान्य जीवन इन समस्याओं का समाधान चाहते हैं। उनके सम्बन्ध में राष्ट्र के वर्गद्वारा से कुछ शिक्षा चाहते हैं। इस दृष्टि से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अभाव एक बड़ा निराशा का कारण बनता है। २२ वर्षों और २३ सरकारों का यह बोधना - यह १९६६ से यह धारणा बनती है कि हममें एक सुचना का अभाव है, अल्प शिक्षा नीति की कमी है, या जो बड़े कि शरीर को है किन्तु मानता नहीं है। प्रारूप में विभिन्न अवस्थाओं के एक साथ छोड़ दिये गये हैं। यों ने हमारे सामने सच शिक्षा का एक रूप प्रस्तुत किया था। यह जीवन और समाज से एक रूप था, स्वायत्तता और स्वायत्तता के रूप में अनुपातित था। प्रमाण यों के बार-बार हम बात पर बात देने पर भी कि बुनियादी शिक्षा ही शिक्षा का सर्वोत्तम स्वरूप है, प्रस्तुत प्रारूप में यों कोई सार्वजनिक उल्लेख नहीं है। पहले पृष्ठ पर

अथवा यों की का नाम, उनके विचारों तथा प्रयोगों का उल्लेख किया गया है किन्तु बुनियादी शिक्षा या नयी तालीम शब्द का प्रयोग यों नहीं किया गया है, जिस बुनियादी शिक्षा को उस महापुरुष ने देश के लिए अपनी सर्वोत्तम देन कहा था।

प्रारूप की अन्तर्गत की शिक्षा अत्यन्त उन्नत हुई, अत्यन्त और लम्बी का नाम ही प्रतीत होती है।

आधुनिक शिक्षा के सर्वोत्तम उदाहरण के रूप में उल्लेख किया गया है। किन्तु उदाहरण के रूप में शिक्षा का अर्थ अर्थ, इसकी अवस्था स्पष्ट नहीं की गयी है। देश-भर स्तर की योजना का उल्लेख किया गया है जो एक विदेशी अवस्था है और यह देश में अत्यधिक शिक्षा-विद संपत्ति विद्वत्ता प्रदर्शित करने के लिए उदाहरण उल्लेख अर्थ में है। जो शिक्षा अपने देश के लोगों के लिए चाहिए है उस शिक्षा में और अपनी स्थिति के अनुसार में अत्यधिक इन लोगों के कुछ कहना सीखा ही नहीं है।

प्रोढ़ शिक्षा के सम्बन्ध में कोई भी बात नहीं कही गयी है क्योंकि जो बातें कही गयी हैं वे सब प्रोढ़ शिक्षा की राष्ट्रीय नीति में १९७७ में घोषित हो चुकी हैं। इसमें पुनः अत्यधिक अवस्थाओं की परीक्षा देने की बात कही गयी है जिसका सरकारी वर्गद्वारा द्वारा अनुपालन नहीं किया जा रहा है और यह स्थिति अत्यन्त की जा रही है कि अत्यधिक अवस्थाओं की अवस्था और शिक्षा अत्यधिक में अत्यधिक अवस्था।

आधुनिक शिक्षा में अत्यधिक अवस्था पर ध्यान दिया गया है और यह अत्यधिक अवस्था बहुत अर्थ में अत्यधिक अवस्था द्वारा अत्यधिक अवस्था है। उच्च शिक्षा के सर्वोत्तम में अत्यधिक ५२ में अत्यधिक अवस्था कही गयी है और यह यह कि सामान्य स्तर के काम करने के लिए अत्यधिक अत्यधिक अवस्था की अवस्था को अत्यधिक नहीं है, उच्च शिक्षा में अत्यधिक अवस्था दिया जाय। यदि ऐसा हो सका और अवस्था की अत्यधिक अवस्था में अत्यधिक अवस्था में अत्यधिक अवस्था, न कि अत्यधिक अवस्था में अत्यधिक अवस्था

पर, तो निश्चित है कि शिक्षा का स्तर भी ऊपर उठेगा और परीक्षाओं में स्थाय प्रत्याहार भी दूर होगा ।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में तीन वर्षों के शिक्षा कोर्स की संस्तुति की गयी है । जो सच्चरिखा के कर्णधारों से, जिन्होंने इस प्राकृतिक रचना में महत्वपूर्ण योगदान किया होगा वह पूछा जाना चाहिए कि क्या के निम्न-विद्यालय, शिक्षा के निम्न उपसहस्र प्रथम को वर्षों का समुचित उपयोग कर रहे हैं । दो से तीन वर्षों की अवधि बढ़ाने का औचित्य क्या है ? क्या अवधि बढ़ा देने से स्तर ऊपर उठेगा ? क्या उन स्नातकों का स्तर ऊपर उठा है जो किसी के लिए तीन वर्षों का समय व्यतीत करते हैं । फिर एक गरीब देश के लिए कड़ा सीट करोड़ों लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, एक वर्ष की अवधि बढ़ाना गरीबी को उच्च शिक्षा से वंचित करता है । कदाचित् सचरिख उच्च शिक्षा के विशेषज्ञ ऐसा चाहते भी हैं कि गरीब उच्च शिक्षा से वंचित रह जाय । देश के लोगों को इस प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक चिन्तना चाहिए और अपनी भाषाएँ एक वर्ष की अवधि वृद्धि के विरोध में उठानी चाहिए । जब दूधरे देश शिक्षा पर बहुत कुछ धन से ऊपर कर अवधि को कम करने के उपाय पर विचार कर रहे हैं, हम तीन वर्षों बढ़ाने के उपाय सोच रहे हैं । आशा है सचरिख समझण जो देश के करोड़ों गरीबों के प्रतिनिधि हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इस बिन्दु पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे ।

शिक्षा के क्षेत्र के बारे में स्पष्ट बात नहीं कही गयी है । जो मोव १० + २ योजना के संकेत, समर्थक और संप्रदाय से उन्होंने बड़ी सफुर्दा से गोसमोल धर्मों में यह अंकित कर दिया है कि स्कूली शिक्षा १२ वर्षों की रहेगी । वास्तव में १० + २ की योजना केवल वर्षों का प्रश्न नहीं था । वह विदेशी प्रयोगों से मुक्त एक योजना थी जिसमें १० वर्षों की स्कूली योजना को आधार माना गया था । किन्तु गरीब देश में कदाचित् ३ वर्षों या ८ वर्षों की भी समग्र स्तर: पूर्ण शिक्षा की बात सोचनी होगी । इसीलिए गांधीजी ने ७ या ८ वर्षों की प्राथमिक शिक्षा का प्रतिपादन किया था और प्रमाण सभी की इस बात पर चल दे

वह वे किन्तु १० + २ योजना से भोग इसका प्रतिबन्ध है कि सीमित क्षेत्रों की बात स्पष्ट रूप से नहीं कही गयी ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्राकृतिक में तकनीकी शिक्षा, कृषि शिक्षा तथा चिन्तनीय शिक्षा की बात भी कही गयी है जो समीचीन है । कारोकिर शिक्षा, शिक्षा का माध्यम धातुभाषा हो, शिक्षाया गुरु आदि विषयों पर वर्षों की गयी है । देश की भाषाओं के विज्ञान पर विशेष धन दिया गया । हिन्दी की सम्पूर्ण भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है ।

परीक्षा सुधार के सम्बन्ध में स्पष्ट बातें कही गयी हैं । बाह्य सूत्रावन पर चल है और आंतरिक मूल्यांकन पर भी । सब से महत्वास्पद बात यह है कि राष्ट्रीय नीति में क्रेडिट सिस्टम की संस्तुति की गयी है । राष्ट्रीय नीति का सचरिख नीति की घोषणा करता है, कि कैसे माध्यम बनाना चाह, कैसे उससे संप्रति किया जाय, ऐसे विषयों में हस्तक्षेप करना है । पुष्ट रूप पर क्रेडिट सिस्टम का अस्पष्ट हमारी चिन्तन परम्परा का अंतर्गत है । व्यवस्था में सचीकरण बिना क्रेडिट सिस्टम के भी माना जा सकता है । यह कदाचित् नीति का प्राकृतिक तैयार करने वालों की बात नहीं है ।

अध्यापकों तथा अध्यापकों के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में कार्मिक आदर्शवाद की और अस्पष्ट बातें कही गयी हैं । शिक्षण प्रशिक्षण की बात जो अवलत समझाई है, उनके समाधान का कोई विश्रस्त नहीं है ।

आर्थिक व्यवस्था में स्थानीय सहयोग की बात कही गयी है । किन्तु सरकार शिक्षा की हर बात का नियंत्रण अपने हाथ में रखेगी जो स्थानीय सहयोग के विमर्शित होगा ? शिक्षा में विन्-प्रीकरण के शिक्षा की पूर्ण उपेक्षा की गयी है ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्राकृतिक निष्पन्न प्रतीत होता है । इसने विभिन्न प्रकारण सुझाव भी नहीं है । कई स्थानों पर भाषा अस्पष्ट और उलभी हुई है । फिर भी यह प्राकृतिक एक महत्वपूर्ण अविलेख है और आदर है देश के चिन्तनशील व्यक्ति, शिक्षा के व्यवसायिक सफल अपनी प्रतिनिधता समय से प्रस्तुत करेंगे और शिक्षा की नयी शिक्षा देने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे ।

लेने ऐसे स्थान के निर्माण में हाथ बटा सकें, जिसमें
स्थानता हो और जिसमें निजी तथा सामाजिक जीवन के
बुनियादी सिद्धांतों के रूप में वास्तव - निर्भरता तथा धर्म-
निष्ठा को स्थान दिया गया हो ।

इसके स्तर पर विषयवस्तु को नया रूप देने तथा
इसकी व्यवस्था को साकार देने के काम के लिये गांधीजी
द्वारा प्रतिपादित यह उद्देश्य स्पष्टतया रहना चाहिए कि
शिक्षा जिसी-न जिसी प्रकार के चारीयिक और उन्नत
कर्म में ली जावे तथा शिक्षार्थी के वातावरण के साथ
कर्म में रूप में सम्मिलित हो । इस नीति के मसविदे की,
विशेष रूप से इसकी प्रस्तावना, उद्देश्य, विषयवस्तु और
प्रवस्था के बारे में अधिक विविधता और अस्पष्टि-
कर्म की संकरता है जिससे उसमें उपयुक्त विचार प्रवि-
र्तित हो सके नदीकि हमारी जनता के एक बड़े भाग
की, जो प्रवर्तित व्यवस्था में बड़े महत्वपूर्ण और बुनियादी
परिवर्तन का हस्तगत रहा है, ऊँची अपेक्षाएँ पूरी नहीं हो
रही हैं । इस दृष्टि से सम्पूर्ण मसविदे के योजना को रचना
तथा सुसंगत करना होगा, जिससे यह अधिक प्रभावी
हो सके ।

विशेषकर है, उसके बारे में उत्पन्न सकारण धुर करने
के लिए निम्न स्पष्टताएँ जरूरी हैं—

१. प्रवर्तित शिक्षा व्यवस्था के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया
शिक्षा के सभी स्तर पर, जिसमें उच्च शिक्षा भी है,
एक साथ प्रारम्भ होगी और काम करेगी ।

२. शिक्षा के सभी स्तर पर पाठ्य पुस्तकें, सामाजिक, सांस्क-
रिक, उच्च शिक्षा की या तकनीकी और व्यवसायिक
शिक्षा की, समाज की दृष्टि से सामान्य उत्पादन
काम और सामुदायिक सेवा पाठ्यपुस्तकें का अधिक
की शिक्षा के बराबर, जो विषय, क्षेत्र, प्रकार, मुख्य
रूप मादि की दृष्टि से मिले हैं, बराबर माना
जायगा । इसकी प्रत्येक विषयवस्तु या साथ में प्रत्येक
बाना शिक्षा समान नहीं माना जायगा । यह भी
आवश्यक है कि इसका साथ पूर्ण रूप से एक प्राकृतिक

विषय क्षेत्र और आवश्यक हो । इसे नि-
निश्चित करना जरूरी होगा कि इस
को कम से-कम जिसना समय दिया जाए
भी स्पष्ट हो जाना चाहिए कि यह स्तर का
की शिक्षा में बढ़ता जायगा ।

३. यद्यपि मसविदे के अन्तर्गत गांधीजी के
है, किन्तु प्राथमिक स्कूल व्यवस्था में
वास्तव में प्रयोग नहीं किया गया है । इसका
सुधार आया और पूरी व्यवस्था को ही समान
नाम दिया जाय । सभी सामाजिक के सामाजिक
की सामाजिक और उच्च शिक्षा पर ही ध्यान
जाय । जब तक सभी सामाजिक सामाजिक
बातों, बुनियादी शिक्षा समस्याओं की प्रस्तावना
अलग बनाए रखना होगा ।

४. वर्षों में प्रारम्भिक शिक्षा के मुद्दे में होने लगे
और इसलिए यह 'टर्मिनल' होगी चाहिए । जिसमें
अनुच्छेद ५२ को लागू करने की दृष्टि से प्रारम्भिक
की चारोंपक्ष बनाने के लिए यह आवश्यक है कि
यह औपचारिक हो या अनौपचारिक यह कानून और
केन्द्र और कम केन्द्रित होगी चाहिए ।

५. चार वर्ष की सामाजिक शिक्षा को इसी मासिक
कर्म है, जिससे यह शिक्षा अधिक सुलभ होगी
है । इस स्तर पर विविधता का रूप, विषयों के रूप
में सम्मिलित होगा, न कि अलग-अलग भागों के रूप
में कि मान्य है । सामाजिक रूप से सामाजिक शिक्षा
को अलग-अलग चारोंपक्ष में विभाजित करना
विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक स्कूलों का एक
विरुद्ध वांछनीय नहीं है । इसका भी सर्वोत्तम
आवश्यक है कि प्रत्येक स्तर पर शिक्षा के रूप में
होगी और उसका प्रत्येक स्तर की शिक्षा के लिए
जान मुद्रा कर देने का नहीं होगा । जहाँ यह वास्तव
कि शिक्षा एक छोटी की भांति है, अल्पकालिक
है और शिक्षाओं तथा विषयों के अनुचित बोझ को
कम करना जरूरी है ।

अखिल भारत नयी तालीम सम्मेलन १९७६

सर्वसम्मत निवेदन

अखिल भारत नयी तालीम समिति की ओर से नयी तालीम कार्यक्रमों तथा इसमें अधिक करने वाले अन्य महा-मुम्बार्थों का एक अखिल भारत नयी तालीम सम्मेलन दिनांक २७, २८, २९ मई १९७६ को बोम्बे महानगर और मुम्बई (नवमन्सा) में आयोजित किया गया जिसका उद्देश्य समस्त के वर्तमान अष्ट तन्त्र में शिक्षा की राष्ट्रीय नीति का, जो मतविषय पैदा किया गया, उनका अभ्यस्त करना था। सम्मेलन में सभी तालीम के शिक्षक, विज्ञान-मन्त्री तथा अन्य महामुम्बार्थों के अलावा योजना आयोग और राष्ट्रीय शिक्षा परिषद समान (एन सी ई आर सी,) के अधिकारियों के भी भाग लिया। सम्मेलन का उद्घाटन प्रधान मन्त्री माननीय श्री मोरार जी देसाई ने किया। अखिल भारत के राज्यपाल, नवमन्सा उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश एच जे केन्द्रीय शिक्षामन्त्री श्री पी वी गे गुरु आदि ने सम्मेलन को संबोधित किया।

सम्मेलन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसविदे की शीर्षी से छानबीन की गयी तथा अन्तिम विचार के पश्चात् निम्न सर्व सम्मत निवेदन स्वीकृत किया गया :-

दिनांक २७, २८, २९ मई १९७६ को औरमुम्बई (नवमन्सा) में आयोजित यह अखिल भारत नयी तालीम सम्मेलन शिक्षा की राष्ट्रीय नीति के मसविदे में सुचित निम्नलिखित आवश्यक मुद्दों के अतिरिक्त देश में प्रचलित शिक्षा पद्धति में पुनर्निर्माण करने के भारत शासन के प्रयासों की वहाद्व करण है :-

- १) समाजोपयोगी उन्नयन कार्य
- २) समान-वैद्य
- ३) नैतिक शिक्षा

४) प्रारम्भिक स्तर को छोड़कर, बड़ी मात्रावा शिक्षा का माध्यम हो, उच्च-शिक्षा समेत सभी स्तर पर प्रत्येक शास्त्र के माध्यम से शिक्षण

५) शिक्षक-अध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका

नयी तालीम के कार्य में समे समान एवम् दिनांक १९७७ में दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आदि सभी के द्वारा इन आवश्यक मुद्दों की निवारण की गयी है। निम्न स्तरों पर स्तरों से भी अधिक समस्त के नयी तालीम 'समिति वर्तमान शिक्षा प्रणाली में गांधी जी के अनुकरा परिवर्तन करने की दृष्टि से तथा नयी तालीम का योग विज्ञानविज्ञानविज्ञान, उच्चस्तरीय शिक्षण समेत सभी स्तर पर लागू करने के लिए वर्तमान शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन आवश्यक प्रयत्न करती रही है। नयी तालीम की शिक्षा में निम्न तत्त्व प्रयोगों में गांधीजी के विचारों में जो वास्तव और समाधान है उन्हें पूर्ण रूप में समाहित किया है।

किन्तु भी, क्योंकि शिक्षा की वर्तमान व्यवस्था विभा-जित करने वाली और विविध वर्गीय है तथा स्तरीकरण (स्ट्रैटिफिकेशन) और परकीकरण (एलिमेंटेशन) को प्रोत्साहन देनेवाली है, इसलिए केवल इतना पर्याप्त नहीं होता कि सरकार को ये आवश्यक विधु स्वीकार हैं। उसके साथ-साथ सरकार ने नयी तालीम के वर्तमान तथा कार्यक्रम के प्रति ऐसी प्रतिबद्धता भी होनी चाहिए, जो सत्य और मर्यादित हो।

नयी शिक्षा व्यवस्था की मूल्यांकन तभी हो सकेगा, जबकि हम हस्तिकारक प्रवृत्तियों का प्रभावी रूप से निराकरण हो, जिससे क्षेत्र में अधिकतम लोग भी, जो प्रचलित शिक्षा व्यवस्था से सहज हैं, उनका भाग उठा सकें। इस-लिए शिक्षा में योग में ऐसी शिक्षा व्यवस्था में विकास किया जाय, जो व्यक्ति और समाज की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हो और जिसमें इस बात पर विशेष ध्यान हो कि इसके माध्यम में अधिकारहीन ८० प्रतिशत लोगों को भी समझा है। इसके लिए जरूरी यह है कि शरीर, पशुपक और आस्था (हाथ, दिमाग और मस्तिष्क) का एक साथ विकास हो जिससे शिक्षार्थी और शिक्षक

सब सामान्य की मुनम होनी चाहिए और उसे स्वतन्त्र, स्वच्छ और सुख होना चाहिए।

डा० चन्दर ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की ओर विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट किया और शिक्षा के छावनीकरण, प्रौढ़ शिक्षा और औद्योगिक शिक्षा की चर्चा की। उन्होंने ने पारिपरिक और नैतिक शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा नीति निर्धारण ही चर्चा नहीं है। उसका कार्यान्वयन जल्दा ही महत्वपूर्ण है।

श्री के० अवराज बलू जी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में हरीपुरा कांग्रेस में बुनियादी शिक्षा के प्रस्ताव को स्वीकृति और उसके परिणामात्मक हिन्दुस्तानी तालीमों के गठन के नयी तालीम समिति के अध्यक्ष कायें पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि नयी तालीम में जिया और शांति का समन्वयन अद्वितीय है। नयी तालीम का कम स्कूल तक ही सिमित न रहकर जीवन पर्यन्त चलने वाला कम है। आपने प्रस्तावना व्यक्त किया कि १९७४ तथा १९७६ के 'नयी तालीम सम्मेलनों में राष्ट्रीय शिक्षा के लिए जो मुख्य निर्धारित दिए गए थे उनमें से अन्तिम पर वर्तमान प्रस्तावित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सम्मिलित कर दिए गए हैं। आपने इस तथ्य पर जोर दिया कि कि बोझारी भाषण में बुनियादी शिक्षा की सराहना की विभिन्न प्रकारों से बुनियादी शिक्षा की सहायता कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि एकत्र राज्यों के प्रतिष्ठित राज्य सरकारों ने बुनियादी शिक्षा को समर्थन कर पुनः पुनर्जीव पाठ्यक्रम अपना लिया है। वर्तमान प्रस्तावित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी बुनियादी शिक्षा का बड़ी उल्लेख नहीं है।

आपने धन की प्रतिष्ठा पर बल दिया और छात्रों-

रिज धन तथा शैक्षिक धन के पारिपरिक में भारी अन्तर को दूर करने पर बल दिया। आपने शिक्षा की दुर्गति का उल्लेख करते हुए इस बात पर बल दिया कि राजकीय तथा गैर राजकीय सेवाओं में चुनाव योग्यता के आधार पर किए काम। चुनाव के लिए प्रत्येक सेवा के लिए अपनी जाँच प्रणाली होनी चाहिए। शीकरियों के लिए उपायों और प्रमाण - पत्रों की बातें समाप्त की जानी चाहिए, तभी शिक्षा में स्वातंत्र्य आधार दूर हो सकेगा और सेवाओं के लिए अधिक योग्य शक्ति मिल सकेंगे।

प्रथम चारों सत्र अपराह्न ३ बजे प्रारम्भ हुआ। श्री रामलाल पारिख अध्यक्ष ने प्रारम्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति और उसके मुख्य बिन्दुओं पर प्रकाश डाला।

२८ मई को प्रातः के सत्र में प्रस्तावित शिक्षा नीति में प्रारम्भिक विषय पर चर्चा हुई। इस विषय को प्रारम्भ में डा० बादलक, मुख्य, शिक्षा अनुमान, योजना आयोग ने किया। इसी सत्र में राज्य नयी तालीम समितियों ने अपने राज्यों में नयी तालीम के कार्य के सम्बन्ध में अपनी आस्था प्रस्तुत किया। अपराह्न के सत्र का शुभारम्भ डा० जय विजय, निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद ने किया। इस सत्र में शिक्षकों की भूमिका चर्चा का विषय था।

सम्मेलन के सभी सत्र आयोजन रहे। प्रतिनिधियों ने जारी सभा में चर्चा के भाग लिया। सत्र में प्रतिनिधियों ने अधिवेशन का प्राक्कण तैयार करने के लिए एक उप समिति का चयन किया। उप समिति ने २९ मई की प्रातः प्राक्कण तैयार किया। यह प्राक्कण सभी दिन बल बने के प्रारम्भ होने वाले सत्र में प्रस्तुत हुआ और सत्रों में सहित स्वीकार किया गया।

प्रारम्भिक तथा माध्यमिक सभी स्थापक प्रशिक्षण संस्थाओं को, चाहे छात्रावासों को बुनियादी स्कूलों में बदलना है। यह पैर-बुनियादी स्कूलों में नयी तालीम के अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं में परिवर्तित किया जाना चाहिए। बुनियादी शिक्षा की पद्धति तथा जीवन शैली में प्रतिष्ठित अस्थायक वर्तमान अध्यापकों से कहीं अच्छे सिद्ध होंगे।

केवल सामान्य नौकरियों के लिए नहीं, बल्कि सभी प्रकार की मशीनों के लिए डिग्री के भी मीकरी के सम्बन्ध विच्छेद होने से उच्च शिक्षा अधिक उपयोग बन सकेगी।

बच्चों तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के अधिकारिक सहूने होते जाने के कारण जनता का अविश्वसनीय बन उठे बर्तित रह रहा है। यह बात बड़ी चिन्ता की है और तत्काल प्रदान की जान करनी है।

पारिपरिक और मौखिक कार्य से होने वाली क्षति को साई है, उसको घटाने के लिए तथा बचपनी के समाज को ध्येय को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि सरकार को मजदूरी नीति समझनी हो।

६. प्रवर्धित शिक्षा व्यवस्था के पुनर्निर्माण में समर्पित स्वयंसेवी संस्थाओं का रोष ध्यान में रखा जाना चाहिए। अतः उनको नए प्रयोग करने के लिए स्वायत्तता प्रदान करने में सहयोग देना चाहिए और उनको इसके लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। यदि शिक्षा का सत्य नाम शोष के होना है, तो सत्ता संचालन होकर-चाहो के हाथ में न रहकर मुख्यतः स्वयंसेवी संस्थाओं के हाथ में रहना चाहिए।

१०. शिक्षा केवल राष्ट्रीय नीति तक सीमित रहकर भारत में एक राष्ट्रीय प्रयास बने, इसके लिए अन्य बातों को समान ही महत्त्व देना है कि शिक्षा सम्बन्धी निर्णय और शिक्षा संस्थाएँ स्वयंसेवी राजनीति से मुक्त हों।

इस पर तथा सम्बन्धित अन्य विद्वानों पर ध्यान विस्तृत चर्चा को प्रोत्साहन देने के लिए नयी तालीम समिति के सम्पन्न, शिक्षा धारिणियों के एक प्रतिन द्रुप को मन्त्रीयत कर सकते हैं।

विभिन्न प्रदेशों की नयी तालीम समितियों को नये विद्वानों पर प्रत्यक्ष बनाने के लिए विचार-विनिर्माण माधो-बित्त करनी चाहिए।

सम्मेलन में पारित राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षण कार्यक्रम

सम्बन्धी प्रस्ताव

नयी तालीम कार्यक्रमों का यह सम्मेलन भारत सरकार के अपने अधिकतम है प्रौढ़ शिक्षण के राष्ट्रीय कार्यक्रम को प्रारम्भ करने, साथ ही इस कार्य के लिए एक दृढ़ धनराशि स्वीकार कर इसे राष्ट्रीयता कार्य-क्रम बनाने की सहायता करता है। निम्नलिखित बातों के प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अनुभवों ने गोपीयो के इस विचार से अपनी एकात्मता सिद्ध की है कि केवल छात्र-रता शिक्षण का न हो प्रारम्भ है और न अन्तः। यह ही केवल शरण निर्भरता और आजीवन शिक्षण को सिद्ध करने की प्रक्रिया का एक साधन, एक भीतर माध्य है।

सम्मेलन यह प्रस्ताव करता है कि सामाजिक शिक्षण के उचित आदर्शों को प्राप्त करने की समानताओं को विकसित करने की दृष्टि से यह कार्यक्रम एक विद्यालय में व्यापक अवसर द्वारा छात्रों प्रस्तुत करता है और नयी तालीम समिति से एक कार्यकारी बल 'टास्क फोर्स' को रखना करने के लिए अनुरोध करता है। कार्यकारी दल का यह प्रमुख कार्य रहेगा कि यह ही कार्यक्रम में सभी वा सन्ने वाली संस्थाओं से अपना सादात्म्य साधे और प्रौढ़ शिक्षण के कार्यक्रम को एक नयी विद्या देने में उनकी सहायता करे। प्रौढ़ शिक्षण को हमारा पारम्परिक अनुसार

ग्राम समाज ही पाठशाळा बन जाता है। ग्रामीण समाज के मानवीय, सामाजिक एवं आर्थिक स्रोत हो शिक्षण का माध्यम बनेंगे। इसी को ग्राम स्वराज्य नवी तालीम की अवधारणा कहा गया है। यह परिदृष्टिगत न केवल उन लड़के-लड़कियों को जो बीचमे ही अध्ययन छोड़ चुके हैं तथा आर्थिक तथा सामाजिक अवयव परिस्थिति के कारण पाठशाळा में नहीं जा पाते हैं उन्हें अपने शिक्षणिक साधने में सहाय, बल्कि ऐसे श्रमियों को भी, जो जीवन में शिक्षण का अवसर तो चुके हैं और जो शिक्षा के साधन मिलने पर अपनी कुशलता समृद्ध करने में सक्षम हैं, का भी समावेश करने। यह अवधारणा अपने ही विशेषता की। पढ़े की पाठशाळा की बल्बत्वा तथा पाँधी की समन्वित प्रौढ़ शिक्षा के द्वारा शिक्षा में आत्मनिर्भरता की परिदृष्टिगत के तत्त्व समावेश करती है।

हम मानते हैं कि अब समय आ चुका है जबकि इस अवधारणा को विभिन्न प्रकार के प्रयोग तथा अनुभवों के आधार पर व्यवस्थित रूप दिया जाय। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में ग्राम विकास की दृष्टि से कार्यरत शक्तियों को यह चुनौती स्वीकार करने का आवाहन दिया जाय। नवी तालीम के लिए इस रूप में एक नया माध्यम चुन जाता है जिसके द्वारा नवी तालीम में निहित उन मुख्य और तकनीकी का प्रत्येक परिवार तथा समूहों में तक प्रसार किया जा सकेगा है। इस प्रकार के प्रयोगों और अनुभवों में समुचित दस्तावेज 'रेकार्ड' आदि यथोचित दृष्टि से सुरक्षित रखे जाय तथा उनका विश्लेषण भी किया जाय। उन प्रयोगों के आधार पर समुचित साहित्य का निर्माण भी किया जाय। इसके आधार पर समूह राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को एक

नया गुणात्मक मोड़ और गति मिले बिना नहीं रहेगी लोक शिक्षण की सीमा या परिधियों को भी यह प्रकट करेगी क्योंकि जो कुछ हासिल होगा वह शिक्षाविदों के समृद्ध और प्रचुर अनुभवों पर आधारित होगा। श्रमिति की प्रौढ़ शिक्षण कार्यक्रम के कार्यक्रमगत का समय समय पर मूल्यांकन तथा समालोचना करना चाहिए और इस प्रकार ग्राम स्वराज्य नवी तालीम को अपनी शिक्षा की तकनीकी प्रक्रिया को जलरोधक तथा सतत समृद्ध करते रहना चाहिए।

यह सम्मेलन अपने कार्यक्रमों से अवगत करता है कि वे नये तरंगों को भर्ती करते हुए प्रादेशिक नवी तालीम समितियों को मजबूत करें तथा प्रदेश स्तर पर इस प्रकार के सम्मेलन आयोजित करें। यह भी एक महत्वपूर्ण बात होगी कि नवी तालीम के कार्यक्रमों अपनी बात प्रभावी रूप से प्रतिपादित करें और नवी तालीम की भावना और रूप को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षण को नवीन रूप देते हुए प्रयोग आदि करने की दृष्टि से स्वैच्छिक कार्य से इस अवसर का पूरा उपयोग करें।

समुदाय आलेख शिक्षण जब नवी तालीम की शिक्षा पद्धति को रूप में परिवर्तित होगा वह समय विभिन्न विषय वस्तु तथा पद्धतियों पर आधारित इन प्रयोगों का महत्व हमारे लिये कीमती साबित होगा।

जोशों में सामाजिक पुनर्निर्माण में लिये उपयुक्त ऐसी मनःस्थिति एवं परिस्थिति निर्माण करने की दृष्टि में अपेक्षित चेतना का विकास करते हेतु नवी तालीम के कार्यक्रमों को अपने आपको निष्ठापूर्वक तथा समर्पण भाव से इस काम में लग जाने के लिए यह सम्मेलन अनुरोध करता है।



अध्यक्षीय भाषण

श्री वे० अरुणाचलम्

हम नवी राष्ट्रीय समिति के वार्षिक सम्मेलन के लिए ऐसे दिन में एकत्र हुए हैं जिसने राष्ट्रीय शिक्षा के विचार को १९०६ में ही जन्म दिया है। श्री बालगेंगे ने निरुद्ध और अनिवार्य शिक्षा का एक विधेयक साम्राज्यीय विधान परिषद में १९१९ में प्रस्तुत किया। गांधी जी उन दिनों टागोरदास फार्म पर शिक्षा का प्रयोग कर रहे थे। वे भी होम्स के अनिवार्य शिक्षा के विचार से सहमत नहीं हुए, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि ऐसी शिक्षा को मनुष्य नहीं संसार करती थी और जो हमें कर्तव्य सामग्री के योग नहीं बनाती थी, देश पर अनिवार्य रूप से लाद दी जाए।

गांधी जी प्रचलित शिक्षा पद्धति में विश्वास नहीं करते थे। अत्यंत साहसिक निश्चय किया कि टागोरदास फार्म पर करने अनुभव और प्रयोग द्वारा ऐसी वास्तविक पद्धति विकसित करेंगे जो व्यक्ति के चरित्र और व्यक्तित्व का विकास करे। अतः वहाँ के प्रयोग से उन्होंने जो पद्धति विकसित की उसे ही 'बुनियादी शिक्षा' या 'नवी राष्ट्रीय' कहते हैं। गांधी जी के अनुसार उनके द्वारा देश को दिए गए कार्यकर्मी में यह सर्वोत्तम है। नवी राष्ट्रीय 'राष्ट्रीय शिक्षा' का प्रतिरूप है। नवी राष्ट्रीय शिक्षा और ज्ञान को समन्वित करती है। यह समष्टि अद्वितीय (Unique) स्वतंत्र है। विश्वास में विश्वास और ज्ञान अलग-अलग माने जाते हैं और एकता से उत्पन्न होता है वह स्वतंत्र अज्ञान विद्या ज्ञान है। ऐसा माना जाता है कि एक ही पद्धति से कुछ वर्षों में सफल जीवन व्यतीत करने के लिए आवश्यक समस्त ज्ञान विद्या जाता है। गांधी जी ने प्रारम्भ में बात कर्म की बुनियादी शिक्षा की बात कही। किन्तु १९४४ में आभा था मनुष्य से मुक्त होने के बाद उन्होंने माओद्वय शिक्षा—जन्म से मृत्यु तक की शिक्षा की बात कही। उन्होंने कहा कि होखाना, जीवन और उनकी विभिन्न प्रविधियों के साथ उत्तम चलने वाला कर्म है। इस प्रविद्या में कार्य से ज्ञान उत्पन्न होता है और मनुष्य के लिए कार्य के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना मनुष्य के जन्म से ज्ञान प्राप्त करने की अन्तिम सत्य है। कार्य

और ज्ञान के विमल से अधिक मनुष्य नागरिक संसार होते हैं।

हरीपुर कांग्रेस में फरवरी १९२८ के द्वितीय सत्राह में श्री सुभाषचन्द्र बोस की अध्यक्षता में एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। उसके अनुसार 'बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षा' का कार्यक्रम संसार करने तथा उसको विकसित करने की दृष्टि से प्रयोग करने हेतु श्री बाहिर हुनेन तथा श्री मार्थनाथकम् को को अधिकृत किया गया। इस तरह हिन्दुस्तानी तात्वीय सत्य का जन्म हुआ। यह सत्य सर्व सेवा सत्य के साथ, सत्य समय विरोध हो गया, जब समग्र सभी रचनात्मक सत्वात्मान विकास का समन्वित कार्य-क्रम बनाये हेतु सञ्चलित हो गयी। सर्व सेवा सत्य ने एक स्वतंत्र सत्वा "अखिल भारत नवी राष्ट्रीय समिति" इस कार्य को आगे चलाने हेतु पटित किया। अपने जन्म (Inception) के साथ ही वह विभिन्न प्रौद्योगिकीय सत्राहों के साथ अपना कार्य कर रही है।

समिति द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलनों में १९४४ में सेवाराज में तथा १९७७ में नवी दिल्ली में अनेक प्रस्ताव देश में शिक्षा के क्रम को मजबूत करने हेतु पारित हुए। यह प्रस्ताव उपयुक्त सत्वाओं के सम्मुख कार्यान्वयन हेतु प्रस्तुत किए गए।

मुझे यह जानकर प्रसन्नता होती है कि इनमें अनेक सत्त्वुधियाँ राष्ट्रीय शिक्षा प्रस्ताव के प्राप्ति में स्वीकार की गयी हैं और उसमें सम्मिलित की गयी हैं। यह सम्मेलन इस प्राप्ति पर गौरव है। विचार करेगा और अपनी सुविचारित राय प्रस्तुत करेगा।

गांधी जी की बुनियादी शिक्षा स्वतंत्र सत्य में भीति के रूप में स्वीकार हुई थी और यह प्रथम सत्य पञ्चवर्षीय योजनाओं तक चलती रही है। विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के अध्ययन हेतु अनेक आयोग गठित हुए थे। मोठारी आयोग ने, जो इस तरह का अन्तिम आयोग था, बुनियादी शिक्षा को सराहना की है। किन्तु हमने सुझाव दिया कि आरम्भिक स्तरों पर शिक्षा को एकात्मता के

लिए इसे प्राथमिक शिक्षा कहा जाय। ऐसे विद्यार्थियों ने, विभिन्न मूल में प्राथमिक धर्म के प्रति निरुत्साह था, इस अवसर पर शास्त्र उद्घाटन कार्य आयोजित किया जो पुस्तक आधारित शिक्षा में परिवर्तित कर दिया। यहाँ तक कि प्रदेशों में जहाँ बुनियादी शिक्षा ने स्थापित पा लिया था, इस अवसर का नाम उद्घाटन पुस्तकोप्य शिक्षा को नुन अपना लिया। संवत् एक या दो राज्यों ने राष्ट्रीय की वृद्धि और मुख्यों को समर्थन दिया है। कुछ स्वयं सेवी संस्थाएँ भी हैं जो बुनियादी शिक्षा की वृद्धि और तकनीक के प्रयोग कर रही हैं। किन्तु यह स्वीकार करना होगा कि उन्हें भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का घोषणा पत्र जो १९९८ में प्रस्तुत हुआ था, अपने प्रयास के बावजूद प्रचलित पद्धति के भागे नहीं जा सका।

बीप्राय की वर्तमान स्थिति ने, जो राष्ट्रीय की के आर्यों के वादाविवरण हेतु प्रतिबद्ध हैं, नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्राथम प्रस्तुत किया है। यह राष्ट्रीय की के शिक्षा नीति के अधिक निष्कर्ष है। किन्तु इस प्राथम में भी बुनियादी शिक्षा का उल्लेख न तो प्राथमिक स्तर की शिक्षा पर है, न माध्यमिक और उच्च स्तर पर ही। इसने स्वयंसेवी संस्थाओं का उल्लेख अत्यन्त सामान्य रूप से किया है। शिक्षा तथा विद्या में नवीन प्रयोगों को एकत्रित करने के नाम पर प्रोत्साहन नहीं मिलता। सबसे उच्चान सेवा के लिए वाध्य नहीं किया जाना चाहिए।

वर्तमान शिक्षा प्रणाली, जिसका विस्तार से अभीष्ट वर्णन है नवीन विचार धारा में बदलने के लिए सक्षम कर रही है। इसने भी भी प्रयास किया है, जहाँ सम्भव नहीं हो पाया है और न ७० प्रतिशत व्यापारी को संतुष्ट हो कर पाया है। शिक्षा प्राप्त करने वाले (drop out and pass out) की समस्या से परीक्षण है। फिर भी वे ऐसी शिक्षा प्रणाली नहीं विकसित कर पा रहे हैं, जो विद्यालयीय शिक्षा प्रणाली से शिक्षा ग्रहण करने वाले भारी संख्या के लोगों को सिद्धि कर सके। वर्तमान

प्रस्तावित शिक्षा नीति ने विद्यालयीय प्रणाली को अपूर्ण छोड़कर शिक्षा लोगों के लिए कार्यपरक शिक्षा के सम्बन्ध में घोषा है। विद्यालयीय प्रणाली की विभिन्न स्तर के लोगों के लिए उपयोगी बनाने की चेष्टा की प्रेरणा लोगों को वास्तविकतापुष्कार विद्यालयीय प्रणाली से निम्न शिक्षा पद्धति विकसित करना अधिक उपयोगी है। इस हेतु परीक्षा पत्र की व्यवस्था करनी होगी। प्राचीन स्कूलों को, अब वे कहीं काम कर रहे हो मरवा लेते रहे हैं, सिद्धि दिया जाना चाहिए।

ग्रीक शिक्षा नीति, जो न केवल साधार बनाने हेतु अपितु स्वशिक्षा की मातृ विकसित करने हेतु सामाजिक कार्यकर्ता करने की है, राष्ट्रीय की के विचारों के अधिक निष्कर्ष है।

दुर्भाग्य से आज शिक्षा की रोजगार में जोड़ दिया गया है। शिक्षा का कर्तव्य परिपक्व शिक्षा न होकर, औरों हेतु प्रमाण पत्र और उपाधिका प्राप्त करना ही रहा है। यह प्रवृत्ति बदलनी चाहिए। शासकीय सेवाओं में प्रभाव के लिए कार्य करने का अपना पाठ्यक्रम विकसित करना चाहिए, जिसमें उपाधियों का आग्रह हो। शैक्षणिक सेवाओं में भी गरी नीति होनी चाहिए। शीकरियों में उपाधियों की पाठ्यपद्धति देने से विश्व-विद्यालयों, कॉलेजों में प्रवेश की भीषण वृद्धि होगी, परीक्षाओं के प्रभुत्व की समाप्ति होगी और सेवाओं में अधिक योग्य अभ्यर्थी मिल सकेंगे।

इस देश में प्रत्येक व्यक्ति धर्म की प्रतिष्ठा की मातृ करता है, किन्तु वास्तविकता यह है कि धर्म की प्रतिष्ठा कोई नहीं करता है। यहाँ धर्मिक हो, जोध और कलम चलाने वालों से दूर पचकट्टी मिलती है। शिक्षा नीति के धाम ही मजदूरी और आय की नीति भी होगी चाहिए। जब तक प्रमाण पत्र तथा उपाधियों के द्वारा अधिक वेतन प्राप्त होता रहेगा, तब तक धर्म और धर्मिक के विराट पर बल देना सम्भव न होगा। ऐसे प्रमाण-पत्रों और उपाधियों के पीछे ही मल्लो रहेंगे। अतएव यह वास्तविक है कि शिक्षा नीति को औद्योगिक, कृषि नीति आदि के साथ जोड़ा जाय, अन्यथा वर्तमान शिक्षा नीति वास्तविक तक ही सीमित रह जायगी।

शिक्षा की राष्ट्रीय नीति का प्रारूप [१९७६]

शिक्षा एवं समाज मन्त्रालय भारत सरकार

प्रस्तावना :—

१-१ आदर्श शिक्षा व्यवस्था वह है जो लोगों को सभी दार्शनिक और मानसिक क्षमताओं का ज्ञान कला और उन्हें पूर्णरूप से विकसित करने के योग्य बनाए, और जो उनके सामाजिक और मानवीय मूल्यों को नेतृत्व को विकसित करने में सहायता करे जिससे वे एक चरित्र का विकास कर सकें और समाज के विविध सदस्यों के रूप में बेहतर जिम्मेवारी स्वीकार कर सकें और अपने अधिकारों का निर्वाह कर सकें। मनुष्य में व्यक्तिगत रूप से परिवर्तन लाकर ही समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है।

उद्देश्य :—

१-२ शिक्षा का उद्देश्य स्वनिष्ठ भीमवर व्यापारिक व्यक्ति का ऐसा विकास होना चाहिए जो समाज के विकास और प्रगति तथा स्वतंत्रता, समता एवं सामाजिक न्याय के आकांक्षित मूल्यों की प्राप्ति में सहायक हो। इस दृष्टि से शिक्षा का उद्देश्य नैतिक-नैतिक धर्मनिरपेक्ष-वादी तथा समाजवादी मान्यताओं को समर्थन देना है।

शिक्षा को राष्ट्रीय एकता में अपनी सहायिका के प्रति एवं और देश के प्रति में विश्वास की भावना में सहायक होना चाहिए। जीवन में नैतिक तथा नैतिक मूल्यों का समर्थन करने तथा ज्ञान की ओर अग्रसर होने का प्रयास होना चाहिए।

विषय वस्तु :—

१-३ शिक्षा की विषय वस्तु को पूर्ण रूप से बदलने की आवश्यकता है जिससे शिक्षा की प्रक्रिया, लोगों की समता और अनुभूति, आवश्यकताओं के अनुसार वे कार्य-योग्य हो सकें। शिक्षण की अवस्था सीखने पर अधिक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सीखने वाले की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है। शिक्षा में मानवीय की के विचार और प्रयोग उनकी सभी प्रकार के क्षमताओं में अन्तर्द्वेष की विधि, उनका ज्ञान और क्षमता के सहसम्बन्ध पर ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के रूप के सहयोग की प्राप्ति

होती है तथा उनकी शिक्षा की सामाजिक जिम्मेदारियों पर ध्यान देना भी महत्व रखता है। इस दृष्टि से वे अत्यन्त आवश्यक तथा उपयोगी हैं। समाज सेवा तथा स्वतंत्रता एक समाजवादी लोगों के मूल्य हैं। सभी स्तरों पर शिक्षा का अनिवार्य बन होना चाहिए।

मानव निर्भरता और धर्म के प्रति सम्मान का पोषण हो सके, सभी विषयों के परस्पर सम्बन्ध पाठ्यक्रमों और पाठ्यक्रमों पर कार्यकर्ता के माध्यम से नैतिक शिक्षा पाठ्य-विषय वस्तु का अंग बननी चाहिए और उसकी जिम्मेदारी सभी शिक्षकों और पूरी संस्था में होनी चाहिए। पाठ्य विषय वस्तु में महान राष्ट्रीय नेताओं की सोच और जीवनकृतियाँ तथा स्वतंत्रता आन्दोलन के इतिहास भी समावेश होना चाहिए।

व्यवस्था :—

१-४ वर्तमान भारतीय वास्तविकताओं और आवश्यकताओं के सम्बन्ध में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था का पुनर्गठन होना चाहिए, राष्ट्रीय सहमति के आधार पर निर्धारित स्वतंत्रता, समता और न्याय की बुनियादी संरचनाओं को दृष्टि में रखते शिक्षा व्यवस्था को भी और विभिन्न परिस्थितियों के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए, समता के अर्थ में भी कोसला न करते हुए, उत्तमता प्राप्त करने का एक प्रयास होना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था में हम बात का प्रयास होना चाहिए कि जनता और निहित वर्गों के बीच की खाई कम हो और उनके बीच भावना, होनमानता और दूरान दूर होना चाहिए। पाठ्यक्रम का पठन विषय वस्तु तथा अवधि में लचीला-पन होने से विद्यार्थी अपने समय और अध्ययन की विषय का चुनाव स्वयं कर सकते हैं और अपनी गति से प्रगति कर सकते हैं। शिक्षा संस्थाएँ तथा समाज एक दूसरे की सहायता करें तथा व्यक्तिगत परस्पर सहयोग में रहें। बेहतर ज्ञान और कौशल प्रदान करें और इस प्रकार उनके बेहतर भविष्य की व्यवस्था करें। स्थानीय क्षेत्र के

विकास सम्बन्धी क्रियाकार्यों से स्कूल का पवित्र सम्बन्ध होना चाहिए।

सामूहिक प्राथमिक शिक्षा

सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा :—

२-१ जैसा कि संविधान के निर्देशक सिद्धान्तों में वर्णित है, १४ वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों की निम्नस्तरीय शिक्षा प्रदान करने को सर्वोच्च दायित्व देनी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा सामान्य होनी चाहिए, न कि विशेषीकृत और विद्याविषय की भाषा तथा अन्य उपयोगी विषयों पर विशेषज्ञतापूर्ण अधिकार प्राप्त होना चाहिए। भाषा ही उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समावेश होना चाहिए।

प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य और विषय वस्तु —

२-२ प्राथमिक शिक्षा में अक्षर्य और गणित के विभाग पर बल होना चाहिए, प्राथमिक शिक्षा की विषय वस्तु का गुणवत्ता गंभीरता से परम्पराओं और मान्यताओं की दृष्टि से, जो देश की समन्वित सांस्कृतिक निर्माण करती है, प्रत्यक्ष वर्तमान सांस्कृतिकताओं और समाज के भविष्य की संरचना की दृष्टि से भी आवश्यक है। इस स्तर पर शिक्षा की विषय वस्तु में भाषा, गणित, इतिहास, साधारण प्रारम्भिक विज्ञान, जो वर्णन और सांस्कृतिक संस्थाओं से विशेष रूप से सम्बन्धित हो, तथा सांस्कृतिक शिक्षा का समावेश होना चाहिए। पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से सोपानेय भाषा के अन्तर्गत सामान्य से समाजोपयोगी उत्पादक कार्यों का समावेश होना चाहिए जिससे समाज की आवश्यक सामान और सेवाएँ उपलब्ध हो सकें। तथा सम्पूर्ण कृषि और उद्योग सम्बन्धी कार्यों की व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार शिक्षा कार्योपयोगी होनी और लोगों के जीवन तथा पर्यावरण से भी सम्बन्धित होनी। जिससे वैज्ञानिक मनोवृत्ति को बढ़ावा मिलना चाहिए जिससे पलायन आध्यात्मिकता की समस्याएँ उदात्त मानवीय दृष्टिकोण प्राप्त होना दें। जिसमें सभी जीवन और परिवर्तन की पुनर्जागरण से सम्बन्धित को बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायता देनी।

२-३ प्रारम्भिक शिक्षा के प्रारम्भिक वर्षों में सामान्य जीवन के दृष्टिकोण में परिवर्तन की आवश्यकता है। औपचारिक शिक्षा की अपेक्षा सर्वनात्मक आनन्दपूर्ण प्रक्रियाओं पर अधिक बल दिया जाना चाहिए।

औपचारिक शिक्षा की भाषा न्यूनतम होनी चाहिए और तीन घंटे प्रति दिन में अधिक नहीं होनी चाहिए, जिससे अपरिवर्तनशील रूप से एक शिक्षक वर्ष की निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार स्कूल का सत्र निर्दिष्ट होना चाहिए।

प्राथमिक शिक्षा के लिए सुविधाएँ

२-४ जहाँ यह आवश्यक है कि १-१४ आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षाओं में औपचारिक शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार किया जाए, वही ग्राम जाउट तथा ऐसे १-१४ आयु वर्ग के अधिक आयु वाले बच्चों के लिए शिक्षा विशेष प्रकार की शिक्षा नहीं मिली है, जहाँ औपचारिक शिक्षा की योजनाएँ बनाया भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। उद्देश्य यह है कि आध्यात्मिक १० वर्षों में ऐसे उपलब्ध किए जाने चाहिए जिससे १-१४ आयु वर्ग के सभी बच्चे शिक्षा की परिधि में आ जायें। इससे बच्चों को शिक्षा विशेष पूरा किए हुए स्कूल छोड़ने से रोका जा सकेगा। अव्यय की समस्या का विस्तारपूर्वक अध्ययन होना चाहिए और इसे दूर करने का उपाय करना चाहिए।

२-५ पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए, जो विभिन्न प्रकार के सोते के बच्चों और छोटे बच्चों की परिस्थितियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें और स्थानीय स्थितियों के आधार पर निर्मित हो।

संस्कृत उपलब्धियों और आध्यात्मिक कौशल तथा ज्ञान को शिक्षा की तुलना की दृष्टि से सुनिश्चित विषय वस्तु का एक मूल आधार होना चाहिए। यह मूल आधार न्यूनतम होना चाहिए, आध्यात्मिक को व्यवस्था औपचारिक भवन आलोचनारिक प्रयोग के माध्यम से उपलब्ध होनी चाहिए, जो अधिक रूप से साधारण भवन आलोचन हो सकती है। साधारण प्रयोग ऐसा परिवर्तनशील नहीं होना

बाहिए जिससे ऐसे ज्ञानार्जन करने वाले, जो आर्थिक रूप से ही इस प्रश्न से लक्ष्य उठा सकते हैं, बाजित रह जाय।

प्रोत्साहन :—

२-६ गरीब विद्यार्थियों के लिए ऐसे प्रोत्साहन की जैसे मण्डाल भोजन, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, स्टेसनरी और वस्त्र व्यवस्था की जाय। पानिकारों तथा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बच्चों के लिए शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

विद्यालय और समाज :—

२-७ पाठ्य पठन के विकास के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विद्यालय को कार्य करना चाहिए। इसके करने में समाज की दीक्षित प्रभाव में पूर्णतः सम्मिलित होना चाहिए। विद्यालय के दीक्षित कार्यक्रमों के लिए समाज में उपलब्ध कारीगरों से लाभ उठाना चाहिए।

संयुक्त स्कूल व्यवस्था :—(COMMON SCHOOL)

२-८ प्राथमिक स्तर से ही संयुक्त स्कूल व्यवस्था के लिए स्थापन किए जाने चाहिए। प्रभाव यह होना चाहिए कि सभी प्रकार की शिक्षा उपलब्ध हो सके। इस बात को विचार कर लेना चाहिए कि सभी स्कूलों में शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा हो और शुद्ध तथा प्रवेश के नियम एकत्र हो।

पाठ्यपठन के स्कूल की योजना :—

२-९ संयुक्त स्कूल व्यवस्था की मुख्य विशेषता पाठ्यपठन स्कूल की योजना होगी जिसमें एक क्षेत्र के स्कूलों को पाठ्यपठन के सभी बच्चों को प्रवेश देना होगा, इसके सामूहिक हितों और सामाजिक समन्वय का सम्बन्ध होगा।

प्रौढ़ शिक्षा

प्रौढ़ शिक्षा की आवश्यकता :—

२-१ ऐसा अनुमान है कि अपने देश की आबादी के २३ करोड़ प्रौढ़ निरक्षर हैं। वे अधिकतर निर्धनतम तथा

अर्वाधिक उपेक्षित वर्ग के हैं। यदि उन्हें कुछ शिक्षा मिल जाय तो राष्ट्रीय कल्याण में उनका योगदान अपेक्षाकृत अधिक हो सकता है। उनकी यह दशा है कि वे उन लोगों से वंचित रह जाते हैं जो उच्च विभिन्न विकास योजनाओं में उपलब्ध हैं और वे शोषण और सामाजिक दुर्बलताओं के निवारक बने रहते हैं। राष्ट्र का यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्हें शिक्षा प्रदान करे। राष्ट्र में प्रौढ़ शिक्षा योजना कार्यक्रम, जो पालू किया गया है, तात्कालिकता तथा अवशिष्टताओं से शिथिल बनना चाहिए। इस कार्यक्रम का तात्कालिक लक्ष्य ३ वर्ष की अवधि में १० करोड़ लोगों को शिक्षित करना है, जिससे अपने देश में पारंपरिक साक्षरता का स्तर बने समय में वास्तविकता को प्राप्त कर सके।

सकल्पना :—

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का कार्य केवल साक्षरता और वृद्धि शिक्षा नहीं है, प्रत्युत इसका कार्य पारंपरिकी विकास तथा सामाजिक बेतना है, जिससे लोगों की स्वयं कीर्ति व्यवस्था ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति बढ़ जाय।

संयोजित मूलतम-आवश्यकता-कार्यक्रम :—

२-२ प्रौढ़ शिक्षा, संयोजित मूलतम आवश्यकता कार्यक्रम का अभिन्न अंग है जिसका लक्ष्य (अ) गरीबों तक पहुँचना है। (ब) ऐसे सभी कार्यों का समन्वय विकास में रख सभी विभागों में करना है और (ग) उन्हें क्षेत्रीय नियोजन से सम्बद्ध करना है। संयोजित मूलतम आवश्यकता कार्यक्रम जिसमें प्रौढ़ शिक्षा भी सम्मिलित है, केवल एक मन्त्रालय, विभाग अथवा अधिकरण का प्रसारण मात्र नहीं हो सकता।

अभिव्यक्ति :—

२-३ उम्मा बहा राष्ट्रीय की लागत को अपेक्षा करता है मजदूर इसके त्रिधा वर पर सभी शक्ति योजना होता। सबसे महत्वपूर्ण य. १, जो ध्यान में रखनी है वह यह है कि कार्यक्रम समाप्ति में है। इस कार्यक्रम के लिए अधिकतरों द्वारा लाभों को इस प्रकार निश्चित

करता है कि स्थानीय समाज तथा सरकार के बीच अधिकतम आदान-प्रदान रहे।

३-४ कार्यक्रम विविध स्तरों के माध्यम से समाज जागृत, जिसमें, बड़ा वे सुप्रसन्न हो, ऐतिहासिक प्रतिपत्तियों की प्रधानता रहेगी। प्रारम्भ से ही सम्भावकों विद्याविधियों, व्यापार, उद्योग, मकसदों तथा महिलाओं के सफलता, सामाजिक कार्यक्रमों, विकास-विभागों, नगर विकासकों, पंचायतों तथा अन्य स्थानीय विकासों का सहयोग सुनिश्चित कर लेना होगा।

ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान :—

३-५ ग्रौड निरक्षरता की वास्तविक समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में है। अतएव ग्रामीण समाज तथा ग्रामीण क्षेत्रों के सम्भावकों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत में सम्मिलित करने के लिए विशेष प्रयास करना होगा। महिला मजदूरों और युवा सफलता को अधिक बनाने के लिए भी विशेष प्रयास करना होगा। समाज की ओर से भी कुछ सागत का समाना प्राथमिक होगा जिससे यह कार्यक्रम निरन्तर चल सके।

महिला अनुदेशक :—

३-६ कार्यक्रम का उद्देश्य केवल निरक्षरता दूर करना नहीं है, अपितु दूसरी समस्याओं के प्रति चेतना का निर्माण करना है। अतः यह प्राथमिक होगा कि ऐसे कार्यक्रम जैसे परिवार नियोजन, स्वास्थ्य और भोजन विभागों तथा माताओं की देखभाल आदि विषय भी इस कार्यक्रम में मिश्रित होना चाहिए। इसके लिए यह प्राथमिक होगा कि कार्यक्रम के लिए स्वयंसेवक अनुदेशक समाजसंग्रह महिलाएं हों।

कौशल का विकास :—

३-७ निरक्षरता निवारण और चेतना निर्माण के अतिरिक्त ग्रौड शिक्षा में विकास सम्भाव्य विषय वस्तु भी देनी चाहिए, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम किया जाय, इनके क्षेत्रों में सुधार का उद्देश्य भी धारण रखना चाहिए। इसके लिए सामाजिक शिक्षा की आवश्यकता भी महसूस लेनी चाहिए।

उत्तर साक्षरता कार्यक्रम :—

३-८ ग्रौड शिक्षा कार्यक्रम में निरन्तर शिक्षा की व्यवस्था भी होनी चाहिए, जिससे उन प्रौद्योगिकी, जिन्होंने कार्यक्रम से लाभ उठाया है, साक्षरता में रुचि लेते रहें और वे अपने आप अपने ज्ञान और कौशल का विकास कर सकें। इन संपादकों में कम ध्यान की पुस्तकों और साहित्य ग्रन्थ-पुस्तकालय, मासमिडिया के द्वारा प्रसारित सामग्री भी सम्मिलित होगी। ग्रामीण-पुस्तकालय-व्यवस्था का विकास, निरन्तर शिक्षा के कार्यक्रम के लिए आवश्यक है।

४ माध्यमिक शिक्षा

माध्यमिक शिक्षा का गुणात्मक सुधार :—

४-१ यद्यपि सर्वोच्च वरीयता माध्यमिक शिक्षा के विस्तार और ग्रौड शिक्षा के विकास को दी जाती है, तद्वि माध्यमिक शिक्षा की सुधारता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जिससे विद्यालय छोड़ने पर विद्यार्थी मायलिनरता और विद्यालय के साथ जीवन में प्रवेश कर सकें और सामान्य ज्ञान तथा सम्बन्धित कौशल से युक्त होकर काम में लग सकें।

शैक्षिक बोझ का विविधोत्तरण तथा कम करना :—

४-२ माध्यमिक शिक्षा का वाद्व्ययन बहुविध होना चाहिए और अतिरिक्त शैक्षिक भार को हटाकर इसका नैतिक बल बढ़ा देना चाहिए, जिससे सम्पूर्ण व्यक्तित्व के विकास में सहायता मिल सके। वाद्व्ययन और वाद्व्ययन कार्यक्रम, प्राथमिक शिक्षा, क्षेत्र, समाजोपयोगी उत्पादन कार्यक्रम और समाज सेवा ऐसे होने चाहिए जिसमें विद्यार्थी जीवन में प्राथमिकी भावों से युक्त लोकतांत्रिक, समन्वित और सामाजिकी समाज के लिए ज्ञान और कौशल, कनिष्ठताओं और मायलिनर शक्ति बढ़ सकें।

४-३ शैक्षिक कार्यक्रम के विविधोत्तरण में ग्रामीण ओद्योगिकरण, गुरु विद्या, ग्रामीण स्वास्थ्य, ग्रामीण विद्युत्करण, ग्रामीण स्वास्थ्य-व्यवस्था और अन्य ग्रामीण विभागों का ध्यान हो। ग्रामीण क्षेत्रों

को विविधोक्त विवेचिता अर्थ - व्यवस्था का भी ध्यान रखना चाहिए।

माध्यमिक शिक्षा की भूमिका :—

४-४ दूरी शिक्षा व्यवस्था को एक श्रुत सलाह समझना चाहिए। इस श्रुत सलाह में केन्द्रीय बड़े माध्यमिक शिक्षा है, क्योंकि इसी के माध्यम से पिछले और जागामी कर्मियों को भी पढ़ाई है। प्राथमिक शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे माध्यमिक शिक्षा की सुविधाएँ सुदृढ़ हो और माध्यमिक शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे विद्यार्थी परीक्षा मात्र और भीतर से मुक्त होकर व्यावहारिक जीवन के विरोधी भी क्षेत्र में सीधे भाग ले सकें। माध्यमिक शिक्षा का स्वरूप व्यापक होना चाहिए। एक ओर यह उन लोगों के लिए भी आने शिक्षा नहीं प्राप्त करना चाहते या नहीं कर सकते, अन्तिम पीढ़ी हो और दूसरी ओर उन क्षेत्रों के लिए जिसके पास प्रतिभा है और उच्च शिक्षा के लिए अभिरुचि है, माध्यमिक शिक्षा उच्च स्तरीय अध्ययन के लिए सुदृढ़ बुनियाद तैयार करे। इसके अतिरिक्त व्यवस्था इन प्रकार की होनी चाहिए कि विद्यार्थी जब उनकी इच्छा हो एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जा सकें।

व्यावसायिक शिक्षा :—

४-५ कुछ भी हो, माध्यमिक शिक्षा की दोनों चारों ओर के वास्तविक में सुदृढ़ व्यावसायिक अर्थ होगा चाहिए और उसमें इतनी विविधता होनी चाहिए कि वह सम्पूर्ण दोनों चारों ओर की आवश्यकता पूरी कर सके। स्पष्ट अन्तिम पीढ़ी के रूप में माध्यमिक शिक्षा में दूसरी माध्यम की अवस्था व्यावसायिककरण का मग नहीं भविष्य होगा होगा। माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायिककरण में बुनियाद समाजोपयोगी उत्पादन कार्य के रूप में और पहले से ही सामग्री होती जिससे व्यावहारिक कार्य पर वह प्राथमिक शिक्षाओं के वास्तविक का अनिवार्य बन होगा।

४-६ व्यावहारिक शिक्षा में विविध ज्ञान और कोशल तथा सम्पूर्ण विज्ञान, कृषि तथा अन्य प्रौद्योगिकी कार्य के साथ साथ तकनीकी के प्रवर्धन को सम्मिलित होने। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्राथमिक में उच्च-

तम सुविधाओं से व्यवस्थित सम्पादन स्थापित करना चाहिए। उद्देश्य यह होना चाहिए कि विद्यार्थी रोजगार के योग्य बन सकें या उनमें स्वयं काम में लगने की क्षमता उत्पन्न हो सके।

४-७ व्यावसायिककरण का कार्यक्रम प्रारम्भ करने में पूर्ण सर्वेक्षण करना होना जिससे रोजगार के सम्बन्ध और स्थानीय आवश्यकताओं का मोटे तौर पर अनुमान अनुमान लगाया जा सके। ऐसे सर्वेक्षण और अनुमान समय-समय पर किए जाने चाहिए, जिससे व्यावसायिककरण के कार्यक्रम का पुनरीक्षण हो सके और समय-समय पर उन्हें परिवर्तित या संशोधित किया जा सके।

४-८ ऐसे व्यावसायिक क्षेत्रों और आवश्यकताओं की व्यवस्था करने का प्रयास होना चाहिए जिससे स्वरूप और समानता प्रवृत्ति रख सके, ऐसा धनोपचारिक विधियों के आधार पर उचित स्थिति में बना। सर्वोत्कृष्ट क्षेत्रों की व्यवस्था करके किया जा सकता है। व्यावसायिक क्षेत्रों से निकले हुए लोगों को अन्य व्यवसायों की ओर आकर्षित होने का व्यवस्था विवक्षित है।

४-९ जो व्यावसायिकरण स्वीकार करने की दृष्टि से किया जाय उसमें श्रेष्ठ प्रकार के दूरक माध्यम का भी ध्यान रखा जाय, साथ ही उद्देश्य यह होना चाहिए कि शिक्षा औद्योगिक क्षेत्रों और अन्य सम्पादन से जिसके देश में स्थापना हो रही है, समाजी सम्पादन की माध्यमों का विस्तार हो सके। उस विद्यार्थी को, जो व्यावसायिक क्षेत्रों पूरा करता है, उचित मान्यता मिलनी चाहिए। व्यावसायिककरण को आगे बढ़ाने में निम्ने प्राथमिक योजनाएं इन क्षेत्रों में भी भागू की जानी चाहिए।

समाज का सहयोग :—

४-११ विद्यालय और समाज दोनों को एक साथ जोड़ना होगा। कार्यक्रमों और क्षेत्रों को सुनिश्चित करने में और काम करने में सुविधाओं की व्यवस्था करना में समाज का सहयोग उत्पन्नता मुक्त होगा। इसके अतिरिक्त इनसे स्वयंसेवा के लिए बहुत से अवसर भी निकलेंगे।

विश्वविद्यालय की व्यवस्था को समाज के विकास और विशेष रूप से पूरी शिक्षा व्यवस्था के विकास की बढ़ती हुई जिम्मेदारियाँ लेनी चाहिए। विश्वविद्यालयों को कालेजों से सहयोग करना चाहिए और इस प्रकार कालेजों को पाठ्य प्रशिक्षण के माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालयों से सहयोग करना चाहिए जिससे अत्यधिक समय पर शिक्षा को स्तर में सुधार आ सके। विश्वविद्यालयों, कालेजों तथा समाज के पारस्परिक संबंधों का विकास हेतु पण्डित सम्मेलन होना चाहिए। विश्वविद्यालयों के विस्तार, कार्यक्षेत्रों की वृद्धि स्थान मिलना चाहिए जो शिक्षण और शोध को मिलता है। अवकाश के दिन अक्षा व्यवस्था को कम कर दिए जाए और उच्च की ऐसी पुनर्व्यवस्था की जाए जिसे विद्यार्थी तथा अध्यापक सामील समाज के विकास के कार्यक्रमों में हाथ बटा सकें।

उत्तमता के केन्द्र—

५५ उत्तमता के केन्द्र शिक्षा स्तर विश्व के सर्वोत्तम केन्द्रों से कम न हो, अत्यन्त आवश्यक है। इसे विशिष्ट करने के लिए हर प्रयास किया जायगा।

१. शिक्षा का स्तर—

शिक्षा के क्षेत्रों में मोटे डोरों से तीन स्तर होये प्राथमिक माध्यमिक तथा स्नातक। स्कूली शिक्षा १२ वर्ष की होनी जिसमें प्राथमिक और माध्यमिक सम्मिलित होये। माध्यमिक शिक्षा के अन्त में एक सार्वजनिक परीक्षा होनी। स्नातक स्तर की शिक्षा ३ वर्ष की अवधि की होनी चाहिए। विश्वविद्यालय चाहे, छोटा बड़ा दो वर्ष का सामान्य कोर्स और ३ वर्ष का आगम कोर्स रख सकते हैं।

७. तकनीकी शिक्षा—

जनशक्ति की आवश्यकता और तकनीकी शिक्षा—

५६ तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छी राष्ट्रीय जनशक्ति सुचना व्यवस्था की आवश्यकता है, जिसका विकास आगामी ५ वर्ष में हो जाना चाहिए। सामाजिक जीवन विकास की परिवर्तित प्राथमिकताओं को धृष्टि में रखते हुए सभी स्तरों पर एक जीवन सम्मुखित तक-

नीकी शिक्षा व्यवस्था सशक्ति की जानी चाहिए। तकनीकी शिक्षा का कार्यक्रम अधिक दृढ़ और सार्वक आसार पर निर्भर होना चाहिए।

कोर्सों का पुनर्गठन

७२ तकनीकी शिक्षा की संस्थाएँ विशेषकर प्राचीन-ऐकनिक ऐसी केन्द्र विद्युत होनी जहाँ प्राचीन क्षेत्रों की व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जायगा और उनका समाधान निकाला जायगा। कार्यक्रम ऐसे क्षेत्रों जिसमें शोध के साथ सार्वक सम्बन्ध और सहयोग अनिवार्य रूप से होया। प्रयोगशालाएँ और कार्यशालाएँ सुदृढ़ की जानी चाहिए और प्रतिष्ठान में सुधारमक सुधार होना चाहिए। तकनीकी शिक्षा कोर्सों का उद्देश्य काम का प्रारम्भ करने का कोर्स प्रदान करना की होना चाहिए। प्रथम, विज्ञान शिक्षण के कोर्स इस प्रकार से पुनर्गठित किए जाने चाहिए, जिससे प्राचीन क्षेत्रों की छोटी और मध्यम स्तरों पर जो तथा ऐसी विशालीय आवश्यकताओं में लिए जैसे आतायात, विद्युत, स्वास्थ्य, कृषि, सहयोग और सामाजिक विकास, प्रदम्यारम्भक बन गति मिल सकें, तकनीकी शिक्षा संस्थाओं में सामाजिक और सामाजिक अध्ययन के उद्देश्य कोर्स रखे जाने चाहिए जिससे मजठे दूसरे का विकास हो सके।

७३ देश में सार्वजनिक और निजी दोनों ही क्षेत्रों में एक व्यवस्थित विविधतापूर्ण औद्योगिक क्षेत्र का विकास हो चुका है, इसलिये उद्योगों की तकनीकी सतुतित व्यवस्था कायम रखने में और शोध तथा विज्ञान के आधार का निर्माण करने में बिदे तकनीकी जनशक्ति का उचित उपयोग करने में अपनी अधिकाधिक मूल्य का करना चाहिए।

अनुसन्धान

७४ अनुसन्धान में औद्योगिक और सामाजिक विज्ञान पर बल होगा। संस्थाओं से यह क्षेत्रों की काती है कि वे उच्च स्तरीय शोध इन क्षेत्रों में करेंगे जो राष्ट्र के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। जैसे—ऊर्जा के साधन और सामाजिक विकास के लिए तकनीकी।

८-कृषि शिक्षा

अध्ययन के कोर्स

८.१ सभी प्रदेश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार होना चाहिए और कृषि के विविध कार्यों के माध्यम से अपने आप काम में लगने पर बल देना चाहिए। कृषि विश्वविद्यालयों को बड़ा तक दे हों, कृषि तथा सम्बन्ध क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए प्रदेश-व्यापी जिम्मेदारी लेना चाहिए। प्रत्येक कृषि विश्वविद्यालय में एक सुदृढ़ अनुसंधान केन्द्र, प्रत्येक कृषि सम्प्रदायी पक्षबाधु क्षेत्र में रचना चाहिए, जिससे स्थल विशेष के लिए अनुसंधान किया जा सके। कृषि विश्वविद्यालयों को कृषि विकास से सम्बन्धित राज्य स्तरीय अध्ययन और सुविधाओं अनुसंधान करना चाहिए। दूसरे विश्वविद्यालयों के कृषि विभागों और संकायों की, जिन के पास आवश्यक समता है, सहायता इस दृष्टि से की जानी चाहिए, जिससे वे कृषि शिक्षा के पूरक कार्यक्रमों का विकास कर सकें।

सम्बन्धन

८.२ कृषि विश्वविद्यालयों और विकास विभागों के बीच में समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए, जिससे नयी तकनीक पाठों को स्थानांतरित किया जा सके। कृषि विश्वविद्यालयों को मनोरंजन शिक्षा के कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए, जिससे पंचाचार कोर्से भी सम्मिलित होंगे। इससे ग्रामीण तमाम की जातीयवादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निरन्तर शिक्षा की जा सके।

कृषि विज्ञान केन्द्र

८.३ कृषि विश्वविद्यालयों तथा उपयुक्त स्वयं सेवी समितियों को कृषि-विज्ञान केन्द्रों का संयोजन और संयोजन करना चाहिए जिससे ग्रामीण युवकों को सम्बन्धित कोर्सों में प्रशिक्षित किया जा सके और वे शोध शिक्षा के कार्यक्रमों में भाग ले सकें।

६ चिकित्सीय शिक्षा

६.१ चिकित्सीय शिक्षा के क्षेत्र में जो शिक्षा की जाती है विशेष रूप से स्नातक स्तर पर वह अध्ययन की आवश्यकताओं पर आधारित होती है और बड़का बहुत कम सम्बन्ध देश की वास्तविक समस्या स्वास्थ्य रक्षा की आवश्यकताओं से रहता है। फलस्वरूप अहाँ भूमिगत चिकित्सीय पद्धति में विश्व के विकासों के साथ अपनी प्रति अधिकतर ठीक रहो है, वहाँ हमारे वैदिक कालों में निकले हुए स्नातक समाज की आवश्यकताओं को पूर्ति करने से सम्बन्ध में और उस स्तर की समस्याओं और परिस्थितियों को सुनाने में असमर्थ रहते हैं। अतः हमारी चिकित्सीय शिक्षा को स्वास्थ्य जन शक्ति की आवश्यकताओं के वास्तविक भूस्थान के आधार पर पुनर्गठित होना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यवस्था को इस प्रकार समुल्लेख करना चाहिए, जिससे वह समाज की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुकूल हो सके।

६.२ इसके साथ ही वैसी चिकित्सा पद्धति (परंपरागत चिकित्सा पद्धति) जैसे मानुष, युगानी, मित्राण, प्राकृतिक चिकित्सा और होमियोपैथी यों की उपेक्षा के परभाव अपना स्थाय प्राप्त कर रही है। राष्ट्रीय सरकारों के उचित उपयोग की दृष्टि से यह आवश्यक है कि वे सब पद्धतियों और आयुर्वेद पद्धति में अपनी सीमाएं और क्षमताएं समझे। परस्पर एक दूसरे को सहयोग दें और एक दूसरे से प्रेरणा प्राप्त करें।

१०-संस्कृति

संस्कृति और शिक्षा का सम्बन्ध

१०.१ परम्परागत और आजकल के सांस्कृतिक तथ्यों का औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा से समन्वय सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र प्रवास होना चाहिए। शिक्षा पद्धति ने देश की समृद्ध और विविध विरासत का और उन विरासत सांस्कृतिक संस्करणों का, जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से निचले हुए समाज में उपलब्ध है, अभी तक पूरा साम नहीं ठहरा है। इन सभी संतापनों का

प्रयोग किया जाना चाहिए और उन्हें सभी स्तरों में शिक्षा के ठाने-बाने में बुना जाना चाहिए।

११-शारीरिक शिक्षा

शिक्षा के अनिवार्य अंग के रूप में शारीरिक शिक्षा—

११.१ शारीरिक शिक्षा जिसमें खेल-कूद, रेजि खेल, योग, व्यायाम तथा घाटुस की भावना के बढ़ाने वाले कार्य समावेशित हैं, शिक्षित स्तरों पर शिक्षा का अंग होना चाहिए। बालकों और बालिकाओं को प्रविष्टा शास्त्र करने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए और उन्हें ऐसी सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए, जिससे वे अपनी समस्याओं का विकास कर सकें और खेल-कूद की दक्षता में राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रीय स्पर्धाओं को प्राप्त कर सकें। सभी स्तरों पर स्वास्थ्य और शारीरिक योग्यता के लिए व्यावहारिक ज्ञान दिया जाना चाहिए।

१२-शिक्षा का माध्यम

माध्यम और भाषा का अध्ययन—

१२.१ सभी स्तरों पर शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। आश्चर्य की बात पर शिक्षा का माध्यम हिन्दी भाषा होनी चाहिए।

१२.२ स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षण भाषा एक विदेशी भाषा के शिक्षण की सुविधा प्रदान की जाती है जिससे शिक्षार्थी अपने अपने मातृ भाषा क्षेत्र में विश्व की विशेषता और सम्पूर्ण जीवन को सीखें और समझ सकें।

१३. त्रिभाषा सूत्र

१३.१ माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र का क्रियान्वयन किया जाएगा। इसमें हिन्दी भाषा प्रदेशों में हिन्दी और अंग्रेजी के अतिरिक्त एक आधुनिक भारतीय भाषा का अध्ययन करना होगा। यथासम्भव क्षमता की भारतीय भाषा हिन्दी भाषा क्षेत्र प्रदेशों में क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी का अध्ययन करना होगा।

१४. भाषाओं का विकास

१४.१ भाषा शिक्षण की तकनीकों में सुधार लाने का प्रयास किया जाएगा।

१४.२ भारतीय भाषाओं और साहित्य में विकास के लिए प्रयास जारी रखा जाएगा और सुदृढ़ किया जाएगा।

१४.३ अधिकांश आधुनिक भारतीय भाषाओं को सरलता से किशोर किशोरी रूप में प्रभावित किया है। सरलता के अध्ययन को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रयास किया जाएगा।

१४.४ अन्य प्राचीन भाषाओं के अध्ययन को प्रोत्साहित किया जाएगा।

१४.५ एकलिंग भाषा के रूप में हिन्दी के विकास और प्रचार को बढ़ाने वाले कार्यक्रमों को सुदृढ़ किया जाएगा।

१४.६ स्कूलों के अध्ययन को उचित माध्यम और प्रोत्साहन दिया जाएगा।

१४.७ विदेशी भाषा में अध्ययन की भी प्रवृत्ति दिया जाएगा।

१५. परीक्षा सुधार

परीक्षाओं का स्थान

१५.१ परीक्षाएँ विशेषकर वे सार्वजनिक परीक्षाएँ आधुनिक अधिक प्रतुनिधित्व और विपरीत होती चाहिए? मूल्यांकन के द्वारा शिक्षक अपने शिक्षण की प्रभावशीलता समझ सकते हैं और शिक्षार्थी अपने सीखने के प्रयासों के परिणाम का मूल्यांकन कर सकते हैं। इस प्रकार मूल्यांकन, शिक्षण और आत्मनिर्भर प्रशिक्षण, जिसमें पाठ्यक्रम की विषयवस्तु और शिक्षण विधियों को सम्मिलित है, दोनों में ही सुधार लाने के साधन के रूप में कार्य करता है।

१५.२ मूल्यांकन की विधि ऐसी होनी चाहिए, जिसमें छात्रों को हस्तक्षेपित किया जाए और वह अपनी क्षमता को प्रकट कर सकें। शिक्षण और पाठ्यक्रम के कार्यक्रमों के सम्पूर्ण जीवन में अनुभवों को उचित सम्मिलित किया जा सके।

सार्वजनिक परीक्षाएं

१५.३ सामान्यतः पुरी शिक्षा की अवधि में स्नातक

संरचनाओं के विवेक अधिकांशों को उच्चिन्न मानना दोषपूर्ण है।

क्षेत्रीय वसन्तुलन—

१७१ कुछ राज्यों देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा शिक्षा के क्षेत्र में विद्यमान हैं। अतः तथा सम्बन्धित राज्यों को समान स्तर पर आने के लिए सामान्य रूप से शिक्षा के क्षेत्र में विशेषरूप से व्यवस्थापन रूप से कम समय में साक्षरता को उत्तमोत्तम बनाने के क्षेत्र में विशेष प्रयास करना चाहिए। ऐसा ही देखा गया है कि एक ही राज्य के अर्धवर्ग मंत्री क्षेत्रों में शिक्षा का विकास एकत्र नहीं है। इससे शिक्षावासी योजना व्यवस्था में बहुत प्रभाव की व्यवस्था की जा सकती और क्षेत्रीय योजना पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है। इससे यह निमित्त हो सके कि सभी क्षेत्रों में विद्यमान विद्यमान स्तर को ऊपर उठाने के लिए सहजता हो जा सके।

विकासकों के लिए शिक्षा—

१७७ सभी विकासक वर्गों के लिए उच्च शिक्षा सुविधाओं का विस्तार करने हेतु हम प्रयास किया जाएगा। अधिक विकासक वर्गों के लिए उचित परिधि में शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी जिससे उनकी समस्याओं का पूर्ण विकास हो सके। अन्य वर्गों सामान्य स्तरों में रहे जा सकते हैं और उन्हें आवश्यक अभिरक्षित सुविधाएँ दी जा सकती हैं। विकासकों के लिए उच्चतम पाठ्यक्रम और शिक्षण तकनीकों का विकास, अनुसंधान तथा अन्य देशों में प्रयुक्त तकनीकों के अध्ययन के आधार पर विचारित की जानी चाहिए।

१८. अध्यापक—

अध्यापकों की भूमिका—

१८१ सभी स्तरों पर शिक्षा में सुधार लाने के लिए अध्यापकों को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। इसके लिए उन्हें सर्वसाधारण साक्षरता और प्रेरित होना चाहिए और अपने व्यवसाय के प्रति उच्च गौरव या अनुभव करना चाहिए। सभी स्तरों पर अध्यापकों के व्यावसायिक

गुणवत्ता उन्नत करने के लिए उचित उपाय किए जाने चाहिए। शिक्षकों की अनुसंधान तथा परिवर्तन करने के लिए वैज्ञानिक स्वतंत्रता सुनिश्चित होनी चाहिए।

१८२ अध्यापक वर्ग का अपन उच्च शिक्षा प्रति उत्तरोत्तर जगत्कृत होना चाहिए जो उन्हें देश के सभी नागरिकों के जीवन और चरित्र के निर्माण में सम्मेलन प्राप्त है। इससे लिए राष्ट्रीय सामाजिक पुनर्निर्माण के कार्य से प्रतिबद्ध होकर वह स्वयं आदर्श नागरिक बनना चाहिए।

अध्यापकों की शिक्षा—

१८३ प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर अध्यापकों की शिक्षा का उद्देश्य है उचित परिदृश्य दिए जाने से जिससे शिक्षा में सुधार आने लगे। शिक्षा अपनी उचित सुविधा अर्थात् परीक्षाएँ, उच्च शिक्षा में भी अध्यापकों के लिए विद्या विज्ञान सम्बन्धी और व्यावसायिक सुविधाएँ सुनिश्चित होनी चाहिए। सरकार प्रशिक्षण की सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। पाठ्यक्रमों और सहायक शिक्षण सामग्री का विकास करने के लिए, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में अध्यापकों के साथ ही शिक्षा और चरित्र तथा मनोवैज्ञानिक शिक्षा की व्यवस्था के लिए केन्द्र स्थापित किए जाएंगे।

१९ सामाजिक सहयोग—

स्थानीय सामाजिक सहयोग—

१९१ स्थानीय समितियों की स्थापना करके एक क्षेत्र में विद्यार्थियों को स्थानीय समाज से सहयोग करना प्रोत्साहित होगा। ये समितियाँ सरकारी से वैज्ञानिक सुविधाओं में सुधार लाने और अधिक दक्षता के काम करने के लिए विद्यार्थियों को सहयोग करेंगी।

२० स्वैच्छिक सहयोग—

राष्ट्रीय नीति को कार्यान्वित करने के लिए जो कार्य कम बनाया जाएगा उसके समर्थन और सहयोग के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा।

२१. जल सत्यको की शिक्षा—

सरकार इस बात को जानती है कि धार्मिक और मायावी अलसत्त्वको द्वारा संचालित संस्थाओं ने देश की समुक्त संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान किया है। सरकार इस बात को भी जानती है कि उन्हें इच्छानुसार कामून सम्मत ऐसी संस्थाओं को स्थापना करने और धराने के लिए अधिक है जिससे सम्बन्धित भारतीय समाज का लक्ष्य पूरा हो सके।

२२. शिक्षा में लागत—

२२१ बेस में शिक्षा पर सरकारी व्यय निरन्तर बढ़ता रहा है और अब प्रति वर्ष २८०० करोड़ लक्ष हो रहे हैं। जो नीति उनपर निर्धारित की गयी है उसे कार्यान्वित करने के लिए अधिक धन की व्यवस्था करनी होगी फिर भी धन का अभाव करके उपलब्ध संसाधनों, के प्राधिकारों का और प्रभावी उपयोग करके तथा ऐसे कार्यक्रमों 'कार्य के लिए प्रयत्न' जैसे कार्यक्रमों द्वारा लोगों की प्राप्ति के लिए प्रयास होना चाहिए।

२२२ सामाजिक और उच्च शिक्षा की कक्षाओं में

आवासी के कम कमों से नीस सी जा सकती है जो ऐसी घर घर दे सकते हैं जिसका उचित सम्बन्ध शिक्षा की व्यवस्था करने के लक्ष्य से हो।

२२३ स्थानीय समाज से नकद तथा अन्य स्थापक रूप से, वर्तमान की अपेक्षा अधिक समर्थन करने के लिए प्रोत्साहन मिलना चाहिए।

२२४ यह ठीक है कि नीति को त्रिविधित करने के समूहों प्रयास में धार्मिक सामंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। किन्तु उससे भी महत्वपूर्ण स्थान दाइस से प्रतिबद्ध मानवीय धर्म, मानसिक और नैतिक शक्ति का है। बिना इस मानवीय सहयोग के ऊपर निर्भरित करने के अनुसार शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन और विस्तार तथा गुणात्मक सुधार सम्भव नहीं है।

२३. पुनर्वासन—

२३१ भारत सरकार प्रत्येक ५ वर्ष बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्वय-व्यय का अवलोकन करेगी और अनुभव के आधार पर संशोधन करेगी।

हमें स्कूल को क्यों समाप्त करना है

अनुवादक—डॉ. देवेन्द्र दत्त तिवारी

(गतों से आये)

किन्तु ये बातें हमें प्रस्तावित इस अस्तित्व पर चर्चा से प्रारम्भ होना है कि कबरेस्टेन, तिवारी तथा उपस्थितियों सभी में कमो न कमो यह विचार्यत की है कि अमरीकी शिक्षा व्यवस्था दोषोपर शिक्षकों को बहुत कम प्रोत्साहन देती है जिससे अधिकांश शिक्षकों को उत्तम शिक्षा नहीं मिल पाती। इस प्रकार का प्रस्ताव दृष्टान्त अनुदान, जो शिक्षा पर सर्व शिक्षा आयोग, प्रस्तावित करके स्वयं अपने को नगिनीय बना देता है।

यह बात ऐसी है कि किसी लम्बे आदर्श को र्थवासी इस आधार से दे दो आस कि वह इसका प्रयोग सभी करे जब तक कि शरीर एक साथ भाव दिष्ट भाव। दृष्टान्त अनुदान कर जैसा स्वयं यह समर्थ है उसका दुरुपयोग न केवल दोषोपर शिक्षक करते हैं प्रायुक्त आतिथ्यादी धार्मिक स्कूलों के समर्थक तथा वे लोग भी करते हैं "जिनके स्वार्थ सामाजिक दृष्टि से विनाशित रहते हैं। सर्वोपरि बात यह है कि वैश्विक गहनता, जो शिक्षा व्यवस्था में प्रयुक्त होनी चाहिए, उन लोगों के हाथों में पड़ जाती है, जो ऐसे समाज में रहना चाहते हैं जिसमें सामाजिक प्रगति वारंवारिक ज्ञान पर आधारित नहीं है, बल्कि ज्ञान की लक्ष्य पर आधारित है जिससे द्वारा वह प्रगति वस्तु तथे के प्राप्त की जाती है। शिक्षा की धार्मिक गहनता के सम्बन्ध में जैसा के विवेचन में शिक्षा व्यवस्थाओं के पक्ष में यह भेदभाव प्रधानता रखता है और इससे शिक्षा के सुधार सम्बन्धी अर्थवत्ता व्यवस्था और महत्वपूर्ण है। निदान्त की अवधारणा होती है जिससे ज्ञानार्जन पर प्रत्येक व्यक्ति समोपार्थक शिक्षक की सक्रियता तथा धार्मिक निम्नोदारी पर बल दिया जाता है।

समाज को स्कूल से मुक्त करने का सर्वोपरि ज्ञानार्जन की प्रक्रिया के दो पहलुओं की आवश्यकता है। केवल कोशल के सम्बन्ध पर बल देना आवश्यक होता है। उद्योग कम बल ज्ञानार्जन की विभिन्न प्रक्रियाओं पर नहीं होता

चाहिए। किन्तु वास्तविकता यह है कि कोशल के ज्ञान में लिए भी स्कूल जीक जगह नहीं है और शिक्षा प्राप्त करने की दृष्टि से तो वह और भी खराब स्थान है। स्कूल दोनों काम बहुत खराब ढंग से करता है, हमका अधिकार यह भी है कि स्कूल दोनों बातों के अन्तर को नहीं समझता। स्कूल कोशल देने में असमर्थ है क्योंकि वह वास्तविकता को सीखाने में विविध रूप से रूढ़ा रहता है। अधिकांश स्कूलों में एक कार्यक्रम, जो किसी एक कोशल के सुधार के लिए होता है, सर्वत्र विमो दूधरे सम्बन्ध कार्य से जुड़ा रहता है। इतिहास की गणित की प्रगति से और वस्तु में उपस्थिति को खेल के मैदान का प्रयोग करने से जोड़ दिया जाता है।

स्कूल उन परिस्थितियों की व्यवस्था करने में और भी दुरी हैं जो अतिशय कोशल को मुक्त और गैरवास्तविक प्रयोग से सहायक होते हैं। इसके लिए मैं 'उत्तर शिक्षा' (तिवारी एडुकेशन) का प्रयोग करूँगा। इस स्थिति का मुख्य कारण यह है कि स्कूल के कार्य में एक अनिवार्यता है, और वह शिक्षा की व्यवस्था केवल स्कूल के लिए रहती है—अध्यापकों के साथ अवरोधनी रहना और इस तरह के और अधिक संघर्ष को प्रोत्साहन। जैसे कीशल को शिक्षा की वास्तविकता में सम्पूर्ण से मुक्त रखना चाहिए इसी प्रकार उत्तर शिक्षा को अनिवार्य उपस्थिति से अलग कर देना चाहिए। सर्वोपरि ज्ञान और रचनात्मक व्यवहार के लिये कोशल ज्ञान तथा शिक्षा को संस्थागत प्रक्रम द्वारा प्रोत्साहन दिया जा सकता है, किन्तु के माध्यम से और विरोधी प्रकृति के होते हैं।

अतः तो कोशल में सम्बन्ध से सुधार हो जाता है क्योंकि कोशल का सर्वोपरि परिचायक तथा अनुमान व्यवहार पर अधिकांश प्राप्त करना है। कोशल के शिक्षण में ज्ञान काव्यनिक स्थितियों पर निर्भर किया जा सकता है, विविध कोशल का सम्बन्ध सम्भव है। किन्तु शिक्षा

कार्य में बीजल ने विशेषाधिकार तथा सर्वनात्मक प्रयोग में अभ्यास पर निर्भर नहीं किया था क्षमता। शिक्षा, शिक्षण का परिणाम हो सकती है, यद्यपि यह शिक्षण जिसका परिणाम शिष्या हो, अभ्यास से बुनियादी तौर से शिष्ट होना। शिष्या अपनी प्रक्रिया के सहयोगियों के परस्पर सम्बन्धों पर निर्भर करती है, उनके पास ऐसी कृती होती है जो समाज के उन समस्याओं से परिचय कराती है, जो वह सुरक्षित रखता है। यह शिष्या उन सबके उस विशेषतात्मक उद्देश्य पर निर्भर करती है जो सरकारों का सर्वनात्मक रूप से प्रयोग करते हैं। यह शिष्या प्रयोग के अन्त्यात्मिक प्रयोग के परस्पर पर निर्भर करती है जो साधक और उसके सहयोगियों के लिए जान के ये द्वार खोलती है।

बीजल का शिष्य निश्चित परिस्थितियों की व्यवस्था पर निर्भर करता है जिसमें सामाजिक की निश्चित उत्तर देने का उद्देश्य करना पड़ता है। ऐश्वर्य निश्चित या शिष्या का कार्य यह होता है कि बीजल को देने के भागीदारों की एक दूसरे से मिलने में सह्यता दे जिससे सामाजिक सम्भव हो सके। वह ऐसे व्यक्तियों को सामाजिक बैठका है जिनके पास अपने ऐसे प्रश्न हैं जिनका समाधान उनके पास नहीं है। अधिक से अधिक वह सीखने वाले को अपनी समस्या से निश्चित करने में सहायता देता है क्योंकि समस्या ही दृष्टता में ही उसके अनुकूल और सामाजिक रखने वाले व्यक्ति मिल सकेगा जो सभी की तरह प्रेरित होकर उसी प्रश्न का समाधान उसी समर्थ में सभी समय साथ रहा है।

बीजल शिष्यों और सेवा के भागीदारों की अपेक्षा शिष्या की दृष्टि से सामाजिक रखने वाले भागीदारों का मिलना प्रारम्भ में अधिक बटित प्रतीत होगा है। इसका

एक कारण यह सम्भोदक रूप है जो स्कूल ने हमारे मन में जमा रखा है और जिसने हमें आसना पुक्त बना दिया है। बिना किसी मान्यता के बीजल के आशान प्रदान के परिणाम सराब बीजल के आदान-प्रदान की भासना से अनुमानित किए जा सकते हैं और इसीलिए आदान-प्रदान के उन असीमित क्षमता से कम खतरनाक है, जिसमें कोम मिलते हैं और ऐसी समस्या से सम्बद्ध होते हैं जो उनके लिए सामाजिक, बौद्धिक तथा मानवतात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है।

बीजल के अध्यापक वाली क्रोदरे अपने अनुभव से यह जानते हैं। उन्होंने अपने अनुभव से यह पाया कि शोध ४० घण्टों में अपना प्रारम्भ कर देता है, यदि पहले कुछ समय बिन्दु वह पहुँचावता है सामाजिक कार्य और सत्य रखते हैं। वह अपने अध्यापकों को गाँव में जाने के लिए कहता है और ऐसे कार्य लोगों के सिधे निर्देश देता है जो ऐसी महत्वपूर्ण समस्याओं से सम्बद्ध रहते हैं जैसे बीजल और सामाजिक के साथ पर पक्षदृष्टि ध्यान। सामाजिक गाँव के साथ इनके बीच दृष्टि पर विचार करने के सिधे दृष्टता होते हैं। वे यह समझने लगते हैं कि कार्य समापन पर ठहरा रह जाता है, यद्यपि उसकी दृष्टि समाप्त हो जाती है। अक्सर उनके जीवन के कार्य को उद्घाटित करने सकते हैं और समाज के रूप में उनका समाधान करने में वे अपने को समर्थ पाते हैं। निम्न बहुरा देता है कि जिस प्रकार गाँव के पिछार करने वाले लोगों की सामाजिक चेतना में विकास होता है और वे अपनी ही क्षमता से सामाजिक बहा उठाने के लिए प्रेरित होते हैं जिसकी क्षमता से वे जैसे-जैसे शिक्षा सीखते हैं, वे-वे-वे वे जीवन की वास्तविकता को भी करतमगत कर केने हैं।

(अन्त)

गांधीकुटी का संदेश

। प्रसिद्ध विचारक इयान इनिवर्न शारीर विज्ञान केन्द्र बर्था द्वारा तीसरी दुनिया के गरीबों के लिए सजीव विषय पर आयोजित गोष्ठी का उद्घाटन श्री गांधी आश्रम प्रतिष्ठान रोबाग्राम बर्था में किया। यहां वक्तव्य सारांश दिया जा रहा है। स० ।

मुहर कुज समय मैं मेरा नाम-आश्रय की इस कुटीर में बैठा था, वहाँ महात्मा गांधी रहने थे। तेजी कुटीर में रहती के पीछे बी उनको भोजन दहन करने की तथा उनका सेवा आत्मसाध करने का मैंने प्रयत्न किया। इस कुटीर की दो बीबी हैं। भरे भित्त पर सहस्र छाप प्रियेय रूप में अंकित की है। एक है उसका आध्यात्मिक गहन और दूसरी है उसमें रहती लक्ष्मी सुख-सुविधा। इस कुटीर के पोछे गांधी जी का बड़ा दृष्टिकोण है। इस कमरे में बी बीमिनी मैं करता रहा। मुझ उसकी सादरी मुहरता ■■■ सजाई धूम सम-द आसी। यह कुटीर लखने में प्रेम और समानता के सिद्धांत की घोषणा करती है।

गांधी फुटीर में सान प्रकार के स्थान हैं। प्रवेश करते ही एक जगह आप बूढ़े निवासे के ओर अपने की सादीरिए रूप से फुटीर के भीतर जाने के लिए तैयार करेंगे। फिर मध्य बड़ अटला है जो एक बड़े परिवार की मना लेने के लिए पर्याप्त है। आज और ये बार बने में बड़ा प्रार्थना मंडीत वा तब मेरे साथ बार सोम एक बीमार का सहाग मेकर बैठे थे। सामने की बार भी उतने ही लोगो को बैठन की अवहमी। यह बमरा प्रमा दे जहा हर कोई का सवता है, मिछ सवता है। बीसरी जगह भी, जहा गांधी जी स्वयं रहते थे। एक, बमरा अतिथियो के लिए और एक दूसरा बमरा बीमार के लिए है। एक मुला बरामदा है और एक अच्छा प्राणत स्नान गृह है। ये सब जगह एक दूसरे के साथ कित्तुव नैसर्गिकरूप से मलान दीखती है। उन सबने बीच एक आर्गनिक—दीवन और प्रत्यवान सभ्य है।

यह कुटीर बास मजदी और मिट्टी से बनी है। उसको बनाने में पत्थरों ने नदी किनारे बहुत सारे पत्थरों को इकट्ठा किया है। मैं उसे कुटीर कहता हूँ लेकिन हरीश्वर ने यह ही एक घर ही। दिल्ली में कुछ समय पहले जहाँ मगर रहना मुझा, वह मजदूर तरहर-तरहर की सड़क किनारे और अनुकूलताओं की दृष्टि से बसा था था। पूरा मजदूर ईंट व सिमेंट से बना था, और साते जैसा था।

तात्पर्य यह है बिबकी ये जो सब साजोसामान और तरह तरह की चीजें हमें प्रकट करत रहते हैं, वे हमें आंतरिक बन बढावि नहीं दे सकते हैं। वे सब तो हैं माओ बहुत मनुष्य की रचनाविद्या। जैसे-जैसे हमारे पास ये सब सुख सुविधाएँ बढ़ती जायेंगी। हम ज्यादा से ज्यादा उन पर निर्भर होते जायेंगे। हमारा जीवन दिन-दिन अधिप्राधिक सीमित बनता जायेगा। चाही कुटी भ भने जो फनीगर दखा है वह सब कुछ असम ही प्रकार का है वह हम प्रचार का है कि मनुष्य उस पर भवभावित बन जाये ऐसा कोई कारण नजर नहीं आता।

अविना मुद्रिषा न भया मवान् वताता है नि हम्
उतनी भाषा ये निबल बने हैं। जैसे हमारी जालवा
बढ़नी है बँस ही जसरी फूटि व लिए स्पष्ट हो गयी
चीन्ही पर हमारी निर्मलर को बढ़ती जाती है। यह ता
ऐसी बात है जैसे मोमो के बरोग्य व लिए हम्
नस्पतालो पर नियर रह और अपने बरवो की शिक्षा
व लिए स्कुलो पर। दुर्गम न नस्पताल और स्कुल
राष्ट्र के भारोग्य और बुद्धिपत्ता दर्शन दाश बोर्ड
गए हो वही है। वस्तुतः नस्पतालो की वधती हई

सो अनुदेशको के चुनाव के बाद भारत सरकार के प्रौढ शिक्षा मन्त्रालय के साथ सम्पर्क स्थापित करके अनुदेशको के प्रशिक्षण का कार्यक्रम बना। इस कार्यक्रम के निर्माण में हम निदेशक प्रौढ शिक्षा मन्त्रालय, का ए के जलामुद्दीन तथा डा. कैजनाथ सिंह जी वनस्पति शिक्षा मन्त्रालय का विशेष योगदान मिला। विशेष माहिर भी हम लोगों को मन्त्रालय द्वारा मिला। साथ ही हम इस कार्यक्रम में विशेष भाग्यदत्त श्री करण माई जी डा. बी. डी. डिवागी अध्यक्ष शिक्षा सभा में सम्पूर्ण-मन्त्र सहित विश्वविद्यालय का रहा। डा. जलामुद्दीन निदेशक राष्ट्रीय सेवा योजना गोरखपुर विश्वविद्यालय, और एन अग्रवाल परिसर मिर्जापुर फिलास्फर गोरखपुर डा. कृष्ण मुरारी सात अग्रवाल माध्याम श्री और डि. कालेज बैरिया, मदन सिंह प्रौढ शिक्षा सभा बैरिया, श्री अनुनाथ त्रिपाठी, सोहरी पाट आजमगढ़ श्री केशवप्रसाद श्री प्राचाय मन्वीर डि. कालेज कादवारानी तथा शिक्षाविद श्री कलम विद परमना मीन दवरिया का मिला। श्री तिहासन सिंह, श्री सुरभि नारायण मणि त्रिपाठी, मूलभूत कुलपति सम्पूर्णमन्त्र सहित विश्वविद्यालय पारसगढ़ी, श्री सातजी सिंह महा प्रणय रेलवे तथा आयुक्त गोरखपुर ने भी उदात्ततापूर्ण समय दिया। श्री विमुक्त प्रसाद त्रिपाठी, जित सविन उत्तर प्रदेश सरकार तथा श्री बनवन्त सिंह जिलाधीश गोरखपुर ने तो रात में ८-१० बजे २ जुलाई को पचार कर अनुदेशको के श्री प्रशिक्षण विचार में से सम्मोहित किया। श्री हसनमीन परिचोजना प्रसातक (प्रसार) गङ्ग परियोजना से श्री जङ्ग सत्योन्म मिला। श्री देवकुंज जी उपनिषाद समाज वस्त्राध ने विशेष समय दिया। प्रशिक्षण सिविल के सवालन श्री जित विहारी चन्द्रजी से

प्रशिक्षण के बाद सात मन्त्रा श्री ध्वजस्वा करन १० बेंगरी का सवालन १५ जून से और सेन १० १५ १५ गुर्गाई स शुरू कर दिया गया। प्रत्येक अनुदेशक को २० प्रौढ शिक्षा सभा दिया गया। इस तरह निर्मित सेनो का नाम इस प्रकार -- १-अग्रवाल श्री सेन

२-टंगोर सेन ३-अरविन्द सेन, ४ जयप्रभा सेन, ५-विनोबा सेन।

यह कार्यक्रम बिना जनसहयोग के सम्भव नहीं— अब प्रत्येक गाँव में प्रौढ शिक्षा समिति, जिसे हम लोक शिक्षण समिति कहते हैं— स्थापित की गयी। इन समितियों के संघोदको की मोटिफो और सिविलो का आयोजन होता रहता है। उनसे द्वारा समिति की विचार और गति मिलती रहती है।

आयोग सिविल, शिक्षित युवकों का सहयोग लिए बिना यह कार्यक्रम जन आन्दोलन नहीं बन सकता। इसके लिये प्रत्येक गाँवों में युवक शान्ति सेना की स्थापना की गयी है। इसका उद्देश्य सन्तो के विकास के साथ उनके द्वारा गाँव का विकास है। इनके प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है— इस सम्बन्ध में २ दिन का स्कालटिंग का सिलार और ३ दिन का शान्ति सेना का शिविर १०, ११, १२ सितम्बर को श्री अमरनाथ माई, अधिक भारतीय शान्ति सेना मदन द्वारा होने का रहा है।

अनुदेशको के सर्वप्रथम अपने अपने गाँवों का सर्वेक्षण किया और १५ से ३५ आयु के लोगों में सभी तैयारी करके ३० प्रौढों की कक्षा प्रारम्भ किया। प्रारम्भ करने के पूर्व कुछ सम्पर्क और आयोजन का भी कार्यक्रम रखा। इस सत्रों के सेनो और अध्ययन करने से बिना अनुभव मिले। इन सत्रों में २० सत्र महिलाओं के हैं। उनका भी प्रशिक्षण अनुदेशको के साथ ही होगा तथा उनको कुछ विशेष कार्यक्रम दिया गया और एक महिला सर्व-वेतिका भी है—उन्होंने इनका समय समय पर विशेष प्रशिक्षण ट्रेनिंग के दौरान हो दिया। इनसे गाँवों में महिला मण्डल भी बनाने की योजना चल रही है। साथ ही इस सेन में गाँवों में शक्ति स्थलों को सदा हज़ार से भी ज्यादा है। हम सोच पायी आधार से सम्पर्क करके एक ऐसा कार्यक्रम बनाना चाहते हैं कि जिस दिन जब श्रुत बदलन और रईस गाँवों आधार पर आती है— उस दिन गाँवों आधार के ही सहयोग से २, ३ घंटे का ऐसा कार्यक्रम हो जिसमें उन्हें आज के स्थिति तथा घरों की आज की समस्याओं का कार्यक्रम और परिवारिक सपाई, स्वास्थ्य, सन्तो का सानन आसन, मनुष्य, परि-

द्वार नियोजन तथा साक्षी इत्यादि पर चर्चा हो। इसका एक पाठ्यक्रम बने और कुछ सपनरूप से चीन के लिए चीन और उन मानों में स्थितों के चीन भी विपरसत्ता सम्भूतन और महिला मण्डल का कार्यक्रम चले। इस योजना को हम बिनीबा जयन्ती से शुरू करने जा रहे हैं और महिला पर्यवेक्षिका के देख-रेख में यह कार्यक्रम चलेगा।

अनुदेशको - द्वारा केन्द्रों पर कार्यक्रम चरती पर बनाने को जो अनुभव हुए और हो रहे हैं, वे जसाह-बर्द्धन और मार्गदर्शन हैं। लोगों को विभिन्न प्रतिनियार्थक हैं।

स्थानीय स्तर पर अध्ययन सामग्री तैयार करने में हम कार्य शुरू कर दिए हैं। इस सम्बन्ध में हम सासरता कीमत और व्यावसायिक कीमत को आज की स्थिति में तथा विकास के दिशा बलाओं से जोड़ कर एक सूत्र में बाँधने का प्रयास कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में 'द्वितीय' की अध्ययन सामग्री से भी हम सहायता लेने जा रहे हैं।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य जागरूकता व्यावसायिक कुशलता तथा साक्षरता है। प्रशिक्षण में भी इस पर बल दिया गया है लेकिन प्रौढ़ शिक्षक साक्षरता ही कार्य पर अभी बल दिया दे रहे हैं। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को एक दीर्घकालीन कार्यक्रम के रूप में चिन्तित करना मूल होगी—निष्कर्षता बरीबो में सबसे अधिक है साथ ही इस कार्यक्रम का निर्बन दलित एवं आर्थिक दृष्टि से निम्न वर्ग के लोके जिस से स्वागत किया है। साक्षरता को पारस्परिक भारण को रोजगार प्रदान कार्पात्मक साक्षरता के रूप में परिचित करने का प्रयास किया जा रहा है। बर्जिआई अक्षर है, फिर हमें इसके लिए सहयोग भी मिल रहा है।

सम्पन्न और निम्न वर्गों में इस कार्यक्रम के प्रति न जसाह है और न इस कोई सहूल दिया जा रहा है। मानों में स्थित पाठकों के कुछ प्राप्ताओं और भावनाओं की प्रारणा है कि प्रौढ़ शिक्षा पर सच समान के रूप में पर बालकों की शिक्षा पर साधन संपादन लागू-दायक होगा। प्रौढ़ शिक्षा संकेतों की और सामाजिक

दोनों दृष्टिकोणों से सामाजिक पूर्वाग्रहों को तोड़ने, लोगों को प्रतिष्ठा के आधारित जीवन के विचारों से जोड़ने के लिए अनिवार्य थी। साथ ही यह मानों के सर्वांगीण-विवाह कार्यक्रम है जिससे सभी गैर स्वतन्त्रता होगी, कोई वैरोजगार न रहे, और हर प्रकार से मुक्त हो। यह मुक्ति का आन्दोलन है। हर प्रकार का शोषण, जो चीन के आधार पर है सामाजिक, सांख्यिक, अर्थव्यवस्था, भाग्यवादिता इत्यादि सभी से मुक्त हो। एक ऐसे सहयोगी समाज का निर्माण हो जिसमें सभी प्रेमपूर्ण वातावरण का सृजन करके एक सच्चे समुदाय का निर्माण कर सके।

आज एक महीने से अधिक कार्यक्रम के संचालन का अनुभव है कि पूरे क्षेत्र में २० केन्द्र ऐसे हैं जिन्हें हम लगभग की सजा दे सके हैं। उसमें से हमारा अभिप्राय है जहाँ केन्द्र के लिए पर्याप्त सभी जगह हो तथा सुविधिपूर्ण रूप से सजा और सुव्यवस्थित हो। जहाँ प्रौढ़ की २५ अक्षर उपस्थिति हो, प्रौढ़ों में बेतन्ना का लक्ष्य हो और इस कार्य में सब सेते हो। साहित्य मूल्य भी शिक्षा में कुछ कार्यक्रम हो। लोक शिक्षण समिति तथा युवक संगठन साक्षि सेवा का निर्माण हो। महिलाओं की चीन कार्यक्रम हो। यदि वे स्थानीय रचनात्मक नमूने इस कार्य के लिए उत्तर रहे हो या भविष्य भाग्य कुछ क्रियेवरी बहुत कर रहा हो। साक्षरता का भी स्तर ठीक हो।

इसके बाद 'अच्छा' दूसरी श्रेणी के २५ हैं, जिनमें उपर दिए कार्यक्रम निर्धारित होकर व्यवस्थित १५ से २० तक है। केन्द्र का स्थान है स्थिति सन्तुष्ट है। सभी विभिन्न कार्यक्रम सपनात्मक जो दिए गए हैं—वे जो अभी चल रहे हैं। २५ ऐसे हैं जहाँ उपस्थिति १५ में नीचे है और ठीक केन्द्र का स्थान भी नहीं बन पाया है।

साथ ही यह भी अनुभव मिला है कि एक दर्जन केन्द्रों पर प्रौढ़, प्रौढ़ शिक्षा से आगे हैं। वे मास्टर का ही कार्य नहीं कर रहे हैं—बल्कि म आनेवाले प्रौढ़ों को इकट्ठा करने और सब प्रकार की व्यवस्था

सत्या लोगो के विरुद्ध हुए आरोग्य की और मृत्यु की बढ़ती हुई सत्या उनके बढ़ते हुए अज्ञान की सूचक है। उसी तरह जीवन में ऐसा सब सुख-सुविधाएँ अनेक प्रकार से बढ़ जाती हैं, जो उनमें मानव जीवन में सर्व-सामग्र्य की अभिवृद्धि कम से कम होती जाती है।

आज की परिस्थिति की विवचना यह है कि जिनके पास चित्त की व्याप्ति सुख-सुविधाएँ हैं उन्हीं के लोग व्याप्ति प्रविष्टि माने जाते हैं। जिन समाज में बीमारी को व्याप्ति महत्व दिया जाता हो, और वृद्धि के चक्रों के उपयोग करने वाले को धेड़ धिमा जाता हो, क्या उस समाज की अनेकता समाज नहीं कहा जा सकता ?

गांधी जी की कुटीर में बैठे बैठे मैं आज की इस विवचना और विपरीतता के बारे में खेदपूर्ण सोचता रहा। मैं इस मनोबल पर आया हूँ कि आज की हमारी भौतिक समझता हमें मनुष्य जाति के विकास की ओर ले जा रही है ऐसा मानना बिल्कुल गलत है। अब साबित हो चुका है कि हमारे आर्थिक विकास के लिए उत्पादन के बड़े बड़े औद्योगिक यन्त्रों की ओर व्याप्ति व्याप्ति इतिहास, कारखानों, औद्योगिक यन्त्रों की कोई जरूरत नहीं है। मेरे लिए एक बात बची हो गयी है कि ऐसे सब लोग तब, जब और जीवन की दृष्टि से दृष्टि होते हैं। ऐसे लोगों की ही, गांधी जिसमें रहे थे, उस कुटीर की अपेक्षा अधिक बड़ी जगह की जरूरत पड़ती है। ऐसा बरताना करके वे लोग सुख की एवं अपने जीवन व्यक्तित्व को निर्बल रूप से हथकड़ी कर देते हैं। अंतर्गर्हित, प्राणहीन बनावट की शरण जाते हैं। इस प्रक्रिया में वे अपने गरीब या लचीलापन और निम्न जिन स्थिति की अनुभूति हो जाने की शक्ति को खो देते हैं। अपने जीवन का तब भी गया देते हैं। प्रकृति के साथ उनके संबंध बाँट फटने हो जाता है और अपने मानवपुत्रों के साथ की निकटता भी कम हो जाती है।

आज के औद्योगिकारी को जब ये पूछा जा कि गांधीजी का सिवाया यह सरल अधिकतम आपकी समझ में क्यों नहीं आता ? तब वह कहते हैं कि गांधीजी का

रास्ता बड़ा बज्जिन है, सोच उस रास्ते से नहीं जा सकते। परन्तु सही बात यह है कि गांधी जी के सिद्धांत में बीच के बिन्दु दोनों दलानों के लिए स्थान नहीं है और केन्द्रित व्यवस्था के लिए भी गुंजाइश नहीं है। उन्हींलिए औद्योगिकारी, व्यवस्थापकों और राजनीतिज्ञों को गांधी जी के सिद्धांतों के प्रति खास आवेग नहीं है। मध्य और अहिंसा का इतना सरल सिद्धांत भी क्यों नहीं समझ में आता ? क्या लोगो की लगता है कि अहिंसा और हिंसा से उनका काम बढ़ेगा ? नहीं, ऐसा तो नहीं है। साधारण मनुष्य इतना जटिल समझता है कि सच्चे साधन ही उसका सच्चे धर्म की प्राप्ति करा सकते हैं। सिर्फ वे लोग इस बीच को समझने में इनकार करते हैं, निश्चय इसमें कुछ न कुछ स्थापित स्वरूप होता है। सभी लोग यह बात समझना नहीं चाहते। 'सभी लोगो' में मैं उस समय समावेश समझता हूँ, जिन्हें आज साधारण मनुष्य की अपेक्षा ऐसी सारी सुख सुविधाएँ प्राप्त हैं। वे लोग सब अपना हो गए हैं। उनके उपयोग का प्रकार ऐसा है कि सत्य को समझने की उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है। ऐसे लोगों के लिए गांधी को समझना, पहचानना मुश्किल है। सादरी और सरलता का उनके लिए कोई अर्थ नहीं है। दुर्भाग्य से उनकी परिस्थिति उ वे सत्य का ध्यान नहीं करने देती। उनका जीवन इतना उत्साह भरा और सज्जन बन गया है कि जिस काल में वे फँसे गये हैं, उससे छूटने की शक्ति उनमें नहीं बची है। भगवान का उपकार मान कि सभी भी मनुष्य लोगो के पास उसी दोष नहीं है कि वे सरलता और सादरी के सत्य के लिए सबकुछ छोड़ दें। जगत् में इतने अधिक दरिद्र नहीं हैं कि समझने की अपनी शक्ति गवा दें।

एक बात बिल्कुल सच हो जानी चाहिए कि आत्म-निर्भर समाज में ही मनुष्य का गौरव बढ़ सकता है। अन्तर्-अन्तर् हम सर्वोपयोगिता की दिशा में जाने बढ़ते जायेंगे जैसे जैसे मानवीय गौरव को हाथ पकड़नी रहेगी।

यह कुटीर समाज में साथ सरल होने से भिन्न मानवता का प्रतीक है। यहाँ स्वावलम्बन धर्मपद

राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा : एक प्रयोग

बाबा रामचदास सेवाश्रम देवनांव
रामचचन सिंह, संचालक

बाबा रामचदास सेवाश्रम देवनांव, देवरिया में १०० प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की स्वीकृति गत मार्च १९७६ में मिली और यह कार्यक्रम के अन्तर्गत १ वर्षकेअंदर और १०० अनुदेशनों का चुनाव करके प्रथम दिनांक था। पर्यवेक्षणों का प्रशिक्षण राष्ट्रीय प्रबन्ध कक्षों और माध्यमता निदेशन में हुआ, तथा १०० अनुदेशनों का प्रशिक्षण दो बार में आधे घण्टे की आधे घण्टे में सम्पन्न हुआ। प्रशिक्षण कार्य में हमें कमिश्नरी स्तर के सभी विभागीय अधिकारी, विश्वविद्यालय के अधिकारी एवं प्राचार्य, आय निदेशक, विभिन्न संस्थाओं तथा सार्वजनिक स्वयंसेवकों का पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ।

इन कार्यक्रमों की पृष्ठभूमि तथा प्रारम्भिक तैयारी गत जनवरी १९७५ में ही विशेषरूप से श्री अशोक शर्मा, मृत्यु शिक्षा सचिव भारत सरकार के देवनांव भागवत के समय से प्रारम्भ हुई। इन कार्यक्रम हेतु सचिव शाखाओं को कई वर्षों से निर्मित विभिन्न वैश्विक कार्यक्रमों तथा आचार्यकुल, संस्कृत ज्ञानि केन्द्रों द्वारा होता रहा। गोरखपुर मण्डल में आचार्यकुल के अनेक सम्मेलन हुए और १२५ शिक्षा संस्थाओं में आचार्यकुल की गोरखपुर हुई। राष्ट्रीय विचार, विश्वविद्यालय, कालेज तथा अन्य शिक्षा संस्थाओं में पढ़ाई तथा तथा १२५ शिक्षा संस्थाओं में राष्ट्रीय साहित्य प्रयोगों को स्थापित किया गया। इन कार्यक्रमों में डॉ० हरदत्त शर्मा, संयुक्त शिक्षा निदेशक तथा डॉ० देवेश्वर तिवारी, उप शिक्षा निदेशक की अमूल्य प्रेरणा और मार्गदर्शन मिला। डॉ० तिवारी को आचार्यकुल की दलों में मोटिवों को सम्बोधित की गयी थी। देवरिया में १९७७ में एक जनश्रमिक आयोग-कारिक शिक्षा सम्मेलन डॉ० हरदत्त शर्मा की, संयुक्त शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में किया गया था। इन

सब कार्यक्रमों का केन्द्र बाबा रामचदास सेवाश्रम, देवनांव, देवरिया ही रहा है और आज भी रहता है।

सबसे पहले प्रौढ़ शिक्षा कार्य की तैयारी की करण आई तथा श्री जेम्स साई की प्रेरणा और डॉ० देवेश्वर तिवारी की से मार्गदर्शन में जनवरी १९७५ से प्रारम्भ की गयी। सर्वप्रथम शिक्षा विभाग के अधिकारी जिला विद्यालय निरीक्षक, उपविद्यालय निरीक्षक, जी, पी. ओ. तथा मौरी बाजार और बंशालपुर प्रखण्ड के बी.पी.ओ. के सक्रिय सहयोग से १०० गांव का एक क्षेत्र निर्धारित गया। इस क्षेत्र के गांवों से सम्पूर्ण स्थापित हुआ तथा आधे घण्टे पर इस सम्मेलन में मोटिवों तथा शिक्षा की आवश्यकता हुआ। फिर मौरीबाजार और बंशालपुर ब्लॉक के सचिव विकास अधिकारियों के सक्रिय सहयोग से इन क्षेत्रों में १०० गांवों का सर्वेक्षण किया गया।

अक्टूबर १९७५ में गांवों के जगहों पर सप्ताह लगाया गया। उसके कार्यक्रमों के समापन समारोह में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का शुभारम्भ ३ गांवों में जिलाधीन श्री पुनिया, आई ए ए न किया। जिसमें डॉ० क्षमाशर्मा जी, श्री मधुसूदन शर्मा तथा न इन कार्यक्रमों में पूर्ण सहयोग दिया तथा श्री बी.बी.शर्मा की अध्यक्षता में सभी गांवों में शिक्षा के गांव सम्पन्न मानवा से आधे घण्टे पर बैठक इनके शैक्षणिक और आयोजन में लगे।

सभी अनुदेशकों को खोज प्रयोगात्मक रूप में प्रारम्भ कर दी गई थी। भारत सरकार द्वारा स्वीकृति मिलने पर गांवों के २ स्वयंसेवक व्यक्तियों की, जिनको इन कार्यक्रमों में प्रशिक्षण दिया है, एक क्षेत्र शिक्षा समिति बनायी गयी। इस समिति को सहयोग से अनुदेशकों का चुनाव हुआ। इनमें कुछ गांवों में दलित भाषा में बहिर्गर्दीयों को उपस्थित हुई, लेकिन विचारण भी हो गया।

पुरुष नियोजन तथा सादी इत्यादि पर चर्चा हो। इनका एक पाठ्यक्रम बने और कुछ सयनरूप से गाँव से लिए जाय और उन गाँवों में शिक्षकों के बीच भी निरक्षरता उन्मुख और महिला मण्डल का कार्यक्रम चले। इस योजना को हम बिन्दोवा जवाली से शुरू करने जा रहे हैं और महिला एवं शिक्षका के देश रेल में यह कार्यक्रम चलेगा।

अनुदेशकी द्वारा बेन्डो पर कार्यक्रम परती पर उतारने को जो अनुभव हुए और हो रहे हैं, वे उत्साहपूर्ण और मार्गदर्शी हैं। लोगों की विभिन्न प्रतिनिधार्थ हैं।

स्वाधीन स्तर पर अध्ययन सामग्री तैयार करने में हम कार्य शुरू कर दिए हैं। इस सम्बन्ध में हम साक्षरता योजना और व्यावसायिक कौशल को आज की चुनौतियों से तथा विकास के ज़रिया बलाओं से जोड़ कर एक सूत्र में बाँधने का प्रयास कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में पुस्तकों की अध्ययन सामग्री से भी हम सहायता लेने जा रहे हैं।

ग्रीड शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य ज्ञानरूपता व्यापक साक्षरता तथा साक्षरता है। प्रतिष्ठान में भी इस पर ध्यान दिया गया है लेकिन ग्रीड शिक्षक साक्षरता ही कार्य पर अभी धन बचाये दे रहे हैं। ग्रीड शिक्षा कार्यक्रम को एक संगठित कार्यक्रम के रूप में प्रतिष्ठान करना शुरू होनी—निरक्षरता गरीबों में सबसे अधिक है साथ ही इस कार्यक्रम का निर्वहन दक्षिण एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के सुते दिल के स्वागत किया है। साक्षरता की पारस्परिक धारणा की रोज़गार प्रवाह कार्यात्मक साक्षरता के रूप में परिचित करने का प्रयास किया जा रहा है। बटिमाई जरूर है कि हमें इससे लिए सहयोग भी मिल रहा है।

सम्पन्न और शिक्षित गाँवों में इस कार्यक्रम में प्रतिष्ठान उत्साह है और न इस कोई महत्व दिया जा रहा है। गाँवों में शिक्षा वांछितों के कुछ प्राचार्यों और भाचार्यों की धारणा है कि ग्रीड शिक्षा पर न धन खर्च करने पर बालकों की शिक्षा पर साधन खर्चाना लाभदायक होगा। ग्रीड शिक्षा तकनीकी और सामाजिक

दोनों दृष्टिकोणों में सामाजिक पूर्वाग्रहों को तोड़ने, लोगों को मस्तिष्क की आधुनिकीकरण के विचारों से जोड़ने के लिए अनिवार्य थी। साथ ही यह गाँवों के सर्वांगीण विकास कार्यक्रम है जिससे सभी लोग स्वावलम्बी हो कोई बेरोज़गार न रहे और हर प्रकार से मुक्त हो। यह मुक्ति का आन्दोलन है। हर प्रकार का घोषण, जो गाँव के आधार पर है सामाजिक, आर्थिक, जलविस्थापन, स्वास्थ्यविज्ञान इत्यादि सभी से मुक्त हो। एक ऐसे बहुमुखी समाज का निर्माण हो जिसमें सभी प्रेमपूर्ण माता-पिता का ध्यान करने एक सच्चे समुदाय का निर्माण कर सके।

आज एक महीने से अधिन कार्यक्रम के संचालन का अनुभव है कि पूरे क्षेत्र में २० सेंटर पुरे हैं जिन्हें हम उत्तम की सहाय्य दे सके हैं। उत्तम में हमारा समिन्ध्रान है जहाँ सेंटर के लिए पर्याप्त छात्रों जमा हो तथा सुविधिपूर्ण रूप से सेवा और सुव्यवस्थित हो। जहाँ प्रोडों की २५ अक्षरत उपस्थिति हो प्रोडों में पैठना आ गयी हो और इस कार्य में धन लेते हो। साहित्य धुनन भी दिया है कुछ कार्यक्रम हो। तीन शिक्षण समिति तथा मुख्य सगठन साहित्य रीता का निर्माण हो। महिलाओं के बीच कार्यक्रम हो। गाँव में स्वाधीन रचनात्मक मनुष्य इन कार्य को लिए उभर रहा हो या भागे भाकर कुछ जिम्मेवारी बहुत कर रहा हो। साक्षरता का भी स्तर ठीक हो।

इसके बाद 'अच्छा दूसरी थोड़ी' के २५ हैं, जिनमें उपर दिए कार्यक्रम विस्तार होकर व्यवस्थित १५ से १० तक है। सेंटर का स्थान है लेकिन मनुष्यवित है। सभी विभिन्न कार्यक्रम सगठनात्मक को लिए गए हैं—वे जो अभी बन रहे हैं। २५ ऐसे हैं जहाँ उपस्थिति १५ से नीचे है और ठीक सेंटर का स्थान भी नहीं बन पाया है।

सम ही यह भी अनुभव मिला है कि एक अलग सेंटर पर ग्रीड, ग्रीड शिक्षण के साथ है। वे मास्टर का ही कार्य नहीं कर रहे हैं—बल्कि वे आनेवाले प्रोडों को इकट्ठा करने और सब प्रकार की व्यवस्था

और सहयोग में आते हैं। एवं स्थान पर एक पौध ने बताया कि हमारे लिए तब बड़हन बात बा कि बिग भरी बाकान धूर हो जात बा—हम पुरान कुदारी न पटा टपके बाड़ी जब राति क बजाद से सब जा जासा। ऐसी ही चर्चा कई जगह सुने में मिली।

महिलाओं ने भी २० म १२ नेट्र अप्त हैं। ५ की स्थिति आमत से भी नीचे हैं। उसको लिए प्रयास हो रहा है।

एक १० गांव का ऐसा क्षम बना है जिसमें स्थानीय नेतृत्व-विशेषरूप से कार्य समाप्त रहा है। उस क्षम में विशेषरूप से कार्य करने का कार्यक्रम बनाया जा रहा है। इसी गांव के कार्यक्रम की बिकसित करने के लिए स्वेच्छा से ही अवकाश प्राप्त जिला पंचायत राज वर्य अधिकारी ने जो इस क्षम के निवासो हे अपने ऊपर

(पृष्ठ २९ का शेवाश)

है। हमें समझ सेना वास्तिक कि मनुष्य अनारक्षक भीतो और साधनो का नितना ज्यादा सपष्ट करता जाता है। उतनी माया में अपने आसपास की परिस्थिति और वातावरण से आनंद प्राप्त करने की उसकी गति घटती जाती है। इसीलिए गांधी ने बार बार कहा है कि उत्पादकता की हमारा अपनी ज़रूरतों की सीमा में ही रहे। परन्तु उत्पादन का आज का प्रकार ही ऐसा है कि जो किसी प्रकार की सीमा की ही नहीं मानता। बरिब बिना दिन केतहासा उत्पादन रहते रहते में ही पचसा मानता है। आज तक यह सब हम सत कामे हैं। परन्तु अब समय का गया है उस मनुष्य की समय सेना बाहिर कि असा पर अधिक निभर होत जाने में यह अपना ही आसपास कर रहा है।

समर्पित समय दुनियां अब यह बात समझने लगी है कि यदि हमें विनाश करना है तो उपरोक्त माय टोक नहीं है। व्यक्ति ने और समाज ने स्वयं के लिए यह स्पष्ट है कि लोग स्वयं अपनी प्राथमिक आवश्यकताएं ही अपने पास रखें। हमें ऐसी कोई पद्धति ढूँढ निकालनी चाहिए जो इस विचारधारा के प्रतिपक्षीय प्रयत्न की दुनियां में मुश्किल बाधन परित्यक्त कर दे। यह मूल्य-परवतन वास्तविक दबाव से नहीं हो सगा। नदित समस्याओं के द्वारा भी यह बाध नहीं अनेका। इसमें लिए गैर-जागति पर वातावरण बनाया पड़ता।

जिया है। साथ ही स्थानीय लोगों के सुझाव में मैं इस अपना क्षम मान लिया है।

जब सहयोग उन गांवों में ज्यादा मिल रहा है जहाँ पिछले वर्ष में निरक्षर लोग हैं। वे निरक्षर साधारण हैं। वे चाली हैं विचारवान हैं उनके जीवन के मूल्य हैं। उनका जीवन धर्म आधारित है। वे हृदय प्रमाण हैं और उनके हृदय में बल्लभ और स्नेह है। धननिष्ठा व साथ स्वयंपरक्षणता बिनामता और गान्धिमिता है। वे सरल और मोद हैं अतः आभावा के विचार कम पाते हैं। उनके जीवन और जीविका में अनुग्रह है। अतः हमें सा इतिक मृजन का स्रोत है। ऐसा आवास होता है कि प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम द्वारा पीछा से मुक्त होने के लिए पीछित स्वयं सहा होना। २०

लोगों की यह समझना पड़ता कि समाज में मुक्ति की चीज चीनसी है।

आज तो मोटरधार रखने वाला मनुष्य साइजिन वाले से अपने की शक्ति मानता है। परन्तु यदि इतना और हम स्वसाधारण की दृष्टि में देखें तो ध्यान में लायें कि मोटर की अपेक्षा साइजिन ही स्वसाधारण लोगों का वाहन है। इसलिये वस्तुतः सबसे अधिक महत्व साइजिन को देना चाहिए। पहले एक वाहन स्वयंभार बगैरह सब प्रकार का आयोजन भी सामाजिक की केन्द्र में रख कर हाना चाहिए और मोटर की रीज समाप्त विनशुना चाहिए। परन्तु आज परिस्थिति इससे ठीक उल्टी है। आज तो पूरा आयोजन मोटर की ध्यान में समर्पित किया जाता है। साधारण मनुष्य की ज़रूरतों का प्रति विचार ध्यान नहीं दिया जाता। सारा विचार धन बिना लोगों की ज़रूरतों का धारें में ही दिया जाता है।

गांधी का यह कुटीर दुनिया को बता रहा है कि साधारण मनुष्य का मोरख किश प्रकार रक्षाया जाय। सदी सरलता सेवा और स्वयं का पालन कर हम नितना आनन्द प्राप्त कर सकते हैं। इस बात का भी यह गांधी-कुटीर एक प्रतीक है। गांधी-कुटीर का यह संदेश हम आत्मसाद करें।

वर्तमान संदर्भों में गांधी जी के शैक्षिक चिन्तन का महत्त्व

कु० कमला द्विवेदी

अक्सर तो यही सत्यते हैं कि गांधी एवं राजनीति से और उनका विचार से कोई सीधा संबंध नहीं था। इसी आम धारणा यह है कि गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा के रूप में जो कुछ विचार देना बोधिया उसका आशय नये 'संदर्भों' में तो कोई महत्त्व है, न उसकी कोई उपयोगिता ही है। भला यह मत है कि गांधी जी का संस्कार में वे दोनो धारणाएँ अत्यंत प्रमुख हैं। न तो गांधी जी मूलतः राजनीतिज्ञ हो पड़े और न उनका विचार किसी एक ही ओर था—यह कुछ था। गांधी जी न मनुष्य जावन को सर्वत्र समग्र दृष्टि से देखा जिसमें राजनीति अथ मम आदि अपना-अपना रूप न रखते थे। उनका चिन्तन सामाजिक और आर्थिक मूल्यों पर आधारित था। इसीलिए उन्होंने कहा था कि यदि भिक्षा के सिद्धांत का हनन पर ध्यान देना तो जनता दिव्य हो में उस स्वीकार नहीं करेगी। इसका अर्थ यह है कि गांधी जी पूर्ण मानवता को अपनी दृष्टि में रखते थे।

गांधी जी न बुनियादी शिक्षा की जो बातें उही यह धर्म देना की हास्यपूर्ण अवधारणाओं से सम्बद्ध की किन्तु बुनियादी शिक्षा के सिद्धांत वास्तव में शास्त्र और साधन हैं और इसीलिए किसी का यह दावा नहीं होना कि उनको निरन्तर की दृष्टि से देना। बोझी प्रयोग न सत्य सत्य में स्वीकार किया है कि बुनियादी शिक्षा के सिद्धांत सत्यम् है। अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की (१९७६) की घोषणा भारत सरकार ने की है उसमें भी गांधी जी के शैक्षिक सिद्धांतों का अनुसरण करने की बात नहीं कही गई है। इसलिए ऐसा समझना कि गांधी जी के शैक्षिक सिद्धांतों की नव सदियों में आवश्यकता नहीं है नम से नम जातिवार्तिक समाप्त हो स हिंद नहीं होता। फिर प्रत्यक्ष यह उल्टा है कि नये आम धारणा यह कभी हुई है कि गांधी जी के शैक्षिक सिद्धांतों की आज अपादेयता नहीं है।

इसका कई कारण हैं। एक तो यह कि अर्थों की हस्त में हमारे मन में शिक्षा की या सत्यता कभी थी यह आज भी मिटी नहीं है और आज भी अच्छी शिक्षा उही सज्जी जाती है जिसमें अच्छी नींवरी मिल सके। इसमें अतिरिक्त के सम्पूर्ण विज्ञान का कोई महत्त्व नहीं है। दूसरा कारण यह है कि गांधी जी न जो शिक्षा के सिद्धांत प्रतिपादित किये उनमें आज के समय पर अधिक बल दिया गया। हाथ द्वारा उत्पादन कार्य को ही शिक्षा का माध्यम माना गया। आज भी शिक्षा का काम उच्च वर्ग के ही लोग प्रान्त करते हैं। वे ऐसी शिक्षा की विवृष्ट सम्पत्ते हैं जिसमें शरीर का धर्म या हाथ से महत्त्व ठरती पडे। तीसरा कारण यह है कि योगी क मन्दय आधुनिक विज्ञान से प्रान्त सुविधाओं का प्रति बड़ा आकर्षण है। वे आवश्यकता न होते हुए भी मोटर पर चढ़ने का स्वप्न मनो है। अल्प मोक्ष में ही अज्ञानमूलक की सुविधा माहृत हैं। बल वारंशों के उत्पादकों पर अपनी जिदगी बसर करना चाहते हैं चाहे उनसे विज्ञान ही निमाधकारी प्रवृत्त क्यों न हो रहा हो। चौथा कारण यह है कि उच्च वर्ग के हाथ में ही प्रशासन की चाकरी है और वे गांधी जी के शैक्षिक सिद्धांतों की माह्र प्रशंसा करते हैं और भीतर ही भीतर उनको पूषा करते हैं। धर्म के अपने की शिक्षित सज्जते हैं किन्तु वास्तु उतने अधिक बुनियादित देन में नम लोग होते नमो कि उन्होंने अनुचित सुविधाओं प्राप्त कर दूसरों को पीछ रखने की चाल मीठी है। उन्होंने विवृत परीक्षा प्रणाली के आधार पर सुस्वाभाव ज्ञान प्राप्त करने समाज के व्यावहारिक जीवन से अलग की अलग रखा है। उनका दृष्टिकोण मनुचित और स्वाभाविक होता है। ऐसे लोग अर्थों के समय में भी और आज भी प्रशासन की रीढ़ समर्थ जाते हैं। गांधी जी के विचारों को ध्वनित करने की जिम्मेदारी मुख्यतः इही लोग पर है।

हम पुराने और नये सन्दर्भों पर विचार करें। आज गांधी जी के दार्शनिक चिंतन की आवश्यकता और भी अधिक प्रतीत होती है। आज उद्योग और तकनीकी के विकास के कारण लोग गहरो में सिमटने जा रहे हैं वही जाने पीने रहने विश्राम करने, शिक्षा प्राप्त करने की मुविधा अधिकांश लोगों को नहीं मिल पाती है और बड़े-बड़े नगरों के जीवन को यदि देखा जाए तो वहाँ के वातावरण में बीना इन्सान के लिए भुविबल हो रहा है। बड़े बड़े शल्य-कारखानों के कारण न केवल आर्थिक विपत्तियों को प्रथम मिल रहा है बल्कि समस्त वातावरण प्रदूषित हो रहा है। समाज और परिवार का विघटन बड़ी तीव्रता से हो रहा है। अगल में रहने वाले व्यक्ति को लोग नहीं पहचानते और न उसके दुष्परदा को समझने की प्रयत्नियों को प्रोत्साहित ही है। विद्या-भूषण बति-पत्नी, माई बहन के सम्बन्ध आर्थिक शिन्धो पर टकरा कर चूर-चूर हो रहे हैं। आज यह स्थिति केवल इस देश की ही नहीं है प्रभुत्व विषय में उन सभी समाकल्पित प्रगतिशील देशों की है जो अपने को सम्पूर्ण समझते हैं।

वही नहीं आज विभिन्न राष्ट्रीय विध्वंसक सम्प्राप्तियों के निर्माण में लगे हुए हैं। जो करीब है ये भी अनुभव बनाने की तैयारी में हैं। यह कहा जाता है कि विभिन्न राष्ट्रीय ने आज इतने विनाशकारी बम बनाकर रख लिए हैं कि जितने एक बार बम दम बार यह पृथ्वी निष्प्राण की जा सकती है।

यह हमारे मते सत्य है। इनसे बचने के लिए अगर कोई रास्ता है तो वह गांधी जी का बताया हुआ मार्ग ही है। गांधी जी ने जीवन की अथ व्यवस्था, राजनीति व्यवस्था को विवेचित करने की बात कही थी। उन्होंने अपनी आवश्यकताओं को कम करने और आत्म नियंत्रण

करने की बात भी कही थी। यह सभी की बात है कि बिना आत्म विमर्शता के चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो या सामाजिक व्यवस्था राष्ट्रीय स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं होता। उन्होंने जीवन के इस साद्वर्त लक्ष्य को बुनियादी शिक्षा के द्वारा प्राप्त करने की बात प्रतिपादित की थी। आज नये सन्दर्भों में उनके दार्शनिक सिद्धांतों की आवश्यकता नहीं है। यह वही वह सब है जो सामने खड़े हुये विनाश के प्रति उदासीन हो और जिन्हें यह चिन्ता नहीं है कि मानवता किसी भी समय सर्व्व के लिए विनाश के मार्ग में विलीन हो सकती है।

जैसा मैंने पहले कहा है कि गांधी जी राजनीतिक बम और मानववादी अधिक थे। वे एक महान शिक्षक थे। यह बम लोगों को मानव है कि गांधी जी जहाँ एक ओर ऐसे साम्राज्य से सबाई सड़ रहे थे जिसमें प्रेषित नहीं होता था। वही वे हिन्दी शिक्षा के लिए पहली पुस्तक बम बोधी भी लिख रहे थे। जितने विद्वानों ने इस आवश्यकता को महसूस किया है? यही नहीं गांधी जी ने उस पुस्तक में लिखा है कि बच्चों और शिक्षकों के लिए कम से कम पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग किया जाय क्योंकि इससे शिक्षण और शिक्षक दोनों की ही मौलिकता नष्ट होती है। शिक्षक आवश्यकता पड़ने पर सन्देश बच्चों का प्रयोग कर सकते हैं। गांधी जी ने सूत्ररूप में एक बहुत बड़े शिक्षा सिद्धांत की जो बात कहो है उसे सामोना करना तो अल्प सम्मान भी अनेक उपायविधि विद्यावास्तविकों के लिए मुक्तिकारक होगी। उनका यह सूत्र इतना चान्तिकारी है कि यदि उत्तम अनुसरण किया जाय तो आज के भौतिक पाठ्यक्रम और भौतिक पुस्तकों से मुक्ति अवश्य मिल जायगी और शिक्षा वास्तविक जीवन से सम्बद्ध हो सकेगी।

गत दस वर्षों में हमारी शिक्षा

—श्रीमती उषा चिन्हा

प्रस्ता

आज हमारा देश मन्त्री शैक्षीय परिवर्तनों के साथ माने जा रहा है। एक के परिचलनों को भी गति और भी तीव्र होगी। देश को प्रगति पर चलाने का येय शिक्षा को है। भारत में आज राष्ट्रीय और प्राथमिक शिक्षा-पद्धति का अग्रिम महत्व है। शिक्षाविदों के प्रयासों में आज की परिधि का जिस अनुपात में विद्या है वह अनुपात में इस मने आज के प्रति हमारा उत्तर-वापिस भी बना है।

देश में शिक्षा के वर्तमान विस्तार को मही अर्थों में मण्डले के लिए हम सम्पूर्ण राष्ट्रीय स्थिति पर विचार करना होगा, क्योंकि आज देश में बहुत जाने जाये हुए विद्यापियों को करना १० करोड़ है। विद्युत दमक के शोधन शिक्षा को प्रगति पर पहुँची नजर चलाने में पता चलता है कि देश में इस सौम्य में निश्चित नीति और योजना के आधीन प्रगति को है। यह सम्बन्ध स्वाभाविक था क्योंकि इन दमक में दौरान १९६६ में शिक्षा आयोग की रिपोर्टों और दो वर्ष बाद शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति का स्वीकार किए जाने के परिवर्तन को गयी हुआ वह पत्नी है। संक्षिप्त मर्यादा में पूर्ववत् काम होता रहा किन्तु बादान्तर में परिवर्तन होने लगा। इन प्रकार ऐसे पुन का प्राप्ति द्वारा जिसमें आज पर ही सम्पूर्ण ध्यान नहीं दिया जाता था, इसके साथ ही शिक्षा को उसका माते बनने से मुक्त करना तथा आर्थिक बन्धनों के बाद भी शिक्षा का सर्वेज जनता तक पहुँचाने के लिए नयी विचारपरामर्श बननी।

आज की दृष्टि में भी शिक्षा की प्रगति अनुदी रही है आज शिक्षा पर ध्यान होने वाली धनराशि कुल १,६० करोड़ रुपये है जब कि १९५७ में शिक्षा पर केवल २० करोड़ रुपये खर्च होता थे। इस अवधि में विभिन्न स्तरों पर कृत्य जीवन बान और पढ़ाये

बगजार मद्रको को समस्या विशेषत विचारणीय मानी गयी थी। विद्युत दमक शिक्षा के क्षेत्र में नये मोड़ पड़ रहा था।

शिक्षा आयोग ने इस बात पर और दिया था कि शिक्षा को सामाजिक एवं आर्थिक संपादनरग का साधन बनाया जाय। उसमें इस बात का भी पता लगाया कि शिक्षा के बारे में एक सुसज्ज नीति की आवश्यकता है। मदनमर सद्य में १९६५ में शिक्षा में राष्ट्रीय नीति को स्वीकार किया, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे प्रथमिक क्षेत्रों को महत्व दिया था जहाँ राष्ट्रीय व्यक्तियों के अविश्व ध्यान देने को आवश्यकता थी।

केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय बोर्ड ने १९७२ में शिक्षा क्षेत्र में व्यापक स्थिति की समीक्षा की और पाकवी पञ्चवर्षीय योजना के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम की योजना की स्वीकृति दी। इन कार्यक्रमों पर १,९२० करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान था। इस बात को देखते हुए केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय बोर्ड की स्थाई समिति ने जून, १९७२ में एक संगठित कार्यक्रम तैयार किया और प्राथमिकता के अनुसार कुछ निश्चित कार्यक्रम प्रस्तुत किए।

केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय बोर्ड की बैठक नवम्बर १९७४ में देश की आर्थिक स्थिति पर विचार करने के लिए पुन हुई। बोर्ड ने यह स्वीकार किया कि देश की तत्कालीन स्थिति को देखते हुए शिक्षा को भी अपने व्यय में कटौती करनी होगी। अपने शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति सुनिश्चित करने के लिए एक नीति की घोषणा की थी।

इसकी प्रमुख विशेषताएँ—१. एक कार्यक्रमों और प्रयासों को भी अब उपबोधों नहीं है, समाप्त करने के लिए सभी योजनाओं चर्च की गयी थी। गयी और

इस प्रकार बताया गये घन से गये कार्यक्रम शुरू करने या उन वर्तमान कार्यक्रमों को चलाने की आवश्यकता बतायी गयी जिन्हें अतिरिक्त धन की जरूरत है।

२—योजनागत और नैसर्गिक योजनागत खर्चों को मिला देने की आवश्यकता बतायी गयी ताकि नैसर्गिक योजनागत खर्चों का कोई भी अर्थ वसूली बाधों के लिए उपलब्ध न हो।

३—शिक्षण कार्यक्रमों में नये व्यक्तियों का अधिक कारगर उपयोग करने पर बल दिया गया।

४—अधिक छात्रों को भर्ती करने या नये कार्यक्रम विकसित करने के लिए उपलब्ध हमारतों का उत्तम उपयोग करना आवश्यक बताया गया।

५—योजना के लिए नियत राशि को बढ़ाने के लिए समाज के सभी वर्गों का सहयोग प्राप्त करने की आवश्यकता बतायी गयी।

नयी नीति—

बोर्ड ने निम्नलिखित सिफारिशों को १. उच्चतर माध्यमिक और उच्च शिक्षा में वर्तमान छात्राओं को मुक्तिपट्ट बनाने, उचित मानकों को बनाए रखकर और छात्रों की भर्ती को नियमित करके व्यवस्थित और शिरोधार्य विस्तार को रोका जाए। नये विषयविद्यालय की स्थापना में सक्षम बरतना, और बहुत ही पिछड़े इलाकों की छोकरीय गये बालिकाओं की स्थापना पर रोह लगाने की अपेक्षा है जहाँ पिछड़े और उपरिष्ठ वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण करने के साथ प्रौढशिक्षण छात्रों की भर्ती को नियमित किया जायगा। अनौपचारिक शिक्षा का विस्तार दिया जायगा, ताकि उन सभी को, जो उच्च शिक्षा की इच्छा रखते हैं, हमारा लाभ मिले।

२—कुछ विशेष महत्वपूर्ण और प्राथमिकता के कार्यक्रमों पर जोर दिया जाना चाहिए। इसमें प्राथमिक शिक्षा की अविनाश व्यवस्था और उच्च गुणवत्ता माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था प्रदान करना, सभी राज्यों में शिक्षा की १०+२+३ प्रणाली का चलन, युक्त सहायता का विकास और १५-२५ आयु वर्ग के बच्चों की अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था शामिल है।

३—अनौपचारिक शिक्षा पर जोर दिया जाने वाला जोर समाप्त कर दिया जाए और इस व्यवस्था के जोर को अनौपचारिक शिक्षा की जाए। बहुप्रतिष्ठ और अमान्य शिक्षा का कार्यक्रम बड़े पैमाने पर स्थानांतरित किया जाना चाहिए। माध्यमिक और विश्वविद्यालय स्तर पर अमान्य और पत्राचार शिक्षा का विकास किया जाना चाहिए।

४—नैसर्गिक पुनर्निर्माण के सभी कार्यक्रमों में अध्यापकों छात्रों और समाज को पूरी तरह से सम्मिलित करने सभी शिक्षा स्तरों में उदाहरण और निरंतर पठन परिधम का वातावरण बनाया जाना चाहिए।

पिछले दशक के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले विकास—

शिक्षा का समान अवसर—अब सभी राज्यों में ५-११ आयु वर्ग के बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। १२ राज्यों में ११-१४ आयु वर्ग के बच्चों तक शिक्षा भी निशुल्क है। १९७४-७५ के अन्त तक ६-११ आयु वर्ग के ८६ प्रतिशत बच्चों के लिए और ११-१४ आयु वर्ग के लिए ३६ प्रतिशत बच्चों के लिए शिक्षा सुविधाओं की व्यवस्था की गयी है। पाचवीं पंचवर्षीय योजना में ६-११ आयु वर्ग के ८७ प्रतिशत और ११-१४ आयु वर्ग के ४७ प्रतिशत बच्चों के लिए शिक्षा सुविधाएं प्रदान करने का लक्ष्य है। इसमें १९८२-८४ तक २५ पर न सर्वसाधारण प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में काफी सहायता मिलेगी।

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में ग्युलतम आवश्यकता कार्यक्रम पर विशेष जोर दिया गया है। इसमें प्राथमिक शिक्षा के विस्तार, क्षेत्रीय असंतुलन और असमानताओं को दूर करने और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, लड़कियों एवं समाज के दुर्बल वर्गों को, विशेषकर शिक्षा व्यवस्था में सहभागिता मिलेगी। शिक्षा व्यवस्था में प्रवर्धित परिवर्तन से जिसमें अनौपचारिक शिक्षा पर जोर दिया जाना और नये विदुषों पर प्रवेश स्थानांतर

जिसे चायया, बहन ऐसे बच्चों की शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर मिलेगा, जो स्कूल नहीं जा सकते हैं यथवा जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया है।

प्रोत्साहन—सरकार सामान्य व दुर्बल वर्गों विशेष रूप से अनुप्राणित जाति व इनके बच्चा और सदस्यों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहन तरह के प्रोत्साहनाएँ और छात्रवृत्तियाँ दे रही हैं। दोगहुर का जीवन लज्जियों की निवृत्त गोरान, नाबल वैद्यक जाति की भी व्यवस्था की जाती है। सामान्य व सभी वर्गों की शिक्षा का समान अवसर प्रदान करने के लिए राज्य सरकारें योग्यता और आय के आधार पर छात्र वृत्तियाँ प्रदान करती हैं। इस्वी शिक्षा में विज्ञान की शिक्षा की विशेष महत्वा दिया गया है। समुक्त राष्ट्र बाल-बोध की सहायता से विज्ञान के सम्पादन का प्रतिष्ठान की व्यवस्था और विज्ञान पाठ्यक्रम में सुधार करने रूनी में विज्ञान की पढ़ाई में सुधार किया गया है।

साइंट एन द्वारा क्षेत्र जहाँ गुणात्मक सुधार हो रहा है, शिक्षा प्रौद्योगिकी है। उपग्रह, दूरदर्शन शिक्षा कार्यक्रम साइंट के अधीन वैज्ञानिक प्रसारण की गुणात्मक बढ़ावा के लिए छ राज्यो के ४०० गाँव की पाठशालाओं में दूर दर्शन सेट लगाये जा रहे हैं। राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद दिल्ली द्वारा आयोजित विज्ञान प्रतिष्ठा योजना और अनुसंधान कार्यक्रमों से भी स्कूलों स्तर पर शिक्षा के सुधार में सहायता मिलती है।

शिक्षा क्षेत्र में निवेश—

१९४७ में शिक्षा पर होने वाला कुल व्यय २७ करोड़ रुपये था। अब यह बढ़कर १,६०० करोड़ रुपये हो गया। स्कूल स्तर पर सबसे अधिक उत्प्रेषणीय कर्तव्य बना। १० तक की छात्राध्य शिक्षा के पाठ्यक्रम में वायव्युक्त की शामिल करना है। इसका लक्ष्य छात्रों में बुनियादी कुशलता पैदा करना है। उपर्युक्त सामान्य निर स्तर पर पाठ्यक्रमों को व्यवसायिक स्तर प्रदान करने पर ध्यान दिया गया है।

शिक्षा और राष्ट्रीय विज्ञान को समुक्त करने वाला पर दूसरा कार्यक्रम बहस शिक्षा कार्यक्रम है। इससे

दो भाग हैं, एक का सम्बन्ध अतिप्रति, अर्द्ध शिक्षित व्यवस्था जनता के समूह से है और दूसरे का विज्ञानों को करने काम से सम्बन्धित शिक्षा देने से है। पहले का उद्देश्य उन लोगों को अनुत्तम शिक्षा देना है जिनको सभी प्रारम्भिक शिक्षा देने का भी अवसर नहीं मिला। उन्हें लोगों की सामान्य शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है और इस प्रकार अपनी व्यावसायिक शिक्षा बढ़ाने का अवसर दिया जाता है। दूसरे कार्यक्रम में आधीन शालीनों को उनके कार्य से सम्बन्धित शिक्षा दी जाती है। इसमें १९७२-७४ के अन्त तक तीन लाख विज्ञान लाभ उठा चके थे। १९७४-७५ में १५० लाख विज्ञान अपने कार्य से सम्बन्धित शिक्षा के रहे थे। यह कार्यक्रम १९७७ तक चल रहा है। पाचवी योजना के दौरान इसे अग्र्य विकास योजनाओं जैसे बगानी होती, छोटी और सीमान्त तटी, औद्योगिक विकास और परिष्कार नियोजन से जोड़ देने का प्रस्ताव है।

अनौपचारिक शिक्षा—

इसके अतिरिक्त अनौपचारिक शिक्षा का कार्यक्रम है, जो शिक्षा विकास की मुख्य रणनीति है। इसका लक्ष्य निम्नी काम से बने लोगों को बुनियादी साक्षरता प्रदान करना और शिक्षा प्रदानों को विकास कार्यों के साथ जोड़ना है, जिससे वे युवक, विशेष रूप से १५-२५ आयु वर्ग के विद्यार्थी बच्चों में कार्यक्रम रूप से बने रह सकें। प्रारम्भिक पेशेवर और व्यावसायिक कुशलता के विकास की और जो युवकों को रोजगार और अपना काम शुरू करने के लिए तैयार करेगी, समुचित ध्यान दिया जायगा। देश के सभी जिला मुख्यालयों में नेहरू युवक केन्द्रों की स्थापना की जा रही है, ताकि उन युवकों को, जो छात्र नहीं हैं, राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा में शामिल किया जा सके। १९७४-७५ में ऐसे ११० केन्द्र देव भर में कार्य कर रहे थे।

उपयुक्त विवरण पिछले दशक के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति को दर्शाता है। नेहरू और पारोरिक शिक्षा के क्षेत्र में भी उत्प्रेषणीय प्रगति हुई है।

सेलकूद को प्रोत्साहन—

इस क्षेत्र में पिछले दशक की एक उत्सेसनीय विशेषता ग्रामीण और जन जातीय युवकों की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किये जाने की है। नेहरू युवक केन्द्रों के साथ विशेषज्ञों को सम्बद्ध किया गया है, नवो कि ग्रामीण और जन जातीय युवक, अपिकायत सेल-बूद की मुख्य धारा से अलग रहे हैं। १९७०-७१ में ग्रामीण सेलकूद प्रतियोगिताओं का एक देशव्यापी कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के अधीन कुछ निश्चित क्षेत्रों में देश भर में छण्ड स्तर पर प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाती हैं। इससे अब तक ९ लाख युवक युवतियों में काम किया है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है।

देश के सभी नगरों, विश्वविद्यालयों एवं गाँवों में सेल-कूद सुविधाएँ प्रदान की गयी हैं। नवे स्टैडियमों एवं रिश्मिन् पूल के निर्माण के लिए सरकारी सहायता दी जाती है। नीचे स्तरों पर सेल-बूद के विकास का एक मूलतम कार्यक्रम तैयार किया गया और राज्यों को कार्यान्वयन के लिए भेजा गया है। आशा है कि गाँवरी योजना के अन्त तक ५० लाख ग्रामीण और जन-जातीय युवक सेल-बूद की गतिविधियों में आम लेने लगे हैं।

इस क्षेत्र में देश में वृद्धिक्रमिय प्रगति की है। हिंदी और भारतीय भाषाओं एवं विदेशी भाषाओं के शिक्षण का कार्य न केवल पूर्ण स्तर तक चलाएँ रखा गया है वरन् पिछले १० वर्षों में उसमें तेजी लक्ष्यी भयो है। ब्रिहिरी भाषी राज्यों में २,००० से अधिक अध्यापक हिन्दी शिक्षण का कार्य कर रहे हैं। आभासी वर्षों में उसमें वृद्धोदारी की जासगी। विभिन्न राज्यों में हिन्दी अध्यापकों के १६ प्रतिशत वृद्धोद क्रम कर रहे हैं। दो नवे प्रतिशत वेद मणिपुर और मिजोरम में शुरू किये गये हैं। गैर हिन्दी राज्यों के छात्रों को मैट्रिक के बाद हिन्दी की पढाई के लिए छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं। ११वीं योजना के अन्त तक ऐसी छात्रवृत्तियों की गन्ना २,५०० कर देने का प्रस्ताव है। स्वयंसेवी सरपंचों को हिन्दी के प्रचार प्रसार के लिए अनुदान

दिया जाता है। गैर हिन्दी राज्यों में हिन्दी की बधाएँ चवाने के अतिरिक्त हिन्दी टाइम की कक्षाएँ और पुस्तकालय भी चलाये जाते हैं।

सांस्कृतिक मामले—

स्वतन्त्रता के बाद संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए कई कदम उठाये गये हैं। साहित्य अकादमी, सलित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी ने भारत की प्राचीन समृद्ध संस्कृति में धमेक नये और समन रूपों में अपने को प्रकट किया है, जिसे पुनर्जागरण 'रेनैसा' का नाम दिया जा सकता है। साहित्य, संगीत, कला, सभी मंचों की स्थापना साहित्यिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों के स्वाति प्राप्ति क्षेत्रों को पुरस्कार चतती फिरती प्रब-धनियों का आयोजन और सांस्कृतिक संस्थाओं के साथ सदस्यों का आवाग-प्रदान इन अकादमियों का निमित्त कार्य है जो प्रतिवर्ष विस्तार और विविधता से प्रगति कर रहा है। इसके अतिरिक्त विदेशों के साथ सांस्कृतिक सम्बन्धों को मजबूत बनाने में सहायता मिलती है। प्रत्येक वर्ष अनेक दलों का अवान-प्रदान होता है, इस सांस्कृतिक आदान-प्रदान से विभिन्न देशों की चम्ता एक दूसरे के समीप आती है। इससे विचारों और अनुभवों के आदान-प्रदान में सहायता मिलती है।

शिक्षा और संस्कृति पर अनुरीवी उप-आयोग की स्थापना एक प्रमुख घटना है। इस उप-आयोग ने विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में परियोजनाओं की मजूरी दी है। देश के भीतर स्थैच्छिक सांस्कृतिक सरदनों, ध्यानसाधक, नृत्य, नाटक, थियेटर समूहों की सहायता देना, अन्तर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक मंचों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं की स्थापना, विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में छात्रवृत्तियाँ, सांस्कृतिक प्रतिभा की खोज, छात्रवृत्ति योजनाएँ आदि प्रमुख सांस्कृतिक गतिविधियाँ हैं। इसके अलावा भारतीय नरतत्वीय सर्वेक्षण समन्वय, भारतीय अखिलेखापार, राष्ट्रीय समग्रालय, मेघनल गैलरी आफ़ मास्टर और राष्ट्रीय पुस्तकालय, हवाई सम्पन्न विरासत को बचाए रखने के लिए निर्-न्तर प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार शिक्षा और संस्कृति के सम्पूर्ण क्षेत्र में नवे प्रगति के लिए सभी स्थितियाँ विद्यमान हैं।

अनौपचारिक शिक्षा : कुछ विचार विन्दु

प्रभाकर सिंह

क्षेत्रीय सप्ताहकार (१० जे० को० एच प्र० स०)

हमारे सविद्यान मे केवल दस वर्षों मे ही म्यूनसिप (१-१४ वय वर्ष) अनिवार्य शिक्षा के लक्ष्य सिद्धि की गयेगा की नहीं, जो हमारे तारकात्मिक उल्लाह तथा आकांक्षा का द्योतक है। द्वितीय समय की औपनिवेशिक शिक्षा-व्यवस्था से छुटकारा पाने की सभी लोगों ने दुहाई दी। फलतः बेमिन्न, मातृमिन्न तथा उच्च शिक्षा की तत्प्राप्त नई संरचनाएँ उभरी। उत्तर प्रदेश मे आध्यात्म नरेन्द्र देव समिति ने प्रस्तावों की बहुत बर्षों हुई और कुछ कार्य 'योगनाथ' बनी। स्पूल और बनेजों की टीली से वृद्धि हुई। परिणाम हमारे सामने है—'निरक्षारी की सख्या में बड़ीसरी' 'मन्द गति से प्रतिष्ठित मे वृद्धि की बात छोड़िए' और साथ ही शिक्षितों मे अधिप्राप्त बेरोजगारी, हस्तशिल्प और बढ़ती हुई बेबेनी। एक ओर शिक्षा पर लागत मे कमी की बात उठाई जाती है, तो दूसरी ओर परिणामों के सम्बन्ध मे अप्रत्यक्षता भ्रमता घातकों के समुद्रमय मे कमी का भी शोष लगाया जाता है। बड़ी विचित्रता की परिस्थिति है। १९७० तक शिक्षा ने सम्मन्य मे जो भी गुणाभास का अनुभव ही रहा था, उसका अन्त दिखाई देने लगा। गीठारी माधोप मे शिक्षा सुविधा, स्वरूप और व्यवस्था के विकल्पी के बारे मे सोचना, इस परिस्थिति की प्रत्यक्ष प्रस्ता है। आज हम सीधिर सच के ऐसे विन्दु पर का पहुँचे हैं, जो हमें कुछ कर मुनरने मे लिए चुनौती देता है। ऐसा लगता है कि अब हमारे पास सम्पूर्ण रूप मे सोचने मे लिए भी समय नहीं। विज्ञातम्न का वही विस्फोट न हो जाय, भ्रम लगता है।

वैराग्य मे गह्वर से उभरने के लिए हम सब विकल्पों की रज्जु की पकड़ने में प्रयासशील प्रवीण होते हैं। लोक-नायक आपमनाथ जी ने व्यक्ति ने निवास तथा सामाजिक परिस्थिति के परिवर्तन हेतु शिक्षा की सक्षमता को स्वीकार करते हुए विचार व्यक्त किया है कि "अभाव-

कत औपचारिक शिक्षा" यवस्था हमारे उद्देश्यों को पूरा नहीं करती है। दूसरी ओर यह उच्च और मध्य वर्ग के लोगों की भी, जो इतने सामाजिक होते हैं गलत शिक्षा देती है। [भूमिका, एन्क्रेडन फार भावर पीपुल] सम्म-वत अनौपचारिक शिक्षा विकल्पों के खोज की प्रवृत्ति में एक गृहलता है।

शिक्षा के विकल्प—

प्राविद्यान की दृष्टि से शिक्षा के तीन स्रोत रहे जा सकते हैं (१) आकस्मिक (२) अनौपचारिक (३) औपचारिक। इनके छात्तिक अर्थ पर न आकर इनको सार्थक बनाने के लिए पारिभाषित करना जरूरी है। आकस्मिक शिक्षा [इनफोरमल अथवा इम्पीडेन्टल] हम हर समय अपने जीवन के अनुभवों के साथ मिलती रहती है जिससे हमारे ज्ञान, जीवन तथा भावना पक्ष की अभिवृद्धि अनायास होती रहती है। हम इसके बारे में कोई संकेत अथवा संरक्षित प्रयास नहीं करते, किन्तु इस माध्यम का तथाज के नेता अथवा सरकार-सुविचारित समुद्रयोग करने व्यक्ति और समुदाय को एक शिक्षा विशेष मे अवसर कर सकते हैं। औपचारिक शिक्षा सरप्रात व्यवस्थापक शिक्षा को कहते हैं। अर्थात् कि हम सभी जानते हैं सरप्रात शिक्षा में एक निश्चित पूर्णकालिक शिक्षाक्रम होता है। इस शिक्षाक्रम में अथाधमक एक प्रयासशील क्षेत्र विशेष अथवा समुदाय विशेष को दृष्टि मे रखकर एकरूपता पायी जाती है। जनन, गर्भवतारी, उपकरण आदि का एक व्यवस्था के अनुसार प्राविद्यान होता है। गेजेटर व्यवस्थाओं की निपुणता, पितृव्य प्रयास ऐतिहासिक कार्यक्रम, विद्यार्थी की पूर्णकालीन उपस्थिति जैसे नियमों का आचरण इसमें विहित है।

अनौपचारिक शिक्षा के सम्मोहन का प्रयोग औप-चारिक शिक्षा के विच्छाद्य में किया जाता है। किन्तु आज ऐसी नहीं है। अनौपचारिक शिक्षा क-

विकल्पो का संयोजित प्रयोग

जिन तीन विकल्पो की ऊपर चर्चा की गयी है, वे एक दूसरे के विरोधी अथवा निवारक नहीं हैं। सम्भवतः शिक्षा का अपना महत्व और उसका सम्बर्द्धन भी होता है। नही मर्यादात शिक्षा में बाध नहीं पड़ रहा है, अथवा अपसाम्य निम्न हो रही है। जहाँ अन्य विकल्पो का प्रयोग जरूरी है। इस दृष्टि से अनौपचारिक शिक्षा एक विरोधी विकल्प नहीं है, और यह अन्य विकल्पो का सम्पूरक है। उदाहरणार्थ ६-११ वय के छात्रों में विशेषरूप से प्राचीन धर्मों में मूलभूत दो सिद्धांतों का ज्ञान है, यद्यपि यह बालक पुरातनिक स्कूली शिक्षा के लिए समय नहीं दे सकते। कुछ प्रारम्भिक स्कूली शिक्षा पारकर कोई व्यक्ति कुछ और पढ़कर अपनी नौकरी में कुछ आगे बढ़ना चाहता है, तो उसे अध्यात्मिक अथवा अपने समय की सुविधा के अनुसार आगे की शिक्षा प्राप्त करने की जरूरत है। ऐसी अन्य अनेक परिस्थितियाँ हमारे सामने आती हैं, जिनसे सम्बन्ध में अनौपचारिक शिक्षा को एक सम्पूर्ण विकल्प के रूप में चलाना सम्भव उपयोगी सिद्ध हो सकता है। ६-१४ वय वर्ग के स्कूल की अपूर्ण शिक्षा वाले बालकों के लिए अनौपचारिक शिक्षा की एक व्यापक योजना पर कार्य हो रहा है, जिसे वैदेशी सरकार की सहायता से राज्य सरकार चला रही है। इसकी एक प्रगतिक अवस्था भी बनायी जा रही है। इसी तरह प्रौढ शिक्षा से सम्बन्धित भी एक अनौपचारिक शिक्षा का कार्यक्रम चल रहा है। इस प्रणाली में यह तथ्य विचारणीय है कि औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रम क्यासमय आकस्मिक शिक्षा के कार्यक्रम भी एक दूसरे के रित्त प्रकार सम्मिश्रित हो।

देखने में आता है कि शिक्षा की विभिन्न योजनाएँ बहुत एक दूसरे से घुलती अलग अलग करके चलती हैं कि जिस घन और घन के अभाव में हम शिक्षा में क्षेत्र में काम करना चाहते हैं यह एक कार्यक्रमों के प्रारम्भ से उभरा बढ़ने लगता है। ऐसा मान्य होता है कि प्रगतिक सत्ता एक व्यापक समन्वय हेतु योजना देने में असमर्थ सिद्ध होती है। वास्तव में औपचा-

रिक और अनौपचारिक शिक्षा की योजनाओं को एक दूसरे से खटाट होना चाहिए। सफलता के लिए चाहिए कि उनको अलग-अलग चलाया ही न जाय यहाँ तक कि एकको एक दूसरे से जोड़कर अर्थात् यौनिक रूप से उचित परिणाम कारक सिद्ध नहीं होता, यद्यपि इस स्थिति में भी कार्यक्रमों में व्यर्थ का दोहराव बनाता रहता है, उदाहरणार्थ यदि किसी दूसरे के पास में तीस प्रोड के एक केन्द्र की देखने के लिए एक पर्यवेक्षक जाय, १-१४ वय वर्ग के लिये प्रस्ताव, बालकों के प्राथमिक विद्यालय के लिए तीसरा तथा क्षानिनाओं के प्राथमिक विद्यालय के लिए चौथा नियुक्त होता है तो क्या इसे हास्यास्पद समझना नहीं चाहेंगे? वास्तव में चाहिए कि इन योजनाओं की सार्थक और मितमयी नियन्त्रण के लिए एक अव्यक्त संगठित अथवा समन्वित नियोजन। यह कंठ हो, यह सम्पूर्ण और स्पष्ट चिन्तन का विषय है।

आइये अब अनौपचारिक शिक्षा पर विशिष्ट रूप से विचार करें।

अनौपचारिक शिक्षा का स्वरूप— अनौपचारिक शिक्षा का केन्द्र

ऐसा कि ऊपर संकेत कर चुके हैं, अनौपचारिक शिक्षा एक प्रवृत्ति है, जो अनेक रूपों में व्यक्त होती है। इसके कुछ नामों से हम अपना नाम अकादमिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, प्रादेशिक शिक्षा, आजीवन शिक्षा, सतत शिक्षा, स्वायत्त शिक्षा, अवकाश कालिक शिक्षा, पुनर्जीवन प्रशिक्षण एपरेण्डिसिप, प्रसार शिक्षा आदि है। अस्तर की अन्यायियों के और पृथिवी के रोम योग आदि विषयों के व्यवस्था और व्यवस्थाओं सह-वास और आचारों की शिक्षा पाते हैं, इसमें ही हम कहे जा सकते हैं। उपर्युक्त संज्ञाओं में स्पष्ट हो जाता है कि अनौपचारिक शिक्षा प्रयोजन सिद्ध होती है, और इसके लिए उद्देश्य सामाजिक महत्त्व की बात है, व्यवस्था तथा प्रयासन केवल साधन मात्र हैं, साध्य नहीं। कुछ विद्व-विश्वविद्यालय तथा 'खुला स्कूल' जिसकी देश और विदेश में काफी चर्चा है इसी प्रवृत्ति के उदाहरण हैं। स्पष्ट है कि अनौपचारिक शिक्षा के नियोजन तथा नियन्त्रण

का एक मुख्य सिद्धान्त नमनशीलता है। इस प्रकार की नमनशीलता सम्भावित अर्थात् अनौपचारिक शिक्षा में भी परिलक्षित होनी चाहिए। स्कूल बानेको के कार्यक्रम में भी अनौपचारिकता के सिद्धान्त को यथासम्भव मुख्य मिला चाहिए। स्कूल में बाहर जाकर विद्यार्थियों को स्वानुभव तथा सामाजिक प्रतिभाषी के रूप में सीखन का अवसर इसी प्रवृत्ति का उदाहरण है। पाठ्यपत्र का कार्यक्रम भी इस प्रभाव को परिलक्षित करते हैं। वह दिन अत्यन्त गुप्त होगा, जब हमारी सरकारी भी अनौपचारिकता को अधिक न अधिक ग्रहण करेंगी और साथ ही गरीब जनित श्रमकुशलता को भी अङ्गीकार करारेंगी। यहाँ वह स्पष्ट करना भी उचित है कि अनौपचारिक शिक्षा में भी एक सुनियोजित व्यवस्था होती है, किन्तु वह ग्यमासिन्धुन कार्य कुशलता में बाधक नहीं।

अनौपचारिक शिक्षा की वर्तमान आवश्यकता

एक प्रवृत्ति के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में अनौपचारिकता के बहुत प्रयोग हैं, और अनेक अनवर हैं, किन्तु उमरती हुई परिस्थितियों में निम्नलिखित प्रयोग विचारणीय हैं।

१ निर्बल अवस्था पवित्र धर्म की प्रमाणी शिक्षा, के लोग पूरा कालिक शिक्षण के लिए समय नहीं दे सकते। इनको, इनकी दुनिया तथा काम के बन्धे हुए समय में शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है। इस क्षेत्रीय में प्रौढ शिक्षा तथा विद्यालय की अपूर्ण शिक्षा प्राप्त बातको की शिक्षा जाती है।

२ आगे की शिक्षा—बहुत से लोग रोटी रोटी कमाने की चोट में अधिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते किन्तु अपने अभियन्त की रुचिकर बनने के लिए समय निकाल कर आगे की शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं। यही नहीं अधिक पढ़े लिखे लोग भी अपनी अभिवृद्धि अपना आनन्दन के लिए आगे की शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक हो सकते हैं।

३ नये रोजगार की शिक्षा—बहुधा तकनीकी परिवर्तन तथा वैज्ञानिकी की समस्या को हल करने के लिए यह जरूरी है कि आवश्यकतानुसार विशिष्ट क्षेत्रों की शिक्षा आयोजित की जाय, ताकि एक

रोजगार को सल होने पर जारीगर दूसरे रोजगार में जाने के योग्य अपन को बना सके। यह हमारे बढ़ते हुए औद्योगिककरण के सम्पर्क में आवश्यक है।

४ पुनर्बोधन प्रविष्टन कार्यक्रम—इनकी आवश्यकता स्वयं सिद्ध है। -

५ आवाज के सहयोग हेतु शिक्षा—

६ सामाजिक शिक्षा—सामाज में परिवर्तन मान हेतु उचित मानसिकता, नैतिकता तथा सामाज्य मान, परिवार नियोजन से सम्बन्धित शिक्षा को देने की आवश्यकता है। अनौपचारिक शिक्षा और उनके अन्य प्रयोग के सवय में हम राष्ट्रीय क्षेत्रीय और स्थानिक स्तर पर सोचने की आवश्यकता है और साथ ही इन आवश्यकताओं में प्रापनिकता निश्चित करने की भी। इस हेतु विशेषतः सहयोग अपेक्षित है, जो सर्वोपलब्ध और योग्य के आधार पर कार्यवाही करें।

अनौपचारिक शिक्षा की कार्यविधि

अनौपचारिक शिक्षा में अनेक विधियों का प्रयोग किया जा सकता है जैसे अल्प कालीन प्रविष्टन विधि, सावकानिक शिक्षण बसाधार, दूर दर्शन, विचार शीटियाँ, कार्य शीटियाँ आदि आदि। किन्तु परिस्थिति में विशिष्ट विधि का प्रयोग सवय है इसके लिए उचित योजना तथा कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है। अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्थापरक न होते हुए भी इसके लिए पूरी तैयारी और विस्तारपूर्वक योजना बनाने की आवश्यकता है। अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों की पाठशाला लक्ष्य बनें बसाधारों के मुख्य के रूप में घाटकट अपनाता इसके प्रति अन्याय करता है। इस प्रकाश में निम्नलिखित तथ्य विशेष रूप में विचारणीय है—इन्के प्रकार करने की आवश्यकता है। साधारण अभिधान के सम्पर्क में तो विशेष रूप से उत्तरेतर सम्बन्धित प्रकार कार्य करने की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए सम्पूर्ण निम्न की आवश्यकता है।

२—सामाजिक आवश्यकताएँ प्रमुख आधार अनौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रमों को सामाजिकयोग्य होने की आवश्यकता है। यदि सामाजिक आवश्यकताओं

को राजनैतिक जागरूकता से सम्बन्धित कर दें तो यह और आवश्यक बन जाती है और राजनैतिक शिक्षा का एक उपयोगी माध्यम बन जाती है। गौनोस्तेरे के शासकों में ऐसी प्रयोग बड़े सफल सिद्ध हुए हैं। यह एक अत्यन्त मातृका प्रयोग है। इसकी क्या सम्भावना है हमारे लिए हो सकती है ?

३—शिक्षण के साथ मुलात्तों का कार्यक्रम अनौपचारिक शिक्षा के बहुत स कार्यक्रमों में से एक है जिसमें पहले सीसी हुई बालों में गुपार लाने की बहुत जरूरत होती है। शिक्षण वर्गों की शिक्षा के तत्त्वों में उनकी मान्यताओं अभावितताओं तथा प्रयोगों के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा के साथ अत्यन्त गुपार काय हो जाता है। इन परिस्थितियों का सामना किया जाय यह एक चुनौतीपूर्ण विषय है।

४ लक्ष्यहीन पाठ्यक्रम जैसा कि पहले चर्चा किया जा चुका है अनौपचारिक शिक्षा में रचनीय आवश्यकताओं में तथा सामाजिक परिस्थिति को देखकर शिक्षाक्रम बनाने की आवश्यकता है। अनौपचारिक शिक्षा की इकाईयाँ तबका की दृष्टि में इनकी छोटी होती है कि पाठ्यक्रम रचना का विशेष काम इनके स्तर पर कैसे हो ? कहा जाता है कि कुछ कोरा पाठ्यक्रम बनाना या बनना है और कुछ रचनीय समस्याओं को लेकर सामाजिक करने के लिए छोड़ा जा सकता है। कहना माहान है करना नहीं है। वास्तविकता की दृष्टि से इस पर सीखने की जरूरत है।

५—सामान्यताओं के प्रति जागरूकता तथा विचारों के निर्माण यदि वास्तव में अनौपचारिक शिक्षा की सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बनना है इसे विचारों के प्रसार और प्रसार और उन पर जनसाधारण को समीक्षात्मक रूप से मनसर देना आवश्यक है। उन्हें सोचने में तरीकों की रचना होना। लेकिन इस बात की जागरूकता है कि यह प्रोग्राम बड़े पैमाने और लक्ष्य से सजाये जाय। इन सम्बन्ध में उचित विधियों का ज्ञान करना है, और उनमें शिक्षा देने वाले को प्रतिष्ठित भी करना है।

६—कार्यभारित शिक्षा अभिवादन लोग जो शिक्षा छोड़ देते हैं उनके छोड़ने में एक प्रमुख कारण शिक्षा की निरसता भी होती है। शिक्षा की कार्यकलाप से जोड़ कर निरसता को दूर किया जा सकता है।

७—समस्या आधारित शिक्षाक्रम इसकी उपयोगिता रखता है।

८—व्यक्तिपरक शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत हम बहुतों ऐसे लोगों को पाते हैं जो पढ़ाई से एक बार मुक्त मोड़ चके होते हैं। अब इस पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। प्रोग्राम के प्रसार में यह तो और भी आवश्यक हो जाता है।

९ स्व शिक्षा तथा सह शिक्षण का प्रयोग आगे की शिक्षा में अनौपचारिक कार्यक्रम के प्रसार में सर्वोत्तम का विशेष महत्व है।

१०—अनौपचारिक शिक्षा के विशेष प्रत्याशी यह होते हैं अनौपचारिक शिक्षा के प्रत्याशी अनेकानेक वर्गों के लोग हो सकते हैं जिनके बारे में ऊपर चर्चा किया जा चुका है। किन्तु वर्तमान परिस्थिति में एक मान्यता के रूप में शिक्षाक्रम बनाने की बात है। उन लोगों के लिए प्रोग्रामों की तीन वर्गों में बांट सकते हैं —

(क) साक्षरता अभियान तथा शिक्षा का साक्षरनीकरण।

(ख) उत्पादनपरक शिक्षा।

(ग) सामाजिक शिक्षा।

इस कार्यक्रम में १९४४ वर्ष के विद्यालय छोड़ने वाले लक्ष्य विद्यार्थियों में न जाने वाले बालक तथा १५-५५ वर्ष के अधिक आयु वाले असिद्धित प्रोग्राम विशेषरूप से आते हैं। इनके लिए (१) साक्षरता तथा (२) उपयोगी शिक्षा, जिसमें उत्पादन प्रेरित तथा सामाजिक शिक्षा भी सम्मिलित है दोनों ही प्रकार के कार्यक्रम निहित हैं। इस समय साक्षरता पर ही विशेष धन तथा प्रायः धन्यता दी जा रही है। १९४४ वर्ष के बालक बालि-

काओं के लिए यह भी सोचने की आवश्यकता है इनको किस तरह द्रुतगति से शिक्षण देकर औद्योगिक शिक्षा की धारा में डालकर बसा ८ लाख की योग्यता प्रदान कराई जाय। इसमें जो छात्र प्रतिभा सम्पन्न हैं उन्हें और आगे की शिक्षा देकर बड़ों का अवसर दिया जाय। इस प्रयत्न में द्रुतगति शिक्षण के लिए १ पाठ्यक्रम की सहजा तथा २ अधिगम के मूल्यांकन के स्वरूप के बारे में विशेष रूप से सोचने की जरूरत है। यह भी आवश्यक है कि इस औद्योगिक शिक्षा केन्द्रों को उचित प्रतिष्ठा दी जाय। जिससे इनके शिक्षितों तथा शिक्षक दोनों ही हीन भावना ग्रस्त नहीं हो। साथ ही इन केन्द्रों का साहस भी बढे।

श्रीलंका की साक्षरता के बारे में उनको अभिरुचि थी तथा उनको साम्यवादों एवं परिवर्तन मानस के अनुरूप शिक्षाक्रम बनाने पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। माया शिक्षा पूरी पढाई की कुन्नी नहीं आ सकती है किन्तु इस सम्बन्ध में जो पाठ्यक्रम और साहित्य मिलता है, साकार्यक नहीं है, क्या उसकी विषय वस्तु सम्प्राप्त मर्याद के भक्तिमय की ही उपज मान ली जाती है ?

उत्पादन परक शिक्षा

देश के आर्थिक विकास के सन्दर्भ में यह काम वात करी जाती है कि हमारे किसान और कारीगरों की उत्पादन क्षमता अन्तराष्ट्रीय स्तर से अति ग़ुप्त है। इसमें कुछ हद तक मनुष्य के ज्ञान के सिद्धांत पर उचित तकनीक के प्रसार की आवश्यकता है। किसानों और कारीगरों को उसके सीखने और प्रयोग करने के लिए समय देना है। इस सम्बन्ध में औद्योगिक शिक्षा की उद्घाटन में विभिन्न कार्यक्रम अन्तर्गत जरूरी है।

इस प्रयत्न में महिलाओं की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण होनी चाहिए क्योंकि वे अधिकोच्च घर के चूल्हे बनाती तथा ही सीमित रह जाती हैं। महिलाओं के हस्तशिल्प की क्षमता का प्रयोग करके अनेक प्रकार की वस्तुओं का प्रसार किया जा सकता है। क्या इससे लिए हमारे सामने कोई प्रोत्साहन है ?

सामाजिक शिक्षा

सामाजिक शिक्षा की जड़ें बड़ी पुरानी हैं। इसमें सम्बन्धित विभाग और उपविभाग भी बम्हरी हैं। साम्यद फंजन व रूप में आये और उसी के अनुरूप लुप्त भी हो गये। इसने प्रोत्साहन प्रसार प्रसार विचार गये। साम्य-कता है कि सामाजिक शिक्षा में व्यापक साम्यवाद बसाए जाय जो साक्षरता अभियान और उत्पादन कार्यक्रमों से जुड़े हों। इस प्रयत्न में निम्नलिखित उद्देश्य विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हैं।

- (१) बच्चों की देखभाल
- (२) घरों की साज सज्जा
- (३) स्वास्थ्य शिक्षा तथा सेस क्लब
- (४) सांस्कृतिक तथा मनोरंजन कार्यक्रम
- (५) अन्धों नागरिकता की शिक्षा जिसमें नेचुरल की शिक्षा भी सम्मिलित है।

नागरिकता की शिक्षा के साथ राजनैतिक शिक्षा का जोड़ना समीचीन प्रतीत होता है। अथवा तीन हजार वर्ष पूर्व पेरिक्लीज ने कहा था कि एथेन्सवासी अन्य लोगों से इस बात में भ्रष्ट हैं कि उनका प्रत्येक नागरिक राजनीति में सक्रिय भाग लेता है। यदि यह आदर्श आजकल के सन्दर्भ में हमें भाग्य हो तो हमें क्या करना चाहिए ? विशेष रूप से दक्षिण और प्राचीनता की शिक्षा के सन्दर्भ में ?

बच्चों की देखभाल के सम्बन्ध में क्या यह उपयुक्त होगा कि बड़ी बस्तियों और ग्रामों में निम्न वेग्न लीते जाय। आन्दोलनों और आतङ्कवादों के कार्यक्रम कुछ राज्यों में फाँड़ी सक्रिय है। उत्तर प्रदेश के सन्दर्भ में इसके बारे में सोचा जाय ?

व्यवस्था तथा क्रियायन

जैसा कि ऊपर सकेत कर चुके हैं औद्योगिक शिक्षा को भी एक तरह की व्यवस्था चाहिए और सफलता के लिए एक उत्कृष्ट नियोजन। राष्ट्र की और विशेषरूप से हमारे राज्य की परिस्थितियों को देखते हुए यह उचित प्रतीत होता है कि औद्योगिक शिक्षा (रोप पृष्ठ ४६ पर)

शिक्षा पर राष्ट्रीय-नीति का प्रारूप

छात्र आत्मसम्मान आन्दोलन

सुप्रसिद्ध शिक्षा सारणी एवं संसद-सदस्य

इस निबन्ध में विद्वान् नेमके ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नवीन प्रारूप के एक-एक अंश का समीक्षा परम्परा तत्परकर विवेचन प्रस्तुत कर, समाज के सभी वर्गों के लोगों को इसका सही भाति सम्यपन करने की तरफ सहाह दी है। लेख ने अन्तिम भाग में इसने कतिपय इसकी कमियों की ओर भी मनेत दिया है। वर्तमान सरकार का यह पुनीत कर्तव्य हो जाना है कि इस नवीन प्रारूप को अन्तिम रूप में स्वीकार करने में पहले यह इन कमियों का निपटकरण करें ताकि नवीन नीति के समर्थ में यह शिक्षा-वर्द्धति किसी प्रकार की कुठारों से मुक्त रह कर राष्ट्र की युवा पीढ़ी को, परिवार, समाज तथा राष्ट्र के प्रति उत प्रतिपत्त उपारेय बनाने में सफल हो सके।

—संपादक

सरकार ने शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति का प्रारूप, 1९०६ में प्रस्तुत किया है। सबसे मोझू पृष्ठों के इस विवरण-पत्र में कतिपय अंशों को आरम्भ में ही एक प्रकार के प्रस्तावना के रूप में स्थान कर देना आवश्यक है।

प्रथम यह सरकारी नीति का विवरण पत्र है, किसी एक मंत्री अथवा मन्त्रालय के किसी अधिकारी का वक्तव्य नहीं। यह एक नीति-विवरण-पत्र है जो केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल द्वारा अनुमोदित है।

दूसरे, यह प्रारूप है; यैसा कि विवरण-पत्र के प्रारूप में कहा गया है, इसका उद्देश्य कोई हस्तोपन अथवा परिवर्तन कर सकती है।

तीसरे, अन्ता सरकार के अन्तर्गत होने के समय से ही तैयार की गयीं के वर्तमान विचार-विमर्श का फल है। प्रस्तुत पहले ही दिन प्रमाणमयी और शिक्षा मंत्री ने विचार विमर्श शुरू कर दिया था, जिसके लिए १९१६ की संसद द्वारा स्वीकृत शिक्षा की प्रथम राष्ट्रीय नीति में व्यवस्था भी है कि हर पाँच वर्ष पर नीति विवरण पुनरीक्षित होता चाहिए। इसका पुनरीक्षण हमें १९०४ में ही कर लेना चाहिए था। पर हम चुन गये। इस प्रकार इस प्रथम विवरण-पत्र में स्वीकृत हुए बाव १० वर्षों हो चुके और पिछले दो वर्षों में कई बार विचार

विमर्श होये रहे हैं। शिक्षा मन्त्रालय ने, और अन्य प्रधान मंत्री ने भी विचार-विमर्श, शिक्षाविदों तथा राज्यों के शिक्षा अधिकारियों से कई बार विचार विमर्श किए, बल्कि हर राज्य के शिक्षा मंत्री से विचार-विमर्श करने के लिए भी शर उनके सम्मेलन आयोजित किए गए। इस प्रकार प्रत्येक राज्य की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सम्मेलन, विरल-विशालय अनुदान आयोग इत्यादि के साथ नीति के प्रारूप की चर्चा करने और उस पर टीका टिप्पणी करने का अवसर मिला था।

यह विवरण पत्र ऐतिहासिक निरन्तरता और साथ ही नवी उद्भावनाओं - कतिपय नयी बातों का परि-पक्व सम्मिश्रण है। यह विस्तृत नहीं बोल ही, ऐसी बात नहीं। ऐसा हो भी नहीं सकता। शिक्षा अपना यह रूप नहीं भूल सकती कि वह एक स्थायी क्रिया है, जीवन चरन्त है, एक निरन्तर प्रक्रिया है, परीक्षण करती है। इसलिए ऐतिहासिक निरन्तरता का तत्पर इसमें है और हममें से कोई जबर् इसमें देवता नयी बातें हो देखा चाहें तो यह बलत होगा। इसमें नयी उद्भावनाएँ भी हैं, किन्तु भारत की वास्तव्य ऐतिहासिक प्रणाली के विस्तृत चौखटे के भीतर हम नीति विवरण का व्यापक प्रारूप है और इसमें शिक्षा के सभी अंश, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च, प्राथमिक, उच्च, नवस्क शिक्षा स्तर, माध्यमिक

शिक्षा स्तर, विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा स्तर तथा तकनीकी, कृषि विषयक और चित्रितकारी शिक्षा सबका समावेश है। इस विवरण-पत्र में इस बात की निम्नलिखित व्यवस्था है कि प्रत्येक स्तर पर संश्लेष प्रणाली का भेद समान से घनिष्ठ सम्बन्ध बने रहना चाहिए।

इस नीति विवरण के प्रारूप के निम्नलिखित महत्वपूर्ण पक्षों पर मैं विशेष बल देना चाहूँगा।

प्रथम, इस विवरण-पत्र के ये आदर्शपरक भाग मुझे बहुत पसन्द आये हैं। कहा गया है कि शिक्षा का लक्ष्य है व्यक्ति का विकास और व्यक्ति के विकास से ही सामाजिक विकास सम्भव है। इस लक्ष्य में वस्तुतः साथ यानी स्वयं नैतिकता पर अधिक जोर है। उदाहरण के लिए उक्त कहा गया है कि सत्यपूर्ण जीवन के द्वारा व्यक्ति का विकास ही शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए और यही मूल व्यापक मीमांसा में शिक्षा के प्रयोजन की धारा है। कहा इन बातों पर जोर है कि वह प्रयोजन शिक्षण से हटकर ज्ञानार्जन होना चाहिए। विष्णुन जीक। समस्त शिक्षा ज्ञानार्जन हो तो है, शिक्षण तो मात्र एक साधन है।

द्वितीय, इस प्रयोजन में गांधीजी की शिक्षासिद्धि के तीन मूल तथ्यों का समावेश किया गया है। एक-समस्त ज्ञानार्जन के प्रति गंभीरी का भाव निरीक्षणमय दृष्टिकोण, इसका तात्पर्य यह कि ज्ञानार्जन एक ऐसी प्रक्रिया है, जो आपके ही भीतर होती है, वह ऊपर से योनी नहीं जाती। दूसरा—हाथ और हृदय के परस्पर सम्बन्ध पर उनका शिक्षा के प्रभावित रूप—बौद्धिक कार्य और शारीरिक कार्य में समन्वय स्थापित करता है, और तीसरा है शिक्षा के सामाजिक दायित्वों में गंभीरी की भावना।

इस प्रकार शिक्षा के प्रयोजन का तीसरा भाग है समुदाय-सेवा तथा रचनात्मक और सामाजिक उपयोग के कार्यों में भाग लेना, और जहाँ न नैतिक शिक्षा पर पुन जोर दिया गया है जिसकी, मेरी दृष्टि में, हमारे जीवन के इस चरण में बहुत जरूरत है। नैतिक शिक्षा सभी विषयों में अन्तर्सम्बन्धित पाठ्यक्रमों और सह-

पाठ्यक्रमों कायंक्रमों के द्वारा पाठ्यक्रम का एक अंग हो जानी चाहिए, और वह सभी अध्यापकों और समस्त सस्थाओं का दायित्व होना चाहिए।

तब मैं उस उपाय पर जोर दूंगा जिससे शिक्षा एक और तो जीवन पर्यन्त जारी बनी रहे, धूल तथा वातैय प्रवाह बरकर साधारणता के अभाव, ब्रह्म, छह वर्ष, आठ वर्ष बारह वर्ष के लिए न रहे, और दूसरे, प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह बच्चा हो या बरकर, अपने ज्ञानार्जन का रास्ता चुनने के लिए स्वतन्त्र है। उस पर पाठ्यक्रम की कोई खास पद्धतियों, शिक्षा प्रणालियों और इस तरह की चीजें लागू नहीं करनी चाहिए।

तीसरे में, प्राथमिकताएँ स्पष्ट कर दी गयी हैं। इसमें एक नयी उद्घाटना है। एक तो प्रारम्भिक शिक्षा की निम्नलिखित प्राथमिकता दी गयी है अर्थात् विवरण-पत्र में कहा गया है कि लघुविद्यालय की व्यवस्था में अनुसार, १४ वर्ष तक की शिक्षा की अपने बस प्रथम में निश्चित व्यवस्था हो जायेगी और दूसरे, वरकर शिक्षा को उच्च प्राथमिकता है। जहाँ तक माध्यमिक शिक्षा की बात है, कहा गया है कि उसका बहुत प्रचार नहीं, बल्कि सुचारु होगा और व्यवसायीकरण की व्यवस्था होगी। समस्त माध्यमिक शिक्षा के और अभाव अस्तित्व दो वर्षों के व्यवसायीकरण की नयी दृष्टि को अपनाया गया है, और साथ ही उच्च शिक्षा में एक और तो सत्यावत-स्थायित्व की व्यवस्था होगी और दूसरी और शिक्षा की विभिन्न और औपचारिक प्रणालियों के द्वारा शिक्षा के दृष्टिकोण व्यक्तियों के लिए उनमें अधिकतर उपलब्ध रहेगे।

पाचवा, प्रत्येक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा ही रहेगी। यह एक नयी उद्घाटना है, क्योंकि साथ यह समझें कि पाठ्यप्राप्तिक स्तर से लेकर पी० एच० डी०, वाकटरी शिक्षा, दैनिकीयों को शिक्षा और कृषि शिक्षा के लिए सीमित निश्चित है कि हमें क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग को और बढ़ाना चाहिए। अविष्म के लिए यह बड़े महत्त्व की बात है। इसमें हम उन सभी देखेंगे समन्वय है जहाँ समस्त वास्तविक शिक्षा स्वयं अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा में ही जाती है।

किन्तु हमारे देश में एक समस्या है जो अन्य देशों में उस हद तक नहीं है। हमारे देश में कई भाषाएँ—१५ प्रमुख भाषाएँ हैं। एक बहुत रोचक और महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि प्राइमरी स्कूलों में भाषा के पच्चे घंटे का अनुपात बनाने के लिए जो तीन पच्चे प्रतिदिन से अधिक नहीं है। कोई क्या बर्बाद करेगा यदि नहीं होता चाहिए। मतलब यह है कि ६ मास, १२ मास का न हो। वह प्राइमरी स्कूल हो जिसका समय स्थानीय भाषा पर बनाने के अनुसार निर्धारित हो। अगर वह बाबा नित बुला हो प्राइमरी स्कूल की विस्तृत व्यापकता हो तो जायगी। हमारे बच्चों के लिए तीन पच्चे प्रतिदिन काम में दिनों की सप्ताह पहले से ही नहीं बल्कि उनके घंटों के काम और जिम्मेदारी के अनुसार निर्धारित होनी।

उपर बहस शिक्षा में इस बात पर जोर है कि यह भाषा साधारणता ही भाषा बन लेना नहीं है, बल्कि एक और तो कार्यनीति प्राप्त करना और दूसरी ओर सामाजिक जागरूकता का होना है। मुझे यकीन है कि नीति विवरण में यह बात गहरी से बनी है कि हमने एक अवधि में है क्योंकि जैसे ही बहस शिक्षा द्वारा गरीब, भूमिहीन बेरोजगार मजदूरों की जमात को अपनी स्थिति और गीतों का एहसास होने लगेगा, सामाजिक शक्ति बढ़ना इस कार्यक्रम की रीढ़ और सत्य करने में कुछ उठा न रहेगी।

माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की मैं वर्षों से चला हूँ, जिसमें सामाजिक उद्देश्यों के एकत्रित कार्य और निम्नलिखित विशेषताएँ व्यावसायिक कार्यक्रमों के द्वारा माध्यमिक शिक्षात्मक के सभी छात्रों को किसी प्रकार का व्यावसायिक प्रशिक्षण मिल पायगा और कुछ को तो विस्तृत पूरी अवधि का प्रशिक्षण प्राप्त होगा। यहाँ तक उच्च शिक्षा की बात है, इसमें और औपचारिक पद्धतियों पर जोर दिया गया है।

यहाँ कि मैं बता चुका हूँ कि यह नीति विवरण अभी प्राथमिक की स्थिति में है और आप में से हर किसी

को इसे पढ़ लेना चाहिए, माता-पिताओं को, छात्रों को अध्यापकों को, उद्योगपतियों को, मजदूर लोगों को और सबसे बढ़कर छद्म के सदस्यों को, जिनके समक्ष यह प्रस्तुत किया गया है इसकी जाँच परत करनी चाहिए। सुद मेरे सामने भी छद्म या सत्य प्रत्यक्ष है, जिसकी व्यवस्था कर देना आवश्यक है। पहला, प्राथमिक शिक्षा में जो खर्चा होता है उसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह छव गरीबी के कारण है। यह खर्चा रोचक में स्कूल भवन का तो कुछ नहीं कर सकते हैं। हम जब गरीबी का उन्मूलन कर देंगे तभी गरीबों के सभी बच्चे स्कूल में पढ़ सकेंगे। दूसरा मैं वह उक्ति बसत नहीं करता कि माध्यमिक शिक्षा आवश्यकता नहीं टर्निंग है। कोई भी शिक्षा टर्निंग नहीं है। स्वयं नीति विवरण में ही कहा गया है कि शिक्षा एक जीवन पर्यन्त किया है, इसलिए टर्निंग स्पष्ट को हटा देना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति माध्यमिक शिक्षा समाप्त कर जीविकोपार्जन करते रहता चाहते हैं उन्हें फिर शुरुआत अपनी इच्छा के अनुसार उच्च अथवा व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने की स्वतन्त्रता रहनी ही चाहिए तीसरा, मेरा स्वागत यह है कि उच्च शिक्षा का लक्ष्य कमजोर है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य प्राथमिक शिक्षा में नहीं है, माध्यमिक शिक्षा में नहीं है, बल्कि शिक्षा में नहीं है हमारे विश्वविद्यालयों और कालेजों में है। किन्तु इस बात की पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया है। पाठ्यपुस्तक शिक्षा का लक्ष्य भी अचूक है यह एक ऐसे आदर्श की तरह है जो मुझे मैं जानो तो ला दे पर बात नहीं खत्म हो जाए। सांस्कृतिक लक्ष्य तो बड़ा दायित्व है। क्या निभायायी पाठ्यपुस्तक की बात सुनना भी नहीं है पर हब अच्छी तरह जानते हैं कि तमिल नाडु जैसे कुछ राज्यों में हि मायायी पाठ्यपुस्तक है और यहाँ उत्तर भारत में ही कुछ राज्य हैं जहाँ एक मायायी पाठ्यपुस्तक है। इसलिए यह बात स्पष्ट कर दी जानी चाहिये यह कि मायायी पाठ्यपुस्तक किस प्रकार एक राज नीतिक पदों के अलावा और भी कुछ है। तब समस्या है पन्थिन स्कूलों की, और उन्हें सामान्य प्रणाली के अधीन करने के लिए पन्थिन स्कूल के माध्यमिक शिक्षा

वही सावधानी से विचार-विमर्श करने की आवश्यकता होगी।

और अन्त में अन्धकार विषयक खण्ड, जो अत्यन्त महत्वपूर्ण है, बिल्कुल दकियानुसी है और उस ओर जो कुछ करना आवश्यक है। अपनी यह वार्ता मैं इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त कहूँगा कि यह एक अच्छा विवरण-पत्र है जिस पर हमें विचार, चिन्तन-मनन करना

चाहिए, और इसमें प्रत्येक व्यक्ति और प्रधान मंत्री के भी प्रयास की स्पष्ट छाप है। वस्तुतः प्रधान मंत्री ने बनेक अवसरों पर कहा कि वाश "मे गिस्ता मंत्री होते।" इस कथन से निहित उनका भाव मैं समझ सकता हूँ।

(पृष्ठ ४२ का अंश)

मे उपर्युक्त तीनों कार्यक्रमों को बड़े पैमाने पर आन्दोलन के रूप में चलाया जाय। बड़े पैमाने पर चलाने से इकार्ड-बन्धन कम होगा और बहुत सी कठिनाइयों को तो आन्दोलन की आधी अपने आप उठा ले जायेगी। ऐसे आन्दोलन की गतिशील और प्रभावी बनाने के लिए वर्तमान डग का प्रयासन सम्भवतः कारगर सिद्ध न हो। प्रयासन कैसा हो और उसकी क्या संरचना हो? यह एक खुले भिदाव का विषय है।

शोध तथा मूल्यांकन

अनीतवारिध शिक्षा की जो तस्वीर हमारे सामने उभर कर आती है उससे यही सगुता है कि उसके किया-

गमन के लिए स्कूली शिक्षा की अपेक्षा कहीं अधिक पहल, समझदारी तथा उत्पन्न शक्ति की जरूरत है। ऐसी परिस्थिति का समानरूप से सामना करने के लिए अधिक जानकारी चाहिए। यह जानकारी सर्वोद्योग-प्रयोग तथा शोध द्वारा ही मिल सकती है। यह कैसे और कहाँ सम्पन्न हो? यह एक मूल्यांकन आवश्यकता है। इसी से सम्बन्धित निरन्तर कार्यक्रम मूल्यांकन का आयोजन भी होगा जरूरी है। आज कल ऐसे मूल्यांकन से हम खी कतराते हैं। जब करोड़ों रुपये स्वाहा हो जाते हैं तब पूछ-ताछ होती है कि क्या कोई काम हुआ है। इस परिस्थिति से कैसे बचे ?

किसी काम में लगा देते थे। इस बारे में उनकी सेवा नेपाव के रूप में सुनसी मेहर की कोटि की थी। प्रभावशाली के द्वारा इस प्रकार की पारिवारिकता का दायरा बढ़ता गया, बढ़ता गया। इसका कारण था उनकी स्फुटिकृत व्यक्तित्व धरिय और अगाध प्रेम।

मैंने उनसे अस्पताल नाम में देखा कि वे दूसरे व्यापक रचनात्मक कामों में नहीं पड़े थे। अपने दायरे में रहकर जो बन रहा, कर रहे थे। उसमें भी व्यक्ति-मतरूप से जो भी व्यक्ति की सहायता हो सके, उस पर उनका पत था। उनसे मैं नहीं स्नेह कार्य से हर्म दुनिया जोड़ें, ऐसा उनका मान था। जब तक नूदान आन्दोलन शुरू नहीं हुआ, वे सेवाश्रम कार्य के बाहर के व्यापक क्षेत्र से काम ही सम्पन्न रखते थे। गिनोबा की आज्ञा से नूदान कार्य निमित्त आश्रम प्रदेश का सर्वोच्च कार्य उनका ध्यान बना और इसके एक पैर सेवाश्रम और दूसरा आश्रम रखते थे। उनका कहना रहता कि, रात को मैं जब भी, जहाँ भी सोता हूँ अनुभव करता हूँ कि बापू के आश्रम में, सेवाश्रम में ही हूँ और सुबह उठ कर उन्हीं के कामों में लग जाता हूँ। उनका वादा रहता कि रात की उपस्थिति सेवाश्रम में गिनी जागी चाहिए। वे सेवाश्रम आश्रम प्रतिष्ठान बनाने जाने पर उतने बड़ी बने और हाल तक उस पद की निमित्त रहे।

आश्रमप्रदेश में सभी रचनात्मक कार्यकारिणों से प्रेम का स्वयं रखकर उन्हें परस्पर जोड़ने का कार्य तो वे करते ही रहे पर उनकी दूसरी बड़ी विशेषता रही राजसक्ति के माध्यम से प्रत्यक्ष प्राप्त करने की। दिल्ली में ही या प्रदेश में वे कभी जल्दी अजीबगणों से भिन्नकर उनका सहयोग प्राप्त कर लेते थे। बापू, राजेन्द्र प्रसाद, रविवर नेहरू, इन्दिरा जी सभी के पास उनका आना-जाना रहता था। मुझे कभी कभी शक होता है उनकी सेवाश्रम बापू की अनुप्राण भी और उनका गहुर तथा निश्चिन्त स्वभाव और निश्चिन्त श्रद्धा यह सब सामने वाले को बापू की सहज मात्र दिव्य और अपने दिल की बात प्रभावशाली की वहाँ की उसकी दृष्टि हो-ने। जो हो बड़ी-बड़ी में उनका सम्बन्ध रहता था और उसके द्वारा वे अनन्त सेवा शर्म कराने में सफल होते थे। किसी का

जैसा भी शर्म हो, उससे प्रति प्रवित होकर वे उनके काम को उठा लेते और वहाँ भी जाना-आना हो, दोष धूप कर के धुल्लाते थे। उनसे इस गुण से बहुतों को सहारा मिलता। मर्यादा सामाजिक कार्य और व्यक्तिगत कार्य के बीच की सीमारेखा में इससे स्पष्टपण आता, पर उनका मित्र का मानना था कि उनकी नृति सामाजिक हित की दृष्टि से ही, सब नामों को देखने की है।

जिन सेवा-सत्याग्रहों से उनका घनिष्ठ सम्पर्क था उनमें प्राकृतिक निर्विस्तार का स्वभाव था। उनके लिए उन्होंने बहुत शर्म किया और अनेक उपचारानुभवों को सहायता पहुँचायी। उनके अपने जीवन में भी वे प्राकृतिक सिद्धान्तों का अंगुल करते थे और उनकी अतिम बीमारी में भी जब तक उनकी हालत बर्बाद होने से बचता रहा। शरीर में वे पूर्णतः और शक्ति थे। बड़ छोटा और इनका था, पर शर्म करने को उनकी क्षमता किसी से कम नहीं थी। उनका प्रवास तो इतना अधिक था कि कभी कभी तो आधा सहीता देश में ही प्रवास रहता। अपने लिए, बाँट सहन करने की उनकी क्षमता थी, पर दूसरे का दुःख ऐसा नहीं जाता था।

१९७७ में आश्रम में लूकान जी गैट में कृष्णा जिले का दिवाी तालुका [तहसील] सबसे अधिक प्रभावित हुआ। उते उन्होंने अपना क्षेत्र मानकर बहुत काम किया। अभी एक माह पूर्व दूसरा लूकान ओगोल तट पर आया। वे उसी के निरीक्षण के लिए गये थे तब बीमार पड़ गये। मस्तिष्क के बाहरी भाग में रोग का असर हो गया 'मेनिन्जोइटिस'। सात दिन बेहोश रहे। पुटूर ने सर्वे अस्पताल में डॉक्टरों ने जी तोड़ कोशिश की, पर वे उनके शरीर को बचा नहीं सके। पुटूर, विजयवाड़ा और हैदराबाद में हजारों में उनका अतिम दर्शन दिया। उनका अतिम संस्कार हैदराबाद में शिव-रामपल्ली आश्रम में किया गया, जहाँ वे अपना आश्रम का हैडक्वार्टर बना कर रहते थे। पर वे तो सतत प्रवासी थे, अनिवार्य वृत्ति थे। अन्त की उनकी यात्रा थी, अन्तपुत्र नाम ने स्थापित थे गुरु हर्ष इस जन्म में और अन्त तक चलती रहने वाली है।

३१ सात पूर्व व्यक्त की सभी उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें बलि दी गयी, यो बचना देखिये के हाथों आज की असेमबली ने उनकी श्रद्धाजति अर्पित की और मनोरंजन तथा विषादकों ने उनका अंतिम दर्शन दिया ।

गोमेवा के साथ वे सहज ही जुड़ गये । जंगली माह से उन्होंने बेलन की सीमा में बाहर के माह-बेलन करने में जाने एगरे मुहिम में वे रुके थे । सभी रास्ता का सम्पन्न कर के उनकी रोहवे में प्रविष्ट लगा रहे थे । अर्धदेतन अवस्था में वे मरने के धाउ दिन पूर्व बीच-बीच में बहरी बोलते थे, देखो-देखो गाव बटने जा रही है । उसे रोको बेलन सीमा पर ।

इस प्रकार सेवा के आनन्द द्वारा अपने को पहुँचाने का उनका रास्ता था । अनेकों की अनेकों प्रकार से उन्होंने सेवा की । सेवा सेना उनकी सम्पन्न नहीं लगा । जन्म से ईसाई के घर बापू के पास आ कर सभी घरों के

साथ इतने सराबोर हो गये थे कि भूल गये कि घरों का सेवास क्या था । मजन, पीतो म दूब जाते थे । खात-पति भी, आदमी-आदमी के बीच भेद-भाव करने वाली दीवारें उन्हें बाधद दी । उन्होंने वे दीवारें तोड़ने वाली को हमेशा सहारा दिया । रूनी-बलिन विकास उनके घरों में प्रभुत्व स्थान पाता रहा । अवि-बाहित रहे पर अपना परिवार छोटा नहीं बनने दिया । सभी के परिवारों को वे अपना बना लेते थे । सबसे सुन-सुन में पामिल होते थे । आज जब वे नहीं रहे, इन सभी परिवारों में उनके बिछोह का गहरा दुःख है और दुःख है उन समेक सम्पत्तियों और भावनों में जिनको उन्होंने लगाया दिया । पर अव्यक्त दुःख तो अनेकों को है ही ।

बदल मत असंजन पछता,
दुःखदुःख उभय बीच बाग़ बरना ।
बिस्मृत एक प्राण हरि लेही,
मिलत एक दुःख साधन देही ।



जिम साहित्यिक शक्ति के बिना भारत का एक भारतीयता का बचना दुष्कर प्रतीत हो रहा है, वह मानवीय शक्ति होगी, आन्तरिक शक्ति होगी—ऐसी शक्ति होगी, जिससे भारत का सम्पूर्ण व्यक्तित्व के जीवन में उत्तर जायेगा । तब व्यक्ति अपने हितों का धर्म समुदाय के हितों में करने लगेगा और ईसा ही जीवन जीने लगेगा । इस शक्ति के बिना न समाजवाद बन सकेगा न साम्यवाद । सर्वोदय तो उसी शक्ति का दूसरा नाम ही है । व्यक्ति समूह के लिए जीए और समूह व्यक्ति के लिए । यह हमारी आधुनिक शक्ति आलोचना की एक प्रक्रिया है ।

— व्यपप्रकाश नारायण

हम यह नहीं चाहते हैं कि सुख बढ़ते चले जाएँ। वह पारव
धमरीका के लोग करते हैं। हम लोग इतना ही चाहते हैं कि
दुःख मिटे। यदि दुःख नहीं रहेगा, संसार की चिन्ता नहीं
रहेगी, तो हम प्रेम से भगवान का नाम लेते रहेंगे। यह अपने
देश का हृदय है। यह बात दूसरे राष्ट्रों को सोखनी होगी।
सुख को बढ़ाते रहने से सुख बढ़ता नहीं, उसे मर्यादा में रखने
से ही बढ़ता है। यह बात सारी दुनिया को भारत से सीखनी
होगी। दुनिया यह बात ठन सीखेगी, जब हम हिन्दुस्तान में
किस को दुखी नहीं रहने देंगे। फिर भारत की सम्भ्रता में
ये शांति और प्रेम है, उसका मूल्यांकन दुनिया करेगी।

—विनोद

वर्षा १९७६ नयी तालीम समिति के लिए श्री अशोक कुमार वरुण अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश नयी तालीम समिति
आग प्रकाशित एवं विना शुल्क नयी तालीम समिति से प्रकाशित